Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

112998

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

1036

सम्पदा

गणतंत्र परिशिष्ट-सहित

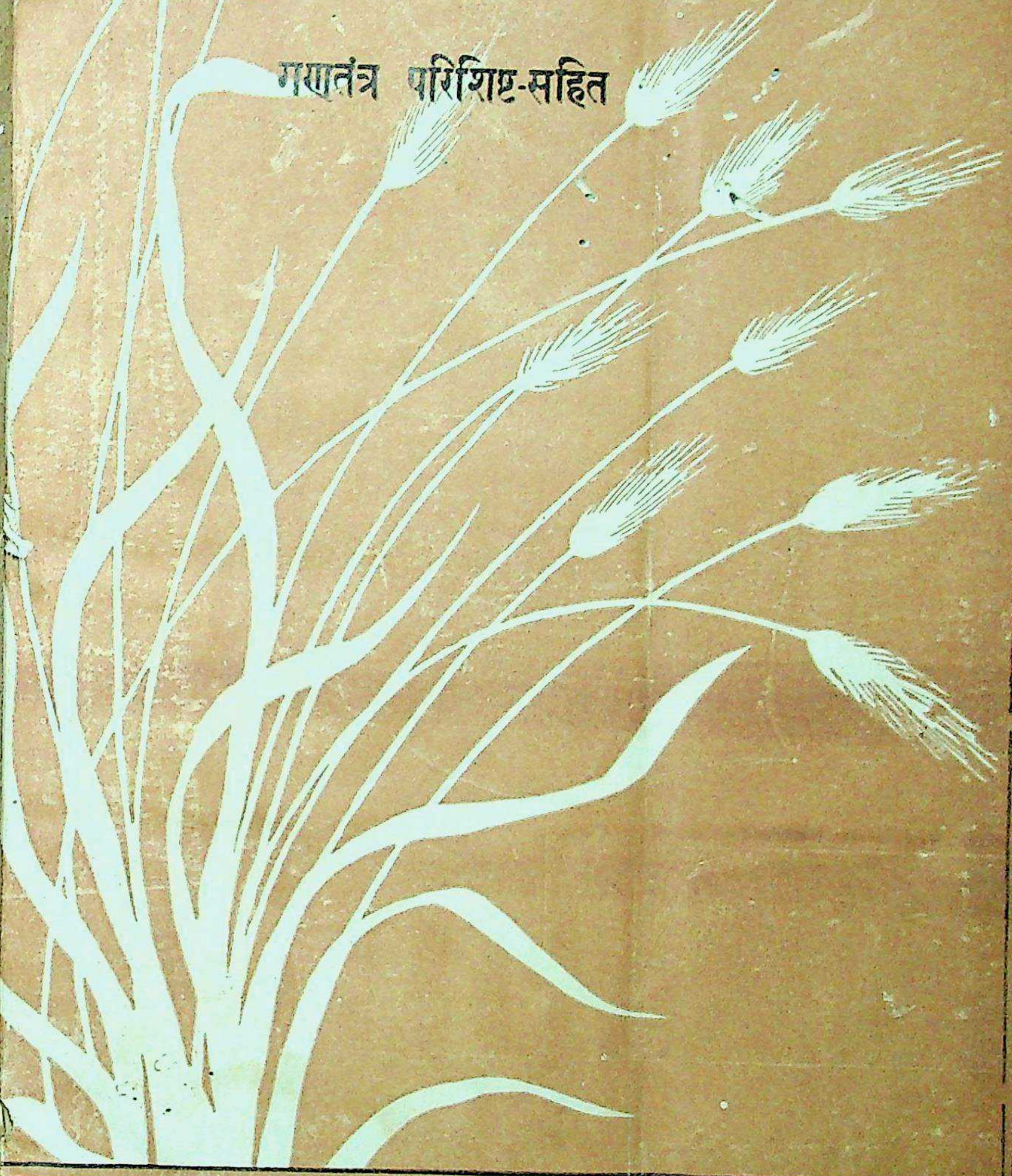

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर दिल्ली

मूल्य
७५ नये पैसे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

1038

खेती के मोरचे पर पंजाब की प्रगति

सफलताएँ : एक दृष्टि में

- पंजाब में प्रति एकड़ अधिकतम पैदावार इस तरह हुई—गेहूं ८३ मन, धान १०० मन, मक्का १२० मन और जवार ४८ मन।

- किसानों को बढ़िया किस्म के बीज देने तथा उपज बढ़ाने के लिए राज्य सरकार १४० बीज-फार्मों को चला रही है। १९६०-६१ के अन्त तक इन फार्मों की संख्या २२८ हो जायगी।

- १९५८-५९ के फसली साल में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए सरकार ने किसानों को २४ लाख रु० तक ऋण दिये थे। ९ लाख रु० उद्यान लगाने और १६ लाख रु० ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण दिये।

- १९५८-५९ में दो लाख एकड़ खेतों में हरी खाद दी गई थी, जबकि १९६०-६१ में यह लक्ष्य ३॥ लाख एकड़ नियत किया गया है। शहरी व देहाती केन्द्रों में सालाना ६० लाख टन कम्पोस्ट खाद तयार की जाती है।

- जापानी पद्धति से धान की फ़सल बोने का लक्ष्य १९५८-५९ में २,८१,२५० एकड़ था जबकि १९६०-६१ में यह लक्ष्य ३,५०,००० एकड़ रखा गया है।

- फल वाले वृक्ष १९५५-५६ में ५३००० एकड़ में बोये गये थे, पर १९६०-६१ से ७५,००० एकड़ में बोये जावेंगे।

• • •

विस्तृत जानकारी के लिए

पंजाब मंडप

विश्व कृषि मेला, नयी दिल्ली में पधारिए।

पुस्तकालय गुरुकुल कांगड़ी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विषय-सूची

१. कृषि के यंत्रीकरण से पूर्व— ५
२. कोलम्बो योजना से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ७
३. सम्पादकीय टिप्पणियां ८
४. तृतीय योजना के स्रोत ११
५. भूमि-सुधार १३

गणतंत्र परिशिष्ट (१५ से ३० पृष्ठ)

६. हमें क्या करना है ? १५
७. बंगलौर कांग्रेस का आर्थिक कार्यक्रम १६
८. हमारे अनुभव बदल गये हैं ! १७
९. भारत में अणुशक्ति का विकास १८
१०. गिरता हुआ रुपया २०
११. भारत की खाद्य समस्या २१
१२. सोवियत संघ का भारत से समझौता २२
१३. भूमिग्रहण कैसे रुके ? २४
१४. आखिर अनाज की महंगाई क्यों ?
१५. गणतंत्र का १०वां वर्ष : आर्थिक प्रवृत्तियां २७
१६. महत्वपूर्ण सांख्यिकी ३०
१७. वस्त्र संकट आता-आता रह गया ३३
१८. सर्वोदय पृष्ठ—ग्रामोद्योगों का अर्थशास्त्र ३५
१९. विदेशों में कागजी सुवर्ण ३८
२०. १९५८-५९ में भारत की आर्थिक स्थिति ४०
२१. नया साहित्य : समालोचना ४३
२२. पंजाब में खाद्य मोर्चे पर संघर्ष ४६
२३. विदेशी मुद्रा व विदेशी सहायता ४८
२४. विदेशी अर्थ चर्चा :—रूस में कृषि का यंत्रीकरण—पौण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका—महान व्यवसायी श्री गैमन ५०
२५. भारत की वन सम्पदा ५२
२६. अर्थवृत्त चयन ५३
२७. जीवन बीमा निगम ५५
२८. वीयरवैल साइकल कं० ५५
२९. नया-निर्माण ५६

बजट परिशिष्ट

'सम्पदा' के पाठकों, एजेन्टों एवं विज्ञापनदाताओं को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 'सम्पदा' के मार्च के अंक में एक **'बजट परिशिष्ट'** दिया जायेगा ! इसमें देश के राजस्व सम्बन्धी अनेक प्रश्नों की सैद्धांतिक चर्चा के साथ साथ बैंक व राज्यों के नवीन बजट पर विचारात्मक और सूचनात्मक लेख होंगे ।

—सम्पादक

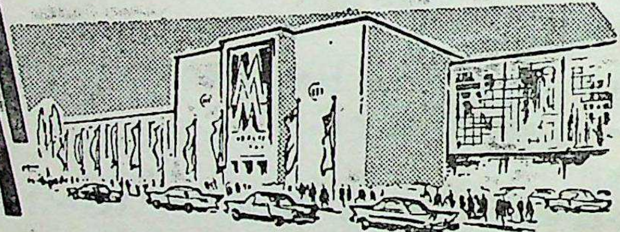

28th FEBRUARY
TO
8th MARCH 1960

LEIPZIG TRADE FAIR

TECHNICAL FAIR AND SAMPLE FAIR

The Leading Centre of East-West Trade

A mirror of Technical Progress

9500 Exhibitors from 50 Countries

Direct flights - Reduced fares by train over the Continent.
Literature from all leading travel agencies.

For details contact : LEIPZIG FAIR AGENCY. P. O. Box No. 1993, Bombay 1. D-17, Nizamuddin East, New Delhi 13. 34-A, Brabourne Road, Calcutta 1. "Lomond", 46, Harrington Rd., Madras 31.

Further information and free advice on sources of supply from

LEIPZIGER MESSEAMT - HAINSTRASSE 18a - LEIPZIG C1
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

११२९९८
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
112998

सम्पदा

वर्ष : ९
अंक : १
जनवरी, १९६०

कृषि के यंत्रीकरण से पूर्व

यद्यपि तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रधान उद्योगों पर विशेष बल दिया जायगा तथापि कृषि की उपेक्षा नहीं की जायगी। सच तो यह है कि प्रधान उद्योगों पर विशेष बल देने का कारण कृषि भी है। देश के नेता यह विश्वास करने लगे हैं कि कृषि के विकास के लिए बड़े-बड़े ट्रैक्टरों और बुलडोजरों आदि की आवश्यकता होगी। रूस और अमेरिका आदि देशों में कृषि के यन्त्रीकरण ने वस्तुत यह विश्वास उत्पन्न करने में बहुत प्रेरणा दी है। अब तक की योजनाएं भी अन्न के संकट को दूर नहीं कर सकीं। इसलिये यदि वे कृषि के यंत्रीकरण की ओर अधिक आशा की दृष्टि से देखें तो यह अस्वाभाविक नहीं है। दिल्ली में हो रही कृषि प्रदर्शनी में दिखाये गये दैत्याकार यंत्र भी इस दिशा में प्रलोभन देते हैं। रूस और चीन की कृषि पद्धति में दो विशेषताएं हैं—यंत्रीकरण और केन्द्रीकरण। अमेरिका में केवल एक विशेषता है यंत्रीकरण। भारतवर्ष में अमेरिका की केवल एक विशेषता का अनुसरण नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय किसान अत्यन्त साधनहीन है। यहां यदि यंत्रीकरण किया जाय तो उसमें सरकार को ही ट्रैक्टर संगठन तथा सहकारी समितियों को विशेष सहायता देने के रूप में केन्द्रीयकरण अनिवार्य-सा हो जायगा। इसलिए यदि भारत में कृषि का पूर्ण यंत्रीकरण किया गया तो उसके लिए रूसी पद्धति की दोनों विशेषताओं को थोड़े-बहुत भेद के साथ अपनाना अनिवार्य हो जायगा।

किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत न तो अमेरिका है और न रूस। यहां जनसंख्या अधिक और कृषि अपेक्षाकृत कम है। रूस और अमेरिका में भारत के विपरीत जनसंख्या ५० प्रतिशत कम और भूमि २-३ सौ प्रतिशत अधिक है। इसलिए कृषि के यंत्रीकरण से यहां भयंकर बेकारी आदि समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी।

फिर रूस के भी अनुभवों से हमें लाभ उठाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की बैठक में २५ दिसम्बर, ५९ को रूस के महान नेता और शासक श्री ख्रुश्चेव ने अपने देश की कृषि प्रणाली की जो आलोचना की थी, उसका आशय निम्नलिखित है—

१—रूस की कृषि सम्बन्धी सप्तवर्षीय योजना के लक्ष्य अब भी खतरे में हैं, और इसका कारण सरकारी मशीनरी की वे ही त्रुटियां हैं, जिसके कारण १९५७ में रूस की अर्थ-व्यवस्था का पुनः संगठन करना पड़ा था। यद्यपि खराब मौसम भी उत्पादन में कमी का कारण है, तथापि अनाज की बरबादी, अव्यवस्था, अनिश्चित्तता और खेती के वही दकियानूसी तरीके भी इसका एक बड़ा कारण है।

२—अनेक क्षेत्रों में बहुत कम उत्पादन हुआ है। त्रियांस्क जिले में ५१००० टन मांस का लक्ष्य नियत किया गया था। कजाकस्तान में प्रबन्ध की त्रुटियों के कारण १६,१८,००० हैक्टर में (एक हैक्टर = २॥ एकड़) अनाज खड़ा-खड़ा सड़ गया, क्योंकि १८००० ट्रैक्टर, ३२०००

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम्बाइन, २१००० ट्रक तथा ११००० रीपर (फसल काटने वाले यंत्र) ऐसी बुरी हालत में थे कि उनका प्रयोग नहीं हो सका।

३—कुछ उदाहरण ऐसे भी मिले हैं कि किसानों को जब फसल काटने में लगना था वे वस्त्र की फसल बोने की तैयारी में लगे हुए थे। खेती की बहुत सारी मशीनें लापरवाही से जोड़ी गयी थीं और पहले ही दिन वे टूट गईं। खेती में लगे हुए मजदूर व कर्मचारी भी इतने अशिक्षित और असंगठित थे कि सरकार को फसल काटने के लिए विद्यार्थियों, व्यापार में लगे आदमियों तथा दूसरे लोगों को, जिनमें कृषि-सम्बन्धी योग्यता व अनुभव की कमी थी, फसल काटने के लिए भेजना पड़ा।

श्री ख्रश्चेव ने यह भी शिकायत की कि बहुत से खेतों को आवश्यक मशीनें नहीं भेजी जा सकीं, क्योंकि रूस के कारखाने मशीनों की मांग को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे। कुछ मामलों में सरकारी अधिकारियों ने किसानों को अनुत्पादक कामों में अधिक समय तक लगाये रक्खा, जबकि उनकी आवश्यकता दूसरे कामों में थी। खेती का हिसाब-किताब रखने का तरीका भी ठीक नहीं था और सरकारी खेतों का प्रबन्ध करने के लिए जो प्रबन्ध और आर्थिक व्यवस्था की गई थी, वह भी बुरी तरह भारी भरकम थी। उदाहरण के तौर पर कजाकस्तान में ही एक सरकारी खेत पर ११० सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये गये थे, जिनमें २५-३० तो सिर्फ हिसाब-किताब रखने वाले क्लर्क थे। एक खेत के फार्म पर हिसाब-किताब रखने और १५००० कागजों को तैयार करने के लिए एक सरकारी खेत को १८००००० सूचियों की आवश्यकता होती है। इतनी भारी कागजी कार्यवाही व फाइलों की जांच-पड़ताल असम्भव ही है।

चीन के अनुभव रूस से भी ज्यादा खराब हैं। वहां १९५८ और १९५९ के लिए ३७५० और ५२५० लाख टन अनाज के दावे किये गये थे, किन्तु पीछे मालूम पड़ा कि २५०० और २७५० लाख टन से अधिक की संभावना नहीं है। यंत्रीकरण से वहां अत्यधिक उत्पादन की आशा करते हुए सरकार ने लाखों किसानों को कोयले व लोहे की खानों में भेज दिया। कोयले की नई खानों व लोहा पिघलाने की भट्टियों की संख्या तो बढ़ गई, पर उधर फसलें सूखने लगीं। कम्बाइनों और रीपरों ने अनुमान से बहुत कम काम किया। इससे परेशान होकर बन्दरगाहों के खेती से अनाड़ी मजदूर खेती पर भेजे गये, इससे जहाजों पर से माल उतारने का काम ठप्प हो गया और उधर खेती पर से पूरी फसलें भी नहीं काटी जा सकीं।

ये दो उदाहरण ऐसे हैं, जिनसे भारत के अर्थशास्त्री शिक्षा ले सकते हैं। आज देश में कृषि का न यंत्रीकरण है और न केन्द्रीकरण। यदि हमने बड़े-बड़े यंत्रों पर बहुत जोर दिया तो उसके साथ-साथ केन्द्रीकरण भी अनिवार्य हो जायगा, क्योंकि यहां बड़े यंत्रों का प्रयोग सरकार के सहयोग पर ही किया जा सकता है और इसका अर्थ है हजारों-लाखों सरकारी कर्मचारियों की देशभर में नियुक्ति, जो समस्त व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होंगे।

सरकारी कर्मचारियों पर, जिनकी गैरजिम्मेवारी, लालफीताशाही, आलस्य तथा भ्रष्टाचारिता के कारण देशभर में पर्याप्त असंतोष पहले से विद्यमान है, देश के सर्वाधिक व्यापकतम उद्योग कृषि को निर्भर कर देना कहां तक युक्तियुक्त होगा? भारत में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि लाखों रु० व्यय करके ट्रैक्टर मंगाये गये, किन्तु असावधानी व आलस्य के कारण वे बेकार पड़े रह गये। उदाहरण के लिए उत्तरप्रदेश की लेखा-निरीक्षण रिपोर्ट (१९५९) के अनुसार—

"उत्तरप्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए ४६ लाख रुपये के ट्रैक्टर खरीदे गये, किन्तु जिस काम के लिए वे खरीदे गये उस काम में वे न आ सके। वे बेकार पड़े रहे। आखिर सन् '५४ से '५८ तक वे अन्य विभागों को दिये गये। नियोजन की गड़बड़ी के कारण ही उत्तरप्रदेश में सहकारी क्षेत्र में ४६२ नलकूपों में से ३१६ बेकार पड़े हुए हैं। प्रत्येक नलकूप की औसत लागत १५०००) के हिसाब से करीब ४५ लाख रुपया बेकार पड़ा हुआ है और यन्त्र-सामग्री नष्ट हो रही है। मरम्मत में १ लाख ६५ हजार रुपया खर्च हुआ वह ऊपर से! या तो इन नलकूपों को चलाने के लिए आवश्यक बिजली नहीं मिल पा रही है अथवा जिन सहकारी समितियों की ओर से ये बनवाये गये उन्होंने दूरदृष्टि से काम नहीं लिया।" यह उत्तरप्रदेश का ही उदाहरण नहीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। प्रायः सभी राज्यों में ऐसी घटनाएं इससे भी व्यापक रूप से हुई हैं।

इन सब बातों को यह कहकर टाला नहीं जा सकता कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर लेंगे। यह सुधार होते हुए भी यदि यह संभव हो तो वर्षों लग जायेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि वर्तमान परम्परा के औजारों में थोड़ा-बहुत सुधार करके बढ़िया बीज, सिंचाई और अच्छे गोदामों की व्यवस्था पर बल दिया जाय तथा किसानों को आवश्यक उपकरणों, बीज तथा बैलों के लिए आर्थिक सुविधा दी जाय।

कोलम्बो योजना से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

किसी भी देश को बड़े पैमाने पर विकास करने के लिए मशीनों, पूंजी के रूप में साधनों, और शिल्पिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। कम विकसित देशों में इनका अभाव रहता है। उनके लिए सामान मंगाने में विदेशी मुद्रा की भारी कठिनता होती है। इन समस्याओं को हल करने में कोलम्बो योजना दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की विकास योजनाओं को पूरा करने में सहायता देती है। इस सहायता के निम्नलिखित रूप हैं—

राष्ट्रीय विकास योजनाओं को अनुदान और ऋण; अनाज, उर्वरक, उपभोक्ता सामग्री तथा अन्य वस्तुएं; मशीनें, खेती के औजार, मोटर गाड़ियां, प्रयोगशाला के सामान; विशेषज्ञों और कारीगरों की सेवाएं और छात्रों को शिल्पिक शिक्षा।

कोलम्बो योजना के विवरण से ज्ञात होता है कि आरम्भ से लेकर अब तक दस वर्षों में कुल ६ अरब डालर की विदेशी सहायता प्राप्त हुई। ६ अरब डालर में से अकेले अमेरिका ने ५ अरब ६० करोड़ दिए हैं। बाकी सहायता आस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन ने दी है। कोलम्बो योजना क्षेत्र के कुछ देशों ने भी मदद की है, जिसमें भारत भी है।

भारत ने भी नेपाल और बर्मा के आर्थिक विकास में योग दिया है और अन्य देशों को भी शिल्पिक सहायता दी है। नेपाल की पंचवर्षीय योजना के लिए १३ करोड़ २७ लाख रु० की सहायता दी है। भारत ने १९५५-५६ में बर्मा को २० करोड़ रु० ऋण देने का प्रस्ताव किया।

बाद में १९५४ में जापान इस योजना में शामिल हुआ। न्यूजीलैण्ड से पूंजीगत सामान तथा शिल्पिक सहायता के रूप में ३१ मार्च १९६० तक ९३ लाख पौण्ड मिल चुके होंगे। ब्रिटेन ने १९५१ से जून १९५९ तक कर्ज, अनुदान, उधार सामान तथा कारीगरी की सहायता के रूप में १५ करोड़ पौण्ड देने का वादा किया है। अमेरिका ने इन देशों को यह ऋण अपनी मुद्रा में चुकाने की भी सुविधा दी है। इसके अलावा अमेरिका ने और सहायता देने के लिए विकास-ऋण कोष कायम किया है। इस कोष से ४२ करोड़ १० लाख डालर के ३५ ऋण कोलम्बो योजना के देशों को दिये गये हैं। अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक ने इस क्षेत्र के देशों को ४० करोड़ २० लाख डालर ऋण मंजूर किया है। कोलम्बो योजना के अलावा आर्थिक सहायता का दूसरा महत्वपूर्ण साधन विश्व-बैंक भी है। इसने १९४९ से ३० सितम्बर, १९५९ तक कुल ९३ करोड़ ५० लाख डालर का ऋण दिया है, जिसमें ६१ करोड़ ६० लाख डालर मिल चुका है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के साथ-साथ शिल्प या कारीगरी सहयोग भी चलता है। १९५० में इस योजना के सदस्य देशों ने मिलकर ८० लाख पौण्ड के कोष से शिल्प सहयोग कार्यक्रम जारी किया।

१९५० में कोलम्बो योजना के जन्म से लेकर अब तक १८,००० व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गयी है और १०,००० विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुई। जून १९५९ तक २९ लाख पौण्ड की मशीनें ट्रेनिंग और विशेषज्ञों के इस्तेमाल के लिए मिलीं। इसमें अमेरिका की मशीनें शामिल नहीं हैं। सचमुच यह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग उक्त सभी देशों के लिए बहुत लाभकारी है।

इस विकास से यह ज्ञात होता है कि इस योजना के क्षेत्रीय देशों में विकास के लिए बहुत प्रयत्न किये जा रहे हैं। यद्यपि इस क्षेत्र के देशों में प्रतिवर्ष जनसंख्या में १ करोड़ की वृद्धि हुई है, फिर भी पिछले दस वर्षों में राष्ट्रीय आय जनसंख्या की अपेक्षा अधिक बढ़ी हैं। अधिकांश देशों में खाद्य स्थिति भी सुधरी है। अभी यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मोर्चा जीत लिया है,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्योंकि अभी तक सिंचाई के लिए अधिकतर देश वर्षा पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन इन सभी देशों में धीरे-धीरे सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।

इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में नदी के पानी का सिंचाई के लिए कम ही उपयोग हो पाता है। भारत की गंगा, दामोदर और महानदी; बर्मा की इरावदी; श्रीलंका की महावेली; थाईदेश, लाओस, वियतनाम और कम्बोदिया की मेकांग तथा इन्दोनेशिया की जीतारम जैसी नदियों का अधिकांश पानी समुद्र में ही चला जाता है और सिंचाई के काम में बहुत कम उपयोग हो पाता है। भारत में १६५१ तक स्थिति यह थी कि जहां नदियों से १ अरब ३५ करोड़ ६० लाख एकड़ फुट पानी मिलता था, उसमें से केवल ७ करोड़ ८० लाख एकड़ फुट यानी केवल ५.६ प्रतिशत पानी ही सिंचाई के काम आता था।

लगभग सभी देशों में कृषि विस्तार सेवाएं चल रही हैं, जिससे किसान विज्ञान का पूरा लाभ उठा सकें। फसल को रोगों तथा कीड़ों से बचाने के लिए सभी देशों में आधुनिक उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। चाय, रबड़, पटसन, काफी और नारियल, इन देशों की विदेशी मुद्रा कमाने वाली फसलें हैं। इन फसलों की उपज काफी बढ़ रही है तथा किस्म भी सुधर रही हैं।

हालांकि दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देश कृषि-प्रधान देश हैं, लेकिन अब यहां आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उद्योगों का विकास हो रहा है। सबसे अधिक प्राथमिकता इस्पात, उर्वरक तथा मशीन औजार बनाने वाले कारखानों को दी जा रही है। साथ ही उपभोग्य वस्तुएं बनाने के कारखाने भी खोले जा रहे हैं। औद्योगिक विकास के लिए अनुसंधान का काम जारी है और अनेक देशों में औद्योगिक अनुसंधान संस्थाएं काम कर रही हैं।

सामाजिक स्थिति सुधर रही है तथा शिक्षा का प्रसार हो रहा है। शिक्षा में व्यवसाय पर अधिक जोर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों को आधुनिक शिल्प तथा विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, जिससे ये लोग राष्ट्रीय विकास के कामों में सहायता दे सकें।

एक प्रकार से लोगों में विज्ञान का महत्व बढ़ रहा है। विज्ञान की सहायता से कृषि-उपज बढ़ रही है। आधुनिक मशीनों तथा शिल्पिक जानकारी की सहायता से प्राकृतिक साधनों का अधिक उपयोग हो रहा है। नये-नये उद्योग शुरू हो रहे हैं।

यह सब समृद्धि और उन्नति की शुरूआत है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है—उपज बढ़ानी है, लोगों के लिए और अधिक कपड़ा तैयार करना है, बहुत संख्या में मकान बनाने हैं, शिक्षा का बहुत प्रसार करना है, प्रत्येक स्त्री-पुरुष के लिए विकास की पूरी-पूरी सुविधाएं जुटानी हैं। ये कुछ ऐसे काम हैं, जिनमें काफी समय लगेगा। लेकिन इनके लिए जिस तरह से काम शुरू हुआ है, उससे भविष्य की झांकी मिलती है। यह सब इन देशों की जनता और सरकारों के प्रयत्न तथा कोलम्बो योजना और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग का परिणाम है।

बंगलौर का संदेश

कांग्रेस का बंगलौर अधिवेशन, पाठकों के पास यह अंक पहुँचते पहुँचते समाप्त हो चुकेगा। इस अधिवेशन में, भारत पर चीन के आक्रमण के कारण, यह स्वाभाविक था कि देश का ध्यान इस विकट समस्या की ओर अधिक जाता। कांग्रेस ने आवडी अधिवेशन में समाजवाद का नारा देश को दिया था, तो नागपुर अधिवेशन ने संयुक्त सहकारी कृषि का नारा देश को दिया। मालूम होता है कि जनता को संयुक्त सहकारी कृषि का प्रस्ताव अभी तक भारी मालूम पड़ रहा है और वह हजम नहीं कर सकी है। इसलिये भी यह स्वाभाविक था कि कोई नया क्रान्तिकारी कार्यक्रम या प्रस्ताव आर्थिक दिशा में प्रस्तुत न किया जाए।

बंगलौर अधिवेशन में जो आर्थिक कार्यक्रम पेश किया गया है, उसका आशय पाठक अन्यत्र पढ़ेंगे। इसमें योजना की पूर्ति में कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को अपना अधिक उत्तरदायित्व अनुभव करने, प्रधान उद्योगों को विकसित करने पर विशेष बल देने के बाद सहकारी समितियों को भी संगठित करने की ओर सबका ध्यान खींचा गया है। वस्तुतः इस प्रस्ताव में देश को कोई नया कार्यक्रम न देकर उत्साह और प्रेरणा देने पर ही विशेष बल दिया गया है। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि विकास योजनाओं में जनता का पूर्ण सहयोग मिले, जो अब तक दुर्भाग्य से प्राप्त नहीं हो सका

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है, परन्तु इसके लिए जरूरी यह है कि योजना को चलाने वाली मशीनरी में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय। इसकी ओर प्रस्ताव में विशेष संकेत किया गया है। योजना की पूर्ति में जितनी बाधाएं कांग्रेस के नेताओं ने अनुभव कीं, यदि उन्हें दूर किया जा सके तो निस्संदेह आर्थिक विकास की दिशा में हम उन्नति कर सकेंगे।

परन्तु प्रश्न यह है कि प्रस्ताव में निहित भावनाओं को मूर्त रूप क्या हम दे सकेंगे ? क्या इसके लिए देश के नेता वर्तमान आडम्बर व सरकारी कुर्सियों का मोह छोड़कर गांव-गांव में जा सकेंगे ? क्या अपने जीवनस्तर को निम्न करके भी कार्यकर्ता ग्रामों की दरिद्र व अशिक्षित जनता के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे ? बड़े उद्योगों का विकास तो सरकारी मशीनरी के द्वारा हो सकता है, किन्तु देश का सर्वांगीण विकास तो उक्त प्रश्नों के उत्तर पर ही निर्भर है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर 'हाँ' में है तो बंगलौर का अधिवेशन सफल है। यदि उत्तर 'नहीं' में है तो इस प्रस्ताव का उपदेशक के प्रवचन मात्र से अधिक महत्त्व नहीं है।

ग्रामोद्योगों की ओर उदासीनता

हम इन पंक्तियों में कभी लिख चुके हैं कि आज देश के नेता और अर्थशास्त्री पश्चिमी अर्थशास्त्र के अनुसरण में ग्रामोद्योगों की उपेक्षा कर रहे हैं। यद्यपि वे ग्रामोद्योगों की चर्चा बारबार करते हैं, परन्तु उनका मन प्रधान उद्योगों के आडम्बरपूर्ण विकास की ओर ही अधिक जाता है, ग्रामोद्योग उपेक्षित से रह जाते हैं। हमारी इस बात का समर्थन उस समिति की रिपोर्ट से होता है, जिसे कांग्रेस ने अक्टूबर, ५८ में नियत किया था। इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है—"राज्यों के मण्डल, विकास आयुक्तगण और उद्योग निर्देशकगण अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम चरितार्थ नहीं कर पाये हैं। अभी तक इनमें से अधिकांश ने केवल अन्य शाखाओं को धन दिया है और वास्तविक कार्य बहुत थोड़ा ही किया है।" श्री ढेबर ने उदासीनता के दोष को कम करते हुए कहा कि "बड़े पैमाने के उद्योग खड़े कर देना आसान है, कारण, इनमें केवल मशीनों का सरोकार होता है। पर, यहां ग्रामोद्योग में तो मनुष्य से पाला पड़ता है।"

पर यही तो मुख्य समस्या है। सरकारी अधिकारी नगरों के आराम को छोड़कर गांवों में जाकर ग्रामीण जनता के निकट सम्पर्क में आना नहीं चाहते।

विदेशी विनियोजन का वातावरण

भारत की तटस्थता की वैदेशिक नीति और उसके समाजवादी समाज के सम्बन्ध में योरोपीय देशों का सन्देह जाता रहा है कि वह विदेशी निजी क्षेत्र के विनियोजकों के लिए अहितकर नहीं है। श्री ब्लेक के सुझाव पर निजी क्षेत्र के व्यापारियों का एक अन्तर्राष्ट्रीय दल का विनियोजन का वातावरण जानने के लिए भारत में आने का निश्चय हुआ है। इसके सिवा श्री सी० जे० एम० एलपोर्ट राष्ट्र मंडल के ब्रिटिश मंत्री ने यह घोषित किया कि इंगलैंड पहुंच कर निजी क्षेत्र के व्यापारियों को यह परामर्श देंगे कि वे एक प्रतिनिधि मण्डल भारत में भेजें जो विनियोजन के नए क्षेत्रों को चुने। इस समय यह माना जाने लगा है कि भारत में विनियोजन की जोखम उठाना अनुकूल है। संभव है कि भारत की नयी आर्थिक नीति से यह विश्वास पैदा हुआ हो। यदि विदेशी विनियोजक कोई विश्वास चाहते हैं तो उस सम्बन्ध में टाइम्स मेगजीन ने कहा है कि 'भारत ने पूंजीवाद और समाजवाद की उलझनों में वर्षों तक रहने के बाद निजी क्षेत्र के व्यापारियों का आह्वान किया है। पर ये विचार कुछ नए रूप में उत्पन्न हुए हैं। भारत यह देखता है कि उसे कितनी विदेशी सहायता मिलती है। कितनी सहायता सरकार को सरकार की व्यवस्था से और कितनी व्यापारियों से मिलती है। भारत में जो अंग्रेजी प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं, वे अपने अर्जित मुनाफे का पुनर्विनियोजन कर रहे हैं। श्री एलपोर्ट ने यह प्रकट किया है कि जहां तक सम्पदा से विनियोजित पूंजी और डिविडेंडों की वापसी और करों का प्रश्न है, भारत का रेकार्ड बड़ा सुन्दर है।

'सम्पदा' के नये वर्ष से ग्राहक बनिये या बनाइये

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पिंपरी पेनिसिलिन कारखाना

पिम्परी में पेनिसिलीन का सरकारी कारखाना—हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लिमिटेड—२०० एकड़ जमीन में फैला हुआ है। यह कारखाना, चीन को छोड़कर, एशिया में सबसे बड़ा है। यहां तीन पाली काम होता है, अर्थात् यहां रात दिन पेनिसिलीन तैयार की जाती है। कारखाने में पेनिसिलीन का बनना सन् १९५६-५७ में शुरू हुआ था। तब के मुकाबले में जुलाई १९५९ से यहां का उत्पादन चौगुना हो गया और यहां अब ४ करोड़ मेगा यूनिट पेनिसिलीन तैयार हो रही है।

देश में हर साल ६ करोड़ ५० लाख मेगा यूनिट पेनिसिलीन की जरूरत होती है। इसमें से लगभग तीन-चौथाई यही कारखाना बनाने लगा है।

मार्च १९५२ में इस कारखाने का शिलान्यास किया गया और अगस्त १९५४ में कारखाना तैयार हो गया।

दिसम्बर १९५४ से मार्च १९५६ तक प्रयोग के रूप में पेनिसिलीन तैयार की गई। फिर सन् १९५६-५७ में ९८ लाख ९० हजार मेगा यूनिट तैयार हुई। १९५७-५८ में दो करोड़ १४ लाख ३० हजार मेगा यूनिट तैयार हुई और १९५८-५९ में उत्पादन बढ़कर २ करोड़ ९० लाख ३० हजार मेगा यूनिट हो गया।

देश में पेनिसिलीन की मांग भी तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए कारखाने को बढ़ाया गया। नयी इमारतें बनायी गयीं और नयी मशीनें लगाई गयीं।

कारखाने में पेनिसिलीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ, स्ट्रेप्टोमाइसीन और डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसीन बनाने की भी तैयारी की जा रही है। ये एण्टिबायोटिक दवाएं तपेदिक के इलाजमें बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इन दवाओं के बनने से काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

जब ये सब कारखाने चालू हो जायंगे, तब यहां हर साल ४ करोड़ रु० की प्रति जीव (एण्टीबायोटिक) दवाएं बनने लगेंगी।

खरीदिये सैंचुरी की
प्रसिद्ध फैशन फैब्रिक्स
● असली आरगन्डी
● लैक्स ब्यूटी मल्स
● मोती वायल और फुल वायल
● एम्बोस्ड प्रिन्ट्स
● परमसुख धोती
● सादी और धारीदार पापलीन
● छपी हुई छींट, लट्ठा, ड्रिल्स
● चादरें, तौलिये, कॉटन-वेस्ट
● कम्बल—आदि आदि
निर्माता :
दी सैंचुरी
स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग
कम्पनी लिमिटेड
इण्डस्ट्री हाउस, ५९, चर्चगेट रिक्लेमेशन
बम्बई—१
मैनेजिंग एजेन्ट्स :
बिरला ब्रदर्स (ग्वालियर) प्रा० लि०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीसरी योजना के मूल स्रोत

—एक जागरूक

आज समूचे देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्त्वपूर्ण समस्याओं के विवाद पर सभी का ध्यान केन्द्रित हो रहा है। एक ओर बराबर इस बात पर विचार-विमर्श चल रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में समाजवादी समाज को किस प्रकार आधार बनाया जाय ? और दूसरी ओर योजना-निर्माण में उचित और आवश्यक स्तर का समावेश किस प्रकार किया जाए ? ऊटी गोष्ठी (सैमिनार) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्लानिंग सब-कमेटी की रिपोर्ट, फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के प्लानिंग सेमिनार से भी योजना के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है।

अतः यह आशा करना स्वाभाविक ही है कि इस नवीन योजना का निर्माण द्वितीय योजना के प्रकाश में, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर ही होगा। दो महत्त्वपूर्ण समस्याएं खाद्यान्न की कमी के कारण खाद्य समस्या तथा वाहन साधनों के गलत अनुमान से प्रादुर्भूत विदेशी मुद्रा की समस्या योजना निर्माण में अजीब बाधाओं को उत्पन्न करती है जबकि भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है। बिना किसी ध्येय को ग्रहण किए हुए एवं आलोचनाओं का मूल्यांकन किए बगैर कि वे भारतीय वातावरण के कितनी अनुकूल हैं, यह आश्चर्य की बात है कि गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी लोगों ने निर्माण की निरंतरता पर बल दिया और प्रधान मन्त्री ने इस प्रकार के निर्माण को योजना की 'मास्टर स्ट्रेटेजी' बताया।

इस अनुमान से कि खाद्य की आवश्यकताओं में औचित्य के स्तर के लिए कृषि-आधार को मजबूत बनाया गया और दूसरे कार्यों को जो स्थायीत्व कायम करने के लिए नियन्त्रण के अन्तर्गत थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण आर्थिक विकास और प्रजातंत्रीय प्लानिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इससे १९५६ में ७० प्रतिशत से १९६१ में ११ प्रतिशत, १९६६ में १४ प्रतिशत, से १९७१ में १६ प्रतिशत, १९७५ में १७ प्रतिशत की स्थायी दर से सहयोग्यता की पूंजी पर प्रकाश पड़ा। यह अनुमान किया गया था कि केवल वृद्धि और पूंजी की इस दर से, प्लानिंग में असन्तुलित निर्माण अर्थात् भारी पूंजीगत उत्पादक साधनों में पूंजी की एकचित्तता, प्रयुक्त होनी चाहिए।

यह माना गया है कि कृषि की उन्नति के साथ-साथ चतुर्मुखी विकसनशील औद्योगीकरण को निर्धनता की समस्या से लड़ने के लिए और जीवन स्तर ऊंचा बनाने के लिए आवश्यक समझा जाए। लेकिन भारी उद्योग से समन्वित योजना असन्तुलित आधार के नियमों पर आधारित एक आदर्श था जैसा कि रूस और उसके अनुयायी देशों में यथा पौलैंड, हंगरी और चीन में स्वीकार किया गया है और सन्तुलित वृद्धि के नियमों पर आधृत योजना—ऐसी योजना पूंजी-वृद्धिगत भारी उद्योगों और उपभोग्य सामानों के उद्योगों का अर्थ स्पष्ट करती है—विशाल मध्यस्थ और लघु-उद्योग की दुनिया में अन्तर था, और साथ ही साथ जो हमारे गांवों की विशेष परिस्थितियों में कृषि-औद्योगिक सम्बन्ध पर जोर देती है। कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री ढेबर का ध्यान इस पहलू पर गया और अपने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण से—"हमने शीघ्र औद्योगीकरण पर अत्यधिक जोर दिया है, बावजूद इसके कि इस प्रकार का जोर एक प्रकार की चुनौती है जो आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है और उस ध्येय की पूर्ति में भी देरी कर सकता है, जिस पर हम जोर दे रहे हैं।" उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र औद्योगीकरण लाने की चिन्ता में हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सन्तुलन बनाए रखने में असफल रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि कतिपय आशाओं की पूर्ति न होने के कारण निराशा का वातावरण बन गया है। इसलिए उन्होंने यह जोर ठीक ही दिया है कि 'भारत एक सन्तुलित दृष्टिकोण अपनायेगा। अन्त में केवल खाद्य-समस्या से सम्बन्धित आर्थिक व्यवस्था ही हमारी सब समस्याओं का हल नहीं है। लेकिन आगे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आने वाले कुछ वर्षों में, यह हमारे साथ रहेगी। औद्योगिक निर्णयों पर असाधारण जोर, जैसा कि हम सबको मान्य है, केवल कृषि विकास की समस्या पर ही छाया नहीं डालता, बल्कि काम की वृद्धि का भी द्वार खोलता है—देहाती अर्थ-व्यवस्था के कार्यों में अवसरों को उत्पन्न करता है।"

उत्साह का संचार नहीं

वस्तुतः अब यह अधिकांश रूप से अनुभव किया जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और बड़े-बड़े प्रोजेक्टों की योजनाएं भी, जनता में किसी भी प्रकार का उत्साह उत्पन्न करने में असफल रही हैं जो प्रजातंत्रीय प्लानिंग की किसी भी योजना के लिए अनिवार्य है। यह बात भी उल्लेखनीय है कि 'मास्टर स्ट्रेटेजी' से काफी लगाव होते हुए भी प्रधान मन्त्री को कहना पड़ा—"बड़े-बड़े प्रोजेक्टों के निर्माण को पूरा करने में केवल लम्बा समय ही नहीं लगा, बल्कि वे मनुष्यों तक पहुंचने में और उनकी समझ में आने तथा उनका सहयोग पाने में भी असफल रहे। इसके विपरीत उन्होंने हजारों परिवारों को उखाड़ फेंका और इस प्रकार उनकी सहानुभूति से वंचित ही रहे।" भविष्य में यह आशा की जाती है कि 'जोर' देने में परिवर्तन होगा और इन हजारों छोटे प्रोजेक्टों तथा योजना को शुरु करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जिनसे प्लानिंग के प्रति लोगों में सही समझ पैदा होगी और वे प्लानिंग का महत्त्व समझेंगे। इस प्रकार जनता में विकास के महान कार्यों के प्रति जनतंत्रीय मेल और सहयोग की भावना जगेगी।

अर्ध विकसित देशों के सम्मुख—जैसे कि हमारा देश है—यह समस्या आती है कि वह निम्नलिखित दो बातों का सही अर्थ समझे—

(१) भारी उद्योग के साथ पूंजीगत प्रबल विनियोजन;

(२) सीमांत उत्पादकता का ग्रहण, क्योंकि अकेले ग्रहण किए हुए किसी भी ढंग का पृथक् ग्रहण हमारी आवश्यकताओं के प्रतिकूल होगा। पहला ढंग भारी और मूलभूत उद्योगों का पक्षपाती है और इस आशा का संचार करता है कि इससे अर्थ-व्यवस्था में सुधार होगा जिससे बढ़कर अन्त में देश आत्मनिर्भर बन जायेगा।

इसके विरुद्ध, दूसरा ढंग पूंजी के फैलाव की हिमायत करता है और उत्पादन-ढंग में पूंजी की अपेक्षा श्रम को महत्त्व देता है। पूंजीगत प्रबल ढंग में सब से महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि यह अर्ध-विकसित देशों के सीमित साधनों के बावजूद भारी मांग की अपेक्षा रखता है। भारी उद्योगों के लिए इसके लम्बे और अपरिपक्व समय में इस परिवर्तनशीलता के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग समाप्त हो जाते हैं जिस से वस्तुओं और सेवाओं का अभाव हो जाता है, अर्थ-व्यवस्था पर घाटे की वित्त-व्यवस्था का दबाव पड़ जाता है और अन्त में उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी नहीं होती, महा दुख और क्लेश का कारण बन जाता है। इन सबसे एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे किसी भी उदीयमान प्रजातंत्र की, जैसा कि हमारा देश है—आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न प्रायः हो जाती है। यह कहना भी महत्त्वहीन नहीं है कि अन्य तत्त्वों के साथ हमारे देश में कम्यूनिस्ट भी भारी उद्योगों की स्थापना का और उनके राष्ट्रीयकरण का अत्यन्त प्रबलता से पक्ष लेते हैं और राजकीय अंचल, राजकीय व्यापार तथा कृषि-सहकारी समितियों के अर्थों में खींचातानी करते हैं। यही एक ऐसी समस्या है जो अर्ध-विकसित देशों के समक्ष आती है और जो असंतुलित विकास के सिद्धान्त पर आधारित आर्थिक क्रांति के आदर्श को अपनाने के लिए बाध्य करती है।

सबसे अच्छा समाधान, जोकि सोचा जा सकता है, यह है कि इन दोनों ढंगों का समन्वय कर दिया जाए और इन की परिधियां बांध दी जाएं, साथ ही उन खतरों से भी सावधान रहा जाए जो इनसे प्रादुर्भूत हो सकते हैं। उस देश के लिए जो प्रजातांत्रिक नियमों पर बढ़ना चाहता है, सही कदम यही है कि वह सब ओर से अपने विकास में साथ-साथ लगे, और साथ ही अपनी अर्थ-व्यवस्था को भी संतुलित और ठीक करता चला जाय। तथा उन खतरों से सावधान रहे जो किसी एक ही दिशा में अधिक जोर डालने से उत्पन्न होते हैं।

अतः यह आवश्यक है कि अपनी योजना के निर्माण में हम अत्यन्त सतर्क रहें और उसे फिर से विचारें तथा देखें और तीसरी योजना के निर्माण में व्यावहारिकता का ध्यान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूमि-सुधार और अन्न-उत्पादन

श्री राजनारायण गुप्त

भूमि सुधार साध्य है या साधन ? सवाल चाहे अटपटा लगे परन्तु है मूल भूत ! हम भूमि सुधार किस लिए चाहते हैं। इसलिए कि देश की पैदावार बढ़े और हमारी विकट खाद्य समस्या का कोई स्थाई हल निकले, या फिर इसलिए कि यह एक आकर्षक नारा है जिसके द्वारा कुशल राजनीतिज्ञों को अपने मतदाताओं की कोमल भावनाओं को उभारने का अवसर मिलता है और इस प्रकार वह उनकी वोटों के हकदार बन जाते हैं ? यदि पहला उद्देश्य ही ठीक है तो स्पष्ट ही है कि 'भूमि सुधार' साध्य नहीं, वरन् वह 'साधन' है जिसके द्वारा हमारा लक्ष्य खाद्य समस्या को सुलझाना है।

भारत की खाद्य समस्या कितनी कठिन है, यह इसी बात से स्पष्ट है कि पिछले २२ वर्षों में हमारे देश को १००० करोड़ रुपए से अधिक का अन्न विदेशों से मंगाना पड़ा है। पहली पंचवर्षीय योजना को बनाते समस यह लक्ष्य सम्मुख रखा गया था कि योजना काल की समाप्ति पर देश अन्न के क्षेत्र में स्वावलम्बी हो जाय। हुआ यह कि सन् १९५४ व ५५ में प्रकृति और मौनसून की कृपा को हम स्वावलम्बी लक्ष्य की पूर्ति समझ बैठे और इतने खुश हुए कि दूसरी योजना बनाते समय कहने लगे कि अब के उत्पादन की दिशा में तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब कसर केवल इतनी है कि अन्न को छोड़कर दूसरी खेती की वस्तुओं की पैदावार पर जोर दिया जाय। द्वितीय योजना के पहले वर्ष में ही हमारा घमंड चूर हो गया और दूसरे वर्ष में तो ऐसी खाद्य समस्या उपस्थित हुई कि योजना निर्माताओं को खाद्य उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य १४ प्रतिशत से बढ़ाकर २४ प्रतिशत कर देना पड़ा। परन्तु जैसा हमारे भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री अजितप्रसाद जैन ने कहा है कि इस बढ़ाए हुए लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधन नहीं बढ़ाए गए। परिणाम यह हुआ कि यद्यपि हमारी पैदावार थोड़ी सी बढ़ी परन्तु उतनी नहीं जितनी हमारी जनसंख्या। इस पर जब जनता ने अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए अधिक अन्न का उपयोग आरम्भ कर दिया तो एक दम खाद्यान्नों के मूल्य २० प्रतिशत तक बढ़ गए।

प्रश्न उठता है कि हम कब तक अपनी रोटी की आवश्यकता के लिए विदेशों पर निर्भर रहेंगे ? और विदेशी मुद्रा के संकट काल में भी इस प्रकार अपने आर्थिक विकास की गति में अवरोध पैदा करते रहेंगे ?

कहा जाता है कि भूमि सुधार अधिक अन्न उत्पादन की दशा में ही अपेक्षित कदम है। जब तक देश के किसान यह अनुभव नहीं करेंगे कि जिस जमीन को जोतते हैं, वह अभी अपनी है, तथा अपनी महत्व की कमाई में कोई दूसरा बेकार आदमी शामिल नहीं होगा, तब तक उनमें अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक जोश पैदा न होगा। बात बहुत कुछ ठीक ही है और इसीलिए भूमि सुधार योजना के अन्तर्गत अधिकतर उपायों पर सभी अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ एकमत हैं। उदाहरणार्थ, वह सभी ज़मींदारी उन्मूलन के पक्ष में हैं, वह बिचौलियों के अधिकारों की समाप्ति भी चाहते हैं। वह जमीन के उपविभाज्य व जगह जगह बिखरा हुआ होने के खिलाफ हैं, वह लगान की उचित मात्रा निर्धारित कराना चाहते हैं तथा किसानों को अपनी जोत का मालिक हुआ देखना पसन्द करते हैं। इन सभी दिशाओं में बहुत अच्छी उन्नति हुई है और विभिन्न राज्य सरकारों ने आवश्यक कानून पास करके किसानों की

रक्खें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अर्ध-विकसित अर्थ-व्यवस्था में पूंजीगत साधनों का उपयुक्त निर्धारण भी एक विषम समस्या है। इसलिए हमें मध्य मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए और भारी उद्योगों पर इतना जोर नहीं देना चाहिए; बल्कि एक ओर हमें पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में, और दूसरी ओर औद्योगिक एवं ग्रामीण अंचलों में उचित संतुलन रखना चाहिए। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दशा को सुधारा है। परन्तु आज कल जिन भूमिसुधार कार्यक्रमोंके सम्बन्ध में मतभेद पैदा हो गया है वह हैं—(१) जमीन की अधिकतम जोत का निश्चय, और (२) सामूहिक खेती का प्रश्न।

जमीन की अधिकतम जोत के सम्बन्ध में दो बातें सम्मुख आती हैं—एक यह कि अलग अलग राज्यों की अपनी समस्याओं तथा विभिन्न परिवारों की आवश्यकताओं को देखते हुए यह सीमा किस प्रकार निश्चित की जाय, तथा इस सीमा निर्धारण के पश्चात् जिन लोगों के पास इससे अधिक जमीनें हैं, उनके टुकड़े कर दिए जायं, या फिर आगे के लिए और जमीन की खरीद पर रोक लगाई जाय ? दूसरा, यह कि न्यूनतम जोत की सीमा निर्धारित कर देने के पश्चात् उन लोगों का क्या किया जाय, जिनको जमीन नहीं मिल सकेगी ?

कुछ लोगों का कहना है कि भारत में जितने कृषि परिवार हैं, उनको यदि बराबर बराबर खेती की जमीन बांटी जाय तो एक परिवार के हिस्से में ७ एकड़ जमीन से अधिक नहीं आती। इसमें से कुछ जमीन इतनी खराब है कि जब तक एक परिवार के पास ५० या १०० एकड़ जमीन न हो उसका गुजारा ही नहीं चल सकता। फिर प्रति वर्ष जनसंख्या में जो ४० लाख की वृद्धि हो जाती है, उसका मुकाबला किस प्रकार किया जाय ? इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर दो सुझाव दिए जाते हैं —पहला यह कि जोत की न्यूनतम सीमा थोड़ी रखी जाय जिससे अधिक लोग बेकार न हों, और दूसरा यह कि छोटे छोटे खेतों को मिलाकर उनमें सामूहिक खेती का प्रयोग काम में लाया जाय।

इन दोनों ही सुझावों को लेकर आज देश में भारी कटुता का वातावरण पैदा हो गया है। स्वतन्त्र दल का निर्माण तो मुख्यतः सामूहिक खेती के प्रयोग का विरोध करने के लिए ही हुआ है। न्यूनतम जोत की मुखालफत उन लोगों द्वारा की जा रही है जो बड़े बड़े काश्तकार या जमींदार हैं। उनका कहना है कि कृषि की पैदावार की दृष्टि से जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना किसी भी प्रकार उचित नहीं। खेती के आधुनिक औजार केवल बड़े-बड़े फार्मों में ही काम आ सकते हैं। बड़ी बड़ी एक-चक जमीनों के जोतने बोने से ही खेती की पैदावार बढ़ सकती है, उसके टुकड़े कर उसे गरीब साधनहीन किसानों में बांटने से नहीं।

उपर्युक्त दोनों ही मतों में काफी जोर है। परन्तु यदि भाव और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति को अलग रख कर समस्या पर ठीक ढंग से विचार किया जाय, तो कोई कारण नहीं कि इन विरोधी मतों में ऐक्य स्थापित नहीं किया जा सके। उदाहरणार्थ, यदि यह कहा जाय कि जो फार्म या खेत, चाहे वह कितने ही बड़े क्यों न हों, बहुत अच्छी प्रकार संचालित हैं तथा उनमें औसत से अधिक अन्न की पैदावार होती है, उन पर जोत की अधिकतम सीमा का नियम लागू करके उनके टुकड़े न किए जायं, तो इसमें किसी को भी ऐतराज नहीं होगा। इसी प्रकार यह कहा जाय कि जो किसान स्वेच्छा से अपना भला समझकर सामूहिक खेती के पक्ष में हैं उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी जाय, तो इस बात में भी किसी को आपत्ति नहीं होगी। आज कांग्रेस तथा सरकार के अधिकतर नेता भी इसी बात को दोहरा रहे हैं, परन्तु दुर्भाग्य से आज हम भावों की लहर में इस प्रकार बहे जा रहे हैं कि तर्क को ताक पर रख कर हम केवल दलगत नीति से ही देश की समस्याओं पर विचार करते हैं, दलहीन भावना से नहीं।

प्रत्येक भूमि सुधार योजना पर हमें केवल एक ही दृष्टि से विचार करना चाहिए कि क्या अमुक योजना को अपना कर हम देश की भीषण अन्न समस्या को हल कर सकते हैं ? यदि इस दृष्टिकोण को अपनाया जाय तो कोई कारण नहीं कि खेती के क्षेत्र में हम राजनीतिक दलों के मतभेदों को दूर न कर सकें।

लेखकों से

'सम्पदा' में आर्थिक लेख ही छपते हैं, कविता, कहानियां या अन्य विषयों के नहीं। अतः लेखकों से प्रार्थना है कि वे केवल आर्थिक लेख ही हमारे पास भेजें जो कागज के एक ओर काफी हाशिया छोड़ कर स्पष्ट अक्षरों में लिख गए हों। अस्वीकृत लेख वापिस मंगाने के लिए १५ न. पै. के टिकट भेजें।

—सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

गणतन्त्र परिशिष्ट, जनवरी १९६०

हमें क्या करना है ?

भारतीय गणतंत्र के १० वर्ष समाप्त हो गए और ११ वां वर्ष प्रारम्भ हो रहा है। इस वर्ष हमें जो महत्व-पूर्ण आर्थिक समस्याएं हल करनी हैं, वे संक्षेप से निम्न-लिखित हैं—

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम वर्ष है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इस वर्ष हमें इस योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करने में प्रयत्नशील होना होगा। इन लक्ष्यों की पूर्ति देश में नवीन आशा और स्फूर्ति का संचार करेगी।

(२) लोहे के बड़े कारखाने, तेल की शोध, मशीन-निर्माण आदि में अधिक तेजी से काम करके तीसरी योजना के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार कर लेनी चाहिए।

(३) इस वर्ष की सफलता का मानदण्ड हमारा कृषि-उत्पादन होगा। बिना इसके हमारी समस्त योजनाएं अपूर्ण रहेंगी। चीजों की महंगाई रहते जनता में कोई उमंग पैदा नहीं होगी।

(४) इसी वर्ष हमें अपनी आगामी तृतीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप निर्धारण कर लेना है। यह योजना व्यावहारिक होनी चाहिए, जिसके नियोजन और आय के अनुमान अपनी शक्ति और क्षमता के अनुरूप हों। कल्पना के पंखों पर बैठकर यह योजना न बनानी चाहिए।

(५) इसी वर्ष हमें विदेशों से वे समझौते कर लेने हैं, जिनसे आगामी योजना की अवधि में विदेशी मुद्रा की समस्या मार्ग में आकर बाधा उत्पन्न न करे।

(६) चीन के आकस्मिक आक्रमण के कारण हमारा रक्षा-व्यय बहुत अधिक बढ़ सकता है। इसका भार भी सरकार को और फलतः करदाताओं को उठाना है।

(७) संयुक्त सहकारी कृषि आज संभव नहीं हो तो भी इस वर्ष सहकारी समितियों का जाल सारे देश में फैला देना है, परन्तु इन समितियों की स्थापना से पूर्व जनता में इनके अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा।

(८) १९५९ में अधिकांश राज्यों ने जोत की अधिक-तम सीमा निर्धारित की है। इस को व्यवहार में लाने के लिए हमें अनेक कठिनाइयों को इसी वर्ष हल करना है।

(९) १९५९ में शासन-सत्ता की विकेन्द्रीकरण की दिशा में कुछ राज्यों में पंचायतें बनाई गई हैं। इस वर्ष इन को व्यवस्थित सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता है।

(१०) जैसा कि बंगलौर कांग्रेस के प्रस्ताव में कहा गया है, योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकारी मशी-नरी तथा सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन इस वर्ष कर लेना होगा।

(११) देश की कोई विकास योजना केवल सरकार पर निर्भर रहकर पूरी नहीं हो सकती। जनता को स्वयं तत्परता से अपने कर्तव्य पालन में मनोयोग देना चाहिए। उद्योग में विध्वंसक या बाधक प्रवृत्तियों को, जात-पांति की झूठी भावनाओं को, फिजूल खर्ची और आडम्बरप्रियता को छोड़-कर देश की वास्तविक ठोस सेवा में जुट जाना चाहिए।

(१२) पुरुषों और स्त्रियों दोनों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि इस वर्ष देश की जनसंख्या कम से कम बढ़े।

(१३) सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को परस्पर सहयोगपूर्वक साक्षरता और शिक्षा-प्रसार, कुरीतियों के निवा-रण व मद्यपाननिषेध की ओर सतत प्रयत्न करने चाहिएं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बंगलौर कांग्रेस का आर्थिक कार्यक्रम

आवड़ी कांग्रेस ने समाजवादी समाज तथा नागपुर कांग्रेस ने संयुक्त सहकारिता के संदेश देश को दिये थे। बंगलौर अधिवेशन ने कोई नया कार्यक्रम प्रस्तुत न करके वर्तमान कार्यक्रमों पर ही अधिक बल देने का निश्चय किया है। कांग्रेस के प्रस्तुत आर्थिक प्रस्ताव का आशय निम्नलिखित है :—

प्रस्ताव में कृषक संघटन व्यवस्था के बारे में नागपुर अधिवेशन के निर्णयों की पुनः पुष्टि और भूमि सुधार एवं सहकारिता की दिशा में हुई प्रगति की सराहना की गयी। कहा गया है कि इस दिशा में कदम तेजी से बढ़ाया जाय, जिससे प्रत्येक गांव में एक कुशल सेवा सहकारी संस्था स्थापित हो जाय।

इस नाजुक समय में औद्योगिक प्रगति के लिए बड़े उद्योगों के महत्व पर प्रस्ताव में काफी प्रकाश डालकर कहा गया है—लोहा, इस्पात, मशीन निर्माण और बिजली उद्योग ही वह चीज़ें हैं जिनके बल पर अन्य उद्योग बढ़ सकते हैं।

प्रस्ताव में आगे कहा गया है—बड़े उद्योगों का विकास सम्पूर्ण तृतीय आयोजन-काल में जारी रखना होगा। इसके साथ ही लघु और ग्राम-उद्योगों का भी विकास चलाना होगा।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि आयोजन की चरितार्थता पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। भारतीय इतिहास के इस नाजुक काल में समय और उपलब्धियों का महत्व बहुत ही मार्मिक है। विलम्ब हो जाने से उत्तम नीतियां और कार्यक्रम भी अपना आकर्षण खो देते हैं। अनुशासन और ऐक्यपूर्वक कार्य सम्पादित होने में ही राष्ट्र का बल है। फूट और विघटनात्मक विचारों से दूर रहने की ही जरूरत है। राष्ट्र की प्रगति के इस समय में ऐसी बातें खास तौर से घातक ठहरेंगी। जब हमारे भविष्य के मार्ग में अभी अनेक प्रकार की बाधाएं आशंकित हो सकती हैं, ऐसे समय उत्पादन एवं राष्ट्रीय ऐक्य के मार्ग में कोई भी गलत कदम हानिकर होगा।

सहकारी कृषि के प्रश्न पर प्रस्ताव में कहा गया है—सेवा सहकारी समितियों का कार्यक्रम प्रत्येक गांव के लिए तो होना ही चाहिये, लेकिन जहां कृषक अनुरोध करें और स्थिति अनुकूल हो, वहां सहकारी कृषि की भी व्यवस्था की जानी चाहिये। इसे समझने में कोई गलतफहमी न होनी चाहिये कि सभी तरह के सहकारिता सम्बन्धी आंदोलन स्वेच्छा आंदोलन है।

आवश्यकता इस बात की भी है कि सामुदायिक विकास आंदोलन को भी पुनरुज्जीवित किया जाय।

प्रस्ताव में कहा गया है कि कृषि और औद्योगिक श्रमिकों के कल्याणकारी कार्यों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये। उत्पादन का स्तर ऊंचा उठाकर श्रमिकों को भी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। देश तालाबन्दी और हड़तालों के फलस्वरूप उत्पादन में रुकावट गंवारा नहीं कर सकता। आशा की जाती है कि देश की जनता विकास संबंधी महत्व के कार्यों में अपनी पूरी ताकत लगा देगी तथा राष्ट्र की लक्ष्य पूर्ति के लिए एकता और शक्ति के साथ कार्य करेगी।

कृषि का द्रुतगति से विकास भी बहुत आवश्यक है और यह कार्य निश्चित रूप से हो सकता है। लघु सिंचाई योजनाएं कृषि विकास में बड़ी सहायक हो सकती हैं।

आर्थिक विकास सम्बन्धी प्रस्ताव में कहा गया है कि आर्थिक क्षेत्रों में, चाहे वह क्षेत्र कृषि का हो या उद्योग का, स्वावलम्बी होना इस देश का मुख्य लक्ष्य है और भविष्य में उस लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त व्यापक नीतियों एवं कार्यक्रमों में यथोचित परिवर्तन करना आवश्यक है। आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही हमारा देश कल्याणकारी एवं समाजवादी ढंग की समाज रचना की दिशा में तेजी के साथ प्रगति कर सकता है। प्रगति का कदम इतनी तीव्रता के साथ उठाया जाय कि देश की बढ़ती हुई आबादी की बुनियादी जरूरतों का प्रबन्ध हो जाय तथा जनता के पास इतना अधिक धन इकट्ठा हो जाय कि वह अपने भावी विकास के लिए उस धन का विनियोग कर सके। इस दिशा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में काम शुरू कर दिया गया है और देश धीरे-धीरे अपने निर्देशित लक्ष्य के निकट पहुंच भी रहा है।

राष्ट्र की प्रतिरक्षा अन्ततः उसकी आर्थिक सुदृढ़ता पर निर्भर करती है। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वय के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ते रहना जरूरी है। इसके साथ-साथ हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना इतनी बड़ी होनी चाहिये कि देश को इस बात का इतमीनान हो जाय कि आर्थिक क्षेत्रों में स्वावलम्बी होने के स्तर पर वह पहुंच रहा है। कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है।

कृषि-उत्पादन

कृषि-उत्पादन में प्रगति लाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। इस दिशा में अभी तक जो प्रगति हो रही है, उसमें पूर्वापेक्षा और भी तीव्रता लायी जा सकती है, इसमें सन्देह का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस दिशा में जहां-जहां तीव्रता लायी गयी वहां-वहां आशातीत सफलता मिली है। इस दिशा में अभी तक उठाये गये कदमों से भी लोग सुपरिचित हैं। अब जरूरत इस बात की है कि कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने की भावना का प्रसार पूरे वेग के साथ गांवों में किया जाय। सिंचाई की सुविधाओं, खेती के लिए वैज्ञानिक औजार, अच्छी किस्म के बीज, भूमि संरक्षण, खादों के उपयोग आदि के लिए जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाय। इन सारे कार्यों को पूरा करने के लिए धन की अपेक्षा सामूहिक संघटित प्रयास की आवश्यकता है।

छोटी-छोटी कृषि योजनाओं के कार्यान्वय पर बहुत जोर दिया जाना चाहिए। छोटी-छोटी योजनाओं में धन कम लगता है और इनके कार्यान्वय से बड़ी जल्दी में फल की प्राप्ति होती है।

पूरे कृषक वर्ग में नयी प्रगति का जागरण पैदा करने पर भी में जोर देते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि देहाती अंचलों में काम करने वाले सरकारी अफसर किसानों से घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ायें और किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान करें। सरकारी अफसर किसानों की समस्याओं एवं कठिनाइयों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। इसके साथ ही उनको इस ढंग से काम करना चाहिए जिससे किसानों के वे विश्वास भाजन बन सकें। गांव में काम करने वाले सरकारी अहलकार यदि निष्ठापूर्वक काम करें तो उत्पादन में वृद्धि निश्चित रूप से होगी।

हमारे अनुभव बदल गये हैं!

एक समय था कि जब जनता ने उद्योग के राष्ट्रीयकरण के रूप में समाजवादी नारे को इसलिए स्वीकार किया था कि उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, परन्तु पिछले वर्षों का अनुभव सर्वथा विपरीत है। हम लोग अनुभव करते हैं कि निजी उद्योग के संचालक के पास हृदय होता है जबकि सरकार के पास केवल एक निर्जीव मशीनरी। लोगों ने अब यह भी अनुभव किया है कि सरकार द्वारा उद्योगों का प्रबन्ध इतनी कुशलता से नहीं होता, जितना निजी उद्योग के संचालकों द्वारा।

किसी समय यह भय किया जाता था कि निजी उद्योग का अर्थ 'मोनोपली' या एकाधिकार है, परन्तु अब हमारा अनुभव यह है कि सरकारी स्वामित्व निरंकुश एकाधिकार है। एक उद्योगपति अपने व्यापार को अपने ग्राहकों द्वारा कमाये गये लाभ से बढ़ाता था, किन्तु सरकार अपने कारोबार को करदाता के धन से तथा मुद्रा प्रसार से बढ़ाती है।

राष्ट्रीयकरण उन दिनों में एक तर्कसम्मत नारा था, जब मजदूर संगठित नहीं थे और उनकी शोषणकर्त्ता से रक्षा करनी आवश्यक थी। आज मजदूर न केवल सुसंगठित है, बल्कि अनेक कानूनों के द्वारा संरक्षित भी है और यही कारण है कि आज भारत संगठित मजदूर की आमदनी असंगठित मजदूर से ४, ५ गुना है।

—आचार्य कृपलानी

सम्पदा के विशेषांक आपके पुस्तकालय को समृद्ध करेंगे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में अणुशक्ति का विकास

अणुशक्ति-संस्थान

ट्राम्बे (बम्बई के पास) का अणुशक्ति-संस्थान भारत का अणुशक्ति अनुसंधान और विकास केन्द्र है। दो वर्ष पहले इसका उद्घाटन हुआ था। यह संस्थान २,४०० एकड़ जमीन पर बना है और यहीं पर भारतीय अणुशक्ति आयोग के कार्यक्रमों के अनुसार नए-नए अनुसंधान होते हैं, जिन्हें बाद में उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस समय संस्थान में ८०० भारतीय वैज्ञानिक और शिल्पिक काम कर रहे हैं। आणविक अनुसंधान के लिए जिन यंत्रों और उपकरणों की आवश्यकता होती है, वे सब यहीं पर बनाए जा रहे हैं, जिससे देश विज्ञान के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही बहुत सी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

ट्राम्बे में भारत की पहली अणुभट्टी अप्सरा, रेडियो-रसायन प्रयोगशाला और थोरियम साफ करने का यंत्र है। इसके अलावा कनाडा-भारतीय अणुभट्टी-ज़रलीना, यूरेनियम धातु यंत्र और फ्यूएल-एलिमेंट बनाने के यंत्र शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएंगे।

अप्सरा

भारत की पहली अणुभट्टी-अप्सरा अगस्त १९५६ में चालू हो गयी थी। रूस के बाद एशिया में चालू होने वाली यह पहली भट्टी है। ईंधन के काम आने वाले फ्यूएल एलिमेंटों के अलावा इस भट्टी को पूरा भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ही बनाया है। इसका नकशा भी उन्होंने ही तैयार किया और आवश्यक मशीनें और उपकरण भारतीय कारखानों में बनाए गए। भारत फ्यूएल एलिमेंट (अलुमिनियम के डिब्बों में बन्द यूरेनियम और अलुमिनियम की मिश्र धातु की उन्नतोदर प्लेट) इंग्लैंड के अणुशक्ति विभाग ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दिए। नकशा तैयार होने के एक साल बाद ही यह अणुभट्टी बनकर तैयार हो गयी थी।

इस भट्टी पर ३५ लाख रु० लागत आयी। यहां पर तैयार होने वाले आइसोटोप कृषि, चिकित्सा और उद्योगों में काम आ रहे हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के अनुसंधान कार्यों में भी इनका उपयोग हो रहा है। यहां पर अणुभट्टी-शिल्प भी सिखाया जाता है। भौतिकी, इंजीनियरी और जीवविज्ञान के उन अनुसंधानों की भी सुविधा है, जिनमें न्यूट्रोनों की तेज धारा की आवश्यकता होती है।

ज़रलीना

इस समय दूसरी अणुभट्टी-ज़रलीना बनायी जा रही यह भट्टी नयी अणुभट्टियों की प्रणालियों के अध्ययन और नकशे तैयार करने में सहायक होगी।

रेडियो-रसायन प्रयोगशाला में रसायनज्ञों को अत्यन्त रेडियो सक्रिय पदार्थों के प्रयोग की ट्रेनिंग दी जाती है। अणुशक्ति संस्था की सब शाखाओं में अनुसंधान के लिए रेडियो सक्रिय पदार्थों के प्रयोग में भी प्रयोगशाला मदद करती है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक डा० वेल्स इस प्रयोगशाला के संगठन और संचालन में सहायता कर रहे हैं।

थोरियम यंत्र

थोरियम यंत्र चार साल पहले चालू हुआ था। इस समय इसकी उत्पादन क्षमता ६ गुनी बढ़ गयी है। इस यंत्र से अणुशक्ति के उत्पादन के लिए आवश्यक थोरियम और यूरेनियम को शुद्ध करके, अणुभट्टी में इस्तेमाल के योग्य बनाया जाता है। इस यंत्र को भी पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ही बनाया है और यह दुनिया के सबसे बड़े थोरियम नाइट्रेट यंत्रों में है। एशिया भर में गैस की लालटेनों के मैंटल बनाने के लिए जितने थोरियम नाइट्रेट की आवश्यकता पड़ती है, वह प्रायः सबका सब यहीं से भेजा जाता है। इसके अलावा अमरीका और यूरोप के बाजारों को भी थोरियम नाइट्रेट भेजा जाता है। भविष्य में देश की आवश्यकताओं के लिए कुछ थोरियम नाइट्रेट सुरक्षित रखा जाता है।

यूरेनियम-धातु-यंत्र

अणुशक्ति में आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त यूरेनियम मिलना सबसे जरूरी है। इसलिए यूरेनियम को साफ करके अणुभट्टियों और अनुसंधान-कार्यों में इस्तेमाल लायक बनाने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए ट्राम्बे में यंत्र लगाया गया। इस यंत्र के लगाए जाने से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भविष्य में ऐसे यंत्रों का नक्शा तैयार करने और इन्हें बनाने का काफी अनुभव हो गया है।

अमरीका की सहायता

अमरीका ने कोलम्बो योजना के अंतर्गत सदस्य देशों के वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण पर १६५८-५६ में २ लाख ५० हजार डालर खर्च करने की योजना बनायी थी।

नई भट्ठी

कनाडा इस समय भारत में ७॥ करोड़ रु० की लागत की एक अणुभट्ठी लगा रहा है। यह वैज्ञानिकों और शिल्पिक सहयोग की बहुत बड़ी मिसाल है। यह भट्ठी चालू हो जाने पर संसार की आइसोटोप तैयार करने वाली सर्वोत्तम भट्ठियों में होगी। भट्ठी अगले साल चालू हो जाएगी। इस भट्ठी में हर प्रकार के आइसोटोप तैयार किए जा सकेंगे। यह भट्ठी कनाडा की चाक-रिवर, आनटेरिओ में बनी एन० आर० एक्स० अणुभट्ठी के नमूने पर बनायी जा रही है। पर इसमें कुछ परिवर्तन और सुधार भी किए गए हैं। इस अणुभट्ठी पर कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा ७५ लाख डालर खर्च करेगा। अणुभट्ठी के लिए लगभग २० टन भारी पानी (हैवी वाटर) की जरूरत पड़ेगी, जो भारत ने अमरीका के अणुशक्ति आयोग से खरीद लिया है।

इस अणुभट्ठी का बनना शुरू होने से अब तक भारत के अणुशक्ति विभाग के इंजीनियर और शिल्पिक चाक-रिवर आनटेरिओ की ४० हजार किलोवाट की अणुभट्ठी में ट्रेनिंग पा चुके हैं।

इस अणुभट्ठी के बन जाने पर उच्च अनुसंधान की सुविधा बहुत बढ़ जाएगी। यह भट्ठी अणुशक्ति से सम्बन्धित भौतिक, रासायनिक, जीवविज्ञान और धातुकर्म के मौलिक अनुसंधानों के लिए बनायी जा रही है। इस भट्ठी में चिकित्सा, खेती और उद्योग के उपयोग के लिए तथा रेडियो सक्रियता की विधि से रासायनिक, जीव-विज्ञान और चिकित्सा सम्बन्धी अनुसंधान के लिए आइसोटोप तैयार किए जाएंगे।

यह आपका अपना ही कर्तव्य है

बचे हुए रुपये को नियमित रूप से जमा करने की आदत बनाइये और आप देखेंगे कि जल्दी ही एक मोटी रकम आपके पास जमा हो गयी है। और तभी आप अपने भविष्य की योजना पूरी आस्था के साथ बना सकेंगे।

कार्यकारी कोष ... १६८ करोड़ रुपये से अधिक
जमा कोष ... १३५ करोड़ रुपये से अधिक

दि पंजाब नैशनल बैंक लि०
(स्थापित १८९५)
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली

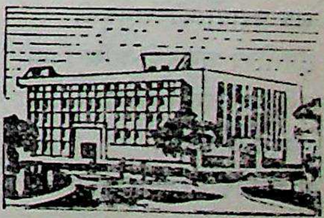

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गिरता हुआ रुपया

श्री जी. एस. पथिक

रुपए की स्थिति के संबंध में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ लोग विश्वास रखते हैं कि वह मजबूत बना रहेगा, कुछ चिंता प्रकट करते हैं और दूसरे अत्यंत निराशावादी बन गए हैं।

कारण ? हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय ऋण के चार-पंचमांश भाग की सम्पदा का ब्याज चुकता है, १९५३-५५ में राष्ट्रीय आय में सरकारी ऋण का औसत ४६ प्रतिशत था। देश की आर्थिक प्रगति मजबूत हुयी है, किन्तु उसके साथ ही जन संख्या में भी वृद्धि हुई है। और वस्तुओं के दाम तेजी से चढ़े हैं। किसी देश की मुद्रा की शक्ति उत्पादन की स्थिति और दामों के संबंध पर आधारित है। पश्चिम जर्मनी अमेरिका तथा भारत के तत्सम्बन्धी आंकड़े इस अवस्था का दिग्दर्शन करते हैं।

यहां पर प्रकट करना होगा कि गणना के अंकों की अपेक्षा वस्तुओं के वास्तविक दाम बहुत ऊंचे रहे। ये दाम मजदूरों के केन्द्रों में तथा अनाज के कमी वाले क्षेत्रों में सब से ऊंचे रहे। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार रिजर्व की जमा जारी किए हुए करंसी नोटों की देनदारी में १६.३ प्रतिशत है। इस में एक रुपए का नोट शामिल नहीं है। अक्तूबर १९५९ में विदेशी मुद्राएं कोष में ३७.६६ करोड़ रुपए की जमा थीं।

हमारी अपेक्षा ग्रेट ब्रिटेन ३०००० लाख डालर सोना और विनिमय की मुद्राएं रखता है। अमेरिका में रक्षित कोष में सितम्बर १९५९ में १९५८ करोड़ डालरों के मूल्य का सोना जमा है। न्यूयार्क में रुपए की विनिमय दर प्रति डालर ५.८० रुपए है, जबकि असली मूल्य ४.७५ रु० है। स्टर्लिंग में रुपए का विनिमय मूल्य १६.२५ रुपए प्रति पौंड है, जबकि असली मूल्य १३.३० रुपए है। इस अवस्था में सरकार के लिए यह आवश्यक है कि रिजर्व बैंक के रक्षित क्षेत्र में सोने की जमा में वृद्धि करे, स्थानीय खरीद करे या उधार ले। सोने की प्राप्ति के लिए विस्तृत क्षेत्र है। ब्याज की दरों में वृद्धि की जाए, जिससे विदेशी पूंजी की आमद बढ़ने का आकर्षण पैदा हो। इसके साथ ही मुद्रा-स्फीति के साधन दबाए जाएं, वस्तुओं की तेजी कम की जाए। लागत व्यय में कमी की जाए और उत्पादन की वृद्धि में तेजी का कदम बढ़ाया जाए।

	आधार वर्ष	वर्तमान अनुसूची
पश्चिमी जर्मनी		
औद्योगिक उत्पादन की अनुसूची	१९५३	१५२ (जुलाई १९५९)
थोक भाव अनुसूची	१९५३	१०५ (जुलाई १९५९)
उपभोक्ता-अनुसूची	१९५३	१११ (जुलाई १९५९)
अमेरिका		
औद्योगिक उत्पादन की अनुसूची	१९५३	११४ (जुलाई १९५३)
थोक भाव अनुसूची	१९५३	१०९ (जुलाई १९५३)
उपभोक्ता भाव अनुसूची	१९५३	१०९ (जुलाई १९५३)
भारत		
थोक भाव अनुसूची (अनाज)	१९५२-५३	१२०.९ (नवंबर ४, १९५९)
सब पदार्थों की अनुसूची	१९५२-५३	११७.९ (नवंबर ४, १९५९)
उपभोक्ता अनुसूची-अखिल भारतीय (मजदूर वर्ग)	१९४९	१२५ (सितंबर १९५९)
कृषि-उत्पादन अनुसूची (अनाज)	१९४९-५०	१२८.२ (१९५८-५९)
समस्त उत्पादन	१९४९-५०	१३१.९ (१९५८-५९)
औद्योगिक उत्पादन अनुसूची	१९५१	१४६.१ (जनवरी-जून १९५९)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की खाद्य-समस्या

श्री सदाशिव कान्होजी पाटिल

हमारे सामने देश की विशाल तथा निरन्तर बढ़ती हुई आबादी के लिए गल्ला पैदा करने का कठिन काम है। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना १९५१-५२ में शुरू हुई थी और उसमें पैदावार बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया था। उस समय देश की आबादी अनुमानतः ३६ करोड़ थी और इसके लिए ६ करोड़ ५५ लाख टन गल्ला पैदा करने का लक्ष्य रखा गया, जो आसानी से पूरा हो गया था। उस अवधि में हर साल २.८ प्रतिशत उपज बढ़ी अर्थात्, जिस अनुपात से आबादी बढ़ी, उससे अधिक अनुपात से उपज बढ़ी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना १९५५-५६ में शुरु हुई और उसमें १९६०-६१ तक ८ करोड़ ५ लाख टन गल्ला पैदा करने का लक्ष्य रखा गया। पहले तीन वर्षों में पैदावार में ३.९ प्रतिशत सालाना वृद्धि हुई। पिछले साल गल्ले तथा नकद फसलों की उपज अन्य वर्षों से काफी अधिक हुई; परन्तु लोगों की खरीदने की क्षमता तथा देशमें आबादी बढ़ने से गल्ले और नकद फसलों का भाव गिरा नहीं।

अब हमारी आबादी हर साल १.९ प्रतिशत बढ़ती जा रही है। यह हमारे लिए काफी चिन्ता का विषय है। आबादी की वृद्धि को रोकने के लिए हमने परिवार आयोजन का कार्यक्रम चलाया है और आगे हम इसे और भी तेजी से चलाएंगे। पता चला है कि दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश है, जिसने यह कार्यक्रम सरकारी तौर पर बनाया है, परन्तु इस कार्यक्रम से हमें काफी समय के बाद लाभ पहुँचेगा। इस समय तो हमारा मुख्य काम पैदावार बढ़ाना है, ताकि देश की पूरी आबादी को पर्याप्त भोजन मिल सके।

एक बात और है और वह यह कि दूसरी योजना के पहले तीन वर्षों में अनेक विकास कार्यों के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय १०.४ प्रतिशत बढ़ी है। इससे प्रति व्यक्ति आय में ६.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से प्रायः कम आय वालों को लाभ पहुँचा है अर्थात् उनकी आमदनी बढ़ी है। फलतः अब वे अधिक अनाज खरीदने लगे हैं। इसीलिए देशवासियों के हित तथा गणराज्य के स्थायित्व के लिये अगले ८-१० वर्षों में तेजी से पैदावार बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है। अतः तीसरी योजना में कृषि उत्पादन, और विशेषकर अनाज के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

तीसरी योजना में खाद्य

तीसरी योजना में अनुमान किया जाता है कि देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए हमें १९६५-६६ के अन्त तक कम से कम १०-११ करोड़ टन गल्ले की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमें खाने की वस्तुओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन करना पड़ेगा। दूध, फल आदि का भोजन बढ़ाना होगा, इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम में गोपालन, मुर्गी-पालन और अधिक फल तथा सब्जी पैदा करने का काम भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे पौष्टिक खाना तो मिलेगा ही, साथ ही अनाज की मांग भी कम होगी।

तीसरी योजना के अन्त तक ११ करोड़ टन गल्ला सालाना पैदा करने के लिए जरूरी है कि अगले अनेक वर्षों तक हर साल लगभग ८ प्रतिशत उपज बढ़ायी जाए। पिछली दो योजनाओं में उपज इतनी अधिक नहीं बढ़ी थी। इसलिए अब हमें ८ प्रतिशत पैदावार बढ़ाने के लिए और भी अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी।

कठिनाइयां

भारत में पैदावार बढ़ाने में अनेक कठिनाइयां हैं, जैसे-

१. पानी जमा करने और भू-रक्षण की व्यवस्था की कमी;

२. अधिक मवेशी और कम चारा;

३. खेती करने के पुराने औजार और तरीके;

४. फसल में अनेक प्रकार के कीड़ों का लगना;

५. छोटे-छोटे दूर-दूर खेत;

112998

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सोवियत संघ और भारत का नया आर्थिक समझौता

श्री टी० शोखोरोव

सोवियत सरकार ने भारत को उसकी तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए १ अरब ५० करोड़ रूबल (१८० करोड़ रुपये) का ऋण देने को कहा है। भारत सरकार के प्रतिनिधियों तथा सोवियत संघ की वैदेशिक आर्थिक सम्पर्क समिति के बीच हाल में ही सोवियत संघ व भारत के बीच एक नये व्यापार-समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

इस समझौता वार्ता की सफल समाप्ति पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्री बी० के० नेहरू ने कहा है कि समस्त विचार-विनिमय इतनी अच्छी तरह हुआ कि किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मतभेद की गुंजाइश नहीं रही। यह समझौता निस्संदेह सोवियत संघ और भारत के आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने में सहायक होगा।

समझौते में भारत को १८० करोड़ रुपये का ऋण देने की व्यवस्था है, जिसका एक हिस्सा अनेक औद्योगिक कृषि तथा अन्य योजनाओं के लिए, जो कि भारत सरकार तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में आरम्भ करेगी, दी जाने वाली सोवियत प्राविधिक सहायता के एवज में भुगतान करने के काम आएगा। सोवियत ऋण भारत को अविलम्ब ही अधिक आवश्यक योजनाओं के निर्माण का काम आरम्भ करने में सहायता देगा, जिससे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के अनुसार और अधिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में सहायता मिलेगी।

ऋण की असाधारण अनुकूल शर्तें

"यह ऋण २.५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर दिया गया है। यह ब्याज की दर उस न्यूनतम दर से भी कम है, जो भारत अन्य देशों से प्राप्त ऋणों पर दे रहा है।

'यह पहला ऋण है जो भारत की अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना के खर्चे के लिए प्राप्त हुआ है और यह वास्तव में महत्वपूर्ण श्रीगणेश है।'

किसी भी पूंजीवादी देश ने कभी भी सहायता के लिए २.५ प्रतिशत का ऋण नहीं लिया। वे अक्सर ५-६ प्रतिशत या इससे अधिक की मांग करते हैं। सोवियत संघ के इस ऋण की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे भारत को विदेशी मुद्रा की भारी कठिनाइयों पर जिनका कि वह इस समय अनुभव कर रहा है, विजय पाने में सहायता मिलेगी।

भारत को इस ऋण के भुगतान के लिए या सोवियत संघ द्वारा भिलाई लोहा और इस्पात कारखाने, औषधि उद्योग के विकास, तेल साफ करने के कारखाने के निर्माण,

---

६. शिकमियों को बेदखल होने का डर;
७. ऋण की अपर्याप्त व्यवस्था और अधिक ब्याज;
८. किसानों में उत्साह की कमी; और-
९. समन्वित कार्यक्रम का अभाव।

योजना में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनेक विकासकार्य किये जा रहे हैं। भारत में पानी बहुतायत में है। यदि इसका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग किया जाय तो इससे लाखों को लाभ पहुंच सकता है।

पैदावार कैसे बढ़े ?

देश में पैदावार बढ़ाने का केवल यही रास्ता है कि इसके लिए सभी लोग व्यवस्थित ढंग से प्रयत्न करें। जिस देश में अनाज की कमी हो, उसे पैदावार बढ़ाने का तो भरसक प्रयत्न करना ही चाहिए, साथ ही जिस क्षेत्र में अधिक अनाज होता हो, उसे भी कम उपज वाले क्षेत्र को मदद देनी चाहिए। इसे ध्यान में रखकर मैं खाद्य संगठन के महानिर्देशक ने भुखमरी दूर करने का आन्दोलन चलाने के बारे में जो प्रस्ताव रखा है, उसका स्वागत करता हूँ। मेरे विचार से यह हरेक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ ही इससे दुनिया के लोगों में परस्पर सहयोग और सद्भावना पैदा करने का भी अच्छा अवसर मिलेगा। अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना करने का प्रयत्न तब तक नहीं हो सकता, जब तक दुनिया के एक बड़े भाग में भुखमरी हो।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रूस के राष्ट्रपति मार्शल वोरोशिलोव

चश्मों के शीशे के कारखाने और अन्य संस्थानों जैसी योजनाओं के लिए पहले दिये गये ऋणों के भुगतान के लिए अपने पौंड-पावने का उपयोग नहीं करना होगा।

लेकिन इस ऋण से भारत को यही एकमात्र लाभ नहीं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग भारत के राष्ट्रीय उद्योग के विकास के लिए किया जाएगा। यह स्मरणीय है कि अनेक विदेशी हित भारत के उद्योगीकरण का विरोध कर रहे हैं। वे उसके कृषि के विकास की वकालत कर रहे हैं— इस आशा से कि इस प्रकार भारत का दर्जा उन्हें कच्चा माल देने वाले देश का बना रहेगा।

सोवियत जनता को यह देखकर खुशी होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है और उसे यह जानकर भी प्रसन्नता होती है कि रूस ने इस प्रगति में योग दिया है। यह कहने की जरूरत ही नहीं है कि वह भारत को दी गई सहायता को दान नहीं समझता है। स्वयं सोवियत लोगों को अपने महान् सप्तवर्षीय आर्थिक कार्यक्रम के लिए बड़ी-बड़ी रकमों की जरूरत है। उन्हें अपने पिछले आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश को एक प्रमुख औद्योगिक देश में बदलने के लिए जिसकी सफलताओं के कारण समस्त विश्व अब उनकी सराहना करता है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा था।

सोवियत सरकार के मुखिया निकिता ख्रुश्चेव ने बार-बार कहा है कि समस्त मानव-समाज के साथ एकता स्थापित करने के मानवीय दृष्टिकोण से अल्पविकसित देशों को आर्थिक सहायता देना आवश्यक है। इस विचार से प्रेरित होकर ही सोवियत सरकार ने भारत को नया ऋण दिया है।

हमारी कामना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपनी जनता की भलाई के लिए उन्नत हो तथा सोवियत और भारत का आर्थिक सहयोग अधिक घनिष्ट होता जाए एवं वह भारत की स्वतन्त्रता को मजबूत बनाने में सहायता करे।

● ●

सुभाषित रत्न माला

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

७ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था। कई वर्ष से पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी! अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा में प्रकाशित हो रहा है—

- वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी सुविधापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं।
- श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ।
- पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियाँ, जिनका उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सकें।
- आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य।
- उपहार और पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयुक्त।

मूल्य एक प्रति १.०० रु०। 'सम्पदा' के ग्राहकों से ००.७५ न० पै० प्राप्त होने पर 'बुक पोस्ट अन्डर-पोस्टल सर्टिफिकेट' द्वारा भेजी जाएगी। स्कूलों-कालेजों और पुस्तकालयों को १० प्रतियाँ ७.०० रु० में।

प्रकाशक :

अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्षरण या कटाव कैसे रोका जाय ?

डा० जे० के० वसु

वर्षों से भूमि का कटाव या क्षरण तेजी से होता जा रहा है। इससे बहुत सी जमीन खेती के योग्य नहीं रही। बहुत से क्षेत्रों में इससे पैदावार में बहुत कमी हो गई है।

भूमि के कटाव की समस्या की गम्भीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बम्बई और दक्षिण के कम उपजाऊ क्षेत्रों की लगभग तिहाई जमीन क्षरण के कारण बेकार हो गई है। नदी के किनारे की लगभग ७० लाख एकड़ जमीन में, जो एक समय बहुत उपजाऊ थी, कटाव के कारण, गहरे खार और बेहड़ बन गए हैं, जिससे यह खेती के लायक नहीं रही। यही नहीं, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश में ऐसे इलाके खतरनाक डाकुओं के गढ़ बन गए हैं।

उड़ीसा में झूम की खेती के कारण लगभग १,२०० वर्गमील जमीन बेकार हो गई है। पंजाब में, हिमालय की तराई में पहाड़ी नालों से लाई रेत के कारण बहुत सी उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई है। यह भी भय है कि ४०-५० साल में, सिंचाई के लिए बनाये गये बड़े तालाब और जलाशय मिट्टी भर जाने से बेकार हो जाएंगे। नदियों और झीलों के उथले हो जाने से बाढ़ का खतरा और भी बढ़ जाता है। देश में बाढ़ों से हर साल आदमियों और ढोरों की मृत्यु के अलावा लगभग ५० करोड़ रु० का नुकसान होता है। इधर राजस्थान का ५ करोड़ एकड़ का रेगिस्तान आसपास की उपजाऊ जमीन को हड़पता हुआ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।

अनुमान है कि विभिन्न क्षेत्रों में लगभग २० करोड़ एकड़ जमीन की रक्षा के लिए तुरन्त कार्रवाई की जरूरत है। इसमें से लगभग १० करोड़ एकड़ जमीन (यह सारी कृषि भूमि का लगभग तिहाई भाग है) पर खेती होती है और ५ करोड़ एकड़ परती है। ५ करोड़ एकड़ जमीन राजस्थान के रेगिस्तान की है जहां तेज हवा के कारण मिट्टी

उद्योग-व्यापार पत्रिका

देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण में कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई कर सकते हैं? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या दशा है? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही है? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य जानने चाहिए, और इन सबकी जानकारी पाने का श्रेष्ठ साधन है—उद्योग व्यापार पत्रिका। इसलिये आप ६ रु० भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक बन जाइये। नमूना पत्र लिखकर मंगाइये।

एजेन्टों को भरपूर कमीशन।

पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय,

भारत सरकार, नई दिल्ली।

पञ्च पुरस्कार

दिव्य-ज्योति सं० मासिक का अपूर्व आयोजन

संस्कृत साहित्य के प्रसार और प्रचार एवं इसके नाटकीय, उपन्यासीय कथा कहानी क्षेत्र में नव जागरण के हेतु अ० भा० संस्कृत कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।

प्रतियोगिताओं को तीन पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार १५०) रु०, द्वितीय पुरस्कार १००) रु०, तृतीय पुरस्कार ५०) रु०।

आधुनिक पद्धति से लिखी गई संस्कृत कहानी एक हजार शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिये। पुरस्कृत तथा उत्तम कहानियां दिव्य-ज्योति में प्रकाशित होंगी। भेजने की अन्तिम तिथि २९ फरवरी १९६० है।

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये दिव्य-ज्योति का ग्राहक बनना अनिवार्य है।

व्यवस्थापक, दिव्य-ज्योति कार्यालय,

आनन्दलाज, जाखू शिमला (पंजाब)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उड़ती रहती है।

भूमि संरक्षण के कार्यक्रम

स्वाधीनता से पहले देश में भूमि-संरक्षण का कोई अखिल भारतीय कार्यक्रम नहीं था। दिसम्बर १९५३ में योजना आयोग की सिफारिश पर 'केन्द्रीय भूमि संरक्षण मंडल' की स्थापना की गई है। यह मंडल भूमि की रक्षा के सम्बन्ध में अनुसन्धान कराता है तथा भूमि-रक्षण का काम सिखाने की व्यवस्था करता है। राज्यों और नदी-घाटी योजनाओं में भूमि की रक्षा का जो काम हो रहा है, उसमें मंडल आर्थिक और शिल्पिक सहायता देता है। मंडल ने देश में भूमि संरक्षण सम्बन्धी पड़ताल, और उसके उपाय सिखाने और दिखाने का एक सम्मिलित कार्यक्रम बनाया है।

मई १९५८ से भाकड़ा, हीराकुड, चम्बल, मच्छकुंड, कोसी और दामोदर घाटी क्षेत्रों में लगभग ५० लाख एकड़ की पड़ताल की जा चुकी है। विभिन्न क्षेत्रों की भूमि रक्षण की समस्याओं की जांच करने के लिए मंडल ने ९ क्षेत्रीय अनुसंधान और प्रदर्शन केन्द्र खोले हैं। ये केन्द्र देहरादून, (हिमालय क्षेत्र) चंडीगढ़ (बाहरी शिवालिक), नेपाल में छतरा (जहां से नदियों का बहाव भारत की ओर होता है), कोटा (राजस्थान के खार), बोरसद (गुजरात की कोटर भूमि), आगरा (यमुना के बेहड़) बेलारी (काली मिट्टी), ऊटकमंड (पहाड़ी) और जोधपुर (सूखी जमीन) में है। रेत का उड़ना रोकने के लिए राजस्थान में हरियाली लगाने या चरागाह बनाने का काम शुरू किया गया है। लाल मिट्टी के बारे में अनुसन्धान के लिए दो और केन्द्र खोले जाएंगे।

अन्य कार्य-क्रम

दूसरी योजना में २० लाख एकड़ कृषि भूमि और १० लाख एकड़ अन्य भूमि को क्षरण से बचाने की योजना है। इस पर लगभग २० करोड़ ५० लाख रु० खर्च आएगा। भूमि की रक्षा का मतलब मिट्टी को बहने या उड़ने से बचाना है। मामूली मेड़बन्दी, या ऊंची-नीची जमीन पर कंटूरबन्दी, पहाड़ी जमीन पर सीढ़ीनुमा खेत बनाने और कटी हुई जमीन पर पेड़-पौधे लगाने से कृषि की रक्षा होती है।

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र० की

विज्ञप्ति संख्या ४।२२८० : २७।३३।५३, दिनांक १५ द्वारा

पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

		रु०	आ०
वेद सार	प्रो० विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग			
सच्चा सन्त		०	३
सिद्ध साधक कृष्ण		०	३
जीते जी ही मोक्ष		०	३
आदर्श कर्मयोग		०	३
विश्व-शान्ति के पथ पर		०	१
भारतीय संस्कृति	प्रो० चारुदेव	०	३
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१३
हमारा समाज		६	०
व्यावहारिक ज्ञान		२	१२
फलाहार		१	४
रस-धारा		०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां		१	०
नये युग की कहानियां		१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	०
विशाल भारत का इतिहास	प्रो० वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार

साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विश्व कृषि मेले में जर्मनी का मंडप

श्री उलरिस फोएस्टर

कृषि मेले में जर्मन जनवादी जनतंत्र ने २८००० वर्ग फीट स्थान लिया है। इस मण्डप से दर्शक उस मौलिक ऐतिहासिक कायापलट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो जर्मन जनवादी जनतंत्र में कृषि के क्षेत्र में हुआ है और जिसकी बदौलत पैदावार बढ़ गयी है और देश की पूरी जनता का जीवन-स्तर उन्नत हो गया है। कृषि में सभी कार्यों के लिए मशीनों का होना और पैदावार के उच्च आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि यहां की कृषि पूर्णतया यंत्रीकृत और अति उत्पादक है। मण्डप के अन्दर आकर्षण का केन्द्र त्रिनविलेरशांगन की कृषि उत्पादन सहकारिता रोट्सबैनर (लाल झण्डा) का माडल है। इस माडल में एक भूतपूर्व सामन्ती गांव और उसके निवासियों का विकास दिखाया गया है। इस ग्राम के निवासी आज गांव की सम्पदा के उत्पादक ही नहीं हैं, बल्कि अपने श्रम के फलों का स्वयं उपभोग करते हैं तथा स्वयं भूमि के स्वामी हैं।

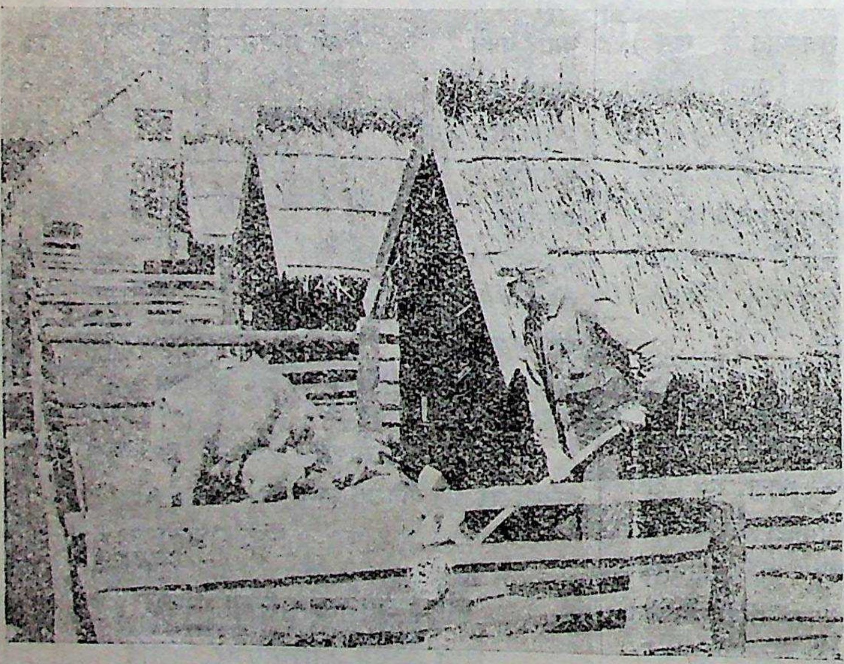

जर्मनी के आर्थिक विकास का एक दृश्य

कठिन परिश्रम करके उन्होंने शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर ली। त्रिनविलेरशांगन की कृषि उत्पादन सहकारिता जो १००० हा (२४७० एकड़) कृषि भूमि पर काम करती है, इस बात का उदाहरण बन गई है कि किस प्रकार सहकारी खेती से ही खेतिहर तथा किसान अभाव और परवशता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और नये जीवन का शुभारम्भ कर सकते हैं। प्रदर्शनी के एक अन्य भाग में बीमारों और गर्भवती नारियों की देखभाल की निःशुल्क व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा और अन्य अनेक नये कदमों के बारे में जो जर्मन जनवादी जनतंत्र के नये स्वरूप का परिचय देते हैं, परिचय मिलता है। नियमित प्रबन्ध तथा मण्डप का एक आकर्षण "कांच की गाय" है। यह दुनिया में अपनी किस्म की सर्वप्रथम चीज़ है और विज्ञान एवं प्रविधि का एक आश्चर्यजनक करिश्मा है। मण्डप के बाहर कृषि की मशीनें दिखायी गयी हैं। यहां दिखायी जाने वाली वस्तुओं में औजार वाहक आर० एस० ०६ और मछली के कांटे की जगह से दूसरी जगह ले जायी जाने वाली चक्की जैसी मशहूर चीज़ें हैं। प्रदर्शनी में विविध प्रकार के खेती के, बागबानी के और फूलों के बीज भी हैं जो निश्चय ही अनेक दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

'सम्पदा' में विज्ञापन देकर लाभ उठायें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गणतंत्र का दसवां वर्ष: आर्थिक प्रवृत्तियाँ

१. १६५६ के समाप्त होते-होते अणु-शक्ति केन्द्र के प्रमुख अधिकारी श्री एच० भाभा ने यह समाचार सुनाकर सचमुच भारत को विस्मित कर दिया है कि भारत बिना किसी बाहरी शक्ति के अणुबम बनाने की क्षमता रखता है।

२. चित्तरंजन इन्जन के कारखाने ने ६५० इन्जन बना लिये हैं और अब इन्जिन के ५३३० पुर्जों में से सिर्फ १४ पुर्जे बाहर से आते हैं।

३. औद्योगिक उत्पादन की सूचना के अनुसार उत्पादन में इस वर्ष ७ प्र० श० की वृद्धि हुई जबकि १६५८ में १.५ प्र० श० की तथा १६५७ में ३.५ प्र० श० की वृद्धि हुई थी।

४. दसवें गणतन्त्र वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रपति ने रूरकेला और भिलाई की धमन भट्टियों का उद्घाटन किया था, जबकि वर्ष के अन्त में दुर्गापुर की धमन भट्टी का उद्घाटन किया। भिलाई में ब्लूमिंग और बिलैट मिलें भी चालू हो गई हैं।

५. एक समाचार के अनुसार वर्ष के पूर्वार्द्ध में लोह पिण्डों और लोह मिश्रित धातुओं के उत्पादन ४५ प्र० श०, इस्पात में २२ प्र० श०, मोटरों में २५ प्र० श०, बिजली में १६ प्र० श०, सूत, कागज और टायरों के उत्पादन में ५ से ११ प्र० श० तथा सीमेंट और सिगरेटों के उत्पादन में ३.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चाय और चीनी के उत्पादन में क्रमशः ५ तथा ३ प्रतिशत की कमी हुई है।

६. औद्योगिक विकास के निर्देशक चिन्ह उद्योग के डिविडैन्ड होते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विवरण से ज्ञात होता है कि डिविडैन्डों का निर्देशक अंक १४ नवम्बर १६५६ तक १५८ था, जबकि उससे पिछले वर्ष यह १३६.५ था।

७. भारत के उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह के अनुसार इस वर्ष मशीनों, औजारों, औद्योगिक मशीनों, मशीन निर्माण, मशीन और विद्युत इन्जीनियरिंग उद्योग, सैरिमिक सीमेंट तथा औषध उद्योगों में उत्पादन बहुत अधिक बढ गया है। मशीनी उद्योग के उत्पादन का सूचक अंक तो ८६६ हो गया और मशीन निर्माण का यह अंक ४२६ हो गया है। बिजली की मशीनों का यह अंक ३०२ हो गया।

८. १६५८ में कुल २६७८८ मोटर गाड़ियां बनी थीं। गणतंत्र के दसवें वर्ष यह संख्या ३५५०० तक पहुँचने की संभावना है। खनिज लोह के उत्पादन में भी २७ प्र० श० की वृद्धि हुई है।

ये कुछ समाचार हैं उन सैकड़ों समाचारों में से जिन्हें हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। देश के विभिन्न भागों में नये उद्योगों की स्थापना, पुराने उद्योगों के विकास और नई योजनाओं की घोषणा आदि के समाचार प्रायः आते रहते हैं।

औद्योगिक उत्पादन के लाखों करोड़ों के अंकों के फेर में न उलझते हुए हम इस वर्ष की कुछ मुख्य निम्नलिखित आर्थिक प्रवृत्तियों की चर्चा करना चाहते हैं।

दो समस्याएं

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्पादन में सबसे बड़ी दो कठिनताएं देश के सामने आईं। पहली तो यह कि अन्न-उत्पादन में वृद्धि होते हुए भी अनाज के मूल्य बढ़ते रहे। उनमें यदि कुछ कमी आई भी तो वह उल्लेखनीय नहीं थी। दूसरी कठिनता यह थी कि विदेशी मुद्रा भारत में दुर्लभ होती गई। इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये—

१—विदेशों से प्रभूत मात्रा में अन्न मंगवाया गया।

२—भारत में कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए विविध प्रयत्न किये गये।

३—उद्योगों के विकास के लिए संचालकों को नई सुविधाएं दी गईं, तथा देश में ऐसा वातावरण बनाने की ओर ध्यान दिया गया जिससे उन्हें अधिक प्रोत्साहन मिल सके।

खाद्य-समस्या

करीब एक अरब रु० को अन्न के आयात से खाद्य-समस्या का कुछ समाधान किया गया।

जापानी-पद्धति की कृषि, बंजर पड़ी जमीनों पर खेती, विविध राज्यों में ज्यादा गहरी जोत का आन्दोलन किसानों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को अधिक उत्पादन करने के लिए अनेक प्रोत्साहन, अच्छे बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई की सुविधाएं, नये औजार, और किसानों को ऋण देने की अधिक सहूलियतें आदि उपाय अन्न उत्पादन में वृद्धि के लिए किये गये। इसमें सन्देह नहीं कि इन सब उपायों का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। १९५७-५८ में जो कमी हुई थी वह कुछ पूरी हुई। चावल और गेहूँ का उत्पादन क्रमशः २९७.२ और ९६.६ लाख टन तक जा पहुँचा। यदि चावल १९५६-५७ में ७९३ लाख एकड़ में हुआ था तो १९५८-५९ में ८१६ लाख एकड़ में बोया गया।

अन्न के बढ़ते हुए मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए भी कुछ विशेष प्रयत्न किये गये। समस्त देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया और अन्न के यातायात पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये, परन्तु अनुभव के बाद फिर उन क्षेत्रों का पुनःसंगठन किया गया और बंगाल एवं उड़ीसा को मिलाकर एक कर दिया गया। इसी तरह बम्बई को मध्यप्रदेश के साथ मिलाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। बढ़ते हुए मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यों द्वारा अन्न का व्यापार करने का कदम उठाया गया। इसका अनेक क्षेत्रों में घोर विरोध होने के बावजूद सरकार समाजवादी नारे के आवेश में टस से मस न हुई। लेकिन कुछ समय के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकार का आग्रह दूरदर्शितापूर्ण नहीं था। खाद्यमंत्री श्री अजित-प्रसाद जैन को अपनी नीति में असफल होने के कारण त्याग पत्र तक देना पड़ा और नये मंत्री श्री पाटिल ने इस संबंध में पूर्ण आग्रह न करने की नीति अपनाई।

दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में की गई विश्व कृषि प्रदर्शनी इसी दिशा में एक प्रयत्न है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि तथा तत्सम्बद्ध उत्पादनों का विकास करने के लिए देश को और विशेषतः किसानों को प्रोत्साहित करना है। हम नहीं कह सकते कि इस प्रदर्शनी से यह उद्देश्य कहां तक पूरा होगा; किन्तु इससे शिक्षित वर्ग व कृषि विभाग का ध्यान कृषि-समस्या की ओर अवश्य चला गया है।

आदर्शवाद से व्यवहार की ओर

हमारी सम्मति में इस वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक वर्षों के अनुभव के बाद हम कोरे आदर्शवाद के प्रलोभनों को छोड़कर व्यावहारिकता की ओर जा रहे हैं और वास्तविक तथ्यों पर अधिक व्यावहारिक दृष्टि से विचार करने लगे हैं। समाजवादी समाज स्थापित करने के आदर्शवादी और आकर्षक नारों से प्रभावित होकर हरेक उद्योग के राष्ट्रीयकरण की चर्चा में कुछ कमी हुई है। अपनी उद्योग नीति में जिन उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चलाने की दृढ़तापूर्वक घोषणा की जाती थी, अब वह ऊंचा स्वर सुनाई नहीं देता। देश के आर्थिक विकास में परिस्थितियों से विवश होकर अनुभव किया जाने लगा है कि कर दाता पर बिना बोझ डाले निजी उद्योग अधिक मित-व्यय से देश के आर्थिक विकास में अधिक सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए ये विदेशी कम्पनियों का सहयोग प्राप्त कर सकें, इसकी भी भूमिका इस वर्ष तैयार हुई है। देश के शासकों ने विदेशी पूंजी का स्वागत किया है और उसे अनेक आश्वासन दिये हैं। अलूमीनियम के दो कारखाने निजी उद्योग के रूप में चलाने की अनुमति, खाद के नये कारखाने निजी क्षेत्रों में भी चला सकने का आश्वासन, जहाजी उद्योग को निजी योजनाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के वचन तथा तेल संशोधन के लिव निजी पूंजी का स्वागत आदि सब घटनाएं इसी ओर संकेत कर रही हैं कि शासन के कर्णधार आकाश में विचरण छोड़कर परिस्थितियों की ठोस भूमि पर चलने लगे हैं। बैंकों तथा चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से स्पष्ट इन्कार भी इसी नीति के उदाहरण हैं। गन्ने के मूल्य भी अधिक बढ़ाने से इन्कार करके सरकार ने वास्तविक स्थिति को स्वीकार किया है।

हमने ऊपर खाद्य संकट की चर्चा करते हुए अन्न के सरकारी व्यापार में कुछ शिथिलता का उल्लेख किया है। नये खाद्य मंत्री श्री पाटिल ने यह अनुभव कर लिया है कि अन्न के व्यापार में अधिक प्रतिबन्ध बहुत लाभकारी नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि अन्न के सीमित नियंत्रण पर ही हमारा १५,१६ करोड़ रुपया व्यय हो गया है। पूर्ण नियंत्रण व एकाधिपत्य में तो एक अरब रुपये तक के व्यय की नौबत आजायगी। एक विचाराधीन प्रस्ताव यह भी है कि चीनी के अधिक उत्पादन के लिए गन्ने के मूल्य पर नियंत्रण समाप्त कर दिया जाय।

इस प्रकार देश के उद्योग और व्यापार को कठोर बंधनों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से मुक्त करने की दिशा की ओर उठाये गये कदम इस वर्ष की सबसे महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति है।

विदेशी मुद्रा

देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा विदेशी मुद्रा की अनुभव की गई। विदेशी अन्न तथा पूंजीगत मशीनरी के भारी आयात ने विदेशी मुद्रा की समस्या को बहुत विकट बना दिया है। इसे सरल करने के लिए इस वर्ष रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रूमानिया, जैकोस्लोवाकिया, जर्मनी आदि देशों से विपुल ऋण लेने के अनेक समझौते किये गये हैं, जिनके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की समस्या आसान हो रही हैं। विदेशी पूंजी पर दोहरा कर न लगे, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत में एक चौथा लोहे का कारखाना खोलने की सम्भावनाओं पर विचार कर रहा है। कोलम्बो राष्ट्रों ने भी अपना कार्यकाल और अधिक पांच वर्षों के लिए चालू करने का निश्चय करके बहुत अधिक प्रशंसनीय कार्य किया है। अनेक उद्योगों के निर्यात को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पंचवर्षीय विकास योजना

यद्यपि भाखरा बांध की एक सुरंग टूटने से देश को भारी आघात लगा, तथापि अन्य दिशाओं में पंचवर्षीय विकास योजनाओं की पूर्ति में निश्चित रूप से प्रगति हो रही है। तीनों लोह कारखानों के कार्यारम्भ का श्रेय गणतन्त्र के इसी दसवें वर्ष को है। भूपाल में बिजली मशीनों के कारखाने का निर्माण प्रायः समाप्त हो चुका है। विद्रोही नदी ब्रह्मपुत्र पर पुल का शिलान्यास इसी वर्ष किया गया है पंचेत के बांध का उद्घाटन इसी वर्ष के अन्त में हुआ है। तेल मिलने की सम्भावनाएं इस वर्ष पहले से बहुत अधिक बढ़ गई हैं। तेल शोधन के कारखाने तथा आसाम में बरौनी तक की पाइप लाइन के प्रारम्भ का प्रयत्न (जिस पर करीब ५४ करोड़ रुपया व्यय होगा), छोटे उद्योगों के लिए सैकड़ों योजनाओं की स्वीकृति, कागज के नये ११ कारखानों की स्वीकृति आदि इसी दसवें वर्ष की घटनाएं हैं। अनेक नये खनिज पदार्थों की नई खानों की तलाश इसी वर्ष हुई है।

विचार के क्षेत्र में इस वर्ष दो महत्त्वपूर्ण समस्याओं ने देश के विचारकों, अर्थशास्त्रियों व नेताओं का ध्यान खींचा। नागपुर में स्वीकृत संयुक्त सहकारी कृषि के प्रस्ताव पर बहुत विचार मंथन हुआ। पक्ष विपक्ष में बड़े-बड़े नेताओं ने तर्क वितर्क किये। अभी संयुक्त कृषि बाद की चीज हो तो भी सहकारी समितियों की संख्या इस वर्ष बहुत बढ़ गई है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के विविध पहलुओं पर विविध हितों की दृष्टि से जितना विचार मंथन इस वर्ष किया गया, उतना पहले कभी योजनाओं पर नहीं हुआ। अब यह प्रायः निश्चित हो चुका है कि तीसरी योजना बृहदाकार और सम्भवतया ९० से १०० अरब रुपये तक की बनेगी, जिसमें करीब ३० अरब रुपये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

गणतन्त्र के इस दसवें वर्ष में औद्योगिक सम्बन्धों में भी कुछ सुधार हुआ है। श्रम मंत्रालय के परिश्रम से मालिकों और श्रमिकों में अनुशासन संहिता पर आचरण करने की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। विभिन्न उद्योगों में न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की दिशा में काफी कदम उठाये गये हैं। सूती उद्योग की वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। चीनी मिलों में गन्ना उत्पादकों ने हड़ताल करने का प्रयत्न किया, किन्तु वे सफल न हो सके। बम्बई जैसी विशाल नगरी में बसों और ट्रामों की हड़ताल बहुत महत्त्वपूर्ण थी। इन पंक्तियों को लिखने तक अन्तर्राष्ट्रीय वायु यातायात में पाइलटों की हड़ताल जारी है सामान्यतया इस वर्ष हड़तालों को जनता की सहानुभूति नहीं मिल सकी।

संक्षेप से हम कहें तो गणतन्त्र का दसवां वर्ष आर्थिक दृष्टि से संतोषप्रद रहा।

राज्यों में 'सम्पदा' स्वीकृत

सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा-विभागों ने अपने-अपने राज्य के स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक वाचनालयों के लिए स्वीकृत किया है—

(१) उत्तरप्रदेश, (२) बिहार, (३) पंजाब, (४) मध्यप्रदेश, (५) राजस्थान, (६) जम्मू-काश्मीर।

शायद आपकी शिक्षण-संस्था में भी 'सम्पदा' आती है। यदि नहीं आती तो अर्थशास्त्र की इस प्रमुख पत्रिका को शीघ्र मंगाना आरम्भ करें!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पिछले ६ वर्षों में अनाज की पैदावार

(हजार टनों में)

अनाज	१९५८-५९	१९५७-५८	१९५६-५७	१९५५-५६	१९५४-५५	१९५३-५४
चावल	२९,७२१	२४,८२१	२८२८२	२७,१२२	A २४,५३१	२७,७६९
गेहूँ	९,६९४	७,६५४	९,३१४	८,६२२	८,७७८	७,८९०
ज्वार	८,६८९	८,०५६	७,२४९	६,६१९	९,०९३	७,९५४
बाजरा	३,७९१	३,५६५	२,८८५	३,३७४	३,४२१	४,४७५
मक्का	२,९९०	३,०६४	३,००९	२,५६१	२,९३९	२,९९१
रागी	१,७२२	१,७१६	१,७१५	१,८१७	१,६४६	१,८४६
दूसरे छोटे अनाज	२,०४३	१,७५९	१,९६४	२,०३७	२,४५६	२,४३८
जौ	२,६४०	२,१७५	२,८२७	२,७७१	२,८७०	२,९०५
कुल जोड़	६१,२९५	५२,८१०	५७,२४५	५४,९२३	५५,७३४	५८,२६८
चना	६,८२६	४,७५४	६,२६४	५,३५२	५,३९३	४,७५६
अरहर	१,६६२	१,३६९	१,९५४	१,८३२	१,६८८	१,८३४
खरीफ की अन्य दालें	१,५४२	१,३९०	१,५१५			
रबी " " "		१,६६५	१,७७०			

१९५९ की विभिन्न तारीखों को हापुड़ में मुख्य अनाजों का भाव

(प्रति मन रुपयों में)

अनाज	१ जनवरी	१ मार्च	१ जून	१ सितम्बर	१ दिसम्बर
	रु० न. पै.	रु० न. पै.	रु० न. पै.	रु० न. पै.	रु० न. पै.
गेहूँ	२४-७५ से २६-०० तक	२२-०० से २५-०० तक	१८-२५ से २०-५० तक	१८-२५ से १९-५० तक	१७-०० से १८-२५ तक
चना	१९-५०	२१-०	१३-६२	११-८७	१२-३७
जौ	१६-५०	१४-५०	१३-२५	१२-०	११-७५
बाजरा	१६-७५	१९-०	१३-०	११-२५	११-२५
चावल बांसमती सेला	२९.०	३३-०	३३-० से ३६-० तक	३३-० से ३५-० तक	२८-० से ३०.० तक

केन्द्रीय सरकार का कर्जा

(रुपए करोड़ों में)

	कुल रकम	तबदीली	विशुद्ध ऋण
१९५९	१८३.८४	८९.३८	९४.४६
१९५८	२०१.८१	९.३६	१९२.४५
१९५७	१३६.१७	४५.०८	९१.०९
१९५६	१५७.७३	८०.५२	७७.२१

राज्य सरकारों का कर्जा

(करोड़ रुपयों में)

	कुल रकम	तबदीली	विशुद्ध ऋण
१९५९	६७.९५	०.८७	६७.०८
१९५८	५४.४२	५.२४	४९.१८
१९५७	९.९१	१.३३	८.५८
१९५६	६८.७१	२.१८	६६.५३

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आखिर, अनाज की मंहगाई क्यों ?

प्रो० श्री आर० के० अमीन

भारत में गणतन्त्र शासन पद्धति को स्थापित हुए १० वर्ष और विकास योजनाओं को प्रारम्भ हुए आठ वर्ष व्यतीत हो गये हैं। इन वर्षों में भारत ने अपनी योजनाओं में बहुत प्रगति की है, इसमें सन्देह नहीं, किन्तु महंगाई की समस्या काबू में नहीं आ रही है। बहुत प्रयत्नों के बाद भी वह विकट से विकटतर होती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार १९५८-५९ में ७ करोड़ २३ लाख टन अर्थात् १९५७-५८ से १७, १८ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ था, किन्तु पदार्थों के मूल्य घटने के बजाय बढ़ गये हैं। १९५७-५८ में यदि निर्देशक अंक (१९५२-५३=१००) १०६ था, तो अगस्त १९५९ में यह १२० तक पहुँच गया। चावल का उत्पादन १९५७-५८ में २ करोड़ ४८ लाख टन हुआ था, तो १९५८-५९ में २ करोड़ ९७ लाख। परन्तु चावल के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई। इसका निर्देशक अंक १०५ ही रहा।

कारण

देश के समस्त अर्थ-शास्त्री महंगाई की पहेली पर विचार करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए निम्नलिखित कारण बताये हैं।

१—मुद्रा प्रसार, देश में घाटे की अर्थ व्यवस्था,

२—विकास योजनाओं पर अत्यधिक व्यय,

३—व्यापारियों की सट्टेबाजी और नफाखोरी,

४—किसानों और व्यापारियों में अनुचित संग्रह की प्रवृत्ति,

५—सरकार के यातायात व व्यापार सम्बन्धी तरह २ के नियन्त्रण,

६—अन्नों का राज्य द्वारा व्यापार।

७—जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि।

ये सब कारण अपनी २ जगह ठीक हैं, किन्तु इसका एक मूल कारण तो अवश्य होना चाहिए और उस कारण की हमें तलाश करनी चाहिए।

मांग में निरन्तर वृद्धि

अन्नों के मूल्य बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि उपलब्धि से मांग अधिक हो रही है। यह मांग तीन ओर से बढ़ी है।

१—एक शहर में रहने वाले उपभोक्ताओं द्वारा।

२—थोक और फुटकर व्यापारियों द्वारा।

३—देहातों के उन उपभोक्ताओं द्वारा, जो वस्तुतः अपनी आवश्यकता से कम अनाज उत्पन्न करते हैं।

शहरों में

शहरी उपभोक्ताओं की मांग भी दो कारणों से बढ़ी है। (१) प्रतिवर्ष शहरों की जनसंख्या में ५-६ प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। (२) श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में नियुक्त अनाज जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि अब शहरों में अनाज संग्रह की प्रवृत्ति, जो पहले नहीं थी, बढ़ रही है। व्यापारी और किसान भी संग्रह में अधिक उत्सुकता दिखा रहे हैं। नागरिकों में राशनिंग और कन्ट्रोल की आशंका ने भी संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ाई है। १९५७-५८ में महंगाई तथा सरकार द्वारा अन्न के व्यापार करने की घोषणा से नागरिकों में अनाज संग्रह करने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। अब नागरिक पहले की अपेक्षा ३ महीने अधिक का स्टाक रखने की चिन्ता करने लगा है। इसका परिणाम यह है कि देश में ३० लाख टन की मांग बढ़ गई है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में नागरिकों की आय से निसन्देह वृद्धि हुई है और उनमें अधिक अनाज जमा करने की क्षमता आ गई है। १९५६ की अपेक्षा नगरों की जनसंख्या करीब १० प्रतिशत बढ़ गई है। इस कारणभी २० लाख टन की मांग पहले से अधिक बढ़ गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि करीब ५० लाख टन की मांग बढ़ी।

व्यापारियों में

व्यापारियों में भी संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये महंगाई की सम्भावना देख कर संग्रह करने लगते हैं और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सस्ते की सम्भावना देखकर निकालने लगते हैं। इस कारण यह सम्भावना नहीं की जा सकती कि उन्होंने अनाज का पहले की अपेक्षा बहुत अधिक संग्रह किया होगा। उनको सदा यह भय भी रहता है कि राज्य किसी भी क्षण उनका स्टाक ले सकता है। राज्य द्वारा अन्न के व्यापार से भी व्यापारियों के संग्रह की प्रवृत्ति बहुत नहीं बढ़ी।

किसानों द्वारा संग्रह

आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि किसान लोगों ने अन्न का काफी संग्रह किया हुआ है। हमारी सम्मति में यह धारणा एक सीमा तक ठीक है। उनके पास बहुत संग्रह की क्षमता ही नहीं हैं, परन्तु यह भी ठीक है कि वे पहले की तरह आधे पेट भूखे नहीं रहते हैं। ग्रामों की आबादी भी बढ़ी है। इसलिए यह सम्भावना की जा सकती है कि गांव में भी १० लाख टन अनाज की मांग बढ़ गई है।

व्यापारिक फसलें

मांग पर विचार करने के बाद अनाज की पूर्ति पर विचार करें। किसानों में व्यापारिक फसलों (तम्बाकू, गन्ना, कपास आदि) से अधिक आय होने की सम्भावना देखकर अनाज कम पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। पिछले दो वर्षों में व्यापारिक फसलों के मूल्य काफी बढ़े हैं। इसके दो परिणाम हुए हैं। एक तो यह है कि अनाज की पैदावार कुछ कम हुई हैं। और दूसरी यह है कि भोजन के सम्बन्ध में पहले की अपेक्षा किसानों का जीवन-स्तर ऊंचा हो गया है। अन्न सम्बन्धी क्षेत्रों के निर्माण और राज्य द्वारा अन्न के व्यापार ने उसे कुछ अधिक सतर्क कर दिया है और अब वह अपना अनाज बेचने में जल्दबाजी नहीं करना चाहता।

इस तरह यदि विचार करें तो निम्नलिखित रूप से अन्न की मांग में वृद्धि हुई हैं।

१—शहरों में जनसंख्या की वृद्धि से	१० लाख टन
२—शहरों में अन्न संग्रह की प्रवृत्ति से	३० लाख टन
३—ग्रामों में जनसंख्या की वृद्धि से	१० लाख टन
४—ग्रामों में अन्न का अधिक उपयोग	१० लाख टन
५—ग्रामों में अन्न संग्रह की प्रवृत्ति	१० लाख टन
कुल	७० लाख टन

इस तरह कुल ७० लाख टन की अतिरिक्त मांग पैदा हुई है। देश में कुल अनाज करीब १३६० करोड़ टन उत्पन्न होता है और ४० लाख टन दो वर्षों में विदेशों से मंगवाया गया है। इस तरह दो वर्षों में मिलाकर १०-२० लाख टन की कमी पड़ती है और यदि १९५९-६० में फसल कुछ खराब हुई तो यह कमी और भी बढ़ जायगी।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गत वर्ष फसल अपेक्षाकृत अच्छी होने के बावजूद अन्न का संकट कम नहीं हुआ। १९५७-५८ में अनाज के भंडारों में काफी कमी आ गई थी, उसको भी पूर्ण करना है, तथा नई मांग को भी जो उपर्युक्त कारणों से बढ़ गई है, पूरा करना है। श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में जो अनाज जांच कमेटी बैठी थी, उसने अन्न संकट के अनेक कारणों का उल्लेख किया है, किन्तु मांग के एकाएक बढ़ जाने के जिस मूल कारण की चर्चा हमने ऊपर की हैं वह बहुत अधिक महत्व रखता है। इस कारण पर विचार करने से अन्न संकट की पहेली कुछ समझ में आ जाती है। इस समस्या का समाधान केवल एक है और वह है अधिक उत्पादन।

* एक अंग्रेजी लेख के आधार पर।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनीतिक अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिकअली

सम्पादक : श्री सुनील गुह

★ हिन्दी में अनूठा प्रयास

★ आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख

★ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,
७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वस्त्र-संकट का नया दौर

संकट आता आता टल-सा गया !

श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

राजनीतिक घटनाचक्र की भांति आर्थिक घटनाचक्र भी कभी-कभी आकस्मिक मोड़ ले लेता है। चीन और भारत में संघर्ष की कल्पना किसी ने नहीं की थी ठीक इसी प्रकार देश के सूती वस्त्र उद्योग में आने वाले नए आकस्मिक संकट की संभावना भी बहुत कम की गई थी।

कुछ समय पूर्व सूती मिलों में एक संकट उत्पन्न हो गया था। मिलों के गोदाम भर गए थे। उत्पादन कम करने के लिए कई पालियां बन्द हो गई थीं और कुछ मिलें तो बिलकुल बन्द होगई थीं। किसी भी क्षण किसी दूसरी मिल के बन्द हो जाने की सम्भावना की जा रही थी। हजारों मजदूर कोई पाली या मिल बन्द होने से बेकार होगए थे, किन्तु आज अवस्था बिल्कुल विपरीत है।

भिन्न दिशा में नया संकट

आज कपड़े की मांग जोरों से बढ़ने लगी है। मिलों के गोदाम खाली हो रहे हैं। मिलों ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। कुछ बन्द मिलें चालू हो रही हैं। और यह अवस्था देखकर अधिकाधिक रुई खरीदने लगी है। मांग के बढ़ने तथा विदेशी रुई के आयात पर कुछ प्रतिबंधों के कारण रुई के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण मिलों ने अपने कपड़े के दाम बढ़ा दिए हैं। मांग के अधिक बढ़ जाने के कारण व्यापारी ज्यादा दाम भी देने को तैयार हैं। मिल-मालिकों के कथनानुसार आज कपड़े के व्यापारी अपने गोदाम भरते जा रहे हैं। कपड़े के व्यापारी इस आरोप को स्वीकार नहीं करते। उनके कथनानुसार गांवों के छोटे व्यापारियों के पास कपड़ा बिलकुल नहीं है। इस कारण वे मिलों से अधिक कपड़ा खरीदने को विवश हो रहे हैं।

कपड़े की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आज मिलें समर्थ नहीं हो पा रही हैं। जनवरी से मार्च के आगामी तीन मासों में बिक्री का अच्छा मौसम होता है, क्योंकि किसान फसल पकते ही कपड़ा खरीदते हैं और गांवों के दुकानदार इससे पहले अपनी दुकान में माल जमा करना शुरू कर देते हैं। आज मिलों के पास जैसा कि श्री घनश्यामदास बिड़ला ने स्वीकार किया है, गोदामों में बहुत कम कपड़ा है और यदि कपड़े की मांग ने जोर पकड़ा तो संकट का आना असम्भव नहीं है। बम्बई के दूसरे प्रमुख उद्योगपति श्री नवल टाटा ने भी यही भय प्रकट किया कि क्या यह संकट फिर कन्ट्रोल और राशन का युग उपस्थित करेगा? क्या फिर दुकानों पर कपड़ा खरीदने वाले पुरुषों और स्त्रियों की कतारें खड़ी होकर चार-चार पांच-पांच गज के लिए घंटों इन्तजार किया करेंगी? बहुत सम्भव है, यह आशंका बिलकुल निर्मूल हो, परन्तु स्थिति की विकटता देखते हुए व्यापारियों में घबराहट का फैल जाना अस्वाभाविक नहीं है।

ऐसी स्थिति क्यों हुई?

पर प्रश्न यह है कि कपड़े की स्थिति में ऐसा आकस्मिक परिवर्तन क्यों आया? अब तक तो मिलें कपड़ा न बिकने और घाटा उठाने की बातें करती थीं। आज संकट का विपरीत दौर क्यों चल पड़ा है? इसका प्रमुख कारण है देश और विदेश दोनों में कपड़े की बढ़ती हुई मांग।

विदेशों से कपड़े की मांग पिछले कुछ समय से एकदम बढ़ती जा रही है, कुछ समय तक व्यापारिक मंदी रहने के बाद तेजी आना स्वाभाविक है। इधर भारत सरकार ने भी वस्त्रों के निर्यात को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया है। निर्यात होने वाले कपड़े पर उत्पादन कर में कमी, रुई के आयात में कुछ सुविधा आदि के कारण विदेशों में भारतीय कपड़ा कुछ अधिक बिकने लगा है।

१९५८ में बम्बई के बन्दरगाह से २४३७ लाख गज कपड़े का निर्यात हुआ था। इस वर्ष २४ अक्तूबर तक ४३८१ लाख गज कपड़ा विदेश जा चुका है और वर्ष के अन्त तक ७५०० लाख गज कपड़े के विदेश जाने की संभावना की जा रही है। इंग्लैंड से कपड़े की मांग बढ़ती जा रही है। इण्डोनेशिया ब्लीच लौंग क्लाथ और शर्टिंग का कपड़ा ज्यादा मंगाने लगा है। सिंगापुर भी गतवर्ष की अपेक्षा अधिक कपड़ा मंगा रहा है। अदन से फैंसी कपड़े

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की मांग बढ़ रही है।

आल इण्डिया एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रमुख श्री नारणजी ने सरकार की निर्यात प्रोत्साहन नीति के अतिरिक्त मांग बढ़ने के दो और कारण बताए हैं—

(१) चीन विदेशी बाजारों में निर्यात प्रतिस्पर्धा से अब हट गया है।

(२) अमरीका में जापान के माल पर मर्यादित प्रतिबंध के कारण भारतीय कपड़े की मांग बढ़ने लगी है।

प्रतिस्पर्धा कम : मांग अधिक

गत वर्ष यह भय किया जाने लगा था कि चीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्पर्धा में भारत, जापान और हांगकांग को नीचा दिखाने लगा है। पर अब यह प्रतीत होता है कि चीन में स्वयं नई समस्याएं उपस्थित होगई हैं। विदेशों में अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने की ऊंची आकांक्षाओं के कारण वह अपनी शक्ति से बढ़कर और स्वयं अपने देशवासियों की आवश्यकताओं को पूरा न करके भी डम्पिंग के द्वारा विदेशी बाजारों पर अधिकार करने को उत्सुक था। लेकिन ऐसा सम्भव नहीं हो सका था। फिर इण्डोनेशिया में फैले हुए चीनी व्यापारियों पर प्रतिबंधों के कारण चीनी व्यापार को धक्का पहुँचा है। चीनी उद्योग अब शायद सामरिक आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान दे रहा है। इस कारण चीन की प्रतिस्पर्धा कम होने से भारतीय कपड़े की मांग विदेशों में बढ़ने लगी है।

भारत में भी

विदेशों के अतिरिक्त वस्तुतः भारत में भी कपड़े की मांग बढ़ रही है। भारत सरकार के द्वारा घोषित अंकों से यह प्रकट है कि देश में अनाज और दूसरी फसलों का उत्पादन अधिक हुआ है। इस कारण गांवों में कपड़े की मांग स्वतः बढ़ गई है। इससे मिलों में कपड़े का स्टाक बहुत कम रह गया है। अक्तूबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक मिलों के पास कुल कपड़ा ३३४ हजार गांठ था। पिछले अनेक वर्षों में इतना कम कपड़ा कभी नहीं बचा। इस भंडार में से भी ८० प्रतिशत कपड़ा बिक चुका है, जो जल्दी ही मिलों के गोदामों से उठा लिया जाएगा। पिछले वर्षों में मिलें डरते-डरते कपड़ा तैयार कर रही थीं कि कपड़ा नहीं बिकेगा। अब एकदम मांग बढ़ने के कारण मिलों के गोदाम खाली हो रहे हैं।

इस नई परिस्थिति के परिणामस्वरूप रुई के दाम बहुत बढ़ गए हैं। रुई के व्यापारियों को यह शक है कि कपास की फसल बहुत अच्छी नहीं हुई है। गत वर्ष सूती मिलों ने भारत में उत्पन्न रुई की ४६ लाख गांठें प्रयुक्त की थीं और अब नई फसल की सम्भावना यह है कि ४३ लाख गांठों से अधिक फसल नहीं होगी। फिर किसान भी आज अधिक समझदार होता जा रहा है। वह आज कपास को रोकने में ही अपना लाभ देखता है। इस कारण रुई बाजार में कम आ रही है और रुई के दाम बढ़ते जा रहे हैं।

रुई के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए भारत-सरकार ने विवश होकर पिछले दिनों एक नया आदेश निकाला कि कोई मिल ३ महीने से अधिक का स्टाक नहीं रख सकती। कुछ मिलों को ४-४०० पौंड की २ लाख गांठें बाहर से मंगाने की अनुमति भी मिली है। पी० एल० ४८० के अन्तर्गत भी अमरीका से रुई आ सकेगी। इन सब व्यवस्थाओं से भी व्यापार व उद्योग को संतोष नहीं हुआ। और वह विदेशी रुई के आयात की अधिक सुविधाएं देने का आग्रह करता रहा। यह जानकर वस्त्र-उत्पादक को कुछ सन्तोष होगा। कि ५-६ लाख गांठों के बजाय इस वर्ष १०-१२ लाख गांठें विदेशों से मंगाने का निश्चय सरकार ने कर लिया है। और इस तरह आने वाला संकट टल गया है।

श्री घनश्यामदास बिड़ला ने संकट को आने से रोकने के लिए यह परामर्श दिया था कि मिलों को पर्याप्त रुई मिलती रहनी चाहिए। श्री नवल टाटा ने भी एक सूती मिल के अध्यक्षीय भाषण में संकट आने से पूर्व ही वस्त्र उत्पादन को अधिकाधिक सुविधाएं देने की मांग की थी। बम्बई के एक प्रसिद्ध व्यापारी के शब्दों में, "यदि सरकार ने शीघ्र ही कदम न उठाया तो बाजार में आग लग जाएगी।" इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार किया जाए। बन्द मिलों को फिर चालू किया जाए। जिन मिलों में एक या दो पाली चालू हैं, वहां दूसरी या तीसरी पाली चालू की जाए। गांवों से भी रुई को अधिकाधिक बाजार में लाना तथा पावरलूम व हथकरघे के द्वारा भी वस्त्र-उत्पादन बढ़ाना चाहिए। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ग्रामोद्योगों का अर्थशास्त्र

भारत गांवों का देश है। इसकी २६.५० करोड़ जनसंख्या अर्थात ८२ प्रतिशत गांवों में ही रहती है। भारत में गांवों की संख्या ५५६,००० है। गांव वालों का मुख्य पेशा खेती है। वे खेती आर्थिक स्तर पर नहीं, जीवन-निर्वाह के स्तर पर करते हैं। देश की जनसंख्या आशातीत वृद्धि के साथ बढ़ रही है। यह वृद्धि यहां तक पहुँच चुकी है कि यहां प्रति व्यक्ति जोत-योग्य भूमि की संसार के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम औसत पड़ता है।

भारत की खेती विज्ञान की अपेक्षा दैवी दया पर ही अधिक आधारित है। यहां अधिकांश रूप से पानी की व्यवस्था इन्द्रदेव ही करते हैं। भारत की सिंचित भूमि का क्षेत्र केवल १७ प्रतिशत है और इसमें ११ प्रतिशत क्षेत्र पर एक से अधिक फसल पैदा की जाती है।

रोजगार

यद्यपि भारत का मुख्य धंधा खेती है, किन्तु इसमें लगे हुए बहुत कम लोगों को उचित रोजगार मिल जाता है। लगभग १४ प्रतिशत लोग प्रतिदिन एक घण्टा या उससे कम काम करते हैं। ४ प्रतिशत दो घण्टे काम करते हैं। ११.५ प्रतिशत चार घण्टे या उससे कुछ कम काम करते हैं। १७.३ प्रतिशत ६ घण्टे या उससे कम काम करते हैं। १३८८-लाख में से ६४० लाख यानी ४६ प्रतिशत लोगों को खेती से पूरा रोजगार नहीं मिल पाता।

खेती से राष्ट्रीय आय का प्रतिशत ४८.६ है, तथा प्रति-व्यक्ति आय ५०८ रुपए है जबकि फैक्टरी के मजदूरों की आय ११८० रुपये तथा दूसरे देश वालों की १२४८ रुपए प्रति व्यक्ति है। १९५७-५८ के बढ़े मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय २०२ है और देहातों की आय का औसत २६५ रुपये है। एक खेतीहर की आय का औसत केवल १०४ रुपए है। 'नेशनल सैम्पिल सर्वेज' के कथनानुसार तो लगभग ६८० लाख लोगों की वार्षिक आय ६६ रु० से भी कम है।

ग्रामों की जीवन धारा

गांव औरतों के समान हैं। उनके हाथ में जाति (समाज) का झूलना-पालना है। औरत के समान गांव का यह काम है कि वह जनता की मुख्य जरूरतें पूरी करें। उन्हें भोजन, आनन्द जीवन का रस दे। सहज ही जुटने वाले सुन्दर उत्सवों का मौका दे, जिससे खुशियां फैलें। पर जब उस पर लगातार मनमानी मांगों का भार पड़ता है, जब लोभ के कारण उससे नाजायज फायदा उठाया जाता है, तब उसकी जीवनधारा सूखने लगती है। उसका दिमाग कुन्द पड़ने लगता है। उसमें सिरजन करने की शक्ति नहीं रहती। वह शहर की बराबरी की है, पर उसकी हालत नौकरानी जैसी बनादी गई है। और शहर अपने पद और घमंड में इतना चूर है कि उसे पता नहीं है कि उसके जीवन, स्वास्थ्य और आनन्द का मूल स्रोत सूखता जा रहा है।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

ग्रामोद्योगों से बेकारी निवारण

केवल औद्योगीकरण तथा भारी उद्योगों की स्थापना से ही बेरोजगारी की समस्या के हल होने तथा देश में प्रगति व समृद्धि होने में सहायता नहीं मिलेगी। इसमें संदेह नहीं कि बड़ी फैक्ट्रियां मजदूरों को अच्छी मजदूरी दे रही हैं तथा उन्हें सुविधाएं दे रही हैं, परन्तु बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो रही है। हमारा विश्वास है कि देश भर में ग्रामोद्योगों का जाल बिछाने से ही बेरोजगारी की समस्या दूर होगी तथा देहाती क्षेत्रों में जनता की हालत में सुधार होगा। ५० वर्ष पूर्व गांव स्वावलम्बी थे तथा वे अपनी आवश्यकताएं गांव के अन्दर ही पूरी कर लेते थे, परन्तु अब स्थिति बदल गई है तथा गांवों में भी लोग असली चीज नहीं पा सकते।

—राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीय आय

भारत में अधिकांश देहाती अदक्ष होते हैं। उनको प्रशिक्षण देने की दो ही व्यवस्थाएं सम्भव हैं। एक तो स्कूलों में छात्रों को प्रशिक्षण देना तथा दूसरे अधिकांश जनता को उत्पादक कार्य सुलभ कराना। यदि प्रत्येक देहाती को, जो बेकार है अथवा बहुत कम आमदनी रखता है, चार आने दैनिक का भी काम मिल जाये और वर्ष भर में केवल १५० दिन काम करे तो राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है, तथा उपयोगी पदार्थों की खपत बढ़ सकती है। उस समय कपड़े के गोदाम भरे होने की शिकायत या दूसरी वस्तुओं की कम खपत की शिकायत नहीं रहेगी। आधुनिक उद्योगों का विकास भी तब तक नहीं हो सकता जब तक अधिकांश जनता की क्रय शक्ति न बढ़ जाये। कुछ लोगों का कहना है कि गांवों में बिजली पहुंचाकर हम ग्राम उद्योगों का अधिक विस्तार कर सकेंगे, किन्तु यदि किसी प्रकार यह कागजी योजनाएं पूर्ण भी हो गई तो १५,२० वर्ष से पूर्व नहीं हो सकेगा। तीसरी योजना के अन्त तक भी २०, २५ हजार से अधिक गांवों में बिजली नहीं पहुँचाई जा सकेगी। कोयले और तेल के स्रोत भी भारत में बहुत सीमित ही है इसलिए शक्ति-चालित उद्योगों की समस्त देश में कल्पना कर लेना बहुत उचित नहीं होगा। आगामी २०-२५ वर्षों तक तो हाथ के श्रम को ही महत्व देना होगा। तभी मानव-श्रम के साथ-साथ अणु शक्ति का भी पूर्ण उपयोग किया जायेगा। निम्नलिखित कारणों से भी अभी यंत्र-शक्ति का प्रयोग कठिन दिखाई पड़ता है।

१.—अभी मशीनों को चलाने की आवश्यक क्षमता और योग्यता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय की इन्तजार करनी पड़ेगी।

२—मशीनें खरीदने की सामर्थ्य अभी गरीब देहातियों में नहीं है।

३—शक्ति को प्राप्त करने के लिए अभी साधन भी बहुत कम सुलभ है। इसलिए वर्तमान रूप में ही कुछ सुधारों के साथ ग्रामोद्योगों को चलाना आवश्यक है।

इन सब कारणों से वर्तमान परम्पराओं के साथ ग्रामोद्योगों का भी अपना एक स्थान है। देश में आय तथा जीवन के स्तर को देखते हुए उसका अपना महत्त्व है।

दो सत्य

यह निश्चित है कि सब नदी-बांधों की योजनाओं के पूरा हो जाने के बावजूद कृषि को मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरा एक सत्य यह भी है कि कृषि कभी बारह महीनों का उद्योग नहीं बन सकती, इसलिए यह आवश्यक है कि वर्ष में सात आठ महीनों तक की बेकारी के लिए कोई काम दिया जाय। देहात का एक कृषक साल भर तक चलने वाली फैक्टरियों में भी नहीं जा सकता। उसे तो ऐसा कार्य चाहिए जो वह खाली महीनों में बिना किसी प्राविधिक योग्यता (Tecknical) के सम्पन्न कर सकें और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की बाजार में आम खपत हो। इस कार्य के लिए उसे ऐसी वस्तुएं निर्माण करनी होंगी, जिनका उपयोग हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य हो।

प्रत्येक नागरिक को चाहे वह ग्राम का निवासी हो या शहर का, पिसा हुआ आटा, छिलका उतारा हुआ चावल, दली हुई दाल और तिलहनों से निकला हुआ तेल तथा पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। इन सब वस्तुओं के लिए कच्चा माल गाँव में ही उत्पन्न होता है।

भारत सरकार ने यह सब देखते हुए खादी और ग्रामोद्योग संघ को निम्नलिखित उद्योग चलाने या विकसित करने का काम सौंपा है।

१. खाद्य उद्योग

(क) अनाज और दालों का पीसना और दलना

(ख) तेल निकालना

(ग) गुड़ और खाँडसारी बनाना।

(घ) मधु मक्खियों का पालन और शहद निकालना।

२. खाद्य भिन्न उद्योग।

(क) सूती, रेशमी और ऊनी खद्दर तैयार करना।

(ख) अखाद्य तेलों से साबुन बनाना।

(ग) मिट्टी या दूसरे पदार्थों से बर्तन और टोकरियां बनाना।

(च) चमड़े के जूते तथा अन्य सामान बनाना।

(छ) हाथ का बना कागज।

(ज) लोहार और बढ़ई के काम।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन उद्योगों का विकास करने से बेकारी की समस्या अधिक हल हो सकती है। इन उद्योगों के विकास से हम देश के करोड़ों देहातियों की शक्ति, योग्यता और प्रतिभा का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। सैकड़ों को नौकरी देना या रोजगार देना सम्भव हो सकता है। परन्तु करोड़ों लोगों को नौकरी देना सम्भव नहीं है। इसके लिए अपना २ स्वतंत्र कार्य ही जहाँ मानव की रोटी की समस्या को हल करेगा वहां उनको आत्मसम्मान और संतोष भी प्रदान करेगा। घरेलू उद्योग के औजार उसके अपने होंगे, वह अपने परिवार की और अपने निकट पड़ोसियों की आवश्यकता पूरी करेगा। इसके लिए उसे गाँव से बाहर न कच्चे माल को ले जाना पड़ेगा और न बाजार तलाश करना पड़ेगा। वह अपने आप स्वावलम्बी होगा।

ग्रामोद्योगों में एक बड़ा लाभ यह है कि वे समय और रुचि के साथ २ बिना किसी झंझट के बदले जा सकते हैं। जबकि बड़े उद्योगों के औद्योगिक झगड़े, शोषक और शोषितों का संघर्ष आदि भी ग्रामोद्योगों के साथ समाप्त हो जायेंगे। आज भी ७१.३ प्रतिशत व्यक्ति देश में स्वतन्त्र आजीविका चलाते हैं वह चाहे खेतों में हो या उद्योगों में। आवश्यकता यह है कि स्वतन्त्र आजीविका को अधिक पूर्ण बनाया जाय। उनकी आय का स्तर बढ़ाया जाय। उनकी उत्पादन शक्ति और अर्जन शक्ति को बढ़ाने के लिए ग्रामोद्योगों के अतिरिक्त अन्य और उपाय नहीं हैं। आवश्यक सुविधाएं आर्थिक शिल्पिक, और संगठनात्मक सुविधाएं देहातों तक पहुँचाई जायें।

अम्बर चरखे से क्रांति

खादी जगत में अम्बर चरखे ने उत्पादन में क्रांति की है। इस चरखे से आर्थिक दिशा में किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, यह नीचे लिखे आंकड़ों से स्पष्ट हो जायेगा।

परम्परागत चरखे के अंक

कत्तिनों का नाम	वर्षभर में सूत उत्पादन	वर्षभर की मजदूरी	महीने की मजदूरी	दैनिक मजदूरी
तुलसीदेवी	।ऽ७	६२=)	५=)।।।	=)।।।
रुक्मणीदेवी	।ऽ१।।	३७।।≡)	३=)।	-)।।।
ग्यारसीदेवी	।ऽ८	५४।।=)।।।	४।।-)	=)।
चांद देवी	।ऽ२।।।	३७।।।-)	३=)।।	-)

अम्बर चर्खे के अंक

अब अम्बर चरखे से कताई करने वाली कत्तिनों की मजदूरी के आंकड़ों पर दृष्टि डालिये—

सन् ५८-५९ के अम्बर द्वारा मजदूरी अंक

कत्तिन का नाम	वर्ष भर में सूतका उत्पादन	वार्षिक मजदूरी	मासिक मजदूरी	दैनिक मजदूरी
नर्वदादेवी	१।।ऽ।।	३९०।।-)	३२।।)।।।	१-)।
विरदीदेवी	२।।२।।	४१३=)	३४।=)।।।	१=)।
जमनादेवी	१।।ऽ४।=	३५९।।-)।।।	३०)	१)
गुल्लीदेवी	१।।ऽ१।।=	३६८।।।-)।।	३०≡)	१)

उपर्युक्त आंकड़े भी दौसा केन्द्र के हैं। दौसा में २।।) से ४।।) तक प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करने वाली कत्तिनें सैकड़ों की संख्या में हैं।

अब जरा बुनकरों की मजदूरी पर निगाह डालिये!

नाम बुनकर	वर्ष भर की बुनाई मजदूरी	मासिक मजदूरी	दैनिक मजदूरी
आनन्दीलाल	१,२८१।।।)	१०६।।।-)	३।।)।।।
केशाराम	१,१५०।।।)	९५।।।=)।	३≡)।
हरलाल दूला	१,१३१)	९४।)	३=)।
भगवानसहाय	१,१२३)	९३।।-)	३=)

ये अंक १९५८-५९ के हैं, जो दौसा से लिये गये हैं। सन् १९५१-५२ से ५४-५५ तक बुनकर की मजदूरी १) से अधिक नही है। अम्बर से तीन गुनी मजदूरी मिली है। दौसा में लगभग ३० बुनकर ऐसे हैं, जो ३।।) से ५) तक दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं।

इन अंको में अम्बर की जिन कत्तिनों का नाम दिया गया है, उन्होंने वर्ष भर में ठीक नौ महीने काम किया है। हिसाब १२ महीने के अनुसार दिखाया गया है। अम्बर से कामगरों की मजदूरी में चार गुना से आठ गुना तक अंतर पड़ गया है।

—राजस्थान खादी पत्रिका

सम्पदा
आपके विज्ञापन का श्रेष्ठ माध्यम है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशों में 'कागजी सुवर्ण'

श्री जी० एस० पथिक

संसार में शताब्दियों से सुवर्ण का महत्व कायम है। आज भी सुवर्ण की प्रभुता बनी हुयी है। भारत और फ्रांस को छोड़कर राष्ट्रीय रक्षित कोषों में सोना जमा है। अन्य देशों में आभूषणों में सोना जमा नहीं किया जाता है। आज द्रव सोना (पेट्रोल) और नीला सोना (काफी तथा सफेद सोना स्पात) आदि शब्द नए रूप में प्रचलित हैं। स्पात और पेट्रोल के उत्पादन से देशों की आर्थिक सम्पन्नता प्रकट होती है।

किन्तु इधर कागजी सुवर्ण एक नयी चीज संसार के सामने आयी है। यह योजना यकायक नयी नहीं है। इंग्लैण्ड में तीन शताब्दी पूर्व सेम्यूएल मोंटेग्यू ने इस योजना का प्रयोग किया था। यह कागजी सुवर्ण क्या है?

जोहांसवर्ग के १६ व्यापारियों ने दक्षिण अफ्रीका में अन्तर्राष्ट्रीय सुवर्ण कार्पोरेशन की स्थापना की है। इस कार्पोरेशन को दक्षिण अफ्रीका के स्टेंडर्ड बैंक और सोने के व्यापारिक प्रतिष्ठान जानसन में थे का सहयोग प्राप्त है। इस कार्पोरेशन के कामकाज से स्टर्लिंग क्षेत्र में सोने में कामकाज की रुकावटें ढीली पड़ेंगी। इस कार्पोरेशन की एक शाखा लंदन में भी स्थापित होगी। इस संस्था का कामकाज जनवरी १९६० से आरम्भ होगा। यह कार्पोरेशन ३.५ प्रतिशत के प्रीमियम पर बाजार दर पर सोना जमा करता है, और बदले में बियरर बांड जारी करता है, जिन पर किसी का कोई नाम नहीं होता है। इन बांडों से सोने के पांसे प्राप्त किए जा सकते हैं। आरम्भ में जो केन्द्र कायम किए गए हैं, उनमें से किसी भी केन्द्र में ये बांड सोने में भुनाए जा सकते हैं। ये बांड ५० ग्राम से १ किलोग्राम के बीच तक होते हैं। इससे भारी पांसे भी स्वीकार किए जा सकते हैं। सोने की चलतू दरों में, जिनमें में प्रीमियम भी शामिल है, इन बांडों की लागत २७ पौण्ड १६ शिलिंग से ४१५ पौण्ड १६ शिलिंग तक है। इन बांडों को दक्षिण अफ्रीका का स्टेंडर्ड बैंक इंडोर्स करेगा और सोने के पांसे लंदन में जमा रहेंगे। बांडों के क्रय विक्रय की दरें प्रतिदिन प्रकट होंगी, किन्तु जब इन बांडों से सोना प्राप्त करना होगा, तब उन बांडों में लिखा हुआ सोना ही मिलेगा। सोना वापस लेने पर कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा।

यह योजना किस प्रकार काम करेगी, उसे भी देखिए। जो व्यक्ति सोना जमा करता है, उसे बाजार भाव से ३.५ प्रतिशत अधिक मिलता है। जिसे वह आवश्यकता पड़ने पर कभी भी ले सकता है। इस प्रकार ३॥ प्रतिशत बिना किसी नुक्सान के मूल अर्जन होता है। सोना जमा करने वाले के लिए यह बड़ा आकर्षण है। इससे सारे संसार में सोने के दाम चढ़ने की संभावना है। जबकि यह हर एक कोई जानता है कि विनियोजन में जाने वाली रकम पर मिलने वाले ब्याज की दरें ऊंची हैं, और उसकी तुलना में कागजी चलन मुद्रा के दाम गिर रहे हैं।

भारत में कागजी सुवर्ण का उपयोग

भारत में जो सोना मुद्रा के उपयोग में नहीं है, उसके सम्बन्ध में अनुमान किया जाता है कि वह करीब ३००० करोड़ रुपए से १०,००० करोड़ रुपए तक का है। इससे भी अधिक हो सकता है। दूसरी ओर भारतीय रक्षित कोष में सुवर्ण और विदेशी मुद्राएं-स्टर्लिंग और डालर हमारे व्यापार की बाकी और भुगतान चुकाने की दृष्टि से न्यूनतम हैं। पिछले दिनों लोक सभा में यह चर्चा हुई थी कि लोगों के पास जो निजी सोना है, उसका एक बड़ा अंश राष्ट्रीय रक्षित कोष में लाया जाए, किन्तु केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री इस सम्बन्ध की कठिनाइयों से दबे हुए प्रकट हुए। पर यह कठिनाई को दूर करने का मार्ग अन्तर्राष्ट्रीय सुवर्ण कार्पोरेशन ने अपने संगठन द्वारा हमें प्रदान किया है। इस कार्पोरेशन को बम्बई में अपनी शाखा स्थापित करने के लिए इस शर्त पर आमंत्रित किया जाए कि वह सोने के पांसे भारतीय रिजर्व बैंक में जमा रखेगा। मगर इससे बाहरी कारबार का हस्तक्षेप माना जा सकता है, पर भारत के रिजर्व बैंक के लिए कोई अड़चन नहीं हो सकती है कि वह एक कागजी सुवर्ण विभाग की स्थापना करे, बशर्ते कि वह बिना किसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Subscribe
&
Read

SOVIET LAND

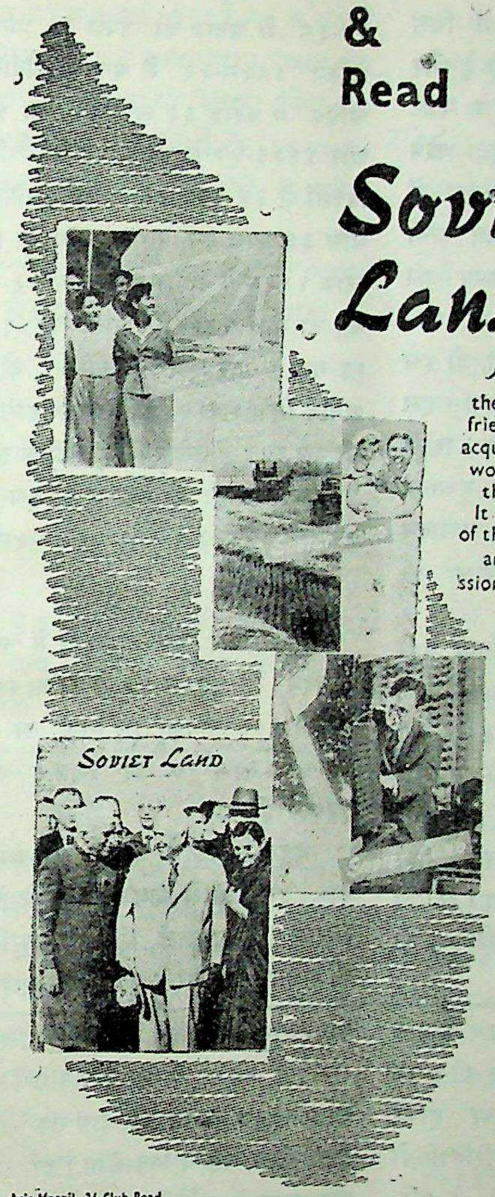

SOVIET LAND, the magazine of Indo-Soviet friendship, the magazine that acquaints the readers with life, work and achievements of all the peoples of the USSR. It appears in the languages of the peoples of India, in Nepali and in English. Special concessions and gifts are being offered to subscribers for 1960.

GIFT CALENDAR

Four page multi-colour calendar will be sent to those who subscribe before 31st January, 1960

CONCESSION

Yearly subscription will be accepted at the special concessional rates of Rs. 6.00 (usual Rs. 7.00) for English magazine and Rs 4.00 (usual Rs. 5.00) for language editions upto 31st January, 1960.

SPECIAL GIFT

Those who send their subscriptions for two years, will receive a calendar for 1960, a calendar for 1961 when printed next year and a set of four booklets published by us about different aspects of Soviet life.

Yearly	Rs. 7.00
Half Yearly	Rs. 3.75
Quarterly	Rs. 2.25

PRICE PER COPY 0.40 nP

Aziz Manzil, 26 Club Road,
Byculla,
Bombay-8

25, Barakhamba Road
New Delhi

1/1, Wood Street
Calcutta-16

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५८-५९ में भारत की आर्थिक व वित्तीय स्थिति

यद्यपि इस साल भारत की आर्थिक अवस्था पर काफी बोझ रहा, किन्तु फिर भी पिछले साल १९५७-५८ से इसमें काफी सुधार हुआ है। विदेशी मुद्रा कोष में जिस गति से ह्रास हो रहा था, वह काफी धीमी पड़ गई है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष केन्द्र और राज्यों के बजट का घाटा भी कम रहा। १९५६-५७ में विदेशी मुद्रा कोष में २ अरब २१ करोड़ ३० लाख रु०, १९५७-५८ में दो अरब ५९ करोड़ ९० लाख रु० और इस वर्ष यानी १९५८-५९ में केवल ४६ करोड़ ६० लाख रुपए की कमी हुई। इसी प्रकार केन्द्र और राज्यों के बजट में १९-५७-५८ में ४ अरब ९९ करोड़ रु० का घाटा था, जो इस साल घटकर १ अरब ५६ करोड़ रु० का रह गया। इस वर्ष पैदावार पिछले साल से १४ प्रतिशत अधिक रही। १९५७-५८ में ६ करोड़ २५ लाख टन अनाज पैदा हुआ था और इस साल ७३५ लाख टन अनाज हुआ। यह उत्पादन जो तब तक का सबसे अच्छा साल था, ४७ लाख टन अधिक पैदा हुआ।

१९५८-५९ की आर्थिक और वित्तीय नीतियां वहीं थीं, जिनके कारण साधनों और मांग के अन्तर को कम करने में सहायता मिली। व्यापार सम्बन्धी नीति का उद्देश्य, देश के आंतरिक साधनों को और बढ़ाने तथा पूंजी-सम्बन्धी नीति का उद्देश्य माल को दबाकर बाद में ऊंचे दामों पर बेचने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने का रहा, फिर भी अधिक पूंजी लगाने को प्रोत्साहन दिया गया। निर्यात बढ़ाने और आयात को कम करने की बराबर कोशिश की गई।

कृषि-उत्पादन

देश के बहुत से भागों में सूखा पड़ने के कारण १९-५७-५८ में अनाज की उपज १० प्रतिशत घट गई थी। लेकिन १९५८-५९ में अन्न की पैदावार पिछले साल से अधिक ७ करोड़ ३५ लाख टन या १८ प्रतिशत अधिक और १९५६-५७ से भी ७ प्रतिशत अधिक हुई। इस साल विदेशों से ३४ लाख टन अनाज मंगाया गया, जबकि पिछले साल ३६ लाख टन मंगाया गया था। अन्न का सरकारी स्टाक १९५८ के अप्रैल के शुरू में १५ लाख १० हजार टन था, जो मार्च १९५९ के अन्त तक ११ लाख ५० हजार टन रह गया। इस प्रकार देशवासियों को इस साल अधिक अनाज मिल सका। अधिक लाभकारी फसलों की पैदावार भी इस साल पिछले साल से अधिक हुई।

अनाज आदि की पैदावार का इस साल का अस्थायी सूचक अंक १२३.६ और १९५७-५८ का ११४.६ था।

उद्योग

इसी प्रकार कल-कारखानों में बनने वाली चीजों का उत्पादन भी १९५८-५९ में ऊंचा रहा। १९५१ के उत्पादन को १०० मानकर इस साल का सूचक अङ्क १४१ है, जबकि १९५६-५७ का १३५.६ और १९५७-५८ का १३७.९ ही था।

बहुत से उद्योगों की उत्पादन-क्षमता भी इस वर्ष काफी बढ़ी। इस दृष्टि से कागज, गंधक के तेजाब, कास्टिक सोडा, रंगरोगन, दियासलाई, सीमेंट, अलमुनियम, रेयन, सिलाई की मशीन, बिजली के पंखे, और साइकिल इत्यादि उद्योग

खर्च के सोने के साफ करने और स्टेंडर्ड आकार के पांसे बनाने और सोना जमा करने वालों को बाजार दर की तुलना में ३॥ प्रतिशत का प्रीमियस देने के लिए तत्पर होकर बियरर बांड जारी करने को अग्रसर हो। जिन परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय सुवर्ण कार्पोरेशन के आयोजक बढ़े, वे परिस्थितियां भारत के भी अनुकूल हैं। यहां भी वैसी ही ही स्थिति है। इस योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार सोना रखनेवालों को यह यकीन हो जाए कि कागजी सुवर्ण को जब कभी भी पीले सुवर्ण में बदला जा सकता है, तो वह प्रीमियम पाने के लिए सोना जमा करने का प्रोत्साहन पाएगा और जब तक सोना मांग पर प्राप्त होता रहेगा, वह न निकालेगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार, व्यापारी वर्ग और अर्थशास्त्रियों की एक समिति स्थापित करे, जो देश में बिना धातु का सुवर्ण जारी करने की योजना तैयार करे। इस अवस्था से रुपए में मजबूती आएगी और तब घाटे की अर्थ-व्यवस्था को भी छोड़ देना पड़ेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उल्लेखनीय हैं। वर्तमान इस्पात कारखानों को बढ़ाने का काम प्रायः पूरा हो चला है और आशा है कि १९५९-६० में कारखाने के विस्तार के फलस्वरूप इस्पात का उत्पादन भी लगभग ५ लाख टन बढ़ जाएगा। १९५९-६० के शुरू के दिनों में भी औद्योगिक उत्पादन अच्छा रहा। पटसन और सूती कपड़े के उद्योगों में जमा माल की निकासी संतोषजनक रही। वर्तमान रुख से यह आशा होती है कि १९५९-६० में औद्योगिक उत्पादन पिछले दोनों सालों से अधिक रहेगा।

कुल क्षेत्र में १५२.८० करोड़ रु० व्यय

कोलम्बो योजना क्षेत्र में १९५४-५५ की अपेक्षा राष्ट्रीय व्यय में ७७ करोड़ पौंड की वृद्धि हुई है। १९५४-५५ में राष्ट्रीय व्यय ६५ करोड़ पौंड था, जो बढ़कर १९५८-५९ में एक अरब ५२ करोड़ ८० लाख पौंड हो गया। १९५९-६० में १ करब ४७ करोड़ ८५ लाख पौंड व्यय की योजना है।

अधिकांश देशों में कृषि-उपज में वृद्धि हुई। लोहा, कोयला, पेट्रोल तथा अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि का रुख रहा।

मूल्य

थोक मूल्यों का सूचक-अङ्क (१९५२-५३=१००) इस वर्ष पिछले साल से ४ प्रतिशत अधिक रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से खाने-पीने की चीजों के सूचक अङ्क के बढ़ने (लगभग ८ प्रतिशत) के कारण हुई। १९५६-५७ के शुरू में थोक मूल्यों का सूचक अंक ९८ था, जो इसी साल के अन्त में १०६ हो गया। अगले साल यानी १९५७-५८ का सूचक अङ्क पिछले साल से ३ प्रतिशत अधिक था।

१९५८-५९ में मूल्यों पर अच्छी फसल का कुछ असर तो अवश्य पड़ा, लेकिन मांग के बढ़ने और कोयले आदि उद्योगों में कर्मचारियों के वेतन बढ़ने से अनाज को छोड़कर अन्य चीजों के मूल्य ऊपर हो गये।

भुगतान सन्तुलन की स्थिति

दूसरी योजना के शुरू से ही भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी नहीं रही है। पहली अप्रैल १९५६ को यानी दूसरी योजना के शुरू के दिन भारत के रिजर्व बैंक की विदेशी लेनदारी ७ अरब ४६ करोड़ १० लाख रु० थी जो मार्च १९५७ के अन्त में घटकर २ अरब १९ करोड़ ३० लाख रु० रह गई थी। यद्यपि इस बीच अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से भी ६० करोड़ ७० लाख रु० निकाल लिया गया था। मार्च १९५८ के अन्त तक इस लेनदारी में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ३४ करोड़ ५० लाख रुपए लेने पर भी २ अरब ५९ करोड़ ८० लाख रु० की कमी हुई और मार्च १९५९ तक तो यह ५३ करोड़ ९० लाख रु० और घटकर २ अरब १३ करोड़ १० लाख रुपये की रह गयी।

भुगतान की इस प्रतिकूलता का मुख्य कारण योजना के पहले तीन सालों में भारत के विदेशी व्यापार में जबर्दस्त घाटा था। आयात और निर्यात में १९५५-५६ में जहां १ अरब २१ करोड़ ५० लाख रु० का अन्तर था, वहां अगले साल, १९५६-५७ में यह अन्तर बढ़कर ४ अरब ६४ करोड़ ३० लाख रुपए और १९५७-५८ में ६ अरब ९ करोड़ ५० लाख रुपए का हो गया। १९५८-५९ में यह घाटा ४ अरब ७० करोड़ ४० लाख रु० का यानी १९५६-५७ से कुछ ही अधिक रहा।

१९५६-५७ में कुल आयात ३ अरब ३८ करोड़ १० लाख रु० बढ़कर १० अरब ९९ करोड़ ५० लाख रु० का हो गया। इस प्रकार इस साल आयात में ४४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगले साल, १९५७-५८ में आयात में १ अरब ४ करोड़ ७० लाख रु० या लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि हुई, किन्तु आयात घटाने के प्रयत्नों के फलस्वरूप १९५८-५९ में आयात में १ अरब ५७ करोड़ ७० लाख रु० की कमी की जा सकेगी। १९५७ के शुरू से ही विदेशों से कम माल मंगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

निर्यात

१९५८-५९ में निर्यात में कमी रही। निर्यात से १९५६-५७ में ६ अरब ३५ करोड़ २० लाख रु० और १९५७-५८ में ५ अरब ९४ करोड़ ७० लाख रु० की आय हुई। १९५८-५९ में निर्यात में १८ करोड़ ६० लाख रु० अर्थात् ३ प्रतिशत की कमी हुई।

इस साल चाय और कपास के निर्यात में वृद्धि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हुई। इस साल १७ करोड़ ७० लाख रु० की चाय और ७ करोड़ १० लाख रु० की कपास भेजी गयी। पर पटसन के सामान, सूती माल और वनस्पति तेल के निर्यात में कमी हुई। इस साल ११ करोड़ ६० लाख रु० का पटसन का सामान, १३ करोड़ २० लाख रु० का सूती माल और ५ करोड़ रु० का वनस्पति तेल भेजा गया। कच्चे मैंगनीज का निर्यात भी १९५७-५८ के २६ करोड़ ४० लाख रु० से गिरकर में १३ करोड़ २० लाख रु० रहा।

विदेशी सहायता

अप्रैल १९५६ के आरम्भ से जुलाई १९५६ के अंत तक ११ अरब ६ करोड़ २० लाख रु० का ऋण तथा अनुदान मिला। पहली योजना से भी १ अरब ६३ करोड़ ४० लाख रु० बचा हुआ था। इस प्रकार जुलाई १९५९ के अंत में दूसरी योजना के लिए १३ अरब २ करोड़ ६० लाख रु० विदेशी सहायता के रूप में उपलब्ध था। इसमें वह ३५ करोड़ डालर भी शामिल है, जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक और पांच देशों की सरकारों ने दिया था।

मार्च १९५९ के अन्त तक इस रकम में से ७ अरब रु० खर्च किया गया था। इस प्रकार अप्रैल १९५९ के आरम्भ में ६ अरब २ करोड़ ६० लाख रु० बाकी रह गया था।

मार्च १९५८ के अन्त में देश में २३ अरब ८९ करोड़ रु० चलन में रहा। १९५८-५९ में इसमें १ अरब ६ करोड़ रु० की वृद्धि हुई, जबकि १९५७-५८ में ७५ करोड़ ६० लाख रु० और १९५६-५७ में १ अरब २८ करोड़ ६० लाख रु० की वृद्धि हुई थी।

आय नीति

१९५८-५९ में देश की अर्थ-नीति प्रायः वही रही जो पिछले साल थी। आय बढ़ाने के लिए १९५७ में जो काम किये गये थे, वे १९५८-५९ में भी किये गये, यथा—करों में वृद्धि, बैंक दर में वृद्धि, आयात पर नियन्त्रण, निर्यात को प्रोत्साहन आदि।

उत्पादन बढ़ाने में जो दिक्कतें आ रही थीं, उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया गया। उद्योगों को अधिक कच्चा मौल दिलाने का प्रबन्ध किया गया, ताकि वहां पूरी सामर्थ्य से उत्पादन हो सके।

अनुमान

वर्तमान स्थिति को देखकर आशा की जाती है कि दूसरी योजना के लिए जो रकम रखी गयी है, वह योजना को पूरा करने के लिए कम नहीं पड़ेगी। फिर भी भाव बढ़ने और अनुमानों में संशोधन करने से हो सकता है कि १०-२० प्रतिशत की कमी पड़े।

पहली योजना में राष्ट्रीय आय की ५ प्रतिशत पूंजी, जो कारबार में लगाई जाती थी, वह बढ़कर लगभग ७ प्रतिशत हो गई थी और अब वह १०-११ प्रतिशत हो गई है। दूसरी योजना में जो पूंजी लगाई गयी थी, उसमें से अब कुछ से लाभ भी होने लगा है और बाकी से शीघ्र ही लाभ होने लगेगा।

अभी देश की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं हुई है, फिर भी आरम्भ अच्छा ही हुआ है। ❀

❀ कोलम्बो योजना की सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर

पंचवर्षीय योजनाओं पर अपूर्व साहित्य

आज पंचवर्षीय योजनाओं का ध्यान प्रत्येक शिक्षित भारतीय के लिए और विशेषतः अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है।

हमारे निम्न तीन विशेषांक आपको इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देंगे।

(१) योजना अंक (प्रथम पंचवर्षीय योजना का परिचय)
(२) राष्ट्रीय विकास अंक (आजकल चलने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना)
(३) राष्ट्रीय प्रगति अंक (दूसरी योजना की प्रगति तथा नई समस्याओं का विवेचन)

तीनों अंक एक साथ मंगाने पर रु. ३.५० में

मैनेजर—
'सम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर
शक्तिनगर दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया साहित्य

इण्डियन इकौनोमिक्स ईयर बुक (१६५६-६०)--लेखक श्री राजनाराण । प्रकाशक—किताब महल, इलाहाबाद । मूल्य ३) रु० ।

संशोधित और परिवर्धित संस्करण के रूप में यह पुस्तक दूसरी बार प्रकाशित की गई है। भारतीय अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, लेखकों व पत्रकारों के लिए हमारी दृष्टि में इससे अच्छी संक्षिप्त पुस्तक नहीं आई, जिसमें आर्थिक तथ्यों व अंकों की आवश्यक जानकारी तथा इसके साथ सभी प्रस्तुत समस्याओं का संक्षिप्त परिचय सरल व सुबोध रूप में दिया गया हो। स्थान-स्थान पर अन्य देशों से तुलनात्मक अंक भी दिये गये हैं। उदाहरण के लिए भारत की भूमि, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, खनिज, बड़े व घरेलू उद्योग, पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक योजनाएं, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, यातायात, राजस्व, विदेशी मुद्रा, बैंकिंग व बीमा, और राष्ट्रीय आय, घाटे की अर्थव्यवस्था आदि प्रायः सभी ज्ञातव्य सामग्री का संग्रह इसमें किया गया है। क्या ही अच्छा होता कि प्रकाशक इसका हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित करके हिन्दी पाठकों को भी पूरी जानकारी दे सकते।

अध्यापन सिद्धान्त एवं विशिष्ट पद्धतियां—ले० श्री वंशीधरसिंह और श्री भूदेव शास्त्री। प्रकाशक—गयाप्रसाद एण्ड सन्स आगरा। मूल्य ५)।

देश में शिक्षाप्रसार के साथ-साथ प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इसी कारण देश के प्रत्येक भाग में ट्रेनिंग स्कूलों व कालेजों की संस्थाएं लगातार खुल रही हैं। इनमें प्रविष्ट होने वाले प्रशिक्षार्थी भी निरन्तर बढ़ रहे हैं। कुछ समय पूर्व तक उन प्रशिक्षार्थियों का अध्ययन अध्यापन प्रायः अंग्रेजी में होता था। अब हिन्दी के माध्यम होने के कारण पाठक व सहायक पुस्तकों का हिन्दी में प्रकाशन अनिवार्य है। प्रस्तुत पुस्तक इसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए लिखी गई है। एल० टी०, बी० टी० तथा बी० एड० के प्रशिक्षार्थी इससे लाभ उठा सकेंगे।

हमने प्रस्तुत पुस्तक का अवलोकन किया है। मुझे यह पुस्तक हिन्दी में लिखी गई एतद्विषयक पुस्तकों में सर्वोत्तम मालूम हुई। किसी भी अंग्रेजी पुस्तक के मुकाबले में इसे मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। लेखक ने इस विषय पर लिखे अंग्रेजी साहित्य का पूर्ण उपयोग किया है। प्रकाशक ने भी पुस्तक की छपाई व बहि-रंग को सुन्दर रूप देकर अपनी सुरुचि का प्रदर्शन किया है।

—सैयद अन्सारी

बुनियादी शिक्षालय और समाज व्यवस्था—ले० श्री मिलापचन्द दुबे। प्रकाशक—वही; मूल्य ५)।

म० गांधी ने विविध क्षेत्रों में देश को जो अमूल्य देने दी हैं, बुनियादी शिक्षा उनमें से एक है। वे समस्त शिक्षा क्रम को मौलिक व क्रांतिकारी रूप देना चाहते थे। यद्यपि उनके व्यक्तिगत प्रभाव के कारण इस दिशा में कुछ काम हुआ है, तथा राज्यों की सरकारों ने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत इसको भी उचित स्थान देने का निश्चय किया है, तथापि यह दुःखद सत्य है कि शिक्षा विभागों का बहुत कम हार्दिक सहयोग इसे मिला है, क्योंकि इसमें जिस तत्व के सात्विक शिक्षक की आवश्यकता होती है, वैसे शिक्षकों की भी काफी कमी है।

प्रस्तुत पुस्तक इस उद्देश्य से लिखी गई है कि बुनियादी स्कूलों के अध्यापक अपने कर्तव्य तथा शिक्षा पद्धति अच्छी तरह पहचान सकें। एक बुनियादी स्कूल के संगठन तथा उसकी प्रबन्धव्यवस्था के मूल सिद्धान्तों की समीक्षा व आलोचना की दृष्टि से पुस्तक उत्तम है और एक अभाव को पूर्ण करती है। सरल, स्पष्ट और सुबोध बोलचाल की भाषा में लिखी यह पुस्तक प्रायः उन सब समस्याओं पर प्रकाश डालती है, जो बुनियादी स्कूल चलाने के सिलसिले में उपस्थित होती हैं। बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों व अधिकारियों की ही नहीं, किन्तु इस विषय में रुचि लेने वाले सामन्य शिक्षित जनों को भी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। स्कूल की अर्थव्यवस्था, पाठ्यक्रम, समय विभाग, अनुशासन आदि सभी प्रश्नों पर इसमें प्रकाश डाला गया है।

पथ की वंशी—ले० श्री यदेवेन्द्र शर्मा चन्द्र। प्रकाशक राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली। पृष्ठ संख्या १३८, सजिल्द मूल्य २.२५ रु०।

पिछले दिनों हिन्दी संसार ने यादवेन्द्र की अनेक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कृतियों का परिचय प्राप्त किया है। पांच छः उपन्यास तो हमारी दृष्टि से भी गुजर चुके हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में एक ऐसे विकलांग, दरिद्र परन्तु ऊंचे कलाकार की कथा है, जो अपने जीवन में निरन्तर संघर्ष करता हुआ अन्त में परास्त हो जाता है। जीवन में उसको अनेक कटु अनुभव होते हैं। उसकी उच्च कृतियों का लाभ सब उठाना चाहते हैं, परन्तु किसी को उससे हार्दिक सहानुभूति नहीं। सबसे अधिक कटु अनुभव उसे तब होता है, जब उसकी प्रेमपात्र इन्दु ही, जिसके निर्माण में, जिसे समाज में यथोचित गौरव दिलाने में उसने अत्यन्त विश्वास व श्रद्धा के साथ अपनी समस्त शक्ति अर्पित कर दी थी, उसके साथ विश्वासघात करके सम्पन्न व्यक्ति की हो जाती है। इन्दु में ऐसी नारी का चित्रण है, जो श्रद्धा, प्रेम और हृदय की गहरी अनुभूति सबको ठुकरा कर पैसे के पीछे अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। उसके विश्वासघात ने ऊंचे कलाकार के कोमल हृदय को चूरचूर कर दिया है।

एक बात हमें अवश्य कहनी है। यद्यपि लेखक ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में पूंजीवादी युग को कोसा है, तथापि वस्तुतः उपन्यास में केवल पूंजीवाद नहीं, मानवता के तिरस्कार का अधिक वर्णन है। स्वयं उपन्यास का प्रधान नायक जिसके प्रति लेखक पाठक की सहानुभूति खींचना चाहता है, अपनी वृद्धा माता आदि के प्रति अज्ञातव्य उदासीनता का परिचय देकर उसी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखता है। आज के युग का दोष धन के प्रति मोह के साथ-साथ मानवता का तिरस्कार भी है, जिसके अपराधी गरीब अमीर सभी एक समान हैं।

अपनी करनी—ले०--श्री रमेश चौधरी आरिगपूडी। प्रकाशक—वही। पृष्ठ संख्या १२० सजिल्द पृष्ठ २)।

हिन्दी के उपन्यास क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के कलाकार श्री रमेश का अधिकार के साथ प्रवेश यह सिद्ध करने के लिए अच्छा प्रमाण है कि हिन्दी केवल उत्तर भारत की नहीं, भारत के लिए राष्ट्रभाषा है।

सामान्य उपन्यासों से इस उपन्यास का कथानक सर्वथा भिन्न है। इसमें न प्रेम का कथानक है, न किसी ऐतिहासिक कथा का आधार है। विक्षिप्तचित्त सम्पन्न वृद्ध महिला जिसे पुरुष जाति से घृणा हो गई है, जो प्रत्येक व्यक्ति पर अविश्वास करती है, सनकी है, कुछ कुत्तों को लेकर रहती है। वह दूसरे किसी भी व्यक्ति या सम्बन्धी के लिए अत्यन्त कंजूस है। किन्तु कुत्तों को सन्तान से भी प्रेम करती है, उन पर हजारों रु० व्यय कर लेती है। उसके हृदय का परिवर्तन होता है, परन्तु तब, जब वह अपने जीवन के अन्तिम श्वास ले रही है और इसका श्रेय है एक निःस्वार्थ जनसेवक के महान् मानवतापूर्ण सहृदय हृदय को। डा० रंगस्वामी के रूप में लेखक समाज को एक संदेश देना चाहता है।

जादू का दीपक—(अरेबियन नाइटस का संक्षिप्त हिन्दी अनुवाद) प्रकाशक—वही। मूल्य १.५० रु०।

'अरब की एक हजार और एक रातें सम्पूर्ण संसार में अत्यन्त प्रसिद्ध है। जादू की वीरतापूर्ण कहानियां चमत्कार-पूर्ण रोचकता में अपना जोड़ नहीं रखतीं। उन्हीं में से अलीबाबा चालीस चोर आदि कुछ प्रसिद्ध सुन्दर कहानियों को को सरल भाषा व आकर्षक रूप देकर इस पुस्तक में संग्रहीत किया गया है। सभी कहानियां किशोर ही नहीं, वयस्क पाठकों का भी मनोरंजन करेंगी।

जज़्बी—जीवनी और संकलन, प्रकाशक : राजपाल एण्ड संज, दिल्ली, पृष्ठ संख्या ६६, मूल्य डेढ़ रुपया।

अहमद नदीम कासमी—जीवनी और संकलन, प्रकाशकः वही पृष्ठ संख्या १०४, मूल्य डेढ़ रुपया।

कभी उर्दू भाषा का समूचे भारत में, विशेषकर उत्तरी भारत में बोलबाला था। समय की गति के साथ उसकी महत्ता को भी ठेस लगी। चाहे राजनीतिक दृष्टि से उर्दू का पूर्ववत् सम्मान न रह गया हो, परन्तु इसकी शायरी में आज भी वही जान है, श्रोताओं को झिंझोरने की शक्ति है। हिन्दी-साहित्य पर भी उर्दू काव्य का अभूतपूर्व प्रभाव है, यद्यपि हिन्दी में उर्दू काव्य जैसी जिन्दादिली, फड़कन और आवेश अभी तक नहीं आ पाया है, तथापि आज का प्रत्येक जागरूक हिन्दी पाठक उर्दू काव्य का भी यत्किंचित ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, इस प्रवृत्ति से इन्कार नहीं किया जा सकता।

राजपाल एण्ड सन्ज ने अपनी सीरीज़ 'उर्दू के लोक-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रिय शायर' के द्वारा इस प्रवृत्ति को बहुत सीमा तक परितोष दिया है, यद्यपि इस प्रयास को अंतिम और सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता। उपर्युक्त दोनों पुस्तकें इसी सीरीज़ के दो पुष्प हैं। जज़्बी का उर्दू साहित्य में अच्छा स्थान है। उनका काव्य उनके जीवन की असह्य परिस्थितियों की एक लम्बी कहानी है। यद्यपि कुछ आलोचक उन्हें निराशावादी कवि सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, तथापि उनके काव्य में जीवन के प्रति गहरी आस्था है और संघर्षों से जूझ जाने की शक्ति। 'मरने की दुआयें क्यों मांगू' में उनका अपूर्व जीवन-विश्वास है।

इसी प्रकार 'कासमी' का काव्य भी जीवन की यथार्थ परन्तु ऊबड़-खाबड़ धारा के मानस पर लहलहाता हुआ वह पौदा है, जिसमें फलने-फूलने की साध है और पल्लवित रहने की असीम तमन्ना। आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान उनके काव्य की आधार-शिलाएं हैं।

उपर्युक्त पुस्तकों में इन कवियों का संक्षिप्त परिचय है और उनके कुछ चुने हुए काव्य-अंश हैं। फुट नोट में कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। इनसे साधारण पाठक भी सहज ही काव्य-रस प्राप्त कर सकता है। यह 'सीरीज' इस दिशा में अभी तक का सर्वोत्तम प्रयास है। प्रकाशक और संपादक इस प्रयास के लिए निःसंदेह बधाई के पात्र हैं।

प्राप्ति स्वीकार

१. भारत का आर्थिक भूगोल व आर्थिक विकास—ले० श्री जे० आर० कुम्भट और श्री एच० एन० पुरोहित। प्रकाशक—गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा। मूल्य ६)।

२. सरल अर्थशास्त्र—ले० सर्वश्री रामशरण गुप्त, श्री ए० वी० भट्टाचार्य और जे० एन सिंहल। प्रकाशक वही मूल्य ६)।

३. भारत की अर्थव्यवस्था—ले० श्री सत्यदेव देशश्री। प्रकाशक—लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा। मूल्य ४)।

४. लहरों से पूछिये—ले० श्री प्यारेलाल 'बेदिल' प्रकाशक—भारती साहित्य मन्दिर, फुव्वारा, दिल्ली। मूल्य ६)।

क्वालिटी मिनरल सप्लाई सिण्डिकेट

सब प्रकार के मिनरल्स के विश्वस्त व्यापारी

ठिकाना—

४४, ओल्ड कस्टम हाउसरोड, फोर्ट, बम्बई-१

तार का पता—SYMPATHY, Bombay.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब द्वारा खाद्य-मोर्चे पर संघर्ष

श्री हरबंसलाल, कृषि उपमंत्री, पंजाब

पंजाब का इस समय वार्षिक कृषि उत्पादन ६० लाख टन है। यह उत्पादन द्वितीय योजना के लिए जो लक्ष्य रखा गया है, उससे लगभग एक लाख टन अधिक है।

पंजाब राज्य में कुल ३,०३,००,००० एकड़ भूमि है। इसमें से २१,००,००० एकड़ कृषियोग्य बेकार भूमि और ७८,००,००० एकड़ भूमि ऐसी है, जिसमें अकृषि-पदार्थ बोए जाते हैं या बेकार या बिना कृषि के पड़ी है। १३,००,००० एकड़ भूमि परती है और कुल १,८१,००,००० एकड़ क्षेत्र में खेती होती है। इसमें से लगभग ५८,००,००० एकड़ क्षेत्र में वर्ष में एक बार से अधिक खेती हुई। इस प्रकार वर्ष १९५७ में कृषि के अधीन २,३९,००,००० एकड़ क्षेत्र हो गया। वर्ष १९५६-५७ में कुल सिंचित क्षेत्र ७६,००,००० एकड़ क्षेत्र था। यह सारे कृषिगत क्षेत्र का लगभग ४० प्रतिशत है। पंजाब की १ करोड़ ६० लाख से अधिक की आबादी में से १ करोड़ ३० लाख व्यक्ति गांवों में रहते हैं और लगभग १ करोड़ १० लाख व्यक्ति (कुल आबादी का ६६ प्रतिशत) प्रमुखतः कृषि से सम्बद्ध हैं।

विभाजन से कृषि उद्योग को बड़ा भारी आघात पहुँचा है। हमारा नहरों द्वारा सिंचित उत्पादक क्षेत्र (लगभग ७९ प्रतिशत) पाकिस्तान में रह गया और कम उपजाऊ क्षेत्र पूर्वी पंजाब के हिस्से में आया। हमारी पैदावार कम हो गई और ७७,००० हजार टन खाद्यान्नों का बाहर से आयात करना पड़ा। हमें खाद्यान्नों में ही हानि नहीं उठानी पड़ी, अपितु कपास में और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हमारा तकरीबन ८० प्रतिशत कपास उत्पादक क्षेत्र और लगभग साढ़े ९६ प्रतिशत अमरीकन कपास का क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में रह गया। हमारी सारी ही नहरी बागानी बस्तियां में पाकिस्तान में रह गईं। यहां तक कि सरकारी कृषि कालेज और प्रमुख अनुसंधान संस्थान भी पाकिस्तान के भाग में आए।

प्रथम योजना

प्रथम योजना में कृषि विकास कार्यक्रम को सर्वप्रमुख स्थान दिया गया और कृषि विकास को ही देश की आर्थिक प्रगति की बुनियाद माना गया। पहली योजना में कृषि उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इनमें निम्नलिखित कार्यक्रम थे : प्रमुख सिंचाई योजनाएं, छोटी सिंचाई योजनाएं, खाद एवं रासायनिक खादों की सप्लाई, कृषि के उन्नत औजारों का निर्माण और वितरण।

राज्य में वर्ष १९५०-५१ के मध्य विभिन्न कृषि पदार्थों का उत्पादन स्तर निम्नलिखित रूप से रहा :

खाद्यान्न ३२.४५ लाख टन, कपास ३.७१ लाख गांठें, गन्ना (गुड़) ४.४ लाख टन और तिलहन १.०९ लाख टन।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त उत्पादन के लिए निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए :

खाद्यान्न ६.४९ लाख टन, कपास २.३ लाख गांठें, गन्ना (गुड़) ०.७७ लाख टन और तिलहन ०.०८ लाख टन।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में संतोषजनक सफलता प्राप्त हुई। न केवल सारे लक्ष्य ही प्राप्त कर लिए गए, वरन् कइयों में तो लक्ष्य से भी अधिक सफलताएं प्राप्त की गईं। वस्तुतः कृषि उत्पादन में साढ़े १३ लाख टन की वृद्धि हुई जबकि लक्ष्य साढ़े ६ लाख टन निर्धारित किया गया था। कपास-उत्पादन में भी विशेष वृद्धि हुई और उत्पादन लगभग दुगना हो गया। गन्ने और तिलहनों के उत्पादन में भी क्रमशः २७ और ३० प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई।

द्वितीय योजना

द्वितीय योजना में विभिन्न कृषि पदार्थों का जो स्तर निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार है :

खाद्यान्न ५९.४१ लाख टन, कपास १०.५० लाख गांठें, और गन्ना (गुड़) ७.८ लाख टन तथा तिलहन १.८५ लाख टन।

वर्ष १९५५-५६ में जो सफलताएं प्राप्त की गई थीं

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उनकी तुलना में ये लक्ष्य खाद्यान्नों में ३२ प्रतिशत, कपास म ७० प्रतिशत, गन्ने गुड़ में ४० प्रतिशत, और तिलहनों में ३४ प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। योजना के प्रथम तीन वर्षों में जो सफलताएं प्राप्त की गई हैं, वे बड़ी उत्साह वर्धक हैं। वर्ष १९५७-५८ के मध्य ५४.३३ लाख टन खाद्यान्नों का, ८.२५ लाख गांठें कपास का, ६.०७ लाख टन गन्ने (गुड़) का और १.७० लाख टन तिलहनों का उत्पादन हुआ। अर्थात् सब कृषि-पदार्थों के उत्पादन में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु केवल तिलहनों में १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष १९५८-५९ में कृषि-उत्पादन रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया, अर्थात् ६०.७८ लाख टन तिलहनों का भी उत्पादन हुआ और इस प्रकार दो वर्ष पूर्व इन पदार्थों के लिए जो लक्ष्य रखे गए थे, वे लगभग पूरे कर लिए गए। परन्तु कपास की फसल को पिछले कुछ वर्षों में हानि पहुंची।

तृतीय योजना का प्रारूप

राज्य ने कृषि की तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए ५.७४ करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाई गई थीं।

इस प्रारूप में कृषि विकास के सारे पहलू आ गए हैं। इसके साथ ही इसमें सुधरे हुए बीजों का वितरण और विस्तृत परिमाण में रासायनिक खादों के वितरण तथा पौध सुरक्षण कार्य को लोक प्रिय बनाने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी प्रस्ताव है कि बंजर भूमियों को विस्तृत रूप से कृषि के अधीन लाया जाए जिससे कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो।

इसके साथ ही इस प्रारूप में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की भी बड़े पैमाने पर व्यवस्था है। इस बारे में सर्व प्रमुख बात ग्राम अर्थात् कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। इस योजना में सारी ही अनुसंधान शाखाओं की वृद्धि एवं विकास किया जाएगा जिससे समय की मांग पूरी की जा सके।

कृषि सम्बन्धी तृतीय योजना की एक प्रमुख विशेषता चुने हुए क्षेत्रों में परीक्षात्मक रूप से कृषि बीमा योजना का चालू करना भी है। इसके अतिरिक्त आधुनिकतम प्रणाली से कृषि करने के बारे में कृषकों को जानकारी पहुँचाने की भी व्यवस्था की जाएगी।

तृतीय योजना की सम्पन्नता पर विभिन्न कृषि पदार्थों का उत्पादन स्तर निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया गया है :

खाद्यान्न ७४ लाख टन, गन्ना (गुड़) ९ लाख टन, कपास १३ लाख गांठें, तिलहन २.५० लाख टन, फल ५.६० लाख टन और सब्जियां १२.५० टन।

अधिक अन्न उगाओ आन्दोलन

पंजाब के लिए यह प्रशंसा की बात है कि इस राज्य ने भारत सरकार से ५०,००० रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है। वर्ष १९५८-५९ में जो विगत ३ वर्षों की रबी फसलों के औसत उत्पादन में २४ प्रतिशत की वृद्धि की गई। यह पुरस्कार उसी उपलक्ष्य में राज्य को प्राप्त हुआ है।

इसी प्रकार अनावृष्टि एवं दुर्भिक्ष के लिए प्रसिद्ध हिसार जिले ने अपने उत्पादन में १५ प्रतिशत की वृद्धि करके जिलों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। हिसार ने यह स्थान अपनी रबी फसल के उत्पादन में ६४ प्रतिशत की वृद्धि करके प्राप्त किया और इसे 'राज्य कलश' की उपाधि दी गई। इस वर्ष राज्य के सारे ही ११ जिलों को १०-१० हजार रुपए का पुरस्कार मिला। इन पुरस्कारों का प्रयोग इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

प्रतिदिन हमारी डाक में

सहकारी कृषि अंक

के लिए आर्डर आ रहे हैं, क्योंकि इस सामयिक महत्वपूर्ण प्रश्न के विविध पहलुओं पर निष्पक्ष दृष्टि से एक साथ प्रामाणिक जानकारी अन्यत्र मिलनी असंभव है।

हमें सन्देह है कि हम एक महीने के बाद हम नई मांग पूरी कर सकेंगे। इसलिए आप जल्दी ही रु. १.७५ भेजकर यह अंक मंगालें। रजिस्ट्री से .५० न. पै. अतिरिक्त व्यय होगा।

—मैनेजर
'सम्पदा' अशोक प्रकाशन मन्दिर
२८/११ शक्तिनगर दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी मुद्रा और विदेशी सहायता

श्री मुरारजी देसाई, वित्तमंत्री, भारत सरकार

भारत जैसे कम विकसित देशों को विदेशी भुगतान का जो टोटा पड़ रहा है, वह अस्थायी या दो चार दिन की कठिनाई नहीं है, बल्कि हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद वह तब तक बनी रहेगी, जब तक हमारे देश में उद्योगों का कुछ विकास नहीं हो जाता और माल का बनना और निर्यात होना काफी नहीं बढ़ जाता। उद्योगों में अधिक बढ़े हुए देशों में इधर जो और आर्थिक उन्नति हुई है, वह उन देशों के लिए तो शुभ है ही, उससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ेगा और कम विकसित देशों की पूंजी और पूंजीगत सामान भी निर्यात होगा। पर उससे विकास में लगे देशों का काम कुछ सरल नहीं हो जाता।

जितना ध्यान अधिक विकसित देशों की विदेशी विनिमय की अस्थायी कठिनाइयों पर दिया जा रहा है, उतना ही अल्प-विकसित विदेशी भुगतान की कठिनाई पर भी देना चाहिए, जो कि अभी काफी समय तक बनी रहेगी।

पिछली ब्रिटेन की यात्रा से मैंने जो निष्कर्ष निकाला वह यह है कि ब्रिटेन में जो आर्थिक स्थिरता और शक्ति बढ़ रही है, वह हमारी योजनाओं के लिए शुभ है। ब्रिटेन से राष्ट्रमंडल के देशों में काफी पूंजी जा रही है और इस रुख के और भी जोर पकड़ने की आशा है।

वाशिंगटन में कोष-बैंक की बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना का निश्चय हुआ, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने प्रस्तुत किया था। इस संबंध में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि इस संघ का मुख्य उद्देश्य कम विकसित देशों को ऐसी शर्तों पर और काफी रुपया देना होना चाहिये जिससे आगे उनके भुगतान संतुलन पर अधिक बोझ न पड़े।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विचारवान् लोग विकास की समस्याओं में रुचि लेते हैं और चाहते हैं कि अमेरिका इस कार्य में दूसरों की मदद करे। मैंने यह भी देखा कि अमेरिका में भारत की योजनाओं और समस्याओं को लोग पहले से कहीं अधिक समझते हैं।

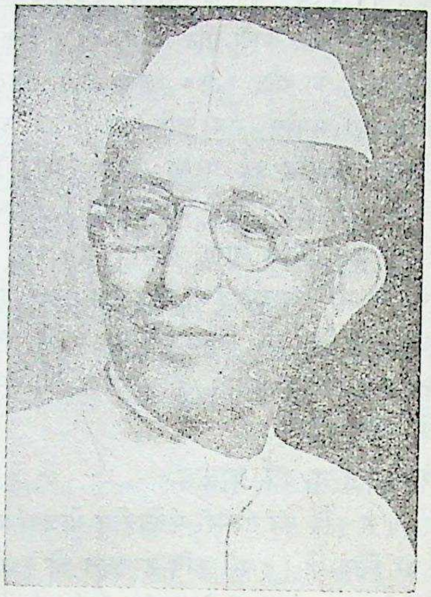

— लेखक —

स्वभावतः लोगों ने हमसे पूछा कि निजी उद्योग के प्रति और विदेशी लोगों के भारत में रुपया लगाने के बारे में हमारा क्या रुख है और आगे इसकी भारत की गुंजायश है। मैंने विदेशी निजी पूंजी के बारे में अपनी नीति समझाई और बताया कि हमने अपने देश में पूंजी लगाने वाले विदेशियों को अपना मुनाफा और अपनी पूंजी अपने देश भेजने या ले जाने के बारे में क्या सुविधा और आश्वासन दिये हैं। हम यह चाहते हैं कि जो भी विदेशी पूंजी हमारे देश में लगायी जाय, उससे हमारी योजना में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हो। हमारे देश में देशी और विदेशी उद्योग या कारखानों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। पूंजी लगाने या उद्योग स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए हमने करों में जो रियायतें दी हैं वे देशी और विदेशी दोनों प्रकार के लोगों को समान रूप से दी जाती हैं, परन्तु मैंने यह भी बताया कि विदेश के निजी लोगों के पूंजी लगाने की भी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक सीमा स्वाभाविक है और इसलिए इसकी जरूरत है कि दूसरे देशों की सरकार हमारे देश की सरकार को सहायता दे। राष्ट्रीयकरण को हम मतवाद के रूप में नहीं मानते। इसलिए इसका कोई अलग कार्यक्रम नहीं है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सार्वजनिक हित में आवश्यक होने पर किसी खास उद्योग का राष्ट्रीयकरण न किया जाय। राष्ट्रीयकरण करने पर मुआवजा दिया जायगा। विदेशी पूंजी लगाने वालों को और भी आश्वस्त करने के लिए भारत सरकार दूसरे देशों के साथ, ऐसा समझौता करने को राजी है कि बिना पूरा मुआवजा दिये उनके कारबार पर कब्जा नहीं किया जायगा।

विदेशी विनिमय

हमारे विदेशी विनिमय की स्थिति निम्नलिखित है। १३ नवम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाले सप्ताह में हमारा पौण्ड पावना २०२ करोड़ था जबकि पिछले वर्ष अर्थात् १४ नवम्बर १९५८ को यह १८४ करोड़ ८० लाख था। इससे स्पष्ट होता है कि १९५७ में और १९५८ के अधिकांश में हमारे विदेशी पावने में जो कमी तेजी से हो रही थी, उसे हमने रोक दिया है, साथ ही हमारी योजना का काम भी चालू रहा। हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने बढ़े हुए हिस्से की अदायगी में २४ करोड़ रु० का सोना दे दिया है, जो कि उसके लिए रिजर्व बैंक नागपुर के तहखाने में रखा है। अवश्य ही हमने अपने आयात पर कड़ी रोक लगायी है और हमारी जनता ने भी इस काम में हमसे सहयोग किया है।

पर अभी हमें अपने प्रयत्नों में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देनी है। विदेशी भुगतान में जो संतुलन हुआ है यह केवल हमारे ही प्रयत्नों से नहीं, बल्कि हमारे मित्र देशों और संस्थाओं की उदार आर्थिक सहायता से भी संभव हुआ है। ३० सितम्बर १९५९ तक पिछले १२ महीनों में हमने करीब २४१ करोड़ रुपये दूसरे देशों से लिये हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हमें जिन्स की भी सहायता दी है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमें ९०८ करोड़ रु० की विदेशी सहायता के पक्के वायदे मिले हैं। इस संख्या में पी० एल० ४८० की सहायता शामिल नहीं है जिसका परिमाण ४३२ करोड़ ६० लाख रु० है। अक्टूबर, १९५९ तक हमने ४५८ करोड़ रु० लिये हैं और आशा है कि दूसरी योजना की शेष अवधि में हम ३२२ करोड़ रु० विदेशी सहायता और लेंगे। इससे ३१ मार्च, १९६१ के आगे के लिए १२८ करोड़ रु० की रकम विदेशी सहायता राशि से बच रहेगी। इसका कारण यह है कि कुछ ऐसी योजनाएं जिनके लिए कुछ देशों ने विशेष सहायता दी है, ३१ मार्च, १९६१ तक पूरी नहीं होंगी और वे तीसरी योजना में भी चालू रहेंगी। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं: जापान और अमेरिका की सहायता से कच्चा लोहा निकालने और निर्यात करने की योजना, कोयना जल-बिजली और कलकत्ता तथा मद्रास बंदरगाह विकास योजनाएं जो विश्व बैंक की सहायता से पूरी होंगी, और सोवियत रूस की सहायता से बनने वाला मशीन निर्माण कारखाना। जो सहायता निर्दिष्ट कार्यों के लिये दी जाती है वह दूसरे कामों में नहीं लगायी जा सकती, न इसमें कोई लाभ ही है। पूरी सहायता का उपयोग न होने का एक कारण यह भी है कि कुछ सहायता इसी शर्त पर दी गयी है कि उससे उन्हीं देशों में माल खरीदा जाय। इसके साथ ही हमारी भी यह नीति है कि हम बहुत जरूरी योजनाओं के लिए ही विदेशी सहायता का उपयोग करें और किसी भी देश में माल खरीदते समय यह देख लें कि और जगह से वहां दाम ज्यादा तो नहीं हैं। इसलिए यह निश्चय करने में कि कौनसे काम जरूरी हैं और दाम जांचने और तय करने में समय लगता है तथा इसीलिए खरीद का आर्डर देने में देर लगती है।

हमारे विकास कार्यों की गति बहुत तेज हो गयी है। इस कारण १९६०-६१ में हमें निर्यात से जितनी आमदनी होगी और विदेशी सहायता से जितना रुपया मिलेगा उससे करीब १४० करोड़ अधिक रुपया हमें दूसरे देशों को चुकता करना पड़ेगा। अतः हमें इतनी रकम की विदेशी सहायता अपनी दूसरी योजना के लिये और चाहिये। जो देश हमें सहायता दे रहे हैं उन्हें हमारी जरूरत बता दी गयी है। गत वर्ष मार्च महीने में वाशिंगटन में हमारे सहायक देशों की जो बैठक विश्व-बैंक के तत्वावधान में हुई, उससे हमें यह इशारा मिला कि हम अपने विकास कार्यों को चालू रख सकते हैं और अपनी जरूरत भर विदेशी सहायता हमें उपलब्ध हो सकेगी। दूसरी योजना की शेष अवधि में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रूस में कृषि का पूर्णतः यंत्रीकरण

सोवियत रूस कृषि के यंत्रीकरण की दिशा में बड़ी छलांगें मार रहा है।

संसार का पहला स्वचालित ट्रैक्टर कज़ाख़स्तान में इस साल के लिए निश्चित परीक्षाओं में से गुजरा। शरद ऋतु की जुताई में एक साथ बारह स्वचालित क्रालर ट्रैक्टरों की परीक्षा की गई थी। उन पर कण्ट्रोल करने वाला कोई नही था—केवल एक ट्रैक्टर ड्राइवर उन्हें पूरी दूरी तक चले जाने पर मोड़ने के लिए था।

लोजीनोव द्वारा बनाये गये स्वचालित दूर नियंत्रण यंत्र कटाई की परीक्षाओं में भी सफल उतरे हैं। एक राजकीय फार्म पर मिस्त्री कोन्स्टैंटिन इन्फेंडोपुलो ने १२०० हैक्टर क्षेत्र पर गेहूँ काटा, पर ट्रैक्टर का नियंत्रण एक स्टैंडर्ड हार्वेस्टर कम्बाइन के ब्रिज से बटन दबाकर किया।

९५ प्रतिशत शक्ति मशीनों से

रूस के कुल खेतों में लगने वाली शक्ति १५ करोड़ अश्व शक्ति हार्स पावर है। लेकिन इसमें ६० लाख एकड़ अश्व शक्ति अर्थात् केवल ४ प्रतिशत शक्ति घोड़ों आदि पशुओं से ली जाती है। शेष १४ करोड़ ४० लाख अश्व शक्ति मोटरों, कम्बाइनों व ट्रैक्टरों के रूप में प्रयुक्त होती है। मोटर रूस के कृषकों के जीवन का एक आवश्यक शक्ति बन गई है।

कृषि के सब कठिन कार्यों में यंत्रीकरण के लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं। १९५९ से १९६५ तक के सात वर्षों में १० लाख से अधिक नये ट्रैक्टर ४ लाख अनाज कटाई यंत्र तथा बहुत सी अन्य मशीनें प्राप्त होंगी।

राजकीय फार्मों का खेती वाला क्षेत्र ५.३ करोड़ हैक्टर है। (सोवियत संघ में खेती का कुल क्षेत्र १९.५६ करोड़ हैक्टर है)। इन फार्मों के पास (१५ अश्व शक्ति इकाइयों के रूप में) ५,३८,००० ट्रैक्टर, १६८,००० हारवेस्टर कम्बाइन तथा १,४०,००० ट्रक हैं। औसतन प्रत्येक फार्म के पास १९४० के युद्ध के पहले के वर्षों की अपेक्षा ४ से ५ गुना अधिक विविधता वाली मशीनें हैं।

१९६५ तक और मशीनों के प्रयोग द्वारा श्रम उत्पादकता ६० से ६५ प्रतिशत तक और बढ़ जाएगी।

किन्तु यह यंत्रीकरण कितनी ही आकर्षक और रूस के लिए लाभकारी क्यों न हों, भारत के लिए उपयोगी नहीं हो सकेगा। यहां भूमि कम और किसान बहुत ज्यादा है। गौ बैल भी यहाँ अनिवार्य रूप से रखने होंगे। उनकी शक्ति को व्यर्थ जाने देना राष्ट्र की बड़ी भारी हानि होगी।

विश्व-बैंक और जर्मनी से हमें जितनी सहायता मिलने वाली है, उसका अंदाज भी हमें लग गया है। अगले साल के शुरू में हम उन देशों से करार की बातचीत करेंगे जो हमें १९६०-६१ में सहायता देंगे। सब मिलाकर मुझे आशा है कि हम अपनी दूसरी योजना के मुख्य अंश को पूरा करने के लिये अपने मित्रों की सहायता पर भरोसा कर सकते हैं। परन्तु साथ ही हमें अगले कुछ महीनों में विदेशी मुद्रा खर्च करने पर कड़ा अंकुश रखना पड़ेगा।

अभी तो हम तीसरी योजना तैयार करने में लगे हैं और इसकी रूपरेखा बनाने में कुछ समय लगेगा। फिर भी यह स्पष्ट है और दूसरे देश भी इसे समझते हैं कि तीसरी योजनाके लिए हमें काफी अधिक सहायता की दरकार होगी और इसे चुकाने के लिए भी हमें लम्बी मियाद चाहेगी।

सब मिलाकर जहां तक कहना संभव है मैं कह सकता हूं कि तीसरी योजना के लिए मुझे विदेशी सहायता मिलने की अच्छी आशा है। यह सहायता हमारी जरूरत भर होगी या नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी हमारी जरूरतों का ही पक्का अंदाज नहीं लगाया गया है। परन्तु एक बात साफ है और वह यह कि हमारी तीसरी योजना, और हमारी सभी योजनाओं की सफलता इस पर निर्भर है कि हम अपने देश में स्वयं कितने साधन जुटा सकते हैं। यही हमारी मुख्य समस्या है और इस समय हमारा मुख्य ध्यान इसी बात पर होना चाहिये कि हम अपनी योजना के लिए अपने देश में ही किस प्रकार साधन जुटाएं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वयं चालित कम्बाइन

रात में चुकन्दर उखाड़ना खेती के लिए नयी चीज है है। परन्तु यह जानकर और भी अचरज होता है कि यह कम्बाइन अपने आप काम करता है। कोई उसे चलाने या देखरेख करने के लिए नहीं है।

इस साल यूक्रेन के निप्रोपेत्रोव्स्की खेती मशीन कारखाने ने कई सौ ऐसे स्वयं चालित चुकन्दर फसल कटाई कम्बाइन बनाये। ये कम्बाइन पहले के बने कम्बाइनों से इस पर भिन्न हैं कि ये कम्बाइन बिना चालक के काम करते हैं। कम्बाइन एक विशेष विधि, हाइड्रोजन कापींइंग विधि के द्वारा अपने आप चुकन्दर की कतारों में अपनी दिशा पा लेता है। चालक की जरूरत तब पड़ती है जब कम्बाइन को मुड़ना होता है और नई कतार में काम शुरू करना होता है।

विश्व व्यापार में पौंड की महत्त्वपूर्ण भूमिका

(यूजिन ब्लैक)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त में पौंड आज भी महत्त्वपूर्ण भाग ले रहा है, और यथार्थतः यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में फिर से स्वस्थ और स्फूर्त्तिमय हो गई है।

निम्न तीनों उद्देश्यों से ब्रिटेन ने विश्व बैंक की स्थापना का समर्थन किया था और इस दिशा में सहायता दी। १-दीर्घकालीन पूंजी विनियोग के लिए एक नये स्रोत की व्यवस्था करना, २-ऋण देने की व्यावहारिक रीतियों के पालन से विनियोजित धन पर लाभ कमाना सम्भव है: यह प्रमाणित कर सकने वाले संगठन की स्थापना, तथा ३-(इस प्रकार) समुद्री पार देशों में विनियोग की लाभदायकता और वांछनीयता में निजी विनियोगकर्ता का भरोसा बढ़ाना। उपर्युक्त तीन उद्देश्यों में से प्रथम-दो, और डालर प्राप्ति का और भी एक स्रोत निकालने में सहायता देना भी एक उद्देश्य था। ब्रिटेन का इस सम्बन्ध में आयोजन, आशातीत सफलता का परिचय देता है।

स्वर्ण और डालर के रूप में दिए गये अंशदान सहित, विश्वबैंक के लिए ब्रिटेन का कुल अंशदान ६,३०,००,००० पौंड बैठता है। इसके अतिरिक्त, ६,००,००,००० पौंडों की प्राप्ति राष्ट्रकुल के विविध स्वशासी सदस्यों से इसी ढंग से होने की आशा विश्व बैंक कर सकता है।

स्वशासी देशों को मिले ऋण कुल ४६,००,००,००० पौंड बनते हैं। अस्वाधीन देशों द्वारा लिये गये ऋणों की राशि को हम अतिरिक्त ७,००,००,००० पौंड पाते हैं। इस प्रकार, हम देखते हैं कि विश्व बैंक से राष्ट्रकुल को मिले हुए ऋणों की कुल राशि ५३,००,००,००० पौंड बनती है, जो विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों की तृतीयांश बैठती है।

महान व्यवसायी मि. गैमन

ब्रिटेन की गैमन इंडिया लिमिटेड अनेक नयी निर्माण विधियों में अग्रणी रही है, तथा भारत के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार के टावरों और विद्युत स्टेशनों का निर्माण कर चुकी है। इस समय वह अन्य निर्माण कार्यों के अतिरिक्त कोई ८० पुलों को भी बना रही है, जिनमें एक चम्बल पर बनाया जा रहा है। यह पुल एशिया का सबसे लम्बा पुल होगा।

बम्बई के निकट ट्राम्बे स्थित अणु-शक्तिअधिष्ठान में ४०० फुट ऊंचे गोलाकार तालाब का निर्माण भी यही कम्पनी कर रही है। एक जर्मन कम्पनी की भागीदारी में यह कम्पनी रूरकेला, उड़ीसा, में बन रही नयी इस्पातशाला में भी निर्माण कार्य कर रही है। पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर और बर्नपुर में यह २५० फुट ऊंची इस्पात ठंडा करने वाली मीनारों का निर्माण कर रही है। इस कम्पनी के अन्तर्गत अनेक कम्पनियां भारत तथा दूसरे देशों में काम कर रही हैं।

अन्य देशों में गैमन कम्पनिया जो कार्य पूरे कर चुकी है या कर रही है उनमें मुख्य हैं: करांची (पाकिस्तान) में एक बन्दरगाह जिससे आवश्यकता पड़ने पर जल निकाला जा सके, हांगकांग में कार्ट टाक हवाई अड्डा, अदन, लिबिया, और सिंगापुर में नये विमानस्थल, फिजी में नया जलयान घाट, नाइजीरिया में सीमेंट कर्मशाला और तम्बाकू के कारखाने, और बहरीन में समुद्र के गहरे पानी तक पहुँचने के लिए एक पुल।

इन सभी कम्पनियों की स्थापना श्री गैमन ने की थी जिन्होंने इन्जीनियर की हैसियत से अपना जीवन ५० वर्ष पूर्व भारत में प्रारम्भ किया था। १६१० में आप भारतीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर हुए। आज ही वे गेटवे आफ इंडिया की नीव बनाने का काम किया था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की वन-सम्पदा

श्री आर० सी० सोनी, वन-महानिर्देशक, भारत सरकार

भारत का २२.३ प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। इन वनों में असंख्य वस्तुएं मिलती हैं, जिनका देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्री सोनी ने इस लेख में इसी वन-सम्पत्ति और उसकी रक्षा तथा विकास की समस्याओं पर प्रकाश डाला है।

भारत में वनों की सदा बहुतायत रही है, किन्तु जनसंख्या के निरन्तर बढ़ने, खेती के लिए जमीन की मांग बढ़ने और बिना सोचे-समझे जंगलों को काट डालने से हमारी यह सम्पत्ति धीरे-धीरे क्षीण होती गयी है। जो जंगल बचे हैं, वे या तो ऐसी जगह पर हैं, जहां मनुष्यों का पहुँचना सम्भव नहीं, या ऐसे क्षेत्रों में हैं, जिनका जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है; तराई इसी तरह का एक क्षेत्र है।

भारत के भौगोलिक क्षेत्र के २२.३ प्रतिशत भाग पर वन उगे हुए हैं और देश की ३६ करोड़ २० लाख आबादी के हिसाब से प्रतिव्यक्ति इनका औसत क्षेत्र ०.५ एकड़ बैठता है। इसके मुकाबले अमेरिका में वनों का प्रतिव्यक्ति क्षेत्र ४.५ और रूस में ९ एकड़ है।

तरह-तरह की वनस्पति का भंडार

हमारे जंगलों में भांति-भांति की वनस्पति उगती हैं और इस दृष्टि से भारत के वन बहुत समृद्ध हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में बर्मा की सीमा से लगते हुए वर्षा-बहुल क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक में विविध भांति के वृक्ष, झाड़ियां और बेलें मिलती हैं। इनमें से करीब आधे वृक्ष ऐसे हैं जिनकी लकड़ी इमारतों आदि में काम आती है। भारत में मुख्य रूप से साल सागवान, और चीड़ तथा देवदार आदि के पेड़ उगते हैं। साल पहाड़ों के निचले हिस्सों और देश के मध्यवर्ती भाग में उगता है। सागवान देश की सबसे मूल्यवान लकड़ी है और इसके पेड़ देश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में होते हैं। इसके अलावा शीसम, आसना, हल्दू, रोजवुड, पडोक, जामन, और चन्दन आदि अनेक जाति के उगते हैं। बहुत से पेड़ों या उनसे निकली हुई चीजों से छाल, लाख, सुगन्ध तेल, चमड़ा बनाने की चीजें, कत्था, दवाएं आदि मिलती हैं। इनके अलावा जड़ी बूटियां, बेंत, रेशे और कई तरह के तेल आदि भी वनों से प्राप्त होते हैं।

उत्पादन के लिहाज से हमारे वन दो भागों में बांटे गये हैं। एक, वे जिनकी लकड़ी आदि चीजों का सब उपयोग करते हैं और दूसरे, वे जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकता। पहली किस्म में ८२ प्रतिशत या कुल २,२८,७६१ वर्ग मील के जंगल आ जाते हैं। इस तरह के जंगलों में प्रायः ऐसे वन हैं, जिनमें नुकीली पत्तीदार पेड़ नहीं होते। देश में लगभग ८५ अरब ६९ करोड़ ६० लाख घनफुट लकड़ी होने का अनुमान है। इसमें से ८० अरब ३ करोड़ २० लाख घनफुट (९३ प्रतिशत) लकड़ी उन वृक्षों की है, जिनके पत्ते चीड़ या देवदार की तरह सुई जैसे नुकीले नहीं होते। बाकी ५ अरब ६६ करोड़ ४० लाख घनफुट या ७ प्रतिशत पेड़ नुकीली पत्ती वाली नस्ल के हैं।

वन-उपज

जंगलों से भारत को प्रतिवर्ष ३४ करोड़ ३० लाख रु० की लकड़ी मिलती है, जिसमें से ३ करोड़ ४० लाख रु० की नुकीली पत्ती वाले पेड़ों की होती है और ३० करोड़ ९० लाख रु० की दूसरी तरह के पेड़ों की। इसी प्रकार वनों से १२ करोड़ १० लाख रु० की बांस, बेल, राल, रेशे और दूसरी चीजें प्राप्त होती हैं। देश को वनों से प्रतिशत ४६ करोड़ ४० लाख रु० की आमदनी होती है और इन पर प्रतिवर्ष ९ करोड़ ४० लाख रु० खर्च होता है। इस प्रकार २७ करोड़ का शुद्ध लाभ होता है। इस राशि को वन के प्रति एकड़ क्षेत्र पर फैलाने से २.६० रु० बैठता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ-वृत्त चयन

विविध देशों में उत्पादन

नीचे की तालिका में कोलम्बो क्षेत्र के सब देशों में १९५६ से १९५८ तक के कुछ खास-खास वस्तुओं के उत्पादन-आंकड़े दिये गये हैं :

(हजार मीट्रिक टनों में)

	१९५६	१९५७	१९५८
चावल	९३,१७२	८३,५९०	९३,१८८
गेहूँ	१२,०८५	१२,८५६	१३,६९५
मक्का	६,३५३	६,६२३	६,४९२
तम्बाकू	६३४	६४५	प्राप्य नहीं
चाय	५३९	५५१	५८०
रुई	१,२५८	१,२७०	१,३७८
चीनी	३,९९८	४,७५६	४,३५६
रबड़	१,५९८	१,६११	१,५७१
खनिज लोह	८,२३२	९,०६०	९,७५०
टेट्रोल (बिना साफ हुआ)	१३,६०८	१६,५८४	२२,१४०
टीन	१०८	१०४	७२
कोयला	४१,७६३	४५,५६४	४७,४९२
सीमेंट	६,८०२	७,८१६	८,४९१
बिजली (बिलीयन किलोवाट)	१३,५००	१५,२००	१५,९००
इस्पात	१,७७६	१,७५९	१,८५२
सूती धागा	९९७	९५४	९२३
सूती कपड़ा (बिलियन मीटरों में)	५,३८२	५,४१६	५,१०५

मत्स्य-उद्योग से विदेशी मुद्रा

यद्यपि देश की एक बड़ी जनसंख्या मांसाहार को पाप और अभक्ष्य मानकर इससे घृणा करती है, तथापि देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा भाग है। इसी कारण भारत सरकार मत्स्य-उत्पादन को बहुत महत्त्व देती है।

केन्द्रीय खाद्य और कृषिमंत्री, श्री सदाशिव कान्होजी

वन उद्योग

देश के बहुत से उद्योग वनों पर ही निर्भर हैं। देश भर में २,७५० लकड़ी चीरने की मिलें हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता ८ करोड़ घनफुट लकड़ी की है और जिनमें लगभग ३० हजार लोग कामकरते हैं। १३८ दियासलाई कारखाने चलते हैं, जिनमें ६० लाख घनफुट मुलायम लकड़ी काम आती है और लगभग २५ हजार व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। इनके अलावा, प्लाईवुड के ६६ कारखाने, कागज और लुगदी के २१ कारखाने, पेन्सिल के १७ कारखाने भी वनों पर ही निर्भर हैं। इन कारखानों से भी कई हजार आदमियों की जीविका चलती है। कत्थे, राज, गोंद, बेंत इत्यादि के कामों में भी हजारों लोग लगे हुए हैं।

इतना ही नहीं, देश के लगभग ३ करोड़ २० लाख पशु भी वनों पर ही पलते हैं। जंगली पशु-पक्षियों के लिए तो भारत जगत् विख्यात है। हाथी, शेर, चीते, गेंडे, सांभर, जंगली भैंसे, चीतल, कस्तूरी मृग आदि पशु और भांति-भांति के पक्षी हमारे वनों की शोभा हैं। वनों की झीलों, तालाबों और नदियों में मछलियां और मुर्गाबियां आदि भरी रहती हैं। जंगली पशु-पक्षियों की रक्षा के लिए पांच राष्ट्रीय वन (नेशनल पार्क) और ७८ रक्षा वन हैं। इनके अलावा २२ चिड़िया घर हैं।

केवल लकड़ी और वनों की दूसरी चीजों से जो आर्थिक लाभ होता है, उसी तक अपनी दृष्टि सीमित रखना उचित नहीं होगा। भूमि की रक्षा और पानी के अदृश्य स्रोतों के रूप में वनों के कारण जो हमें लाभ होता है, वह तो अवर्णनीय है। यदि वन न हों तो वर्षा का जल भूमि को बुरी तरह काट दे और हमारे कुएं, तालाब, नदी और झरने, एक साथ उफन पड़ें और फिर अगली वर्षा तक तक सूखे पड़े रहें। पेड़ों की जड़ों के साथ-साथ ही पानी भूमि के गर्भ में जाता है, जहां से हम कुएं खोदकर उसे फिर निकाल लेते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि 'वन नदियों की जननी है।' मनुष्य, वृक्ष और जल तीनों मानों अभिन्न तत्व हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पाटिल ने एक भाषण में मत्स्य उत्पादन का महत्त्व बताते हुए बताया है कि यह केवल देश की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि इससे अधिक विदेशी मुद्रा भी पैदा की जा सकेगी। इसलिए तीसरी योजना में मछली-पालन के विकास के लिए ४५ करोड़ रु० की व्यवस्था की जा रही है। इससे हम ८ लाख टन अधिक मछलियां पकड़ सकेंगे और इस तरह १९६६ तक देश में २० लाख टन मछलियां पकड़ी जा सकेंगी।

१९५८ में मछलियों के निर्यात से भारत ने ६ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा कमाई। मछली-पालन के विकास के लिए यदि आवश्यक सुविधाएं दी जाएं, तो यह राशि तीन गुनी हो सकती है।

भारत में बिजली का विकास

१. स्वतंत्रता के बाद ही भारत में ताप-बिजली और पन-बिजली के विकास का काम आयोजित ढंग से शुरू हुआ।

२. पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय में देश में २३ लाख किलोवाट बिजली पैदा होती थी। पहली योजना की अवधि में ११ लाल किलोवाट बिजली और बनने लगी।

३. दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३४ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है और तीसरी योजना में और भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

४. देश में बिजली उत्पादन की मुख्य योजनाएं दामोदर घाटी निगम, हीराकुंड, भाकड़ा-नंगल, कोयना, चम्बल, नागार्जुनसागर, रेंड और शरावती हैं। इनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं और कुछ शीघ्र ही हो जाएंगी तथा कुछ का निर्माण-कार्य शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से मछकुंड, मोयार, बोकारो और पथरी बिजलीघरों में भी बिजली पैदा होने लगी है।

५. पहली योजना के शुरू होते समय ३,००० गांवों में बिजली लगी थी, और इसके अंत में यह संख्या बढ़कर ७,००० हो गयी।

८. दूसरी योजना में १०,००० और गांवों में बिजली लगाने लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने २९ दिसम्बर, १९५९ को दुर्गापुर इस्पात कारखाने की पहली धमन भट्टी का उद्घाटन कर दिया है। यह कारखाना भारत सरकार और ब्रिटेन की फर्मों के संगठन के बीच एक समझौते के अन्तर्गत बनाया जा रहा है। यहां अब लोहा तैयार होना शुरू हो जाएगा। अन्य दो सरकारी कारखानों—राउरकेला और भिलाई—में इस्पात बनाना शुरू हो गया था। दूसरी योजना के अन्त तक इन तीनों में ३० लाख टन इस्पात सालाना बनने लगेगा। ताता इस्पात कम्पनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी और भद्रावती इस्पात कारखाने (मैसूर) में भी ३० लाख टन सालाना इस्पात तैयार करने का लक्ष्य पूरा होगा।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हर साल १० लाख टन इस्पात, ३ लाख ५० हजार टन लोहा और अमोनियम सल्फेट, बेन्जीन, एक्सीलीन, नेफ्थलीन, कोलतार आदि तैयार होगा।

● ●

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की स्वास्थ्य सम्बन्धी श्रेष्ठ मासिक पत्रिका)

'आपका स्वास्थ्य' आपके परिवार का साथी है।

'आपका स्वास्थ्य' अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

'आपका स्वास्थ्य' में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और ग्रामीणों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक

आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीवन बीमा निगम—

गृह निर्माण के लिए सहयोग

कुछ समय से जीवन बीमा निगम इस बात पर विचार कर रहा था कि वह देश में मकानों की भारी कमी की समस्या को हल करने के कार्य में किस प्रकार सहायता कर सकता है। कारपोरेशन प्रांतीय सरकारों को उनकी आवास-योजना के लिए धन देती है, किन्तु बाद में ऐसा महसूस किया गया कि मकान बनाने के लिए ऋण देने के कार्य में "और सक्रिय तथा सीधा योग" निगम के पालिसी-होल्डरों के हित में होगा।

नयी योजना के अनुसार बीमेदारों को ऋण मिलेगा, किन्तु उनके साथ ही साथ सहकारी समितियों और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सबसे चोटी की अर्थ-सहकारी समितियों के मारफत यह ऋण निम्नतर सहकारी समितियों को दिया जावेगा। अपेक्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को ऋण देने की शर्त यह होगी कि राज्य-सरकारों को इस ऋण की गारंटी देनी होगी। इस ऋण के ब्याज की दर ५ रुपये प्रतिवर्ष होगी।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की किसी भी आवास-योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए भारत की पहली गिरवी जायदाद पर यह ऋण दिया जायेगा। कुल जायदाद के ७० प्रतिशत का धन, अधिक से अधिक, इसके अन्तर्गत ऋण के रूप में दिया जायेगा। इस पर ६½ रुपये प्रतिवर्ष प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लिया जायेगा। इस तरह के ऋण की अधिकतम अवधि २० वर्षों की होगी। पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के द्वारा मूलधन तथा सूद की गारंटी मिलने पर इन समितियों को ऋण मिलेगा। उक्त समिति के सदस्य को ऋण की रकम के बराबर जीवन-बीमा करना होगा और उस पालिसी का अभ्यर्पण (एसाइनमेंट) अतिरिक्त सुरक्षा के हेतु, कारपोरेशन के नाम पर करना होगा। इन मियादी पालिसियों की अवधि ऋण की अवधि से अधिक न होगी।

१० लाख से अधिक आबादी वाले नगरों-बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और हैदराबाद में रहने वाले बीमेदारों को ही मकान बनाने के लिए ऋण दिये जायेंगे। इसके लिए अनेक नियम उपनियम बनाये गये हैं, जिसके अन्तर्गत ऋण मिल सकेगा। ● ●

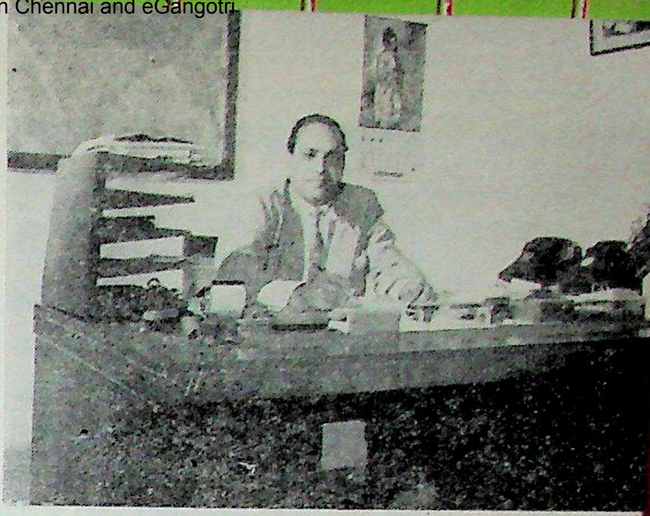

जनरल मैनेजर श्री अग्रवाल

वीयरवैल साइकिल कम्पनी

आज के कट्टर भौतिकवादी भले ही भाग्य की महत्ता को ठुकरादें, किन्तु यह सत्य है कि आजकल विश्व कृषि मेले में भाग्य की काफी चर्चा है। लोग जेबों में अपने टिकटों को इस प्रकार सुरक्षित रखते हैं जैसे वे उनकी भाग्य-लिपियां हों। इसलिए कि वीयरवैल साइकिल कम्पनी लि० फरीदाबाद प्रतिदिन उस आदमी को अपनी एक साइकिल मुफ्त देती है, जिसके टिकट के नम्बर की लाटरी खुल जाती है।

वीयरवैल साइकिल कं० का साइकिल उद्योग में काफी महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत में इस उद्योग का अभी बाल्य-काल ही समझना चाहिए, परन्तु यह उद्योग दिन-दूना रात चौगुना पनप रहा है। १९५८ में १९५७ की अपेक्षा साइकिल उद्योग में २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई, अर्थात् १० लाख के लगभग साइकिलों का निर्यात हुआ। अगले वर्षों में तो इसकी गति निरन्तर वृद्धि की ही ओर है। वीयरवैल कं० का इस उद्योग की प्रगति में काफी हाथ है। यह कं० फरीदाबाद में स्थित है और आधुनिक युग के प्रायः सभी आवश्यक यन्त्रों से सुसज्जित है। ५०० के लगभग मजदूर काम करते हैं जिन्हें कं० की ओर से रहन-सहन की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं, और सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि इस कं० का प्रबन्ध श्री के० सी० अग्रवाल के हाथों में है। आज तक यह कम्पनी १४ विभिन्न रंगों में वीयरवैल साइकिल के २४ मौडल बना चुकी है जो अपने ढंग के निराले ही हैं। इस कं० से भारतीय साइकिल उद्योग को बहुत बहुत आशाएं हैं। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया निर्माण

बंजर भूमि का विकास

एक ओर समस्त देश में विकास और निर्माण की योजना का कार्य हो रहा है, दूसरी ओर भविष्य के लिए नई नई योजनाओं के सुझाव दिए जाने लगे हैं। इन्हीं में से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है मध्यप्रदेश के ३० हजार वर्ग मील ऐसे क्षेत्र का विकास, जो बड़े बड़े गढ्ढों टीलों और नदी नालों के कारण दुर्गम व खादर बना हुआ है और डाकुओं से आक्रान्त रहता है। राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने मध्यप्रदेश के इस समस्यापूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की है, जिसके अनुसार इस क्षेत्र को बिशालकाय बुलड़ोजरों द्वारा समतल करके कृषि-योग्य बनाया जायगा। इस योजना पर लगभग ४ करोड़ रुपया प्रारम्भिक व्यय होगा। और तीन बर्ष में यह भूमि इतना गेहूँ और चावल पैदा करने लगेगी कि समस्त मध्यप्रदेश की आवश्यकता इसी क्षेत्र से पूरी हो जायगी। कोटा से इटावा और आगरा ग्वालियर से बहुत दूर तक यह प्रदेश फैला हुआ है, जहां डाकुओं के दल के दल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकारों के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। यदि इस क्षेत्र को ट्रैक्टरों, बुलडोजरों आदि के द्वारा कृषि के योग्य बना दिया गया तो ५० हजार परिवारों को इस क्षेत्र में बसाया जा सकेगा।

आज भी देश में पांच करोड़ तीस लाख एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है, जहां खेती नहीं होती। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वे इतनी बेकार पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य बनायें। राजस्थान में करीब पौने दो करोड़ और मध्यप्रदेश में एक करोड़ एकड़ और उत्तरप्रदेश और आन्ध्र में चालीस चालीस लाख एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। इस विशाल भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए जो आवश्यक व्यय होगा, उसका एक बड़ा अंश केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

मूल्यों में कमी

यों भी कृषि के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। विदेशी गेहूं के आयात और कुछ अन्य व्यवस्थाओं से पिछले कुछ सप्ताहों में अनाज के भाव काफी घटे हैं। खास तौर से पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम, उत्तरप्रदेश और पंजाब में चावल का भाव घटा है। उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश और राजस्थान में गेहूँ की कीमतें कम हुई हैं।

पूर्वी और उत्तरी भारत के बहुत से केन्द्रों में चावल की कीमतें धान की फसल कटने से पहले की कीमतों से ५) रु० प्रति मन घटी हैं। उत्तर प्रदेश में सब जगह गेहूँ का भाव गिरा है। मध्यप्रदेश और बम्बई के कुछ स्थानों में भी गेहूँ का भाव गिरा है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में उत्तर प्रदेश और गंगानगर (राजस्थान) में छः रुपए से लेकर सात रुपए और मध्यप्रदेश में ५ रु० प्रति मन बाजार-भाव गिरा है।

चावल की भूसी से तेल

देश के वैज्ञानिक खाद्य-समस्याओं को हल करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं, यह जानकारी कौतूहल-वर्द्धक है। एक समाचार के अनुसार केन्द्रीय खाद्य औद्यौगिक अनुसन्धान संस्था ने चावल की भूसी से तेल बनाने का तरीका निकाला है, जो खाने के काम भी आ सकेगा। अनुमान है कि चावल की भूसी से एक पौंड तेल निकालने में पचास नये पैसे का खर्च आएगा।

इस तेल में विटामिन की काफी मात्रा पायी गई है। यह तेल खाना आदि पकाने और सलाद में डालने के लिए अच्छा है। वनस्पति बनाने के लिए इसे हाइड्रोजनयुक्त भी किया जा सकता है।

इसके अलावा चावल की भूसी से चीनी और चावल का मांड भी बन सकेगा। इस चीनी में सकरोस ग्लुकोस और विटामिन 'बी' भी होगा। मांड से कई तरह की पालिशें बनायी जा सकेंगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजस्थान में व्यापक सहकारी बैंक सुविधाएं

राजस्थान में सहकारी बैंक सुविधाओं का संतोषजनक विस्तार हुआ है। अब तक राज्य की राजधानी में एक शीर्ष सहकारी बैंक तथा छब्बीस जिला केन्द्रों में से बाइस में जिला सहकारी बैंक स्थापित हो चुके हैं।

इस बैंक की कार्यशील पूंजी १९५३-५४ में ५,-८६,७०० रुपए के विरुद्ध १९५८-५९ में ३,२८,०६,३०० रुपए थी। बैंक का मुनाफा भी १९५३-५४ में १,५०० रुपए से १९५८-५९ में २,५५,९०० रुपए तक बढ़ गया।

विकास खंडों में सहकारी आंदोलन

राजस्थान के १२२ विकास खण्डों में सहकारी आन्दोलन की प्रगति हुई है। इन विकास खण्ड क्षेत्रों में ४,१५७ लाख सहकारी समितियां, ९८९ औद्योगिक सहकारी समितियां, तथा १०९३ अन्य समितियां कार्य कर रही है, जिनकी कुल सदस्य संख्या २,८०,३८१ हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले बाईस प्रतिशत परिवार इस आन्दोलन से लाभान्वित हो रहे है।

पूसा का पहला गेहूँ

गेहूं की बढ़िया किस्म तैयार करने के लिए दिल्ली को पूसा भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला प्रमुख केन्द्र है। वहां जो नए और अच्छे किस्म के गेहूं तथा अन्य अनाज तैयार किया जाता है, उन्हें 'न्यू पूसा' वा 'एन० पी०' किस्म का अनाज कहते हैं।

इस शताब्दी के आरम्भ में देश में जो गेहूं होता था, उसका दाना छोटा होता था और खेत में गेहूँ की पैदावार भी बहुत कम होती थी। पूसा में सर अलबर्ट हावर्ट ने अपने अथक परिश्रम से बढ़िया गेहूं तैयार किया, जिसे पूसा—४ (अब न्यू पूसा—४ या एन० बी०-४) नाम दिया गया। यह देश में पहला बढ़िया किस्म का गेहूं था, जो बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और बम्बई खूब में प्रचलित हुआ। यही नहीं बल्कि यह आस्टेलिया और दक्षिण रोडेशिया में भी खूब बोया गया और उससे संकर गेहूँ पैदा किया गया।

इस सफलता को देखकर अनुसन्धानशाला में और भी संकर गेहूं तैयार किए गए, मसलन—एन० पी० ५२, एन० पी० ८०-५, एन० पी० १११, एन० पी० ११४, एन० पी० १२५ और एन० पी० १२२। ये सभी गेहूं बहुत प्रचलित हुए।

अनुसन्धानशाला में इस समय गेहूं की किस्म को तेजी से सुधारने के लिए एक्स-रे और रेडियो-सक्रिय आइसोटोप का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही इसका भी प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसी किस्में तैयार हों, जिन पर रोग न लगे और साथ ही जिनमें पौष्टिक तत्व भी काफी मात्रा में हों। इसके लिए केन्द्रीय अनुसन्धानशाला में केन्द्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।

सौराष्ट्र का एक आदर्श ग्राम

देश के ग्रामों में कायाकल्प करने की कोशिशें की जा रही हैं। गांव के समझदार और परिश्रमी निवासी अपने पैरों पर खड़े होकर गांवों का नव निर्माण करने लगे है। सौराष्ट्र में किंदरखेड़ा गांव महात्मा गांधी के जन्म-स्थान पोरबन्दर से १४ मील दूर है। इस गांव की आबादी केवल ८७५ है। इस गांव की पंचायत ने गांव वालों की शिक्षा के लिए सराहनीय काम किया है। १९५१-५० में केवल १० प्रतिशत गांव वाले साक्षर थे। इस गांव के ८० प्रतिशत पुरुष और ६० प्रतिशत स्त्रियां पढ़-लिख सकती हैं।

ग्राम की पंचायत ने खेती के सुधार पर सबसे अधिक ध्यान दिया। अच्छे बीज और सुधरे हुए औजारों तथा अच्छी हाट व्यवस्था के लिए गांव वालों ने सहकारी समिति बनायी। अच्छे बीज उगाने और सुधरे हुए औजारों की आजमाइश के लिए बीस एकड़ जमीन रखी गयी। साथ ही भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिए भी १० एकड़ जमीन दी गई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गांव में ६ सो ढोर हैं। इनकी देखभाल की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। गांव वाले अपनी आवश्यकता का साठ प्रतिशत कपड़ा गांव में ही बना लेते हैं। उन्हें आशा है कि वे लोग दो साल के भीतर ही अपनी जरूरत का पूरा कपड़ा गांव में ही बनाने लगेंगे। गांव में १०८ चर्खे लगाए गए हैं। हर साल लगभग तीस मन से अधिक सूत कपड़ा बुनने के लिए गांव के जुलाहों को दिया जाता है। गांव की घानी में ही गांव भर की आवश्यकता के लिए तेल निकाला जाता है।

गांव में स्वच्छ पानी के लिये पक्का कुंआ, पानी भरने की टंकी और पंचायतघर, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, गौशाला, आरामघर बस-स्टैंड आदि को पानी देने के लिये नल लगाये गये है। इन कामों पर ३० हजार ५८५ रु० खर्च आया। इसका दो तिहाई १६ हजार ७८५ रु० गांव वालों ने नकद, सामान और मजदूरी के रूप में अपनी ओर से लगाया। पंचायत, एक स्कूल, बाल-मंदिर शाला पंचायत, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और बच्चों का पुस्तकालय चलाती है। पंचायत का खेल का मैदान भी है।

गांव वाले अपनी बचत का कुछ रुपया नेशनल प्लान सार्टिफिकेट खरीदने में लगाते हैं। गाँव के प्रत्येक परिवार ने ये सार्टिफिकेट खरीदे हैं। इस प्रकार किन्दरखेड़ा गांव बापू के स्वप्न का आदर्श गांव बनाने की दिशा में काफी प्रगति कर चुका है। पर अपनी इस सफलता से गांव वालों में शिथिलता नहीं आई है! वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

● ●

—१९५८-५९ में यात्री-कर के रूप में ११.६७ करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई जो राज्य-सरकारों में इस प्रकार वितरित कर दी गई—आंध्र प्रदेश ९७ लाख, आसाम ३० लाख, बिहार १.०२ लाख, बम्बई १.७७ करोड़, केरल २० लाख, मध्य प्रदेश ६१ लाख, मद्रास ७० लाख, मैसूर ४८ लाख, उड़ीसा १६ लाख, पंजाब ८८ लाख, राजस्थान ७४ लाख, उत्तर प्रदेश २.०४ करोड़ और पश्चिमी बंगाल ६६ लाख।

पाठकों का पृष्ठ

राष्ट्रीयकरण

'आज सरकार उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में प्रयत्न कर रही है। इस प्रवृत्ति को अधिकाधिक लोकप्रिय करने के लिए उसे जनता को पूरी सुविधाएं देनी चाहिए न कि उसे पहले से भी कम सुविधाएं दे। लेकिन सरकार क्या कर रही है, यह अकोला स्थित 'आज' के सम्वाददाता के शब्दों में सुनिए—

अकोला का बिजलीघर अभी तक एक प्राइवेट कम्पनी के हाथों में था, किन्तु अब वह सरकार के हाथों में चला गया है। लोगों ने सोचा था कि सरकार के हाथों में जाने से कुछ सुविधाएं बढ़ेंगी, किन्तु इस मामले में लोगों को भारी निराशा हुई। सरकारी विद्युत मंडल ने बिजली की दर ≡)। 'यूनिट' से बढ़ाकर ।)॥ कर दी है। प्राइवेट कम्पनी पहले घर-घर जाकर पैसा वसूल कर लेती थी। अब लोगों को जाकर सरकारी खजाने में पैसे जमा करने होंगे और उनका समय नष्ट होगा। पुरानी कम्पनी के पास अकोला के नागरिकों का 'डिपाजिट' और 'रिबेट' का मिलाकर एक लाख दस हजार रुपया जमा है। सरकार ने इस रकम की जिम्मेदारी नहीं ली। पता नही यह रकम लोगों को कब वापस मिलेगी। सरकार ने तो यह निकाल दिया है कि तीन महीने में जितना बिजली खर्च आता है उतना जमा करो। यानी लोग नए सिरे से 'कनेक्शन' ले रहे हों। इस बात का परिणाम यह हो रहा है कि राष्ट्रीयकरण से लोगों का विश्वास घटता जा रहा है।''

—मुकुट धर

—१९५८ में भारतीय बैंकों ने आयात व्यापार के लिए लगभग २ अरब २० करोड़ ६० लाख रु० और निर्यात व्यापार के लिए २ करोड़ १ लाख ४० हजार रु० दिया। १९५७ में बैंकों ने आयात के लिए ३ करोड़ २५ लाख ६० हजार रु० और निर्यात के लिए २ करोड़ ४ लाख ५० हजार रु० दिया था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सूखी नहर में जीवन लहर

मिल-जुल कर मेहनत करने से बडे बडे काम भी पूरे किये जा सकते है।

जम्मू-कश्मीर के रामहाल इलाके में करना खण्ड में एक साढे सात मील लम्बी नहर काफी दिनों से सूखी पड़ी थी।

एक दिन लोगों मे जोश उमड़ा। इलाके के कोई ४०० आदमी इकट्ठे हुए और फावड़ा-कुदाली सम्भाल कर नहर ठीक करने निकल पड़े। जमी हुई मिट्टी निकाल बाहर फेंकी गयी, पाट चौड़ा कर दिया गया, किनारे ऊंचे उठा कर मजबूत कर दिये गये, पानी का बहाव रोकने वाली चट्टानों को उड़ा दिया गया। वर्षों से सूखी उस नहर में कल कल करता हुआ पानी बहने लगा। वही नहर आजकल आस पास के कई गांवों की सूखी धरती की प्यास बुझा कर उसे हरा भरा करती है।

इस प्रकार श्रमदान से अपनी सहायता आप करके अपनी सुख-सुविधा बढ़ाई जा सकती है। इससे देश की प्रगति भी तेजी से होती है।

योजना की सिद्धि आपकी समृद्धि

DA-59/333

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हस्तकला-कौशल का घर

राजस्थान

आपको अवसर प्रदान करता है

अपने मनपसन्द की कलापूर्ण कृतियाँ खरीदिये

- हाथी दांत व चन्दन की वस्तुएं
- लाख की कलापूर्ण चूड़ियां
- रंगीन लहरिये की साड़ियां, रूमाल व चुन्दरियां
- कुट्टी तथा लकड़ी के खिलौने
- चमड़े के कसीदा वाले बटुए
- जोधपुर के बादले (पानी की सुराहियां)
- सांगानेर व बारमेर की छींटें
- जयपुर व जोधपुर के बढ़िया जूते
- पीतल के कलापूर्ण मीनाकारी के बर्तन
- सजाने के लिए आकर्षक व कलापूर्ण बर्तन
- कलात्मक कालीन व दरियां

निम्न स्थानों पर प्राप्य—

राजस्थान सरकार के हैण्डिक्रैफ्ट एम्पोरियम

१. मिरजा इस्माइल रोड, जयपुर
२. जनपथ लेन, नयी दिल्ली
३. कचहरी रोड, जोधपुर
४. चेतक सिनेमा के सामने, उदयपुर
५. पुरानी तहसील, माउण्ट आबू
६. कैसरगंज, अजमेर
७. रेलवे स्टेशन के सामने, चित्तौड़गढ़
८. मन्दिर मार्ग, नाथद्वारा
९. रामपुरा बाजार, कोटा
१०. किंग एडवर्ड मैमोरियल रोड, बीकानेर

विश्व-कृषि मेले में हमारी दुकान पर दर्शन दीजिये

उद्योग व पूर्ति संचालक राजस्थान द्वारा प्रकाशित

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस प्रा० लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली से मुद्रित व अशोक प्रकाशन मन्दिर [illegible] दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

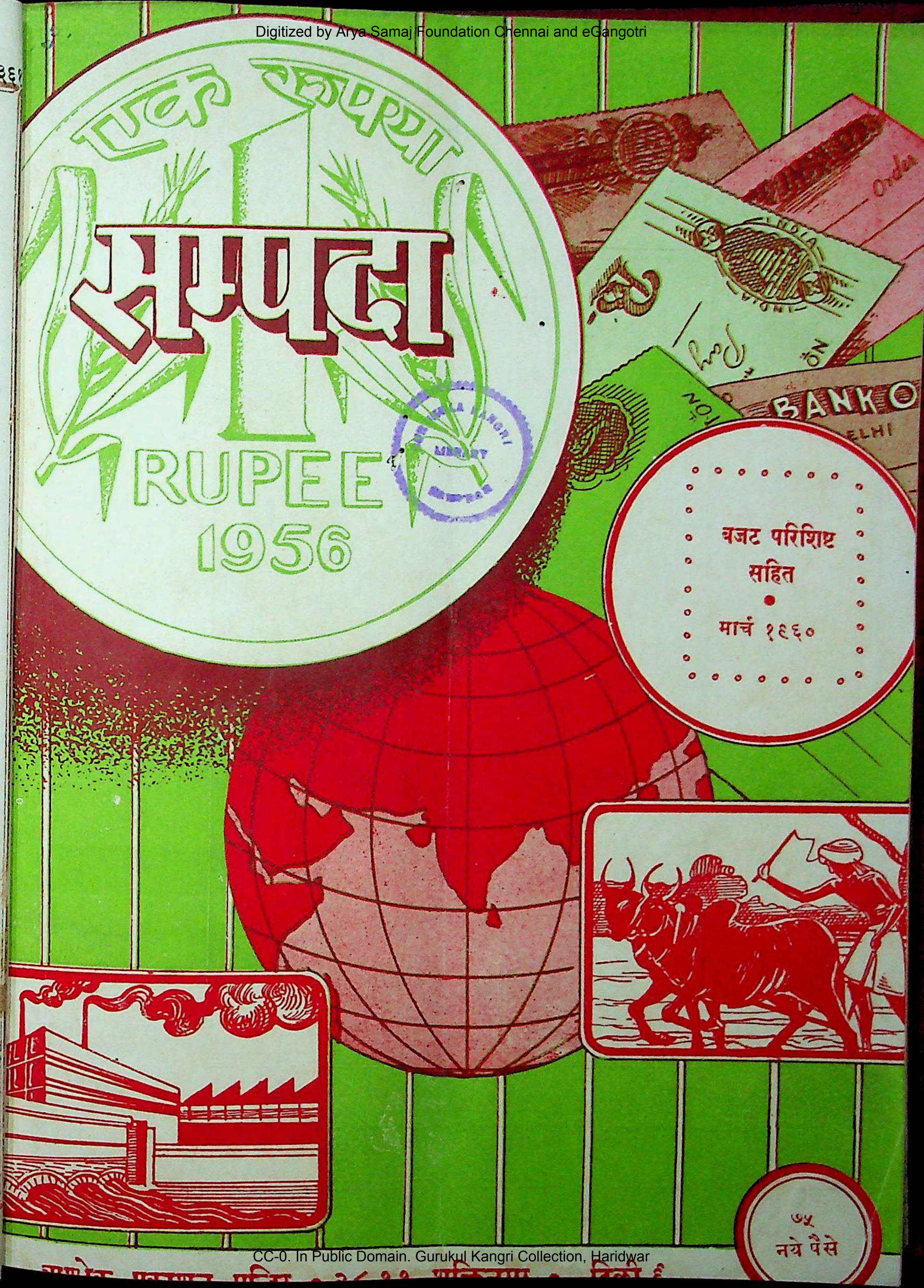

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक्सल की कहानी

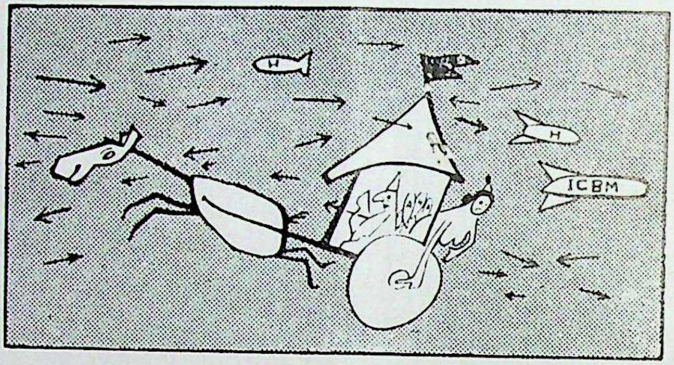

सारे रामायण महाकाव्य का उद्भव वास्तव में एक पुर्जे के टूटने से हुआ था. घमासान युद्ध के बीच शाही रथ का एक्सल टूट गया, परन्तु रानी कैकेयी ने अपनी उंगली डाल कर पहिए को यथास्थान रखा. राजा दशरथ ने उस से कोई वर मांगने को कहा जिस का फायदा कुटिल रानी ने श्री राम को बनवास भेजने में उठाया.

इसलिए आप मानेंगे कि हमें अपने एक्सल मजबूत रखने होंगे. वियरवेल साइकिलें हर प्रकार के काम के लिए बनाई गई हैं. उन का हर पुर्जा मजबूत होता है.

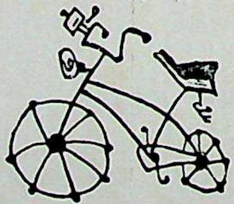

वियरवेल साइकिल्स

विमपेक्स (एजेंट्स) नई दिल्ली • बम्बई • कलकत्ता • मद्रास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस अङ्क में

नये वर्ष का बजट — सम्पादकीय १३३

राष्ट्रीय सम्पत्ति का विनाश, आडम्बर में कमी,
वस्त्र व सीमेंट उद्योगों में वेतन
१॥। लाख और ३६००० डालर — टिप्पणियाँ १३४

बजट परिशिष्ट

योजनाएं और बजट — श्री राजनारायण गुप्त १३८

बजट और आधुनिक अर्थशास्त्र — प्रो० वि० ना० पाण्डेय १३९

राज आय के विभिन्न साधन — श्री सत्यदेव देराश्री १४२

बजट कैसे बनता है — १४४

राष्ट्र की आर्थिक स्थिति — श्री मोरारजी देसाई १४७

भारत के वित्त मन्त्री — १५२

उत्पादन कर बढ़ रहे हैं — १५४

सांख्यिकी — १५५

संघों और राज्यों में राजस्व का वितरण — १५६

राज्यों के बजट — १६०

नये वर्ष का रेलवे बजट — १६३

बजट १९६०-६१ के नये प्रस्ताव — १६७

जी हाँ, मैं वित्त-मन्त्री हूँ ! — १७१

विदेशों के बजट — १७२

समाचार-समीक्षा — १७३

नया साहित्य — १७८

जरमनी गणराज्य में स्वतन्त्र बाजार — १८०

●●●

सुरक्षा का रहस्य

पंजाब नैशनल बैंक के सेफ डिपाज़िट वॉल्ट आपकी मूल्यवान वस्तुओं की चोरी से पूर्ण सुरक्षा की गारन्टी हैं।

पी० एन० बी० के सेफ डिपाज़िट वॉल्टों में

* लाकरों को दो चावियों (डुअल कन्ट्रोल) वाले ताले लगे हैं
* लाकरों को केवल वे ही खोल सकते हैं जिनको खोलने का अधिकार है
* लाकर सभी मुख्य नगरों में उचित किराए पर प्राप्य हैं

कार्यगत कोष — १७९ करोड़ रुपये से अधिक
जमा धनराशि — १४१ करोड़ रुपये से अधिक

दि पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड
(स्थापित सन् १८९५ ई०)
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा के अनूठे उपहार : ११ विशेषांक

'सम्पदा' का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विश्व-कोष ही होते हैं। प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम० कॉम० कहते हैं—'सम्पदा' के विशेषांक तो हमारे लिए गीता व बाइबिल के समान हैं।'

१-योजना अंक

(प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्व सामग्री)

एक प्रशंसनीय प्रयत्न। यह अंक पंचवर्षीय योजना को समझने की कुंजी है।

मूल्य : १.०० —जीवन साहित्य

२-भूमि-सुधार अंक

(भूमि समस्याओं का अद्भुत विवेचन)

इस विषय में अपने ढंग का अद्वितीय प्रकाशन है।

मूल्य : १.०० (अप्राप्य) —प्रताप

३-वस्त्र-उद्योग अंक

(भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं)

इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। सम्पादक को बधाई।

मूल्य : १.२५ —श्री घनश्यामदास बिड़ला

४-चम्बल अंक

(चम्बल योजना का विस्तृत परिचय)

अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है।

मूल्य : ००.७५ (अप्राप्य) —श्री मिश्रीलाल गंगवाल

५-मजदूर अंक

(मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन)

लख बहुत रोचक व उपयोगी हैं। ···मानव की नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की संस्कृति व परम्पराओं के अनुकूल है।

मूल्य : १.२५ —श्री खंडूभाई देसाई

६-उद्योग अंक

(प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय)

भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याओं पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का अच्छा संग्रह है।

मूल्य : १.२५ —अजन्ता

७-राष्ट्रीय-विकास अंक

(द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन)

ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा।

मूल्य : १.२५ —श्री मोहनलाल सुखाड़िया

८-बैंक अंक

(भारतीयों बैंक की समस्याओं का निरूपण)

Here is one more 'Sampada' Special worth treasuring. (अप्राप्य)

मूल्य : १.२५ —Organiser

९-समाजवाद अंक

(समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार)

सम्पदा का समाजवाद अंक मिला। यह काफी अच्छा और पठनीय है।

मूल्य : १.५० —श्री श्रीमन्नारायण

१०-राष्ट्र-प्रगति अंक

(द्वितीय योजना काल की समस्याओं का विवेचन)

यह अति लाभदायक तथा उपयोगी है। लिखने का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है।

मूल्य : १.५० —श्री अमरनाथ विद्यालंकार

११-सहकारी कृषि अंक

देश के अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न पर विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण। —मू० १.५०

रजिस्ट्री से सब प्राप्य अंक मंगाने के लिए रु० १०.५० भेजिये।

सम्पदा • २८-११ शक्तिनगर • दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष : ६

अंक : ३

मार्च, १६६०

नये वर्ष का बजट

१६६०-६१ का नया वर्ष भी प्रस्तुत हो गया। आज की साधारण अवस्थाओं को देखते हुए और पिछले वर्षों की परम्पराओं को देखते हुए यह आशा किसी को नहीं थी कि बजट में घाटा नहीं दिखाया जायगा अथवा नये कर नहीं लगाए जायेंगे। इसलिए यह बजट भी घाटे का बजट हो और कुछ नये कर लगाए जायें, यह स्वाभाविक था, किन्तु जिस कुशलता के साथ वित्त मन्त्री ने अपना बजट बनाया है, उसके लिए वे वस्तुतः प्रशंसा के पात्र हैं।

किसी देश का बजट उस की आर्थिक स्थिति की सूचना देता है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो यह बजट यद्यपि बहुत आशाओं और उत्साह को प्रकट नहीं करता किन्तु इससे विशेष निराशा भी नहीं झलकती। किसी लोकतंत्री देश की संसद में बजट पर जो, आलोचनाएं प्रति आलोचनाएं होती हैं, हमारी नम्र सम्पत्ति में वे वस्तुस्थिति का पूर्ण दर्शन नहीं कराती क्योंकि उनके मूल में केवल गुणावगुण नहीं, राजनैतिक दलों का आग्रह होता है। विरोध या समर्थन करना है, इसीलिए पक्ष या विपक्ष में भाषण दिए जाते हैं। बजट के प्रस्तावों पर विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, न कि दलीय दृष्टि से।

दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है और तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने का समय निकट आ गया। उधर उत्तरी सीमा पर चीन ने जो असाधारण परिस्थिति उत्पन्न कर दी हैं, उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि बजट में घाटा हो और नये कर लगाये जायें। तथापि केवल २३,२३,००००० रुपयों के कर लगाये गये हैं, जो सम्भावना से अधिक नहीं हैं। जो कर लगाये भी गये हैं वे भी वित्त-मन्त्री की कुशलता को प्रकट करते हैं। अधिकांश कर अप्रत्यक्ष कर हैं और वे उद्योग पर लगाये गये हैं। लोहा टीन व अलुमूनियम की चादरें, गाड़ियों के इन्जन, बिजली की मोटरों पर लगे कर से जनता को विशेष हानि नहीं होगी। साइकिल के पुर्जों, जूतों और बिजली के बल्बों तथा पंखों पर भी कुछ कर लगे हैं, इनका प्रभाव मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। यद्यपि मध्यम वर्ग पहले से ही पीड़ित वर्ग है और उस पर यदि भार न डाला जाता तो अधिक अच्छा होता, परन्तु यह बोझ भी असह्य नहीं है और न प्रतिदिन पड़ने वाला बोझ है। साइकिल, पंखे, बिजली के बल्ब, और जूते आदि प्रति दिन नहीं लिए जाते। इसलिए अवांछनीय होते हुए भी यह अप्रत्यक्ष कर असहनीय नहीं है। विशेष कर ऐसे समय में जबकि वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक से अधिकतम सहयोग देने की अपेक्षा की जा रही है।

पिछले कुछ वर्षों से एक परम्परा चली आ रही थी कि उद्योग पर अधिकतम कर लगाये जायें। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण को जब विशेष प्रोत्साहन मिलना था, निराशा ही हुई। आज पूंजी निर्माण को हम जितनी सहायता दे सकेंगे, उतना ही निकट भविष्य के लिए आशाजनक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

होगा। इसलिए उन्होंने इस दिशा में उद्योगों को सम्पत्ति कर व अधिक लाभांश कर समाप्त करने की सूचना दी है तथा पहले से अदायगी करने पर कम्पनी कर की दर की कमी को स्थायी मान लिया गया है। नये कारखानों को और पाँच साल की छूट या कुछ अन्य सुविधाएं दी गई हैं। उनसे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारी सम्मति में यह व्यावहारिकता का तकाजा था। देश की वर्तमान समस्याओं के प्रति यही व्यावहारिक नीति है। भावुकता के नारों से बजट नहीं बना करता।

घाटे की वित्तीय व्यवस्था तथा विदेशी ऋणों का आश्रय लेना जितना वित्त मंत्री के लिए सुगम व आकर्षक होता है। उतना ही हानिकर भी। घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा मुद्रा-प्रसार सदा मँहगाई का दुषचक्र उत्पन्न करता है। आज देश में उत्पादन की अधिकता के बावजूद महंगाई का एक कारण मुद्रा-प्रसार भी है। इस बजट में किसी से बचा नहीं गया। १५३ करोड़ रु० के लिए नासिक के प्रेस की सहायता ली गई है। मुद्रा-प्रसार असाध्य होता है। निरन्तर ऋण लेते रहने की प्रथा पर भी अंकुश लगना चाहिए था। एक आलोचक की निम्न पंक्तियाँ कम विचारणीय नहीं है: "ऋण लेने को हम टाल नहीं सकते, किन्तु हम इतना तो अवश्य कर सकते हैं कि जो ऋण लें, उसे इस प्रकार खर्च करें कि वह उत्पादक हो तथा अपना ब्याज खुद कमा सके। बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र के दूसरे विवरण के अनुसार इस वर्ष शासन १६१ करोड़ ८० लाख रुपए ब्याज के रूप में देगा, जबकि उसे केवल ८२ करोड़ २६ लाख रुपए इस मद में प्राप्त होगा। यह भारी हानि है। हमारा यह खर्चा आगे और बढ़ने वाला है। प्रति वर्ष हम भारी तादाद में ऋण ले रहे हैं। भारत सरकार के ऊपर सब प्रकार के ऋण और अन्य देय मिलाकर ३१ मार्च १६६० को कुल ५८५४ करोड़ ६७ लाख रुपए होते हैं। एक वर्ष बाद यह आंकड़ा बढ़कर ६५८६ करोड़ ४० लाख रुपया हो जायगा। यदि इसमें राज्य सरकारों तथा अन्य निकायों के ऋण और जोड़ लिए जाएं तो हमें पता चलेगा कि हम अपनी राष्ट्रीय आय के लगभग ७० प्रतिशत तक कर्जदार हैं। यह भारी कर्जा आने वाली पीढ़ी पर एक भारी बोझ होगा। यदि हमने योग्य एवं उत्पादक विनियोग से अपनी राष्ट्रीय आय तेजी से नहीं बढ़ायी तो कर्जे का चुकाना तो दूर ब्याज का भुगतान भी हमारे लिए कठिन हो जायगा।"

इनामी बौण्ड की घोषणा एक नई चीज है, जो जुआ होते हुए भी जनता की जेब से पैसा खींचने और इस तरह मुद्रा संकोच में शायद एक अंश तक सहायक हो सके।

जहाँ हम वित्त-मंत्री को युक्ति-युक्त अनिवार्य कर वृद्धि के लिए बधाई देना चाहते हैं वहाँ हमें यह दुःख है कि व्यय की दिशा में उन्होंने कोई सन्तोषजनक कदम नहीं उठाया। जहाँ एक ओर आय बढ़ाने की आवश्यकता है वहाँ दूसरी ओर यह भी अनिवार्य आवश्यकता है। वर्षों से सरकार से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह अपने खर्चे को कम करे, लेकिन वे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वर्ष के बजट के अंकों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट है कि प्रायः प्रत्येक मद में व्यय बहुत बढ़ गया है और इन कारणों से यदि पिछले वर्ष संशोधित बजट के अनुसार घाटा १५.३६ करोड़ था, तो इस वर्ष घाटा ६०.६७ करोड़ अनुमानित किया गया है। वस्तुतः सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक मंत्रालय में होने वाले अनाप-शनाप व्ययों की जाँच पड़ताल करे और इसके लिये प्रत्येक मंत्रालय के कर्मचारियों से आवश्यक गुप्त परामर्श माँगे। हमारी सम्मति में इन परामर्शों पर विचार करने से बहुत से व्यय कम किये जा सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यों पर होने वाला अधिकांश व्यय आसानी से स्थगित किया जा सकता है। विभिन्न मंत्रालयों के प्रकाशनों में भी व्यय कम हो सकता है। यदि समस्त देश में मंत्रियों के उद्घाटन समारोह और भाषणों के चित्र व ब्लाक ही बनने बन्द हो जाएं और कागज की किस्म साधारण कर दी जाय तो एक विपुल राशि बच सकती है। अन्त में हम उन्हीं पंक्तियों को पुनः उद्धृत करना चाहते हैं जो हमने गत वर्ष बजट की चर्चा करते हुए लिखी थीं—

"हम समाजवादी समाज की घोषणा करते हैं, किन्तु करों की वृद्धि के अतिरिक्त इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाता। जीवन स्तर को जहां ऊँचा करना है, वहाँ ऊंचे स्तर को कम भी करना होगा। दोनों सिरों से एक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरे की ओर चले बिना समानता का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। वेतनों में कटौती सम्भव नहीं है, तो दो-तीन वर्ष ५००-६०० रु० से अधिक वेतन पाने वालों की वार्षिक वृद्धि रोकने का प्रस्ताव संयुक्त सहकारी कृषि से कम क्रान्तिकारी परन्तु अधिक सुविधाजनक है। कुछ बचत की अपेक्षा अधिक महत्त्व उस भावना का है जो देश को समाजवाद की ओर ले जाने में सहायक होगी।" ● ●

राष्ट्रीय सम्पत्ति का विनाश

देश में बार-बार होनेवाले उपद्रवों और संघर्षों का एक प्रधान कारण यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अभी तक हम लोगों में राष्ट्रीयता का विकास नहीं हुआ है। जब तक हमने स्वराज्य प्राप्त नहीं किया था, हम समस्त देश में मातृभूमि के दर्शन करते थे, किन्तु स्वाधीन होने के पश्चात् हमारी मातृभूमि की भावना खण्डित हो गई, और वह अपनी भाषा, अपने प्रदेश की भौगोलिक सीमा तथा अपनी अपनी जाति, अपने-अपने वर्ग तक सीमित हो गई है। यही कारण है कि हम इस समय समस्त भारत को अपना देश नहीं समझते। इसी कारण हम उपद्रवों में, हिंसा में और राष्ट्र की सम्पत्ति को नष्ट करने में तनिक भी संकोच नहीं करते। किसी भी एक व्यक्ति, या अधिकारी या किसी भी एक दल से असन्तोष प्रकट करने के लिए हम राष्ट्र की सम्पत्ति को नष्ट करने लग जाते हैं। कानपुर में पुलिस से अधिक असंतोष प्रकट करने का प्रदर्शन लाखों रुपयों की सम्पत्ति—तार, बिजली की बत्तियाँ, बसें और मोटर गाड़ियाँ, सरकारी दफ्तरों की खिड़कियाँ आदि तोड़ने व अग्निकाण्ड के रूप में हुआ है। भिलाई में कुछ मजदूरों को प्रबन्ध से शिकायत थी तो राष्ट्रीय उद्योग की कीमती मशीनरी को भी नष्ट कर दिया गया और दो जीप गाड़ियाँ जला दी गईं, मानों वह मशीनरी उस अधिकारी इंजिनियर की अपनी सम्पत्ति हो। बम्बई की विशाल राष्ट्रीय दुग्धशाला कालौनी के कर्मचारियों को कुछ शिकायत हुई तो उन्होंने दूध की सैकड़ों बोतलें तोड़ डालीं और मशीनरी को नुकसान पहुँचाया। वे यह भूल गये कि ये बोतलें और मशीनरी समस्त राष्ट्र की, और इस नाते उनकी भी सम्पत्ति थीं। कलकत्ते में दो बसें जला दी गईं; क्योंकि एक बस ड्राइवर ने एक साइकलिस्ट के बचाने के लिए पायदान पर चलने वाली एक सवारी को नीचे धक्का दे दिया।

राष्ट्रीय सम्पति के इस तरह विनाश की खबरें जहाँ-तहाँ मिल सकती हैं और मजा यह कि समाजवादी समाज के नारे लगाने वाले कम्युनिस्ट तथा अन्य सार्वजनिक कार्यकर्ता यह भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय सम्पति का विनाश एक जघन्य अपराध है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने भिलाई के उपद्रवों की चर्चा करते हुए कहा था कि "मैं ऐसे प्रसंगों में किसी तरह का समझौता नहीं करूँगा। इस प्रकार की विध्वंस प्रवृत्तियों की, चाहे वे किसी की ओर से भी हों कठोरतम निन्दा होनी चाहिए।" सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और विशेषकर मजदूर कार्यकर्ताओं को यह अनुभव करना चाहिये कि राष्ट्रीय सम्पति किसी अधिकारी या दल की अपनी सम्पति नहीं है। हमारी नम्र सम्पति में राष्ट्रीय अनुशासन का यह सन्देश एक-एक नागरिक तक पहुंचाना आवश्यक है। इस प्रकार का उपद्रव करने वालों को कठोर दंड देने की आवश्यकता है। उनसे समझौते की बातचीत तो किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए।

आडम्बर में कमी

श्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों का ध्यान पुनः इस ओर खींचा है कि वे अपने राज्य में निर्माण किये जाने वाले भवनों पर आवश्यकता से अधिक व्यय न करें। वस्तुतः आज समस्त देश में बड़ी से बड़ी और शानदार खर्चीली इमारतों पर बेतहाशा खर्च हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि सब राज्यों की सरकारें अपनी राजधानी और नगरों को अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए परस्पर होड़ कर रहीं हैं। लेकिन ऐसा करते समय वे इस बात पर ध्यान नहीं देती कि देश के करदाता इतना भारी व्यय सहन कर सकते हैं? बड़ी शानदार इमारतें आँखों को अच्छी लगती हैं और शासकों को आत्मसन्तोष देती हैं। कला अपने आप में बहुत ऊँची चीज है और इससे मानव की संस्कृति और सभ्यता का दर्शन होता है; किन्तु आज जब कि हम लोगों को गाँवों में स्कूल और अस्पताल खोलने के लिए रुपये की कमी मालूम होती है, बड़ी इमारतों पर लाखों करोड़ों रुपयों का व्यय करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता इसलिए हम श्री नेहरू के विचार का विशेष समर्थन करना चाहते हैं; किन्तु राज्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भी केन्द्र का अनुकरण कर रहे हैं, और इसलिए केन्द्रीय सरकार यदि राज्यों पर प्रभाव डालना चाहती है तो उसे स्वयं आदर्श बनकर दिखाना होगा। नई दिल्ली तथा अन्य नगरों में केन्द्र की ओर से जो इमारत बन रही हैं, वे सादी और मजबूत होनी चाहिएँ। तभी राज्य भी सादी और कम खर्चीली इमारतें बनाने की ओर प्रवृत्त होंगे।

वस्त्र व सीमेंट उद्योगों के वेतन

भारत सरकार ने सीमेंट और वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में वेतन मन्डल नियत किये थे। इनकी नियुक्ति का उद्देश्य यह था कि इन दोनों उद्योगों में मजदूरों व कर्मचारियों की वेतन-सम्बन्धी समस्याओं का स्थिर निर्णय हो जाए, अधिकांश औद्योगिक संघर्षों का मूल कारण वेतन वृद्धि की माँग होता। श्रमिक सदा अधिकाधिक वेतन पाने की माँग करते हैं, जबकि उद्योग संचालक वेतन देने में असमर्थता प्रकट करते हैं। उनके मत में वस्त्र-उद्योग की स्थिति इतनी संकट पूर्ण है कि वह मजदूरों को एक पैसा भी अधिक नहीं दे सकता। मिलों के गोदाम भर रहे हैं। कभी रुई मँहगी हो जाती है तो कभी माँग बहुत कम हो जाती है। इधर श्रमिकों का कहना यह है कि मिलों में अव्यवस्था, मुनाफाखोरी तथा भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और रुपये का इतना दुरुपयोग होता है कि मिलें अन्त में घाटा दिखाने लगती हैं। वेतन सम्बन्धी इस विवाद के कारण औद्योगिक क्षेत्र में सदा अशान्ति रही और इसका राष्ट्रीय उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए आवश्यकता थी कि प्रतिदिन उठने वाले इस संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए। भारत सरकार ने सरकार, मिल मालिकों तथा श्रमिकों का त्रिपक्षी मंडल नियुक्त किया, जो वेतन संबंधी समस्या के सब पहलुओं पर विचार करके यह अन्तिम निश्चय कर दे कि किस शहर में मिल के मजदूरों को कितना वेतन दिया जाय। इस मंडल ने सब क्षेत्रों में घूम घूम कर सब स्थितियों का अध्ययन किया और सब पक्षों पर विचार करके एक सर्व सम्मत रिपोर्ट दी है। सरकार ने भी उसकी सिफारशें स्वीकार कर ली हैं। मंडल की सिफारशों के सम्बन्ध में हमें कुछ नहीं कहना है; सम्भव है किसी को उनसे मतभेद हो, हमें तो मंडल की एक सलाह की ओर इन सब का ध्यान खींचना है। उसने वेतन वृद्धि की सलाह देते हुए यह आशा प्रकट की है कि अब से ५ वर्षों तक वेतन वृद्धि की कोई माँग की जाय। यदि इस परामर्श पर अमल न किया गया और वेतन बढ़ाने और घटाने की माँग फिर भी की गई तो वेतन मण्डल नियुक्त करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हमें यह आशा करनी चाहिए कि आगामी पांच वर्षों में वस्त्र-उद्योग के क्षेत्रों में अब श्रमिक इस निर्णय को शान्तिपूर्वक स्वीकार कर लेंगे। दूसरी ओर उद्योग भी इन निर्णयों का स्वागत करेगा। यह ठीक है कि इस मंडल के प्रस्तावों से उद्योगों पर प्रति वर्ष ९ करोड़ रुपये और जनवरी, ६२ से ११½ करोड़ रुपये का बोझ बढ़ जायगा। उन्हें उद्योग के अभिनवीकरण तथा अन्य उपायों द्वारा इस व्यय को सहन करना चाहिए।

जो बातें हमने वस्त्र-उद्योग के सम्बन्ध में लिखी हैं, वही सीमेंट उद्योग के सम्बन्ध में कहना चाहते हैं। इस उद्योग के कर्मचारियों के लिए भी वेतन वृद्धि की सिफारिश की गई हैं, किन्तु दूसरी तरफ सरकार ने यह भी स्वीकार किया है इस वृद्धि से जो बोझ उद्योग पर पड़ेगा, उसको हलका करने के लिए सरकार उत्पादन-कर कम करने अथवा राज्य व्यापार निगम के लाभों में कमी करने के प्रश्न पर विचार करेगी।

हमें आशा करनी चाहिए कि अन्य उद्योगों में भी सरकार वेतन सम्बन्धी कठिन प्रश्नों का अन्तिम निर्णय कर देगी जिससे वेतन, बोनस तथा कार्य स्थिति आदि अन्य प्रश्नों के नाम पर उद्योग में अशान्ति उत्पन्न न हो और उद्योगों के संचालक व श्रमिक मिलकर अधिकाधिक उत्पादन द्वारा देश की समृद्धि में सहायक हो सकें।

राज्यों के बजट

पाठक इसी अंक में विविध राज्यों के बजट पढ़ेंगे। गत वर्ष राज्यों के बजटों में जो प्रवृत्ति प्रकट हुई थी, वह इस वर्ष भी जारी रही है। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने नये कर नहीं लगाये हैं, बिक्री कर आदि में कहीं-कहीं थोड़ा बहुत हेर फेर अवश्य किया है। वस्तुतः पिछले कुछ समय से कर इतने बढ़ाये जा चुके हैं कि अब और कर बढ़ाने की गुंजाइश नहीं रही, इस लिए वित्त मंत्री अब व्यापार-उद्योग के रूप में अधिक रुपया एकत्र करने की नीति पर चल रहे हैं। जगह जगह विद्युत् और सिंचाई का क्षेत्र

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

बढ़ा कर तथा सड़क यातायात पर अधिकाधिक अधिकार करके राज्य अपनी आय के साधन बढ़ा रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में नई विकास योजनाओं से कृषि की भूमि का भी सुधार किया गया है। इस से भी राज्यों की आय बढ़ी है। दूसरी ओर वित्त मंत्रियों ने स्कूल, अस्पताल, सड़कें आदि के निर्माण की दिशा में ध्यान देकर लोकप्रियता प्राप्त करने की चेष्टा की है। लेकिन समाज सेवाओं का यह कार्य क्षेत्र इतना विशाल है और साधन इतने सीमित हैं कि इस दिशा में उठाये गये कदमों से बहुत कम संतोष होता है।

राज्यों के इन बजटों की दो और विशेषताएं भी हैं। पहली यह है कि राज्य जब एक और अपनी आमदनी के साधन नहीं बढ़ा सकते विकास योजनाओं के नाम पर केन्द्र पर अधिकाधिक निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। प्रायः सभी मदों में वे केन्द्र के मुखापेक्षी हो गये हैं। १९६०-६१ के केन्द्रीय बजट में करीब ५२ करोड़ रुपया राज्यों को अंशदान और सहायक अनुदान के लिए नियत किया गया है। पूंजीगत व्यय की भारी राशि इसके अतिरिक्त है।

पिछले वर्षों में केन्द्र ने अनेक कर लगा कर भी राज्यों के वित्त मंत्रियों को कुछ हलका कर दिया है। सम्पत्ति कर, उत्तराधिकार कर, रेलवे यात्रा कर आदि में से राज्यों को पर्याप्त अंश मिलता है। मृत-सम्पत्ति शुल्क का बड़ा अंश राज्यों में बाँट दिया जायगा। रेलवे यात्री कर में से १२.९६ करोड़ रुपया राज्यों को मिल जाएगा। इसी तरह आय कर तथा निगम कर से प्राप्त आय में से भी ६० प्रतीशत राज्यों को मिलता है। क्योंकि इस कर की आमदनी लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए राज्यों को मिलने वाला भाग भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार राज्यों के वित्त मंत्रियों का भार कुछ कम होता जा रहा है।

राज्यों के बजट की दूसरी विशेषता यह है कि राज्यों के वित्त मंत्रियों ने मितव्यय की ओर ध्यान नहीं दिया। शासन के खर्चे, बड़े-बड़े वेतन व सब आडम्बर यथापूर्व रहने दिये गये हैं। इस कारण जनता का विश्वास प्राप्त करने में सरकार को काफी कठिनता आती है। शराबबन्दी और प्रगति तो कई वर्षों से रुक गई है। केन्द्रीय सरकार का परामर्श इस दिशा में उनकी ढाल का काम देता है। चीन के भारत पर आक्रमण का प्रभाव केवल केन्द्रीय बजट पर ही नहीं पड़ा, उत्तर सीमा वर्ती, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल पर भी पड़ा है। इन राज्यों को सीमा वर्ती क्षेत्रों के विकास व सुधार पर अधिक ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा है। ● ●

१।। लाख और ३६०० डालर

१८१३ में जब संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में कर लगाने का कानून अमल में आया तब संघ की सरकार को लोगों के निजी और कम्पनियों के नफे से ३५० लाख डालर आय कर आदि मिले। इसका अर्थ यह है कि प्रति मिनट सरकार को ६७ डालर मिले।

आज संघ सरकार को ६८.४ अरब डालर आय व लाभ करों से मिलते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रति मिनट १ लाख ३० हजार डालर सरकार को मिलते हैं। अन्य भी करों को मिलाकर यह राशि १४५३५८ डालर बनती है १९६० में संघ की सरकार को जो कुल कर मिलेंगे, उसका अर्थ होगा १।। लाख और ३६०० डालर!

और भारत में

यदि इसी तरह भारत में संघ सरकार की आमदनी का हिसाब लगावें तो १९६०-६१ के बजट के अनुसार उसे प्रति मिनट डालर कर या कर भिन्न सब स्रोतों से मिलाकर १७५०३ रुपये (अर्थात् केवल ३६८५ डालर) मिलते हैं।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजनाएं और बजट

श्री राजनारायण गुप्त

भारतवर्ष में पिछले दस वर्षों की प्रगति की कहानी योजनाओं की कहानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् से हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में जो उन्नति की है उसका मुख्य श्रेय हमारी योजनाओं को है। कृषि, उद्योग, यातायात संचार, सिंचाई, बिजली, समाज-सेवा, रोजगार, शिक्षा, सांस्कृति उत्थान—अर्थात् राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ही भारत बहुत आगे बढ़ा है और आशा है आगे आने वाले दस-पंद्रह वर्षों में देश उस मंजिल पर पहुँच जाएगा कि एक स्वचालित यंत्र की भाँति देश की आर्थिक अवस्था निरंतर सुधरती रहेगी। यह ठीक है कि योजनाओं को सफल बनाने के लिए देश के प्रत्येक वर्ग को भारी कुरबानी देनी पड़ी है, और आगे के दस-पंद्रह वर्षों में हमें इसी प्रकार घोर परिश्रम करना पड़ेगा, परन्तु आने वाली पीढ़ियों पर इस का जो सुखद प्रभाव पड़ेगा उसका आभास अभी से मिल सकता है।

प्रश्न उठता है कि बजट का योजनाओं से क्या संबन्ध है तथा किस प्रकार बजट पर दृष्टि डाल कर हम देश की योजनाओं के स्वरूप तथा उनकी प्रगति का हाल जान सकते हैं ?

योजना का अर्थ देश के सीमित साधनों को वैज्ञानिक ढंग से नियोजित कर अधिक से अधिक द्रुत गति से देश का आर्थिक विकास करना होता है। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमारे साधन अत्यन्त सीमित थे। और हमारी समस्याओं का कोई आर-पार न था। ऐसे समय में हमारे योजना निर्माताओं को यह निश्चय करना पड़ा कि देश की थोड़ी पूंजी को किन कार्यों की पूर्ति के लिए सबसे पहले लगाया जाय। स्पष्ट है कि सन् १६५०-५१ में हमारी सबसे बड़ी समस्या खाद्य समस्या थी। देश की बढ़ती हुई आबादी के लिए हमारे यहाँ इतना अन्न उत्पन्न नहीं होता था कि सब लोगों की भूख शांत की जा सके। इसलिए अरबों रुपये का अन्न विदेशों से मंगाकर हम अपनी जनता की इस प्रथम आवश्यकता को पूरा करते थे। अधिक अन्न उत्पादन

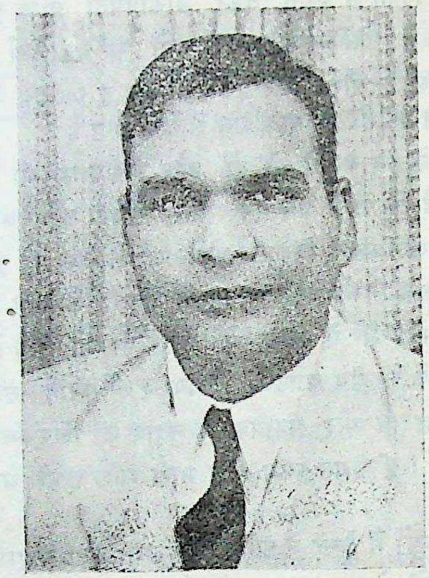

लेखक

के लिए सिंचाई, खाद, अच्छे बीज, उपजाऊ जमीन, उन्नत यंत्र, तथा अच्छे यातायात साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमारी प्रथम योजना में इन्हीं साधनों की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया। देश के औद्योगीकरण, रोजगार की समस्या तथा समाज सेवाओं के विस्तार की बातों को पीछे रखा गया।

प्रथम योजना का ढाँचा बनाते समय हमारे अर्थ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि आने वाले पाँच वर्षों में देश अधिक से अधिक दो हजार करोड़ रुपये के विनियोजन की व्यवस्था कर सकेगा, इससे अधिक पूंजी का एकत्रित किया जाना संभव नहीं है। हर प्रकार के नये करों के सुझाव तथा बचत व ऋण की योजनाओं पर विचार किया गया, परन्तु इससे अधिक साधनों का उपलब्ध होना असंभव जान पड़ा। यही कारण है कि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना आकार में छोटी थी और उसमें लगभग आधी पूंजी कृषि, सामुदायिक विकास तथा सिंचाई और बिजली की योजनाओं पर खर्च की गई।

(शेष पृष्ठ १७५ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

बजट परिशिष्ट
•
मार्च १९६०

बजट और आधुनिक अर्थशास्त्र

प्रो० विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, एम० ए०

शास्त्रीय आर्थिक सिद्धान्त यह मानता था कि व्यक्तिगत व्यवसाय किसी भी समाज में पूर्ण-वृत्ति (पूर्ण रोजगार) की स्थिति स्वतः ही स्थापित किये रखता है। यह सिद्धांत फिजिओक्रैट्स की भव्य 'प्राकृतिक व्यवस्था' और आदम स्मिथ की मंगल-विधायिनी 'अदृष्ट सत्ता' की कल्पना (जिसके आधार पर उसने आर्थिक क्षेत्र में 'स्वच्छतावाद' (Laissez faire) का प्रचार किया जो पूँजीवाद का मूल दर्शन कहा जा सकता है) कि तार्किक निष्पत्ति था। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों* ने हर प्रकार के सरकारी आर्थिक हस्तक्षेपों को अनावश्यक और अवांछनीय बताया। उनके मतानुसार राज्य व्यावसायिक क्रियाओं के स्तर को बढ़ा नहीं सकता। यदि कभी सरकार ने रोजगार (वृत्ति) के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिये अपने व्यवसायों को बढ़ाने का निर्णय किया भी तो वह ऐसा अपने व्ययों को बढ़ाकर ही कर सकती है। अधिक व्यय के लिये सरकार को जिस अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता होगी वह

(क) करों को बढ़ाकर प्राप्त हो सकता है; अथवा

(ख) अतिरिक्त मुद्रा की सृष्टि कर प्राप्त हो सकता है।

करों के बढ़ाने से जनता की क्रय शक्ति कम हो जायेगी तथा बचत में कमी के कारण पूँजी-निर्माण की गति शिथिल पड़ जायेगी। इन दोनों का ही परिणाम यह होगा कि क्रमशः बाजार-माँग (Market Demand) और विनियोग (Investment) में ह्रास के कारण उत्पादन का स्तर गिर जायेगा और रोजगार में कमी हो जायेगी। अतिरिक्त मुद्रा की सृष्टि से मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, जिसका अप्रत्याशित प्रतिकूल प्रभाव उपभोक्ता के जीवन-स्तर पर पड़ेगा।

इस तरह 'रोजगार' की वृद्धि के लिये नयी मुद्रा की सृष्टि का उपाय जनता के लिये महँगा पड़ेगा।

इन सब तर्कों के बल पर प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने वित्त-पत्र (बजट) के निर्माण-सम्बन्धी तीन निष्कर्ष निकाले थे—

(क) बजट को छोटा रक्खा जाय,

(ख) बजट को सन्तुलित रक्खा जाय,

(ग) ऐसी कर-पद्धति का निर्माण हो, जो उपभोग पर कर लगाए, न कि बचत पर।

आधुनिक-अर्थशास्त्र

आधुनिक युग के दिवंगत अर्थशास्त्री श्री जे० एम० किन्स ने अर्थशास्त्र के अनेकों क्षेत्रों में नये विचार दिए, जो प्राचीन (शास्त्रीय) अर्थशास्त्र से कई अर्थों में भिन्न थे और विरोध प्रगट करते थे। किन्स महोदय और उनके अनुयायियों के विचार-समुदाय को ही नव्य अथवा आधुनिक अर्थशास्त्र कहते हैं। इस आधुनिक अर्थशास्त्र के

* सर्व श्री आदम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस, मिल तथा अल्फ्रेड मार्शल तथा उनके अनुयायी अर्थशास्त्रियों को 'शास्त्रीय अर्थशास्त्री' अथवा 'प्राचीन अर्थशास्त्री' Classical Economists) की संज्ञा दी जाती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनुसार शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता कि वित्तपत्र बजट को सन्तुलित और छोटा होना चाहिए, सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में गलत तथा हानिकारक है। सुप्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री लर्नर ने संतुलित वित्त-पत्र के इस सिद्धान्त को पंसारी की दुकान का सिद्धान्त' (Principle of grocery Store) कहा है।

वित्त-पत्र किसी सरकार का निश्चित वित्तीय काल (साधारणतः एक वर्ष) के प्रत्याशित आय और प्रत्याशित व्यय राशि का विस्तृत उल्लेख होता है। यदि आय-राशि व्यय-राशि के बराबर हुई तो वित्त-पत्र सन्तुलित कहा जाता है। यदि व्यय-राशि आय-राशि से अधिक हुई तो वित्त-पत्र 'घाटे का' (Deficit) कहा जाता है, इसी प्रकार यदि आय-राशि व्यय-राशि से अधिक हुई तो वित्त-पत्र 'अधिक' या 'बचत' (Surplus) कहा जाता है। वस्तुतः वित-पत्र का ऋणात्मक और धनात्मक असन्तुलन विशेष आर्थिक एवं वितीय परिस्थितियों में राष्ट्र के व्यापक हित की दृष्टि से सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों में उतना अपेक्षित और अनिवार्य होता है जितना उनका सन्तुलन। अतः आधुनिक अर्थ शास्त्र संतुलित वित्त-पत्र के प्रति शास्त्रीय अर्थशास्त्र की भांति किसी प्रकार की अन्ध-भक्ति व अपरिवर्तनीय दृष्टि नहीं रखता। वृत्ति (रोजगार), पूंजीनियोजन तथा उत्पादन के वर्तमान स्तरों को देखकर अर्थतन्त्र में अपेक्षित परिणाम उत्पन्न करने के लिए बजट को असन्तुलित किया जा सकता है, क्योंकि बजट अपने आप में सिद्धि नहीं, अपितु राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक अंग का साधन मात्र है—एक संचालन-यंत्र है।

श्री किन्स के अनुसार वर्तमान समाज में व्यक्ति-गत तथा लोकगत अंचल (Private and Public Sectors) का कुल व्यय उस समय में पूर्ण वृत्ति (रोजगार) के लिए आवश्यक व्यय-राशि से कम होता है। ऐसी हालत में यदि राज्य अपना वित्त-पत्र व्यय के मदों को घटाकर या कम कर संतुलित रखता है तब अ-वृत्ति (बेरोजगारी) फैलेगी तथा लोगों की आय में कमी के कारण मांग में कमी होगी—जो उत्पादन में कमी करेगी जिससे पहले की अपेक्षा कुछ और अधिक बेरोजगारी फैलेगी, बेरोजगारी-हीन आय-माँग में कमी-उत्पादन का संकुचन और पुनः बेरोजगारी का यह दुश्चक्र राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को निरन्तर निम्नः तर स्तर पर उतारता जायेगा। अर्थतंत्र (उत्पादन, आय तथा वृत्ति) की इस अधोमुखी प्रवृति को रोकने का उचित और प्रभावकारी उपाय यह है कि आय और उपभोग अथवा पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक व्यय-राशि तथा वास्तविक व्यय राशि के अन्तर को मिटाने के लिए राज्य स्वयं अपना व्यय बढ़ाये। राज्य की इस नीति के कारण पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित की जा सकेगी, बाध्यता मूलक बेरोजगारी दूर होगी तथा आय एवं उत्पादन उच्चतम संभव स्तर पर ले जाये जा सकेंगे।

इस कार्य के लिए जिस अतिरिक्त कोष की आवश्यकता होगी, वह कर, ऋण तथा मुद्रा की सृष्टि, इन तीन मार्गों से जुटाया जा सकता है। प्रथम दो के कारण अपेक्षित परि-णाम उत्पन्न नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि अधिक कर तथा ऋण के बल पर एक तरफ जहाँ राज्य का व्यय बढ़ेगा। दूसरी तरफ उसी अंश में आय की कमी के कारण जनता का कुल व्यय घट जायेगा। अतः कुल व्यय की प्रवृति शून्य ही रहेगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अतिरिक्त सरकारी व्यय के कोषाधिक्य का प्रबन्ध रचित मुद्रा से ही होना चाहिए। रचित मुद्रा अविलम्ब वहाँ मुद्रा स्फीति उत्पन्न करेगी। जब तक देश में अनियुक्त उत्पादन के साधन रहते हैं तब तक अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति से उनका नियोजन सम्भव होता है कि जिससे मुद्रा की सृष्टि के साथ ही उत्पादन भी बढ़ता है और सामान्य मूल्य स्तर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यह किन की भाषा में 'हीन वित्तीकरण' 'घाटे का वित्तीकरण' (Deficit financing) या 'आय हीन व्यय' (Deficit spending) कहीं जाती है। राष्ट्रीय योजना समिति के शब्दों में—

"हीन-वित्तीकरण शब्द युग्म उस स्थिति को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें वित्तीय अल्पता के माध्यम से कुल राष्ट्रीय व्यय प्रत्यक्ष रूप से बढ़ा दिया जाता है। इस नीति का मूल तत्त्व सरकार के आय से अधिक व्यय करने में होता है। सरकार इस व्ययाधिक्य को अपने पूर्व संचित कोष का उपयोग कर तथा बैंकिंग जगत (मुख्यतः देश के केन्द्रीय बैंक) से उधार लेकर और इस प्रकार मुद्रा की सृष्टि करके पुरा कर सकता है।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

घाटे का बजट (Deficit Budget) और घाटे का वित्तीकरण (Deficit financing) का अन्तर स्पष्ट है। प्रथम सरकारी आय पर व्यय का आधिक्य मात्र है, यह आकस्मिक हो सकता है। किन्तु द्वितीय व्यायाधिक्य की आय पर सप्रयोजन और सौद्देश्य सृष्टि है।

कीन्स ने व्यापार चक्र की मन्दी और तत्कालीन बेरोजगारी को मिटाने के लिये 'हीन वित्तीकरण' का स्थायी नीति के रूप में उल्लेख किया है। इस नीति के पक्ष में उनके तर्क निम्नांकित हैं—

१. कुल व्यय राशि को पूर्णवृत्ति (पूर्ण रोजगारर) के हित में ऊंचा रखने का यह एकमात्र प्रभावपूर्ण ढंग है।*

२. जब तक देश में उपलब्ध साधनों की अनियुक्ति (Unemployment) रहेगी, इससे मुद्रास्फीति नहीं उत्पन्न होगी।

३. आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए देशों में जहां अतिरिक्त कर और लोक ऋण (Public Debt) प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय आय अल्प होती है, वहां विकास और योजना मूलक आर्थिक क्रियाओं को कोष-सम्वलित करने का यह एक मात्र उपाय है।

बजट का यह असंतुलन विपरीत दिशा में मोड़ा जा सकता है। अत्यधिक मुद्रा-प्रसार, ऊंचे मूल्य स्तर और तेजी के काल में सरकार को व्यय घटाकर तथा कर की दर तथा लोकऋण बढ़ाकर बाजार से अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति खींच लेनी चाहिये ताकि मूल्य स्तर सामान्य हो सके।

औषध नाकि भोजन

इतना होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि 'हीन वित्तीकरण' एक दम निरापद अस्त्र है। वस्तुतः 'हीन वित्तीकरण' दवा है, भोजन नहीं। इसके समर्थन और व्यापक प्रयोग के विरुद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा जो तर्क या आशंकायें उठायी जाती हैं वे निम्नांकित है—

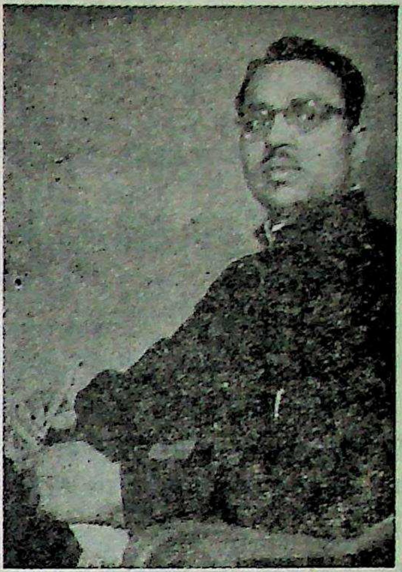

लेखक

१. आन्तरिक ऋण के कारण क्रय-शक्ति का हस्तांतरण धनियों के पास अधिक होता है जिससे राष्ट्रीय आय का वितरण दोषपूर्ण हो जाता है।

२. आशंका है कि सरकार हीन वित्तीकरण की मुद्रा-स्फीति परक प्रवृत्ति को रोक सकने में समर्थ न हो।

३. सरकारी पूंजीविनियोग के कारण व्यक्तिगत (Private) विनियोजन को धक्का लगेगा तथा निरुत्साह प्राप्त होगा।

४. औद्योगिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से अविकसित या अर्धविकसित देशों में उत्पादक वस्तुओं (Capital goods) तथा प्राविधिकों (Technicians) का अभाव होता है। साथ ही रूढ़िवादिता और श्लथता के कारण उत्पादन के साधनों की गतिशीलता भी पूर्ण और पर्याप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में सरकारी अतिरिक्त व्यय और मुद्रा सृजन का परिणाम मूल्य-स्तर की वृद्धि (मुद्रा-स्फीति) मात्र होगा।

५. हीन वित्तीकरण का सिद्धान्त, हो सकता है सरकार को असावधान और फिजूल खर्ची बना दे।

* पाश्चात्य अर्थशास्त्र की दृष्टि में पूर्णवृत्ति (Full Employment) की स्थिति, वह स्थिति है जिसमें कोई भी उत्पादन का साधन परेच्छया अनियुक्त नहीं होता है। इस प्रकार यह विचार केवल संख्यात्मक (Quantitative) है गुणात्मक (Qualitaiive) नहीं। किन्तु पूर्ण-वृत्ति समस्या केवल सभी साधनों को येन-केन नियुक्ति या वनाव मात्र देना ही नहीं होना चाहिए, उत्पादन के सभी योग्य साधन इस प्रकार कार्यरत होने चाहिएं कि वे समाज और अर्थतंत्र को अपनी सर्वोत्तम क्षमता और सर्वश्रेष्ठ सेवा दें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज-आय के विभिन्न साधन व सिद्धान्त

श्री सत्यदेव देराश्री

राज आय का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग-अलग तरह किया है। प्रोफेसर फिण्डले शिराज ने राज आय के साधनों को दो मुख्य भागों में बांटा है—१. करों से प्राप्त होने वाली आय (Tax Revenue) २. करेतर आय (Non Tax Revenue)।

करों से प्राप्त होने वाली आय में कभी कभी दण्ड या जुर्माने से प्राप्त होने वाली आय तथा कभी कभी सरकारी उद्योगों से प्राप्त होने वाली आय को भी शामिल कर लिया जाता है। किन्तु शिराज उसे दूसरे वर्ग में ही रखते हैं।

करों के अतिरिक्त दूसरे साधनो से होने वाली आय में ४ उपवर्ग हैं—(अ) सरकारी उद्योगों से प्राप्त होने वाली कीमतें जिनमें रेलों, डाक, तार, टेलीफोन, टकसाल, वन तथा सिंचाई आदि साधनों से प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित की जाती है। (आ) सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय, जिसमें विद्यालयों तथा अस्पतालों से प्राप्त होने वाला शुल्क आता है। (इ) सरकारी ऋणों से प्राप्त होने वाली आय जिसमें सरकार के अधीन कर्मचारियों को तथा अन्य व्यक्तियों को दिए गये ऋणों का ब्याज सम्मिलित होता है। (ई) विविध आय, जिसमें उपरोक्त वर्गों के अतिरिक्त अन्य सब आय के सूत्र सम्मिलित हैं। यथा विदेशी विनिमय आदि से होने वाली आय।

'कर' क्या है ?

प्रो० शिराज के अनुसार—'कर सार्वजनिक अधिकारियों को अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले अंशदान हैं जो सरकार का साधारण खर्चा चलाने के लिए दिए जाते हैं और जिनसे विशेष लाभों की आशा नहीं की जाती।

इस प्रकार कर की दो मुख्य विशेषताएं स्पष्ट हैं—१—कर की उगाही बाध्य रूप से की जाती है। इससे 'कर' और कीमत का अन्तर स्पष्ट है। क्रेता किसी वस्तु या सेवा का क्रय करते समय स्वेच्छा से कीमत देता है, परन्तु करदाता कर देने के लिए मजबूर किया जाता है। २—कर सरकार का साधारण खर्च चलाने के लिए वसूल किए जाते हैं। करदाता को कर के बदले विशेष सेवा या लाभ मिलना आवश्यक नहीं है।

अतः अर्थशास्त्रियों की राय में हीन वित्तीकरण के सिद्धान्त का प्रयोग यथेष्ट सतर्कता तथा निश्चियता के आधार पर ही होना चाहिए। हीन वित्तीकरण के कुप्रभावों के नियंत्रण तथा प्रतिरोध के लिए आधुनिक अर्थ-शास्त्र निम्नांकित उपाय बतलाता है जिन पर हीन वित्तीकरण सूत्र का उपयोग करने वाली सरकार की सतत एवं जागरूक दृष्टि रहनी चाहिए—

(क) पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद भी मुद्रा-सृजन के माध्यम से हीन वित्तीकरण करने से मुद्रास्फीति होगी। अतः पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद 'हीन वित्तीकरण' का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(ख) मुद्रा स्फीति के लक्षण दिखाई देते ही सरकार को केन्द्रीय बैंक की सहायता से मुद्रा संकुचन के उपाय प्रयोग में लाने चाहिएं।

(ग) चूँकि अविकसित देशों में उत्पादान में वृद्धि अतिरिक्त मुद्रा-सृष्टि के अनुपात में नहीं होती, बल्कि कम अनुपात में होती है) इसलिए सरकार को मुद्रा की सृष्टि के साथ ही जनता से ऋण लेकर मुद्रा-संकुचन के उपाय भी काम में लाने चाहिए तथा जनता की बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए।

(घ) हीन वित्तीकरण में परिकल्पित अतिरिक्त व्यय यथा सम्भव देश की उत्पादकता के विकास में होने चाहिएँ।

(ङ) यदि देश किसी अंश में 'महाजन' (Creditor) देश है तो उसे हीन वित्तीकरण कुछ काल के लिए उसी परिमाण में करना चाहिए जिस परिमाण में उसे विदेशी ऋण की चुकती पाने की सम्भावना है। भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में 'हीन वित्तीकरण' बहुत कुछ इसी सिद्धांत पर निर्मित किया था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शुल्क

शुल्क वह आमदनी है, जो कर और कीमत के बीच की होती है। यह वह वसूली है, जो आवर्तक सेवाओं के लिए की जाती है। ये सेवाएं राज्य द्वारा मुख्यतः सार्वजनिक हित के लिए की जाती हैं। परन्तु इनसे शुल्क दाता को कुछ विशेष लाभ होता है। उदाहरण के लिए शिक्षा शुल्क या रजिस्ट्री शुल्क आदि। कीमतों की तरह शुल्क देने वाले को भी विशेष लाभ होता है। परन्तु शुल्क लगाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है। और व्यक्ति विशेष का लाभ गौण होता है। करों की तरह शुल्क भी न्यूनाधिक बाध्य रूप से दिया जाता है।

चार प्रमुख सिद्धांत

एडम स्मिथ ने करों के चार प्रमुख सिद्धान्त (Canons of Taxation) बतलाए हैं।

पहला सिद्धांत—'समानता या न्याय का सिद्धान्त (Principle of Equality or Equity) है। प्रत्येक राज्य के प्रजाजनों को राज्य की सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुपात से यथा सम्भव कर देना चाहिए। इस नियम के पालन या उल्लंघन में कर की समानता या असमानता है।

उपर्युक्त नियम का आशय यह है कि कर इस प्रकार लगाए जाएं कि प्रत्येक करदाता को समान त्याग करना पड़े। साधारणतः केवल जीवनोपयोगी पदार्थों के प्राप्त करने के ही योग्य आय रखने वाले को कुछ भी त्याग करने में बहुत कष्ट होता है और उससे अधिक आय रखने वाले आदमी को उतना ही त्याग करने में अपेक्षाकृत कम कष्ट होता है। इस कारण करदाता की आय जितनी अधिक हो, उस पर कर उतनी ही ऊंची दर से लगे। अर्थात कर वर्द्धमान (Progressive) होना चाहिए।

दूसरा सिद्धान्त—स्पष्टता और निश्चिन्तता का सिद्धांत (Principle of Certainty) है। 'किसी व्यक्ति को जो कर देना पड़े, वह निश्चित हो। कर देने वाले व्यक्तियों को कर देने का समय, कर देने का ढंग और कर की मात्रा स्पष्ट रूप से ज्ञात होनी चाहिए।' कर की अनिश्चितता असमानता से भी अधिक बुरी है। यदि कर की मात्रा स्पष्ट और निश्चित न रहेगी तो कर वसूली करने वाला अधिकारी अधिक कर वसूली करके स्वयं खा सकता है।

तीसरा सिद्धान्त—सुविधा का सिद्धान्त (Principle of Convenience) है। 'प्रत्येक कर ऐसे समय में और ऐसी विधि से वसूल किया जाना चाहिए कि करदाता को अधिकतम सुविधा हो।' उदाहरणतः किसानों को लगान देने की सुविधा उस समय होती है, जबकि उनकी फसल घर आ सकती है। परोक्ष कर (Indirect Taxes) विशेष कर विलास सामग्री पर लगाये कर, अधिक सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि ये कर जब-जब चीज खरीदी जाती है, कीमत के साथ थोड़े-थोड़े वसूल किये जाते हैं।

चौथा सिद्धान्त—मितव्ययिता का सिद्धान्त (Principle of Economy) प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि 'राजकोष में आने वाली रकम से ऊपर करदाताओं के पास से कम से कम धन निकले और रहे।' इसका आशय यह है कि प्रजा से वसूल की हुई कर की आमदनी का अधिक से अधिक भाग सरकारी कोष में जमा हो जाय। कर वसूल करने का व्यय कम से कम हो, बहुत अधिक सरकारी नौकर केवल इसी काम के लिए न रखने पड़ें। यदि कर वसूल करने में अपेक्षाकृत अधिक खर्चा होता है या कर का देश के उद्योगधन्धों और सम्पत्ति-संचय पर कुप्रभाव पड़ता हो तो इस नियम की अवहेलना होती है।

कुछ अन्य सिद्धांत

श्री एडम स्मिथ के सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ अन्य विचारणीय नियम इस प्रकार हैं।

(१) कर प्रणाली ऐसी सरल होनी चाहिए कि साधारण नागरिक सुगमता से समझ सके।

(२) कर यथेष्ट लोचदार (Elastic) हों, जो देश की सुख समृद्धि की वृद्धि के साथ करों से होने वाली आय को उठावें और उसके कम होने के साथ इसको घटा दें, जो देश-काल के साथ घटाये बढ़ाये या बदले जा सकें।

(३) कर उत्पादक (Productive) हों अर्थात् ऐसे हों कि जिनसे राज्य को अपेक्षाकृत अच्छी आय हो सके।

(४) कर विविध प्रकार (Variety) के हों जिससे राज्य को किसी कर पर आश्रित न रहना पड़े। करों की संख्या अधिक होने से उनका भार अपेक्षाकृत कम मालूम पड़ेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बजट कैसे बनता है ?

कुछ लोगों के दिमागों में बजट का भय भूत की तरह समाया रहता है । अर्थशास्त्री सरकारी आर्थिक ब्यौरों को कुछ अजीब ढंग से रहस्यमय बना देते हैं और एक साधारण मनुष्य की यह इच्छा होती है कि न जाने वह कौन-सा समय आयेगा जब वह बजट के गोरख-धन्धे को समझने में समर्थ होगा ।

बजट भाषण

बजट का मूलाधार वित्तमंत्री का बजट भाषण होता है, जिसमें वह नये करों के प्रस्तावों की (यदि ऐसे प्रस्ताव होते हैं) व्याख्या करता है । साथ ही वह वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा भी देता है । इस प्रक्रिया को 'केन्द्रीय सरकार का बजट' कहते हैं । यह बजट वित्तमंत्री के बजट-भाषण के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है । वार्षिक आय-व्यय के ब्यौरे के दो भाग होते हैं—चालू और पूंजी । चालू आय को राजस्व आय-व्यय का हिसाब भी कहते हैं । इस मद की आय-व्यय से सरकार की साख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । उदाहरण के लिए, आय-कर से प्राप्त किया हुआ धन लौटाया नहीं जाता । इस प्रकार की आय को 'चालू आय' कहते हैं । इसी प्रकार राज्य-प्रबन्ध पर किया हुआ व्यय किसी से वसूल नहीं किया जाता, जबकि भवन-निर्माण पर किया हुआ व्यय उसे बेचकर वापिस प्राप्त किया जा सकता है । पहले प्रकार का व्यय 'चालू व्यय' कहलाता है, और दूसरे प्रकार का 'पूंजीगत व्यय' ।

पहली बात

बजट की सबसे पहली बात होती है चालू हिसाब की । चालू हिसाब से यह पता चलता है कि एक्साइज ड्यूटी, आय-कर, सम्पत्ति-कर, डाकखाने और तार-घर आदि, केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित बिजली की योजनाओं तथा इसी से मिलती-जुलती अन्य योजनाओं का क्या आय-व्यय है । व्यय के खाते में इस प्रकार की मदें होती है—जैसे प्रशासनिक, सार्वजनिक कार्य और प्रतिरक्षा व्यय । अर्थशास्त्र की दृष्टि से वही बजट उचित और विद्वतापूर्ण समझा जाता है जिसमें आय-व्यय समान हों ताकि चालू हिसाब में पिछले घाटे का दबाव न पड़े । इस हिसाब में चार वर्षों का उल्लेख होता है—

१. अनुमानित बजट
(आगामी वर्ष की आय-व्यय का अनुमान)
२. संशोधित (Revised) बजट—
(ठीक-ठीक आय-व्यय का ब्यौरा)
३. चालू वर्ष का अनुमानित बजट, और
४. गत वर्ष का हिसाब

पूंजीगत व्यय

दूसरी बात होती है सरकार के अन्य आय-व्यय की । पहली बात में जो लाभ या घाटा होता है, वह सबसे पहले इस मद में लिखा जाता है । पूंजीगत व्यय में वे सारे ऋण लिखे जाते हैं जो केन्द्रीय राज्य सरकारों को विकास आदि के कार्यों या अन्य कार्यों के लिए देती है । आय के खाते में वे ऋण की मदें लिखी जाती हैं जो सरकार जनता या रिजर्व बैंक से लेती है । इसी मद में अल्प बचत योजनाओं, प्रोविडेन्ट फंड आदि की आय का भी उल्लेख होता है । अंतिम मद में उस नकदी का हवाला होता है जो सरकार के पास होती है । इस मद में उल्लिखित हिसाब तीन शीर्षकों में रखा जा सकता है—

१. भारत का समेकित फंड (Consolidated Fund) इस फंड में कर या उधार से अर्जित धन का उल्लेख होता है ।

२. आकस्मिक फंड—इसमें अप्रत्याशित व्यय के लिए धन रक्खा जाता है और,

३. सार्वजनिक खाता—इसमें प्रोविडेन्ट फंड, डाकघर की बचत योजना, राष्ट्रीय सेविंग सर्टिफिकेट तथा अन्य विभिन्न धरोहरों (Deposits) का उल्लेख होता है ।

सरकार के काम पर चूंकि संसद का नियंत्रण होता है, अतः इस प्रकार का विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । समेकित फंड में से सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन के अतिरिक्त अन्य

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सब प्रकार के खर्चों के लिए संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। कहने का अर्थ यह है कि सार्वजनिक खाते के धन पर सरकार का अधिकार नहीं होता, बल्कि जनता की ओर से सरकार उसे अपने संरक्षण में रखती है। इसलिए जब भी सरकार को आवश्यकता होती है, वह इस खाते में से संसद की स्वीकृति के बिना व्यय कर लेती है। बाकी के शेष आर्थिक खातों में इन्हीं तीन खातों का विस्तार से विवरण होता है। उदाहरण के लिए, इन विवरणों से आप तुरंत मालूम कर सकते हैं कि सरकार ने गत वर्ष सार्वजनिक कार्यों या अकाल पीड़ितों की सुरक्षा के लिए या भारतीय शासकों के भत्तों में कितना व्यय किया, अथवा आगामी वर्ष में कितना व्यय करने का इरादा है। इसी प्रकार आप यह भी जान सकते हैं कि प्रतिरक्षा के लिए अथवा ब्याज चुकाने के लिए पिछले वर्षों में सरकार ने कितनी धन-राशि का व्यय किया। विवरणों से ही यह पता चलता है कि कर उगाहने में कितना व्यय हुआ। यही कारण है कि बजट में आपको एक व्यय का खाता 'यूनियन एक्साइज़ ड्यूटीज' के नाम से मिलेगा जो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि 'एक्साइज़-ड्यूटी' से आय होती है, व्यय नहीं। इस खाते का अर्थ-प्रायः उस व्यय को प्रदर्शित करना है जो 'एक्साइज ड्यूटीज़' वसूल करने में खर्च हुआ है। इससे हुई आय का विवरण आय वाले खाने में देखा जा सकता है।

प्रवर्तित ऋण

अर्थ शास्त्री 'घाटे की वित्त-व्यवस्था' के बारे में प्रायः कहते सुने जाते हैं। इस व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। चालू हिसाब के विषय में जो घाटा बजट में बताया जाता है, इस व्यवस्था का उस घाटे से कोई सम्बन्ध नहीं होता। घाटे की वित्त-व्यवस्था का अर्थ है वह समूचा घाटा जो चालू एवं पूंजीगत हिसाबों दोनों के कारण होता है। इसलिए आय के खाते में एक मद होती है जिसे 'प्रवर्तित ऋण' (Floating Debt) कहते हैं। इसमें अपनी कीमती धरोहर (ट्रेजरी बिल्ज) बेचकर सरकार रिजर्व से ऋण लेती है। कभी कभी जब ट्रेजरी के बिलों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो सरकार इनके बदले में अपनी कोई कीमती वस्तु धरोहर के रूप में रख देती है। इसलिए प्रवर्तित ऋण से सही आंकड़ों का पता करना बहुत मुश्किल होता है। इनके लिए सभी विभिन्न मदों का जानना आवश्यक है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रत्येक आय-व्यय की मद की व्याख्याएं एक अलग परिचय में दी जाती हैं जिसे 'व्याख्यात्मक ज्ञापन' कहते हैं। जिससे प्रत्येक साल के आय-व्यय को समझने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, आपको ज्ञात है कि पिछले वर्षों में धातु और सिक्कों के प्रचलन से आय में वृद्धि हुई। यदि आप इसका कारण जानना चाहते हैं, तो आपको यही ज्ञापन देखना चाहिए। इससे पता चलता है कि इस वृद्धि का मुख्य कारण रिजर्व बैंक के लाभ की वृद्धि है, क्योंकि सरकार ने एक खासी राशि रिजर्व बैंक से ऋण में ली है। और खासी राशि उसके ब्याज में दे रही है। इसी प्रकार व्यय के खाते की मदों को भी समझना चाहिए।

(एक अंग्रेजी लेख के आधार पर)

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनीतिक अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिकअली

सम्पादक : श्री सुनील गुह

★ हिन्दी में अनूठा प्रयास

★ आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख

★ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु०   एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ग्रामीण-उद्योगों से अधिक रोजगार

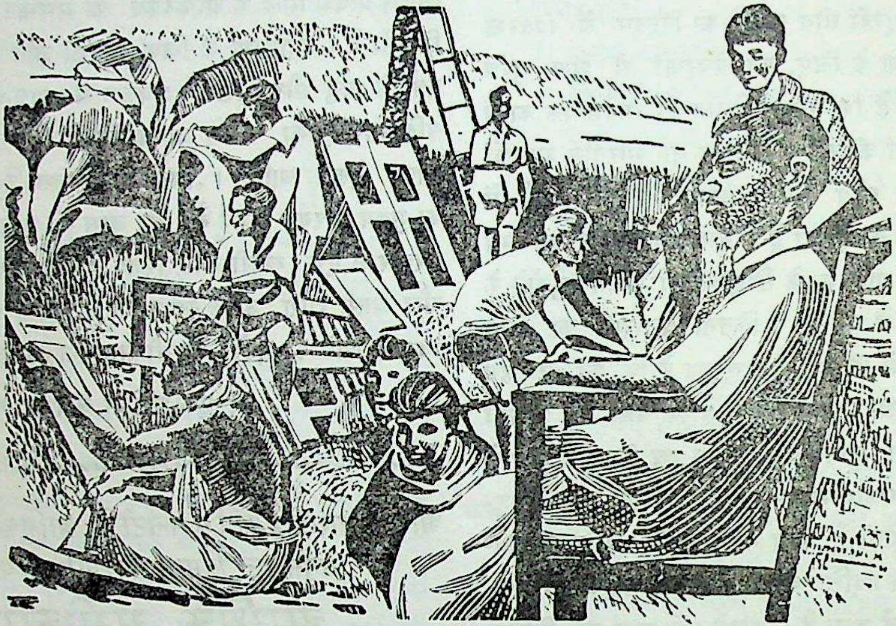

स्थानीय लोगों के उत्साह और कुशल संगठन द्वारा उड़ीसा के पुरी जिले के तेजपुर गांव में रोजगार की सुविधाएं बढ़ गयी है ।

इस गांव के निवासी श्री अर्जुनदास ने एक बहुमुखी सहकारी समिति शुरू की । यह समिति बढ़ई का काम सिखलाती है । इसके कारखाने में मेज, कुर्सियां और खिड़कियों व दरवाजों की चौखटें बनाई जाती हैं, जिन्हें सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं खरीद लेती हैं ।

साथ ही एक और उपयोगी धंधा इस समिति ने शुरू किया है—नारियल रेशे का उद्योग । इससे रस्से, रस्सियां, चटाइयां और अन्य चीजें तैयार की जाती हैं, जो आस पास के गांवों में बिक जाती हैं ।

गांवों की दस्तकारियों को प्रोत्साहन दीजिये । इनसे रोजगार बढ़ता है और आय भी

योजना की सिद्धि आपकी समृद्धि

DA-59/514

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्र की आर्थिक स्थिति : एक समीक्षा

श्री मोरारजी देसाई

यह वर्ष दूसरी योजना का आखरी वर्ष होगा और इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि जब वर्ष समाप्त हो और तीसरी योजना शुरू हो, तब देश की अर्थ-व्यवस्था भली-भाँति सन्तुलित रहे।

चालू वर्ष के बजट में ७८०.१० करोड़ रु० के राजस्व और राजस्व से किए जाने वाले व्यय के लिए ८३६.१८ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी, जिससे राजस्व खाते में ५६.०८ करोड़ रु० की कमी रही। वास्तविक आय की प्रवृत्ति को देखते हुए अब अनुमान है कि ८३८.६६ करोड़ रु० की राजस्व प्राप्ति होगी और ८५४.०५ करोड़ रु० का खर्च होगा और कमी केवल १५.३६ करोड़ रु० रह जायगी।

राजस्व में ५८.५६ करोड़ रु० की वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से अधिक प्राप्ति हुई। अब अनुमान है कि सीमा शुल्कों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों से ५१०.८२ करोड़ रु० की प्राप्ति होगी। इसमें से ३५०.८२ करोड़ रु० की प्राप्ति उत्पादन शुल्कों से ही हो जायगी। उत्पादन के बढ़ते जाने से राजस्व में सभी ओर सुधार हुआ है। आय कर की प्राप्ति में जिसमें निगम कर भी शामिल है, सम्भवतः ५ करोड़ रु० की वृद्धि होगी, लेकिन सम्पति कर, व्यय-कर और दान-कर से होने वाली कुल प्राप्ति में १.६ करोड़ रु० की कमी रहेगी। लोहे और इस्पात के अधिभार (सर-चार्ज) से जो लोहा और इस्पात समकरण निधि को दे दिया जाता है, ६ करोड़ रु० अधिक प्राप्त होने की सम्भावना है, जबकि पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अनुसार, अमरीकी सरकार से १३ करोड़ रु० कम अनुदान प्राप्त होंगे।

प्रशासन व्यय में वृद्धि

इस वर्ष ६१०.३५ करोड़ रु० का असैनिक व्यय होने का अनुमान है, जबकि मूल बजट में ५६६.५० करोड़ रु० का अनुमान किया गया था। प्रतिरक्षा व्यय का अनुमान २४३.७० करोड़ रु० है, जबकि मूल बजट में २४२.६८ करोड़ रु० का अनुमान किया गया था।

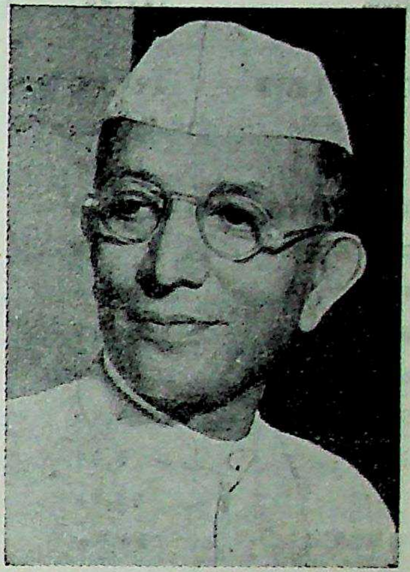

वित्तमंत्री : श्री मोरारजी देसाई

असैनिक खर्च में १३.८५ करोड़ रु० की वृद्धि कई मदों के अन्तर्गत होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव है। जैसे ऋण सम्बन्धी अदायगियाँ, लोहे और इस्पात के अधिकार का इस्पात समकरण निधि में दिया जाना, विस्थापितों पर खर्च, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से राज्यों के हिस्से की अदा की जाने वाली रकम में वृद्धि और कम्पनी करों में परिवर्तन के कारण राज्यों के आय कर के हिस्से में हुई कमी की पूर्ति।

१.०२ करोड़ रु० की वृद्धि दिखलाई गयी है। इसका कारण वायुसेना के बजट में वृद्धि है, जो मुख्यतः विदेशों में खरीदे गये सामान के सम्बन्ध में १६५८-५६ से आगे लाई गयी देनदारियों और वर्ष के अन्दर मंजूर किए गए प्रस्तावों के कारण हुई है। जल सेना के खर्च में कमी हुई है, जिसका मुख्य कारण सामान की खरीद में कमी होना है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आय

(लाख रुपयों में)

	बजट	बजट
राजस्व	१९५९-६०	१९६०-६१
सीमा शुल्क	१३२,७०	१७०,००)
		+२,५०)
केन्द्रीय, उत्पादन शुल्क	३२४,३२	३५८,९१)
		+ २१,०३)
निगम कर	५८,७५	१३५,००
निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर	८७,६३	५२,९४
मृत सम्पत्ति शुल्क	१४	१०
सम्पति कर	१३,००	७,००
रेल किराया कर	११	११
व्यय कर	१,००	९०
दान कर	१,२०	८०
अफीम	३,९२	५,६९
ब्याज	१०,७५	१५,७१
असैनिक प्रशासन	३५,८०	५३,१९
मुद्रा और टकसाल	५५,६०	५७,२२
असैनिक निर्माण कार्य	३,००	३,०४
राजस्व के अन्य स्रोत	४१,९३	३९,७३
डाक और तार सामान्य राजस्व में वास्तविक अंशदान	४,२०	४७
रेलें–सामान्य राजस्व में वास्तविक अंशदान	५,९८	५,६४
जोड़ राजस्व	७८०,१०	८९६,४५

वित्त वर्ष १९६०-६१

वर्तमान कर-व्यवस्था के आधार पर १९६०-६१ के वर्ष ८९६.४५ करोड़ रु० की राजस्व-प्राप्ति और ९८०.३५ करोड़ रु० के व्यय का अनुमान है। इस प्रकार राजस्व खाते में ८३.९० करोड़ रु० का घाटा रहेगा। सीमा शुल्कों से उतनी ही राजस्व प्राप्ति होगी, जितनी चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में रखी गई है, अर्थात १६० करोड़ रु०। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से ३५८.९१ करोड़ रु० की प्राप्ति का अनुमान है, जो संशोधित अनुमान से ८.०९ करोड़ रु० अधिक है। आय-कर और निगम-कर की प्राप्तियों में १० करोड़ रु० की वृद्धि की सम्भावना है। सम्पति कर में ५ करोड़ रु० की कमी होगी, क्योंकि कम्पनियों पर लगने वाला कर उनके आय-कर में मिला दिया गया है। ब्याज प्राप्तियों में ७.४४ करोड़ रु० की वृद्धि होगी, जिसका मुख्य कारण दो इस्पात कम्पनियों और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से होने वाली अनुमानित प्राप्तियाँ हैं। कम्पनी आय कर को निगम-कर में मिला देने से अगले वर्ष आय में से राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से में २७.२६ करोड़ रु० कमी होगी, परन्तु यह इरादा है कि जब तक अगला वित्त आयोग आयकर के बंटवारे के बारे में अपनी रिपोर्ट न दे दे, तब तक राज्यों के घाटे की पूर्ति एक विशेष अनुदान द्वारा की जाती रहे।

अगले वर्ष में ९८०.३५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें से २७२.२६ करोड़ रु० प्रतिरक्षा सेवाओं पर और ७०८.०९ करोड़ रु० असैनिक कार्यों पर खर्च होगा। उन्होंने बताया कि असैनिक व्यय में संशोधित अनुमानों की अपेक्षा अगले, साल ९७.७४ करोड़ रु० की वृद्धि दिखायी गयी है। देशी और विदेशी ऋणों में वृद्धि होने से ऋण की अदायगी पर ९.४५ करोड़ रु० अधिक खर्च होने की सम्भावना है। विकास और सामाजिक सेवाओं पर, जिसमें सामुदायिक विकास सम्मिलित हैं, २७ करोड़ रु० अधिक खर्च होने का अनुमान है। लोहे और इस्पात-सम्बन्धी अधिकार के अपने आप सन्तुलित होने वाले दो मदों और पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमरीका से प्राप्त होने वाले अनुदानों के कारण १५ करोड़ रु० की वृद्धि हुई है। आयकर में राज्यों के हिस्से में कमी होने से उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने वाले अनुदानों में अगले वर्ष २८ करोड़ रु० की वृद्धि होगी।

सेना में अधिक व्यय

अगले वर्ष प्रति रक्षा खर्च २७२.२६ करोड़ रु० होगा, जो २४३.७० करोड़ रु० के संशोधित अनुमान की तुलना में २८.५६ करोड़ रु० अधिक हैं। स्थल सेना और जल सेना के अनुमानों में वृद्धि होगी। जबकि वायु सेना के खर्च में कमी होगी। वायुसेना के खर्च में कमी का मुख्य कारण यह है कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में पहले वर्ष की देनदारियों की भारी रकमों को शामिल कर लिया गया है

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रतिरक्षा सेवाओं के अनुमान हमारी सीमाओं के मौजूदा खतरों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हो सकता है, बाद में इसी वर्ष, परिस्थितिवश आवश्यकता पड़ने पर, लोकसभा से अतिरिक्त रुपयों की मांग करनी पड़े।

कुछ विशेष बातें

एक-दो बातों का अगले वर्ष के अनुमानों पर असर पड़ता है। इनमें से पहली बात का सम्बन्ध डाक और तार विभाग से है। साधारण राजस्व और डाक तथा तार विभाग के बीच वित्तीय व्यवस्था की हाल में जाँच की गयी थी, खास तौर से इस ख्याल से कि डाक और तार विभाग अधिकाधिक पूंजी लगा रहा है और उसे पर्याप्त सुरक्षित निधि जमा करने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इसलिए यह निश्चय किया गया है कि अगले वर्ष से डाक और तार विभाग को उसी स्थिति में ले आया जाए, जिसमें सरकार के दूसरे बड़े-बड़े व्यापारिक विभाग हैं, जैसे रेलें। भविष्य में यह विभाग साधारण राजस्व को, वर्ष में लगी हुई औसत पूंजी पर, उसी दर से लाभांश देगा, जो भारतीय रेलों के लिए समय-समय पर लागू होगी। लाभांश देने के बाद विभाग अधिशेष (सरप्लस) की बाकी रकम अपनी सुरक्षित निधियों, खासकर नवीकरण सुरक्षित निधि (रिन्यूवलस रिजर्व फंड) को बढ़ाने के लिए रख लेगा।

वेतन आयोग

दूसरी बात का सम्बन्ध केन्द्रीय आयोग से है। आयोग की सिफारिशों पर अमल करने में सरकार को वार्षिक रूप से कुल मिला कर, जिसमें पहले ही मंजूर की जा चुकी अन्तरिम सहायता भी शामिल है, ४४ करोड़ रु० खर्च करना पड़ेगा। इस रकम के लगभग ५५ करोड़ रु० तक पहुँच जाने की सम्भावना है। सरकार ने आयोग की जो सिफारिशें स्वीकार की हैं, वह १ जुलाई, १९५९ से लागू हैं। लेकिन इस बारे में चालू वर्ष के बजट-अनुमानों में कोई व्यवस्था नहीं की गयी, क्योंकि सारी अदायगियाँ १९६०-६१ में की जाएंगी। इस प्रकार नए वर्ष के बजट में इस खर्च के लिए एक वर्ष से ज्यादा की व्यवस्था की गयी है।

व्यय

(लाख रुपयों में)

	बजट	बजट
राजस्व से प्रत्यक्ष व्यय	१०१,६५	१०७,३३
सिंचाई	१६	१७
ऋण व्यवस्था	५७,८८	७४,५९
असैनिक प्रशासन	२२२,७३	२६७,७६
मुद्रा और टकसाल	९,८३	१०,२७
असैनिक निर्माण और विविध		
सार्वजनिक सुधार कार्य	१९,३५	२०,३२
पैंशनें	९,६३	१०,११
विविध—विस्थापितों पर व्यय	१९,६९	२०,२८
अन्य व्यय	७१,३०	१११,७०
राज्यों के अनुदान आदि	४९,०२	५१,८१
असाधारण मदें	३५,२६	३३,७५
रक्षा सेवाएं (वास्तविक)	२४२,६८	२७२,२६
जोड़—व्यय	८३९,१८	९८०,३५
कमी (—) (—)	५९,०८	(—) ६०,३७

पूंजीगत व्यय

चालू वर्ष में पूंजीगत आवश्यकता का संशोधित अनुमान ३६२.८५ करोड़ रु०, अर्थात् ५७.२९ करोड़ रु० कम है। बचत मुख्यतः दो मदों में हुई है। अब रेलें १२१.८१ करोड़ रु० के मूल अनुमान की तुलना में केवल ८५.०३ करोड़ रु० खर्च करेंगी। अन्न की खरीद के वास्तविक व्यय में २१.०१ करोड़ रु० की कमी होगी। इसका मुख्य कारण बिक्री और वसूलियों से पहले की अपेक्षा अधिक प्राप्ति होना है।

अगले वर्ष के लिए ३७०.८४ करोड़ रु० की व्यवस्था है। औद्योगिक विकास का परिव्यय, मुख्यतः कोयला और तेल के विकास का खर्च, ३०.५९ करोड़ रु० अधिक होगा। रेलें और डाक तथा तार विभाग भी चालू वर्ष की अपेक्षा क्रमशः ३५.७८ करोड़ रु० और ३.६० करोड़ रु० अधिक खर्च करेंगे। अनाज के लेन-देन के वास्तविक व्यय में १९.४१ करोड़ रु० की वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्यों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

को ऋण देने के लिए अनुमानों में इस वर्ष २८२.१८ करोड़ रु० और अगले वर्ष ३३१.४१ करोड़ रु० रखे गए हैं। अन्य पार्टियों को, जिनमें पोर्ट ट्रस्ट, सरकारी स्वामित्व वाले निगम और विदेशी सरकारें शामिल हैं, ऋण देने के लिए इस साल २२१.७४ करोड़ रु० और अगले साल १७६.७४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है।

योजना के लिए धन

योजना को चलाने के लिए अगले वर्ष के अनुमानों में कुल ८८६ करोड़ रु० की व्यवस्था है, जिसमें से १७३ करोड़ रु० राजस्व बजट में और ७१६ करोड़ रु० पूंजी बजट में है। इसमें से ६४ करोड़ रु० राजस्व बजट में और १७५ करोड़ रु० पूंजी बजट में राज्यों की सहायता के लिए है। इसके अलावा अपने साधनों से रेलें ३४ करोड़

वार्षिक बजट केवल सरकार की गृहस्थी का हिसाब नहीं होता। प्रत्येक बजट देश के निरन्तर विकास की एक अवस्था बतलाता है और इसकी सार्थकता विकास को आगे बढ़ने में है।...हमें योजना को सफल बनाना है... (और तदर्थ) कर लगाकर तथा ऋण लेकर अधिकतम साधन जुटाना है, विकासेतर व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखता है और विकास की वित्तव्यवस्था के लिए केन्द्रीय बैंक से कम से कम उधार लेना है।

—मोरारजी देसाई

रु० और राज्य २४१ करोड़ रु० खर्च करेंगे। इस प्रकार १९६०-६१ का सम्पूर्ण योजना परिव्यय १,१७४ करोड़ रु० होगा। व्यय में साधारणतः होने वाली कमी को छोड़ते हुए, सरकारी क्षेत्र में योजना की ५ वर्ष की अवधि में लगभग ४,६०० करोड़ रु० का वास्तविक व्यय होगा। अनुमान है कि संगठित गैर-सरकारी क्षेत्र में लगायी गयी पूंजी योजना के लक्ष्य तक पहुँच जाए और हो सकता है कि यह कुछ बढ़ भी जाए।

उधार लेने का कार्यक्रम

अगले वर्ष २५०.करोड़ रु० का बाजार-ऋण लिया जाएगा। सरकार ने इनामी--बौंड जारी करने का निश्चय किया है। यह इनामी-बौंड १ अप्रैल, १९६० से बेचे जाएंगे और दो रकमों १०० रु० और ५ रु०—के होंगे। इन बौंडों के खरीदारों को उन लाटरियों में शामिल किया जाएगा, जिन्हें डाल कर हर तिमाही पुरस्कार विजेताओं के नाम निकाले जाएंगे। पुरस्कार पर आयकर नहीं लगेगा।

हाल के वर्षों में छोटी बचतों में बराबर वृद्धि हुई है। इस वर्ष ८२ करोड़ रु० तक इकट्ठा होने का अनुमान है, जबकि बजट-अनुमान ८५ करोड़ रु० है। अगले वर्ष के बजट में छोटी बचतों की वास्तविक रकम ९० करोड़ रु० रखी गयी है।

नवीनतम सूचना के अनुसार अगले वर्ष ३६२ करोड़ रु० की विदेशी सहायता मिलने की आशा है। चालू वर्ष में विदेशों से पर्याप्त सहायता मिली है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने निश्चय किया है कि बैंक की सम्बद्ध संस्था के रूप में एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ स्थापित किया जाए। इस संघ का कार्य है। अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसी शर्तों पर धन की व्यवस्था करना, जिनसे ऋण लेने वाले देशों की भुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति पर कम बोझ पड़े।

आर्थिक स्थिति की समीक्षा

चालू वर्ष में खेती की पैदावार के लक्षण अच्छे हैं। आशा है, १९५९-६० में अन्न की पैदावार का स्तर प्रायः उतना ही ऊंचा रहेगा, जितना १९५८-५९ में था। कपास और जूट की उपज में कुछ कमी हो सकती है।

औद्योगिक उत्पादन में १९५९ के पहले दस महीनों में लगभग ७.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले दो वर्षों के मुकाबले काफी अधिक है। इस वर्ष की एक बड़ी विशेषता यह रही कि लोहे, इस्पात और एलुमिनियम के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्षमता का पहले से अधिक उपयोग किया जाना है। बहुत से उद्योगों में कुल उत्पादन-क्षमता भी बढ़ी है। तैयार मशीनों और साज-समान के उत्पादन में भी प्रगति हो रही है। भोपाल में बिजली के भारी यंत्र बनाने के कारखाने के निर्माण का पहला चरण प्रायः समाप्त हो रहा है। रांची में भारी मशीनें बनाने के कारखाने की क्षमता भी इतनी बढ़ायी जानी है कि प्रतिवर्ष ८० हजार टन की बनायी जा सकें।

चालू वर्ष में जहाजों की संख्या में बराबर वृद्धि होती जा रही है। १९५९ के अन्त में भारतीय जहाजों का कुल टन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भार ७ लाख ४० हजार था और अनुमान है कि १९६०-६१ के अन्त तक यह टन भार योजना के लक्ष्य—९ लाख—तक पहुँच जाएगा।

रिजर्व बैंक के पास जो सुरक्षित विदेशी मुद्रा निधि है, वह इस वर्ष प्रायः स्थिर रही है। निर्यात से होने वाली आय में कुछ बढ़ती और आयात में कुछ घटती हुई। परन्तु विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी स्थिति की मजबूती का बड़ा कारण विदेशी सहायता का अधिक मात्रा में उपलब्ध होना ही रहा। मुद्रा-उपलब्धि और ऋण सम्बन्धी प्रवृत्तियों से यह प्रकट होता है कि अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति पैदा करने वाला प्रभाव काफी प्रबल रहा। शेयर बाजारों में प्रायः वर्ष भर तेजी रही। इन सब बातों से जाहिर होता है कि अगले वर्ष मूल्यों की प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में बहुत सजग रहना, आयात में कड़ाई जारी रखना और साथ ही निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न अधिक तेजी से करना आवश्यक होगा।

पिछले कुछ वर्षों में जो पूंजी लगायी गयी है, उससे लाभ होने लगा है। और हम यह आशा कर सकते हैं कि अगले वर्षों में उत्पादन में काफी वृद्धि होगी, साथ ही देश में खपत और पूंजी लगाने की माँग बढ़ रही है और निर्यात बढ़ाने की भारी आवश्यकता भी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में इस बात का अधिक से अधिक प्रयास करना बहुत आवश्यक है कि कुल माँग उपलब्धि से बढ़ न जाए।

यह जरूरी है कि दूसरी योजना के अन्त तक विकास की जो गति हो जाएगी, उसे केवल ज्यों की त्यों ही न रहने दिया जाए, बल्कि इसे और भी तेज किया जाए। तीसरी पंचवर्षीय योजना का यही महत्वपूर्ण काम है। इस दिशा में सफलता पाने के लिए खेती की पैदावार बढ़ाना सबसे जरूरी है। किन्तु यदि अगले दस या पन्द्रह वर्षों में अर्थ-व्यवस्था को काफी तेजी से बढ़ना है तो उद्योग, खनिज, उत्पादन, बिजली, परिवहन और संचार जैसे दूसरे क्षेत्रों का भी तेजी से विकास करना पड़ेगा।

इस समय यह बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उन लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों को, जिनसे हमें हार्दिक प्रेम है, सुरक्षित और सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक विकास के महत्व को अच्छी तरह समझें और यह भी अनुभव करें कि विकास तब तक सम्भव नहीं, जब तक चीजों की खपत पर थोड़ा सा नियंत्रण न रखा जाए और हम राजस्व और मुद्रा विषयक ऊँचा अनुशासन न मानें। ● ●

'सम्पदा' के सम्बन्ध में जानकारी

रजिस्ट्रार न्यूज़ पेपर्स एक्ट के नियम ८ के अन्तर्गत विज्ञप्ति

१-प्रकाशन का स्थान	२८/११ शक्ति नगर, दिल्ली-६
२-प्रकाशन की अवधि	मासिक
३-४-५. मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक,	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	२८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६
६. स्वामित्व	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

मैं, कृष्णचन्द्र विद्यालंकार घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार बिल्कुल ठीक है।

प्रकाशक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्री लियाकत अली　　श्री षण्मुखम् चेट्टी　　श्री जॉन मथाई　　श्री चिन्तामणि देशमुख　　श्री मोरारजी देसाई

भारत के वित्तमंत्री : नीतियों का सिंहावलोकन

भारत १९४७ में पूर्ण स्वतंत्र हुआ किन्तु उससे पहले १९४६ में एक अंतरिम सरकार बनी थी । उसके प्रधान मंत्री यद्यपि श्री पं० जवाहरलाल थे, तथापि उसके वित्त-मंत्री मुस्लिमलीगी श्री लियाकत अली खां थे और उन्होंने ही सबसे पहला बजट पेश किया। उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, उन्होंने भारतीय उद्योग और व्यापार को, जो अधिकांशतः हिन्दुओं के हाथ में था, नष्ट करने के लिए उद्योग और व्यापार पर भारी कर लगा दिये । उनकी अव्यावहारिक कर नीति ने उद्योग के विकास पर बहुत बुरा प्रभाव डाला और देश में व्यापक असंतोष फैला। देश के विभाजन के साथ ही नई सरकार कायम हुई और श्री लियाकत अली को पाकिस्तान जाना पड़ा।

२—स्वतन्त्र भारत के प्रथम वित्त-मंत्री के रूप में सर षण्मुखम् चेट्टी आये । वे महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने लियाकत अली की अर्थ नीति को छोड़ कर व्यावहारिक नीति अपनाई। उस समय पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं हुआ था । पुनर्वास व अन्न की समस्या ही उनके सामने मुख्य थी। उनको अपनी स्वतन्त्र वित्त नीति निर्धारित करने का अवसर नहीं मिला कि उन्हें एक घटना के शिकार हो पृथक हो जाना पड़ा।

३—स्वतन्त्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री श्री जौन मथाई थे। वे भी महान अर्थशास्त्री थे। वे स्वतन्त्रचेता पुरुष थे। उन्होंने देश में गणतन्त्र स्थापित होने के बाद प्रथम बजट पेश किया जो बचत का बजट था। दूसरे बजट में भी उन्होंने ६० करोड़ रुपये की बचत दिखाई। उनकी सम्मति थी कि भारत गरीब देश है, इसलिए वहाँ राजस्व और पूंजीगत आय-व्यय के अलग २ बजट नहीं हो सकते, परन्तु उनका विचार सफल नहीं हो सका। पंचवर्षीय विकास योजनाएं बहुत विकासशील हो रही थी और वार्षिक आय में से विकास योजनाओं को चलाना सम्भव नहीं था। इस कारण यह मार्ग छोड़ना पड़ा।

कुछ समय बाद मंत्री मंडल से उनका गहरा मतभेद हो गया। योजना आयोग की देश में धूम मची। देश की अर्थ-नीति के निर्धारण का कार्य उसे सौंप दिया गया। श्री जॉन मथाई इसे मन्त्री मंडल की नीति-निर्धारण की स्वतन्त्रता पर प्रहार समझते थे। इससे वित्त मन्त्री योजना आयोग का अनुचर हो जाता था। फलतः उन्होंने त्याग पत्र दे दिया।

उन्होंने अपने बजटों में देश के उद्योगों और व्यवसायों को इस प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयत्न किया था, जिससे देश में पूंजी का निर्माण और संग्रह हो सके। दुर्भाग्यवश वह इस नीति का परिणाम प्रकट होने के पूर्व ही मंत्री मंडल से अलग हो गये।

४—श्री मथाई के बाद श्री चिंतामणि देशमुख ने इस भार को अपने कन्धों पर संभाला। वे भी देश के महान अर्थ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शास्त्री थे। वर्षों तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। उन्होंने पाँच-छः बजट पेश किये। मन्त्री मंडल की ओर विशेषकर प्रधान मंत्री की नीति को व्यवहारिक रूप देने में वे अत्यन्त कुशल थे। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को पूर्ण करने के लिए जहाँ सार्वजनिक ऋण लेने की नीति अपनाई, वहाँ उससे भी अधिक बल घाटे का अर्थ व्यवस्था पर दिया। उनके वित्त मंत्री काल में कागजी मुद्रा निरन्तर बढ़ने लगी। यदि देश का उत्पादन भी साथ बढ़ जाता तो मंहगाई न बढ़ती। श्री देशमुख ने इन दोनों से भी सन्तुष्ट न होकर नये-नये कर लगाने की नीति अपनाई। इससे औद्योगिक जगत में बहुत असन्तोष फैला।

कांग्रेस के समाज वादी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अथवा अकस्मात ही बिना किसी प्रयास के सरकार को करोड़ों, अरबों रुपयों का स्वामी बना देने के उद्देश्य से उन्होंने जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया। इसका निजी उद्योगों के उत्साह पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। श्री देशमुख ने भी बम्बई के विभाजन के प्रश्न पर वित्त मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया।

५—श्री देशमुख के त्याग पत्र के बाद जब श्री कृष्णमाचारी वित्त मंत्री बने, तब उद्योग को यह आशा थी कि वे उद्योग को उत्साहित करेंगे, किन्तु उन्हों ने उद्योग पर अधिक से अधिक कर लगाने की नीति का आश्रय लिया। सम्पत्ति कर, व्ययकर और उत्तराधिकार कर उनके समय में लागू हुए।

श्री कृष्णमाचारी ने स्वंय कहा था कि मेरी कर पद्धति की रूपरेखा द्वितीय योजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए है। अब नये करों की सम्भावना नहीं करनी चाहिए। उनके समय में देश की वित्तीय दशा बहुत चिन्तनीय हो गई और उन्हें विदेशों से सहायता लेने के लिए विदेशों की यात्रा करनी पड़ी, जिसमें उन्हें कुछ सफलता अवश्य मिली थी। श्री चिंतामणि ने जीवन बीमा उद्योग को इस आधार पर सरकार के हाथ में लिया था कि बीमा कंपनियों के कुछ संचालक बेइमानी करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं किन्तु मूंदड़ा काण्ड ने यह सिद्ध कर दिया कि सरकारी संस्थाओं में भी शिकायत के मौके मिलते हैं। इसी प्रसंग में श्री कृष्णमाचारी को भी त्यागपत्र देना पड़ा। उनके काल में तेजी से घटती हुई विदेशी मुद्रा एक गम्भीर समस्या बन गई।

६—नये वित्त मंत्री की नियुक्ति तक श्री नेहरू ने एक चलतू बजट पेश किया। इस बजट में भी कोई नई विशेषता न थी। नये करों की शृंखला में उपहार कर को भी जोड़ दिया गया था। एक आलोचक के शब्दों में नेहरू की बोतल में टी. टी. की शराब थी।

७—इसके बाद आये श्री मुरारजी देसाई। उन्होंने अब दूसरा बजट पेश किया है। बम्बई में देश के आर्थिक चक्र के निकट संपर्क में रहने के कारण वे उद्योग व व्यापार की समस्याओं के वास्तविक स्वरूप को भलि-भांति जानते हैं। उन्हें पिछले मंत्रियों की विभिन्न नीतियों और उनके परिणामों को देखने का भी अनुभव है। इसलिए अव्यावहारिक और भावकतापूर्ण नारों में वे नहीं बहते। आज देश की सरकार को जहाँ धन की आवश्यकता है, वहाँ आवश्यकता यह भी है कि सरकार के साथ-साथ निजी उद्योग भी अधिक विकास में पूरा सहयोग दें, इसी लिए उन्होंने नया मार्ग ग्रहण किया है। यथा शक्ति नये करों से बचते हुए देश में पूंजी निर्माण की सुविधाएं दी गई हैं। इसी लिए उनके बजटों का देश व्यापी विरोध के बजाय प्रायः स्वागत ही हुआ है। अप्रत्यक्ष कर भी जो लगाये गये हैं, वे सामान्य जनता पर बहुत बोझ नहीं डालते। जनता के एक बड़े भाग को देश के विकास में अनुदान देना चाहिए, इस दृष्टि से अप्रत्यक्ष कर बहुत प्रभावकारी होते हैं। विदेशों से सहायता प्राप्त करने की नीति पर श्री देसाई अधिक सफलतापूर्वक चले हैं। इनामी बोण्ड की नई योजना व्यवहार में कितनी प्रभावकारी होगी, यह आज कहना कठिन है।

वस्तुतः वित्त मंत्री की नीति अनेक वर्षों के बाद अच्छा या बुरा फल दिखाती है। इसलिए श्री देसाई की नीति पर अन्तिम रूप से कोई निश्चित मत प्रकट करना आज कठिन है। एक कमी सभी वित्तमंत्रियों की नीति में रही है कि उन्होंने बढ़ते हुए शासन व्यय, कर्मचारियों व भारी वेतनों व भत्तों में कमी करने का साहस नहीं दिखाया। जहाँ आवश्यकता आय बढ़ाने की है, वहाँ व्यय में कमी भी कम आवश्यक नहीं है।

यदि चीन से अत्यन्त संकट के कारण रक्षा व्यय बहुत न बढ़ जाता तो संभवतः करों में भी अधिक कमी होती।

• •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्पादन कर बढ़ रहे हैं !

यदि अंग्रेज जाति की नब्ज़ को पहचानना हो तो ब्रिटिश पार्लियामैण्ट पर नहीं, लन्दन के स्टाक एक्सचेंज की गतिविधि पर दृष्टि डालनी चाहिए, इन शब्दों में जर्मनी के प्रसिद्ध राजनैतिक 'विस्मार्क' ने १९ वीं सदी में एक सत्य का प्रकाशन किया था। वस्तुतः व्यापारी वर्ग बहुत अनुभवशील होता है और देश में होने वाली विविध सरकारी या गैर सरकारी प्रवृत्तियों का उस पर एक दम प्रभाव पड़ता है। निकट भविष्य में होने वाली अपने अनुकूल या प्रतिकूल का भी तत्क्षण प्रवाव पड़ता है।

ब्रिटेन की भांति अन्य देशों में भी सरकार इसीलिए देश के शेयर बाजारों पर विशेष दृष्टि रखती हैं। विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री नये टैक्स लगाने के विरोध में कितनी ही आलोचनाएं क्यों न करें सरकार यह देखती है कि नये करों का शेयर बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि शेयरों के मूल्य में बहुत गिरावट नहीं आई तो स्पष्ट है कि अभी जनता में कर देने की शक्ति है।

भारत सरकार की गत २० वर्षों से निरन्तर कर बढ़ाने की नीति रही है, यह भी निम्न अनुपात तालिका से स्पष्ट हो जायगा।

कर	१९३८-३९	१९५९-६०
तट कर	४८.९	१८.३
आय कर	१९.१	१९.९
उत्पादन कर	१०.५	४५.१७
अन्य	१.६	१.५

इन अङ्कों से यह स्पष्ट है कि कुल कर राशि में तटकरों का अनुपात ४८.९ प्रतिशत से गिर कर २० वर्ष के बाद १८.३ प्रतिशत रह गया। अन्य करों के अनुपात में बहुत अन्तर नहीं हुआ, तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आयकर का अनुपात १९ प्रतिशत से बढ़कर १९४४-४५ में ४९.३ प्रतिशत हो गया था, फिर यह बहुत तेजी से गिरा और १९५०-५१ में ३०.६ प्रतिशत और १९५७-५८ में २७.३ रह गया। इस गिरावट का मुख्य कारण दूसरी ओर उत्पादन कर में भयंकर वृद्धि का होना था। इसके कारण करों का परस्पर अनुपात बहुत बदल गया। केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण उत्पादन करों का कुल कर राशि में अनुपात किस तरह बढ़ता गया, यह निम्न तालिका से स्पष्ट है—

उत्पादन कर का प्रतिशत अनुपात

१९३८-३९	१०.५
१९५०-५१	१६.७
१९५३-५४	२२.३८
१९५५-५६	२९.९४
१९५७-५८	३९.३३
१९५९-६०	४५.१७

१९३८-३९ की अपेक्षा आज सरकार को करों से ९ गुनी आय होती है और इस आय की वृद्धि में उत्पादन करों का बहुत बड़ा हाथ है। वे इतनी तेजी से बढ़े कि आय कर भी बढ़ने के बावजूद अनुपात में कम रह गये उत्पादन कर एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसका भार वस्तुत: उत्पादक या उद्योगपति पर नहीं, उपभोक्ता और जनसाधारण पर पड़ता है। शेयर बाजार की स्थिति बताती है कि इसका उद्योगपति पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। वह खरीददारों से ही यह कर वसूल कर लेता है। फलतः जन-सामान्य की क्रय शक्ति कम होती जा रही है और समर्थ उद्योगपति और भी अधिक सम्पन्न हो रहा है। वस्तुतः युद्ध के बाद इन अप्रत्यक्ष उत्पादन करों के द्वारा जन सामान्य पर ही अधिकतर भार डाला गया है।

आज के उत्पादन करों के द्वारा प्रति व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ता है इस बारे में इतना जानना ही काफी होगा कि प्रति दिन काम में आने वाली जनसाधारण की वस्तु चीनी पर ५ आना सेर सरकार करों के रूप में लेती है। कपड़ा, तम्बाकू, सिगरेट, दियासलाई, चाय और कोयला, मिलों का कपड़ा, बड़े कारखानों में बना हुआ जूता कोई नागरिक खरीदता है तो वह सरकार को कोई न कोई टैक्स देता है। इसी तरह सीमेन्ट और शराब तथा अन्य अनेक वस्तुओं पर भी सरकार ने जो कर लगा रखे हैं, उनका प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता है। और आज सरकार की अधिक आय बड़े उद्योगों के विकास के कार्य में व्यय होती है। एक नागरिक को इन सरकारी उद्योगों का तत्काल कोई लाभ नहीं दिखता और जब मिलेगा भी तो इतना अप्रत्यक्ष और इतना नगण्य होगा कि उनके लिए सहसा कोई त्याग करने में विशेष औचित्य नहीं देखता।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्यों और केन्द्र की सम्मिलित आय

इन पृष्ठों में सांख्यिकी देने का उद्देश्य यह है कि अर्थशास्त्र के प्रेमी विद्यार्थी जान सकें कि भारत व अन्य राज्यों की अर्थ व्यवस्था कैसे चलती है। केन्द्र व विभिन्न राज्यों की आय के स्रोत, व्यय के मद कौन-कौन हैं और उनमें पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं। चाहते हुए भी हम नवीनतम अंक प्रस्तुत नहीं कर सके, किन्तु इससे प्रमुख दिशा व तत्वों का समझने में कठिनता न होगी।

(लाख रुपयों में)

	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५८-५९
अ-करों की आय	७४१,७०	७६७,६१	१०५३,६२
१. आयकर	१४५,९९	१३४,४३	१६०,०५
२. निगम कर	४१,४१	३७,०४	५५,५०
३. उत्तराधिकार कर	—	१,८१	२,५३
४. व्यय कर	—	—	३,००
५. सम्पत्ति कर	—	—	१२,५०
६. उपहार कर	—	—	३,००
७. कृषि आयकर	४,३७	४,७१	७,८१
८. लगान (मालगुजारी)	५१.७५	७८८९	९९,१०
९. केन्द्रीय उत्पादन कर	८५,७८	१४५,२८	३०४.७६
१०. तटकर	२३१,६९	१६६,७०	१७०,००
११. राजकीय उत्पादन कर	५२-०९	५५,१५	४४,२३
१२. बिक्री कर	५९,०४	८०.१५	८७,१३
१३. रजिस्ट्रेशन स्टाम्प	२८,०२	३०८३	३५,७२
१४. मोटर गाड़ी कर	१०,१६	१५,९४	२०,८७
१५. रेल भाड़ा कर	—	—	९,६९
१६. मनोरंजन कर	८,९४	७,९५	८,९९
१७. अन्य कर	२२,४६	१८,१३	३०,७५

(लाख रुपयों में)

	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५८-५९
ब-कर भिन्न आय	१६९,७६	२२९,४६	३०९,७८
१. रेलवे	६,९३	५,८०	७,०४
२. डाक तार	३,४४	३,४७	२,३४
३. मुद्रा व टकसाल	११,३०	२३,०९	३६,६२
४. नागरिक प्रशासन	४८,५४	६५,२८	११२,९२
५. सुरक्षा	१५,३३	१६,१४	१३,६५
६. निर्माण	५,५१	८,७५	७,५९
७. वन (जंगल)	२४,७९	२९,५५	३५,९३
८. ऋण सेवा	८,२८	१४,३८	२५,९९
९. सिंचाई	८,०४	८,८६	१४,६०
१०. विद्युत योजना	३,४६	६,१७	८,१२
११. सड़क और पानी योजना	७८	२,८६	२,८६
२२. अन्य *	३३,३६	४७,११	४२,१२
स. फंडों से निकाला गया	९,८१	—	—
द. कुल योग	९२१,२७	९९७,०७	१३६३,४०

केन्द्र व राज्यों के उत्पादन-कर बढ़ रहे हैं, तटकर कम हो रहे हैं, निर्यात पर प्रतिबन्ध कर लग रहे हैं; उत्तराधिकार आदि कर नये लगे हैं, बिक्री कर निरन्तर वेग से बढ़ रहा है, मनोरंजन कर भी युग प्रवृत्ति के साथ आय का अधिकाधिक साधन बनता जाता रहा है, नये नये सिंचाई साधनों के कारण सिंचाई से भी आय बढ़ने लगी है। १९६०-६१ के अंकों से भी इसी प्रवृत्ति का विकास अधिक स्पष्ट होगा।

---

* बिजली कर, तम्बाकू कर, व्यापार कर अचल सम्पत्ति कर आदि अन्य कर सम्मिलित हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केन्द्र तथा राज्यों के सम्मिलित व्यय

	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५८-५९ (वी. ई)
अ. विकासेत्तर	५२९,७५	५७३,२१	७९६,८३
१. कर वसूली पर खर्च	३९,३५	५८,४९	७३,१३
२. ऋण सेवा	४७,४९	६१,५०	८६,७७
३. सुरक्षा	१८६,२८	१८८,३७	२९१,७९
४. प्रशासन	४७,९३	६२,५५	६५,४०
५. पुलिस	५९,२८	६२,९१	७४,३०
६. न्याय प्रशासन	१८,८२	१९,१६	२१,७८
७. स्टेशनरी तथा प्रिन्टिंग	६,९२	९,१६	११,३६
८. मुद्रा तथा टकसाल	२,५१	३,३४	८,५०
९. अन्य *	१२१,१७	१०७,७१	१६६,७६
ब. विकास सम्बन्धी	२५१,००	४२४,२०	५९३,०४
१. कृषि तथा ग्राम विकास	१७,०२	३१,०७	४१,२९
२. सिंचाई	१७,६७	२३,५३	२३,२१
३. बहुद्देशीय नदी घाटी योजना	२,१६	२,२४	७,९१
४. पशु चिकित्सा	४,४२	६,२३	१०,७७
५. सामुदायिक योजना	६	२४,९०	३४,९७
६. आदिम जाति क्षेत्र	१,७४	५,०१	९,४१
७. निर्माण कार्य	४९,५९	७६,१९	६६,४५
८. उद्योग	१६,४३	३०,०५	७७,७३
९. वन	१०,२८	१४,३३	१९,६६
१०. हवाई उड़ान	२,६७	२,५३	३,२५
११. वैज्ञानिक शोध	५,७३	९.४४	१९,१३
१२. शिक्षा	६५,३४	११५,३२	१५८,९४
१३. जन स्वास्थ्य और चिकित्सा	३१,७६	५०,०६	७०,३७
१४. आकाशवाणी	१,९५	२,६८	३,७४
१५. अन्य **	२६,१८	३०,६४	४६,२१
स. निधियों में हस्तान्तरण	४६	—	—
द. जम्मू कश्मीर को सहायता	—	४,००	४,२५
इ. कुल योग	७८१,२१	१०,०१,४१	१३९४,१२

* राजनीतिक पेंशन, विभाजन से पहले का भुगतान, प्रिवियर्स, अकाल पीडित सहायता आदि सम्मिलित हैं।

मँगाई तथा कार्य विस्तार के कारण प्रशासनिक व्यय, सेना सुरक्षा, शिक्षा जनस्वास्थ्य, चिकित्सा आदि सभी विभागों में केन्द्र व राज्यों के व्यय बढ़ते जा रहे हैं। १९५९-६० और १९६०-६१ में भी इन प्रवृत्तियों में कमी नहीं हुई।

** हलके मकानात, छोटे जहाज, बन्दरगाहों की मरम्मत, सहकारिता आदि विकास के कार्य सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक ऋण का औसत हिसाब

देशों के नाम	मापक इकाई	राष्ट्रीय आय	कुल आन्तरिक ऋण	विदेशों से कुल ऋण (वाह्य ऋण)	राष्ट्रीय आय का औसत
बर्मा	१० लाख में क्याता	४३३६	४९५	३८८९	१३.९
फ्राँस	१००० दस लाख में फ्राँस	१३९९०	५४१३	६३६७	४५.५
प० जर्मनी	,, दस लाख मार्क्स	१४७	१०	२०	१३.६
भारत	दस लाख रु० में	९६५००	२९३५९	३०५१३	३१.६
जापान	१००० दस लाख में येन	७४२७	४२६	५१५	६.९
ब्रिटेन	दस लाख पौं० में	१६४६५	२५२४६	२७३२१	७६५.९
संयुक्त राज्य अमरीका	१ हजार दस लाख डालरों में	३४४	२७३	२७३	७९.९

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्यों की आय

अनेक अर्थशास्त्रियों की सम्मति में राज्यों की आय के अधिकांश स्रोत अ-लोचशील हैं, जबकि व्यय के मद विकासशील। परन्तु राज्य के वित्त मंत्रियों ने बिक्रीकर व उत्पादन कर को अपनी प्रतिभा के बल पर लचीला बना दिया है। केन्द्रीय सरकार से भी निरन्तर आय बढ़ रही है। चीनी कपड़ा आदि के केन्द्रीय बिक्री करों का भी बड़ा भाग राज्यों को मिलने लगा है। सिंचाई व भूमि विकास कर भी राज्यों को लाभकारी प्रतीत हो रहे हैं।

	१९५७-५८	१९५८-५९
अ कर	४४९,१४	४७९,७०
१. आय कर का हिस्सा	७२,३६	७५,५२
२. उत्तराधिकार का अंश	२,४२	२,४२
३. कृषि आय कर	६,७७	७,८१
४. भूमि कर (लगान)	८५,६८	९६,५८
५. केन्द्रीय उत्पादन कर का हिस्सा	२९,७४	३४,११
६. अतिरिक्त उत्पादन	७,६७	३३,२७
७. राज्यीय उत्पादन कर	४३,२०	४२,५७
८. बिक्री कर	१०७,३३	८७,१३
९. रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प कर	८३०,९१	३१,७१
१०. रेल भाड़े पर कर	५०७	९,६०
११. मोटरगाड़ी विधेयक	१९,७५	२०,५३
१२. मनोरंजन व जुआ कर	९,७५	९,९९
१३. अन्य कर ❀	२६,४९	२८,४६
ब करों से भिन्न आय	१५८,६९	१७०,८६
१. प्रशासन	५७,०३	६८,६८
२. निर्माण कार्य	४,४१	४,७३
३. ऋण सेवा	१८,२३	१९,३९
४. वन (जंगलात)	३२,२०	३३,३६
५. सिंचाई	१०,२५	१४,५९
६. बिजली योजना	८,९५	८,११
७. सड़क और पानी योजना	३,०७	२,९०
८. अन्य ❀❀	२४,५५	१९,१०
स केन्द्रीय सहायता	१३४,९४	१४०,५९
१. जूट निर्यात कर का हिस्सा	३,१५	३,१५
२. आय में कमी के कारण सहायता	—	—
३. २७५१ विधान की धारा के अनुसार	३३,२५	३३,२५
४. अनुच्छेद २७५ (१) के अंतर्गत	३,९१	४,५४
५. कम्युनिटी प्रोजेक्ट तथा राष्ट्रीय विस्तार कार्य	१५,२३	१६,०७
६. केन्द्रीय सड़क कोष से	५,१२	४,५९
७. औद्योगिक मकानात तथा सफाई	१,७७	२,२७
८. विस्थापितों का पुनर्वास	१२,५६	१०,९५
९. हाथ करघा तथा कुटीर उद्योग	४,०७	५,४०
१०. बेकारी निवारण सहायता	९७	९३
११. कमी की आय वाले (ग) राज्यों की सहायता	—	—
१२. अन्य समस्त सहायताएं +	५४,९१	५९,५५
य कुल योग	७४२,७७	७९१,१५

❀ तम्बाकू, बिजली कर आदि सम्मिलित हैं।

❀❀ बहुद्देश्यी नदी घाटी योजनाएं और अन्य मिश्रित कार्य सम्मिलित है।

+ कृषि सहायता, सहकारिता पानी, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक मूलभूत आवश्यकताएं आदि सम्मिलित हैं।

जिला तथा स्थानीय बोर्डों के आय व्यय

(रुपए करोड़ों में)	१९५०-५१
आय	
प्रान्तीय दर	८.७५
सार्वजनिक कार्य	३.३५
अन्य साधन	१५.६७
कुल	२८.७७
व्यय	
शिक्षा	१३५.६
सार्वजनिक कार्य	७.६०
सफाई, स्वास्थ्य, तथा चिकित्सा आदि	२.८७
ऋण और अन्य मिश्रित विषय	५.४७
कुल	२९.५०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केन्द्र तथा राज्यों की आयव्ययक स्थिति

(लाख रुपयों में)

	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५८-५९
१. बचत अथवा घाटे की आय का लेखा	१४०,०६	—४,३४	—३०,७२
२. बचत या घाटा पूंजीगत	११५,२४	१६०,९५	२०७,१४
३. कुल बचत-अथवा घाटा	२४,८२	१६५,२९	२३७,८६

१९५१-५२ में बचत हुई है, पर अब तो घाटा परम्परा बन गई है।

केन्द्र की ओर से ऋण व सहायता

(लाख रुपयों में)

	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५८-५९
ऋण दिया			
(अ) राज्यों को	६०,७७	२४८,८७	२७९,३३
(आ) अन्य संस्थाओं को	१३,३१	३२,००	५५,६०

राज्य व अन्य संस्थाएं अब केन्द्र पर अधिकाधिक आश्रित हो रही हैं।

केन्द्र के अतिरिक्त करों से अनुमानित आय

(रुपए करोड़ों में) कुल आय

	१९५६-६१
आय कर तथा निगम कर	८३.२
उत्तराधिकार कर	१.५
सम्पत्ति कर	४४.२
व्यय कर	९.०
उपहार कर	६.०
आयात कर	२९.०
निर्यात कर	८.०
उत्पादन कर	४९७.७
यात्री भाड़ा कर	३२.४
डाकदर में परिवर्तन	१०.४
कुल	७०५.४

राज्यों में अतिरिक्त करों से अनुमानित आय

(रुपए करोड़ों में) कुल आय

	१९५६-५७	१९५६-६१
१. साधारण बिक्रीकर	४.४	८३.२
२. राज्यीय उत्पादन	०.२	३.६
३. कृषि आयकर	—	७.५
४. भूमि लगान तथा सिंचाई	०.१	९.६
५. खुशहाली कर	—	२.२
६. बिजली दर तथा कर	०.३	८.४
७. मोटर-यात्री व समान पर कर	० ३	१३.१
८. स्प्रिट और डिजेल तेल कर	०.३	७.०
९. स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन		३.७
१०. अन्य कर	३.१	३५.३

उक्त दोनों सूचियाँ बताती हैं कि केन्द्र व राज्यों के वित्तमन्त्री नये व अतिरिक्त करों से किस तरह आयके साधन जुटाते जा रहे हैं। नये बजट मी इसी कुशलता का परिचय देते हैं।

भारतीय नगरपालिकाओं की आय

(रुपए करोड़ों में)

आय के साधन	१९५०-५१
नगरपालिकाओं की करोकीपर तथा कर	
चुंगी	७.२१
मकान तथा जमीन कर	९.८५
पशु तथा भारवहन कर	१.०४
पेले और व्यापार कर	०.७२
सड़क तथा फेरी कर	०.५७
पानी का कर	४.५०
रोशनी कर	१.८२
सफाई कर	१.३९
अन्य कर	२ ०१
कुल	२९.१०
विशेष विधेयक के अन्तर्गत वसूली	०.१८
आय के अन्य साधन	११.४६
असाधारण कर तथा ऋण	७०.२८
कुल योग	१११.०२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संघ और राज्यों में राजस्व का वितरण

संविधान तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा भारत में संघ और राज्यों में कुल आय के मदों का वितरण किया गया है।

संघीय आय के स्रोत

केन्द्रीय सरकार के आय के मुख्य स्रोत निम्नांकित हैं:—

(१) आयात-निर्यात कर;
(२) संघीय उत्पादन कर;
(३) निगम और आय कर (कृषि आय करके अतिरिक्त);
(४) सम्पदा कर, धन कर, व्यय कर और उपहार कर;
(५) टकसाल तथा चलार्थ की आय;
(६) रेलों, डाक और तार घरों से प्राप्त होने वाली आय।

केन्द्रीय आय का लगभग ८५ प्रतिशत भाग आयात और निर्यात करों, उत्पादन करों तथा निगम और आय करों से प्राप्त होता है। सम्पदा कर की आय नगण्य है। शेष आमदनी मुद्रा, टकसाल रेलों तथा डाक और तार विभागों से होती है। संघीय सरकार को देश की सुरक्षा के अतिरिक्त नागरिक प्रशासन, आर्थिक विकास, सार्वजनिक निर्माण कार्य राज्यों की सहायता तथा ऋणों के ब्याज पर अपनी आमदनी का अधिकांश भाग खर्च करना होता है।

राज्यों की आय के मुख्य मद

१. राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले कर तथा उपहार जिनमें भूमि कर या मालगुजारी, राज्यीय आबकारी, स्टाम्प, रजिस्ट्री, मोटर कर, बिक्री कर, रोजगार कर, मनोरंजन कर और कृषि आय कर मुख्य हैं।

२. वे कर जिन पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है परन्तु जिनका कुछ भाग राज्य सरकारों को मिलता है। जैसे संघीय आय कर, सम्पदा कर, उत्पादन कर और रेल और भाड़ों पर कर।

३. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता या अनुदान।

४. राज्यों द्वारा चलाये जाने वाले व्यवसायों से आमदनी।

५. नागरिक प्रशासन तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यों से प्राप्त होने वाली आमदनी।

राज्यों की कुल आमदनी का लगभग आधा भाग उन करों से प्राप्त होता है जो राज्य सरकारें लगाती हैं। केन्द्रीय आय का ६० प्रतिशत भाग, सम्पदा कर का ९९ प्रतिशत और रेल भाड़ों पर उपकर का ९९.७५ प्रतिशत, तथा दियासलाइयों, तम्बाकू और वनस्पति, चाय, कहवा, चीनी, कागज और कुछ तेलों पर लगाये गये उत्पादन करों का २५ प्रतिशत भाग जो राज्य को मिलता है। जिससे राज्यों की कुल आमदनी का लगभग १३ प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। लगभग इतनी ही रकम राज्यों को केन्द्रीय सरकार से सहायता के रूप में मिलती है। राज्यों को नागरिक प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण कार्यों से क्रमशः १० प्रतिशत और ८ प्रतिशत आमदनी प्राप्त होती है।

१९५८-५९ का बजट

नीचे हम विश्व युद्ध से पूर्व १९३८-३९ तथा युद्ध काल १९४४-४५ के बजट संक्षेप में दे रहे हैं। इनसे यह मालूम होगा कि उन दिनों केन्द्रीय सरकार की आमदनी कितनी कम थी और युद्ध के दिनों ब्रिटिश सरकार ने कितनी बढ़ा ली तथा इसे कुल कितना व्यय करना पड़ता था।

	१९३८-३९	१९४४-४५
१. राजस्व	८५.५२	३५६.८८
व्यय	८५.१५	५१२.६५
प्रशासन	३८.९७	११५.४२
सेना	४६.१८	३९७.२३
बजट के सामान्य अंग	३६.७७	३६.७७
युद्ध की तैयारी	——	३३४.२२
३. राजस्व में घाटा	०.६३	९.३२
४. युद्ध का पूंजीगत व्यय		५९.४१
५. ब्रिटेन से प्राप्त युद्ध व्यय	——	४४३.०२
६. सेना पर कुल व्यय	——	७४४.२३

इस तालिका से यह मालूम पड़ता है कि युद्ध का व्यय ७ अरब तक पहुँच गया था और आशा थी कि यह व्यय फिर १९३९ के स्तर के आस-पास पहुँच जायगा किन्तु भीषण महगाई तथा पंचवर्षीय विकास योजनाओं के कारण आज भी भारत सरकार का व्यय ७-८ अरब रुपये से कम नहीं हुआ है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि १९३८-३९ का बजट समस्त अविभाजित भारत सरकार का बजट था, अब पाकिस्तान विहीन भारत का बजट है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्यों के बजट

इस वर्ष भी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने यह ध्यान रखा है कि नए कर लगाने के अप्रिय कार्य से बचें। इसलिए नये कर नहीं लगाए गए। इसी कारण केन्द्र पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं हुई। उत्तरप्रदेश व पंजाब के बजटों पर चीन की सीमावर्ती कठिनाइयों का प्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट है! समाज सुधार को विविध प्रवृत्तियों पर वित्त मंत्रियों ने अधिक ध्यान दिया है। विकास योजनाओं तथा सरकारी उद्योगों व व्यापारों से अब आय अधिक होने लगी है।

आँध्र—

कुल आय	८२.१७ करोड़ रु०
कुल व्यय	८१.१८ करोड़ रु०
कुल घाटा	२.६५ करोड़

कोई नया कर नहीं। उद्योग धंधों को अधिक सुविधा। मुंगफली व रुई पर विशेषकर स्थगित। खली पर बिक्री कर में कमी रियासतों से आय में ९५ लाख रु० की कमी।

उड़ीसा—

कुल राजस्व	३६६७.२१ लाख रु०
कुल व्यय	४०१७.४६ लाख रु०
घाटा	३५०.२ लाख रु०

राजस्व गत वर्ष से ६६४.०३ लाख रु० अधिक है, अतिरिक्त सिंचाई, जल मार्ग से माल परिवहन पर अतिरिक्त कर, अनाज आदि पर बिक्री कर से अधिक आय हुई है।

उत्तर प्रदेश —

राजस्व आय	१३०.९० करोड़ रु०
कुल व्यय	१३३.२३ करोड़ रु०
घाटा	२.३३ करोड़ रु०

कोई कर नहीं लगाये गये।

भारत सरकार की ओर से योजना व उच्च कार्यक्रमों के लिए १९.२६ करोड़ रु० मिलेगा। केन्द्रीय करों से राज्य के अंश के रूप में १६.७१ करोड़ रु० मिलने की आशा है। सिंचाई के क्षेत्र के बढ़ जाने के कारण सिंचाई कर से १ करोड़ रु० अधिक आय की आशा है। योजना की चालू स्कीमों के लिए २५.५७ करोड़ रु० की रकम निर्धारित की गई है। केन्द्रीय सरकार से ३१.९१ करोड़ रु० कर्ज की भी आशा वित्तमंत्री ने की है। उत्तरी सीमावर्ती प्रदेश में सड़क व विकास को अन्य योजनाओं के लिए काफी व्यवस्था इस वर्ष की विशेषता है।

जम्मू काश्मीर—

कुल आय	१९९१.६५ लाख रु०
कुल व्यय	१२८३.४० लाख रु०
	५९७.२५ लाख रु०

१५ वस्तुओं पर बिक्री कर लगाया गया। डीजल तेल पर ५ नये पैसे प्रति गैलन कर वृद्धि, मोटर गाड़ियों पर ३ से ५ प्रतिशत कर।

पंजाब—

कुल राजस्व आय	५८.४२ करोड़ रु०
कुल राजस्व व्यय	५७.७३ करोड़ रु०
कुल बचत	१.६१ करोड़ रु०
पूंजीगत आय	४६.२३ करोड़ रु०
पूंजीगत व्यय	५१.४१ करोड़ रु०
पूंजीगत घाटा	५.१८ करोड़ रु०

कोई नया कर नहीं लगाया। तिब्बत के समीपवर्ती क्षेत्रों का विकास नये बजट की विशेषता। तीसरी योजना की बजाय स्पीति में हवाई पट्टी इसी वर्ष बनाई जायगी। लोक हितकारी कामों पर ४०८ लाख रु० अधिक की व्यवस्था। चौथे दर्जे के कर्मचारियों के भत्ते की दर में वृद्धि। पूंजीगत घाटा ट्रेजरी बिलों की रकम निकाल कर पुरा किया जायगा।

बंगाल—

कुल आय	८८.१६ करोड़ रु०
कुल व्यय	८९.२३ करोड़ रु०
घाटा	१.०७ करोड़ रु०
पूंजीगत घाटा	१.५१ करोड़ रु०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बिहार—

राजस्व की आय	७९.३५ करोड़ रु०
कुल व्यय	७०.७० करोड़ रु०
बचत	८.६५ करोड़ रु०
पूंजीगत आय	५०.२३ करोड़ रु०
पूंजीगत व्यय	५९.३४ करोड़ रु०
घाटा	९.१ करोड़ रु०
विशुद्ध घाटा	३६ लाख रु०

२५०) रु० वेतन तक १०) रु० वृद्धि। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन में ५) रु० वृद्धि। विधायकों का वेतन २०० रु० से २५० रु० तक और भत्ता १० रु० से १५ रु०। इन वृद्धियों से २-२॥ करोड़ रु० अतिरिक्त व्यय।

मध्य प्रदेश—

कुल आय	६४६७.४१ लाख रु०
कुल व्यय	६५३०.४४ लाख रु०
कुल घाटा	६२.६५
पूंजीगत आय	५९.२६ करोड़ रु०
पूंजीगत व्यय	६०.३८ करोड़ रु०
घाटा	१.१२ करोड़ रु०

खर्च में योजना का खर्च १४५९.५२ लाख रु० भी सम्मिलित है। कोई नया कर नहीं। लोक सेवा आयोग से २.०८ करोड़ रु० की आय की संभावना और परिणामस्वरूप ३३ लाख रु० की बचत हैं इस वर्ष योजना के लिए ३६.०९ करोड़ रु०, जिसके लिए केन्द्र से २४ करोड़ रु० की सहायता संभावित है। सार्वजनिक ऋण के रूप में ५ करोड़ रु० और अल्प बचत के रूप में २॥ करोड़ रु० की आशा वित्तमंत्री ने प्रकट की है। राज्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है। और उसकी जनसंख्या का एक तिहाई भाग पिछड़े वर्गों का है, इसलिए वित्तमंत्री ने विकास साधनों की अपर्याप्तता पर चिन्ता प्रकट की।

आप 'सस्ता साहित्य मंडल' की पुस्तकों के प्रेमी हैं। सस्ता साहित्य के व्यापक प्रसार में कृपया योग दीजिये। अपने इष्ट मित्रों, अपने क्षेत्र की संस्थाओं तथा पुस्तकालयों से अनुरोध कीजिये कि वे 'मंडल' की पुस्तकें अपने यहाँ अवश्य रक्खें।

पर ऐसा आप तभी कर सकेंगे
जबकि
'मंडल' के नये प्रकाशनों से
आपका परिचय रहे। इसके लिए आप

जीवन-साहित्य

के ग्राहक बन जाएं। उसके प्रत्येक अंक में 'मंडल' के नवीनतम प्रकाशनों की सूचनाएं रहती हैं।
पत्र की सामग्री भी अत्यन्त उपादेय है।

वार्षिक मूल्य केवल रु. ४.००

सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

उद्योग-व्यापार पत्रिका

देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं? देश में क्या-क्या चीज़ें और कितने परिमाण में कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई कर सकते हैं? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या दशा है? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रह है? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य जानने चाहिए, और इन सबकी जानकारी पाने का श्रेष्ठ साधन है—उद्योग व्यापार पत्रिका। इसलिये आप ६ रु० भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक बन जाइये। नमूना पत्र लिखकर मंगाइये।

एजेन्टों को भरपूर कमीशन।
पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

टिकट सावधानी से चिपकाइये

इससे

डाक प्रेषण में शीघ्रता आती है

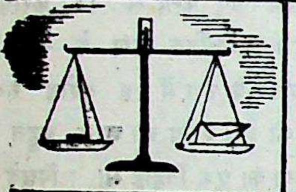

• **तोल के अनुसार ठीक टिकट लगाइये**

कम टिकटों और बिना टिकटों वाली चिट्ठियां देरी से पहुंचती हैं, क्योंकि छंटाई के समय उन्हें हिसाब लगाने के लिए अलग रख दिया जाता है।

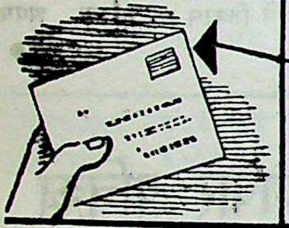

• **टिकट, पते वाली तरफ ऊपर के दाहिने कोने में चिपकाइये**

इससे छंटाई के काम में कम समय लगता है और साथ ही स्वचालित मशीन से मुहर लगाने का काम तेजी से होता है।

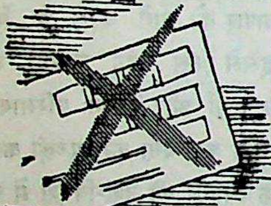

• **आवश्यक मूल्य की कम से कम टिकटें लगाइये**

इससे साफ पता लिखने के लिए काफी जगह बच रहेगी और टिकटों पर मुहर लगाने में भी सुविधा होगी।

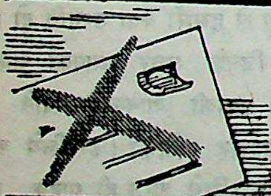

• **टिकट अच्छी तरह चिपकाइये**

अच्छी तरह न लगे टिकट यदि गिर गए तो उन पत्रों को बैरंग अथवा कम टिकट वाले पत्र समझा जाता है। इनके जाने में देरी भी हो सकती है।

हमें उत्तम सेवा का अवसर दीजिये

डाक-तार विभाग

अपर्याप्त और ठीक ढंग से टिकट न लगाने से पत्रों के पहुंचने में देर ही नहीं लगती अपितु उससे समूची डाक-व्यवस्था में अड़चनें पैदा हो जाती हैं।

अपने टिकट ध्यान-पूर्वक लगाइये

DA 59/356

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नये वर्ष का रेलवे बजट

१९६०-६१ में यात्री यातायात से १३५.५० करोड़ रु० की आय का अनुमान है। यह आय पिछले वर्ष की यात्री-यातायात से हुई आय से १.४२ करोड़ रु० अधिक है। मौजूदा माल भाड़े की दरों पर माल यातायात से २९१ करोड़ रु० की आय का अनुमान है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से २७ करोड़ रु० अधिक होगी। इस प्रकार मौजूदा किराये-भाड़े की दरों के आधार पर १९६०-६१ में यातायात से ४५०.५० करोड़ रु० की कुल प्राप्ति का अनुमान है। लेकिन माल भाड़े में पूरक चार्ज से कुल प्राप्ति ४६४.५० करोड़ रु० की आशा है। १९५८-५९ में यात्री-यातायात से ३६०.२१ करोड़ रु० की कुल प्राप्ति हुई, जो संशोधित अनुमान से ४.१७ करोड़ रु० कम थी। आय में यह कमी मुख्यतः माल यातायात तथा थोड़ी-बहुत यात्री-यातायात में हुई। आय में कमी मुख्यतः आर्थिक स्थिति संबंधी कारणों से और अंशतः सड़क यातायात से होड़ के कारण हुई।

रेलवे मंत्री : श्री जगजीवनराम

रेलवे बजट एक दृष्टि में

	करोड़ रुपयों में		
	वास्तविक	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान
	१९५८-५९	१९५९-६०	१९६०-६१
यातायात से कुल प्राप्ति	३९०.२१	४२२.०३	४६४.५०
साधारण संचालन व्यय	२७६.३३	२९१.९२	३२६.९०
युद्ध विविध व्यय	९.४५	१५.७८	१६.८२
मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के लिये विनिमय	४५.००	४५.००	४५.००
चालित (वर्क्ड) लाइनों को भुगतान	०.११	०.०७	०.०८
जोड़	३३०.८९	३५२.७७	३८८.८०
शुद्ध रेलवे राजस्व	५९.३२	६९.२६	७५.७०
सामान्य राजस्व को लाभांश	५०.३९	५४.५१	५७.२७
शुद्ध बचत	८.९३	१४.७५	१८.४३

★ वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरुप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक होने वाले २० करोड़ रु० का अतिरिक्त खर्च भी इसमें शामिल है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरी योजना की प्रगति

दूसरी योजना में रेलों के लिए कुल ११२१.५० करोड़ रु० की राशि रखी गई है। इसमें से मार्च १९६० तक पूरे होने वाले ४ वर्षों में रेलें लगभग ८७२ करोड़ रु० खर्च कर लेंगी। आशा है कि शेष राशि दूसरी योजना के बाकी समय में पूरी हो जाएगी।

इन चार वर्षों में लगभग ७०० मील लम्बी पटरियाँ दोहरी की जा चुकी हैं और ६०० मील लम्बी नई लाइनें बिछाई जा चुकी हैं। इन कामों में इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं को समुचित प्राथमिकता दी गई है। इस्पात कारखानों तथा कोयला खानों के क्षेत्र में अनेक नई लाइनें बिछाई गई हैं, जिससे इस्पात तथा कारखानों को समय पर कच्चा माल मिल सके।

लगभग ९०० मील लम्बी लाइनें बिछाने के लिए पड़ताल चल रही है।

बिजली की रेलें चलाने की दिशा में भी बहुत प्रगति हुई है।

यातायात बढ़ने की आशा

योजना के तीसरे वर्ष में आर्थिक विकास की गति में कुछ रुकावटें हुई। लेकिन अब राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था फिर मजबूत दिखाई देती है और भविष्य काफी आशाप्रद दिखाई देता है। इस्पात के बढ़ते हुए उत्पादन और मुकामा के पास राजेन्द्रपुल खुलने तथा गुवाहटी और बरौनी में दो नये तेल-शोधक कारखाने खुलने जा रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए ऐसा अनुमान है कि आगामी वर्ष में रेलों को १ करोड़ ७० लाख टन अतिरिक्त माल ढोना पड़ेगा और इस प्रकार योजना के अन्त तक १ अरब ६ करोड़ २० लाख टन माल का जो लक्ष्य रखा गया वह पूरा हो गया।

योजना के पहले तीन वर्षों में यात्री-यातायात में लगभग १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह उम्मीद है कि योजना के अन्त तक यात्री-यातायात में १५ प्रतिशत की वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया था, यातायात उससे कहीं अधिक बढ़ जाएगा।

प्रति वैगन पीछे माल की ढुलाई की स्थिति सुधारने का काफी प्रयत्न किया गया है और केवल ३ प्रतिशत वैगन बढ़ाकर १९५८-५९ की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक यातायात हुआ है।

सभी रेलों पर मालगाड़ियों की रफ्तार में काफी सुधार हुआ है। यात्री-गाड़ियों के समय से पहुँचने के बारे में रेल मंत्रालय बराबर ध्यान दे रहा है। अप्रैल से अक्टूबर १९५९ तक सभी रेलों में बड़ी लाइन की गाड़ियां ८२.९ प्रतिशत और छोटी लाइन की गाड़ियां ८१.८ प्रतिशत समय से पहुँची, जबकि पिछले वर्ष बड़ी लाइन की ७६.३ प्रतिशत गाड़ियां और छोटी लाइन की ७९ प्रतिशत गाड़ियां समय से पहुंची थीं।

१९५९-६० के संशोधित अनुमान

यात्री-यातायात से १२४ करोड़ ८ लाख रु० की आय का संशोधित अनुमान है, जो कि बजट के अनुमान से ५ करोड़ ७८ लाख रु० अधिक है। माल-यातायात से अब २६४ करोड़ रु० की आय आँकी गई है, जो कि बजट में अनुमानित २७२ करोड़ ५८ लाख रु० की आय से ८ करोड़ ५८ लाख रु० कम है। लेकिन यात्री-यातायात आदि से आय में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण ४२२ करोड़ ३ लाख रु० की कुल प्राप्ति के अनुमान में कोई फेरबदल नहीं की जाएगी।

चल स्टाक का निर्यात

अब हम इतने इंजन तैयार करने लगे हैं कि कुछ निर्यात भी कर सकते हैं हमारे इंजनों का स्टैंडर्ड ऊँचा है और दाम मुकाबले में ठीक हैं। इसी तरह माल डिब्बा और सवारी डिब्बा भी हम अपनी आवश्यकता के अनुसार तो बनाने ही लगे हैं, अब निर्यात के लिए भी बना सकते हैं। कच्चे माल और इस्पात को छोड़कर कुल खरीद का केवल १० प्रतिशत ही विदेशों से मंगाया गया।

यात्रियों को सुविधाएं

रेलों में भीड़ काफी कम हो गई है। १९५८-५९ में १७० नयी गाड़ियाँ चलाई गई तथा ८५ गाड़ियों का यात्रा मार्ग बढ़ाया गया। चालू वर्ष में १ दिसम्बर, १९५९ तक १७८ नई गाड़ियाँ चालू की गई तथा ११८ गाड़ियों का यात्रा-मार्ग बढ़ाया गया।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

२०० मील से अधिक दूरी की यात्रा करने वाले तीसरे दर्जे के यात्रियों को बिना अतिरिक्त चार्ज के सोने की जगह की व्यवस्था की जा रही है। बड़ी लाइन के २०० सोने के डिब्बे तथा इतनी ही संख्या में छोटी लाइन के भी सोने के डिब्बे बनाने का आर्डर दे दिया गया है। ये डिब्बे नये डिजाइन के होंगे।

कर्मचारियों को सुविधाएं

दूसरी योजना के पहले तीन वर्षों में कर्मचारियों के लिए ३६ हजार क्वार्टर बनाये जा चुके हैं और चालू वर्ष में ९ हजार और क्वार्टर बनने की आशा है। १९६०-६१ में १० हजार क्वार्टर बनाने की व्यवस्था की गयी है।

१९६०-६१ के अन्त तक मूल्य ह्रास अरक्षित निधि और राजस्व आरक्षित निधि में अनुमानतः लगभग ७१ करोड़ रु० की राशि से आरम्भ की गयी थी। लेकिन अनेक कारणों से इस राशि में से काफी रुपया खर्च हुआ है और वर्ष के अन्त तक इसमें लगभग १८ करोड़ रु० बाकी रहेंगे। राजस्व आरक्षित निधि में कोई गड़बड़ नहीं है और उसमें ५३ करोड़ रु० बाकी होंगे।

१९६०-६१ में यात्री यातायात से १२५ करोड़ ५० लाख रु० की आय का अनुमान है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से १ करोड़ ४२ लाख रु० अधिक है। पार्सल आदि की ढुलाई से २५ करोड़ रु० की आय का अनुमान है, जो करीब-करीब चालू वर्ष के अनुमान के बराबर हुई है। अगले वर्ष माल-यातायाता में, १ करोड़ ७० लाख टन की वृद्धि होने की आशा है। इस आधार पर मौजूदा माल-भाड़े की दर से माल यातायात से २९१ करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया है, जो चालू वर्ष से २७ करोड़ रु० अधिक है। फुटकर आय का अनुमान १० करोड़ रु० का है, माल-यातायात में यदि थोड़ी बहुत कमी भी हो जाए तो भी यातायात से १९६०-६१ में मौजूदा किराये-भाड़े की दर के आधार पर ४५० करोड़ ५० लाख रु० की कुल प्राप्ति का अनुमान है।

१९६०-६१ में साधारण संचालन-व्यय का अनुमान ३२६ करोड़ ९० लाख रु० है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान की राशि २९१ करोड़ ९२ लाख से ३४ करोड़ ९८ लाख रु० अधिक है। व्यय वृद्धि के इस अनुमान में २० करोड़ १२ लाख रु० की वह राशि भी शामिल है, जो वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक कर्मचारियों को दी जाएगी।

चालू लाइनों के निर्माण पर १४ करोड़ रु० व्यय का अनुमान है। पूंजीगत व्यय में कुछ वृद्धि होने के कारण सामान्य राजस्व में २ करोड़ ७५ रु० अधिक देने होंगे।

वेतन आयोग की सिफारिशों आदि के कारण बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के बाद शुद्ध बचत अनुमातः केवल ४ करोड़ ५० लाख रु० के करीब होगी जो विकास निधि में जमा कर दी जाएगी।

माल के जोखिम की जिम्मेदारी

पब्लिक कैरियरों की तरह रेलों द्वारा माल के जोखिम की जिम्मेदारी उठाने की सिफारिश पर अमल करने का विचार है और उसके लिए जल्दी ही आवश्यक विधेयक पेश किया जाएगा। इन बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के कारण यह आवश्यक है कि माल-भाड़े की दर में उपयुक्त परिवर्तन किया जाए।

माल-भाड़ा दर जाँच समिति ने भाड़े में १३ प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी, लेकिन माल भाड़ा अधिक बढ़े, इसलिए केवल ४ प्रतिशत वृद्धि की जा रही। जैसा कि मैं बता चुका हूँ मौजूदा स्थिति में खनिज वस्तुओं, सैनिक सामान डाक और रेलों के अपने सामान को छोड़कर पहली अप्रैल से बाकी सब माल तथा कोयले के भाड़ा-दर में प्रति

रेलवे बजट पृथक् क्यों ?

यूरोपीय देशों की पद्धति के अनुसार भारत में भी रेलवे बजट पृथक् रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:—

(१) रेलवे की नीति तथा रेलवे का प्रशासन राजनैतिक प्रभाव से अछूता होना चाहिए।

(२) राष्ट्रीय बजट में अपना योग देने के बाद रेलवे इस बात के लिए स्वतन्त्र होनी चाहिए कि वह अतिरिक्त लाभ को विकास पर व्यय कर सके और इसके कामों में रोज रोज़ हस्तक्षेप न हो।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रुपया पीछे ५ नये पैसे का पूरक चार्ज लगाया जाएगा। इस वृद्धि से प्रति वर्ष लगभग १४ करोड़ रु० की आय का अनुमान है।

ईंधन के खर्च में कमी

रेलों ने एक संगठन बनाया है, जो इस बात की निगरानी करेगा कि खानों से उसी किस्म का कोयला लादा जाय जैसा रेलों के लिए चाहिए। रेलें कोयला सप्लाई करने वालों से खुद ठेका करेंगी, जिससे कि खराब माल मिलने पर वे खुद कारवाई कर सकें और कोयला-नियंत्रक पर निर्भर न रहें। यह जरूरी है कि जल्दी से जल्दी कोयला धोने के कारखाने बनाये जाएं, जिससे कि रेलों को बराबर अच्छी किस्म का कोयला मिल सके।

विदेशी सहायता

अमेरिका की विकास ऋण निधि से ३ करोड़ डालर के एक और ऋण के बारे में बातचीत करीब-करीब पूरी हो चुकी हैं। विश्व बैंक से ८ करोड़ ५० लाख डालर का जो ऋण सितम्बर १९५८ में मिला था, उसका पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है। जुलाई १९५९ में विश्व बैंक से ५ करोड़ डालर का एक और ऋण मिला।

अधिक आत्मनिर्भरता

चितरंजन रेल इंजन कारखाने में ७ हजार टन क्षमता वाला इस्पात का एक कारखाना बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता १० हजार टन तक हो सकेगी।

चित्तरंजन कारखाने में चालू वर्ष में १७३ और अगले वर्ष १६८ इंजन तैयार होने की आशा है। संभवतः टेलको चालू वर्ष १०० इंजन दे देगा और इतने ही इंजन अगले वर्ष तैयार करेगा टेलको द्वारा १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९६० तक सप्लाई किये जाने वाले इंजनों का मूल्य निर्धारित करने के लिए जो पंच नियुक्त किया गया था, उसने प्रति इंजन ३ लाख ८० हजार ९१७ रु० का मूल्य निर्धारित किया है, जबकि टेल को ३ लाख ९२ हजार ८६१ रु० मांगे थे और रेल मंडल ने ३ लाख ७४ हजार ९९४ रु० देना चाहे थे।

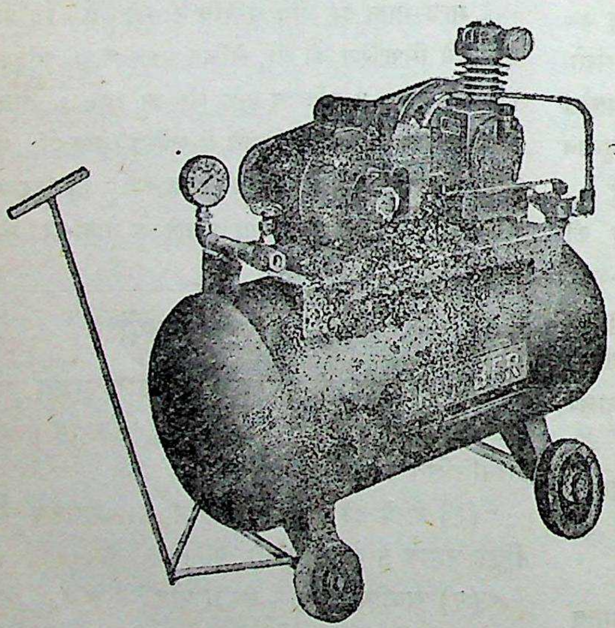

★ एयर कम्प्रेसस

★ स्प्रे पेंटिंग के साधन

★ कार वाशर

★ वैक्युम पम्प

डिडवानिया
ब्रादर्स (प्रा.) लि.

कश्मीरी गेट, दिल्ली-६।

टेलीफोन : २३८१८

टेलीग्राम : डीडवानिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बजट १९६०-६१ के नये प्रस्ताव

बजट के नये प्रस्ताव

गत वर्ष (१९५९) मैंने बताया था कि वह लम्बा युग भी शायद समाप्त हो रहा है जिसमें राजस्व में बचत रहा करती थी; सबसे पहली बार १९५८-५९ की वास्तविक प्राप्तियों में ५ करोड़ रुपये का थोड़ा सा घाटा दिखायी दिया है। आयोजित विकास (प्लाण्ड डवेलपमेंट) की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैंने साधनों को बराबर जुटाते रहने पर भी जोर दिया था। जो बातें मैंने पिछले साल रखी थीं वे ही अगले साल के बजट के लिए भी, उतने ही जोर से, लागू होती हैं और यद्यपि राजस्व का अगले साल का भारी घाटा, वर्तमान आयोजना (प्लान) के आखिरी साल में विकास पर पहले से ज्यादा रुपया खर्च होने और देश की सुरक्षा के लिए बचाव (डिफेंस) की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण हैं, मुझे विश्वास है कि घाटे के एक हिस्से को अतिरिक्त करों से पूरा किया जाना चाहिए। मेरा विचार है कि चालू साल की तरह अगले साल के घाटे का भी एक-चौथाई हिस्सा नये करों से पूरा किया जाना चाहिए।

अगले साल के बजट प्रस्ताव, खास तौर से करों की बुनियादों को चौड़ा करने के प्रस्ताव, तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। प्रत्यक्ष करों से अधिक से अधिक आमदनी करने के लिए बराबर विचार किया जाता रहेगा, लेकिन अधिकांश प्राप्ति अप्रत्यक्ष करों से करनी होगी।

अप्रत्यक्ष कर

१. पहला प्रस्ताव टीन की प्लेटों और टीनदार शीटों (टिण्ड शीट) पर प्रति मीट्रिक टन २०० रुपये का शुल्क (ड्यूटी) लगाने के सम्बन्ध में है। अनुमान है कि इससे पूरे वर्ष में २०८ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

२. दूसरा प्रस्ताव कच्चे लोहे (पिग आयरन) पर प्रति मीट्रिक टन १० रुपये का थोड़ा सा शुल्क लगाने के सम्बन्ध में है। इस शुल्क से हर साल ६० लाख रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, लेकिन जो कच्चा लोहा (पिग आयरन) इस्पात बनाने के काम आयेगा उस पर यह शुल्क नहीं लगेगा।

३. मैं अपने तीसरे प्रस्ताव द्वारा एल्युमिनियम की चद्दरों (शीट) और चक्कों (सर्किल) पर २०० रुपया प्रति मीट्रिक टन, और एल्युमिनियम के डलों (इंगट) पर ३०० रुपया प्रति मीट्रिक टन का शुल्क लगाना चाहता हूँ। इससे ८६ लाख रुपये की आमदनी का अनुमान है।

४. अन्दर से जलने वाले सब तरह के इन्जनों (इण्टर्नल कम्बशन) पर, जो गाड़ियां चलाने के काम आते हैं, मूल्य के अनुसार १० प्रतिशत शुल्क लगाया जायगा। साधारणतः कारखानों और खेती के काम आने वाले स्थिर (स्टेशनरी) ५ प्रतिशत की कम दर का शुल्क लगाया जायगा। अनुमान है कि इससे प्रति वर्ष १०७ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

५. साइकिल के हर 'फ्री ह्वील' पर २ रुपये और हर 'रिम' पर ४ रुपये का शुल्क लगाया जायगा। इस से हर पूरी साइकिल पीछे १० रुपया वसूल होगा; अनुमान है कि इससे हर साल १०० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

६. बिजली की मोटरों पर मूल्य के अनुसार ५ प्रतिशत से लेकर १५ प्रतिशत का शुल्क लगाया जायगा। अनुमान है कि इससे हर साल ४६ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

७. सिनेमा की उतरी हुई (एक्सपोज़्ड) फिल्मों की किस्म के आधार पर यह १० नये पैसे प्रति मीटर से लेकर ५० नये पैसे प्रति मीटर तक अलग-अलग होगा। इससे अनुमानतः ७५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

८. रेशमी कपड़ों हथकरघा क्षेत्र पर इस शुल्क का प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे ३० लाख रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।

९. १९५६ में बड़ी बड़ी मुसाफिर मोटर गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क लगाया गया था। अब सभी तिजारती गाड़ियों और छोटी व बीच के दर्जे की गाड़ियों, मोटर साइकिलों और स्कूटरों आदि पर भी मूल्य के अनुसार १५ प्रतिशत शुल्क लगेगा। अनुमान है कि इससे कुल ६२५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१०. साफ किये गये डीजल तेल पर १९५६ में प्रति गैलन २५ नये पैसे शुल्क लगाया गया था। यद्यपि तब से, यह शुल्क बढ़ा कर ८० नये पैसे प्रति गैलन कर दिया गया है, इस तेल की अन्दरूनी पैदावार और खपत के बढ़ते हुए असन्तुलन से देश के विदेशी मुद्रा-साधनों पर बहुत दबाव पड़ रहा है। इसलिए मैं शुल्क की बुनियादी दर में २५ नये पैसे प्रति गैलन की और वृद्धि की जायगी। इससे हर साल ५०४ लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

११. बिजली से चलने वाले कारखानों में बने जूतों पर १९५५ में उत्पादन शुल्क लगाया गया था, लेकिन बहुत से छोटे छोटे कारखानों को इस शुल्क के क्षेत्र से बाहर रखा गया था। पता लगा है कि कुछ बड़े-बड़े कारखाने, कर से बचने के लिए, जान बूझ कर विकेन्द्रीकरण (डिसेंट्रलाइ-जेशन) की नीति अपना रहे हैं। मुख्यतः राजस्व की रक्षा के लिए, चमड़े या लकड़ी के अलावा दूसरी चीजों से मशीन के बने तलों (सोल) और एड़ियों (हील) पर शुल्क की दर मूल्य के अनुसार १५ प्रतिशत होगी और इससे हर साल २० लाख रुपये की प्राप्ति होगी।

१२. 'स्टेपल' रेशे के धागे से बने कपड़ों, और सूती कपड़े के कटे टुकड़ों से मौजूदा छूट हटा ली जाय। अनुमान है कि इन परिवर्तनों से प्रति वर्ष १६५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी जिस में से ६५ लाख रुपया राज्यों को दिया जायगा।

१३. बिजली के पंखों, बल्बों और बैटरियों पर मौजूदा शुल्कों में ५० प्र० श० वृद्धि और इन चीजों के हिस्सों के शुल्क में भी मुनासिब वृद्धि। इन परिवर्तनों से प्रतिवर्ष ६० लाख रु० की प्राप्ति होगी।

१४. विभिन्न सूत्रों द्वारा अनेक कर लगाने से चाय उद्योग को जो कठिनाई होती है उसे दूर करने के विचार से उत्पादन शुल्क की अधिकतम सीमा को १६ न० पै० से बढ़ाकर ३० न० पै० प्रति पौण्ड किया जा रहा है। इससे इस समय लगे शुल्क की दरों में, जो २ न० पै० से लेकर १२ न० पै० प्रति पौण्ड है, कोई हेरफेर नहीं होगा।

१५. कुछ और भी छोटे-छोटे परिवर्तन किये जा रहे हैं जिनसे प्रतिवर्ष २७ लाख रु० की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। इसमें से ५ लाख रु० राज्यों को दिया जायगा।

१६. सीमा शुल्क: शराब, सुरासार (स्पिरिट) और दूसरी तरह की मद्यसारी शराबों (अल्कोहोलिक लिकर) के शुल्क में वृद्धि होगी। उत्पादन शुल्कों में परिवर्तन होने से आवश्यकतानुसार, प्रति संतुलनकारी (काउण्टर वेलिंग) आयात शुल्क लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सीमा-शुल्कों में परिवर्तन से अगले वर्ष २.५ करोड़ रु० की प्राप्ति का अनुमान है।

प्रत्यक्ष कर

१. व्यक्तिगत आय कर के ढांचे में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। १ अप्रैल, १९६० को प्रारम्भ होने वाले वित्त वर्ष से, कम्पनियों पर लगने वाले संपत्ति कर और अधिक लाभांश कर को समाप्त करने की नियमित कारवाई की जा रही है।

२. ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले कर-निर्धारण वर्ष की पहले से अदायगी करने के लिए कम्पनी करों की दर अस्थायी रूप से ४५ प्र० श० रखी गयी थी। अब इसी दर को अन्तिम मान लिया जायगा। कम्पनी दरों की नयी प्रणाली के संबंध में वित्त विधेयक में दो उपबन्ध रखे जा रहे हैं—एक उन लाभांशों पर कर लगाने के संबंध में है। जो लाभ की उन रकमों से दिये जा चुके हैं जिन पर पहले कर लग चुका है। दूसरा उन कम्पनियों की दरों के बारे में है जिनकी दूसरी कम्पनी का हिस्सा पूंजी में ५० प्रतिशत से कम शेयर हैं। राजस्व का अनुमान तैयार करते समय इनका हिसाब रख दिया गया है।

३. मूल स्रोत से ही कर की रकम बाँट लेने के सम्बन्ध में दो परिवर्तन किये गये हैं। यह प्रस्ताव है कि व्यक्तियों और कम्पनियों दोनों की कर की रकम ३० प्र० श० की समान दर से बाँटी जाय। इस परिवर्तन से राजस्व प्राप्ति में कमी न हो, इसलिए आय कर अधिनियम में संशोधन किया जायगा जिससे सरकार भारतीय कम्पनियों से प्राप्त लाभांश पर अग्रिम कर के रूप में बाकी १५ प्र० श० भी वसूल कर कर सके। वित्त विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है कि तरजी ही हिस्सेदारों का की जाने वाली अदायगियों से भी उसी तरह कटौती की जाय जिस तरह किसी अन्य लाभांश से की जाती है। इन लाभांशों की वास्तविक रकम क्या हो

(शेष पृष्ठ ८२ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सिन्दिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड की

४०वीं वार्षिक आम सभा के अवसर पर चेयरमैन का भाषण

बुधवार २४ फरवरी, १९६० को सायंकाल ४ बजे सिन्दिया हाउस, बैलार्ड इस्टैट, बम्बई में कम्पनी की ४०वीं वार्षिक आम सभा के अवसर पर दिया गया चेयरमैन श्री धरमसी एम० खटाऊ का अभिभाषण।

भागीदारों का स्वागत करने के पश्चात् श्री धरमसी ने कम्पनी की कुल आय अधिक होने पर भी विशुद्ध लाभ कम रहने के कारणों पर प्रकाश डाला।

ओवरसीज ट्रेड्स पर बोलते हुए श्री धरमसी ने समालोच्य वर्ष शिपिंग इन्डस्ट्री के लिए एक कठिन समय बतलाया क्योंकि जहाजों के लिए सामान का भाड़ा बराबर कम रहा तथा कारगो की गति पूर्ण संतोषजनक नहीं रही। दुनिया भर के जहाजों की माल ले जाने की क्षमता बढ़ जाने से जहाज में ले जाने के लिए सामान प्राप्त करने की स्पर्धा रही ताकि वह खाली न जाए। अतः भारतीय जहाजों के लिए यह एक कठिन समय रहा, क्योंकि इन्हें पुरानी स्थापित जहाज कम्पनियों से ही मुकाबला नहीं करना पड़ा बल्कि अन्य देशों के जहाजों के साथ मुकाबले में खड़ा रहना पड़ता है, जिनका या तो भारतवर्ष के साथ कुछ व्यापार है ही नहीं या जहाँ हमारे जहाजों को जाने की इजाजत नहीं है और उन जहाजों से जो भारतीय बन्दरगाहों पर अपने मार्ग के मध्य में आकर जो कुछ सामान उन्हें मिल पाता है अन्य बन्दरगाहों को ले जाते हैं।

भारतीय जहाज, उन्होंने आगे कहा, अपने कठिन भविष्य का मुकाबला करने तथा अन्य देशों के विदेशी व्यापार में अपने लिए उपयुक्त स्थान बनाने के लिए संगठित रूप से दृढ़ता के साथ खड़े रहने के लिए कृतसंकल्प है। इस प्रयास में सरकार का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार भारतीय जहाज रानी का विकासमात्र ही नहीं चाहती अपितु वह यह भी चाहती है कि भारतीय जहाजरानी की

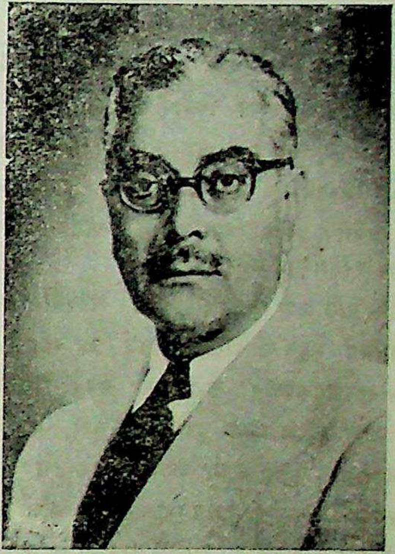

चेयरमैन श्री धरमसी एम. खटाऊ

आवाज विभिन्न कान्फ्रेंसों में जो दुनिया भर के व्यापार मार्गों पर शासन करती हैं दुनिया के साथ भारतीय व्यापार के लाभ को दृष्टि में रखकर सुनी जाए।

भारतीय जहाजों द्वारा ले जाने वाले सामान पर मूल्यवान विदेशी मुद्रा का बचाना एक और महत्वपूर्ण कारण रहा।

उन्होंने यह भी कहा—

"भारतीय जहाजों ने अपनी ओर से—

(१) शिपर्स को नियमित सर्विस देकर दुनिया के विभिन्न बन्दरगाहों के लिए अपनी सेवाएं अधिक व्यवस्थित व तर्कसंगत कर दी हैं;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(२) अपने पुराने जलपोतों के स्थान पर बराबर तीव्रगामी जलपोतों को लगा रही है तथा

(३) नए-नए व्यापार-मार्ग खोल रही है।

मैंने यह सब कुछ भारतीय जहाजों की कठिनाइयाँ व उनका सामना करने के लिए जो पग उन्हें उठाने पड़े, दर्शाने के लिए कहा है। हमें शक्ति और धैर्य की और भी कठिन परीक्षा में से गुजरना पड़ सकता है, परन्तु मुझे विश्वास है कि अन्त में समझदारी की भावना जाग्रत होगी और सद्भावना के साथ परस्पर विचार विनिमय से सभी के लाभ के लिए अन्य प्रतिस्पर्धा करने वाली लाइनों के साथ हमारा समझौता हो जाएगा।"

तटीय तथा निकटवर्ती व्यापार के सम्बन्ध में बोलते हुए श्री धरमसी ने उन कारणों पर प्रकाश डाला जिनमें प्राप्य तटीय माल लादने वाले जहाजों में कमी होती है और जिनके परिणामस्वरूप किराए की कमाई पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने तटीय जहाजरानी को कायम रखने को और उसको विस्तारित करने की राष्ट्रीय आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि इसके बिना देश की यातायात बचत पर भारी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में तटवर्तीय जहाजी उद्योग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब तक रेल-सौ-कोआर्डिनेशन कमेटी की यह सिफारिश कि अधिकतम माल को जलमार्ग द्वारा भेजा जाए, कार्य रूप में परिणित नहीं होती, यह प्रतीत होता है कि इसका भविष्य अन्धकारमय है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम एक उल्टा ही तरीका देख रहे हैं जिसमें परम्परा से जलमार्ग से जाने वाले माल रेल के रास्ते से जा रहे हैं। यह देश की आर्थिक उन्नति के सर्वथा विपरीत है कि तटवर्तीय व्यापार को बर्बाद होने या बिगड़ने भी दिया जाए। मैं विशेष रूप से परिवहन विभाग के मंत्री महोदय, जहाजरानी के मंत्री महोदय और नेशनल शिपिंग बोर्ड से अपील करना चाहूँगा कि अधिकतम सामान को रेल मार्ग से मोड़कर इस बात का आश्वासन प्रदान करें कि वह यातायात अर्थव्यवस्था में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें और इस प्रकार वह दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में सुदृढ़ बनी रह सके। शीघ्रतापूर्ण और पर्याप्त कदम उठाए बिना, मुझे भय है कि एक अच्छी कोस्टल फ्लीट की मालिक के रूप में हमारी कम्पनी इस व्यापार के अन्तर्गत पर्याप्त हानि उठाएगी।

मैं परिवहन और खाद्य मंत्रालयों से भी प्रार्थना करूँगा कि वे बर्मा से चावल का भाड़ा निर्धारित करने में ट्रैम्प टनेज की सट्टा स्थिति पर ही एकमात्र ध्यान रखने के बदले सभी प्रकार के आर्थिक प्रश्नों को दृष्टि में रखकर विचार करें।

जहाजनिर्माण के कार्यक्रम के सम्बन्ध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जून १९६० तक की पंचवर्षीय अवधि के अन्तर्गत कम्पनी का प्राप्य बेड़ा (फ्लीट) करीबन २८ करोड़ मूल्य के २४ जलपोतों का होगा, जिनका अधिकांश कम्पनी की विदेशी सेवाओं में लगा है। उन्होंने कहा कि २८ करोड़ की इस लागत में से केवल ११ करोड़ सरकार से ऋण के रूप में लिया गया था।

वर्तमान वर्ष की स्थिति के विषय में उन्होंने अपना यह विचार बताया कि वर्तमान वर्ष १९५८-५९ वर्ष से भी खराब रहेगा, परन्तु फिर भी वे आशावादी हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आर्थिक दरें दृढ़ रहने से कम्पनी की दशा कुछ काल में सुधरेगी।

उन्होंने तृतीय पंचवर्षीय योजना की १६ लाख के जी. आर. टी. लक्ष्य का स्वागत किया और नेशनल शिपिंग बोर्ड के निर्माण का स्वागत किया।

उन्होंने सुझाव दिया कि विकास छूट में से रिजर्व का हस्तान्तरण कुछ वर्षों में फैला दिया जाए, विशेष रूप से विस्तार और तब्दीली के निरन्तर कार्यक्रम के साथ शिपिंग इण्डस्ट्री में। उन्होंने भारत सरकार पर इस बात के लिए जोर दिया कि वह वार-रिस्क-इंश्योरेन्स स्कीम को चलाए जिससे कि संसार में किसी भी स्थान पर युद्ध भड़क उठने की स्थिति से इंडियन रजिस्टर अंकित जहाज पर बहुत बड़े जोखिम से बच जाए।

सब्सीडियरी कम्पनियों की चर्चा करते हुए विशेष रूप से बम्बई स्टीम नैवीगेशन कं० (१९५३) प्रा० लि० के बारे में उन्होंने आशा व्यक्त की कि कोनकन सर्विसेज की तात्कालिक और दीर्घकालिक समस्याओं की परीक्षा करने और प्रतिवेदन देने के लिए एडहोक कमेटी नियुक्त की गई है वह इस प्रकार का निर्णय करेगी कि जिससे भविष्य में बिना बाधा के सेवाएं चालू रहेंगी।

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जी हाँ, मैं वित्त-मंत्री हूँ !

एक प्रमुख वित्तमंत्री के अनुभव

मैं आप को दोष नहीं दूँगा यदि आप भी सामान्य पाठक की तरह यह सोचते हैं कि मंत्री बनना और धरती पर रहते ही स्वर्ग में होना एक ही बात है; क्योंकि कभी बहुत पहले यही विचार मेरा भी था, लेकिन अब मैं स्वयं वित्त मंत्री हूँ और मंत्री बनने के मजे को अच्छी तरह समझ गया हूँ। एक वित्त मंत्रीके सामने कितनी और कितनी तरह की कठिनाई होती है, इसका अनुमान तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि कोई स्वंय को वित्त मंत्री होने की स्थिति में न पाए।

आप कल्पना करें कि आपको एक ऐसे परिवार का बजट बनाना है जिसकी आय सीमित है, और व्यय असीमित। परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी-अपनी अवश्यकताएं हैं। और उनमें से कोई भी अपनी आवश्यकताओं को कम करने को तैयार नहीं। एक छोटे परिवार का बजट बनाने में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो करोड़ों की जन संख्या के देश का बजट बनाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है! जब मैं बजट बनाता हूँ तो शासन के विभिन्न विभागों को लिखना होता है, कि वे आगामी वर्ष के अपने व्यय की मदों से सूचित करें। सभी विभाग बढ़ा-चढ़ा कर अपने व्यय लिख देते हैं। आय के साधन लगभग निश्चित होते ही हैं। उन्हें बढ़ाया जा सकता है तो करो में वृद्धि के द्वारा ही, लेकिन करों में वृद्धि करते समय भी अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ सम्मुख आती हैं। यदि कर पूंजिपति वर्ग पर लगाये जाते हैं तो कर पर्याप्त अधिक लगाने पर भी आय में विशेष वृद्धि नहीं होती, क्योंकि इस वर्ग की संख्या कुल जन संख्या में चार प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसके विपरीत जन साधारण पर मामूली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पर लगाने से ही पर्याप्त आय हो सकती है, किंतु इस वर्ग की आर्थिक परस्थिति इतनी खराब होती कि कोई भी नया कर लगाना उचित प्रतीत नहीं होता। औचित्य अनोचित्य की बात छोड़ कर कर लगा भी दिये जाते हैं, तो चारों ओर हाहाकार मच जाता है। विभिन्न राजनैतिक दल चीख-पुकार मचाना शुरू कर देते हैं। इन दलों की आलोचना इसलिये नहीं होती कि यह वास्तव में जनता का कल्याण करना चाहते हैं। इनकी आलोचना अपने अस्तित्व की घोषणा करने के लिए या सत्तारूढ़ दल को नीचा दिखाने के एक मौके का फायदा उठाने के लिए ही होती है। राजनैतिक दलों की आलोचना के अतिरिक्त समाचार पत्रों के मोटे-मोटे शीर्षक, जलसे, जुलूस, हड़ताल और चुनाव के समय मंत्री महोदय से बदला चुकाने की धमकियाँ भी तो होती हैं।

वित्त मंत्री को जन सामान्य पर कर लगाकर ही तो आलोचना का पात्र नहीं बनना पड़ता, पूँजीपति वर्ग पर कर लगाये जाते हैं तो भी तरह तरह के दबाव वित्त मंत्री पर डाले जाते हैं। इन दबावों के अतिरिक्त अनेक-अनेक प्रलोभन भी प्रस्तुत किये जाते हैं। इन सब दबावों और प्रलोभनों से बच निकलना सरल नहीं होता; फिर भी वित्त मंत्री बच निकलता है, तो भी इधर उधर तरह तरह की कानाफूसी सुनी जा सकती है।

आय में वृद्धि करते समय ही कठिनाइयाँ सामने नहीं आतीं, विभिन्न शासकीय विभागों के खर्च की मदों में कटौती करते समय भी वित्त मंत्री को बहुत आगा पीछा देखना पड़ता है। जिस विभाग के मदों में कटौती की जाती है, वही चीखना चिल्लाना शुरू करता है और अपनी कार्यक्षमता के कम हो जाने की धमकी देता है। यह सब होते हुए भी वित्त मन्त्री को कटौती करनी ही पड़ती है, और इसी लिए आलोचना का पात्र भी बनना ही पड़ता है।

बढ़े हुए खर्चों को पूरा 'करने का एक साधन और है: विदेशों से आर्थिक सहायता लेना। आर्थिक सहायता मिल भी जाती है, लेकिन यह राष्ट्र की प्रतिष्ठा और भावी प्रगति दोनों पर ही अच्छा प्रभाव नहीं डालती। यही नहीं आर्थिक सहायता लेना वित्त मंत्री की असफलता का द्योतक भी माना जाता है और उसके लिए भी उस बेचारे की आलोचना की जाती है।

राष्ट्र का बजट बनाते समय एक और बड़ी कठिनाई का सामना वित्त मंत्री को करना पड़ता है। यह कठिनाई है,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशों के बजट

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका

कुल राजस्व—	८४.० बिलियन डालर (बिलियन = १ अरब)
कुल व्यय	७६.८ बिलियन डालर,
बचत	४.२ बिलियन डालर

बचत का उपयोग ऋणों के कम करने व राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में किया जायगा। सेना पर ४१ बिलियन डालर व्यय होगा। असैनिक अमरीका शोध आदि के लिए बड़ी राशि नियत की गई है। ४.२ बिलियन डालर विभिन्न देशों के पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए रखे गये हैं। शोध व बड़ी विशाल काम योजनाओं के लिए एक राशि नियत की गई है।

ब्रिटेन का बजट १६५६-६०

आय लाख पौण्डों में

कुल आय	५३२५०
कुल व्य	५२२३०
बचत	१०२०

इस वर्ष आयकर व खरीदकर कमी के प्रस्ताव के अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। तटकर व उत्पादन कर में भी कुछ कमी की गई।

प्रत्यक्ष करों के रूप में इंग्लैंण्ड में आयकर, अतिरिक्त आय कर, सम्पत्ति कर स्टाम्प ड्यूटी तथा मोटर कर है।

अप्रत्यक्ष करों में तटकर, उत्पादन कर व खरीद कर, मुख्य है। भारत बिक्री कर को इंग्लैण्ड में खरीद कर कहते हैं।

पाकिस्तान (१६५६-६०)

कुल आय	१५६,४६
कुल व्यय	१५१,४६
बचत	७,००
कुल पूंजीगत व्यय	१७६,७४

सेना व रक्षा पर ६५,८५ लाख रु० पुनर्वास पर २,३६ तथा शासन पर ३३,८१ लाख रु० व्यय होगा। तट कर से ४४,१२ लाख रु० उत्पादन करों से २३.६३ लाख तथा आय ही से २६.३८ लाख रु० व्यय होगा। पूंजीगत व्ययों की पूर्ति के लिए टकसाल व प्रैस से १७,६२ लाख रु० तथा विदेशी सहायता व ऋणों से ११.०३ लाख टन की आय हुई है।

साम्यवादी चीन

राजस्व आय	५,२०,००० लाख युआन
कुल व्यय	प्राप्त नहीं हो सका
पूंजीगत विनियोजन	२४,८०० लाख युआन

हर एक बात को रहस्य बनाकर रखना। किसी भी प्रकार की कर-वृद्धि आदि करने के लिये विभिन्न विभागों से तरह-तरह की सूचनाएँ एकत्रित करनी पड़ती हैं और सतर्क रहना होता है कि नये बजट के किसी भी परिवर्तन की सूचना समय से पहिले किसी अपात्र व्यक्ति को न मिल सके। किसी प्रकार कोई सूचना वित मंत्रालय के बाहर पहुँच जाती है तो उसे वित्त मंत्री की असफलता करार देकर त्यागपत्र देने की धमकी तक दी जाती है। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री हर समय अपने सर पर बाल में बन्धी तलवार को देखता है।

नये बजट की कोई भी सूचना समय से पहले अपात्र व्यक्तियों तक पहुँचने से देश की अर्थनीति पर घोर 'कुप्रभाव' पड़ता है। चतुर उद्योगपति और व्यापारी उन उत्पादनों का संग्रह करना आरम्भ कर देते हैं, जिन पर कि नये कर लगने होते हैं; क्योंकि कर लगने के पश्चात् उनका मूल्य बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में आलोचना का पात्र बनने के अतिरिक्त राष्ट्रहित के लिये भी आवश्यक हो जाता है कि वित्त मंत्री नये बजट को समय से पहिले बाहर की हवा न लगने दें।

यह सब होते हुए भी आप यदि समझते हैं कि मंत्री बनना और धरती पर रहते हुए स्वर्ग में होना, एक ही बात है तो भी मैं आपको दोष नहीं दूँगा क्योंकि इन सभी कठिनाइयों का सामना आपको नहीं, मुझे करना पड़ता है! मैं वित्त मंत्री हूँ न!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समाचार समीक्षा

सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी की प्रगति

सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी का भारतीय जहाजी उद्योग में प्रमुख स्थान है। कम्पनी की ४० वीं वार्षिक आम सभा के अवसर पर भाषण करते हुए कम्पनी के अध्यक्ष श्री धरमसी एम. खटाऊ ने कम्पनी की प्रगति और योजनाओं पर प्रकाश डाला।

३० जून १९५९ को समाप्त वर्ष में कम्पनी के सुरक्षित कोष और बचत में रु० १०.७१ करोड़ की राशि थी जो कि एक वर्ष पूर्व १०.९६ करोड़ थी। कम्पनी ने रु० १.३० प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया।

श्री खटाऊ ने तटीय जहाजरानी का निराशजनक चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसके अस्तित्व को संकट पैदा हो गया है। उनके अनुसार जब तक रेल-जलयान समन्वय समिति की सिफारिशों के अनुसार बड़े पैमाने पर भाड़े का काम जल मार्ग की ओर न बदल दिया जाए तब तक भविष्य अंधकारमय ही प्रतीत होता है।

जीवन बीमा निगम का व्यवसाय

१९५९ में ११ लाख ५० हजार पालिसियों पर ४२९.६४ करोड़ रुपयों का व्यवसाय हुआ है। इससे जीवन-बीमे के क्षेत्र में नया रेकार्ड प्रस्थापित हुआ है। १९५८ के नये व्यवसाय से इस वर्ष का नया व्यावसाय ८४ करोड़ रुपयों या २४% सेअधिक है। और १९५७ से १९५८ का नया व्यवसाय ६२ करोड़ रुपयों या २२% से अधिक था।

१९६३ तक १००० करोड़ रुपयों का व्यवसाय करने की कारपोरेशन ने ठानी है। यही उसका लक्ष्य है। १९५९ में, अपनी योजना के प्रथम वर्ष में, अपने लक्ष्य से १३ करोड़ रुपयों का अधिक व्यवसाय करके उसने लक्ष्य की सीमा पार की है। इससे जीवन-बीमा निगम ने कितनी

गत दस वर्षों से देश का राजस्व निरन्तर बढ़ता रहा है। कुल राजस्व २६,५९,००० लाख तथा कुल व्यय २६,११,००० लाख युआन हुआ है। अर्थात ४८,००० लाख युआन बचत हुई है। १९५० की तुलना में राजस्व आठ गुना बढ़ गए हैं और औसतन वृद्धि २५ प्रतिशत हुई है।

इन दस वर्षों में राजस्व के स्रोतों में भी बड़ा भारी परिवर्तन हुआ और १९५० में निजी राष्ट्रीय उद्योगों से केवल ३२.९ प्रतिशत आय हुई थी। जबकि १९५९ में यह आय घटकर केवल ०.८ प्रतिशत रह गई। दूसरी तरफ राष्ट्रीय उद्योग और सहकारी समितियों से १९५० में ३४.१ प्रतिशत आमदनी हुई थी और १९५९ में यह आमदनी बढ़कर ८७.९ प्रतिशत हो गई। देहातों के कम्यूनों से १९५९ में ११.३ प्रतिशत आमदनी हुई है जबकि १९५० में निजी किसानों से २९.६ प्रतिशत आमदनी हुई थी।

इन दस वर्षों में चीन ने उद्योग की दशा में सबसे अधिक व्यय किया है। गत वर्षों में कारखानों तथा रेलवे और अन्य योजनाओं में ११,४३,००० लाख युआन व्यय किए

गये हैं।

पूर्वी जर्मनी

बजट में प्रति व्यक्ति व्यय

	१९५०	१९५८
व्यापार व शिल्पिक शिक्षणालय	१२.५४ मार्क	५२.२० मार्क
विश्वविद्यालय	१०.०६ मार्क	३५.७८ मार्क
स्वास्थ्य व चिकित्सा	७३.१० मार्क	१४४.९७ मार्क
बालक व युवक	१९.३७ मार्क	३०.३१ मार्क

किसी समय भूमिकर राज्यों की आय का प्रधान साधन था किन्तु आज बिक्रीकर ने उसका स्थान पीछे कर दिया है। पंजाब का नये वर्ष का बजट इसका एक उदाहरण है। इस वर्ष मदों से आय का अनुमान निम्नलिखित हैः—

		प्रति रुपया लगभग
भूमिकर	५.१० लाख रुपया	०.०९
उत्पादन करों से	५.४७	०.०९
बिक्री कर	६२५	०.११
केन्द्रीय कर	७१२	०.११
अन्य कर व उपकर	७२६	०.१२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

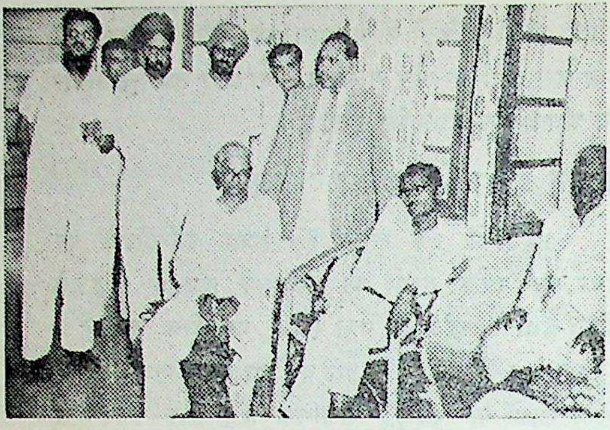

पत्रकारों के सम्मेलन में, उनसे बात करते हुए वीयरवैल साइकल मिल्स के मैनेजिंग डायरैक्टर श्री के. सी. अग्रवाल।

तत्परता और उत्साह से कार्य किया है। इसका अन्दाजा लग जाता है।

२३ कार्यालय नये खोले गये हैं। ३१ दिसम्बर १६५६ को कुल ३७७ कार्यालय जनता की सेवा में दत्त-चित्त थे। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय तथा पुरानी बीमा कम्पनियों के प्रधान तथा शाखा कार्यालय (आइ. एच. ओ युनिट और आइ. बी. ओ. युनिट) भी इस कार्य में जुटे हुए हैं। कार्यालयों की संख्यागत ३ सालों से बढ़ती गयी है। आज ३४ विभागीय, २४० शाखा कार्यालय और १०३ उपकार्यालय काम कर रहे हैं। १६५८ में यह संख्या ३५५ थी तो १६५७ में २४६ कार्यालय थे। १ सितम्बर १६५६ को, जीवन बीमा निगम की स्थापना के अवसर पर यह संख्या २४६ थी। जनता से सम्पर्क प्रस्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय अफसरों की नियुक्ति की गयी है। बीमेदारों की सेवा के लिए निगम की यह महत्वपूर्ण योजना है।

संक्षिप्त आर्थिक समाचार

—भारत सरकार ने बिक्री के लिए १ लाख ७५ हजार टन चीनी देने का निर्णय किया है। उत्तरप्रदेश, उत्तर बिहार और पंजाब की मिलों से खुली बिक्री के लिए चीनी नहीं दी जायगी।

—तीसरी योजना में कोयले के अंगार-करण से प्राप्त होने वाले मुख्य उपोत्पादन कितनी मात्रा में मिल सकते हैं, यह निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है। यह समिति इस बात की सिफारिश भी करेगी कि इन उपोत्पादनों का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाएं।

—उद्योग मंत्री, श्री मनुभाई शाह के कथनानुसार इस साल के मध्य तक दो कम्पनियां देश में ही ट्रैक्टर बनाने लगेंगी। एक कम्पनी को हर साल १२५० ब्रिटिश ट्रैक्टर और दूसरी को एक जर्मन कम्पनी के सहयोग से हर साल इतने ही ट्रैक्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया है। इन दोनों कम्पनियों को बाहर से कच्चा माल, ट्रैक्टरों के पुर्जे आदि मंगाने के लिए भी लाइसेंस दिए जा चुके हैं।

—भिलाई इस्पात कारखाने में फरवरी, १६६० में ३०,४८२ टन इस्पात के ढोंके तैयार हुए। इस प्रकार इस्पात के ढोंकों का कुल उत्पादन ७०,६८६ टन हो चुका है।

इसी महीने में १७,५८६ टन लूम और १६,५२१ टन बिलेट तैयार हुए। अब तक भिलाई से २१,४६० टन बिलेट भेजे जा चुके हैं।

फरवरी में ५१,७६७ टन लोहे का और अब तक का कुल उत्पादन ४,३१,२०४ टन तक पहुँच चुका है।

—मोरक्को का अगादीर नामक नगर भूकम्प से पूर्णतः ध्वस्त हो गया है। वहां करीब १२००० आदमी मारे गए हैं।

पिछले दश वर्षों का बजट (१६५१-६१) एक दृष्टि में

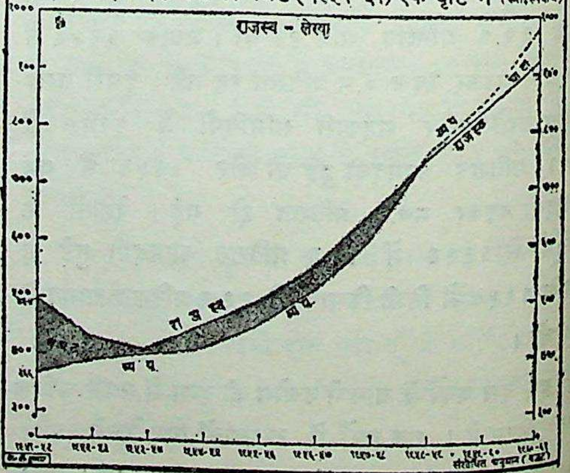

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजनाएँ और बजट

[पृष्ठ १३८ का शेष]

प्रथम योजना काल के बजट

प्रथम योजना की पृष्ठ भूमि में यदि हम सन् १९५०-५१ से सन् १९५५-५६ तक के बजटों का अध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि पूर्व योजनाकाल की अपेक्षा देश ने कितनी कुरबानी करके अधिक से अधिक करों का बोझ सहन कर पूंजी एकत्रित करने का प्रयत्न किया। इस काल में योजना कार्यों पर विभिन्न वर्षों में किस प्रकार धन व्यय हुआ उसका ब्यौरा इस प्रकार है—

वर्ष	योजना व्यय (करोड़ रुपयों में)
१९५१-५२	२५९
१९५२-५३	२७३
१९५३-५४	३४०
१०५४-५५	४७६
१९५५-५६	६१२
कुल जोड़	१,९६०

योजना बनते समय अनुमान लगाया गया था कि पाँच वर्षों में २,३५६ करोड़ रुपया विभिन्न मदों पर व्यय हो सकेगा। परन्तु विनियोजन के यह लक्ष्य पूरे नहीं हुए और लागत लगभग १० प्रतिशत कम रही।

जिन उपायों से उपरोक्त रकम प्राप्त की गई उसका विवरण इस प्रकार है—

राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा	करोड़ रुपयों में
अतिरिक्त कर लगा कर	७४५
जनता द्वारा ऋण	२०३
अल्प बचत	३००
विदेशी सहायता द्वारा	१९७
घाटे की अर्थ व्यवस्था द्वारा	४१५
अन्य साधनों द्वारा	१००
कुल जोड़	१९६०

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि पांच वर्षों में राजकीय तथा केन्द्रीय सरकारों ने ७४५ करोड़ रुपये की रकम नये कर लगाकर प्राप्त की। इसका अर्थ हुआ कि जनता को लगभग १५० करोड़ रुपया प्रति वर्ष करों के रूप में अधिक देना पड़ा। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि योजना-व्यय का सरकार के उस साधारण खर्च से कोई संबंध नहीं है जो वह प्रति वर्ष देश की रक्षा व शासन को चलाने तथा साधारण समाज-सेवी कार्यों पर खर्च करती है। उस खर्च को छोड़ कर, योजनाओं में दो प्रकार के अन्य व्यय शामिल किए जाते हैं—एक वह व्यय जिसे विनियोजन-व्यय या इन्वैस्टमैंट कहा जाता है और जिसका उद्देश्य यही होता है कि ऐसे मदों पर धन लगाया जाय जिनसे उत्पादन बढ़े तथा कालांतर में सरकार को आमदनी हो। दूसरा व्यय विकास कार्यों (Development Projects) पर किया जाता है, जिसका उद्देश्य उत्पादन में सहायता देना होता है, स्वयमेव उत्पादन को बढ़ाना नहीं। इस प्रकार के व्यय के उदाहरण रूप में हम सड़कों का निर्माण, शिक्षा संस्थाओं पर खर्च, औद्योगिक शिक्षा का प्रसार, शोध कार्य को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, मजदूरों को सुविधाएँ इत्यादि के नाम ले सकते हैं। स्पष्ट है कि इन मदों पर रुपया खर्च करने से सीधा उत्पादन नहीं बढ़ता। परन्तु अधिक उत्पादन की सुविधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए योजनाओं में दोनों ही प्रकार के व्यय की व्यवस्था की जाती है, यद्यपि प्राथमिकता की दृष्टि से पूंजी व्यय को अधिक तरजीह दी जाती है।

प्रथम योजना से पूर्व, १९४९-५० में हमारी केन्द्रीय सरकार की कुल आय लगभग ३५० करोड़ रुपया वार्षिक थी। प्रथम योजना काल के अन्त तक, अर्थात् १९५५-५६में वह बढ़कर ५२२ करोड़ रुपया वार्षिक हो गई। इसी प्रकार सब राज्य सरकारों की सम्मलित आय सन् १९४९-५० में लगभग ३०० करोड़ रुपये थी। सन् १९५५-५६ तक वह बढ़कर ५८९ करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यीय तथा केन्द्रीय सरकार, दोनों ने ही मिलकर, आय के साधनों को बढ़ाने का प्रयत्न किया। राज्य सरकारों ने लगान की दर बढ़ाई, बिक्री कर लगाया, मनोरंजन करों में भारी वृद्धि की, मोटर कर बढ़ाया तथा रजिस्ट्री और स्टाम्प कर में बढ़ोत्तरी की। केन्द्रीय सरकार ने आयकर में वृद्धि की, कम्पनियों पर नये कर लगाये, विदेशों से आने वाले माल तथा देश में बनने वाले माल पर भारी चुंगी लगाई, रेल के किराए बढ़ाए, सवारियों पर नये टैक्स जारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

किए तथा सरकारी पूंजी से नये-नये उद्योग धंधे स्थापित कर उनसे आय प्राप्त करने की कोशिश की। इस साल में केन्द्रीय सरकार को सबसे अधिक आय देश में बनने वाली चीजों पर चुंगी लगा कर प्राप्त हुई। सन् १९४९-५० में इस मद से केन्द्रीय सरकार को लगभग ५० करोड़ रुपये की आय होती थी; १९५५-५६ में वह बढ़कर लगभग १५० करोड़ रुपया हो गई थी।

नये करों के साथ-साथ जनता को अल्प-बचत योजनाओं, प्रोवीडैंड फंड, योजनाओं तथा सरकारी हुंडियों में रुपया लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। यही कारण है कि पांच वर्षों में इन साधनों से लगभग ५०० करोड़ रुपये की प्राप्ति संभव हो सकी। भारतवर्ष में साधारण जनता का जीवन-स्तर इतना निम्न कोटि का है कि उसके समक्ष बचत का प्रश्न ही नहीं उठता; अधिकतर लोगों को आमदनी से कहीं अधिक खर्च करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इसीलिए वह कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। यही कारण है कि चालीस करोड़ जनता के विशाल देश में अल्प-बचत योजनाओं से वर्ष भर में लगभग ५० करोड़ रुपया ही प्राप्त हो पाता है।

प्रथम योजनाकाल में अधिक विदेशी सहायता नहीं मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि इस योजना में ऐसे बड़े-बड़े कारखानों की योजना नहीं बनाई गई जिनके लिए विदेशी सरकारें अधिक कर्ज देती हैं। हाँ, घाटे की अर्थ-व्यवस्था द्वारा, अधिक नोट छाप कर, लगभग ४०० करोड़ रुपये और प्राप्त कर लिए गये।

द्वितीय योजनाकाल के बजट

प्रथम योजना ३१ मार्च सन् १९५६ को समाप्त हो गई। यह योजना काफी सफल रही। प्रकृति ने भी इस योजना को सफल बनाने में पूरा योग दिया। मानसूनों की कृपा से अन्न उत्पादन काफी बढ़ी। सन् १९५३-५४ में ६९ करोड़ ८८ लाख टन उत्पन्न करके हमने योजना का लक्ष्य पार कर दिया। साधारण वस्तुओं की कीमतें काफी गिरीं और घाटे की अर्थ-व्यवस्था का कोई बुरा परिणाम नजर नहीं आया।

इन्हीं सफलताओं से प्रेरित होकर हमारे योजना निर्माताओं ने द्वितीय योजना का आकार खूब बढ़ा-चढ़ा कर बना था। सार्वजनिक क्षेत्र में ४८०० करोड़ रुपया तथा निजी क्षेत्र में २४०० करोड़ रुपये के विनियोजन की व्यवस्था की गई। आय के साधनों का हिसाब लगाते समय योजना निर्माताओं को पता था कि नये कर लगाकर, अधिक से अधिक, पांच वर्षों में, ८०० करोड़ रुपये की आय की जा सकेगी। जनता द्वारा ऋणों तथा अल्प-बचत योजनाओं में भी १२०० करोड़ रुपये से अधिक मिलने की आशा न थी। इस पर भी ४८०० करोड़ रुपये की योजना बनाना बहुत साहस का कार्य था। द्वितीय योजना काल के प्रथम तीन वर्षों में तो भारी निराशा का वातावरण पैदा हो गया था, कारण साधारण इस्तेमाल की चीज़ों के भाव निरन्तर बढ़ रहे थे, अन्न उत्पादन कम हो गया था, विदेशी माल का आयात इतनी भारी मात्रा में हुआ था कि हमारे पौंड पावना का ज़ख़ीरा करीब-करीब समाप्त हो चला था और कारखानों की उत्पादन-क्षमता में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई थी। परन्तु धीरे-धीरे चौथे वर्ष में इन सभी दिशाओं में सुधार हो गया। सन् १९५८-५९ में हमारा अन्न उत्पादन सन् १९५७-५८ के मुकाबले ६ करोड़ २५ लाख टन से बढ़कर ७ करोड़ ३५ लाख टन हो गया। औद्योगिक उत्पादन में भी इसी वर्ष लगभग ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमारे विदेशी व्यापार के संतुलन में भी कुछ सुधार हुआ।

द्वितीय योजनाकाल के बजटों पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से पता चलता है कि सन् १९५५-५६ से १९५९-६० तक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये करों से प्राप्त आय में लगभग ९५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह आय ८०० करोड़ रुपये के इस लक्ष्य से कहीं अधिक है जो द्वितीय योजना बनाते समय निर्धारित किया गया था। आशा है द्वितीय योजना के पूरा होते-होते, पांच वर्षों में, अतिरिक्त करों से हमारी आय लगभग १२०० करोड़ रुपये हो जायगी। इस असाधारण सफलता का श्रेय मुख्यतः उन नये-नये करों को है जिनको लगाने का सुझाव प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री श्री कालडोर ने दिया था। इन करों में सम्पत्ति कर, अधिक व्यय कर, दान (गिफ्ट) कर तथा कम्पनी कर मुख्य हैं। सन् १९५५-५६ में आयकर तथा कम्पनी कर से हमारी कुल आय लगभग १६८ करोड़ रुपये थी, १९५९-६० में वह बढ़ कर २३० करोड़ रुपया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हो गई थी और अगले वर्ष इस मद से आय का अनुमान २४० करोड़ रुपये का है। संपत्ति कर से लगभग १२ करोड़ रुपया वार्षिक की आय हो जाती है। अतिरिक्त व्यय तथा गिफ्ट करों से आय का अनुमान लगभग २ करोड़ रुपया वार्षिक है।

अन्य साधन जिनसे केन्द्रीय सरकार की आय में भारी वृद्धि हुई है, इस प्रकार हैं :—

आय (करोड़ रुपयों में)

मद	१९५५-५६	१९५९-६०	१९६०-६१
बाहर से आने वाले माल पर चुंगी	१६६.७	१६०	१६२.५०
देश के अन्दर बने हुए माल पर चुंगी	१४५.२	३५०.८	३८०.०
रेल सवारियों पर कर	—	१२.५	१२.७
करैन्सी और रिज़र्व बैंक	३०.०	५५.८	५७.२

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर राज्य सरकारों ने भी अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न किया है, यद्यपि इस दशा में उतनी सफलता नहीं मिली, जिसकी आशा थी। राज्य सरकारें किसानों पर लगान बढ़ाने से डरती हैं, सिंचाई करों में भी वह अपेक्षित वृद्धि नहीं कर पातीं केवल बिक्री कर, मनोरंजन कर तथा मोटर करों में ही उन्होंने भारी वृद्धि की है। फिर भी सन् १९५५-५६ की अपेक्षा १९५९-६० तक राज्य सरकारों की कुल आय में लगभल ८० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सन १९५५-५६ में राज्य सरकारों की कुल आय ५८६ करोड़ रुपया थी। सन् १९५९-६० में वह बढ़कर ८९२ करोड़ रुपया हो गई थी।

करों को छोड़कर, विदेशी सहायता द्वारा हमारी द्वितीय योजना को सबसे अधिक बल मिला है। पहली अप्रैल १९५६ से ३१ मार्च १९५९ तक हमें विदेशों द्वारा ९६२.२५ करोड़ रुपये की सहायता के वायदे प्राप्त हो चुके थे। यह वायदे उस ८०० करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर गये हैं जिसका निर्धारण द्वितीय योजना-निर्माताओं ने किया था, और आशा है कि योजना के पूरी होते-होते हमें लगभग १२०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हो सकेगी।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था का लक्ष्य, द्वितीय योजनकाल के लिए, १२०० करोड़ रुपया निश्चित किया गया था। पहले चार वर्षों में ही यह सीमा पूरी हो चुकी है और अब आशा है कि योजना समाप्त होने तक यह १४०० करोड़ रुपये के लगभग पहुँच जायगी। बहुत से लोगों का कहना है कि मूल्यों में असाधारण वृद्धि का मूल कारण इतने बड़े पैमाने की घाटे की अर्थ-व्यवस्था है। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि भारत सरकार योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और किन उपायों का सहारा ले? यह बात ठीक है कि नोट छापकर काम चलाने की प्रणाली किसी भी प्रकार उचित नहीं, परन्तु अन्य साधन अपना कर इस प्रणाली के दोषों को काबू में रखने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

तृतीय योजना की रूप रेखा

हमारे योजना निर्माताओं ने तीसरी योजना की रूप-रेखा प्रायः निश्चित कर ली है। आशा है कि इस योजना में लगभग ९,९७५ करोड़ रुपया लगेगा। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि द्वितीय योजना काल में हमें विदेशी सहायता तथा घाटे की अर्थ-व्यवस्था का जितना कम हो सके सहारा लेना पड़े, और अधिक से अधिक आंतरिक साधनों से ही धन जुटाने का प्रयत्न किया जाय। इस संबंध में जो सुझाव दिए जा रहे हैं, वह इस प्रकार हैं—(१) पाँच एकड़ से अधिक भूमि पर जमीन कर दूना कर दिया जाय, (२) जमीन से प्राप्त होने वाले किराये पर भारी टैक्स लगाया जाय, (३) पाँच एकड़ से ज्यादा जिन लोगों के पास जमीनें हैं, उन पर अतिरिक्त कर लगाया जाय, (४) विलासिता की वस्तुओं की खपत पर बहुत अधिक कर लगाया जाय, (५) नमक पर कर पुनः चालू कर दिया जाय तथा (६) बीमे की योजनाओं को ग्रामों में लोकप्रिय बनाया जाय।

योजनाकाल के केन्द्रीय व राज्यीय बजटों पर दृष्टि डालने से भारत की प्रगति का भलीभाँति अनुमान किया जा सकता है। पिछले महायुद्ध से पहले संयुक्त भारत में, हमारी केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारों की कुल आय लगभग २०० करोड़ रुपया थी; आज वह आय बढ़कर लगभग २००० करोड़ रुपया हो गई है, आशा है तृतीय योजना के पूरा होते-होते यह आय प्रति वर्ष लगभग ३००० करोड़ रुपया हो जायगी। यदि इसी द्रुतगति से जनता के जीवन-स्तर में सुधार हो सका तो हम अपने प्रयत्नों को सार्थक समझेंगे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया साहित्य

सरल अर्थशास्त्र—ले०—रामशरण गुप्त, ए० बी० भट्टाचार्य, जे० एन० सिंहल, प्रकाशक—गयाप्रसाद एन्ड सन्स, आगरा पृष्ठ, संख्या—३७१

प्रस्तुत पुस्तक इस भूमिका के साथ रखी गई है कि परीक्षा एक कला है और विद्यार्थियों का इस विशेष कला से परिचित होना चाहिए। इसलिए समस्त पुस्तक को छात्र, छात्राओं के लिए प्रश्नोत्तर रूप में लिखा गया है। अर्थ शास्त्र के विविध अंगों का से परीक्षा में आने वाले प्रश्न देकर विस्तार उचित उत्तर दिया गया है। विद्यार्थियों की बुद्धि तथा आवश्यकता का विचार करते हुए लेखक ने सरल भाषा और सरल शैली का प्रयोग किया है। जहां विवाद-ग्रस्त प्रश्न आये हैं वहां दोनों पक्ष तथा विभिन्न विद्वानों के विविध मत सरल रीति से समझा दिए गए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भी उल्लेख किया गया है जिससे विद्यार्थियों को यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन से प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। पारिभाषिक शब्दों में भी दुर्बोधता नहीं आने पाई।

अपनी अनेक विशेषताओं के कारण यह अर्थशास्त्र सचमुच एक सरल अर्थशास्त्र है और इससे विद्यार्थी तथा परीक्षार्थी बड़ा लाभ उठा सकते हैं।

विश्व इतिहास की झलक—(संक्षिप्त संस्करण) लेखक—श्री जवाहरलाल नेहरू प्रकाशक—सस्ताहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, मूल्य ६ रुपए। पृष्ठ संख्या—५०० सजिल्द।

प्रस्तुत पुस्तक श्री नेहरू की अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक 'विश्व इतिहास की झलक' का संक्षिप्त संस्करण है। आज से बहुत वर्ष पूर्व जब श्री नेहरू प्रायः जेल में थे, अपनी पुत्री इन्द्रा के नाम उन्होंने सरल और मनोरंजक शैली में विश्व के समस्त इतिहास का सुन्दर परिचय दिया था। १२७ पत्रों में यह पुस्तक समाप्त हुई। इसके अध्ययन से पाठक के सामने हजारों वर्ष का विश्व का इतिहास—मानव की प्रगति, संस्कृति का विकास उन्नति के लिए संघर्ष, विविध जातियों का उत्थान व पतन, आदि की एक झांकी पाठक के सामने आ जाती है। और वह अपने को तात्कालिक वातावरण में बैठा हुआ सिनेमा चित्रों की भांति तादात्यय अनुभव करता है।

महा भारत कथा—ले० श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, प्रकाशक—सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली। पृष्ठसंख्या—५०० मूल्य ५ रुपये।

श्री राजगोपालाचार्य देश के महान राजनीतिज्ञ, शासक, और नेता रहे हैं और आज भी देश के सार्वजनिक क्षेत्र में उनका ऊंचा स्थान है, किन्तु उनके अपने शब्दों में उन्होंने अपने जीवन में जो देश की सबसे बड़ी सेवा की है, वह है महाभारत की पुण्य कथाओं को अपने देशवासियों के लिए सामान्य भाषा में लिख देना। वस्तुतः महाभारत और रामायण साहित्य में अमर हैं। महाभारत जैसे विलष्ट ग्रन्थ में रचियता ने मानव जीवन के सभी रूपों का वर्णन किया है। इसी कारण श्री राजगोपालाचार्य के शब्दों में यह ग्रन्थ पाठकों को अजर, अमर, सत्यरूप परमात्मा की ओर बढ़ने को प्रेरित करता है। लेखक ने अपनी सरल सुबोध और प्रभावोत्पादक भाषा में अत्यन्त श्रद्धा और अनुभूति के साथ यह कहानियाँ लिखी हैं और उनका यह विश्वास है कि महाभारत की यह संक्षिप्त कथाएँ मनुष्यों को पहले से अधिक अच्छा आदमी, अच्छा चिन्तक और अच्छा हिन्दू बनायेंगी। वस्तुतः महाभारत ग्रन्थ का प्रत्येक पात्र कोई न कोई प्रेरणा देता है और समस्त ग्रन्थ असत्य से सत्य की ओर चलने की प्रेरणा देता है। प्रकाशक ने इस पुनीत ग्रन्थ को हिन्दी भाषियों के लिए प्रस्तुत करके एक प्रशंसनीय कार्य किया है।

अशोक के फूल—ले०—श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी—प्रकाशक—वही, पृष्ठ संख्या—२१०, मूल्य ३ रुपए।

श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी उन थोड़े से विद्वानों में हैं जिनका विस्तृत अध्ययन और सूक्ष्म दृष्टि तथा गहरा चिन्तन प्रायः दुर्लभ है। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है। भाषा में ओज और प्रवाह है। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक के २१ निबन्ध संग्रहीत हैं, जिनमें से प्राचीन संस्कृति और साहित्य सम्बन्धी लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और प्राचीन परम्परा के मूल स्वरूप को समझाने में सहायता मिलती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिम जर्मनी में स्वतंत्र बाजार

संघीय जर्मन गणराज्य में, सोवियत जर्मनी क्षेत्र से बिलकुल विभिन्न एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसके अन्तर्गत वहाँ की आबादी को पर्याप्त स्वाधीनता, सामाजिक सुरक्षा और ऊँचा जीवनमान सुलभ है। सत्रह वर्षों की सरकार नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था, युद्ध अर्थ-व्यवस्था और युद्धोत्तर संकट के पश्चात्, १९४८ से वर्तमान अर्थ-व्यवस्था, जिसके लिए 'स्वतंत्र बाजार की अर्थ-व्यवस्था" का नाम दिया गया है, संघीय जर्मन गणराज्य के आर्थिक विकास का आधार बन गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ध्वस्त उत्पादन मशीनरी का पुनर्निर्माण, पोलैण्ड और सोवियत सत्ता के आधीन जर्मनी के हिस्सों से १२ दसलक्ष निष्कासितों और शरणार्थियों के लिए रोजगार, और विश्व के बाजार में नये व्यापारिक सम्बन्धों को स्थापित करना संभव हो सका है। सम्पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम होना, निष्कासितों और शरणार्थियों का समन्वय, जीवनमान में तीव्र विकास, स्थायी और ठोस मुद्रा की स्थापना और सामाजिक विधान का व्यापक विस्तार आदि ऐसी "सामाजिक" सफलताएं हैं जो इस दावे को न्यायोचित ठहराती हैं कि स्वतंत्र बाजार की अर्थ-व्यवस्था से सम्पूर्ण समुदाय को लाभ होता है।

इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का स्थापना डा. प्रो. लुडविग इयरहार्ड से निकट संबंध है। इस अर्थ-व्यवस्था को उन आर्थिक और राजनीतिक आदर्शों पर आधारित किया गया है, जिसे अनेक उदार अर्थशास्त्रियों ने प्रस्थापित किया था जिसमें प्रो. युकेन, मूलर-आर्मेक, रॉप्क और हायक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इन अर्थशास्त्रियों में से प्रो. मूलर-आर्मेक ने, जो संघीय मंत्रालय में आर्थिक मामलों के एक प्रमुख नागरिक अधिकारी हैं, इस व्यवस्था को "स्वतंत्र बाजार की अर्थ-व्यवस्था" की संज्ञा दी है। इस शब्द के अन्तर्गत एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था आती है जिसकी बुनियादी रूपरेखा और नियमन बाजार की अवस्थाओं पर निर्भर रहता है। यह अर्थ-व्यवस्था एक गतिशील आर्थिक नीति और स्वतंत्र प्रतियोगिता पर आधारित है और उसका उद्देश्य उच्चतम जीवनमान और एक स्थायी मुद्रा तथा सम्पूर्ण रोजगार के साथ आमदनी का उचित वितरण जैसे वांछनीय सामाजिक परिणामों को प्राप्त करना है। इस व्यवस्था की सामाजिक रूपरेखा को, सामाजिक सुरक्षा और निजी सम्पत्ति की रचना और पारिवारिक संरक्षण नीति का आधार और समर्थन प्राप्त रहता है। इसलिए व्यवस्था न तो जटिलता से परे कोई विमुक्त मनमानी अर्थ-व्यवस्था है और न इसमें सरकारी नियन्त्रण ही विद्यमान है। किसी भी सरकारी आर्थिक और सामाजिक नीति को बाजार की वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और संघीय जर्मन गणराज्य का नमूना वास्तव में एक ऐसी तंत्र-व्यवस्था है जिसकी स्वाभाविक गतिविधियों के जरिये सामाजिक प्रगति संभव है।

केन्द्रीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था से भिन्न इस प्रकार की व्यवस्था के प्रमुख पहलू निम्न प्रकार हैं—

१. बाजार की अर्थ-व्यवस्था का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से होता है जिसमें उत्पादन और खपत के आर्थिक निर्णयों को, सरकारी हस्तक्षेप के बिना लेकिन कानून और नैतिकता के क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादकों और उपभोक्ताओं की स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

२. इस व्यवस्था के अन्तर्गत केवल आर्थिक शक्तियों के समन्वय का सिद्धान्त मानव सम्मान के अनुकूल होता है, जबकि नियोजन में मनुष्यों को आत्मनिर्णय करने की स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है।

३. बाजार अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकों और उपभोक्ताओं को आर्थिक गतिविधियों के विकास और उसकी सीमा निश्चित करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बाजार अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता निश्चित रूप से उत्पादन को प्रभावित करता है, जबकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ता के लिए निर्णय तैयार किये जाते हैं और वह सरकारी प्रतिमानित खपत के अनुसार एक "औसत" उपभोक्ता बन जाता है। स्वतंत्र बाजार अर्थ-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

व्यवस्था में उत्पादक किसी भी समय उपभोक्ताओं की माँग के अनुसार अपनी योजनाओं को बदल सकता है, लेकिन नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन को तुलनात्मक अभाव और उपभोक्ता सामानों पर नियत्रंण के जरिये उपभोक्ताओं की इच्छा से अलग रखा जाता है क्योंकि उत्पादन क्रिया को तथाकथित सामुदायिक पूंजी निर्माण की ओर विभाजित कर दिया जाता है।

४. स्वतंत्र बाजार अर्थ-व्यवस्था में अन्त में कीमतें और ब्याज की दरें आर्थिक गतिविधियों का मार्ग निर्धारित करती हैं। कीमतों तथा ब्याज की दरों के परिवर्तनों से अल्पकालीन हानि हो सकती है लेकिन उनसे तत्काल सीधे और स्पष्ट रूप से उत्पादन और माँग के बीच की असंगतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं और उनका शीघ्र समाधान किया जाता है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उपभोक्ताओं को अपनी इच्छाओं को सीधे रूप में व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है; नियोजन अधिकारी केवल धीरे-धीरे उपभोक्ता आँकड़ों में होने वाले परिवर्तनों के जरिये ही उक्त इच्छा की जानकारी प्राप्त करते हैं। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में उत्पादक को उपभोक्ता की इच्छानुसार तत्काल अनुकूल बनने का अवसर प्राप्त नहीं होता है बल्कि उनको केन्द्रीय नियोजन सत्ता के निर्णयों की बाट देखनी पड़ती है।

बाजार अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक सन्तुलन का चढ़ाव-उतार तत्काल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार के चढ़ाव-उतार को काफी समय तक दुर्लक्ष्य किया जा सकता है। बाजार अर्थ-व्यवस्था में गलतियों को आसानी से पकड़ा और सुधारा जा सकता है, क्योंकि प्रतियोगिता के जरिये उत्पादन सस्ता होता है और जो सस्ते तरीके से उत्पादन नहीं कर सकते हैं वे प्रकाश में आ जाते हैं; और इस तरह से साहसिक प्रयत्नों के जरिये वैयक्तिक पहल हमेशा तुलनात्मक कसौटी पर रहती है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार की तुलनात्मक कसौटी संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ गलतियों को तत्काल नहीं पकड़ा जा सकता है और गलतियों के जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं आ पाते हैं। इसलिए अधिक उत्पादन की प्राप्ति का मुख्य स्रोत माँग का दबाव नहीं है बल्कि निर्धारित लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति प्रायः कठोर प्रयत्नों से की जाती है।

आर्थिक प्रगति अनेक नये विचारों और अनुसन्धानों पर निर्भर करती है और उनका भरसक उपयोग केवल उसी व्यवस्था में संभव है जिसमें वैयक्तिक पहलू के विकास को काफी अवसर मिलता है।

५. फिर भी स्वतन्त्र बाजार अर्थ-व्यवस्था में नियोजन का अभाव नहीं रहता है। वास्तव में उसमें अनेक वैयक्तिक योजनाओं का योग होता है। प्रत्येक उत्पादक को बाजार की दैनिक परिवर्तित पद्धति के आधार पर नये सिरे से नियोजन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है और अपनी योजना को अन्य लोगों की योजना के साथ समन्वित करना पड़ता है। केन्द्रीय नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था में अनिवार्यतः दीर्घकालीन नियोजन किया जाता है जबकि स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था वास्तव में अनवरत परिवर्तन की व्यवस्था है।

६. स्वतंत्र बाजार अर्थ-व्यवस्था में सरकारी प्रभाव का बिलकुल अभाव नहीं होता है; लेकिन उसमें ऐसे किसी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होती जिसके जरिये परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति उत्पादकों की प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सके या बाजार के विधान को समाप्त किया जा सके।

• •

राजस्थान खादी संघ का मासिक मुखपत्र

राजस्थान खादी पत्रिका

खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय-भूदान पर अधिकारी विद्वानों के विचारपूर्ण लेख, खादी-आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी तथा अन्य सांख्यिकी परिशिष्ट आदि।

प्रधान सम्पादक : श्री जवाहिरलाल जैन

वार्षिक मूल्य ३) : एक प्रति ४ आने

राजस्थान खादी पत्रिका

पो० खादीबाग (जयपुर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जम्मू और कश्मीर

में

सामुदायिक विकास योजनाओं की प्रगति

द्वितीय योजना की अवधि के प्रारंभिक तीन वर्षों में सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय सेवा विस्तार के क्षेत्र में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की गईं।

- राज्य में ५३ ब्लॉक स्थापित हुए।
- ६१७ सामुदायिक केन्द्र बनाए गए।
- ३४ ग्राम-नेता प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए।
- ब्लॉक परामर्शदात्री समितियों की १,०२४ सभाएं हुईं।
- ६,१३२ उन्नत औज़ार वितरित किए गए।
- २६८ पीने के पानी के कुएं बनाए गए।

कश्मीर सूचना कार्यालय

जम्मू और कश्मीर शासन

द्वारा प्रसारित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बजट के नये प्रस्ताव

(पृष्ठ १६८ का शेष)

इसका निर्णय कम्पनियों पर ही छोड़ दिया जायगा।

४. नये कारखानों को जितनी अवधि के लिए इस समय कर की छूट दी जाती है, उसमें और ५ साल की वृद्धि की जायगी।

५. दातव्य दी जाने वाली रकम पर छूट बढ़ाकर कुल आमदनी का ७॥ प्रतिशत या १॥ लाख रु०, जो भी कम हो, कर दिया जायगा।

६. वैज्ञानिक खोज के लिए वैज्ञानिक गवेषणा और शिक्षा संस्थाओं को जो रकम दी जायगी, उसका संबंध यदि दान देने वाले के व्यापार से न भी हो, तब भी उसकी व्यापारिक आमदनी का हिसाब लगाते समय यह रकम उसकी आमदनी में नहीं गिनी जायगी।

७. जिस संपत्ति का निर्माण १ अप्रैल १९५० से पहले हुआ है उसके संबंध में स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगायी गयी और संपत्ति के मालिक द्वारा दी जाने वाली करों की पूरी रकम, संपत्ति की कर योग्य आमदनी का हिसाब लगाते समय बाद में दे दी जायगी।

८. खेती, देहाती कर्ज और घरेलू उद्योग धंधों से सम्बन्ध रखने वाली सहकारी समितियों की कारवारी आय को कर से पूरी छूट मिलती रहेगी पर दूसरी समितियों की कारवारी आय को केवल १०,००० रु० तक छूट मिलेगी।

९. व्यय कर अधिनियम के संशोधनों में यह व्यवस्था है कि भारत में छुट्टी सम्बन्धी यात्रा पर किये गये खर्च और भारत में बच्चों की शिक्षा पर किये गये खर्च पर छूट दी जाय। यह भी विचार है कि करदाता द्वारा विदेशी सरकार को दिये गये करों की कुल रकम को छूट मिलनी चाहिये, जबकि अभी ऐसी रकम के सिर्फ एक हिस्से को ही छूट मिलेगी।

१०. दान कर अधिनियम के संशोधन में व्यवस्था है कि पहले से दिये जाने वाले कर की दर वही होगी जो नियमित मूल्य निर्धारण के आधार पर दिये जाने वाले कर के लिए है।

प्रस्तावों का वास्तविक प्रभाव

केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के परिवर्तनों से राज्यों को दिये जाने वाले राजस्व को छोड़कर, २१.०३ करोड़ रु० की अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान है। सीमा शुल्कों के परिवर्तनों से २.५ करोड़ रु० की प्राप्ति का अनुमान है। इस तरह कुल २३.५३ करोड़ रु० अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी जिससे राजस्व खाते का घाटा ८३.९ करोड़ रु० से कम होकर ६०.३७ करोड़ रु० और संपूर्ण घाटा १७७ करोड़ रु० से कम होकर १५३ करोड़ रु० रह जायगा। राजस्व के घाटे को पूरा किये बिना ही छोड़ देने का विचार है। सम्पूर्ण घाटे को राजकोष हुंडियों के विस्तार से पूरा किया जाएगा।

देश पर उत्तरदायित्व

बजट वर्ष के अन्त में आयोजना का कुल खर्च लगभग ४,६०० करोड़ रुपये तक पहुँचेगा। चालू आयोजना की अवधि में, केन्द्र में, आयोजना के दायित्वों को पूरा करने के लिए, जिस में राजस्व बजट से राज्यों को दी गयी सहायता भी शामिल है, राजस्व की भारी रकमें प्राप्त की हैं। मुझे आशा है कि आयोजना की पाँच वर्ष की अवधि में, आयोजना के सभी दायित्वों को पूरा कर लेने और राज्यों को उनकी आयोजनाओं के लिए काफी सहायता देने के बाद हमारे पास ५० करोड़ रुपये से भी अधिक का राजस्व अधिशेष (रेविन्यू सरप्लस) इकट्ठा हो जाएगा। आयोजना के पहिले तीन वर्षों में घाटे की वित्त व्यवस्था की कुल रकम लगभग ८८५ करोड़ रुपया थी। चालू वर्ष में यह मानते हुए कि राज्य सरकारें इसे काफी मात्रा में बढ़ाएंगी नहीं और सम्भावना यही है कि नहीं बढ़ाएंगी—घाटे की वित्त-व्यवस्था की रकम सम्भवत १९० करोड़ होगी। अगले वर्ष के लिए भी यदि १५३ करोड़ रुपये की रकम मान लें, तो आयोजना की सारी अवधि में घाटे की वित्त-व्यवस्था की कुल रकम १,२०० करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक होगी, जिसकी कल्पना आयोजना में कर ली गयी थी। बचतों के सम्बन्ध में हम उतना अच्छा काम नहीं कर सके जितना करना चाहते थे।

दूसरी आयोजना की समाप्ति तीसरी आयोजना के आरम्भ का संकेतमात्र है और यदि देश को पहले से बड़ी आयोजना को संभालना है, जो अनिवार्य है, तो समाज को पहले से अधिक उद्यम और त्याग करना पड़ेगा। ● ●

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस प्रा० लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली से मुद्रित व अशोक प्रकाशन मन्दिर २८/११, शक्तिनगर दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दूसरा चरण

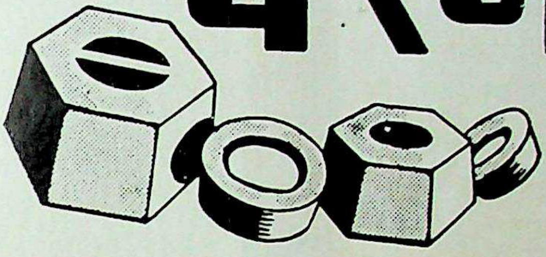

१ अक्तूबर, १९५८ को सभी राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों के कुछ चुने हुए इलाकों में और नियंत्रित मंडियों में मेट्रिक बाटों का प्रयोग चालू किया गया था और इस प्रकार का परिवर्तन पूरा करने के लिए २ वर्ष का समय रखा गया था।

यह दो वर्ष की अवधि ३० सितम्बर, १९६० को समाप्त हो जाएगी और उसके बाद इन क्षेत्रों में मेट्रिक बाटों का प्रयोग अनिवार्य हो जाएगा।

इस प्रकार के परिवर्तन का दूसरा चरण शुरू करने और बाकी क्षेत्रों में मेट्रिक बाटों का प्रयोग शुरू करवाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। समूचे केरल प्रदेश में मेट्रिक बाटों का प्रयोग शुरू हो चुका है और शीघ्र ही अन्य राज्यों में भी ऐसा ही होगा।

अपनाइये | **मेट्रिक प्रणाली**

सरलता व एकरूपता के लिए

भारत सरकार द्वारा प्रसारित

DA 59/541

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
Regd. No. D.-361

पंखों की परम्परा

दक्षिण भारत के लोग ताड के पत्तों से बने पंखे सदियों से लेकर आज तक इस्तेमाल करते चले आरहे हैं। ये सादा लेकिन बहुत ही उपयोगी पंखे आमतौर पर प्राचीन मन्दिरों की शिल्पकला में देखने को मिलते हैं।

बढ़िया उत्पादनों का स्थान सस्ती वस्तुएँ नहीं ले सकतीं!

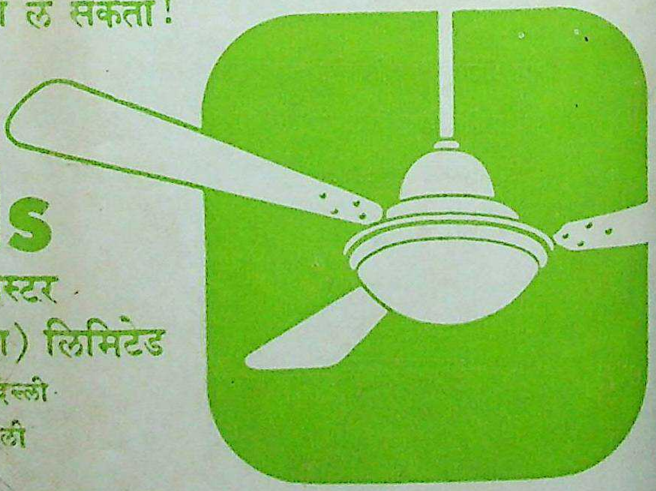

Kassels
कैसल्स एअरमास्टर
मैच्वैल इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड
पो. ऑ. बॉक्स १५६, नयी दिल्ली
कारखाने : पूना और दिल्ली

MEY-4 HIN

भारत के लिए सोलसेलिंग ऐजेंट : **मैसर्स रेडियो लैम्प वर्क्स लि०**
बम्बई-कलकत्ता-दिल्ली-मद्रास-कानपुर-पटना-इन्दौर-वर्धा-गोहाटी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation

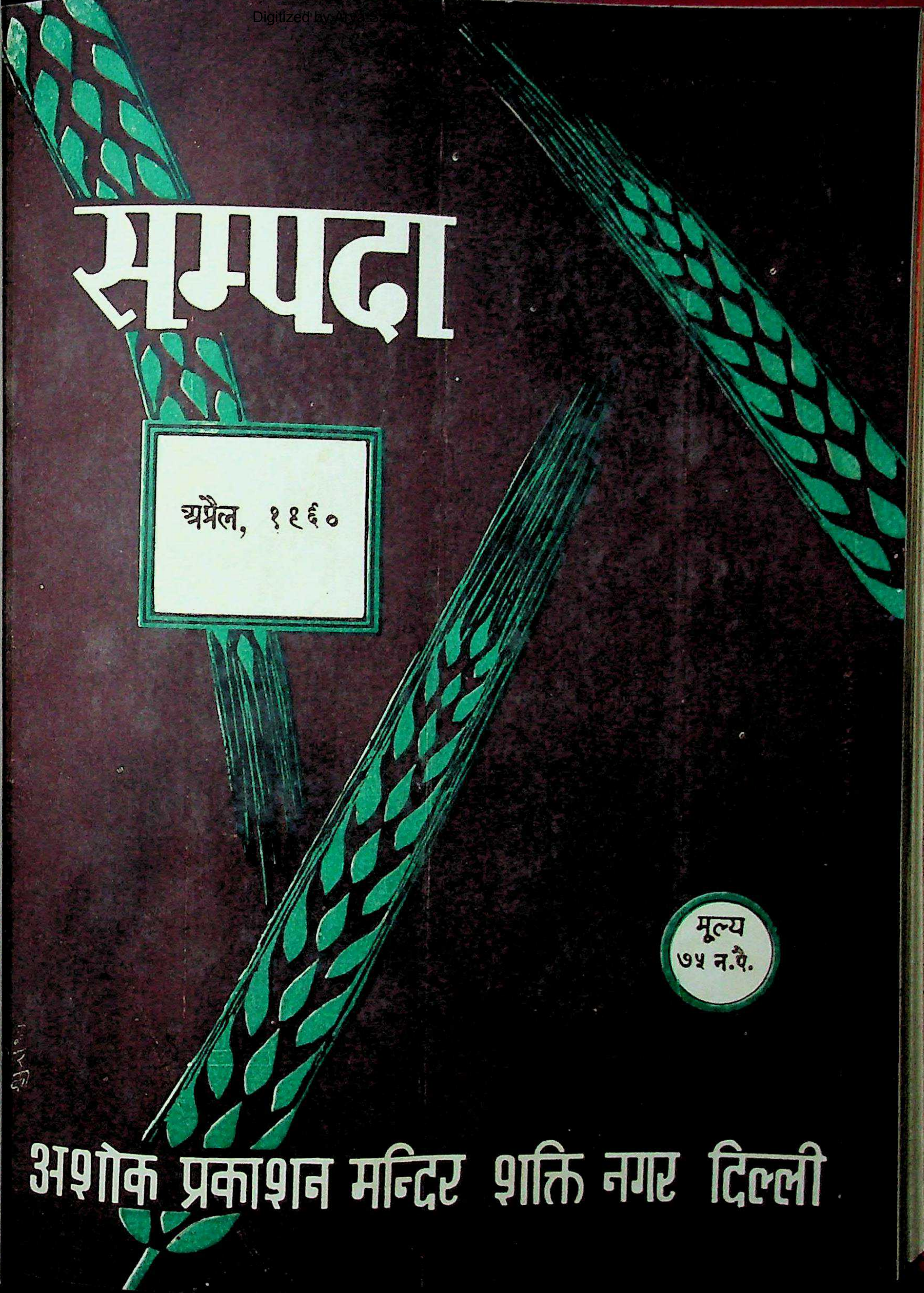

सम्पदा

अप्रैल, १९६०

मूल्य ७५ न. पै.

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर दिल्ली

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक्सल की कहानी

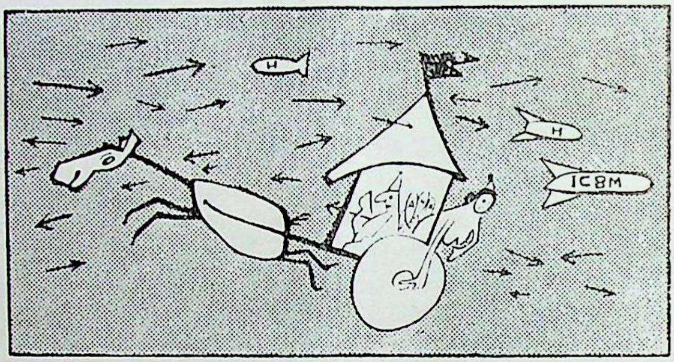

सारे रामायण महाकाव्य का उद्भव वास्तव में एक पुर्जे के टूटने से हुआ था. घमासान युद्ध के बीच शाही रथ का एक्सल टूट गया, परन्तु रानी कैकेयी ने अपनी उंगली डाल कर पहिए को यथास्थान रखा. राजा दशरथ ने उस से कोई वर मांगने को कहा जिस का फायदा कुटिल रानी ने श्री राम को बनवास भेजने में उठाया.

इसलिए आप मानेंगे कि हमें अपने एक्सल मजबूत रखने होंगे. वियरवेल साइकिलें हर प्रकार के काम के लिए बनाई गई हैं. उन का हर पुर्जा मजबूत होता है.

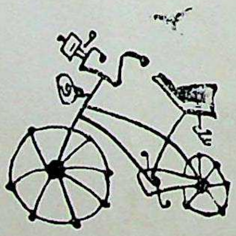

वियरवेल साइकिल्स

विमपैक्स (एजेंट्स) नई दिल्ली · बम्बई · कलकत्ता · मद्रास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस अङ्क में

तृतीय पंचवर्षीय योजना — अग्रलेख — १८९
सम्पादकीय टिप्पणियां — १९१
दक्षिण पूर्वी एशिया में नया आर्थिक संघ — १९४
उत्पादन उपलब्धियां और मूल्य — विनोदचन्द्र सिन्हा — १९५
मुद्रास्फीति यथा संकुचन — विनोदकुमार भटनागर — १९९
सहकारी खेती क्या रूप ले ? — रिपोर्ट — २०३
कम्युनिज़्म : मानव जाति का भविष्य — एस. लिओनलेज — २०४
स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास — प्रो० कैरोट ए० जोसेफ — २०८
आगे बढ़ते हुए देश और श्रमिक — जान सी० लाज — २१०
विविध राज्यों के बजट — २१२
नया साहित्य — २१४
दो विरोधी दलों के आर्थिक कार्यक्रम — २१६
नये बाट — मन्नूलाल द्विवेदी — २१७
उद्योग के बढ़ते चरण — लाल बहादुर शास्त्री — २१९
राज्यों का विकास नियोजन — जी० एस० पथिक — २२१
सर्वोदय पृष्ठ — २२३
सांख्यिकी — २२६
अर्थवृत्त — २२७
हमारे उद्योग — २२९
विदेशी अर्थ चर्चा — २३०
नया निर्माण — २३२
मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं — २३४

विश्वसनीय
बैंक

संपूर्ण भारत में फैली हुई ३८०से अधिक
शाखाएँ और संपूर्ण संसार में सुचारू
रूप से संचालित ओवरसीज़ एजेन्सियाँ।

कार्यगत कोष — १७६ करोड़ रुपये से अधिक
जमा धनराशि — १४१ करोड़ रुपये से अधिक

दि
पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड
स्थापित सन् १८९५ ई०
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा का आगामी विशेषांक

अगस्त १९६० में प्रकाशित होगा । तैयारी प्रारंभ हो गई है ।

किस विषय पर ?

यह जानने के लिए एक मास की प्रतीक्षा कीजिये ! यह विशेषांक आकार और स्तर में सम्पदा के पूर्व विशेषांकों से भी बढ़कर होगा !

नौका सी मधुर चाल

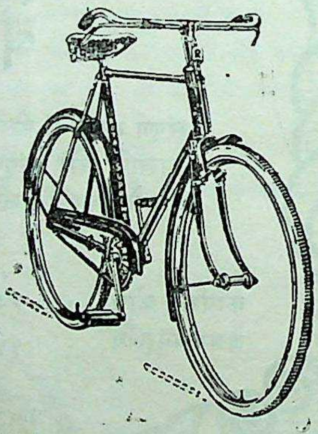

रॉयल सुप्रीम

मधुर चाल के लिये नौका प्रसिद्ध है।
और सड़क पर सुगम चाल के लिये
रोयल सुप्रीम अद्वितीय है।
रोयल सुप्रीम...
भारत की लोक-प्रिय साइकिल

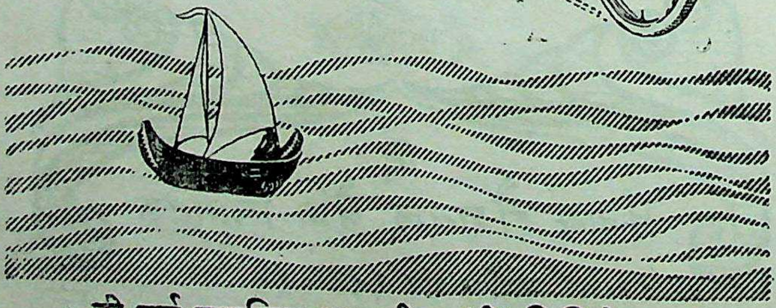

दी पर्ल साइकिल इन्डस्ट्रीज़ (पी) लिमिटेड

नई दिल्ली-१५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष : ९

अंक : ४

अप्रैल १९६०

तृतीय पंचवर्षीय योजना

बहुत संभवतः इस अंक के पाठकों के पास पहुँचने के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा अधिकृत रूप से प्रकाशित हो जायगी, किन्तु राष्ट्रीय विकास परिषद के विचार विमर्श तथा अन्य विचार-विमर्शों से ऐसा ज्ञात होता है कि इस योजना की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित होगी—

इस योजना का लक्ष्य ९,९५० करोड़ रुपया होगा। इसमें से ७० सौ करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र के लिये नियत किया गया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस योजना के लिये निम्नलिखित तत्वों को अत्यावश्यक बताया है—

१. कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि तथा देश की मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग।

२. सरकारी उद्योगों को मितव्यय एवं कुशलता से चलाकर अधिकतम लाभ की प्राप्ति।

३. सम्पूर्ण देश में एक समष्टिगत मूल्य नीति का निर्धारण।

४. देश में निर्माण कार्यक्रमों का व्यय न्यूनतम रखने पर बल।

५. सरकारी प्रशासन की कुशलता और उच्च स्तर पर विशेष ध्यान...

६. सरकारी-निजी उद्योगों से अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र के लिये ५४% अधिक अर्थात् ४,५५० करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है, कृषि तथा सामुदायिक योजनाओं के लिये १,००० करोड़ रुपये अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना से करीब दुगुनी राशि रखी गई है।

अन्य मदों में निम्नलिखित राशि नियत की गई है—

मद	तीसरी योजना	दूसरी योजना
सिंचाई	६५० करोड़	४०० करोड़
विद्युतशक्ति	८०० ,,	४१० ,,
ग्रामोद्योग	२५० ,,	१८० ,,
उद्योग और खनिज	१२०० ,,	८२० ,,
यातायात और संवाद		
संचरण	१४५० ,,	१३३० ,,
समाज-सेवा	१२५० ,,	८८० ,,
शेष मद	—	२०० ,,

यह भी अनुमान किया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय ५% बढ़ जायगी, जबकि द्वितीय योजना में ४% आय बढ़ी है। नई योजना में परिवार नियोजन को विशेष महत्व दिया जायगा, जिससे योजना निर्माताओं के विचार में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात तीसरी चौथी और पांचवी योजनाओं में क्रमशः कम होता हुआ २.१४%, १.९% और १.४७% हो जायगा।

निजी क्षेत्र में करीब ४००० करोड़ रुपये का विनियोजन होगा, जिसका मुख्य वर्गीकरण इस तरह है—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उद्योग और खनिज	१००० करोड़ रुपया
यातायात तथा विद्युत	२५० ,, ,,
कृषि	८०० ,, ,,
ग्रामोद्योग	२७५ ,, ,,
नगरों तथा ग्रामों में गृह निर्माण	१०७५ ,, ,,

वृहदाकार योजनाओं की रूपरेखा बनाना इतना कठिन नहीं है जितना जटिल इन योजनाओं के लिये साधन जुटाने का प्रश्न है। योजना निर्माताओं ने भी इस सम्बन्ध में काफी घोड़े दौड़ाये हैं। ऊंचे लक्ष्य रखकर सुनहरे स्वप्न देखना जितना रोचक होता है, उतना ही साधन जुटाना कठिन और अप्रिय होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की है कि नये करों से विशाल राशि एकत्र की जाय। १,१५० करोड़ रुपये के नये कर केन्द्रीय शासन लगाये और ५०० करोड़ रुपये के नये कर राज्य सरकारें लगाएं। एक अनुमान के अनुसार निम्न मदों से भी इस तरह आय जुटाई जायगी—

बाजार से ऋण	८५० करोड़ रुपया
छोटी बचत	५०० ,, ,,
प्रोवीडेन्ट फंड, सुधार कर तथा इस्पात समीकरण कोष	३८० ,, ,,
रेलवे	१५० ,, ,,
सरकारी उद्योगों से लाभ	४७० ,, ,,
राजस्व में बचत	२०० ,, ,,
विदेशी सहायता	२४०० ,, ,,

(निजी क्षेत्र को सम्मिलित करके)

घाटे की अर्थव्यवस्था से विशेष आवश्यक राशि जुटाये जाने की संभावना करनी चाहिये। आजकल रूस, अमरीका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी आदि देशों से जिस तरह अच्छे सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं, उसे देखते हुए यह असंभव नहीं है कि विदेशी सहायता की अनुमानित राशि उपलब्ध हो जाय, किन्तु योजना पूर्ति में अन्य अनेक समस्याओं का समाधान सरल नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने भी इन प्रश्नों पर विचार किया है। इन प्रश्नों में सबसे विकट देश में बढ़ती हुई महंगाई का है, जब तक अनाज और दूसरे जीवनोपयोगी पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण नहीं किया जायेगा, देश में बढ़ती हुई महंगाई कम नहीं होगी, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती, विकास योजनाओं से नागरिक की आय में जो वृद्धि होती है, बढ़ती हुई महंगाई उसे चट कर जाती है, इस कठिन समस्या का कोई समाधान राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं कर सकी और इस प्रश्न को राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सुपुर्द कर दिया गया। संभवतः इस मास के तीसरे सप्ताह में इस प्रश्न पर पुनर्विचार होगा।

तृतीय योजना के मार्ग में एक और कठिन प्रश्न यह है कि कृषि और उद्योगों में किसे प्राथमिकता दी जाय, भारत सरकार लोहा तथा मशीनरी आदि को विकसित करने पर तुली हुई है, किन्तु इसके कारण कृषि की थोड़ी-सी भी उपेक्षा हमारे लिये हानिकर सिद्ध हो सकती है। कृषि उत्पादन ही समस्त आर्थिक चक्र का केन्द्र है। कृषि उत्पादन के बढ़ने के साथ ही देश में महंगाई कम हो सकती है।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि देश को बहुत बड़े उद्योगों की अपेक्षा लघु व मध्य उद्योगों की अधिक आवश्यकता है। पं० गोविन्द बल्लभ पन्त ने ठीक ही कहा है कि बिहार में लोहे का बड़ा कारखाना तथा आसाम में तेल उद्योग के बावजूद गरीबी है और पंजाब में कोई बड़ा उद्योग न होते हुए भी मध्य उद्योगों के कारण जनता का जीवन स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा है। इसे देखते हुए बड़ी योजनायें आवश्यक होते हुए भी अधिकांश जनता की समृद्धि पर बहुत प्रभाव नहीं डालतीं। इसलिये तीसरी योजना में दो बातों की ओर ध्यान देना चाहिये, एक तो लघु और मध्य उद्योगों की उपेक्षा न हो और दूसरा समस्त क्षेत्रों की दृष्टि से उद्योगों का सन्तुलित विकास किया जाय।

राष्ट्रीय विकास परिषद के कुछ दिन बाद ही अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का वार्षिक अधिवेशन हुआ, मंडल ने सरकार को जहां देश के आर्थिक विकास में पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया, वहां सरकार से यह अनुरोध भी किया कि सरकार भी निजी उद्योगों के मार्ग में बाधक न होकर सहायक और प्रेरक बने। इस मंडल ने अनेक उपयोगी परामर्श दिये हैं, जिनका यदि आदर किया जाय तो निस्सन्देह देश के आर्थिक विकास में सहायता मिल सकती

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। निजी उद्योग की प्रतिभा और अनुभवों का लाभ उठाने की उपयोगिता सरकार भी धीरे-धीरे समझ रही है। उद्योग मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने दो लाख टन खाद के उत्पादन का काम निजी उद्योग के सुपुर्द करने का विचार प्रकट किया है, इसी तरह सरकार अन्य भी अनेक सुविधायें देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है।

योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये प्रशासन में जिस कुशलता और सदाचार की आवश्यकता है, उस पर भी देश का ध्यान खिंचा है। हमें आशा करनी चाहिये कि योजना आयोग बिना किसी पूर्वाग्रह और कोरे नारों से अलग रहकर यथार्थ वस्तुस्थिति का अध्ययन करेगा, और सब परामर्शों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। ● ●

खम्भात के तेल स्रोत

भारत सरकार के खान तथा पेट्रोल मंत्री श्री केशवदेव मालवीय ने लोकसभा में यह घोषणा करके समस्त देश को आल्हादित कर दिया है कि खम्भात में व्यापारिक स्तर पर पेट्रोल निकलना संभव है और इसलिए वहाँ एक मध्यम आकार का पेट्रोल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है। उनके अनुमान के अनुसार ९-१० लाख टन पेट्रोल तैयार होने की संभावना है। सरकार का विचार है कि एक तरफ तेल के कुओं से पेट्रोल निकाला जाए और दूसरी तरफ पेट्रोल शोधन का कार्य भी हो। पिछले दिनों में भारत सरकार के प्रधान मंत्री श्री नेहरू भी खम्भात के तेल के कुओं का दर्शन करने गए थे और उन्होंने यह सम्भावना प्रकट की थी कि इन कुओं से बहुत संभवतः व्यापारिक मात्रा में तेल निकलने लगेगा। इसकी अधिकृत घोषणा श्री केशवदेव मालवीय ने कर दी है। इधर रूस का पेट्रोल निकालने तथा उसके संशोधन में पर्याप्त सहयोग मिल रहा है। आशा करनी चाहिए कि खम्भात के तेल कूप भारत की विदेशी मुद्रा को बचाने में जहाँ बहुत सहायक होंगे, वहाँ नव गुजरात राज्य की आर्थिक समृद्धि पर भी अनुकूल प्रभाव डालेंगे।

खाद के कारखाने

आजकल भारत सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये एक के बाद एक योजना बना रही है। वस्तुतः देश के अर्थचक्र का आधार कृषि ही है। जब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ जाता, तब तक सैकड़ों प्रयत्न भी देश की अर्थ-व्यवस्था को ठीक मार्ग पर नहीं ला सकते, कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक उपाय आज के कृषि विशारदों की सम्मति में रासायनिक खाद की अधिक से अधिक उपलब्धि है और सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। पिछले महीने केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने भारत सरकार का यह निश्चय प्रकट किया है कि तीसरी योजना में प्रत्येक राज्य में एक न एक रासायनिक खाद का कारखाना खोला जायेगा। अनुमान यह है कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष तक नत्रजन खाद की पैदावार १२½ लाख टन प्रति वर्ष हो जायगी, जबकि आज का उत्पादन केवल ८० हजार टन का है। आज विद्यमान कारखानों को भी अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुमति दी गई है। मद्रास की एक कम्पनी ९१ हजार टन अमूनियम फासफेट प्रति वर्ष तैयार करने का कारखाना लगाने पर विचार कर रही है राजस्थान और पंजाब में भी दो नए कारखाने खोलने का निश्चय सरकार कर चुकी है। प्रसन्नता की बात यह है कि सरकार भी खाद की चरम आवश्यकता को अनुभव कर रही है और इसके लिये वह निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेने को तैयार है। वस्तुतः हमारा प्रथम उद्देश्य देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है और इसके लिये निजी क्षेत्र का सहयोग लेने में संकोच नहीं करना चाहिये सरकार उन उद्योगों में अपनी शक्ति लगाये जो निजी क्षेत्र की शक्ति से बाहर हैं। नवसारी में आदर्श केमीकल्स एण्ड फरटीलाइजर्स लिमिटेड, सूरत जिले में एक बड़ा कारखाना खोलने वाली है, इसके लिये उसने एक ब्रिटिश कम्पनी का सहयोग भी प्राप्त कर लिया है। एक कम्पनी मद्रास में खुल रही है, हमें आशा करनी चाहिये कि आगामी दो तीन वर्षों में वैज्ञानिक खाद की कमी एक सीमा तक अवश्य दूर हो जायगी और उसका प्रभाव कृषि उत्पादन पर भी पड़ेगा।

विश्व बैंक के प्रतिनिधि

योजना आयोग ने नई योजना की जो रूपरेखा बनाई है, उसमें विदेशी सहायता से विपुल राशि के प्राप्त होने की संभावना रखी है। कोई देश बिना स्थिति का अध्ययन किये करोड़ों रुपया नहीं दे देता। इसलिए यह स्वाभाविक ही था

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कि विदेश भारत में ऋण या पूंजी के रूप में लगाये गये रुपये के सदुपयोग, विकास की संभावनाओं तथा देय शक्ति का अनुमान लगावें। अमेरिकन राष्ट्रपति श्री आइजनहावर ने कुछ समय पूर्व कुछ विशेषज्ञों का एक शिष्ट मण्डल भेजा था। अब विश्व बैंक का एक छः सदस्यीय शिष्टमण्डल आया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भी ऐसा ही मण्डल आया था। अब तीसरी योजना तैयार होने जा रही है। यह मण्डल विविध सरकारी व निजी उद्योगों व सामुदायिक योजनाओं की स्थिति का अध्ययन करेगा यह योजना आयोग के सदस्यों से मिल रहा है। इसकी भारत में ठहरने की अवधि २॥ मास है। देश जिस वेग से प्रगति कर रहा है, उसे देखते हुए यह आशा करनी चाहिए कि यह मण्डल अनुकूल सम्मति ही देगा।

बैंकों में और वेतन वृद्धि की मांग

इण्डियन बैंक एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री सी० एच भाभा ने पिछले दिनों अध्यक्षीय भाषण देते हुए बैंक कर्मचारियों के वेतनों पर प्रकाश डाला है। इससे मालूम होता है कि पिछले बैंक एवार्ड के कारण कर्मचारियों के वेतन पर कितना व्यय हो रहा है।

(रुपये लाखों में)

वर्ष	कुल वेतन, भत्ते, प्रोवीडेण्ट फण्ड और ग्रेच्युटी बैंक एवार्ड के अन्तर्गत	कर्मचारियों को अन्य सभी कर्मचारियों को	कुल	कर सहित अन्य व्यय
१९५६	६,०७	३,६१	९,६८	५,२९
१९५७	६,८८	३,९५	१०,८३	६,०५
१९५८	७,६७	४,५६	१२,२३	६,१५

इस सूची से यह स्पष्ट है कि बैंकों के व्यय बढ़ रहे हैं। श्री भाभा ने इस सूची की ओर ध्यान खींचते हुये यह मांग की है कि आगे वेतन निर्धारित करते समय दो सिद्धांत अमल में लाने चाहिएं। एक तो यह कि जो काम न करे उसे वेतन न दिया जाय और दूसरा यह कि योग्यता के बिना वेतन-वृद्धि न की जाय।

इधर भारत सरकार ने स्टेट बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद वेतन सम्बन्धी प्रश्न पर निर्णय देने के लिये ट्रिब्यूनल की नियुक्ति कर दी है, जीवन व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिये उनकी यह मांग विचारणीय हो गई है कि वेतन वृद्धि की जाय। बैंकों के डिपोजिट १९५८ की अपेक्षा निश्चित रूप से बढ़े हैं, १९५७, १९५८ और १९५९ के ये अंक क्रमशः १३६७.५१, १५७४.३ और १८२८.०८ करोड़ रुपया है। यह ठीक है कि आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण बैंकों से उद्योग और व्यापार ने उतना रुपया उधार नहीं लिया फिर भी बैंकों की आय बढ़ी ही है। रिजर्व बैंक की जांच के अनुसार २५ अनुसूचित बैंकों की कुल आय १९५७ में ५३.७ करोड़ रुपये थी, जबकि १९५८ में यह आय ६४.४ करोड़ हो गई। यह ठीक है कि खर्च भी बढ़ रहे हैं इसलिये विशुद्ध आय पहले की अपेक्षा कुछ कम हो गई है, इस कमी का कारण बैंक अधिकारियों की सम्मति में व्यय में बेतहाशा वृद्धि है।

हमारी नम्र सम्मति में बैंक हों, कल कारखाने हों, या सरकारी कर्मचारी हों, वेतन वृद्धि की मांग तब तक बढ़ती रहेगी, जब तकः—

१—बढती हुई महंगाई को कम न किया जाय,

२—सब संस्थाओं के उच्च अधिकारी स्वयं त्याग का आदर्श उपस्थित न करें। जब तक इन दोनों की ओर यथोचित ध्यान नही दिया जायेगा, तब तक कर्मचारी वेतनवृद्धि की मांग करते ही रहेंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता। पहला कदम उनकी मांग का वैज्ञानिक उत्तर है। दूसरा कदम उनका मनोवैज्ञानिक उत्तर है। उच्च अधिकारियों के भारी वेतन और आडम्बरमय जीवन को जब तक वे देखेंगे, अपने असन्तोष को दबा नहीं सकेंगे।

सूती मिलों के वेतन

गत अंक में हमने सूती मिलों में सरकार द्वारा घोषित वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में लिखते हुए सलाह दी थी कि यद्यपि इन सिफारिशों से उद्योग पर कुछ बोझ बढ़ जायगा तथापि आज उनका कर्तव्य यह है कि वे त्याग करके भी इन सिफारिशों का आदर करें। अब तक किसी मिल ने नये रेट बढ़ा दिये हों इसका ज्ञान हमें नहीं है।

बम्बई के मिल ओनर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री रामनाथ पोद्दार ने एसोसिएशन की वार्षिक सभा में यह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कहा है कि यदि वेतनबोर्ड अपनी सिफारिशें देने से पहले केन्द्रीय सरकार के वेतन कमीशन की जांच की भी प्रतीक्षा कर लेता तो अधिक अच्छा होता। उस कमीशन ने अपनी जांच में यह लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय के स्तर से अधिक न्यूनतम वेतन निर्धारित करना देश की क्षमता से बाहर की बात होगी। श्री पोद्दार ने वेज बोर्ड के प्रस्तावों पर उद्योग के साधनों को देखते हुए पुनर्विचार की सलाह दी है। अन्य भी अनेक उद्योगपतियों ने उद्योग की क्षमता की दृष्टि से वेतन वृद्धि की सिफारिशों का विरोध किया है। उनकी युक्तियों में सार नहीं है ऐसा हम नहीं कहना चाहते, फिर भी हमारी नम्र सम्मति में नई सिफारिशों को उन्हें मान लेना चाहिये, आखिर वेजबोर्ड ने जिसमें मिल मालिकों के भी प्रतिनिधि थे, सर्वसम्मति से सिफारिशें की हैं।

बिक्री कर से परेशानियां

सरकार द्वारा लगाए गए बिक्री कर के सम्बन्ध में जितना अधिक असंतोष व्यापारियों में रहा है, उतना शायद किसी अन्य कर से नहीं। भिन्न-भिन्न राज्य सरकारें बिक्री कर को कामधेनु समझ कर जनता का दोहन करने लगी हैं। इस कर की वजह से व्यापारियों में असन्तोष बराबर बढ़ता रहा है। उनकी माँग पर ही सरकार ने चीनी, कपड़ा आदि पर बिक्री कर को उत्पादन करके साथ मिला दिया था। इस कारण व्यापारी इन वस्तुओं पर कर के हिसाब-किताब और परेशानियों से बच गए थे; किन्तु अब भी, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, जिन पर बिक्री कर की वजह से छोटे व्यापारियों और दूकानदारों को बेहद परेशानी होती है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने इस सम्बन्ध में सरकार से आग्रह किया है कि वह जहाँ संभव हो, बिक्री कर को उत्पादन कर के साथ मिला दे अथवा उत्पादन कर के रूप में परिणत कर दे। भारत के वित्तमंत्री श्री मुरारजीदेसाई ने इस प्रश्न पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इस पर विचार करने के लिए उपसमिति निर्धारित कर दी गई है। उत्पादन के मूल स्थान पर कर ले लेने से भ्रष्टाचार भी कम होगा, कर प्राप्ति में खर्च भी बच जायगा और व्यापारी आये दिन की परेशानी से भी मुक्त हो जायंगे।

परिवहन विकास

परिवहन तथा संचार मंत्री श्री राजबहादुर ने विकास परिषद् की बैठक में स्वीकार किया है कि सड़क परिवहन पर कर कम होना चाहिए और सब राज्यों में प्रायः एकसे कानून होने चाहिएं। वस्तुतः यदि इस उद्योग का विकास करना है, तो यह अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना निर्बाध प्रेरणा नहीं मिल सकती। विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य इंजीनियरों ने अगले बीस सालों के लिए सड़कों के विकास का एक कार्यक्रम भी बनाया है। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस के लिए ४६० करोड़ रु० की व्यवस्था की जा रही है, जो संचार मंत्री के मत में बहुत कम है। छोटी और बड़ी सड़कों के विकास के लिए कम से कम १०५० करोड़ रु० जरूर रखना चाहिए, जो योजना के कुल व्यय का १० प्रतिशत से भी कम होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इतना रुपया आयगा कहाँ से ?

मंत्रालयों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को कम करने का उपाय !

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दक्षिण-पूर्वी एशिया में नया आर्थिक संघ

यूरोप में दो ऐसे संगठन बने हैं, जिनसे अनेक देश परस्पर मिलकर अपने व्यापारिक प्रतिबन्धों को कम कर रहे हैं। उनका विचार यह है कि ये अपने क्षेत्र में तटकरों को काम करते हुये आर्थिक दृष्टि से एक देश या क्षेत्र बना दे। यद्यपि यह काम बहुत कठिन है तथापि वे देश अपने संघ के सदस्य देशों पर आयात कर शनैः शनैः कम कर रहे हैं।

पिछले दिनों थाईलैंड की बैंकाक की राजधानी में एशिया व सुदूरपूर्व की आर्थिक कमीशन की सोलहवीं बैठक हुई। यह कमीशन संयुक्तराष्ट्र संघ ने इन देशों की आर्थिक उन्नति के लिए स्थापित किया था। इसमें जहां कृषि, खनिज, उद्योग, व्यापार अर्थनीति आदि के सम्बन्ध में एशिया और सुदूरपूर्व के देशों की प्रगति का विवरण पेश किया गया, वहां अनेक प्रतिनिधियों ने यह विचार भी प्रकट किया कि विकसित और अविकसित देशों की अर्थ-व्यवस्था में अन्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिये एक कॉमन एशियन ब्लॉक की स्थापना की जाय इसमें फिलीपाइन्स, थाईलैंड, मलाया, वियतनाम और इण्डोनेशिया सम्मिलित हों। बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए फिलीपीन प्रतिनिधि ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल क्षेत्रीय भावना को बढ़ाना नहीं है। यूरोप और लैटिन अमेरिका में केवल परीक्षण के लिए ही ऐसे संघ स्थापित नहीं किए गये हैं। हमारा उद्देश्य तो यह है कि अन्य देश यदि हम पर आर्थिक आक्रमण करें अन्यथा अनुचित स्पर्धा करें तो हम मिल कर उसका प्रतिकार अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कर सकें।

उन्होंने अनेक सुझाव भी उपस्थित किये जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। इस नए क्षेत्रीय संघ के सदस्य देश परस्पर एक दूसरे को अधिक सुविधा देते हुये अन्तः क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करें।

२. एक उद्योग यदि एक देश में अधिक सफलतापूर्वक चल सकता है तो दूसरा देश उसकी होड़ न करे। हम परस्पर मिलकर उद्योग का वितरण कर लें और जब देश या विदेशों में माल की मांग बढ़ जाय तो अन्य सदस्यों को भी वह स्थापित करने की अनुमति दे दें।

३—कच्चा माल मंगाने के लिये हम एक संगठन बना लें, जिससे हम सदस्य देशों में आपस में कुछ स्पर्धा न हो।

४—सब मिलकर अपने जहाजी बेड़ों का विकास करें ताकि क्षेत्रीय देशों में परस्पर तथा विदेशों से व्यापार करने में विदेशी मुद्रा का व्यय न हो और सब सदस्य देशों को अधिकतम सुविधा मिले।

५—मूल्य निर्धारण करने तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध करने की दृष्टि से एक संगठन बनाया जाय। जिसके लिये सब सदस्य देश एक कोष एकत्र करने में सहायता करें।

६—सब सदस्य देश परस्पर विशेषज्ञों और प्रशिल्पिकों का सहयोग पा सकें, और इसके लिये कानून में भी कुछ परिवर्तन होना चाहिये ताकि विशेषज्ञ सुविधापूर्वक एक दूसरे देश में आ जा सकें।

७—सब सदस्य देश दक्ष व्यक्तियों के आपस में परिवर्तन पर भी एक समझौता करें।

८—सब सदस्य देश परस्पर भुगतान के लिये भी कोई अच्छी व्यवस्था करें, जिससे उनका व्यापार अच्छी प्रकार बढ़ सके।

यह कहना कठिन है कि उक्त संघ का निर्माण कब तक हो सकेगा अथवा हो सकेगा भी या नहीं। इसके मार्ग में बहुत बाधायें आयेंगी। अभी तो इन सब देशों को अपना विकास करने के लिये ही विकसित देशों से आर्थिक सम्बन्ध और भी अधिक घनिष्ठ करने होंगे, फिर एशिया के सब देश इस संघ में सम्मिलित होंगे या नहीं, इसमें भी सन्देह है।

लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों का ऐसा संगठन बन गया तो भारत के सामने एक आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। यूरोप के क्षेत्रीय संघों के निर्माण से भी भारत के निर्यात व्यापार को कुछ न कुछ धक्का अवश्य लगा है। भारत के उद्योग व्यापार मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने भी एक वक्तव्य में यह स्वीकार किया था। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ हमारा निर्यात व्यापार बहुत बढ़ रहा है। उस पर भी प्रस्तावित रशियन ब्लाक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गत वर्षों की उत्पादन-उपलब्धियाँ और मूल्य

विनोदचन्द्र सिन्हा

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का परिणाम है कि एक दशक का नवजात प्रजातंत्र राष्ट्र भारत आज जिस गति से विकास और उन्नति के पथ पर अग्रसर है, उससे शीघ्र ही विश्व के प्रमुख राष्ट्रों की समकक्षता में पहुँचने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। यदि हम विकास और उन्नति की पहली सीढ़ी उत्पादन की अपनी विगत वर्षों की उपलब्धियों पर विहंगम दृष्टिपात करें तो हमें उपर्युक्त कथन की विश्वसनीयता पर संदेह न रह जाए।

भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां १९५७-५८ में कृषि उत्पादन में काफी कमी हुई थी, वहां १९५८-५९ में बहुत वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि उत्पादन का सूचक अंक जो पहले ११४.६ था बढ़कर १३१.० हो गया। औद्योगिक उत्पादन भी १९५९ में १९५८ की अपेक्षा काफी तेजी से बढ़ा है। रहन-सहन के राष्ट्रीय सूचक अंक में ५ प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही मुद्रा उपलब्धि में १९५७ और १९५८ की अपेक्षा १९५९ में काफी वृद्धि हुई, यद्यपि सरकार ने १९५९ में बैंकों से उससे पहले के दो वर्षों की अपेक्षा बहुत ऋण लिया। सम्बद्ध स्थिति में हुए परिवर्तन की एक विशेषता यह भी रही कि जहां १९५७ एवं १९५८ में विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से बहुत बड़ी रकमें निकाली गयीं, वहां १९५९ में इस प्रकार की निकासियां बंद थीं। जान पड़ता है कि १९५८-५९ में अन्न की बढ़ी हुई फसल का कुछ अंश उत्पादकों ने अपने अन्न संग्रह को पूरा करने के लिये रख लिया, जिसमें पहले के वर्ष में उपज कम होने से कमी हो गयी थी।

शोधन संतुलन की १९५९-६० की स्थिति १९५८-५९ से अपेक्षाकृत अच्छी रही। दूसरी आयोजना के प्रारंभ से विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि से कुल ५४३ करोड़ रुपये की कमी हुई। चूंकि वर्तमान शेष से अधिक निकासी की गुंजाइश नहीं है, अतः आशा की जाती है कि निर्यात द्वारा अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करना और आयात नीति में कड़ाई जारी रखना काफी समय तक विदेशी मुद्रा नीति का आधार बना रहेगा। साधनों पर पड़ने वाला दबाव कृषि उत्पादन के गहरे उतार-चढ़ाव के कारण बढ़ गया है। यद्यपि १९५८-५९ का उस समय तक दर्ज किये गये उत्पादनों में सर्वाधिक था, तब भी वह १९५६-५७ के कृषि उत्पादन से लगभग ६ प्रतिशत ही अधिक रहा। वास्तविक राष्ट्रीय आय १९५७-५८ में १.५ प्रतिशत घटी, १९५८-५९ में ६.८ प्रतिशत बढ़ी और दूसरी आयोजना के तीन वर्षों में उसमें १०.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सरकारी क्षेत्र द्वारा उद्योगों में लगाई जाने वाली पूँजी क्रमशः बढ़ती रही है परन्तु साधारण रूप से गैरसरकारी क्षेत्रों द्वारा संगठित उद्योगों में लगाई गई रकम १९५८-५९ में कम रही और यदि १९५९-६० में इसमें कोई वृद्धि होगी भी तो विशेष नहीं। सरकारी क्षेत्रों के लिए जहां आयोजना के पहले दो वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग २१० करोड़ रुपये का पूँजीगत माल विदेशों से मँगाया गया वहां १९५८-५९ में केवल १४२ करोड़ का और १९५९-६० के पूर्वार्ध में ६५ करोड़ रुपये का है। मूल्यों तथा रहन-सहन के व्यय का निरंतर बढ़ते रहना यह प्रकट करता है कि हमारी अर्थ व्यवस्था कितनी कम अतिरिक्त मुद्रा से संचालित हो रही है।

उत्पादन में वृद्धि

अन्न और औद्योगिक वस्तुओं का, १९५८-५९ का उत्पादन उस समय तक के उत्पादनों में सबसे अधिक रहा। कृषि उत्पादन का सूचक अंक (१९४९-५०=१००) १९५६-५७ में १२३.६ था परन्तु देश के बड़े-बड़े क्षेत्रों में सूखा पड़ने से १९५७-५८ में घट कर ११४.६ रह गया था। जो फिर तेजी से बढ़ कर १९५८-५९ में १३१.० हो गया। कुल मिलाकर अन्न की उपज में १९५८-५९ में इससे पूर्व के वर्ष की अपेक्षा ११० लाख टन की वृद्धि हुई और अन्न की उपज का सूचक अंक १०८ से बढ़ कर १२८.२ हो गया। फिर भी यह बात ध्यान में रखने की है कि १९५७-५८ में अन्न की उपज बहुत ही कम हुई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

थी । १९५६-५७ की अपेक्षा, जो वर्ष अच्छा था, १९५८-५९ में अन्न की उपज में ४७ लाख टन (६ प्रतिशत) की वृद्धि हुई ।

अन्न की उपज (१० लाख टन में)

	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९
(१) चावल	२८.२	२४.९	२९.७
(२) गेहूँ	९.३	७.७	९.७
(३) अन्य अन्न (दालों के अतिरिक्त)	१९.७	२०.४	२१.९
(४) दालें	११.५	९.५	१२.२
	६८.८	६२.५	७३.५

अन्न से भिन्न खाद्य वस्तुओं का सूचक अंक जो १९५६-५७ में १३०.० था और १९५७-५८ में घटकर १२७.८ रह गया था, बढ़कर १९५८-५९ में १३६.६ तक पहुँच गया । कपास की उपज १९५८-५९ में इससे पहले के दो वर्षों की अपेक्षा कम थी परन्तु जूट, मूंगफली तथा तिलहनों की कुल उपज अपेक्षाकृत काफी अधिक रही । गुड़ के रूप में गन्ने की उपज जो १९५७-५८ में ०.२% कम हो गई थी, ४.२ प्रतिशत बढ़कर ७१६ लाख टन हो गई ।

पहले के दो वर्षों की अपेक्षा १९५९ में औद्योगिक उत्पादन की गति काफी तेज रही । १९५९ के पहले १० महीनों के उत्पादन का औसत सूचक अंक (१९५१=१००) १४९.४ रहा, जो १९५८ के सूचक अंक से ७.४ प्रतिशत अधिक था । १९५७ में सूचक अंक में ३.५ प्रतिशत और १९५८ में मात्र १.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी ।

गत वर्ष की विशेषता यह रही कि इसमें मध्यवर्त्ती वस्तुओं और पूँजीगत सामानों के उत्पादन में काफी विकास हुआ । लोहे और इस्पात का उत्पादन इस वर्ष ३५ प्रतिशत अधिक रहा । अलौह वस्तुओं के उत्पादन में लगभग २७ प्रतिशत की वृद्धि हुई और अल्यूमीनियम का उत्पादन ८,००० टन से बढ़कर १७०००, टन हो गया । बिजली का उत्पादन १९ प्रतिशत और सीमेंट का ९ प्रतिशत अधिक रहा । कोयला, कच्चा लोहा, लौह धातुओं, रासायनिक पदार्थ, रेयन का धागा, सूत, कागज और गत्ता, रबर की बनी वस्तुएं और कमायी हुई खालों के उत्पादन में भी इस वर्ष वृद्धि हुई । इनके अतिरिक्त जिन अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों के पूँजीगत सामानों के उत्पादन में वृद्धि हुई, उनमें डीजल इंजन, मशीनों के औजार और चीनी उद्योग में उपयोगी मशीनें प्रमुख हैं । गत वर्ष मोटर गाड़ियों की उत्पादन संख्या ३६.४०० थी जो १९५८ की अपेक्षा ३६ प्रतिशत अधिक रही । बिजली की मशीनों, साज–सामान के उपकरणों का उत्पादन भी विगत वर्षों से अधिक रहा, यद्यपि बिजली के ट्रांसफार्मर और मोटरों का उत्पादन कम है ।

उपभोग्य सामग्री

सामूहिक रूप से उपभोग्य सामग्रियां बनाने वाले उद्योगों के उत्पादन में लगभग ३ प्रतिशत वृद्धि के साथ ही मिलों ने लगभग उतने ही कपड़े का उत्पादन किया जितना १९५८ में हुआ था । गत वर्ष मिलों से अधिक मात्रा में जो कपड़ा उठाया गया उसका आंशिक कारण यह था कि विदेशों ने भारत में निर्मित वस्त्रों की फिर मांग की थी । हथकरघों और बिजली से चलने वाले करघों से गत वर्ष लगभग १० करोड़ गज कपड़ा अधिक तैयार किया गया । जिन अन्य उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है, उनमें वनस्पति (६८ प्रतिशत), कार्ड (२३ प्रतिशत), सिलाई की मशीनें (२० प्रतिशत) बिजली के पंखे (१६२ प्रतिशत), रेडियो रिसीवर (७.४ प्रतिशत) तथा साइकिलें (५.९ प्रतिशत) मुख्य हैं । नमक, चीनी और चाय के उत्पादन में भी कमी का अनुमान लगाया गया है ।

स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जो पूंजी लगायी गयी है, उसका परिणाम अब सम्मुख है । उद्योग न केवल अपनी पूर्ण क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं, बल्कि उनमें से लोहा और इस्पात, अल्यूमूनियम, कागज, आधारभूत रासायनिक पदार्थ, सीमेंट, सिलाई की मशीनें तथा साइकिल अधिक बनाने के कारखानों ने अपनी उत्पादन क्षमता काफी बढ़ा ली है । आगामी वर्षों में इस्पात का उत्पादन और बढ़ने का अनुमान है, जिससे निर्माण कार्यों और इन्जीनियरिंग उद्योगों में काफी प्रगति होने की सम्भावना है ।

जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, १९५८-५९ की राष्ट्रीय आय में (वास्तविक अर्थ में) ६८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । जबकि इससे पूर्व फसल अच्छी न हो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से यह १५ प्रतिशत घट गयी थी।

— १९४८-४९ के थोक मूल्यों के आधार पर —

	राष्ट्रीय आय (करोड़ रुपयों में)	प्रति व्यक्ति आय (रुपयों में)
१९५०-५१	८८५०	२४६.३
१९५१-५२	९१००	२५०.१
१९५२-५३	९४६०	२५९.६
१९५३-५४	१००३०	२६८.७
१९५४-५५	१०२८०	२७१.९
१९५५-५६	१०४८०	२७३.६
१९५६-५७	११०००	२८३.५
१९५७-५८	१०८३०	२७५.६
१९५८-५९	११५००	२९०.७

उपर्युक्त तालिका में १९४८-४९ के मूल्यों के आधार पर १९५०-५१ से १९५८-५९ तक की राष्ट्रीय आय (कुल आय और प्रति व्यक्ति आय) दिखलायी गयी है। १९५०-५१ से कुल राष्ट्रीय आय में लगभग ३१ प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति आय में लगभग १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चूंकि हाल ही के अनुभव से पता चला है कि पिछले वर्षों से जनसंख्या में अनुमान से कहीं बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, अतः इस अवधि की प्रतिव्यक्ति आय की वास्तविक वृद्धि उपर्युक्त तालिका में प्रयुक्त वृद्धि सूचक अंकों से अपेक्षाकृत कुछ कम होने की सम्भावनाएं अस्वीकार नहीं की जा सकती।

थोक मूल्यों में वृद्धि

उत्पादन में होने वाली निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप भी १९५९ के थोक मूल्यों में कुल मिलाकर वृद्धि ही दृष्टिगोचर हुई। निम्नलिखित तालिका में इस सम्बन्ध में १९५६ से लेकर अब तक की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है—

थोक मूल्यों का सूचक अङ्क

(१९५२—५३ = १००)

सप्ताहों का औसत

	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९
(१) खाद्य पदार्थ	९९.०	१०२.८	११२.०	११८.२
(क) अन्न	८९.७	९८.६	११२.७	१०३.४
(ख) अन्य	१०७.१	११४.०	१२०.१	१३१.०
(२) मदिरा एवं तम्बाकू	८२.३	९१.८	९३.७	१००.७
(३) ईंधन, बिजली, रोशनी, चिकनाई	१०१.६	१११.५	११५.२	१०६.०
(४) औद्योगिक कच्चा माल	११३.२	११८.१	११४.७	११९.७
(५) निर्मित वस्तुएं	१०४.९	१०८.०	१०८.२	१०९.७
(क) मध्यवर्ती उत्पादन	११०.०	१०८.५	१०९.४	१११.०
(ख) तैयार वस्तुएं	१०४.१	१०७.९	१०८.०	१०९.५
(६) समस्त वस्तुएं	१०२.६	१०८.७	१११.०	११५.५

मूल्यों के सूचक अंक के औसत स्तर में हुई वृद्धि १९५७ की अपेक्षा १९५९ में ४ प्रतिशत अधिक रही। जबकि १९५८ में २ प्रतिशत अधिक थी।

विगत वर्षों से थोक मूल्यों का सूचक अंक ११९ के आस-पास बना हुआ है। जनवरी १९५८ के अन्त में यह लगभग ११४ था। इस प्रकार इसके बाद के १२ महीनों में इसमें ४५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। चावल के १०४.३ अङ्क में लगभग १४ प्रतिशत वृद्धि हुई। परन्तु गेहूँ के अंक ९७.१ में २५ प्रतिशत की कमी हुई है। कुल मिलाकर अनाजों में ३ प्रतिशत की कमी रही, जबकि दालों में २४ प्रतिशत कमी हो गई थी। दूसरी ओर खाद्यपदार्थों के सूचक अंक में सम्मिलित की जाने वाली अन्य वस्तुएं खाद्य तेलों, चीनी तथा गुड़ और चाय में क्रमशः १२, ११ और २४ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

गत वर्ष की अपेक्षा जनवरी १९६० के अन्त में औद्योगिक कच्चे माल के सूचक अंक में लगभग १४ प्रतिशत और तैयार वस्तुओं के अंक में लगभग ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सब मिलाकर थोक मूल्यों के सूचक अंक में होने वाली वृद्धि अन्न से भिन्न खाद्यपदार्थों और औद्योगिक कच्चे माल के सम्बन्ध में वृद्धि की ही सूचक है।

१९५६ और १९५८ के मध्य मूल्यों के सामान्य सूचक अंक की घट-बढ़ ने मुख्य रूप से अन्नों के मूल्यों का ही अनुसरण किया है। इस अवधि में अनाजों (जिस का सामान्य सूचक अंक में २० प्रतिशत हाथ रहता है) का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सूचक अंक ६० से बढ़कर ११५ और तैयार वस्तुओं का अंक १०५ से १०८ हो गया। १९५९ में थोक मूल्यों में हुई वृद्धि में अन्न से भिन्न खाद्य पदार्थों का भाग लगभग २1३, औद्योगिक कच्चे माल का लगभग 1.६ और तैयार वस्तुओं का लगभग 1.10 रहा।

१९५१ के पश्चात् यह पहला अवसर था जबकि मूल्यों में होने वाली वृद्धि में अन्न की अपेक्षा औद्योगिक कच्चे माल और तैयार वस्तुओं का अधिक रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि कच्चे माल के उत्पादन में हुई वृद्धि इन वस्तुओं की मांग से कम रही। स्पष्ट है कि विकासशील अर्थ व्यवस्था में कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है, जितना अन्न अथवा अन्य खाद सामग्रियों का। ● ●

अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए

मान्य महोदय,

कालेज के वाचनालय में सम्पदा आती है, पर उससे मुझे विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि मेरे सहपाठी सम्पदा के आते ही उस पर इतना झपटते हैं कि पढ़ने को मिलती ही नहीं। दो चार दिनों में ही कुछ चालक विद्यार्थी उसके उपयोगी लेख फाड़ कर ले जाने लगते हैं और मास का अन्त आते-आते तो टाइटिल और विज्ञापन के पृष्ठ ही रह जाते हैं। इसीलिए आप मेरे नाम से नीचे लिखे पते पर 'सम्पदा' भेजना आरंभ कर दें।

आपका

विजय, ३ रा वर्ष

बिरला कॉलेज,
पिलानी (राजस्थान)

ऊपर अर्थशास्त्र के एक विद्यार्थी का पत्र है और यह लीजिए अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर की सम्मति—

'सम्पदा' के विशेषांक तो हमारे लिए गीता और बाइबिल के समान हैं।

प्रोफेसर ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम० कॉम०

विद्यार्थियों के अनुरोध पर निश्चय किया गया है कि 'सम्पदा' को उनके लिए और भी उपयोगी बनाया जाए। इसी अंक से अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए विशेष लेखमाला आरंभ की जा रही है। आगामी अंकों में भी नियमित रूप से विद्वान् अध्यापकों और प्रोफेसरों द्वारा विशेष रूप से छात्रों के उपयोग के लिए लिखे गए लेख प्रकाशित किए जाएंगे। आशा है इस आयोजन से छात्रों को लाभ पहुँचेगा। सामान्य पाठकों के लिए भी यह लेखमाला उपयोगी और रोचक सिद्ध होगी।

—सम्पादक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुद्रास्फीति तथा मुद्रासंकुचन

विनोद प्रकाश भटनागर, एम. काम.

मुद्रा स्फीति की परिचयात्मक परिभाषा के अनुसार यह वह परिस्थिति है, जिसमें मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तथा अन्य कीमतें बढ़ जाती हैं। परन्तु प्रत्येक महंगाई मुद्रा स्फीति की द्योतक नहीं होती। महंगाई उत्पादन मूल्य बढ़ने से भी आ सकती है। इसी प्रकार महंगाई की अनुपस्थिति में भी मुद्रा स्फीति हो सकती है, जिसे गुप्त मुद्रा स्फीति का नाम दिया गया है। इसके लिए अमेरिका का आर्थिक इतिहास हमें ठोस उदाहरण देता है। १९२२-२७ में अमेरिका में उत्पादन मूल्य काफी कम हो गया, परन्तु कीमतें पूर्ववत ही रहीं। श्री जे० एम० कीन्स ने इसे "लाभात्मक मुद्रा स्फीति" का नाम दिया।

मुद्रा स्फीति का कीमतों पर प्रभाव

साधारणतया मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के साथ-साथ उद्योगों में भी अधिक धन लगाया जाता है। तर्कानुसार पूर्ति उसकी मांग से अधिक होने पर मुद्रा की कीमत अर्थात् ब्याज कम हो जाता है, इसके परिणामस्वरूप अधिक लोग उधार लेकर उद्योगों में धन लगाते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है तथा साथ ही अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। इस प्रकार अगर मुद्रा की पूर्ति उत्पादन के साथ बढ़ती है तो कीमतों के बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहती। परन्तु मुद्रा स्फीति का आगमन पूर्ण व्यवसाय की परिस्थिति में हो तो महंगाई का आगमन भी अवश्यम्भावी हो जाता है।

युद्ध के दिनों में सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, जिन्हें नये कर लगाकर पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है। इस पर भी घाटे का बजट बनाकर अधिक नोट छापे जाते हैं जो सरकार खर्च करती है। सरकार का खर्च प्रजा की आय होती है। लोगों के पास आय बढ़ जाती है, परन्तु दूसरी तरफ वस्तुओं आदि की कमी हो जाती है, क्योंकि उत्पादक लोग अपने साधनों को नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से हटा कर सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर लगा देते हैं। ठीक यही अवस्था होती है विकास के दिनों में। उदाहरण के लिये भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को ही लिया जा सकता है। इन योजनाओं के दौरान में अधिक नोट छाप कर बांधों आदि पर खर्च किया जा रहा है। कर्मचारियों की आय बढ़ रही है, परन्तु दूसरी तरफ उपभोग्य पदार्थों का उत्पादन कम हो रहा है। बांध आदि बहुत देर बाद लाभ पहुँचाने वाले होते हैं।

मुद्रा स्फीति के भेद

नियन्त्रण के हिसाब से हम मुद्रा स्फीति को निम्न दो भागों में बांट सकते हैं।

अनियन्त्रित मुद्रा स्फीति—इस परिस्थिति में कोई नियन्त्रण नहीं लगाया जाता। मुद्रा की पूर्ति की अधिकता कीमतों पर प्रभाव डालती रहती है। कभी कभी यह सीमा को भी पार कर जाती है। इतिहास इसका साक्षी है। १९२३ में जर्मनी में कीमतें १० खरब गुनी हो गई थीं। १९४८ में चीन में एक टोकरी सब्जी की कीमत एक टोकरी नोट थी। ऐसी परिस्थिति में नोटों का परित्याग कर देना चाहिये तथा कीमतों एवं वस्तुओं की गतिविधि पर नियंत्रण भी लगाना चाहिये—यद्यपि यह सब पर्याप्त नहीं होता।

नियन्त्रित मुद्रा स्फीति—इस परिस्थिति में न केवल वस्तुओं तथा कीमतों की गतिविधि पर नियन्त्रण लगाया जाता है, वरन् लोगों की क्रय-शक्ति को भी नियन्त्रित किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति की अधिकता केवल बैंकों में पड़ी रहती है। लोग न उससे कुछ खरीद सकते हैं और न ही उसे आगे व्यवसाय में लगा सकते हैं। परन्तु कभी-कभी यह नियन्त्रण एकदम हटा लिये जाते हैं—जिससे काफी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिये अभीष्ट यही है कि राज्य अधिकारी काफी सोच विचार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के बाद ही नियन्त्रण हटाने का कदम उठायें।

मुद्रा-स्फीति के कारण

सरकार की आर्थिक स्थिति—देश छोटा हो या बड़ा, समय युद्ध का हो या शान्ति का, सरकार का व्यय देश में अधिकतम होता है। सरकार का व्यय जब आय से अधिक हो जाता है तो वह कई तरीके अपनाती है, जैसे नये कर लगाना, जनता से कर्ज लेना तथा अन्तिम स्थिति में मुद्रा की संख्या को बढ़ाना। यद्यपि वर्तमान समय में मुद्रा का बढ़ाना उतना आसान नहीं रहा है, जितना यह पहले होता था।

लोगों की धन व्यय करने सम्बन्धी आदतें तथा विचारधारा—मुद्रा की वृद्धि के अतिरिक्त लोगों की धन व्यय करने सम्बन्धी विचारधारा भी मुद्रा-स्फीति का एक मुख्य कारण है। अगर मुद्रा की वृद्धि को लोग व्यय न करें तथा बचत को व्यवसाय में पूंजी का रूप दें तो वस्तुओं के बढ़े हुए उत्पादन से मुद्रा स्फीति एक दूर की कहानी बन जायेगी। दूसरी तरफ अगर लोग व्यय न भी करें; परन्तु उसे केवल बचाकर रखें तो मुद्रा स्फीति की किसी समय आशंका की जा सकती है, क्योंकि आज की क्रय शक्ति की बचत का रूप देने के पश्चात् अगर उसे पूंजी का रूप न दिया जाये तो वह बचत कल फिर क्रय शक्ति का रूप धारण कर लेगी। मुद्रा स्फीति को टालने के लिये यह आवश्यक है कि यह दोनों कारण विभिन्न दिशाओं में चलें। कहीं अगर यह दोनों बढ़ोतरी की दिशा में चल पड़े (जैसा जर्मनी में १६२३ में हुआ) तो मुद्रा स्फीति का आगमन अवश्यम्भावी हो जायेगा।

मुद्रा स्फीति रोध

मुद्रा स्फीति को नियन्त्रण में लाने के लिये प्रयोग किये जाने वाले अनेक साधन परस्पर मिलकर मुद्रा स्फीति-रोध कहलाते हैं। परन्तु किस साधन का प्रयोग किया जाये और किसका नहीं, यह मुद्रा स्फीति की प्रकृति तथा कारणों पर निर्भर करता है। अगर मुद्रा-स्फीति सीमा को पार कर चुकी हो तो केवल वर्तमान आर्थिक ढांचे का परित्याग ही एक संभव उपाय बच रहता है। दूसरी तरफ अगर मुद्रा स्फीति अभी सीमित दशा में ही हो तो हम मुद्रा स्फीतिरोध के अन्तर्गत कई साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। मुद्रा स्फीति रोध का उद्देश्य मुख्यतः बढ़ती हुई कीमतों पर एक रोक लगाना होता है।

१. सर्व प्रथम मुद्रा की बढ़ती संख्या पर रोक लगानी चाहिये। २. सरकार की मुद्रा की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा नये करों तथा जनता से कर्ज का सहारा लेना चाहिये यद्यपि यह सब भी विरोधी सदस्यों को आलोचना की प्रेरणा देने के लिये पर्याप्त है। ३. सरकार की आर्थिक नीति का निर्धारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये होना चाहिये। अगर सरकार मुद्रा स्फीति को काबू में लाना चाहती है, तो उसे अपने खर्चों को ही काबू में लाना चाहिये। ४. सरकार का यह भरसक प्रयत्न होना चाहिये कि वह घाटे के नहीं लाभ के बजट बनाए। सरकार को बचत करनी चाहिए और अपने समस्त अनावश्यक खर्चों को समाप्त कर देना चाहिये। यह सब कदम १६२३ में ग्रीस में तथा युद्ध के बाद फ्रांस तथा अन्य पश्चिमी राष्ट्रों ने उठाये थे।

बैंक व मुद्रास्फीति

वर्तमान समय में बैंकों द्वारा उधार दिये जाने वाला पैसा भी मुद्रा की संख्या की वृद्धि में काफी सहायक होता है। इसकी वृद्धि को भी रोकने का पर्याप्त प्रयत्न करना चाहिये। इस सम्बन्ध में बैंकों की उधार देने की क्षमता को कम करना चाहिये जिसके लिये ब्याज की दरें बढ़ा देनी चाहिएं तथा अगर वह भी असफल रहे तो सरकार की स्वयं अथवा केन्द्रिय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को इस विषय पर परीक्षा रूप से निर्देशन करना चाहिये। इंग्लैंड तथा उससे आर्थिक तौर पर सम्बन्धित देश इस उपाय को काफी प्रयोग में लाते रहे हैं; क्योंकि इस उपाय की सफलता के लिये एक सुदृढ़ केन्द्रीय बैंक तथा सुनिश्चित व्यापारिक बैंक क्षेत्र का होना अत्यावश्यक है।

सरकार को केवल मुद्रा की संख्या पर रोक ही नहीं लगानी चाहिये वरन् लोगों की क्रय शक्ति पर भी रोक लगानी चाहिये। इसके लिये जरूरी बचत योजना जैसे उपाय प्रयोग में लाने चाहिएं। अगर वार्षिक बजट में किये गये उपाय अपर्याप्त रहें तो ब्रिटेन की तरह पूरक बजट बना कर करों को बढ़ाना चाहिये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुद्रा की संख्या में कमी देर से होगी। बढ़ी हुई मुद्रा की संख्या अर्थात् लोगों की क्रय शक्ति को भी हम हमेशा के लिये नहीं रोक सकते। इस समस्या का अन्तिम सुलझाव है केवल वस्तुओं के अधिक उत्पादन में। परन्तु अगर देश पहले ही पूर्ण विकसित व्यवसाय की स्थिति को पहुँच चुका है तो उत्पादन बढ़ाने की सम्भावना कम ही होगी। साथ ही अगर देश पूर्ण व्यवसाय की स्थिति को न पहुँचा हो, किन्तु आर्थिक तौर पर अविकसित हो या विकास के दौर से गुजर रहा हो तो उत्पादन बढ़ाने में कुछ समय लगेगा। ऐसी परिस्थिति में उत्पादन के बढ़ने तक यह आवश्यक है कि क्रयशक्ति को नियन्त्रण में रखा जाये। इसके अतिरिक्त अगर सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा हो तो आवश्यक वस्तुओं के आयात को भी वस्तुओं की वृद्धि के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे भारत अब भी खाद्यान्नों का आयात कर रहा है।

अन्त में राशन जैसी योजनाओं पर भी निर्भर किया जा सकता है। यद्यपि आमतौर पर यह जनता में केवल असन्तोष ही बढ़ाती है। भारत में हिन्दु शवों के दाह संस्कार के लिये १९४६-४९ में लकड़ी पर राशन तथा इंग्लैंड में द्वितीय युद्ध के समय अण्डों तथा रुमालों जैसी वस्तुओं पर राशन इसके अच्छे उदाहरण हैं। परन्तु इन राशन योजनाओं से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, वह मनोवैज्ञानिक विचारधारायें, जो इनके कारण लोगों के दिमाग में आती हैं।

अगर कीमतों तथा वस्तुओं के वितरण पर ठीक-ठीक नियन्त्रण हो तो लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तुयें उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित कीमतों पर मिलेंगी जिससे लोगों को अधिक दामों पर खरीदने का कोई उत्साह अथवा प्रेरणा नहीं मिलेगी। परन्तु यह सब जितना धीरे-धीरे किया जायेगा, उतना ही अच्छा रहेगा।

मुद्रा संकुचन

तर्कानुसार यह मुद्रास्फीति का बिल्कुल उल्टा रूप है। इस परिस्थिति में मुद्रा की संख्या इतनी कम हो जाती है कि लोगों की क्रयशक्ति जीवन की आवश्यकताओं के लिये भी पर्याप्त नहीं रहती। मुद्रा की संख्या में कमी आने से ब्याज की दरें बढ़ जाती हैं तथा परिणाम-स्वरूप व्यवसाय में कम धन लगाया जाता है जिससे मुद्रा की संख्या में और कमी आती है। साधारणतया यह परिस्थिति मुद्रास्फीति को सुधारते हुए मुद्रास्फीति रोध के अन्तर्गत कुछ नासमझी तथा जल्दबाजी में उठाये गये कदमों द्वारा ही आती है।

इस परिस्थिति में वस्तुओं की पूर्ति तो पहले से ही अधिक होती है तथा मांग क्रयशक्ति के कम हो जाने से कम होती है जिसके परिणामस्वरूप कीमतें कम हो जाती हैं। फिर प्रत्येक व्यापारी दूसरों से अधिक बेचने के लिये कीमतें और कम करता जाता है। इससे लाभ कम हो जाते हैं तथा कभी-कभी तो वह हानि का भी रूप ले लेते हैं,

सुभाषित रत्नमाला

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

७ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था। कई वर्ष से पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी! अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा में प्रकाशित हो रहा है—

- वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी सुविधापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं।
- श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ।
- पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियाँ, जिनके उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सकें।
- आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य।
- उपहार और पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयुक्त।

मूल्य एक प्रति १.०० रु०। 'सम्पदा' के ग्राहकों से ००.७५ न० पै० प्राप्त होने पर 'बुक पोस्ट अन्डर-पोस्टल सर्टिफिकेट' द्वारा भेजी जाएगी। स्कूलों-कालेजों और पुस्तकालयों को १० प्रतियाँ ७.०० रु० में।

प्रकाशक :
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जिससे पुनः उद्योग व्यवसाय तथा मुद्रा की संख्या में कमी आती है। इस परिस्थिति में निराशावाद का प्रादुर्भाव अवश्यम्भावी होता है। यह निराशावाद अपने साथ मन्दी का समय, वीरान दुकानें, बेरोजगार, तथा कईयों का दीवाला लाता है। इसमें केवल निश्चित रकम पाने वाले ही लाभ में रहते हैं। यह परिस्थिति मुद्रास्फीति से भी बुरी होती है। १९२९-३३ की संसार-व्यापी मन्दी इसकी साक्षी है। इसको सुधारने के लिये कुछ सुधार आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम मुद्रा-विस्तार के नाम से पुकार सकते हैं। परन्तु मुद्रा विस्तार के लिये यह आवश्यक है कि वह जितनी भी जल्दी हो सके लाया जाये, परन्तु यह आकस्मिक न होना चाहिये तथा यह ध्यान भी रखना चाहिये कि यह केवल सीमित मात्रा में ही लाया जाये ताकि कहीं बाद में यह मुद्रा स्फीति का रूप न ले ले।

मुद्रा विस्तार के रूप

१. ब्याज की दरें कम कर देनी चाहिये, जिससे अधिक लोग पैसा उधार लेकर व्यापार में लगायें। परन्तु यह केवल प्रारम्भ में ही किया जा सकता है, जबकि मुद्रा संकुचन का पता काफी देर बाद लगता है, इसके बाद भी हम केवल मुद्रा की संख्या बढ़ा सकते हैं। लोगों को उसे प्रयोग करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते।

२. सरकार को कर कम कर देने चाहिये। उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों का बोझ हल्का होना चाहिये। परन्तु यह ज्यादा लाभदायक नहीं सिद्ध होता, क्योंकि एक बेरोजगार के लिये करों में कमी का कोई महत्व नहीं होता, साथ ही साथ सरकार को कर इतने भी कम नहीं कर देने चाहिएं कि करों में कमी के फलस्वरूप उसके रवैये अर्थात् लोगों की आय पर प्रभाव पड़े। इस हालत में अच्छा यही रहता है कि जहां तक परिस्थितियां आज्ञा दें तथा जहां तक मुद्रा-स्फीति का खतरा न हो सरकार को घाटे के बजट बनाकर केन्द्रीय बैंक से अधिक नोट छपवाने चाहिएं। जहां तक घाटे को कर्जे से पूरा करने का प्रश्न है वह केवल केन्द्रीय बैंक अथवा विदेशों से ही लिया जाना चाहिये, क्योंकि देश से लिया गया कर्जा क्रयशक्ति को और कम करेगा।

३. मुद्रा की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ सरकार को कुछ कार्यों का प्रारम्भ करना चाहिये जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा तथा उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी। लोगों की वस्तुओं आदि की मांग बढ़ने से उद्योग तथा व्यवसाय भी बढ़ेंगे। सरकार की करों से आय बढ़ेगी तथा ५ या ६ वर्षों में ही सरकार के पास इतना पैसा फालतू हो जाना चाहिये कि वह कर्जे वापिस कर सके। इसे श्री जे० एस० कीन्स ने 'गुणक प्रभाव का नाम दिया था। परन्तु कीन्स से पूर्व भारत के राजा लोग इस सिद्धान्त को जानते ही नहीं थे वरन् अकाल आदि के दिनों में इसका प्रयोग भी करते थे।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति हो या मुद्रा-संकुचन उसका सुलझाव सरकार के पास ही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रथम अवस्था में मुद्रा की संख्या कम करना तथा दूसरी में मुद्रा की संख्या बढ़ाना होता है। परन्तु यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिये कि जो कोई भी सुधार किया जाये वह शीघ्र ही किया जाये तथा साथ ही वह आकस्मिक न हो।

उद्योग-व्यापार पत्रिका

देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं? देश में क्या-क्या चीज़ें और कितने परिमाण में कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई कर सकते हैं? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या दशा है? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रह है? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य जानने चाहिए, और इन सबकी जानकारी पाने का श्रेष्ठ साधन है—उद्योग व्यापार पत्रिका इसलिये आप ६ रु० भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक बन जाइये। नमूना पत्र लिखकर मंगाइये।

एजेन्टों को भरपूर कमीशन।

पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सहकारी खेती क्या रूप ले ?

कार्यकारी दल की रिपोर्ट

सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में यह विश्वास प्रकट किया है कि छोटे और मध्यम किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये सहकारी केती का तरीका बहुत अच्छा होगा।

कार्यकारी दल ने सहकारी खेती समिति की परिभाषा इस प्रकार की है—'यह किसानों का स्वेच्छा संगठन है, जिसका उद्देश्य जमीन, श्रम और खेती के साधनों का पैदावार बढ़ाने और लोगों को काम देने के लिये अच्छी तरह उपयोग करना है और जिसके अधिकांश सदस्य स्वयं खेती का काम करें।' सहकारी खेती बिलकुल स्वेच्छा से होनी चाहिये। कुछ राज्यों में ऐसे कानून हैं जिनके अनुसार बहुमत यदि चाहे सहकारी खेती संगठन में शामिल होने को बाध्य किया जा सकता है, यह अनुचित है। इन कानूनों को चाहे वे लागू होते हों या नहीं रद्द कर देना चाहिए। किसान को यह डर है कि सहकारी खेती से उसकी आमदनी कम हो जायगी। सरकारी कर्मचारियों का रुख भी बहुत सहायतापूर्ण नहीं रहा है और सहकारी खेती समितियोंको कानून और नियम की कठिनाइयों के कारण रुपया उधार मिलने में भी कठिनाई होती है।

नमूने

चुने हुए सामुदायिक विकास क्षेत्रों में जहां सहकारिता का काम अच्छा है, अगले चार साल में फी जिले में एक के हिसाब से ३२० नमूने की सहकारी खेती योजनाएं शुरू की जाएं। चालू साल में ४० योजनाएं शुरू की जाएं। प्रत्येक योजना में १० सहकारी खेती समितियां बनाई जाएं। इस प्रकार १९६३-६४ के अन्त तक ३२०० समितियां काम करने लगेंगी। इनके काम में जो सफलता मिलेगी, उससे आशा है कि अन्य क्षेत्रों में भी २०,००० और सहकारी खेती समितियाँ बन जायेंगी।

निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कदम भी शीघ्र ही उठाये जाने चाहिएं। १—सहकारी खेती समिति के सदस्य ही इस काम में अगुवा हों। २—समिति के सदस्यों के हितों या स्वार्थों में संघर्ष न हो। ३—सदस्यों की संख्या या समिति का आकार इतना ही होना चाहिये कि लोग एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते हों। ४—प्रत्येक सदस्य को प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार हो।

स्वामित्व का प्रश्न

सहकारी खेती में जो जमीनें शामिल हों वे साधारणतः ५ वर्ष के लिए होनी चाहियें। जमीनों पर सदस्यों का अधिकार अक्षुण्ण रहना चाहिये और अलग होने वाले सदस्य को यदि वही जमीन न दी जा सके तो उतनी ही पैदावार की जमीन वापस मिलनी चाहिये।

जो खेती करें, वही सदस्य

समिति में ऐसे सदस्यों को शामिल नहीं करना चाहिये जो खुद खेती का काम न कर सकें। इनकी जमीन को सहकारी खेती में शामिल करने के बजाय पट्टे पर ले लेना चाहिये। सदस्यों को अपने एवज में काम करने के लिये दूसरे आदमी देने की भी इजाजत न देनी चाहिये। सहकारी खेती समितियों को ऐसे घरेलू और ग्रामीण धंधे भी चलाने चाहियें, जिनमें सदस्यों को काम मिल सके और उनकी श्रम शक्ति का पूरा उपभोग हो सके।

सहकारी खेती की सफलता इस बात से आंकी जानी चाहिये कि उसके सदस्यों की सम्मिलित या कुल आय कितनी हुई, न कि दैनिक मजदूरी से। योग्य और मेहनती कार्यकर्ताओं को ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिये। सहकारी खेती में जो मुनाफा हो उसमें से खेती के विकास, सुरक्षित कोष, भोजन कोष आदि के लिए यथोचित धन रखकर बाकी रकम सदस्यों को उनके काम के अनुसार बोनस के तौर पर दे देनी चाहिए। बोनस जमीन के हिसाब से भी दिया जा सकता है। ऐसी मशीनों से काम लेना चाहिए, जिनसे बेकारी न बढ़ती हो, जैसे सिंचाई के लिए पम्प आदि।

सहकारी खेती की सफलता के लिए किसानों, सहका-

[शेष पृष्ठ २१८ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कम्युनिज्म : मानव जाति का भविष्य

श्री एल० लियोनलिएन

लोग अकसर पूछते हैं : "कम्युनिस्ट समाज कैसा होगा ?" लेनिन ने कहा था, "कम्युनिस्ट लेटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है—सम्मिलित। कम्युनिस्ट समाज का यह अर्थ है कि भूमि, कारखाने सब कुछ सम्मिलित हैं। कम्युनिज़्म का अभिप्राय है सम्मिलित काम-काज।"

समाजवादी क्रान्ति से पूर्व मार्क्स, ऐंगेल्स और लेनिन ने कम्युनिस्ट समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने के सभी प्रयासों को अस्वीकृत कर दिया था। मार्क्सवाद की प्रकृति बिल्कुल वैज्ञानिक होने के कारण वह वास्तविक तथ्यों से निष्कर्ष निकालता है। पूंजीवादी वास्तविकता में एक भी ऐसा तथ्य न था, जिससे कम्युनिस्ट समाज का विस्तृत ठोस चित्र प्रस्तुत करना सम्भव होता। सभी प्रकार के निर्माण का अर्थ है पहले से विद्यमान तत्वों से किसी नई वस्तु को तैयार करना। कम्युनिज्म के निर्माण पर भी यही बात लागू होती है। कम्युनिज्म के अलग-अलग तत्व, स्वरूप और पहलू पहले से ही मौजूद हैं, जो दिनानुदिन विकसित और शक्तिशाली हो रहे हैं। भविष्य में उनका विकास जीवन के उत्तरोत्तर नये क्षेत्रों में और भी तेजी से व्यापक रूप में होगा।

सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद

कम्युनिज्म पद्धति प्रकृति की शक्तियों पर काबू पाने के लिए समाज के समक्ष बिल्कुल असीम सम्भावनाओं का द्वार खोलती है। मानव जाति के समस्त इतिहास में एक सामाजिक पद्धति से दूसरी सामाजिक पद्धति में परिवर्तन का अर्थ प्रकृति की शक्तियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के निम्नतर स्तर से नवीनतर और उच्चतर स्तर में संक्रमण है। उदाहरण के लिए इस सम्बन्ध में पूंजीवाद ने ऐसे अवसर उन्मुक्त किये, जो पूर्ववर्ती सामन्ती व्यवस्था में बिल्कुल ही मौजूद नहीं थे। लेकिन पूंजीवाद के अन्तर्गत प्रकृति के ऊपर मानव-सत्ता के विकास की सीमाएं हैं। ये सीमाएं उत्पादन के साधन के निजी स्वामित्व द्वारा निर्धारित हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के विकास का निर्धारण जनता की आवश्यकताओं द्वारा नहीं, वरन् मुनाफाखोरी द्वारा होता है।

समाजवाद के अन्तर्गत उत्पादन का लक्ष्य मुनाफाखोरी नहीं, वरन् समूचे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति है। इसलिए समाजवाद ने उत्पादक शक्तियों के विकास के लिए ऐसे व्यापक अवसर उन्मुक्त किये, जो किसी भी पूर्ववर्ती सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान नहीं आये थे।

कम्युनिज्म की उच्चतम मंजिल में प्रकृति के ऊपर मानव-सत्ता का और तेजी से विकास होगा, समस्त पैदावारों का प्रचुर उत्पादन सुनिश्चित हो जायगा तथा मानव की भौतिक एवं आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ण सन्तुष्टि के लिए समस्त अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो जाएगा।

समाजवादी पद्धति के अन्तर्गत समाज के समस्त सक्षम सदस्य अपने काम के परिणाम और गुण के अनुसार समाज से वेतन प्राप्त करते हैं। फिर भी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कुछ अधिक बलशाली हैं, कुछ कमजोर हैं। कुछ विवाहित हैं और कुछ अविवाहित। कुछ के अधिक बच्चे हैं और कुछ के कम। इसलिए सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन वाला समाजवादी सिद्धांत अभी तक पूर्ण समानता को सुनिश्चित नहीं बनाता। कम्युनिज्म की उच्चतम मंजिल में पूर्ण न्याय की उपलब्धि होती है और निम्नलिखित सिद्धान्त लागू होता है : 'हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वेतन पाएगा।' यही कम्युनिज्म का उज्ज्वल आदर्श है।

कम्युनिज्म : समाजवाद का विकसित क्रम

कम्युनिज्म अपनी निचली मंजिल समाजवाद का स्वाभाविक एवं सतत विकास-क्रम है। इसके साथ ही इसकी कई अपनी विशिष्टताएं हैं। सर्वप्रथम वह एक ऐसा समाज होगा जिसने प्रकृति के ऊपर अपारसत्ता स्थापित कर ली है, कम्युनिस्ट समाज की उत्पादक शक्तियाँ इतिहास में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अभूतपूर्व ढंग से शक्तिशाली होंगी। प्रकृति के ऊपर मानव-सत्ता का जिस दिशा में विकास होगा, उसकी मुख्य प्रवृत्तियां स्पष्ट हो चुकी हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग की वर्तमान प्रगति के द्वारा हम इस विषय में अनुमान लगा सकते हैं। समाजवादी समाज में वैज्ञानिक सृजनात्मक कार्य का विकास एक ऐसा तथ्य है, जिसे नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता।

पारमाणविक शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग इस सम्बन्ध में महान् अवसरों को उन्मुक्त करता है। ताप-पारमाणविक शक्ति के उपयोग की और भी वृहत् सम्भावनाएं भविष्य में हैं। इस समय तक समस्या के समाधान की ठीक-ठीक तिथियों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि आज या कल इसका समाधान हो ही जाएगा। तब मानव समाज ऐसे कार्य करने में प्रवृत्त होगा जो मानव बुद्धि के लिए कल्पनातीत हैं: मरुभूमि का पुष्पित उद्यानों में रूपान्तरण, पृथ्वी की जलवायुमें परिवर्तन आदि।

न केवल उत्पादन के शक्ति-आधार में परिवर्तन होगा वरन् राष्ट्रीय अर्थतन्त्रके सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के उत्पादन सम्बन्धी क्रियालापों के स्वरूप में भी आमूल परिवर्तन होंगे। सर्वप्रथम प्रविधि की प्रगति, उत्पादन का यंत्रीकरण एवं स्वचालन मानव को सभी प्रकार के सश्रम कार्य से मुक्त कर देगा। कालान्तर में मानव का श्रम हजारों गुणा अधिक उत्पादनशील हो जायगा।

श्रम की अनेक उत्पादनशीलता अवस्थाओं में स्वयंचालन जारी करने से फौरन ही पाँच से दस गुनी वृद्धि हो जाती है। अब तक इस प्रकार के नतीजे उत्पादन के कुछ ही खण्डों में हासिल किये जा रहे हैं लेकिन भविष्य में उत्पादन की समस्त प्रक्रियाओं में बिना किसी अपवाद के स्वयंचालन जारी हो जाएगा।

उत्पादन और स्वयंचालन का शक्ति-आधार परिमाणात्मक और गुणात्मक दृष्टि से जैसे-जैसे विकसित होगा वैसे-वैसे उत्पादन के परिमाण में अभूतपूर्व पैमाने पर तेजी से वृद्धि होगी। इस प्रकार सार्वजनिक सम्पत्ति का बिलकुल विकास होगा, जो 'हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा। और काम के अनुसार वेतन पाएगा' के समाजवादी सिद्धान्त 'हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसारवेतन पाएगा।' कम्युनिस्ट सिद्धान्त में रूपान्तरण के लिए अपेक्षित है। कम्युनिस्ट समाज आरम्भ से ही लोगों के भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं तथा समस्त सांस्कृतिक आवश्यकताओं की हर तरह से पूर्ति करने में सक्षम होगा। जब समाज प्रचुर परिमाण में उपभोक्ता माल का उत्पादन करने लगेगा और पर्याप्त संख्या में आरामदेह आवासों का निर्माण कर लेगा तब खाने, पहनने और रहने की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा।

श्रम के उत्पादन में महती वृद्धि के फलस्वरूप काम के घण्टों में पर्याप्त कमी करना सम्भव हो गया है। मौजूदा सप्तवर्षीय योजना काल में तो सोवियत संघ में दुनियां में सबसे छोटा कार्य-दिवस और कार्य सप्ताह हो जाएगा। फलतः कार्यकाल में और भी अधिक कमी कर दी जाएगी। कार्य में सुगमता आने और उसके सृजनात्मक स्वरूप में विकसित होने के फलस्वरूप सभी लोगों ने अपनी योग्यतानुसार काम करने की अनुप्रेरणा विकसित होगी। धीरे-धीरे लोग योग्यता के अनुसार काम करने के उसी तरह अभ्यस्त हो जाएंगे जिस तरह भोजन, विश्राम, मनोविनोद आदि के लिए अभ्यस्त हैं। इसके बाद सार्वजनिक रूप में कार्यकाल निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हर व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करेगा। ● ●

राज्यों में 'सम्पदा' स्वीकृत

सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा-विभागों ने अपने-अपने राज्य के स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक वाचनालयों के लिए स्वीकृत किया है—

(१) उत्तरप्रदेश, (२) बिहार, (३) पंजाब, (४) मध्यप्रदेश, (५) राजस्थान, (६) काश्मीर, (७) दिल्ली।

शायद आपकी शिक्षण-संस्था में भी 'सम्पदा' आती है। यदि नहीं, तो अर्थशास्त्र की इस प्रमुख पत्रिका को शीघ्र मंगाना आरम्भ करें!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

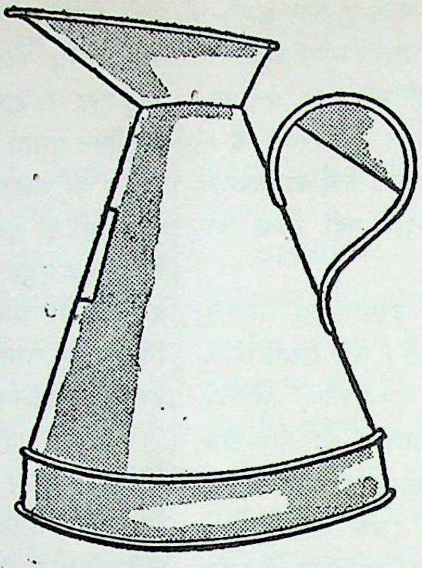

और अब तरल पदार्थ मापने के मेट्रिक पैमाने

तरल पदार्थ मापने के मेट्रिक पैमाने--लिटर--का प्रयोग अप्रैल, १९६० से शुरू हो गया है।
रंग-रोगन और पेट्रोल उद्योग ने मेट्रिक प्रणाली अपना ली है।
अब रंग-रोगन लिटरों के हिसाब से बिका करेगा और पेट्रोल का वितरण भी लिटरों के हिसाब से होगा।

परिवर्तन तालिका

१ गैलन = लगभग ४½ लिटर

१ लिटर = १,००० मिलिलिटर

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तरल औंस	मिलिलिटर (मिलि०) (निकटतम मिलि० तक)
१	२८
२	५७
३	८५
४	११४
५ (=१ गिल)	१४२

गिल	मिलिलिटर (मिलि०) (निकटतम मिलिलिटर तक)
१	१४२
२	२८४
३	४२६
४ (=१ पिण्ट)	५६८

पिण्ट	लिटर (लि)	मिलिलिटर (निकटतम मिलि० तक)
१	...	५६८
२(=१ क्वार्ट)	१	१३६

क्वार्ट	लिटर	मिलिलिटर (निकटतम मिलि० तक)
१	१	१३६
२	२	२७३
३	३	४०९
४ (=१ गैलन)	४	५४६

मिलिलिटर	तरल औंस निकटतम १/४ (तरल औंस तक)
१०	१/४
२०	३/४
३०	१
४०	१ १/२
५०	१ ३/४
६०	२
७०	२ १/२
८०	२ ३/४
९०	३ १/४
१००	३ १/२

मिलिलिटर	पिण्ट	गिल	तरल औंस (निकटतम १/२ तरल औंस तक)
२००	–	१	२
३००	–	२	१/२
४००	–	२	४
५००	–	३	२ १/२
६००	–	४	१
७००	१	०	४ १/२
८००	१	१	३
९००	१	२	१ १/२
१०००(=१ लिटर)	१	३	–

गैलन	लिटर	मिलिलिटर (निकटतम १० मिलि० तक)
१	४	५५०
२	९	९०
३	१३	६४०
४	१८	१८०
५	२२	७३०
६	२७	२८०
७	३१	८२०
८	३६	३७०
९	४०	९१०
१०	४५	४६०

गैलन	लिटर	मिलिलिटर (निकटतम १०० मिलि० तक)
२०	९०	९००
३०	१३६	४००
४०	१८१	८००
५०	२२७	३००
६०	२७२	८००
७०	३१८	२००
८०	३६३	७००
९०	४०९	१००
१००	४५४	६००

लिटर	गैलन	क्वार्ट	पिण्ट	गिल (निकटतम गिल तक)
१	–	–	१	३
२	–	१	१	२
३	–	२	१	१
४	–	३	१	–
५	१	–	–	३
६	१	१	–	२
७	१	२	–	१
८	१	३	–	–
९	१	३	१	३

लिटर	गैलन	क्वार्ट	पिण्ट (निकटतम पिण्ट तक)
१०	२	१	–
२०	४	१	१
३०	६	२	१
४०	८	३	–
५०	११	–	–
६०	१३	१	–
७०	१५	१	१
८०	१७	२	१
९०	१९	३	–
१००	२२	–	–

अपनाइये मेट्रिक प्रणाली

सरलता व एकरूपता के लिए

भारत सरकार द्वारा प्रसारित DA-59/577

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास

प्रो० कैरोट ए. जोसेफ

ब्रिटेन की दृष्टि

राजनैतिक क्षेत्र में उदारवाद (लिबरलिज़्म) ने राज्य को एक ऐसे 'पहलहीन पुलिसमैन' की स्थिति को आदर्श माना था, जो नागरिकों के अपने व्यक्तिगत मामलों से संबंध न रखती हो और केवल शांति व्यवस्था, निजी सम्पत्ति का संरक्षण और कुछ सार्वजनिक कार्य से ही सम्बन्धित हो। इसी प्रकार उदारवाद ने उस सरकार को आदर्श माना था जो सांविधानिक प्रतिनिधित्व और संसदीय हो, जिस में जायदाद वाले मध्यम और शिक्षित व्यवसायी वर्गों के लोगों की संख्या काफी हो और जिसके अंतर्गत जनता को काफी वैयक्तिक स्वाधीनता प्राप्त हो और करों का भार कम और सहनीय हो।

इस उदारवाद के विकास के लिए ग्रेटब्रिटेन एक अत्यन्त अनुकूल देश प्रमाणित हुआ, क्योंकि यहाँ की जनता स्वतंत्र व्यापार और स्वतंत्र राजनैतिक पद्धति में दृढ़ विश्वास करती है। वाटरलू (१८१५) के युद्ध के बाद की शताब्दि में जो अविच्छिन्न शांति और समृद्धि स्थापित हुई, उसका श्रेय उसी उदारवादी विचारधारा को है। पुनरुत्थान (रिनेसां) और सुधार (रिफोरमेशन) के साथ बौद्धिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तांत्रिक प्रगति, संसदीय सार्वभौमिकता, और बड़े-बड़े शहरों का जन्म, गंभीर वर्ग संघर्षों का अभाव, भूपति, श्रीमंतशाही, बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग और साहसी व्यावसायिक समुदाय का सहयोग—और सबसे उल्लेखनीय वस्तु अंग्रेजों का व्यावहारिक यथार्थवाद, राजनीति में ईमानदारी और सहनशीलता तथा जीवन के वैज्ञानिक, प्रगतिशील तथा आशाजनक दृष्टिकोण आदि ने ग्रेटब्रिटेन में उदारवाद को विकसित होने में सहयोग दिया।

समाजवादी आंदोलन

फिर भी इस उदारवादी युग के सभी परिणाम सुखद नहीं थे। अनेक दिशाओं में जहां उल्लेखनीय प्रगति हुई वहां कुछ क्षेत्रों में सामाजिक अन्याय भी हुआ। उदाहरण तौर पर कार्य करने में अधिक घण्टे और काम की भयंकर अवस्थाएं, गन्दी बस्तियां, महान असमानताएं, कुछ अविवेकशील व्यक्तियों द्वारा सामाजिक मूल्य के नाम पर व्यक्तिगत शोषण आदि उस युग के कुछ अवांछनीय पहलुओं का जन्म औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इन बुरे परिणामों के प्रति एक नैतिक प्रतिवाद के रूप में समाजवादी आंदोलन का जन्म हुआ। इस विचारधारा ने उत्पादन, विनिमय और वितरण के सभी साधनों पर इस आशा और विश्वास के साथ राज्य का स्वामित्व स्थापित करने का समर्थन किया कि उससे होने वाले दुष्परिणामों को समाप्त कर दिया जायगा और औद्योगिक प्रगति के परिणामों का समुचित वितरण हो सकेगा। ग्रेटब्रिटेन में फेबियन समाजवाद और मजदूर दल का विकास इसी प्रकार के नैतिक प्रतिवाद के उदाहरण हैं।

आशाएँ झूठी सिद्ध हुईं

लेकिन मजदूर दल द्वारा सत्ता प्राप्त करने तथा राष्ट्रीयकरण के जरिये राजकीय स्वामित्व की नीति कार्यान्वित करने पर भी उनकी पूर्वापेक्षित आशाएं झूठी पड़ गईं। यह देखा गया कि राष्ट्रीयकरण से समाजवाद कायम नहीं हुआ, राजकीय उद्योगों को चलाने वाले नौकरशाली वर्ग पर निजी उद्योग की तुलना में नियन्त्रण रखना कठिन हो गया, असमानताएं यथावत् जारी रहीं, और केवल सैद्धांतिक स्वामित्व कामगारों के लिए प्रोत्साहन का पूरक नहीं बन सका। इसके साथ-साथ वैयक्तिक स्वतंत्रता भी, जिसे समाजवादी इतना महत्व देते थे, नौकरशाही विस्तार में शीघ्रता से विलय होने लगी। बाद में यह मालूम पड़ने लगा कि राजकीय स्वामित्व से साम्यवादी देशों की तरह राजकीय पूंजीवाद की स्थिति पैदा होने लगी है, जहाँ पर, जैसाकि युगोस्लेविया के एक प्रमुख साम्यवादी मि. मिलोवान डिजिलास ने बताया है नौकरशाही एक 'नया वर्ग' और दल के प्रमुख व्यक्ति सभी नागरिकों के जीवन और भाग्य के अत्यन्त क्रूर नियंत्रक बन जाते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्रीयकरण पर विवाद

ग्रेटब्रिटेन में हाल ही के चुनाव के फलस्वरूप अब समाजवादियों के बीच राष्ट्रीयकरण तथा राजकीय स्वामित्व के प्रश्नों पर फिर से विचार किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैण्ड की भूतपूर्व श्रम दल की सरकार के वित्त-सचिव मि. डगलस जे का कहना है कि 'राष्ट्रीयकरण' शब्द ही अब श्रमदल के लिए हानिकारक हो गया है। वास्तव में यह तथ्य है; और इससे इनकार करने से कोई लाभ नहीं है हालांकि आप उसकी निन्दा भले ही करें। इसलिए अब हम लोगों को सम्पूर्ण रूप से इस धारणा को नष्ट कर देना चाहिए: अन्यथा हम लोग कभी भी विजयी नहीं हो सकेंगे।

इस प्रकार से सामाजिक न्याय के सम्वर्द्धन में समाजवाद और साम्यवाद दोनों असफल हुए। लेकिन पश्चिमी जर्मनी ने यह बात प्रमाणित कर दी है कि किस प्रकार निजी उद्योग का राज्य द्वारा उचित नियमन करने के फलस्वरूप १९वीं शताब्दि के औद्योगिक समाज की बुराइयों को हटाकर सभी के लिए स्वाधीनता तथा समृद्धि की गारंटी दी जा सकती है।

लेकिन भविष्य में क्या होगा? विख्यात विचारकों तथा मेधावियों का विचार है कि स्वतंत्र विश्व की सभ्यता का भविष्य, स्वतंत्र लोकतंत्र में स्वतंत्र उद्योग के पुनरुत्थान पर निर्भर है, उदार आदर्शों में विश्वास की स्थापना करना जरूरी है, जिसके कारण ही प्रमुख रूप से आधुनिक औद्योगिक समुदाय की आश्चर्यजनक सफलताएं संभव हो सकी हैं। एक आदर्श के रूप में उदार व्यक्तिवाद का भविष्य अब भी उज्ज्वल है। इससे आत्मनिर्भरता को बल और पहल को प्रोत्साहन मिलता है तथा वह अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप का प्रतिकार करता है। इस व्यवस्था में समाज के व्यक्ति के महत्त्व को मान्यता दी जाती है उसमें व्यक्तिगत स्वाधीनता में जगह-जगह पर हस्तक्षेप करनेवाले बेकार कानूनों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। यदि हमको केवल समाजवाद के अन्तर्गत होने वाली घटनाओं का तथा अन्यत्र और यहाँ तक कि उदारवाद के गढ़, ग्रेट ब्रिटेन में होने वाले दमन का आभास मात्र भी मिल जाय तो व्यक्ति विशेष की स्वतन्त्र उद्योग तथा वैयक्तिक पहल को निरुत्साहित करने की राजनीतिक संभावनाएं आसानी से ज्ञात हो जायेंगी। एच. डब्ल्यू. सीमेन द्वारा ब्रिटेन की समाजवादी रूपरेखा का चित्रण अत्यन्त रहस्योद्घाटक है। उनका कहना है कि दिन ब दिन जैसे कारागार की दीवारें निकट होती जाती है, विस्तार सँकरा होता जाता है। दिन ब दिन अफसरों की मर्यादा कम होती जाती है। जेलरों की बढ़ती हुई संख्या के व्यय के लिए कैदियों पर दण्ड दिया जाता है। एक भावनाहीन प्रचार के सिवा अब साहस के लिए और कोई प्रोत्साहन नहीं रह गया है। समाजवाद का स्वरूप अब पुरस्कारहीन प्रतियोगिता, निराशाजनक व्यापार, विजयहीन युद्ध; अनन्त आंकड़े और राहतहीन रूक्षता के रूप में रह गया है। समाजवादका अर्थ है राज्य के हाथ में अधिक अधिकार और वे अधिकार चाहे एक मन्त्री के और चाहे एक पुलिसमैन के हाथ में हों, वास्तव में शक्तिशाली जुलम हैं।

अतः यदि स्वतन्त्र भारत एक स्वाधीन और प्रगतिशील लोकतांत्रिक पद्धति एक कार्यक्षम आर्थिक व्यवस्था और एक गतिशील और व्यवस्थित समाज की रचना करना चाहता है तो उसे "यह मार्ग त्यागना होगा। इसका अर्थ है उदारवाद को पुनरुज्जीवित करना और वैयक्तिक पहल तथा उद्योग में अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाना। भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की रूपरेखा मूल रूप से व्यक्तिवादी वैयक्तिक पहल, प्रतियोगितात्मक कार्यक्षमता और वैचारिक स्वाधीनता एक विकासशील लोकतांत्रिक समाज के आधार हैं।

हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने अपने एक भाषण में कहा है। 'मै स्वयं विज्ञान का भक्त हूँ और मेरा विश्वास है कि यदि विश्व को बचना ही है तो उसे विज्ञान के उन तरीकों से ही बचाया जा सकता है जो वैयक्तिक विचार और पहल को मूल्यवान समझते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की सफलता जो किसी व्यापक भय पर आधारित हो, कदाचित ही वांछनीय हो सकती है और जिस समाज की व्यवस्था का आधार राज्य की आतंकवादी नीति हो और उसके बिना उस व्यवस्था का अस्तित्व न टिक सके, उस व्यवस्था को तो नागरिक प्रशासन के स्थान पर एक फौजी शासन ही कहा जायगा।"

• •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

आगे बढ़ते हुए देश और श्रमिक

श्री जार्ज सी० लाज

●

आर्थिक उन्नति और राजनीतिक स्वाधीनता के लिए विश्व का विशाल जन-समुदाय जो संघर्ष कर रहा है, वह मानव इतिहास में सम्भवतः सबसे अधिक फलदायक प्रयत्न सिद्ध होगा। इस संघर्ष का एक पहलू ऐसा भी है, जिसे अभी व्यापक रूप से मान्यता नहीं दी गई है; और वह है: इसमें श्रम-संगठनों का महत्वपूर्ण योग। समस्त एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका में लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवस्थाएं सुधारने के लिए श्रमिक यूनियनों का अधिकाधिक मुंह ताक रहे हैं।

इन यूनियनों का जन्म किसी ऐसी औद्योगिक क्रांति में नहीं हुआ है जो फैक्ट्री मजदूरों के एक विशाल समुदाय की अच्छे वेतन और काम की अच्छी हालतों आदि से संबंधित तात्कालिक और विशिष्ट आवश्यकताओं के फलस्वरूप हुई है। उनका विकास ग्रामीण सहकारी संस्थाओं, समाज-कल्याण संगठनों, राजनीतिक दलों, भाईचारे के समुदायों और कुछ मामलों में, प्रारम्भिक औद्योगिक यूनियनों के रूप में हुआ है, जिनका बाद में खानों, तेल-क्षेत्रों, रेलों और कपड़ा-कारखानों में विस्तार हो गया।

लेकिन इन यूनियनों की स्थापना मजदूरों की पहल से नहीं हुई और जिस आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरण में उनका जन्म हुआ, उसमें ऐसा हो भी नहीं सकता था। इनका उद्भव एक सामूहिक आन्दोलन से नहीं हुआ। बल्कि राजनीतिक दलों, सरकार, सुधारकों तथा सब प्रकार के व्यक्तियों ने एक ग्रहणशील ग्रामीण समाज के लिए उनका निर्माण किया। बहुत से यूनियन आन्दोलनों का उद्भव विशेषकर एशिया तथा अफ्रीका में, राष्ट्रवाद की तरंग पर हुआ और उन्होंने राजनीतिक स्वाधीनता के लिए उपनिवेशवाद-विरोधी आन्दोलनों का नेतृत्व किया। कुछ यूनियनें मानवीय तथा विचारधारा-सम्बन्धी कारणों से बनीं तथा कुछ इस विश्वास के कारण बनाई गईं कि यूनियनें आधुनिक औद्योगिक युग की महत्वपूर्ण निशानी और औद्योगिक राष्ट्रों के बीच बराबरी का दर्जा दिलाने की आवश्यक शर्त हैं। यह अनायास ही देखा जा सकता है कि किस प्रकार ये यूनियनें जिनकी अपने सदस्यों की इच्छा शक्ति में कोई मजबूत जड़ें नहीं थीं, चतुर नेताओं के हाथों में एक शक्तिशाली राजनीतिक साधन बन सकीं, विशेषकर तब, जबकि राष्ट्रवाद के प्रसार और औद्योगीकरण के आगमन से आर्थिक अस्तव्यस्तताओं तथा सामाजिक उथल-पुथल में वृद्धि हुई। भारत और मलाया में इन यूनियनों का एक व्यापक आधार है और उनमें प्रतिनिधियों के नेतृत्व का विकास हुआ है। वे 'बाह्य' हितों के आधारविहीन साधन से बहुत दूर हैं।

एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के बहुत से देशों में लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव मजदूर संगठनों का है। अरब संसार में सत्ता हथियाने के अपने प्रयत्न में श्री नासर ने श्रमिकों के राजनीतिक महत्व को तुरन्त ही हृदयंगम कर लिया। जब विभिन्न अरब देशों के मौजूदा मजदूर नेताओं ने उनसे सहयोग करने में आना-कानी की तो उन्होंने काहिरा से अन्य अरब देशों के श्रमिकों तक अपनी सीधी पहुंच करने के लिए अरब ट्रेड यूनियनों का महासंघ कायम किया।

पश्चिम में ट्युनीशिया में नियो-दस्तूर पार्टी को अगर संगठित श्रमिकों का ठोस सहयोग प्राप्त न होता तो वह कभी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती थी और स्वतंत्रता तथा सामाजिक सुधारों की प्राप्ति में इतनी सफल नहीं हो सकती थी। मोरक्को में स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान में 'नेशनल फैडरेशन आव लेबर' एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत के रूप में पैदा हुआ है।

प्रेसीडेण्ट ऐन्क्रूमा और उनकी 'कान्वेंशन पीपल्स पार्टी' ने सन् १९५४ में घाना में घरेलू राजनीतिक कारणों तथा कम्यूनिज्म के प्रभाव से उसकी रक्षा करने के लिए मजदूर आन्दोलन का सफलतापूर्वक सहयोग प्राप्त किया। जॉन टेटेगाह का जीवन इस बात का साक्षी है कि विश्व के अनेक उदीयमान राष्ट्रों के मामलों में ट्रेड यूनियनें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

केनिया के २९ वर्षीय श्रमिक नेता टॉम म्बोया पहले केनिया श्रम संघ के महामंत्री के रूप में और फिर ऐकरा में निखिल अफ्रीकी लोक सम्मेलन के सभापति के रूप में अफ्रीकी स्वाधीनता आन्दोलन के अत्यन्त योग्य नेता के रूप में सामने आए। आज वह केनिया विधान परिषद् के सदस्य भी हैं। म्बोया का उत्थान मजदूर संगठनों और उनके नेताओं के नवीन महत्व का एक अच्छा उदाहरण है।

सेकाऊतूरे ने अफ्रीका के नवीनतम स्वाधीन देश गिनी के स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व किया, उन्होंने भी अपना राजनीतिक जीवन एक मजदूर नेता के रूप में शुरू किया था। पहले-पहल एक श्रमिक नेता के रूप में ही उन्होंने यह दिखा दिया कि वे अपने अनुयायियों से वैसे ही श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं जैसी धर्म के प्रति होती है।

लैटिन अमरीका में भी हमें बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, मैक्सिको में ट्रेड यूनियनें आज एक शक्तिशाली ताकत हैं। राष्ट्रपति लोपज मेतियोस, जो पहले श्रम-मंत्री थे, मजदूर समर्थन की बदौलत ही चुने गए ट्रेड यूनियन आन्दोलन की बदौलत ही वहां की वर्तमान सरकार को लोक-समर्थन प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा में मजदूरों के २५ से अधिक प्रतिनिधि हैं और सेनेट में भी एक ऐसी ही स्थिति है। जैसे-जैसे देश का औद्योगीकरण होता जाएगा वैसे-वैसे मजदूर यूनियनों की ताकत भी बढ़ेगी और श्रमिकों में उनकी पैठ अधिक व्यापक होगी।

कोलम्बिया, पेरू और वेनेज्वला में, अर्जेंटाइना तथा बोलीविया में, ट्रेड यूनियनें प्रमुख राजनीतिक भूमिका अदा कर रही हैं क्योंकि इन देशों में ये सबसे महत्वपूर्ण सामुदायिक संगठन हैं। कोस्टा रीका की विधान सभा में लुई अलबर्टो मोंगे फिलहाल विपक्ष के प्रमुख नेताओं में से हैं। मोंगे ने अपने जीवन की शुरूआत ट्रेड यूनियन आन्दोलन से की और हाल के वर्षों में उन्होंने अपने देश के प्रमुख मजदूर संगठन के अध्यक्ष के रूप में तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के अन्तर्राष्ट्रीय महासंघ के प्रादेशिक संगठन 'ओ० आर० आई० टी०' के महामंत्री के रूप में काम किया।

बोलीविया के मजदूर नेता जुआन लेचिन सन् १९५२ की क्रांति के दो मुख्य अधिनायकों में से एक थे। आज वे विपक्ष के नेता हैं। लेकिन सेनेटर होते हुए भी बोलीविया के केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन के कार्यकारी सचिव और खान श्रमिक संघ के मुखिया हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात् आई० एल० ओ० के उद्देश्य मूलतः दो हैं :—

१. अपने प्राविधिक सहायता कार्यक्रमों और शिक्षात्मक कार्यों के जरिये यह समस्त संसार में श्रमिकों के कल्याण में उन्नति करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए वह व्यावसायिक प्रशिक्षण, श्रम विभाग जैसी सरकारी संस्थाओं की स्थापना में सहायता, स्वतंत्रत सामूहिक सौदेबाजी और ठोस श्रमिक-प्रबन्ध सम्बन्धों के विकास में सहायतार्थ प्राविधिक सलाह प्रदान करता है और ऐसे अनेक कार्यक्रम चलाता है जो विकास करने वाले देशों को अपनी मनुष्य-शक्ति का बेहतर उपयोग करने में मदद देते हैं।

२. 'आई० एल० ओ०' अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान निर्धारित करता है, जिनका उद्देश्य अपने लोगों को बढ़िया जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करने वाले विकासमान राष्ट्रों को रास्ता दिखाना है।

अन्तर्राष्ट्रीय ऐजेंसियों में 'आई० एल० ओ०' इस दृष्टि से अद्वितीय है कि इसमें तीन पक्ष शामिल हैं। अर्थात् इसके सदस्यों में कोई ८० राष्ट्रों के श्रमिकों, मालिकों तथा सरकारों के प्रतिनिधि हैं। जेनेवा का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन ही एक ऐसा अवसर है जब यूनियन नेता, जिनमें से बहुत से अपने-अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तियों में से होते हैं, अपने देश से बाहर जाते हैं।

हमने देखा है कि नये राष्ट्रों में श्रमिकों के संगठन आर्थिक उन्नति की जद्दोजहद में निर्णायक शक्ति हैं और बहुत से मामलों में उन्हीं से एकमात्र ऐसा सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व उपलब्ध होता है जिसका असर शिक्षित वर्ग के अलावा दूसरे समाजों पर भी पड़ता है। अगर भविष्य में स्वतंत्रता और लोकतंत्र को खोये बिना भौतिक उन्नति करनी है तो इस शक्ति और उसमें निहित स्रोतों को पूर्णतः समझना पड़ेगा। इसके लिए राजनीतिक अधिकारों और बेहतर जीवन के लिए संघर्षरत लोगों के हितों को अपने हितों जैसा मानकर काम करने की आवश्यकता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विविध राज्यों के बजट

पिछले महीने निम्नलिखित राज्यों के बजट विधान सभाओं में पेश किये गये हैं।

बम्बई

आय	१५०.०६ करोड़ रुपए
व्यय	१४६.६६ करोड़ रुपए
बचत	७ लाख रुपए

यह बजट अस्थायी है क्योंकि बम्बई राज्य का पुनर्विभाजन होने वाला है। इसलिए इसमें कोई नया कर भी नहीं लगाया गया। आय के विभाग में उत्पादन कर, उत्तराधिकार कर तथा रेलवे यात्री कर के अंश के रूप में केन्द्रीय सरकार से ३१ करोड़ रुपये, बिक्री कर से ३६.५० करोड़ रुपये, भूमि कर १२.३५ करोड़ रुपये अनुमान किये गये हैं।

पूंजीगत व्यय में ४७.५५ करोड़ रुपए का अनुमान दिया गया है। इसमें राज्यीय व्यापार योजना में सम्मिलित व्यय नहीं है। पंचवर्षीय योजना के मद में १०१.४६ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं।

केरल

आय	४२.६५ करोड़ रुपए
व्यय	४४.६४ करोड़ रुपए
घाटा	१.६६ करोड़ रुपए

केरल में नए चुनावों के बाद अभी ही नई सरकार बनी है। घाटे को पूरा करने के लिए कोई नया कर नहीं लगाया गया। पूंजीगत व्यय में ६.०६ करोड़ रुपया नियत किया गया है।

राजस्थान

आय	५५.१५ करोड़ रुपये,
व्यय	४५.८६ करोड़ रुपये,
घाटा	१५.२६ लाख रुपए,

कुछ नये कर लगा करके यह घाटा १५.७४ लाख रुपए की बचत में परिणत कर दिया गया, कुल नये कर ६५ लाख रुपए कमी का अनुमान किया गया है, बिक्रीकर से ४५ लाख रुपए, भूमिकर से १० लाख रुपये और उत्पादन कर से ७ लाख रुपये, और उत्पादन-कर से ७ लाख रुपए के अतिरिक्त आमदनी का वित्त मंत्री ने अनुमान किया है।

मद्रास

आय	८०.८७ करोड़ रुपए
व्यय	८१.२१ करोड़ रुपये
घाटा	३४ लाख रुपए

कोई नया कर नहीं लगाया गया, पूंजीगत व्यय में १०.८५ करोड़ रुपए रखे गये हैं।

सरकार का इरादा १० करोड़ रुपया बाजार से ऋण लेने का है, आगामी वर्ष उसे ७.१७ करोड़ रुपया ऋण खाते चुकाना भी है। सब्जी, आलू, फल, पान, फूल, अण्डे, मांस, मछली, कोल्हू का तेल तथा हरे पत्ते वाली चाय को बिक्रीकर से मुक्त करना सरकार के विचाराधीन हैं।

मैसूर

आय	६३.७१ करोड़ रुपया।
व्यय	६२.६३ करोड़ रुपया
बचत	१.०८ करोड़ रुपया

योजना के लिए ४०.७७ करोड़ रुपये नियत किये गये हैं, कोई नए कर नहीं लगाये गये हैं। ● ●

नर-नारी

[काम ● मनोविज्ञान ● स्वास्थ्य ● सौंदर्य]

सम्पादक—श्री द्वारका प्रसाद एम० ए०
श्री वीरेन्द्र वात्स्यायन

समाज-निर्माण एवं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए यौन-ज्ञान महत्वपूर्ण है। यौन-ज्ञान को वैज्ञानिक एवं स्वस्थ स्तर पर समझने के लिए भारतीय कामशास्त्र और विदेशी विद्वानों, चिकित्सकों तथा वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ज्ञान आपको 'नर-नारी' में मिलेगा। स्वस्थ यौन-ज्ञान और यौन-जीवन के लिए यह पत्रिका प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अवश्य पढ़नी चाहिए।

मूल्य—एक प्रति .७५ नये पैसे वार्षिक ८.०० रुपये मात्र

न र - ना री प्र का श न

अशोक राजपथ, पटना-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जम्मू और कश्मीर

में

सामुदायिक विकास योजनाओं की प्रगति

द्वितीय योजना की अवधि के प्रारंभिक तीन वर्षों में सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय सेवा विस्तार के क्षेत्र में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की गईं।

- राज्य में ५३ ब्लॉक स्थापित हुए।
- ९१७ सामुदायिक केन्द्र बनाए गए।
- ३४ ग्राम-नेता प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए।
- ब्लॉक परामर्शदात्री समितियों की १,०२४ सभाएं हुईं।
- ६,१३२ उन्नत औज़ार वितरित किए गए।
- २९८ पीने के पानी के कुएं बनाए गए।

कश्मीर सूचना कार्यालय

जम्मू और कश्मीर शासन

द्वारा प्रसारित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया साहित्य

द्वितीय पंचवर्षीय योजना—मूल्य ४.५०, भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा प्रकाशित।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना आज से करीब चार वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी। इसी योजना पर इन वर्षों में अमल हो रहा है। इस योजना काल का यह अंतिम वर्ष है।

प्रस्तुत पुस्तक में इसी योजना का अविकल रूप से हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया गया है। योजना दो खण्डों और तीस अध्यायों में विभक्त है। इन चार वर्षों में इस योजना के सम्बन्ध में इतना अधिक विचार विनिमय हुआ है कि इन पंक्तियों में इसके सम्बन्ध में कुछ लिखना व्यर्थ है। अच्छा होता यह हिन्दी अनुवाद भी योजना आयोग आज से चार वर्ष पहले ही अंग्रेजी संस्करण के साथ प्रकाशित करता। फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ में अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, विचारकों और विधायकों के लिए गंभीर पृष्ठभूमि दी है जिसे पढ़कर वे न केवल देश की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं। बल्कि विचाराधीन तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में भी स्वतन्त्र रूप से विचार कर सकते हैं, इसमें देश की आर्थिक समस्यायें, कृषि और उद्योग सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम तथा अपने साधनों के सम्बन्ध में अधिकृत जानकारी मिलती है। पुस्तक का कलेवर देखते हुए इसका मूल्य भी अधिक नहीं है।

हमें आशा है कि सब हिन्दी पुस्तकालय और शिक्षण संस्थायें इसका संग्रह करके अपने सदस्यों को प्रामाणिक जानकारी देने में सहायक होंगी।

सरल आर्थिक एवं वाणिज्य भूगोल—ले०—श्री रामशरण गुप्त और श्री ओ० पी० जिंदल। प्रकाशक—गयाप्रसाद एण्ड संस, आगरा। मूल्य ६.००

प्रस्तुत पुस्तक कालेजों के व्यापार-वाणिज्य-विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। लेखकों को इसको पढ़ाने का अनुभव है, इसलिए वे विद्यार्थियों की आवश्यकता व योग्यता से परिचित हैं। प्रस्तुत विषय को प्रश्नोत्तरों के रूप में समझाने की चेष्टा की गई है।

पहले दस अध्यायों में विश्व के प्राकृतिक भूगोल की पृथ्वी, भूकम्प, भूमि की सतहें, वायुमण्डल, सामुद्रिक गरम व शीत धाराएं आदि की चर्चा है, तो शेष अध्यायों में भारत को छोड़कर दक्षिण-पूर्वी एशियाई, चीन, जापान, भूमि, उत्तरी अमेरिका की कृषि, खनिज, उद्योग यातायात आदि आर्थिक विषयों की जानकारी दी गई है। प्रसिद्ध व्यापारिक नगरों व बन्दरगाहों का परिचय बहुत उपयोगी ज्ञानवर्धन करता है।

हमारी नम्र सम्मति में यदि प्रथम दस अध्यायों को कुछ संक्षिप्त करके दूसरे भाग को अधिक पृष्ठ दिये जाते, तो विद्यार्थियों को और भी अधिक लाभ होता। वैसे यह पुस्तक भी कम उपयोगी नहीं है।

अध्यात्म रोगोंकी चिकित्सा—ले०—श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति। प्रकाशक—गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी। हरद्वार, पृष्ठ संख्या १७८, मूल्य २.५० रु० सजिल्द।

शारीरिक रोगों के निवारण के लिए तो सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित होती है और स्कूलों व विद्यालयों में भी अंशतः या पूर्णतः शिक्षा दी जाती है; किन्तु आज समाज इन रोगों की अपेक्षा मानसिक व आध्यात्मिक रोगों से अधिक ग्रस्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं के कारण ही समाज का चारित्रिक व नैतितिक स्तर बहुत गिरा हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक लेखक ने इन रोगों के निवारण की दृष्टि से लिखी है। लेखक वैदिक व संस्कृत साहित्य के विद्वान् हैं और प्रत्येक पक्ष पर स्वतन्त्र विचार करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। सरल लेखन शैली इस पुस्तक की बहुत बड़ी विशेषता है। छोटे-छोटे प्रकरणों में अलग-अलग विषय स्पष्ट किया गया है। वेद व दूसरे ग्रन्थों के प्रासंगिक उद्धरणों की बहुलता के होते हुए भी प्रतिपाद्य विषय जटिल नहीं हो पाया। उसकी सरलता कायम रखी गई है।

लोगों के अपने व विद्यार्थियों व बालकों के चरित्र निर्माण की दृष्टि से यह पुस्तक निःसन्देह उपयोगी सिद्ध होगी।

आकाशवाणी विविधा—प्रकाशक-सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ २६३, मूल्य ३।।)।

आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों से जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, उनमें कुछ कार्यक्रम बहुत उपयोगी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और स्थायी साहित्य की वस्तु होते हैं। ऐसी सामग्री से लाभ उठाने के लिये उसे कुछ स्थायी रूप देना जरूरी है। भारत सरकार के सूचना विभाग ने इसी दृष्टि से यह संग्रह विविधा के नाम से प्रकाशित किया है। इस संग्रह में १६५६ में प्रसारित कार्यक्रमों में से सुन्दर, उपयोगी, पठनीय और रोचक सामग्री का संग्रह किया गया है। वस्तुतः ऐसे संग्रह मनोरंजन और जानकारी दोनों दृष्टियों से लाभकारी हैं।

हमें आशा है कि ऐसे संग्रह निरन्तर वर्ष में दो बार प्रकाशित होते रहेंगे। इससे सिद्धहस्त लेखकों, उत्कृष्ट कलाकारों और ऊंचे कवियों की रचनायें उन लोगों को लाभ पहुँचा सकेंगी जो न तो रेडियो के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित होनेवाले कार्यक्रम सुन सकते हैं और न उन्हें स्मरण रख सकते हैं।

वेदव्याख्या-ग्रन्थ (चतुर्थ पुष्प)—प्रकाशक : वेद संस्थान, अजमेर, ले० श्री विद्यानन्द विदेह।

आचार्य श्री विद्यानन्द विदेह वेदों का जो भाष्य कर रहे हैं उसका यह चतुर्थ खण्ड है। उनकी व्याख्या की शैली यथापूर्व रखी गई है। सन्धिविच्छेद, प्रतिपद का अर्थ, विशेष व्याख्या तथा अन्त में मंत्र का भाष्य और पद्य में आशय दिया गया है। यद्यपि प्रथम खण्डों की अपेक्षा इसमें कुछ संक्षेप किया गया है तथापि अभी अधिक संक्षेप हो सकता है, जिससे यह अधिक सुबोध हो जायगा। छपाई सफाई अच्छी है।

आशा है, वेदोंके प्रेमी इसका अध्ययन करेंगे।

साहित्य वाटिका—प्रकाशक—दिल्ली राज्य संस्कृत विश्व परिषद, २३-एफ, कमला नगर, दिल्ली-६।

पिछले वर्षों में संस्कृत का प्रचार करने के लिए अनेक संस्थाओं का जन्म हुआ है। संस्कृत विश्व परिषद भी उनमें से ही एक है। इसी संस्था की ओर से यह लघु पुस्तिका प्रकाशित हुई है। दिल्ली के अनेक संस्कृत प्रेमी कवियों ने 'कालोऽस्ति नायं शयनस्य मान्याः' समस्या की पूर्ति के सुन्दर प्रयत्न किए हैं। ये समस्या पूर्तियाँ इस पुस्तिका में प्रकाशित हुई हैं। ऐसी रचनाओं के प्रकाशन से संस्कृत-अध्ययन के प्रति रुचि अवश्य बढ़ेगी। रचनाएं भाषा और भावों की दृष्टि से सुन्दर हैं।

• •

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र०
की
विज्ञप्ति संख्या ४।५५८० : २७।३३।५३, दिनांक १५
द्वारा
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

		रु०	आ०
वेद सार	प्रो० विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग			
सच्चा सन्त			३
सिद्ध साधक कृष्ण			३
जीते जी ही मोक्ष			३
आदर्श कर्मयोग			३
विश्व-शांन्ति के पथ पर			१
भारतीय संस्कृति	प्रो० चारुदेव		३
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१३
हमारा समाज		६	
व्यावहारिक ज्ञान		२	१२
फलाहार		१	४
रस-धारा		०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां		१	
नये युग की कहानियां		१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	
विशाल भारत का इतिहास	प्रो० वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार
साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दो विरोधी दलों के आर्थिक कार्यक्रम

स्वतंत्र पार्टी

स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर एन० जी० रंगा ने कहा है कि स्वतंत्र पार्टी कल्याणकारी समाज और जब आवश्यक हो तो कल्याणकारी राज्य की समर्थक है। यह सभी समर्थ लोगों पर बट्टा लगा कर सामाजिक रूप से कम उन्नत और आर्थिक रूप से जरूरतमन्द किन्तु उद्योगी व्यक्ति एवं समूहों की सहायता करेगी। इस तरह व्यक्ति के पूर्ण विकास, आत्म विश्वासपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में बाधा न पड़ने देगी, जिस से उन्हें अपने सामाजिक, आर्थिक अधिकारों और समर्थताओं के लिए गौरव का अनुभव हो।

वर्तमान कांग्रेस सरकार की इन तथाकथित समाज-कल्याण योजनाओं के आधार और उनके प्रशासन के तौर-तरीकों पर फिर से विचार किये जाने का समर्थन करती है। हम उनके न्यायसंगत, रचनात्मक और विकेन्द्रीकरण के आधार पर पुनर्गठन की माँग करते हैं।

किसान आंदोलन की ओर से युगों से हमेशा यह माँग की जाती रही है कि फसलों और माल-मवेशियों के बीमा-करण की योजना और अकाल, बाढ़ तथा अन्यान्य सामान्य संकटों के विरुद्ध अन्य बुनियादी सीमा सम्बन्धी कार्यों का सरकार द्वारा संघठन किया जाय। इससे श्रमिक कल्याण और सुरक्षात्मक कानूनों को यथासंभव कृषि मजदूरों पर भी लागू किया जाए।

सम्बन्धित वर्गों और तबकों द्वारा राज्य की सहायता से स्वयं ही अपने आप ऐसी बीमा-करण योजनाओं को यथा-संभव कार्यान्वित करा दिया जाय, उनकी अपनी योग-दान-योजना-द्वारा और राज्य, खर्च, बट्टा, खतरों का एक हिस्सा बर्दाश्त करते हुए एकाधिक बीमा व्यवसायों के बीच प्रति-द्वन्द्विता चलने देगा। ● ●

कम्युनिस्ट पार्टी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय ने आर्थिक नीति के बारे में श्री डांगे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव में कहा गया है—

भारत में आर्थिक प्रगति हुई है। उद्योगपतियों ने भारी मुनाफे कमाये हैं, पर कर्मचारियों के वेतन स्थिर रहे हैं। कर्मचारियों को कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए अब समय है कि कर्मचारी अपनी माँगों पर डट जाएं। उन्हें आंदोलन और आखिरी हथियार हड़ताल से भी काम लेना चाहिए।

इस समय उद्योगपति लम्बी हड़तालें सहन नहीं कर सकेंगे जिससे कर्मचारियों के साथ समझौता करने पर बाध्य होंगे।

पार्टी के सचिवालय द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का यह भी सम्भावित फल समझा जा रहा है कि आगामी कुछ मास में कम्युनिस्ट पार्टी की ट्रेड यूनियन (अखिल भारतीय ट्रेडयूनियन कांग्रेस) कर्मचारियों को एक आवाहन करेगी। ● ●

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनीतिक अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिकअली
सम्पादक : श्री सुनील गुह

★ हिन्दी में अनूठा प्रयास
★ आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
★ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु०   एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नये जमाने के नये बाट !

मन्नूलाल द्विवेदी

प्रत्येक नया सुधार होने पर जनता में कहीं-कहीं उसके प्रति सन्देह तथा असन्तोष आदि उत्पन्न होते ही हैं। पुरानी प्रणालियों का मोह भी इस असन्तोष को बढ़ाने में सहायक होता है। यही बात बाटों और पैमानों के विषय में भी सही है। हम इस समय मन, सेर, छटांक, तोला, माशा, रत्ती आदि जिन बाटों को वर्षों से काम में ला रहे हैं, उनसे अभ्यस्त होने के कारण हमारा मोह हो जाना स्वाभाविक है। जिन व्यक्तियों की प्रकृति भावुक है उन्हें तो चलतू बाट और पैमानों का परित्याग मार्मिक पीड़ा पहुँचा सकता है।

हमारा देश बहुत विशाल है। इसके भिन्न-भिन्न प्रदेशों ने अपनी सुविधा के अनुसार जैसे सम्भव हुए वैसे बाट और पैमाने बनाकर समय-समय पर काम चलाया है। इस प्रकार से यदि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के बाट और पैमाने हैं तो एक प्रदेश में भी भिन्न-भिन्न वस्तुओं की मापतौल करने के लिये एक ही नाम के परन्तु भिन्न भार और लम्बाई वाले बाट और पैमाने प्रयोग में लाये जाते हैं। फिर इनमें भी समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं।

नापतौल में एकरूपता का अभाव

१९५१ में बाटों के बारे में एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था। उससे ज्ञात हुआ कि भारत में १०० से अधिक तरह के मन चलते हैं। इनका भार २८० तोले से लेकर ८३२० तोले तक है, जबकि इसका प्रतिमानित भार ३२०० तोले है। इसी तरह ८ तोले से लेकर १६० तोले तक के सेर हैं। ८० तोले का प्रतिमानित सेर देश के ६० प्रतिशत स्थानों में चलता है। इसके अतिरिक्त २० तोले, २४ तोले, ३२ तोले, ४० तोले, ५० तोले, ९६ तोले, १०० तोले और १०४ तोले के सेर भी चलते हैं। इसी तरह १ तोले से लेकर ८ तोले तक की छटांक, १६०० तोले से लेकर ३०,००० तोले तक की खण्डी और १ तोले से लेकर १० तोले तक के पलम बाट चलते हैं।

बड़े पैमाने पर अनाज की बिक्री तौलकर होती है। उत्तरप्रदेश के बाट और पैमाने भी विविध प्रकार के होते हैं। स्थान-स्थान और कहीं-कहीं तो गांव-गांव में भी अलग-अलग तरह के बाट होते हैं। एक ही स्थान पर तेलहन तोलने के लिये ४१॥ सेर का मन होता है तो मूंगफली के लिये ५० सेर का। गेहूँ तथा अन्य अनाजों के लिये ४१। सेर का तथा तम्बाकू और चीनी के लिये ४८॥ सेर का मन होता है। सेर में भी बहुत भिन्नता होती है। एक स्थान पर सेर ८० तोले का होता है तो दूसरे स्थान पर ९२ तोले का और तीसरे स्थान पर ११२ तोले का। देहातों में आम तौर पर कच्ची तौल प्रचलित है।

लम्बाई क्षेत्रफल आदि नापने के पैमानों में और भी गड़बड़ी है। लम्बाई अब भी अनेक स्थानों पर हाथ से नापी जाती है जो १४ इंच से लेकर २० इंच तक होती है। दूरी नापने के लिये उत्तर भारत में कोस का बहुत रिवाज है। यह कोस कहीं १॥ मील का तो कहीं २ मील, २। मील और कहीं २॥ मील तक का माना जाता है। जमीन नापने के लिये दक्षिण में कारगी और वेली, तो उत्तर में कट्टा, बीघा, कनाल आदि काम में लाये जाते हैं। बिहार और बंगाल में बीघे में भी बहुत अन्तर है।

युग बदल रहा है

बाटों और पैमानों की यह विविधता उस युग की प्रतीक है जब देश छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और प्रत्येक राज्य अपने आपको अन्य राज्यों से अलग मानता था। तब देश में परिवहन के साधन भी बहुत कम थे। इसलिये व्यापार भी स्थानीय रूप से ही अधिक होता था। अतः स्थानीय बाट और पैमानों से काम चल जाता था। जब कभी दूर-दूर के स्थानों के व्यापारी आपस में खरीद बिक्री करते थे तो नाप तौल करने और बाद में मूल्य का भुगतान करने में उसी प्रकार हिसाब-किताब करने पड़ते थे जैसे कि आज भारतीय व्यापारियों को इटली, ईरान, इन्डोनेशिया अथवा अफगानिस्तान आदि से करने पड़ते हैं। जिस प्रकार इन देशों के व्यापारियों को भारतीय व्यापारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी मानते थे, उसी प्रकार भारत के भीतर ही एक प्रदेश के व्यापारी दूसरे प्रदेशों के व्यापारियों को विदेशी जैसा मानते थे। इससे एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने में भारी बाधा पड़ती थी।

अधिकांश देशों में

देश में नये बाट चलाने का जो प्रयत्न आरम्भ हुआ है उससे विभिन्न प्रदेशों में फैली हुई बाटों की विविधता दूर हो जायगी। समस्त देश में एक से पैमाने और बाट हो जाने से आन्तरिक व्यापार बढ़ने में सहायता मिलेगी और मूल्य में भी स्थिरता आयेगी। नये बाट मीटर प्रणाली के होंगे। अन्य देशों में यह प्रणाली बहुत लोकप्रिय हुई है। भारत में जब तक ब्रिटिश शासन रहा मीट्रिक प्रणाली का प्रचलन नहीं हो सका। इसका कारण यही था कि भारत के उद्योग व्यापार की कुंजी उस समय ब्रिटिश औद्योगिकों और व्यापारियों के हाथ में थी और वे मीटर प्रणाली के विरुद्ध थे। इसीलिये कई बार इसके पक्ष में प्रयत्न किये जाने पर भी कोई प्रगति नहीं हो सकी। राजनीतिक स्वराज्य के साथ ही बाट और पैमानों की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये भी भारत ने अपना निश्चय कर लिया।

आम आदमी को आसानी

श्री नेहरू ने कहा है—'हमारा देश पुराने खयालों का है और पुरानी तथा जमी हुई प्रणाली को बदलना आसान नहीं होता। मुझे विश्वास है कि मीटर प्रणाली को अपनाने का हमारा निश्चय हर दृष्टि से उचित है। वैज्ञानिक, शिल्पी और अंकशास्त्री के लिये तो सबसे उपयोगी यही एक प्रणाली है। यही नहीं, आम आदमी को भी इससे काफी सहूलियत और आसानी हो जाएगी।''

सभी प्रकार की कठिनाइयों और विरोध का केवल एक मार्ग है और वह यह कि इस मीट्रिक प्रणाली के बाटों और पैमानों के नाम वही रहें जो देश में आजकल प्रचलित है। जिस प्रचार से दशमलव प्रणाली की टक्साल का चलन प्रारम्भ करते समय रुपया और पैसा का नाम नहीं बदला गया, उसी प्रकार बाटों और पैमानों के नामकरण में दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए। भले ही पर्यायवाची नाम अंग्रेजी बने रहें।

नई प्रणाली के बाटों और पैमानों के विषय में अच्छी तरह प्रचार होना चाहिये, जिससे जनता इनसे परिचित हो जाय। इसके अतिरिक्त नये बाटों का प्रचलन करने का भार जिन अधिकारियों को सौंपा जाय, उन्हें चाहिये कि वे सहानुभूतिपूर्वक जनता की कठिनाइयां दूर करने का यत्न करें। इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार तो किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, अन्यथा जन-जीवन में बड़ा भारी विष फैल जायगा। जो अधिकारी अथवा लेनदेन करनेवाला इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाय उसके विरुद्ध तुरन्त कड़ी कार्रवाई करनी चाहिये। ऐसा करने से जनता की बहुत-सी असुविधाएं दूर हो जाएंगी और नये बाटों के प्रचलन का मार्ग प्रशस्त हो जायगा। साथ ही जनता में यह भावना दृढ़ होगी कि नये बाटों और पैमानों के प्रचलन से उन्हें धोखा और हानि नहीं होगी।

● ●

[पृष्ठ २०३ का शेष]

मंत्रियों, शिक्षकों, विशेष अधिकारियों, सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं और सम्बन्धित कर्मचारियों को नयी ट्रेनिंग देने के लिए तथा अनुसंधान करने के लिए सहकारी खेती की राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाय।

आर्थिक सहायता

बैंकों आदि द्वारा सहकारी खेती का महत्व न समझने, सहकारी खेती समिति द्वारा जमीन आदि की जमानत देने में असमर्थता के कारण सहकारी खेती समितियों को काफी कठिनाई हुई है। इसलिए सरकार को उपज के कार्यक्रम को देखते हुए प्रत्येक समिति को अधिक से अधिक ४ हजार रु० तक का काम देना चाहिए। जो ऋण थोड़े ही अर्से में चुकाया जाने वाला हो, उसे बिना सरकार की गारंटी लिये ही केन्द्रीय सरकारी बैंकों से सीधे मिलना चाहिए।

भूमितियों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हरेक सोसाइटी से अधिक से अधिक २ हजार रु० के शेयर ले। यह शेयर समिति की शक्ति बढ़ाने के लिए हैं, उस पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं।

सरकारी खेती के कार्यक्रम पर लगभग ३५ करोड़ २६ लाख रु० खर्च होगा। इसमें से २८ करोड़ ६५ लाख रु० समितियों को सहायता देने के लिए, ४ करोड़ २४ लाख रु० ट्रेनिंग और शिक्षा देने तथा २ करोड़ ३७ लाख रु० कारीगर पर खर्च किया जाए।

● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय उद्योग के बढ़ते चरण

लाल बहादुर शास्त्री, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री

विदेशी मुद्रा की बहुत कमी होने पर भी गत वर्ष सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि इस कारण देश के उत्पादन और औद्योगिक विकास को कोई हानि न हो। पिछले वर्ष की अपेक्षा १९५९ में औद्योगिक उत्पादन बहुत बढ़ा। १९५९ के पहले १० महीनों में उत्पादन का सूचक अंक १०.४ बढ़ा। जबकि १९५८ में १९५७ से, सूचक अंक केवल २ अंक ही अधिक रहा था।

जिन उद्योगों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, उनमें चीनी के कारखानों की मशीनों, डीजल इंजनों, मशीनी औजारों, गंधक के तेजाब, लोहा और इस्पात, अलुमीनियम, सुपरफास्फेट, सोडा-एश, सीमेंट और कागज तथा दफ्ती के उद्योग उल्लेखनीय हैं। इस समय देश में प्रति वर्ष १ लाख ३२ हजार टन लोहे के ढांचे, १ लाख टन इस्पात के नल और नालियां, ३० हजार टन स्टील का ढला हुआ सामान, १२ हजार माल-डिब्बे बनाये जा रहे हैं। १९५९ में २॥ करोड़ रु० की कीमत की चीनी कारखानों की मशीनें और औजार बनाये गये। इसके अलावा ४ करोड़ रु० की कीमत के मशीनी औजार बनाये गये। देश में ३० हजार डीजल इंजन, २० लाख बाल-बीयरिंग, ३४ हजार मोटरें, १७५ डीजल के सड़क कूटने के इंजन, ६ लाख हार्स-पावर के बिजली के मोटर आदि बनाये जा रहे हैं।

इस्पात के उत्पादन की वृद्धि के साथ इंजीनियरी उद्योगों का उत्पादन भी बढ़ेगा। देश में प्रतिवर्ष १६ हजार टन अलुमीनियम, ७ हजार ५०० टन तांबा, ६० हजार टन फेरो मैंगनीज और कुछ सीसा-जस्ता तथा एंटीमनी निकाला जाता है। इनके अलावा हाइड्रोजन एमोनियम नाइट्रेट, एसिटोन आदि बनाने के नये उद्योग भी शुरू किये गये हैं।

भारी उद्योगों का विकास

बड़े उद्योगों में भोपाल के बिजली का भारी सामान बनाने के कारखाने में उत्पादन बहुत बढ़ा है। यह कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। भोपाल के कारखाने में भारी ट्रांसफारमरों और स्विच गियरों के अलावा टरबाइन और जैनरेटर भी बनाये जायेंगे।

रांची में रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से मशीनी कारखाना बनाया जा रहा है, उसमें इस्पात कारखानों के लिए मशीनें बनेंगी। इस कारखाने में प्रतिवर्ष ८०,००० टन मशीनें बनाई जाएंगी। रूस के नये ऋण के प्रस्ताव से लाभ उठाकर इस आयोजन में उत्पादन की संभावना बढ़ाई जा रही है। जब कारखाना पूरा उत्पादन करने लगेगा, तो सभी प्रकार की अवैद्युत मशीनें तैयार होने लगेंगी। अन्य भी कई योजनाएं तैयार हो रही हैं।

इनमें खान खोदने की मशीनें बनाने की एक योजना, भारी प्लेटें बनाने और जहाज निर्माण की एक योजना तथा भारी वैद्युत यन्त्रों की अन्य दो योजनाएं उल्लेखनीय हैं। सरकारी क्षेत्र की जो योजनाएं इस समय अमल में लाई जा रही हैं और जो तीसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में उत्पादन करने लगेंगी उनमें देश के विभिन्न भागों में स्थापित किये जाने वाले उर्वरकों के कारखाने, भेषजों और औषधियों की कई योजनाएं, प्रांगारिक रसायनिक उद्योगों के लिये आधारभूत कच्चा माल प्रस्तुत करने वाला मध्यवर्ती संयन्त्र और सिनेमा तथा एक्स रे की फिल्में तैयार करने की योजनाएं उल्लेखनीय हैं।

सरकार ने योजना आयोग की सलाह से तीसरी योजना में भारी मशीनें बनाने के अन्य कई कारखाने खोलने का भी निश्चय किया है। तीसरी योजना में उर्वरक और दवाएं आदि बनाने वाले कई ऐसे कारखानों का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जो आजकल बनाए जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र में बनने वाले कारखानों से निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। उदाहरणार्थ सरकारी इस्पात कारखाने बन जाने पर निजी क्षेत्र में इंजीनियरी का सामान बनाने वाले कई कारखाने शुरू होने लगेंगे। दवाएं बनाने की मशीनें बन जाने से विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

मूलभूत रासायनिक पदार्थों तथा अर्द्ध तैयार वस्तुओं का देशी साधनों से निर्माण होने लगेगा तो भेषजों, रंगों और प्लास्टिकों के निर्माण के लिए विदेशों से कच्चे माल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का आयात करने के हेतु विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर नहीं रहना होगा। मशीन निर्माण की क्षमता बढ़ जाने पर भारतीय उद्योग आयात और उनके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा के खर्च पर निर्भर रहे बिना ही अपनी उत्पादन-क्षमता बढ़ा सकेंगे। जो विकास होगा वह निजी क्षेत्र का पूरक होगा और उससे स्थापित होने वाली क्षमता को बढ़ा देगा।

सब प्रकार की औद्योगिक मशीनों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिये उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत हाल में ही लायसेन्स लेने के लिये दिये जाने वाले आवेदन-पत्रों में निरन्तर वृद्धि हुई है। २,३२००० के० वी० ए० के ट्रान्सफारमर बनाने, २०,००० टन प्रति वर्ष के ढांचे तैयार करने, १२,००० टन प्रति वर्ष इस्पाती ढलाई करने और मीटर गाड़ियों तथा अन्य उद्योगों के लिये उच्च कोटि के भूरे इस्पात को तैयार करने की अतिरिक्त क्षमता भी शीघ्र ही स्थापित हो जायेगी। अलूमीनियम का निर्माण करने के लिये स्वीकृत योजनाओं का योग अब ७५,००० टन वार्षिक से अधिक हो चुका है।

निर्यात में वृद्धि

सरकारी रिपोर्ट से पता लगता है कि सन् १९५९ में निर्यात व्यापार से भी बहुत फायदा हुआ। इस साल ६२६ करोड़ रु० का, अर्थात् १९५८ से १०.२ प्रतिशत ज्यादा का सामान निर्यात हुआ। वैसे तो सभी चीजों के निर्यात में वृद्धि हुई किन्तु तैयार माल के निर्यात में यह वृद्धि उल्लेखनीय है। सूती कपड़े और तैयार चमड़े का काफी निर्यात बढ़ा। इस साल सीमेंट और लोहे के ढोकों का भी निर्यात हुआ। पड़ौसी देशों में यहां के इंजीनियरी सामान की काफी मांग बढ़ रही है। खेती की उपज के निर्यात में आशातीत वृद्धि नहीं हुई। बल्कि चाय, कपास तम्बाकू और कुछ खाने के तेलों का निर्यात कम हो गया।

निर्यात की वृद्धि का जो अनुकूल परिणाम होना चाहिए था, वह नहीं हो सका; क्योंकि आयात व्यापार में भी काफी वृद्धि हुई।

१९५९ में कुल ८६९ करोड़ रु० मूल्य की वस्तुएं बाहर से मंगाई गयीं, जबकि १९५८ में ६८४ करोड़ रु० मूल्य की वस्तुएं बाहर से मंगाई गयी थीं। आयात वृद्धि का मुख्य कारण अन्न संकट था। अनाज भी बड़ी मात्रा में बाहर से मंगाया गया। पहले दस महीनों में ही गत वर्ष की इस अवधि की अपेक्षा ३८ करोड़ रु० का अनाज अधिक मंगाया गया।

उर्वरकों के अतिरिक्त आयात से इसकी कुछ सीमा तक बिना पूरी हुई मांग पूरी की जा सकी। आर्थिक हलचल बढ़ जाने का अर्थ यह है कि अधिक परिवहन की भी आवश्यकता होगी। इसलिए ट्रकों का निर्माण करने के लिए उनके हिस्सों के आयात में भी वृद्धि हुई है। वस्त्र तथा अन्य उद्योगों में काम आने वाले रासायनिक पदार्थों का भी हमने अधिक परिणाम में आयात किया है।

कच्चे पटसन के आयात में कमी हुई। वास्तव में पिछले कई वर्षों में, पहली बार पटसन बाहर भी भेजा गया।

१९५८ और १९५९ के कलेण्डर वर्षों (१० महीनों के आंकड़ों के आधार पर) में हमारे आयात व्यापार का जो रूप रहा है, उससे प्रकट होता है कि पूंजीगत वस्तुओं के आधार का कुल आयात में जो प्रतिशत रहता है, वह १९५८ में जहां १८.२ था वहां १९५९ में घटकर १४.५ प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर औद्योगिक वस्तुओं का प्रतिशत ५५.१ से बढ़कर ६१.८ हो गया। यह प्रवृत्ति हमारे औद्योगिक विकास की गति को प्रकट करती है।

लघु उद्योग

लघु उद्योगों की ओर सरकार ने विशेष ध्यान देने का दावा किया है। लघु उद्योगों को ऋण के रूप में देने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त धन दिया गया। जिन १०० औद्योगिक बस्तियों की योजना बनायी गयी थी, उनमें से ९६ के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। चालू वर्ष में लगभग १६ करोड़ रु० की खादी चर्खे के सूत से बनी।

आलोच्य वर्ष में बगीचा उद्योगों की भी संतोषजनक प्रगति हुई। १९५९ के पहले ११ महीनों में उत्तर और दक्षिण भारत में ६८३० लाख पौंड पैदा हुई थी। १९५९ में भारत से ४७२० लाख पौंड चाय का निर्यात हुआ, जबकि १९५८ में ५०६० लाख पौंड का हुआ था।

विविध

गत वर्ष के समान ही आलोच्य वर्ष में भी भारतीय उद्योगों को तटकर संरक्षण देने तथा उचित मूल्य निर्धारित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीसरी योजना में राज्यों का विकास-विनियोजन

जी० एस० पथिक

राज्यों में आर्थिक विकास के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों की इतनी बड़ी आकांक्षाएं और मांगें हैं कि यदि उन्हें मान लिया जाए तो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना पंद्रह या बीस हजार करोड़ रुपए तक पहुँच सकती है। पर भारत के पास आय के इतने स्रोत नहीं हैं कि वह नौ या दस हजार करोड़ रुपए की विकास योजना को आसानी से आगे बढ़ा सके। इस दिशा में राष्ट्रीय विकास कौंसिल का काम बढ़ जाता है और उसे कांट-छांट करनी पड़ती है।

उत्तरप्रदेश

उत्तरप्रदेश की तीसरी योजना सरकारी क्षेत्र में ४८० करोड़ रुपए विनियोजन की है और ८५० करोड़ रुपए निजी क्षेत्र के विनियोजन के लिए हैं। श्रमदान और जन-साधारण की सहायता का मूल्यांकन ६१० करोड़ रुपए है। उत्तरप्रदेश की दूसरी पंचवर्षीय योजना केन्द्रीय योजनाओं के अतिरिक्त २५३ करोड़ रुपए की थी। पर इस वर्ष के बजट में प्रकट किया गया कि योजना का कुल व्यय २२१.६७ करोड़ रुपए से आगे न बढ़ेगा। निजी क्षेत्र में दूसरी योजना के काल में १०० करोड़ रुपए के विनियोजन का अनुमान है। उत्तरप्रदेश के विस्तृत क्षेत्र, भारी जन-संख्या और निर्धनता के खयाल से अन्य राज्यों के अनुपात में—उसका विकास होना वांछनीय है। पर वह बहुत पीछे है। तीसरी योजना में ७० करोड़ रुपए के व्यय से ११५ लाख टन अर्थात् ५५ लाख टन अन्न की उत्पादन वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसमें ६८ करोड़ रुपए बड़ी और मध्यम सिंचाई और ८४ करोड़ रुपए छोटी सिंचाई में व्यय करने का कार्यक्रम है। इससे राज्य की सिंचाई की जमीन का क्षेत्र ४० लाख एकड़ से १६० लाख एकड़ तक पहुँच जाएगा। ३८४ नए उद्योगों का निर्माण करने की बात है, जिससे ६८,००० लोगों को काम मिल सकेगा। वर्तमान उद्योगों में विस्तार सहित ४५० करोड़ रुपए व्यय होंगे।

बम्बई

बम्बई राज्य की दूसरी योजना का व्यय ३५० करोड़ रुपए रखा गया था। औसतन वार्षिक व्यय ७० करोड़ रुपए था। तीसरी योजना के लिए व्यय का प्रस्ताव २२५ करोड़ रुपए का है। इसमें ३७५ करोड़ नए महाराष्ट्र और १७५ करोड़ रुपए गुजरात राज्य के लिए होंगे। बिहार की तीसरी योजना ५०० करोड़ रुपए की है। पर आन्तरी सुझाव ४८० करोड़ रुपए का है, जिसमें निजी विनियोजन भी शामिल है। उत्तर और दक्षिण बिहार में २७ नए उद्योग स्थापित होंगे। कृषि विकास और बाढ नियंत्रण पर अधिक

करने के मामलों की जाँच करने का दायित्व तटकर आयोग पर रहा।

१९५९ में मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गये तीन विधेयक संसद ने पास कर दिये। ये इस प्रकार हैं : दी कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउण्टेण्ट्स बिल, दी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स (एमेण्डमेण्ड) बिल और इण्डियन टैरिफ (एमेण्डमेण्ड) बिल। इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट (कण्ट्रोल) बिल १९५९ और काटन ट्रांसपोर्ट (एमेण्डमेण्ड) बिल संसद में पेश किये जा चुके हैं और आशा है कि अगले वर्ष के आरम्भ में वे पास हो जाएंगे। कम्पनीज (एमेण्डमेण्ड) बिल १९५९ संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है और समिति की रिपोर्ट संसद के अगले अधिवेशन में आ जाने की आशा है।

संसद के अन्य कार्य के अतिरिक्त २,४१२ प्रश्नों (लोकसभा २,०४५ और राज्य सभा ३६७) के उत्तर दिये गये।

कम्पनी कानून पर अमल

१९५९ के पहले ११ महीनों में १८ नयी सरकारी कम्पनियां बनीं। ३० नवम्बर, १९५९ को सरकारी कम्पनियों की कुल संख्या ११३ थी। जनवरी से नवम्बर १९५९ के बीच १,२८४ नयी कम्पनियां रजिस्टर की गयीं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ९४३ कम्पनियां रजिस्टर की गयीं, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ९४३ कम्पनियां रजिस्टर की गयी थीं। रजिस्टर की जाने वाली कम्पनियों की संख्या १९५६-५७ से लगातार बढ़ रही है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जोर दिया गया है। बिहार की दूसरी योजना १६०.२ करोड़ रुपए की थी।

उत्तरप्रदेश की तुलना में नए उद्योगों के निर्माण में बिहार आगे बढ़ा है। भारी मशीनें तैयार करने का कारखाना और फाउंड्री फार्म रांची में और पेट्रोल का कारखाना बरौनी में खुलेंगे, जिनमें भारत सरकार, सोवियत रूस और चेकोस्लोविका का संयुक्त विनियोजन होगा। इसके सिवा सिंदरी के कारखाने और टाटा स्टील कारखाने का विस्तार करने और मध्य आकार के तीन सरकारी औद्योगिक कारखाने खड़े करने के प्रस्ताव हैं।

राजस्थान

राजस्थान की तीसरी योजना करीब २८० करोड़ रुपए की है और केन्द्रीय सरकार से विभिन्न कार्यों के लिए ऋण और सहायता में १७२ करोड़ रुपए मांगे गए हैं। राज्य स्वतः ६३ करोड़ रुपए की पूंजी खड़ी करेगा। विद्युत को प्राथमिकता दी गयी है, जिसमें ५५ करोड़ रुपए व्यय होंगे। राजस्थान में नांगल और कोटला में २,५०० किलोवाट पावर का पहला कारखाना खड़ा हो चुका है। दूसरा २,५०० किलोवाट पावर का कारखाना पूरा होने से उसकी विद्युत शक्ति बढ़ जाएगी। गांधी सागर के बिजली के कारखाने से उसे १०,००० किलोवाट बिजली मिलेगी। राज्य की दूसरी योजना १०५ करोड़ रुपए की थी। इसी अवधि में राज्य में आय के स्रोत ३१ करोड़ रुपए रहे और तीसरी योजना में ६३ करोड़ रखने का प्रस्ताव है।

तीसरी योजना के काल में लक्ष्य है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को स्थान मिल जाए। मध्यप्रदेश की तीसरी योजना ४०० करोड़ रुपए की है। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई है। राज्य २० लाख टन अन्न उत्पादन में वृद्धि करने की आकांक्षा करता है। दूसरी योजना में अन्न उत्पादन लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। सरकारी क्षेत्र में नए उद्योगों के खड़े करने के प्रस्ताव हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने भिलाई के स्टील कारखाने और बिजली के भारी उद्योग की योजना को केवल स्वीकार किया है। सिद्धान्त रूप में एक खाद का कारखाना और दूसरे एल्यूमीनियम के कारखाने के खड़े करने की बात मानी गयी है। २० करोड़ रुपए नए उद्योगों की योजनाओं में व्यय होंगे, जिनमें ५.४५ करोड़ रुपए मध्यवर्ती उद्योगों के लिए रखे गए हैं। दूसरी योजना में उद्योगों की प्रगति प्रभावशाली नहीं हुई। निजी पूंजी का विनियोजन पिछड़ा रहा। मैसूर की तीसरी योजना २७६ करोड़ रुपए की है, जो दूसरी योजना से दुगने आकार की है। दूसरी योजना १४० करोड़ रुपये की थी। इसमें विद्युत और सिंचाई पर बल दिया गया है। मैसूर सिंचाई में बहुत पीछे है। दूसरी योजना में सिंचाई २४ लाख एकड़ तक पहुंच जाएगी। तीसरी योजना के अंत तक ३४.७ लाख एकड़ तक सिंचाई का विस्तार होगा। खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों की पैदावारों में भी वृद्धि करने के लक्ष्य हैं।

मद्रास

मद्रास अपनी दूसरी योजना के व्यय से २० करोड़ रुपए अधिक व्यय करेगा। इसकी तीसरी योजना ३०० करोड़ रुपए की है। इसमें राज्य में केन्द्रीय विनियोजन शामिल नहीं है। मद्रास की अनेक योजनाओं में काफी विदेशी पूंजी लगी। पेरियर के हाइडेल प्रोजेक्ट और मद्रास संकट के पूर्व दिए जा चुके थे। इसलिए उसकी किसी योजना में विदेशी मुद्रा का संकट खड़ा नहीं हुआ। मद्रास में अन्न का उत्पादन १३.७६ लाख टन के लक्ष्य में ६ लाख टन से ऊपर न जा सका। खाद में उपयोग का अभाव रहा। पर अब सिंचाई के नौ बड़े साधन तैयार हो जाने से २.११ लाख एकड़ में खेती का विस्तार बढ़ जाएगा। निजी क्षेत्र में सब बड़े उद्योग खड़े होंगे, जिनमें सोडा कारखाना, रेयन फेक्टरी, रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स, एल्यूमीनियम की भारी मशीनों के निर्माण का उद्योग और रेलवे वैगन आदि के कारखाने हैं।

केरल

केरल की योजना का कुल व्यय संभवतः ३३८.६५ करोड़ रुपए है, जिसमें ३०७.८६ करोड़ रुपए राज्य का सरकारी विनियोजन और अवशेष केन्द्रीय विनियोजन रखा गया है। केरल में कृषि सेवा का विस्तार अत्यन्त प्रयोजनीय है। केरल विदेशी मुद्रा के अर्जन में मूल्यवान व्यापारिक फसलों द्वारा ५० करोड़ देश के लिए उपलब्ध करता है। तीसरी योजना में ३१.०२ करोड़ उद्योगों में व्यय होंगे।

[शेष पृष्ठ २२५ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सर्वोदय पृष्ठ

मैं अज्ञातवास करना चाहता हूँ !

मैं अब गांव में बैठकर कुछ काम करना चाहता हूँ; केवल विचार-प्रचार से अब काम नहीं चलेगा।

गांव में बैठने की मेरी शर्तें निम्न हैं—

(१) हर घर में सर्वोदय पात्र; (२) हर घर में चरखा;

(३) गांव की पूंजीनिर्माण (कैपिटल फारमेशन) के लिए धर्मगोला, जिसमें किसान पैदावार में से प्रति मन एक सेर अनाज देगा; मजदूर हँसिया पीछे एक सेर अनाज और प्रति चरखे से एक गुंडी सूत प्रति माह देगा।

(४) मेरे और मेरे साथ रहने वाले एक परिवार भर के साल भर के खर्च के लिए १२५ मन अनाज (इसमें कुछ अतिथि, फुटकर स्टेशनरी खर्च हो जायगा) लगेगा।

(५) गाँव के सभी लोग गांव की आदर्श सामूहिक खेती के लिए अपनी जमीन का छठा हिस्सा निकालें। खेती करने लायक एक या दो प्लाट में सारे खेत अदला-बदली करके मिलाये जायं। जमीन की मालकियत छोड़ने की बात इसमें नहीं है। पैदावार का बँटवारा खर्च काट कर इस तरह करने की बात है।

६०% मजदूरी की हाजिरी के अनुसार,

३०% जमीन के मालिक को जमीन के अनुपात में,

१०% जमीन की तरक्की के लिए फंड अलग रखा जायगा।

(६) एक या दो परिवारों के भरणपोषण के लायक जमीन गांव वाले ग्राम-स्वराज्य समिति को दान में दें, जिससे उनके साथ रहने वाले परिवार मेहनत करके अपनी आजीविका चला सकें। कितनी जमीन देनी है, इसका निर्णय गाँव वाले जमीन की स्थिति के अनुसार करें।

(७) पूरा समय देने वाला एक अच्छा प्रभावशाली कार्यकर्ता जो सारे काम की व्यवस्था आदि की पूरी जिम्मेदारी ले सके।

—धीरेन्द्र भाई

औद्योगीकरण से बचें

दूसरी बड़ी चीज, जो देश को तेजी के साथ गलत दिशा में ले जा रही है और जहाँ से फिर वापिस मुड़ना उसके

आत्म-निर्भर बनें !

"मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है कि अगर हिन्दुस्तान को सच्चे माने में आजाद होना है, और हिन्दुस्तान की मार्फत दुनिया को, तो आगे या पीछे हमें इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा कि लोगों को गाँवों में रहना है, शहरों में नहीं, झोपड़ियों में रहना है, महलों में नहीं ! करोड़ों लोग शहरों और महलों में कभी एक-दूसरे के साथ शांति-पूर्वक नहीं रह सकते। ऐसा होगा, तो हिंसा और असत्य का सहारा लेने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा।

"मेरी यह भी मान्यता है कि सत्य और अहिंसा के बिना मानव जाति के लिए विनाश के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और सत्य और अहिंसा को हम ग्रामीण जीवन की सादगी में ही प्राप्त कर सकते हैं तथा वह सादगी चरखे में और चरखे से जिन तमाम मूल्यों का हमें भान होता है, उन्हीं में पायी जा सकती है। मुझे इस बात से कोई डर नहीं है कि दुनिया आज गलत रास्ते पर जा रही है। हो सकता है कि हिन्दुस्तान भी उसी रास्ते पर जाये और जैसे पतंगा दीपक की लौ के चारों ओर उत्तरोत्तर अधिक तेजी के साथ नाचता है और अन्ततोगत्वा उसी में भस्म हो जाता है। लेकिन अपनी आखिरी साँस तक हिन्दुस्तान को और हिन्दुस्तान के माध्यम से तमाम दुनिया को इस दुर्गति से बचाना मेरा धर्म है।

"मैंने जो कुछ कहा है उसका सार यह है कि मनुष्य को वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति में सन्तोष मानना चाहिए और उसके लिए आत्म-निर्भर होना चाहिए। अगर मनुष्य इतना संयम नहीं कर सकता तो वह अपने को सर्वनाश से नहीं बचा सकेगा।"

—श्री नेहरू को लिखे गए महात्मा गांधी के पत्रों से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिए कठिन होगा, वह औद्योगीकरण की योजनाएं हैं। विदेशों से लिए जाने वाले कर्जे, देशी और विदेशी पूंजी-पतियों के गठबन्धन का जाल, बड़े-बड़े केन्द्रित उद्योगों के कारण होता जा रहा शहरीकरण और समाज का विघटन, ये सब थोड़े समय में ही प्रजा के हाथ-पाँव बांधकर लम्बे अरसे के लिए उसे गुलाम बना देंगे।

......देहात-देहात में खुलने वाली तेल, चावल आदि की मिलें, या कपड़े व जमाये हुए तेल आदि के कारखाने के खिलाफ जनता को सक्रिय कदम उठाने के लिए संगठित करना चाहिए।...विरोधी योजनाओं का खण्डन न करना बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। जनता भी हमारी बातों को थोड़े दिन में सुनने से इन्कार कर देगी।

—सिद्धराज ढड्ढा

ग्रामदान का वास्तविक रूप

विज्ञापन तो हम करते हैं हजारों ग्रामदान होने का, पर वास्तव में ऐसे बहुत कम गाँव हैं, जहाँ कि लोगों ने यह समझा हो कि उन्होंने ग्रामदान क्यों किया है और अब आगे उन्हें एक सहयोगी जीवन और सुख-दुःख के बटवारे की भावना के आधार पर गरीबी और गुलामी की समस्याओं को हल करने के लिए बढ़ना है। इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान के गांवों में इस नयी भावना के सफल होने के बीज मौजूद हैं, लेकिन वे गाँव सचमुच ग्रामदानी परिवार बनें, इसके पहले बहुत सावधानी के साथ उस भावना के पोषण की आवश्यकता है। ग्रामदान तो एक अमुक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की निरन्तर सेवा और भक्ति के फलस्वरूप प्रकट होना चाहिए। अपनी सतत सेवा के जरिये वे लोगों में आपसी सहयोग और उन सम्बन्धों से पैदा होने वाली एक नयी सुरक्षा का वातावरण बना सकें। इसके विपरीत कार्यकर्त्ताओं से यह आशा रखना कि वे कागज पर ग्रामदान की संख्या बढ़ाते जायें, अनुचित होगा।

—श्री डोमल्ड

शान्ति सैनिकों की सार्थकता

अगर हम गाँव के स्तर पर कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ा सके होते, ताकि थोड़े-थोड़े गाँवों के छोटे क्षेत्र में वे कार्यकर्ता सतत घूमकर लोगों की सेवा करते रहते और उनको नयी समाज-रचना का सन्देश सुनाते रहते, तो विनोबाजी की इस अद्यतन पुकार को एक ही क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में पूरा करने में सफल हुए होते। इसकी बजाय हम शान्ति-सैनिक यह ढूँढ़ते फिरते हैं कि लोगों की क्या और किस प्रकार सेवा करें? शान्ति-सैनिकों के अस्तित्व की कसौटी तो इस चीज में है कि जिन लोगों की वे चुप-चाप और शून्य होकर सेवा करते रहे हों, उन लोगों में अपनी खुद आन्तरिक शक्ति जाग्रत हुई है या नहीं!

युगोस्लाविया में श्रम-सेना

युगोस्लाविया सन् १९४१ से '४५ तक युद्धग्रस्त था। उन दिनों युद्ध के कारण जवान तो खेती का काम नहीं कर सकते थे, वे जन-मुक्ति सेना में काम करते थे; खेतों में फसल खड़ी थी, काटने वाला कोई नहीं था। तो जवान लड़कियां खेतों में आयीं। फौज के डर से वे छिप कर फसल काटती थीं और अनाज के बोरे पीठ पर लाद कर ले जाती थीं।

युद्ध समाप्त होने के बाद सर्वत्र बरबादी थी—घर जलाये गये थे, विद्यालय, पुल, रास्ते आदि नष्ट हो चुके थे। देश को सम्भालना था। श्रमदान-आन्दोलन ने जोर पकड़ा। जो लड़के-लड़कियां कभी श्रम-दान के लिए नहीं गये, वे अपने को समाज में हीन समझने लगे। यह श्रम-सेना एक के बाद एक काम करती गयी। तब इन सैनिकों और देश के नेताओं को सामूहिक शक्ति का दर्शन हुआ। युगोस्लाविया में ४-५ भिन्न-भिन्न कौमें हैं। परन्तु वे अब अपने को एक समझने लगी हैं। इस तरह जब साथ रहने का संस्कार मिला, लोग व्यक्तिगत रूप में एक-दूसरे के निकट आये, तो एक भाईचारे और पारिवारिक वातावरण का निर्माण हुआ।

एक स्थान पर कोयले की खदानें थीं, लेकिन रेल नहीं थी। स्थिति यह थी कि वहाँ अगर रेल का रास्ता बन जाय, तो देश के उद्योग विकसित हों, और वहाँ के लोगों को काम मिले। श्रम-सेना ने नब्बे मील लंबी रेल बनानी आरम्भ की। मिट्टी काट कर लाइन पर डाली, पत्थर काट कर बिछाये, २२ पुल बनाये और दो 'टनेल' खोदे। ६२ हजार जवान और बाकी सरकारी विशेषज्ञों ने काम किया। सन् १९४६ से १९५२ तक ११ रेलवे लाइनें, १४ कारखाने, ५ हैड्रीलेकेरफ स्टेशन, विद्यार्थी गृह, खेल-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कूद के मैदान आदि बनाये गये।

सन् १९५८ में राष्ट्रपति टीटो की प्रेरणा से 'नेशनल हाई वे' बनाने का काम आरम्भ हुआ। यह मार्ग देश के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के मध्य तक यूरोप को यूनान से मिलाने वाला ६७० मील लम्बा मार्ग होगा। जवानों ने जब यह सन्देश सुना, तो दो लाख नाम आ गये! केवल ५० हजार जवानों को ही काम मिल सका। सन् १९६२ में यह कार्य खतम होने की सम्भावना है। जो कार्य सरकारी योजना के अनुसार दस बरस में समाप्त होता, वह श्रम-सेना चार वर्ष में पूरा करेगी!

वहाँ के नेता समय-समय पर जाकर इन लोगों से मिलते हैं, उनका भविष्य बनाने में श्रम-सेना का कार्य मदद करता है। जहाँ नेता काम में जुटा हो, वहाँ अवाम अवश्य जुटता है। इसके अलावा इन देशों में राष्ट्रीय निर्माण की एक विशेष प्रवृत्ति भी दिखायी पड़ती है। इस तरह अगर हम भी विद्यार्थियों से, देहाती नवजवानों से महीने-दो महीनों की माँग करें और कहें कि वे छः घंटे काम, दो घंटे पढ़ाई करें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है।

—द्वारको सुन्दरानी

जागृति

प्रत्येक अङ्क में जीवन को ऊंचा उठाने वाले लेख, कहानियाँ, कविताएं।

इनके अतिरिक्त बाल-संसार, साहित्य आगे बढ़ता है, आदि स्थायी स्तम्भ

सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर : बहुरंगे चित्र

सूल्य एक प्रति २५ नए पैसे, वार्षिक ३ रु० ५० नए पैसे

एजेन्सी की शर्तें—

५ से १०० कापियाँ मँगवाने पर २५ प्रतिशत और १०१ या ज्यादा कापियाँ मँगवाने पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक खर्च हमारे जिम्मे।

व्यवस्थापक 'जागृति' हिन्दी

सूचना विभाग, चण्डीगढ़

[पृष्ठ २२२ का शेष]

पंजाब की तीसरी योजना ४६८ करोड़ रुपए की है। योजना आयोग ने उसे २४० करोड़ रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया। प्रस्ताव है कि नांगल का वर्कशाप एक करोड़ रुपए की पूंजी से स्टील फैक्टरी में परिणत कर दिया जाए। सारे देश की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ५ करोड़ रुपए की पूंजी से छोटे उद्योगों को खड़े करने की योजनाएं हैं। इसके सिवा अखबारी कागज और सीमेण्ट के कारखाने खड़े करने की भी योजनाएं हैं। पंजाब २८.६४ करोड़ रुपए व्यय करना चाहता है, जिससे परती जमीन खेती में आ जाए। उसका लक्ष्य है कि अन्न का उत्पादन (५६.४१ लाख टन से) ७४ लाख टन गन्ने का ७.८० लाख टन से ६ लाख टन, रुई का १०.५० लाख टन से १३ लाख टन, तेलहन का १.८५ लाख टन से २.५० लाख टन और फल तथा साग-सब्जी का ५.६० लाख टन और १२.५० लाख टन तक क्रमशः पहुंच जाए।

पश्चिमी बंगाल

पश्चिम बंगाल की दूसरी योजना में राज्य के सरकारी क्षेत्र में दुर्गापुर कोयले की भट्ठी खड़ी करने का था। दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग दुर्गापुर में थर्मल पावर स्टेशन निर्माण करने का है। हार डिस्टीलेशन कारखाने खड़े करने की घोषणा हो गई है। दुर्गापुर से कलकत्ते तक गैस लाने की योजना भी केन्द्र ने स्वीकृत कर दी है। ये सब योजनाएं दूसरी योजना के अन्तर्गत नहीं थीं। बंगाल की तीसरी योजना ४८० करोड़ रुपए की थी, उसका लक्ष्य था कि इस विस्तार से वह केन्द्र के खड़े हुए ऋण को रोके रखेगा। परन्तु योजना आयोग ने २४० करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की। पश्चिम बंगाल में खाद्य का संकट केरल के समान ही है। दूसरी योजना में १७.७ प्रतिशत विनियोजन कृषि और सामूहिक विकास के लिए रखा गया था और दूसरा स्थान सिंचाई का था, जिसमें कुल विनियोजन का १३.६ प्रतिशत अंश था। राज्य ने १२५ करोड़ रुपए की योजना कृषि विस्तार के लिए तैयार की थी, जिससे कि ४० लाख टन से ६०.५ लाख टन अन्न प्रतिवर्ष पैदा होने लगे और १९६६ तक यह प्रदेश अन्न के विषय में आत्मनिर्भर होजाए।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सांख्यिकी

विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति के वर्ष

प्रो० डब्ल्यू० डब्ल्यू० रोस्टो के अनुसार राष्ट्रों के विकास में एक ऐसा समय आता है जब आर्थिक प्रगति असाधारण रूप से तीव्र हो जाती है । इस समय में राष्ट्र विशेष का आर्थिक-तंत्र ऐसा रूप ले लेता है कि चिर आर्थिक उत्पादन एक स्तर तक अपने आप होते रहते हैं । निम्न तालिका में विभिन्न देशों के उक्त तीव्र आर्थिक प्रगति के वर्षों को दर्शाया गया है—

राष्ट्र	तीव्र आर्थिक प्रगति के वर्ष
इंग्लैंड	१७८३-१८०२
फ्रांस	१८३०-१८६०
बेल्जियम	१८३३-१८६०
संयुक्त राज्य अमेरिका	१८४३-१८६०
जर्मनी	१८५०-१८७३
स्वीडेन	१८६८-१८९०
जापान	१८७८-१९००
रूस	१८९०-१९१४
कनाडा	१८९६-१९१४
अर्जेन्टाइना	१९५३ —
टर्की	१९३७ —
भारत	१९५२ —
चीन	१९५२ —

भारत और यूरोप में ट्रैक्टरों की संख्या

१९५७ में यूरोप के विभिन्न देशों में तथा भारत में अलग-अलग कुल कितने ट्रैक्टर उपयोग में आते थे तथा एक ट्रैक्टर के पीछे कितनी भूमि पड़ती थी, यह निम्न-तालिका में दर्शाया गया है—

देश	ट्रैक्टर (हजारों में)	प्रति ट्रैक्टर भूमि (हैक्टरों में)
इंग्लैंड	४३६*	१६
जर्मनी	१३८	२१
फ्रांस	१३५	४५
इटली	६६	८४
स्वीडेन	१३४	२७
डेन्मार्क	७७	३१
आस्ट्रिया	७९	३२
चैकोस्लोवेकिया	५३	१०२
हंगरी	२६	२१९
रूमानिया	३८	२६६
यूगोस्लेविया	२१	४०४
बल्गेरिया	२७	१०६
ग्रीक	१०*	३६
यूरोप	२,५८६	५८
रूस	९११	२४४
भारत	१८*	८,५८४
अमेरिका	४,६८५	४०
विश्व	८,७२८	१३४

*१९५६ के आँकड़े

भारत और यरोप में सिंचाई का क्षेत्रफल

१९५७ में यूरोप के विभिन्न देशों में और भारत में खेती योग्य भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में सिंचाई होती थी, निम्न तालिका में दर्शाया गया है । स्पष्ट है कि न केवल कुल सिंचित क्षेत्रफल में बल्कि सिंचित भूमि के प्रतिशत में भी भारत यूरोप के देशों से आगे था—

देश	क्षेत्रफल (हजार हैक्टरों में) कृषि योग्य भूमि	सिंचित भूमि	प्रतिशत सिंचित भूमि
भारत	१५८,३४१	२२,७३८	१४.३६
फ्रांस	२१,३२५	२७	०.१३
ग्रीक	३,५३०	३५०	९.९२
हंगरी	५,७६०	७८	१.३५
बल्गेरिया	४,२८६	३.६०	८.४०
इटली	१५,७८१	१२६	०.८०
पुर्तगाल	४,१३०	३६	०.८७
स्पेन	२०,५८५	१७५२	८.५१
यूगोस्लेविया	८,२९०	८७	१.०५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ-वृत्त चयन

दुग्ध शालाएँ

डेयरियों के कार्यक्रम ने इस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति की। दिल्ली मिल्क स्कीम १ नवम्बर, १९५९ से अंशतः चालू हो गयी। मद्रास के पास माधवरम की मिल्क कालोनी भी ४ नवम्बर १९५९ से शुरू हो गयी। कलकत्ता के पास हरिणघाटा की मिल्क कालोनी में पशुओं की संख्या बढ़ा दी गयी और वहां प्रतिदिन लगभग १३०० मन दूध सम्भाला जाने लगा। बम्बई की आरे-मिल्क-कालोनी यथा-पूर्व प्रतिदिन लगभग ५००० मन दूध सम्भालती रही। पूना, गण्टूर, चण्डीगढ़, गया, त्रिवेन्द्रम, भोपाल, अगरतला और कोयम्बतूर के डेयरी कार्यक्रमों में भी और प्रगति हुई। देश के अन्य भी कई नगरों में डेयरी के काम प्रगति कर रहे हैं। अमृतसर और राजकोट में २ कारखाने दूध की वस्तुएं बनाने के और बरौनी, जूनागढ़ और अलीगढ़ में ३ देहाती क्रीमरियाँ खोलने के भी प्रयत्न चल रहे हैं। देश के डेयरी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को बनाने के लिए न्युजीलैंड सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल-सहायता कोश और अमरीका के टेक्निकल-कोआपरेशन-मिशन से बड़ी मात्रा में सहायता मिली है। इस वर्ष दिल्ली-मिल्क-स्कीम के लिए ७७.३ लाख रु० और देश की अन्य नयी पुरानी दूध-योजनाओं के लिए २७५ लाख रु० की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में रक्खी गयी थी।

पाकिस्तान में भारतीय निजी पूंजी

१९५५ के अन्त में पाकिस्तान में भारतीय व्यापारियों का कुल १७ करोड़ ८३ लाख रु० लगा हुआ था। इसमें से १७ करोड़ ५६ लाख रु० भारतीय ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियों ने पाकिस्तानी कम्पनियों के हिस्सों, हुंडियों आदि में लगा रखा था। इसके अलावा भारत में रहने वाले व्यक्तियों ने बैंकों की मार्फत पाकिस्तानी कम्पनियों के हिस्सों आदि में और वहाँ की कम्पनियों में भारतीय साझेदारों ने कुल २७ लाख रु० लगा रखा था। उक्त तारीख के बाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार इन आंकड़ों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। अब सरकार लोगों को पाकिस्तान में पूंजी लगाने की अनुमति नहीं देती।

जनसंख्या की वृद्धि और भोजन

कांग्रेस की ओर से प्रकाशित 'आर्थिक समीक्षा' में निम्न पंक्तियों के साथ निम्नलिखित सूची दी गई है। यह पाया गया है कि जिन देशों के भोजन में प्राणीय प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, वहां जनसंख्या की वृद्धि का परिमाण धीमा होता है। इसके विपरीत जिन देशों में प्राणीय प्रोटीन कम खाया जाता है, वहां जनसंख्या कुछ तेजी से बढ़ती है।

नीचे के अंकों की तुलना कीजियेः—

देश	जन्म परिणाम	प्राणीय प्रोटीन का दैनिक भोजन में परिमाण (ग्रामों में)
फारमोसा	४५.६	४.७
मलय राज्य	३६.७	८.५
भारत	३३.६	८.७
जापान	२७.०	९.७
यूगोस्लाविया	२५.९	११.२
यूनान	२३.५	१५.२
इटली	२३.४	१५.२
बल्गेरिया	२२.२	१६.८
जर्मनी	२०.०	३७.३
आयरलैण्ड	१९.१	४६.३
डैन्मार्क	१८.०	५९.१
आस्ट्रेलिया	१८.०	५९.९
संयुक्त राज्य अमेरिका	१७.९	६१.४
स्वीडन	१५.०	६२.६

यदि प्राणीज प्रोटीन का इतना ही प्रभाव पड़ता हो तो प्राणीय प्रोटीन स्वागत योग्य है या हानिकर, ?

भारत के निजी क्षेत्र में विदेशी पूंजी

१९५४-५५ में कुल १७ करोड़ ६० लाख रु०, १९५६ में ३६ करोड़ ८० लाख रु०, १९५७ में ४८ करोड़ ६० लाख रु० और १९५८ में २७ करोड़ ६०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाख रु० (अस्थायी आंकड़े) की विदेशी पूंजी लगी। इसमें विदेशी बैंकों की पूंजी शामिल नहीं है।

इस पूंजी का देशवार ब्यौरा इस प्रकार है:—

(करोड़ रु० में)

देश का नाम	१९५४-५५ (वार्षिक अनुपात)	१९५६	१,९५७	१९५८ (लगभग)
ब्रिटेन	९.६	१५.६	६.३	१.२
अमेरिका	४.९	७.१	१०.४	२.९
जर्मनी	१.२	०.२	०.८	०.१
स्विटजरलैंड	०.३	१.६	१.५	०.२
अन्य देश	०.२	०.१	०.९	०.६
अन्तर्राष्ट्रीय बैंक	१.४	१२.१	३२.०	२५.३
जोड़	१७.६	३६.८	४८.९	२७.९

चूहों द्वारा एक ही रात में पूरी फसल का सफाया

अकाल पीड़ित मिजो पहाड़ी बड़े क्षेत्र में चूहों ने रातोरात धान की पूरी फसल बरबाद कर दी है, जिससे वहां गल्ले का संकट उत्पन्न हो गया है। मिजो पहाड़ी क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव डिवीजन से सटा हुआ है।

आसाम मुख्य मंत्री ने बताया है कि चूहे अब भी जनता के १ नम्बर के दुश्मन बने हुए हैं। दिन के समय वे दिखायी नहीं देते, किन्तु रात को खुलकर धान की फसल बरबाद करते हैं। वे चूहे अब आधुनिक विज्ञान के लिए भारी चुनौती बन गये हैं, क्योंकि चूहे मारने के सब साधन उनके सामने व्यर्थ प्रमाणित हो रहे हैं। देश के बजट पर चूहा आक्रमण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

योरोपीय मुक्त व्यापार संघ

योरप में विभेदरहित एक हाट की स्थापना के लिए योरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन या योरोपीय मुक्त व्यापार संघ नामक नया संगठन सात राष्ट्रों—ब्रिटेन, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, स्विज़रलैंड, आस्ट्रिया तथा पुर्तगाल—के मंत्रियों में सोच-विचार के परिणामस्वरूप गत जुलाई में स्थापित हुआ था। जन्म से ही इस संगठन की प्रगति की रफ्तार संतोषजनक रही है।

स्वाभावतः उत्पन्न होने वाला एक प्रश्न यह है कि एक ओर इस संगठन और दूसरी ओर योरोपीय आर्थिक संगठन—या सामान्य हाट—सम्बन्धी छः देशों के बीच सम्बन्ध क्या और कैसे होंगे? उभय संगठनों के सम्बन्धों के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय लिए जाने से पहले सुदीर्घ विचार-विनिमय की सम्भावना पाई जाती है। विचारणा की शुरूआत गत दिसम्बर में, पेरिस में पश्चिमी राष्ट्रों के "शीर्षस्थ" सम्मेलन के दौरान हुई। तभी इस आधार-तुल्य तथ्य पर सहमति देखने में आयी थी कि योरप के दो आर्थिक गुटों के मध्य प्रतिद्वंदिता नितान्त अवांछनीय बात होगी। इन दोनों के मध्य सन्तोषप्रद सम्बन्धों की स्थापना की आवश्यकता निर्विवाद है।

इस समस्या के महत्व को मानते और जानते हुए भी, सम्बद्ध सातों राष्ट्र ने, इस संस्था को मजबूत बनाने, तथा सदस्य-देशों के बीच तगड़े सम्बन्ध बनाने-बैठाने, का दृढ़ निश्चय कर लिया है।

आप 'सस्ता साहित्य मंडल' की पुस्तकों के प्रेमी हैं। सस्ता साहित्य के व्यापक प्रसार में कृपया योग दीजिये। अपने इष्ट मित्रों, अपने क्षेत्र की संस्थाओं तथा पुस्तकालयों से अनुरोध कीजिये कि वे 'मंडल' की पुस्तकें अपने यहाँ अवश्य रक्खें।

पर ऐसा आप तभी कर सकेंगे
जबकि
'मंडल' के नये प्रकाशनों से
आपका परिचय रहे। इसके लिए आप
जीवन-साहित्य
के ग्राहक बन जाएं उसके प्रत्येक अंक में 'मंडल' के
नवीनतम प्रकाशनों की सूचनाएं रहती हैं
पत्र की सामग्री भी अत्यन्त उपादेय है
वार्षिक मूल्य केवल रु. ४.००

सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे उद्योग

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

कोई भी संगठित उद्योग बहुत बड़ा उद्योग हो सकता है, इसका एक उदाहरण हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड है। इसकी गत वर्ष की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि १९५९ में साबुन, वनस्पति, ग्लीसरीन तथा अन्य सामग्री ४१ करोड़ ७५ लाख रुपये की उत्पन्न हुई, जबकि १९५८ में ३६ करोड़ ७३ लाख रुपये का उत्पादन हुआ था। इसी वर्ष सर्फ का उत्पादन आरम्भ हुआ जो सारे देश में प्रसिद्ध हो गया। भिन्न भिन्न शृंगार प्रसाधनों—साबुन, बालों का तेल, पाउडर और स्नो-क्रीम आदि का उत्पादन भी इस वर्ष बढ़ा। करीब ४१ लाख रुपये का १६६४ टन वनस्पति और ४० लाख रुपये की ग्लीसरीन का निर्यात भी इस कम्पनी ने किया। मूंगफली के तेल और खली का निर्यात भी आरम्भ किया गया।

इस कम्पनी को इस वर्ष कर लगाने से पहले ४ करोड़ १६ लाख ८५ हजार रुपये का लाभ हुआ और इसमें से २ करोड़ ८ लाख ५० हजार करों के रूप में सरकार को दिया गया, जब कि गतवर्ष १९५८ में १ करोड़ ७७ लाख ७५ हजार रुपये करों में दिए गये थे। शेयर होल्डरों को डिविडेंड के रूप में १ करोड़ ३३ लाख ६८ हजार रुपये बाँटे गये। शेष लाभ ७४ लाख ६७ लाख रुपया कारोबार में फिर लगा दिया गया। इस कम्पनी की कार्यशील पुंजी ८ करोड़ ९६ लाख १८ हज़ार रुपये है।

स्विस एयर की प्रगति

१९५९ में स्विस एयर ट्रांसपोर्ट कम्पनी की कुल आय २७८० लाख स्विस फ्रैंक रही, जो कि १९५८ में २५२० लाख स्विस फ्रैंक थी। उक्त अवधि में कुल व्यय २७०० लाख स्विस फ्रैंक रहा, जब कि १९५८ में २४७० लाख स्विस फ्रैंक था। कुल लाभ ७,४९८,११० स्विस फ्रैंक रहा।

कम्पनी के हिस्से दारों को ६ प्रतिशत डिविडेंड दिया गया, ८००,००० सुरक्षित मद में और १० लाख स्विस फ्रैंक कर्मचारियों के कल्याण कार्यों के लिए रखा गया।

बिस्कुट उद्योग

यद्यपि नगरों में बिस्कुटों का प्रचार शनैः शनैः बढ़ रहा है तथापि अधिकांश लोग, विशेषकर गांवों में गुड़ और चीनी की विविध मिठाइयां ही खाते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा प्रति-व्यक्ति बिस्कुटों की बहुत कम खपत हो। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ०.०७ पौंड बिस्कुटों की खपत है जब कि अमेरिका और ब्रिटेन में खपत क्रमशः २१ और २०.४ पौंड है। बिस्कुट निर्माता संघ के अध्यक्ष श्री ए.सी. खन्ना के अनुसार भारत में बिस्कुट की कम खपत का एक कारण उसके उत्पादन व्यय की अधिकता है। यहाँ प्रति हंडरवेट आटा २८ रुपये चीनी ५६ रुपये और वनस्पति १३७ रुपये होती है, जब कि ब्रिटेन में ये संख्याएं बहुत कम—अर्थात क्रमशः २२ रुपये, ४४.६० और ७१ हैं। पेकिंग खर्च भी भारत में इंग्लैंड की अपेक्षा बहुत अधिक है। यदि उद्योग को बढ़ाना अभीष्ट हो तो सरकार को करों में कमी करनी चाहिए और अन्य सुविधाएं देनी चाहिएं।

मिठाई-उद्योग

पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन उद्योगों ने पंचवर्षीय योजनाओं के चरम लक्ष्य पार कर लेने में सफलता प्राप्त की है, उनमें मिठाई उद्योग भी एक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष १९५५-५६ में ७८४० टन मिठाई तैयार हुई थी। द्वितीय योजना में १९६०-६१ का लक्ष्य १०,००० टन है, लेकिन एक वर्ष पूर्व ही इस उद्योग ने १२००० टन मिठाई तैयार कर ली है। इस उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री मोहनलाल ने बताया है कि उद्योग की वास्तविक क्षमता ५१००० टन बनाने की है, जबकि अभी केवल २५ प्रतिशत क्षमता ही काम में आ रही है। तीसरी योजना में भी लक्ष्य २५००० टन रखा जा रहा है, जो बिना विस्तार किये ही वर्तमान उद्योग पूरी कर सकता है आवश्यकता केवल यह है कि उद्योग को चीनी व अन्य कच्चा माल मिलने में असुविधा न भोगनी पड़े। इस उद्योग को बड़ी भारी शिकायत है कि सरकारी कण्ट्रोल आदि के कारण चीनी उचित मूल्य में नहीं मिल पाती।

● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी अर्थ-चर्चा

जर्मन जनवादी लोकतंत्र की प्रगति

१९५० से लेकर १९५८ तक जर्मन जनवादी लोकतंत्र ने अपना औद्योगिक उत्पादन २४१ प्रतिशत बढ़ा दिया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गत महायुद्ध में जर्मनी के इस भाग का भीषण ध्वन्स हुआ था। जब जर्मनी के दो भाग कर दिये गये तब उद्योग प्रधान देश पश्चिमी जर्मनी की सीमा में आ गये। इसलिए स्वभावतः पूर्वी जर्मनी ने अपने औद्योगिक विकास के लिए आर्थिक प्रयास किया है।

आज लिंगनाइट उद्योग में इस जनवादी गणराज्य का विश्व में प्रथम स्थान है। कास्टिक सोडा के उत्पादन में इसका स्थान पांचवा और रासायनिक उद्योग में इसका छठा स्थान है। १९५० में कुल राष्ट्रीय आय में उद्योग भाग ५५.६ प्रतिशत था। किन्तु आज यह बढ़कर ६४.८ हो गया है। १९५८ में कुल औद्योगिक उत्पादन ५,८५,००० लाख हुआ था जो १९५५ से २८ प्रतिशत और १९५० से १४१ प्रतिशत अधिक है। भवनों का निर्माण, नये कारखानों की इमारतें आदि इस वर्ष में कल्पनातीत संख्या में बढ़ीं। १९३८ में १९५५ की अपेक्षा दुगने घर बनें। कृषि तथा कृषि उद्योगों की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि उत्पादन में सफलता का श्रेय किसानों के स्वेच्छापूर्वक परस्पर मिलकर काम करने को है। किसानों की सहयोग समितियां लगातार बढ़ रही हैं। और अपना उत्पादन तीव्र गति से बढ़ा रही हैं। १९५८ में एक एकड़ पर १ मीटर टन अनाज पैदा हुआ। पशुओं के उत्पादन और उनके बध तथा दूध और अंडे के उत्पादन में भी व्यय वृद्धि नहीं हुई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए मशीनों और ट्रैक्टरों का बहुत सहयोग रहा।

विदेशी व्यापार १९५८ में १४३० करोड़ रूबल का हुआ जो जो १९५५ से ४५.६ प्रतिशत अधिक है। १९५७ की अपेक्षा १९५८ में निर्यात विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ है उनके मुख्य रूप से कृषि यंत्र, मछली पकड़ने के ट्रौलर और मुद्रण की मशीनें आदि हैं।

शिक्षा, स्वास्थ आदि समाज सेवाओं पर अब बहुत ही ध्यान दिया जा रहा है। प्रति व्यक्ति यह व्यय ८८८ मार्क हुआ है। सांस्कृतिक कला केन्द्रों का प्रचार भी बहुत बढ़ गया है। मृत्यु संख्या का अनुपात कम होता गया है। इस तरह पूर्वी जर्मनी चतुर्मुखी उन्नति कर रहा है।

फिल्म उद्योग में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

ब्रिटेन तथा अमेरिका द्वारा मिलकर निर्मित फिल्में, फ्रांस तथा इटली के संयुक्त फिल्म-प्रयास, ऐसी फिल्में जिनमें पांच या छः देशों के अभिनेता-अभीनेत्रियां भाग लेती हैं, तथा किसी एक देश की फिल्म जिसकी शूटिंग दूसरे देश में की जाती है—निस्संदेह फिल्मों के अन्तर्राष्ट्रीयपन में वृद्धि हो रही है।

उदाहरण के लिये लीजिये "पावर अमंग मेन" नामक फिलम, जिसके निर्देशक ब्रिटेन के थोरोल्ड डिकिन्सन हैं। कई समारोहों में पुरस्कृत इस फिल्म में सृष्टि और संहार, निर्माण और नाश, की मानव शक्ति का मार्मिक चित्रण है। संयुक्तराज्य अमेरिका के जे० सी० शियर्स, इटली के जी० एल० पालिदारो, चेकोस्लोवाकिया के एलेक्जेंडर हैम्मिड तथा भारत के वी० आर० शर्मा की सहायता ब्रिटिश निर्माता डिकिन्सन को प्राप्त हुई है।

विजेता विलियम तथा इंग्लैंड पर उसके हमले, की कथा पर एक विशेष रूप से आकर्षक फिल्म बनाने की योजना सर्वराष्ट्रिक प्रयास का और भी एक उदाहरण ठहरी। अमेरिकन फिल्म निर्माता क्लाड हेलमैन को इस फिल्म के लिये कम से कम आठ देशों का सहयोग प्राप्त होगा, अन्य भी अनेक प्रसिद्ध फिल्मों के निर्माण में अनेक राष्ट्रीय सहयोग मिलता रहा है।

ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति

ब्रिटेन की आर्थिक उन्नति जानने के लिए निम्नलिखित अंक उपयोगी होंगे—

- १९५९ में मजदूरों के वेतनों का निर्देशक अंक १ प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि मूल्यों में बहुत ही कम वृद्धि हुई है।
- उद्योगों का अनुपात १९५८ में निम्नलिखित रहा—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	प्रतिशत अनुपात
इंजिनियरिंग उद्योग	४१.६
रसायन	८.८
धातु उद्योग	८.६
वस्त्र उद्योग	८.२
कपड़ा और चमड़ा	४.७
भोजन, शराब तथा तमाखू	११.१
अन्य	१६.७

युद्ध से पूर्व १९३७ में इंजीनियरिंग और वस्त्र उद्योग का अनुपात क्रमशः २६.२ और १२.८ था। नवम्बर से जनवरी तक के तीन महीनों में निर्यात ११ प्रतिशत बढ़ गया।

जनवरी में भारत ने इंग्लैंड से ५ लाख ६५ हजार पौंड के हवाई जहाज या पुर्जे खरीदे।

अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व

संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों का बहुत महत्व है।

'एक स्वतन्त्र और समृद्ध राष्ट्र की हैसियत से (संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के) अस्तित्व के लिए, दक्षिण अमेरिका अत्यधिक—शायद जीवन्त—महत्त्व का है।...हमारे कुल निर्यात का लगभग एक-चौथाई अंश इस भाग से आता है। दक्षिण अमेरिका में व्यक्तिगत अमेरिकी पूंजी कुल मिलाकर ६ खरब ५० करोड़ डालर के आश्चर्यजनक स्तर तक पहुँच गयी है।...कैरिबियन द्वीप समूह और पनामा नहर पर हमारे अधिकार के बिना संयुक्तराष्ट्र अमेरिका आक्रमण के लिए खुला रह जायगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा में हमारे पक्ष के दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों के बीस वोट काट लिये जायं तो हम कहां के रह जायंगे?...हर बात में यह कहना पड़ेगा—'अगर दक्षिण अमेरिका हमारे पक्ष में न हो तो हमारी दुर्दशा हो जायगी।' दक्षिणी अमेरिका के माल और बाजार से महरूम रहे तो अमेरिका दूसरी श्रेणी का राष्ट्र भर रह जायगा।'

न्यूयार्क टाइम्स में, श्री मैथ्यूज के इस उद्धरण से स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व का कुछ और स्पष्ट अनुमान निम्नलिखित आंकड़ों से हो सकता है।

१—दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों के उद्योग-धन्धों और बागान में लगी हुई सारी विदेशी पूंजी का ४।५ हिस्सा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। अमरीकी तेल कम्पनियां समस्त तेल स्रोतों के तीन चौथाई भाग की मालिक हैं। चिली देश के तांबे का ९२ प्रतिशत भाग अमेरिका की दो शक्तिशाली कम्पनियों, अनाकोण्डा और केन्नीकोट के हाथ में है। ब्राजील की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के ८० प्रतिशत भाग पर अमेरिकी पूंजी का अधिकार है। केला बागान की प्रसिद्ध इजारेदार कम्पनी—यूनाइटेड फ्रूट कम्पनी—कैरीबियन सागर के सभी जनतंत्रों में बागान की मालिक है।

२—दक्षिणी अमेरिका के सभी राष्ट्रों को अपने आयात-निर्यात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इन राष्ट्रों के कुल निर्यात का ४६ प्रतिशत लेता है और ५० प्रतिशत आयात करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पर इन राष्ट्रों की निर्भरता इसलिए और भी गहरी है कि ये राष्ट्र अधिकांशतः एक या दो चीजें ही विदेशों को बेचने के योग्य हैं, उदाहरणार्थ, वेनेजुएला से तेल ब्राजील से कहवा (काफी), अर्जेन्टाइना से गेहूँ, चिली से तांबा और शोरा चीनी (शक्कर) और कई राज्यों से केला भी विदेशों को भेजा जाता है। अमेरिका इनका मुख्य खरीदार है।

भारत और यूरोप के देशों की राष्ट्रीय आय

यूरोप के प्रमुख नौ देशों और भारत की राष्ट्रीय आय में १९५० से अब तक कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, वह निम्न तालिका से स्पष्ट है—

राष्ट्र	राष्ट्रीय आय
पश्चिमी जर्मनी	७.९८
आस्ट्रिया	६.३१
इटली	५.२१
नीदरलैंड्स	४.८१
फ्रांस	४.७५
नार्वे	३.६८
बेल्जियम	३.२८
इंगलैंड	२.७१
डेन्मार्क	२.२६
भारत	३.१७

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया निर्माण

प्रायः प्रति सप्ताह देश के विविध राज्यों से उद्योग, कृषि, खादी, बांध, योजनाएं, विद्युत-शक्ति और सामुदायिक विकास आदि प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में नये से नये उत्साहवर्धक समाचार मिलते रहते हैं। इनसे मालूम होता है कि देश में चतुर्मुखी उन्नति हो रही है और देश के जन-जन विशेष कर किसान में एक नई चेतना व स्फूर्ति का संचार हो रहा है। इसी जानकारी के लिए हम कुछ एक समाचार नीचे दे रहे हैं—

सूरतगढ़ का कृषि फार्म

राजस्थान के मरुस्थल में सूरतगढ़ में एशिया के सबसे बड़े यांत्रिक कृषि-फार्म ने विगत ३ वर्षों में पर्याप्त प्रगति की है। १९५७-५८ में जहां १,८६३ एकड़ में खरीफ की बुवाई हुई थी, किन्तु १९५९-६० में ६,९९० एकड़ क्षेत्र में खेती हुई है। १९५७-५८ में रबी की फसल २,४८४ एकड़ में हुई थी, किन्तु १९५९-६० में रबी की फसल २४,४९० एकड़ क्षेत्र में हुई। यद्यपि आरम्भ में फार्म की स्थापना में रूसी विशेषज्ञों ने भी अपने तकनीकी ज्ञान से सहायता दी थी, किन्तु फार्म का प्रबन्ध अब पूर्णतः भारतीय कर्मचारियों के हाथ में है, जिनकी संख्या लगभग ३०० है।

इस फार्म में उन्नत चीजों के उत्पादन के अतिरिक्त फलों की खेती, मुर्गी-पालन, पशु-पशुपालन और इसी प्रकार की अन्य योजनाएँ भी कार्यान्वित होंगी।

एक एकड़ में २४ २४ मन गन्ना

नैनीताल के एसकर्ट फार्म के श्री पी० एन० मेहता को वर्ष १९५८-५९ में एक एकड़ भूमि में

श्रम साधक : सबसे बड़ा भक्त

परमहंस के वचनामृत पर आधारित इस लघु कथा में श्रम का महत्त्व साकार हो उठा है।

एक बार नारद जी वैकुण्ठ आए, तो उन्होंने देखा कि विष्णु चित्र बनाने में निमग्न हैं। चित्रलीन विष्णु ने नारद जी की ओर दृष्टिपात नहीं किया। नारद जी को विष्णु का यह व्यवहार बड़ा अपमान जनक प्रतीत हुआ। उन्होंने लक्ष्मी जी से पूछा—"आज विष्णु किसका चित्र बना रहे हैं?" लक्ष्मी ने कहा—"अपने सबसे बड़े भक्त का—आपसे भी बड़े भक्त का!"

नारद जी ने पास जाकर देखा, तो आश्चर्य-स्तब्ध हो गये। विष्णु एक मैले-कुचैले अर्द्ध-नग्न मनुष्य का चित्र बना रहे थे। नारद क्रोध में उल्टे पांव भूलोक की ओर चल पड़े। कई दिनों के भ्रमण के बाद एक चमार दिखाई दिया, जो गन्दगी और पसीने से लथपथ चमड़ों के ढेर को साफ कर रहा था। पहली दृष्टि में ही नारद ने पहचान लिया—विष्णु उसी का चित्र बना रहे थे। नारद की उत्सुकता बढ़ी और वे दूर से ही चमार की दिनचर्या का निरीक्षण करने लगे।

संध्या होने को आई, किन्तु वह चमार न तो मन्दिर में गया और न आंख मूंदकर उसने क्षण भर के लिए हरि स्मरण ही किया। नारद के क्रोध की सीमा न रही। आवेशांध हो विष्णु को शाप देने के लिए उन्होंने अपना तेजस्वी बाहु ऊपर उठाया ही था कि लक्ष्मी ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया—"देव, भक्त की उपासना का उपसंहार तो देख लीजिये।"

चमार ने चमड़े के ढेर को एक गठरी में बांधा। फिर एक मैले कपड़े से सिर से पैर तक शरीर पोंछा और गठरी के सामने झुककर कहने लगा—"प्रभो दया करना, कल भी मुझे ऐसी ही सुमति देना, कि आज की तरह ही पसीना बहा कर तेरी दी हुई इस चाकरी में सारा दिन गुजार दूं।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

२,४२४ मन गन्ना पैदा करने के लिए १,५०१ रुपया नकद तथा महात्मा गांधी स्वर्णट्राफी की प्रतिमूर्ति देकर पुरस्कृत किया गया है। वर्ष १९५७-५८ में एक एकड़ भूमि में १,६०३ मन गन्ना पैदा करने के उपलक्ष में बस्ती के श्री जगदेव चौधरी को १,५०१ रुपया नकद तथा महात्मा गांधी स्वर्ण ट्राफी की प्रतिमूर्ति का पुरस्कार दिया गया है।

कृषि उपज में वृद्धि

१९५९ में कृषि उत्पादन का सूचक अङ्क (१९४९-५० के सूचक अङ्क को (आधार=१०० मानकर) बढ़कर १३९.० हो गया। यह १९५६-५७ के सूचक अङ्क से १४.३ प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष ७ करोड़ ३५ लाख टन अनाज, ५२ लाख गांठें, पटसन, ६९ लाख तिलहन और ७२ लाख टन गन्ना (गुड़ के हिसाब से) पैदा हुआ। यह उत्पादन अब तक के उत्पादन में सबसे अधिक है। केवल कपास पिछले साल जितनी ही पैदा हुई।

अनाज की उपज बढ़ाने के लिए किए गए कामों की सफलता के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इनसे १९५८-५९ में उपज बहुत बढ़ी। उपज बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ३६ करोड़ ८७ लाख रु० की राशि दी। इसमें से १७ करोड़ ४८ लाख रु० लम्बी अवधि के ऋण और १५ करोड़ रु० थोड़े समय के ऋण के रूप में दिया गया। इसके अलावा ४ करोड़ ३६ लाख रु० सहायता के रूप में दिया गया।

खाद और उर्वरक

इस वर्ष १८ लाख ८० हजार टन अमोनियम सल्फेट की मांग थी। देश में ३ लाख ८२ हजार टन अमोनियम सल्फेट बनाया गया और ३ लाख ४८ हजार टन बाहर से मंगाया गया। इसके अलावा ४ लाख ६४ हजार टन अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरक इस्तेमाल किए गए। इस वर्ष ३ लाख ४२ हजार टन सुपरफास्फेट की मांग हुई, जबकि १९५८-५९ में १ लाख ७० हजार टन सुपर फास्फेट काम में लाया गया था।

आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली में १९५८-५९ के रबी आन्दोलन में ३२ लाख टन अनाज अधिक पैदा हुआ। रबी आन्दोलन में भाग लेने वाले ९ राज्यों में से ६ राज्यों में उपज १५ प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ी।

पशुपालन, डेरी सुधार, मछली पालन आदि के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। १०७ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का विस्तार किया गया और १९८ नए केन्द्र खोले गए। दिल्ली दूध योजना और मद्रास के पास माधवराम में दूध बस्ती खोली गयी। कलकत्ता के पास हरीघाट में जो दूधबस्ती और कलकत्ता में ६,००० मन दूध की जो डेरी बन रही है, उनके निर्माण में भी काफी प्रगति हुई।

बम्बई, उड़ीसा, और हिमांचल प्रदेश में तीन क्षेत्रीय मुर्गी-पालन फार्म खोले गए। आशा है, चालू साल में ५४ मुर्गी-पालन विस्तार केन्द्र खोले जाएंगे। मछली-पालन के क्षेत्र में मछुओं को और उनकी सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए १० केन्द्र खुले हुए हैं।

९ लाख ४६ हजार एकड़ जमीन के संरक्षण के के लिए केन्द्र ने राज्यों को कुल ३ करोड़ ८० लाख रुपये की सहायता दी। भाखड़ा-नंगल क्षेत्र में भूमि-संरक्षण कार्य-क्रम सिखाने की ६ योजनाएं मन्जूर की गयीं। कई राज्यों में कम पानी से खेती करने के तरीके चलाने के लिए कुल चालीस केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गयी। जोधपुर में रेगिस्तान की जगह वन लगाने और भूमि संरक्षण के लिए जो केन्द्र हैं, उसे यूनेस्को की सहायता से केन्द्रीय मरुस्थल अनुसंधान संस्था बनाया जा रहा है। ●

स्थायी ग्राहक : पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में कठिनाई होगी। संभव है उत्तर जा ही न सके।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएँ

नयी आयात नीति घोषित

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में १९६० के लिए आयात नीति की घोषणा कर दी गयी है।

मोटे तौर पर यह आयात-नीति पिछली छमाही की आयात नीति के समान ही है। इस बार कुछ ऐसे सामानों का आयात कोटा बढ़ा दिया गया है, जिनकी देश में बहुत आवश्यकता है। इनके बदले कुछ ऐसे सामान का कोटा घटा दिया गया है, जिनकी अब देश को ज्यादा जरूरत नहीं है या जिस सामान का अब देश में उत्पादन बढ़ गया है।

विभिन्न उद्योगों में काम आने वाले कच्चे सामान तथा खास मशीनरी के पुरजों के आयात के लिए इस बार ज्यादा विदेशी-मुद्रा रखी गयी है।

कुछ देशी चीजों का उत्पादन बढ़ जाने के कारण इन चीजों का आयात कोटा घटा दिया गया है : बायलर ट्यूब, मेकेनिकल ट्यूबिंग, बाइफरकेटेड रिबिट, बढ़ईगीरी के आरे रेतियाँ, चमड़े की पाल, गम करेबिक, सनोवर का तेल, कपड़ा उद्योग में काम आने वाले कुछ रसायन एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल और निकोटिनेपाइड, विटामिन बी-१२, आदि औषधियां कुछ प्रकार के रसायन, आदि और मोटर गाड़ियों के कुछ पुर्जे।

३४ वस्तुओं के आयात के लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी गयी है। जिन चीजों के लाइसेंस की अवधि बढ़ाई गयी है, उनमें मुख्य चीजें इस प्रकार हैं—बच्चों के लिए दूध, नकली और असली सत, कागज के सामान, रबड़ के गर्भ-निरोधक उपकरण, छापेखाने की मशीनें, मशीनी औजार, कोलतार के रंग, रासायनिक वस्तुएं इत्यादि।

इससे कई अनुसूचित क्षेत्रों के उद्योगों तथा छोटे उद्योगों को काफी सहायता मिलेगी। निर्यातकों को सुविधा होने के अलावा लाइसेंस में संशोधन करने तथा उसकी अवधि बढ़ाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा इससे आयातक विदेशी व्यापारियों से लम्बी अवधि तक माल सप्लाई करने की व्यवस्था कर सकेंगें यथा माल की ढुलाई के लिए पहले से ही प्रबन्ध कर सकेंगे और कच्चे माल की सप्लाई भी हो सकेगी।

भारत और पाकिस्तान में नया समझौता

भारत और पाकिस्तान में एक नया समझौता हुआ है। इस पर अभी अमल शुरू हो जायगा और यह २ साल तक चलेगा। यदि दोनों में से कोई सरकार करार को खतम करने का नोटिस नहीं देगी तो इसे १ साल के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।

नये करार के अनुसार अब दोनों देश एक-दूसरे को २ करोड़ रु० की बजाय ४ करोड़ १० लाख रु० तक का माल भेज सकेंगे। पाकिस्तान भारत को १ करोड़ रु० की पटसन की कटिंग देगा और १ करोड़ से बढ़ाकर १।। करोड़ रु० की कपास का निर्यात करेगा। इसके बदले भारत पाकिस्तान को १ करोड़ रु० का लोहा और इस्पात और ७० लाख रु० की बजाय १।। करोड़ रु० का सीमेंट और बीड़ी की पत्ती देगा।

पाकिस्तान से पान, फिल्म, मछली (सूखी और नमक लगी) दवाएं (आयुर्वेदिक और यूनानी), सैंधा नमक, सुपारी कपोक इत्यादि और भारत से पान, फिल्म, मसाले, मूंगफली और पत्थर जायेंगे।

—सोवियत संघ के वैदेशिक व्यापार संगठन 'सोयुज्नेफ्तीवस्पोर्ट' और भारत की प्राइवेट फर्म, हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई के बीच सोवियत संघ से भारत को मिट्टी का तेल और उच्च गति वाले डिजल तेल देने के लिए लम्बी मियाद का समझौता हुआ है। भारत जिस प्रकार की चीजें चाहेगा, पेट्रोलियम की उसी तरह की चीजें सोवियत संघ भारत को देगा। इन चीजों के मूल्य का भुगतान भारत अपनी मुद्रा में करेगा।

—विश्व बैंक भारत को इस वर्ष १ करोड़ डालर का ऋण देगा। इस प्रकार विश्व बैंक से भारत को मिलने वाली सहायता की राशि ६ करोड़ हो जाएगी।

—भिलाई इस्पात कारखाने की तीसरी खुली भट्ठी (ओपन हर्थ घर्नेस) बनकर तैयार हो गयी है। इस भट्ठी में आग जलायी जा चुकी है। अब शीघ्र ही इसमें इस्पात बनने लगेगा। यह भट्ठी एक बार में दो सौ पचास टन इस्पात बना सकती है। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पश्चिम रेलवे द्वारा

शीघ्र माल पहुँचाने की सेवा

पश्चिमी रेलवे ने अपनी बम्बई और अहमदाबाद, इन्दौर, नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों के बीच चलने वाली बहुत-सी गाड़ियों की शीघ्र माल पहुँचाने की सेवा को और भी तीव्र कर दिया है।

मुख्य मार्गों पर शीघ्र माल पहुंचाने वाली सेवा रविवार के अतिरिक्त अन्य सब दिनों में सुलभ है जब कि अन्य मार्गों पर सप्ताह में केवल तीन दिन गाड़ियां चलती हैं।

सेवाओं का विवरण—ब्राड गेज			माल ले जाने की अवधि
कारनक ब्रिज (बम्बई)	—	नई दिल्ली	५ दिन
कारनक ब्रिज (बम्बई)	—	अहमदाबाद	४ दिन
कारनक ब्रिज (बम्बई)	—	इन्दौर	४ दिन
कारनक ब्रिज (बम्बई)	—	सूरत	३ दिन
कारनक ब्रिज (बम्बई)	—	बेलनगंज (आगरा)	६ दिन
कारनक ब्रिज (बम्बई)	—	बड़ौदा	३ दिन
कारनक ब्रिज (बम्बई)	—	अमृतसर	८ दिन
कारनक ब्रिज (बम्बई)	—	लुधियाना	८ दिन
कारनक ब्रिज (बम्बई)	—	जलंधर शहर	१० दिन
अहमदाबाद	—	बैजवाड़ा	६ दिन
नई दिल्ली	—	कारनक ब्रिज (बम्बई)	५ दिन
नई दिल्ली	—	अहमदाबाद	६ दिन
बेलनगंज (आगरा)	—	कारनक ब्रिज (बम्बई)	६ दिन
अहमदाबाद	—	कारनक ब्रिज (बम्बई)	४ दिन
इन्दौर	—	कारनक ब्रिज (बम्बई)	५ दिन
सूरत	—	कारनक ब्रिज (बम्बई)	३ दिन
अहमदाबाद	—	नई दिल्ली	६ दिन
मीटर गेज			
अजमेर	—	दिल्ली	३ दिन
जयपुर	—	दिल्ली	२ दिन
अजमेर	—	जयपुर	२ दिन
जयपुर	—	अजमेर	२ दिन

शीघ्र माल पहुँचाने वाली सेवा के कारनक ब्रिज से बुक होने वाले सामान के किराए आदि के बारे में विस्तृत जानकारी गुड्स सुपरिटेन्डेन्ट, कारनक ब्रिज, बम्बई से प्राप्त की जा सकती है।

प श्चि म रे ल वे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

GURUKULA KANGRI LIBRARY HARDWAR

राजस्थान हस्तकला का केन्द्र है

राजस्थानी कला के नमूने खरीद कर अपने घरों को सुशोभित कीजिए

तथा

गृह उद्योगों को प्रोत्साहन दीजिए

- हाथीदांत के खिलौने
- लाख व नगीनों के कंगन
- बंधाई व छपाई के स्कार्फ
- जोधपुर की शीतल जल की झारियां
- चन्दन की लकड़ी के खिलौने
- रंगी एवं बंधेज की साड़ियां
- पक्के रंग की चादरें
- लकड़ी एवं खस की वस्तुएं
- कलापूर्ण सामान
- नीले व सफेद पाटरी के सामान
- आकर्षक नमूने की दरियां
- सांगानेरी रंगाई व छपाई के वस्त्र आदि
- उदयपुर के सुन्दर लकड़ी के खिलौने
- जयपुर की कसीदा की हुई जूतियां व जूते
- जयपुर की प्रसिद्धि प्राप्त चूड़ियां व चूड़े
- कोटा के सुन्दर डोरिये

प्रत्येक सरकारी विक्रय-केन्द्र पर प्राप्त

राजस्थानी हस्तकला के नमूने अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं।

राजस्थान हैन्डीक्राफ्ट्स एम्पोरियम
क्वींस वे लेन, नई दिल्ली

राजस्थान हैन्डीक्राफ्ट्स एम्पोरियम
जयपुर, जोधपुर व उदयपुर

राजस्थान राज्य द्वारा प्रसारित

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली से मुद्रित व अशोक प्रकाशन मन्दिर २८/११, शक्तिनगर दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

मई १९६०

GURUKUL KANGRI LIBRARY HARDWAR

मूल्य
७५ न.पै.

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंखों की परम्परा

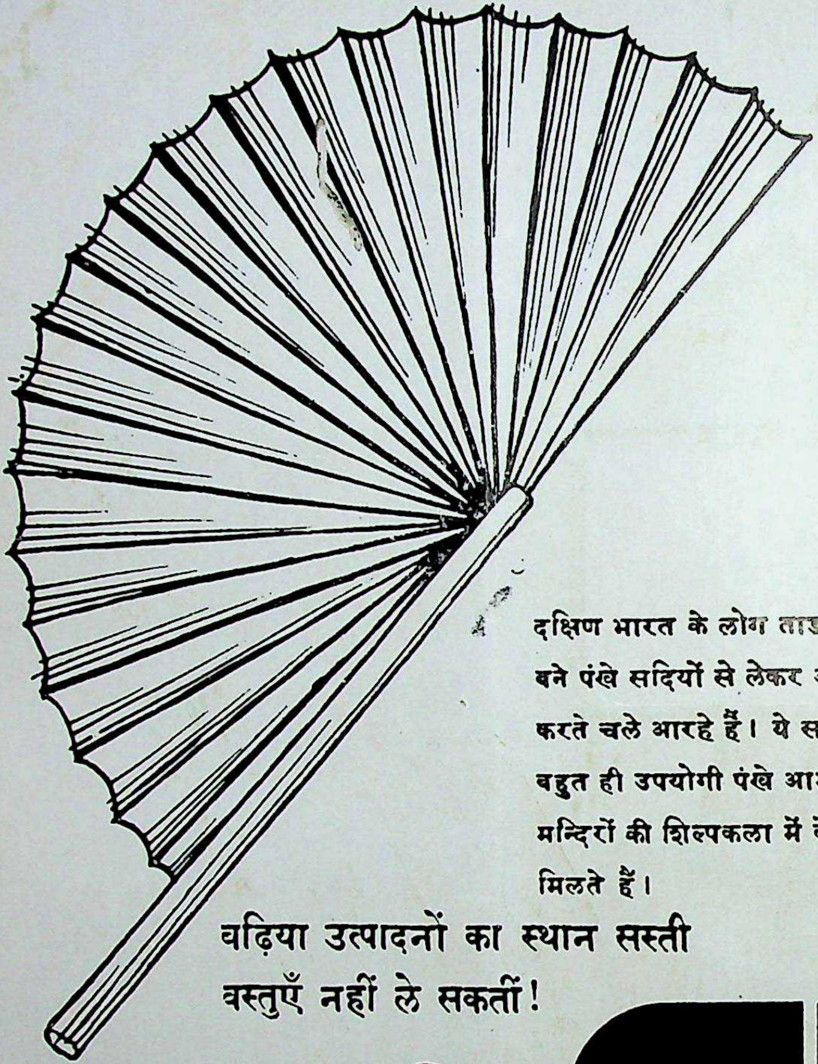

दक्षिण भारत के लोग ताड के पत्तों से बने पंखे सदियों से लेकर आज तक इस्तेमाल करते चले आरहे हैं। ये सादा लेकिन बहुत ही उपयोगी पंखे आमतौर पर प्राचीन मन्दिरों की शिल्पकला में देखने को मिलते हैं।

वढ़िया उत्पादनों का स्थान सस्ती वस्तुएँ नहीं ले सकतीं!

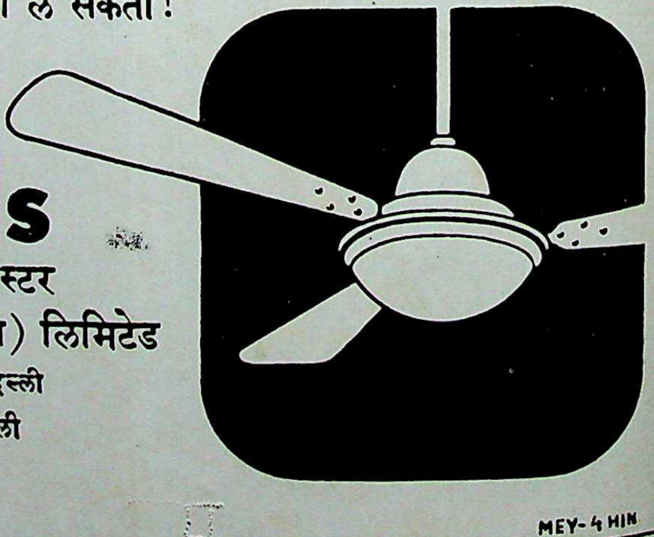

Kassels

कैसल्स एअरमास्टर

मैच्वैल इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड

पो. ऑ. बॉक्स १५६, नयी दिल्ली

कारखाने : पूना और दिल्ली

MEY-4 HIN

भारत के लिए सोल सेलिंग एजेंट : **मैसर्स रेडियो लैम्प वर्क्स लि०**

बम्बई-कलकत्ता-दिल्ली-मद्रास-कानपुर-पटना-इन्दौर-[illegible]-गौहाटी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

शीघ्र माल पहुंचाने की सेवा से
माल गारंटीशुदा समय में पहुंचता है

मध्य रेलवे जिन स्थानों के बीच गाड़ियों की शीघ्र माल पहुँचाने की सेया चलाती है, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :

			माल ले जाने की अवधि
वाडी बन्दर	से	शालीमार	८ दिन
,, ,,	से	टाटानगर	७ दिन
,, ,,	से	नागपुर	३ दिन
,, ,,	से	साल्ट कोटार्स	६ दिन
,, ,,	से	अडोनी	५ दिन
,, ,,	से	येरगुंटला	५ दिन
,, ,,	से	बंगलौर सिटी	५ दिन
,, ,,	से	कोल्हापुर	३ दिन
,, ,,	से	कानपुर	५ दिन
,, ,,	से	बैजवाड़ा	५ दिन
,, ,,	से	सिकन्दराबाद	३ दिन
,, ,,	से	हैदराबाद	३ दिन
,, ,,	से	शोलापुर	२ दिन
,, ,,	से	अकोला	२ दिन
,, ,,	से	अमरोती	२ दिन
,, ,,	से	जबलपुर	३ दिन
,, ,,	से	सतना	४ दिन
,, ,,	से	भोपाल	३ दिन
,, ,,	से	ग्वालियर	४ दिन
,, ,,	से	लखनऊ	७ दिन
पूना	से	नई दिल्ली	५ दिन
,,	से	शालीमार	७ दिन
शोलापुर	से	बैजवाडा	४ दिन
,,	से	साल्ट कोटार्स	५ दिन
,,	से	नई दिल्ली	५ दिन
,,	से	शालीमार	७ दिन

रेल से सामान जल्दी और सुरक्षापूर्वक जाता है !

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया गुड्स सुपरिटेन्डेन्ट वाडी बन्दर से सम्पर्क स्थापित करें ।

म ध्य रे ल वे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस अंक में

अग्रलेख		२४१
सम्पादकीय टिप्पणियां		२४३
गुजरात की समस्याएं	विवेचक	२४५
राष्ट्रीय आय		२४६
योजनाओं का मूल	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार	२४७
सहकारिकता की परम्पराएं	विनोदचन्द्र सिन्हा	२४८
१९५९-६० में विदेशों से सहायता		२५१
राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह	जी० एस० पथिक	२५३
कृषि का अंधकारमय भविष्य ?	सिद्धराज ढड्ढा	२५५
खेती ट्रैक्टर से नहीं		२५६
कांदला का मुक्त बन्दरगाह	यात्री	२५७
कृषि उत्पादन की समस्या	जे० महालनवीस	२५८
सर्वोदय पृष्ठ		२६१
नील नदी पर अस्वान बांध	अशोक	२६३
सामुहिक फार्मों की सम्पत्ति	वाई० बोरीसोव	२६४
पंजाब की औद्योगिक समस्याएं	मोहनलाल	२६६
जहाजी उद्योग की कहानी	सुमति मुरारजी बहन	२६८
अर्थवृत्त चयन		२७१
भारतीय कृषि व्यवस्था की रीढ़		२७३
नया निर्माण		२७४
मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं		२७६
ग्राम निर्माण की दिशा में		२७९
विदेशी अर्थचर्चा		२८०
श्रम समस्या		२८१
हमारे उद्योग		२८३
बैंक बीमा		२८५
नया साहित्य		२८६

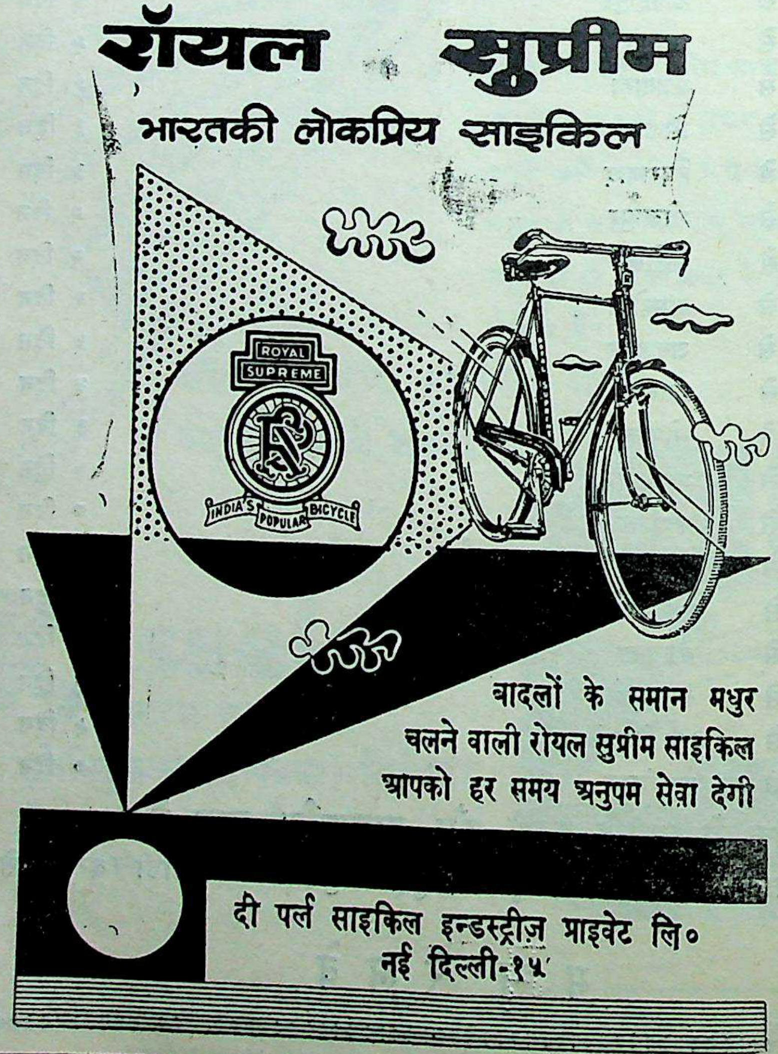

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष ६ : अंक ५ : मई १९६०

सम्पादक
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

संयुक्त सम्पादक
भीमसेन त्यागी

मूल्य निर्धारण और मंहगाई निवारण

जैसा कि हम पिछले अंक में लिख चुके हैं कि देश की सरकार, देश के अर्थशास्त्री और योजना आयोग—सबके सामने एक मुख्य समस्या यह है कि किस तरह बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रण में रखा जाए! इस आवश्यकता को सभी ने तीव्रता से अनुभव किया है और राष्ट्रीय विकास परिषद् के अधिवेशन के कुछ दिन बाद ही मुख्य मंत्री फिर परस्पर मिले और मूल्य स्थिर करने के उपायों पर परामर्श व निर्देश देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति कायम कर दी गई। यह कमेटी कहाँ तक सफल होगी और किन उपायों का निर्देशन करेगी, यह हम नहीं जानते; किन्तु प्राप्त समाचारों से यह तो प्रकट है ही कि खाद्यमंत्री इस दिशा में अन्न के राजकीय व्यापार पर बहुत आग्रह करने के विरुद्ध थे। व्यापारी कुछ समय के लिए अपने षडयंत्र से मूल्य बढ़ा सकते हैं; किन्तु जब देश में किसी चीज की बहुतायत हो तो बहुत समय तक मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता। मूल्य कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता उत्पादन बढ़ाने की है। खाद्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि विदेशों से पर्याप्त मात्रा में अन्न मँगा कर अपने भंडार में रखेंगे ताकि कोई स्वार्थ-रत अनुचित रूप से मूल्य न बढ़ा सके; किन्तु मूल्य वृद्धि रोकने के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है। भारत सरकार की विज्ञप्तियों से मालूम होता है कि अन्न की पैदावार बढ़ी है, फिर भी यदि मूल्य बढ़ें तो उसके कारण कुछ और होने चाहिएं। हमारी नम्र सम्मति में उसके अनेक कारणों में से पिछले अनुभवों से यह देखा गया है कि सरकार जिस वस्तु पर कन्ट्रोल लगाती है, वही वस्तु काले बाजार में पहुँच जाती है। इसलिए हमारी सम्मति में नियंत्रण कम से कम लगाना चाहिए। मूल्य बढ़ने का एक बड़ा कारण मुद्रा प्रसार है। इसलिए यह भी सरकार का कर्तव्य होना चाहिए कि वह जिस तरह एक-एक पैसा विदेशी मुद्रा बचाने का प्रयत्न करती है, उसी तरह एक एक पैसा मुद्रा प्रसार बचाने की कोशिश करे। इनामी बाँडों से कुछ सीमा तक रुपया सरकार खींच सकती है, बैंकों के उधार देने पर भी सरकार कुछ प्रतिबन्ध लगाती रही है; लेकिन इन उपायों का कोई संतोषजनक परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुआ। वस्तुतः मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए एक ही मुख्य उपाय है और वह है; उत्पादन में वृद्धि करना। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक पदार्थों के मूल्य कम नहीं होंगे; इसलिए आज हमें दो दिशाओं में विचार करने की आवश्यकता है। एक तो यह कि हमारी योजनाओं में पूंजीगत सामान तैयार करने पर इतना अधिक बल न दिया जाए कि उपभोग्य सामग्री की कुछ भी उपेक्षा हो जाए। उपभोग्य सामग्री का अधिकाधिक उत्पादन मूल्यों को बढ़ने से रोकेगा। इसलिए हमारे भावी आयोजन का एक ख़ासा भाग उपभोग्य सामग्री के उत्पादन को मिलना चाहिए। दूसरे हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी भूमि सम्बन्धी नीति से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्पादन वृद्धि में सहायता ही मिलनी चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार अन्न है; किन्तु आज किसान को व्यापारिक फसल बोने में अधिक लाभ मिलता है। एक निश्चित सर्वेक्षण से ही यह ज्ञात होगा कि तम्बाकू गन्ना और तिलहन आदि की खेती पर किस अनुपात में प्रतिबन्ध लगाया जाए कि अन्न की पैदावार बढ़े। इस प्रश्न के विविध पहलुओं पर निष्पक्ष रूप से सर्वेक्षण किया जाएगा तो संभवतः विचार करने की एक नई दिशा मिलेगी। चीनी गुड़ और तम्बाकू के दामों में यदि कुछ मामूली सी वृद्धि भी हो तो वह अन्न के मूल्य में कमी होने के कारण सहन की जा सकती है। अन्न जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है और निर्धनों के जीवन निर्वाह में उसका एक बड़ा अंश रहता है। इसलिए इस विषय में अवश्य जांच पड़ताल की जानी चाहिए।

मूल्य निर्धारण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो समिति बनाई है, वह कहां तक उपयोगी सिद्ध होगी इस पर भी हमें सन्देह है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों को न तो महत्वपूर्ण कार्य के लिए समय मिलेगा और न उन सबमें इसकी पर्याप्त योग्यता ही है। उन्हें तो राजनैतिक संघर्षों और विविध जटिल समस्याओं में हमेशा उलझना पड़ता है। मूल्य निर्धारण का काम तो कुशल व्यापारियों और विशेषज्ञों को ही सौंपना चाहिए था, जो किसानों, अनाज की मंडियों और व्यापारिक गतिविधियों के सम्पर्क में रहते हैं।

मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि वेतनों में वृद्धि कम से कम ५ वर्ष के लिए यथासंभव स्थगित कर दी जाए। सरकारी दफ्तरों, व्यापारिक व औद्योगिक संस्थानों में यदि इस पर अमल किया गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विचार करना चाहिए। हम जब यह परामर्श दे रहे हैं, तब हमारा मतलब ४-५ सौ या अधिक रुपया वेतन पाने वालों से ही है। इसका रुपयों की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम नहीं कह सकते; किन्तु इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। देश का रुपया ऐश आराम की चीजों में कम व्यय होगा और सामान्य जनता में उच्च वर्ग के जीवन से ईर्ष्या भी कम होने लगेगी।

ये कुछ विचार हैं, हम चाहते हैं कि देश के अर्थशास्त्री, शासक तथा सार्वजनिक कार्यकर्ता इन पर गम्भीरता से विचार करें।

पदार्थों के मूल्यों के उतार चढ़ाव का एक प्रमुख कारण उत्पादन में वृद्धि या कमी होता है; किन्तु इसके अतिरिक्त भी अनेक कारण मूल्य पर प्रभाव डालते हैं—किस क्षेत्र में आयोजन पर कितना व्यय होता है, वह किस गति से होता है, वित्त विभाग वित्त की कैसी व्यवस्था करता है, जनसंख्या किस परिमाण में बढ़ती है, जनता के स्वभाव और प्रयोग में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, सरकार की नीति किस तरह बदलती है तथा आयात निर्यात नीति में क्या परिवर्तन होता है, इन सबका प्रभाव पदार्थों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर पड़ता है, इसलिए मूल्यों का निर्धारण करते समय जहां हमें उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा, वहाँ उक्त तथ्यों को भी नजरन्दाज नहीं किया जा सकता, मूल्यों को इतना भी नहीं गिराना चाहिये जिससे उत्पादन का प्रोत्साहन नष्ट हो जाय और न मूल्य इतने ऊंचे हों कि जनता की क्रय शक्ति से बाहर हो जाएं। ● ●

पश्चिमी यूरोप को निर्यात

"पश्चिम यूरोप के देशों में अब यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि उनमें और भारत में आपसी आयात और निर्यात काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर भारत इन देशों को अपना निर्यात नहीं बढ़ा सकता तो वहां से भारत को होने वाले आयात को काफी धक्का लग सकता है।" यह विचार भारत सरकार के व्यापार शिष्टमंडल ने व्यक्त किया है, जो सितम्बर, अक्टूबर, १९५९ में इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और पश्चिमी जर्मनी की यात्रा पर गया था।

श्री के० बी० लाल इस शिष्टमंडल के नेता और श्री मदनमोहन रूइया, जो उस समय भारतीय वाणिज्य और उद्योग संस्थाओं के अध्यक्ष थे, इसके वैकल्पिक नेता होकर गये थे।

इधर पिछले कुछ वर्षों में इंगलैंड को छोड़कर अन्य पश्चिम यूरोपीय देशों से भारत को कच्चे सामान, पूंजीगत माल और अन्य मशीनों आदि का आयात काफी बढ़ा है; किन्तु इन देशों को भारत से होने वाले निर्यात में कोई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खास घट-बढ़ नहीं हुई है। १९५७ में भारत को इन देशों के आयात-निर्यात से २०४ करोड़ ८७ लाख रु० का और १९५८ में १४२ करोड़ ९७ लाख रु० का घाटा हुआ। यह भारत के विदेशी व्यापार में कुल घाटे का ४८ प्रतिशत है।

इस शिष्टमंडल ने अपनी ३४ दिन की यात्रा में सरकारी प्रतिनिधियों और संस्थाओं से, यूरोपीय आर्थिक आयोग और प्रमुख व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा बैंक-मालिकों से बातचीत की। इस बातचीत के फलस्वरूप इटली, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सरकारों से मंडल ने व्यापार समझौते भी किये। बेल्जियम सरकार ने यह इच्छा प्रकट की कि वहाँ भारतीय सामान का निर्यात बढ़े।

किन्तु उनकी इच्छा मात्र से भारतीय निर्यात नहीं बढ़ सकते। उक्त मण्डल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत को अन्य देशों के सामान से होड़ भी करनी पड़ती है। हालांकि इन देशों में खपत बढ़ने के बहुत अच्छे आसार हैं, किन्तु इस बात का भी खतरा है कि इन देशों की सरकारें अपनी व्यापार नीति कठोर न बना लें। हो सकता है कि ये देश अपने देशी सामान की खपत पर ही जोर देने लगें। अगर ऐसा हुआ तो इन देशों के साथ भारतीय व्यापार बढ़ाना कठिन हो जाएगा और अब तक के व्यापार को भी धक्का लगेगा। इसके बावजूद मण्डल ने यह आशा प्रकट की है क्योंकि पश्चिमी यूरोप में औद्योगीकरण तेजी से हो रहा है, अतः उन देशों को कच्चा सामान बाहर से जरूर मंगाना पड़ेगा।

मण्डल ने पश्चिम यूरोप के देशों को भारत का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई का सुझाव दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत सरकार और भारतीय उद्योगपति, दोनों ही पश्चिम यूरोप से आर्थिक सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। वहां के देशों में भी यह विचार है कि अगर भारत में उनका निर्यात बढ़े तो उनके यहां भारतीय सामान का आयात भी बढ़ सकता है।

३१६ करोड़ रुपये की हानि

एक सरकारी सूचना के अनुसार विदेशी जहाज कम्पनियों को भारतीय बन्दरगाहों तक माल की ढुलाई के लिए १९५८ में कुल ७७ करोड़ ५० लाख रु० भाड़ा दिया गया। वित्त उपमंत्री ने यह भी बताया है कि १९५४ में ३४ करोड़ ४७ लाख रु०, १९५५ में ४३ करोड़ ६ लाख रु०, १९५६ में ६६ करोड़ ५७ लाख रु० और १९५७ में ९४ करोड़ ९४ लाख रु० भाड़ा दिया गया। वित्त उपमंत्री ने जो वक्तव्य संसद-सदन की मेज पर रखा, उससे पता चलता है कि १९५४ से १९५८ तक की अवधि में जिन विदेशी कम्पनियों ने भारतीय माल ढोया, वे अमेरिका, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, नीदरलेंड्स, जापान, पौलेंड, जर्मनी और इटली की थीं।

यह आंकड़े भारतीय जहाजरानी-उद्योग के विकास के लिए इतने प्रबल तर्क उपस्थित करते हैं कि किसी अन्य युक्ति व तर्क की आवश्यकता नहीं रह जाती। इन पांच वर्षों में अपने जहाज न होने के कारण हम ३ अरब १६ करोड़ ४४ लाख रु० विदेशी मुद्रा की हानि कर चुके हैं।

यद्यपि तृतीय पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप निर्धारित नहीं हुआ तथापि यह लगभग निश्चित है कि जहाजी उद्योग के लिए पचपन करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यद्यपि नेशनल सेविंग बोर्ड ने १४ करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। बोर्ड के अध्यक्ष—श्री जगराज मेहता ने बताया था कि बोर्ड की सम्मति में जहाज निर्माण का लक्ष्य १६ लाख टन होना चाहिए, परन्तु योजना आयोग ने इसे कुछ कम करके १४ लाख ३२ हजार टन का नियत किया था। पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि १९४७ में सरकार ने जहाजरानी की दिशा में यह उद्देश्य निर्धारित किए थे।

१—तटीय व्यापार शत-प्रतिशत भारतीय जहाजों के हाथ में हो,

२—निकटवर्तीय देशों का ७५ प्रतिशत व्यापार भारतीय जहाजों के हाथ में हो,

३—विदेशी व्यापार का ५० प्रतिशत भारतीय जहाजों से हो।

इस दृष्टि से २० लाख टन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए था। आज की कठिनाइयों को देखकर योजना आयोग ने केवल १४ लाख २२ हजार टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह इस वर्ष तक पूरा हो जाने की आशा है। इसके अनुसार ९ लाख टन लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। इसका अर्थ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

यह है कि करीब ६ लाख टन के अतिरिक्त जहाज दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाने पड़ेंगे, किन्तु नेशनल शिपिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री मेहता ने यह संदेह प्रकट किया है कि इतने लक्ष्य की पूर्ति के लिए ५५ करोड़ रुपया तो कम है। इसलिए योजना में निर्धारित राशि के अधिकतम सदुपयोग पर विशेष बल दिया जाएगा।

रूस व अमेरिका के श्रमिक!

रूस व अमरीका की ओर से अपनी-अपनी अर्थपद्धति की ऊंचा सिद्ध करने के लिए कभी-कभी मनोरंजक अंक व सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इनसे दोनों की अच्छी तुलना की जा सकती है। हाल ही में अमेरिका के श्रम मन्त्री श्री जेम्स पी० मिचेल ने श्रम आंकड़ा परिषद द्वारा तैयार एक नई अध्ययन-रिपोर्ट के परिणामों को प्रकाशित करते हुए कहा है कि गत अगस्त में एक सोवियत श्रमिक को अपने एक सप्ताह के रोटी, आलू, मांस, मक्खन, अण्डा, दूध और चीनी के सामान्य आहार का भुगतान करने के लिए अप्रैल, १९२८ की अपेक्षा लगभग ८ प्रतिशत अधिक समय तक काम करना पड़ा। स्मरणीय है कि १९२८ में सोवियत संघ में रहन-सहन का स्तर उच्चतम था। इसके अनुसार १९२८ की अपेक्षा १९५९ में सोवियत नागरिक को अण्डों के लिए लगभग १६० प्रतिशत अधिक, दूध के लिए लगभग १५३ प्रतिशत अधिक, चीनी के लिए लगभग १० प्रतिशत अधिक और रोटी के लिए लगभग १८ प्रतिशत अधिक समय तक काम करना पड़ रहा था। किन्तु १९५९ में वहां मांस लगभग उतना ही सस्ता था, जितना १९२८ में; जबकि आलू और मक्खन कुछ अधिक सस्ते थे।

एक अमेरिकी श्रमिक की तुलना में इस समय एक औसत सोवियत नागरिक को चीनी के लिए लगभग २१ गुना, मक्खन के लिए लगभग ९ गुना तथा अण्डों के लिए लगभग ८ गुना काम करना पड़ रहा है, जबकि मांस, दूध, आलू और रोटी के लिए क्रमशः ४ गुना, ४ गुना, ३.५ गुना और १.५ गुना काम करना पड़ रहा है।

इसी तरह मास्को के श्रमिक को अपना वस्त्र खरीदने के लिए न्यूयार्क नगर के श्रमिक की अपेक्षा ७ से १५ गुना अधिक समय तक काम करना पड़ रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः सोवियत संघ में कपड़ों का बहुत ही अभाव है।

यदि रूस की ओर से इन अंकों का प्रतिवाद न हुआ, तो ये अंक अमेरिकन अर्थपद्धति की श्रेष्ठता ही सिद्ध करेंगे।

सरकार आदर्श मालिक बने

दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय मजदूर-संघ के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए श्री रामानुजम ने जिन तत्वों पर विशेष बल दिया है, उनमें से एक यह है कि सरकार को स्वयं आदर्श उद्योगपति बनना चाहिये। आज सबसे बड़ी नियोजक (Employer) और उद्योग संचालक सरकार ही है और ज्यों-ज्यों सार्वजनिक क्षेत्र में नये प्रधान उद्योगों की स्थापना होती जा रही है, सरकार के सिर पर आदर्श उद्योग संचालक बनने का उत्तरदायित्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। श्री रामानुजम ने ठीक ही कहा है कि जब सरकार उद्योग संचालक के रूप में आती है तो वह सामान्य परिभाषा में सरकारपना छोड़ देती है, उस रूप में सरकार सरकार नहीं सिर्फ उद्योग संचालक है, इसलिये उसे आदर्श उद्योग संचालक बनने का प्रयत्न करना चाहिये। हम सार्वजनिक उद्योगों में भी किसी ऐसे विशेषाधिकार को नहीं देना चाहते जो निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को प्राप्त नहीं है वस्तुतः कभी वह उद्योग की और मजदूरों दोनों की समस्याओं से न्याय कर सकेगी।

सरकारी अन्न व्यापार का एक उदाहरण

अखिल भारतीय अन्न व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री हाशम प्रेमजी ने अपने एक भाषण में अन्न के सरकारी व्यापार का विरोध करते हुए एक रोचक उदाहरण दिया है। मध्यप्रदेश सरकार ने १३-१४ रुपये मन गेहूँ खरीदा और १६ रुपये के भाव पर केन्द्रीय सरकार को दिया। विभिन्न राज्य केन्द्रीय सरकार से यह गेहूँ लेकर २२ रुपये मन पर बेचते हैं। इस तरह मूल कीमत से ८ रुपया प्रतिमन पर यह अन्न ग्राहक को मिला। दूसरी तरफ एक व्यापारी यातायात तथा अपने नफे को मिलाकर २-३ रुपये मन से अधिक पर नहीं बेचता। दोनों में कितना अन्तर है!

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गुजरात की आर्थिक समस्याएं और नई सम्भावनाएं

विवेचक

गत १ मई को विशाल बम्बई राज्य को विभक्त करके गुजरात के नये राज्य की स्थापना की गई है। इसमें राज्य का क्षेत्रफल ७२,१३७ वर्ग मील है और १९५१ की जनगणना के अनुसार उसकी जनसंख्या १,६२,६२,१३५ है। जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान के समान है और क्षेत्रफल में पंजाब और उड़ीसा से बड़ा है।

नवीन गुजरात की अपनी अनेक समस्याएं हैं। जहां भौगोलिक परिस्थितियों ने बम्बई के आर्थिक विकास को बहुत बल दिया है, वहाँ उसकी उन्नति के लिए गुजराती व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी वस्तुतः श्रेय मिलना चाहिए। अब उनके कन्धों पर एक नये राज्य को समृद्ध बनाने का उत्तरदायित्व आ गया है।

अन्न की दृष्टि से गुजरात घाटे वा। राज्य है। वहां केवल ५६ प्रतिशत क्षेत्र में अन्न उत्पन्न किया जाता है और शेष ४४ प्रतिशत में व्यापारिक फसलें पैदा की जाती हैं, जो उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करती हैं। इसीलिए आज गुजरात के सामने अपनी ऊसर पड़ी भूमियों को कृषि योग्य बनाने, गहन कृषि करने और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करने की प्रमुख समस्याएं विद्यमान हैं। गुजरात में ऊसर और परती भूमि का प्रतिशत २८.६ है, जो करीब-करीब शेष भारत से दुगुना है। सिंचित भूमि में केवल ६.६३ प्रतिशत सहकारी नहरों से सिंचाई होती है, और ८३.३१ कुओं से तथा ५.११ प्रतिशत तालाबों से। २८६ लाख एकड़ भूमि में से केवल १४.६ लाख भूमि पर सिंचाई होती है। इन अंकों से यह स्पष्ट है कि गुजरात के सामने सिंचाई की कितनी विषम समस्या है। पानी की तरह गुजरात में बिजली की भी पर्याप्त कमी है। केवल ७६.१३ करोड़ किलोवाट बिजली तैयार होती है। यातायात के लिए भी संतोजनक व्यवस्था गुजरात में नहीं है। रेलवे लाईन केवल ३,२८४ मील, पक्की सड़कें ५,६४८ मील तथा कच्ची सड़कें ६,०३७ मील हैं। अहमदाबाद से न कोई अच्छी सड़क बम्बई आती है न कांदला। पीने के पानी का संकट भी गुजरात के बड़े भाग में है। अच्छा साफ स्वास्थ्यदायक पानी बहुत कम स्थानों में मिलता है। बम्बई राज्य के अधिकारियों का ध्यान अधिकतर बम्बई नगर और उसके समीपवर्ती नगरों तक, बिजली पानी आदि की सुविधाएं पहुंचाने तक रहा है। निजी उद्योग का भी अधिक बल बम्बई की भौगोलिक सुविधाओं—यातायात, बिजली, पानी, कच्चा माल, अच्छा बन्दरगाह आदि के कारण गुजरात की ओर नहीं रहा।

इस दृष्टि से देखें तो नवीन गुजरात के सामने पुनर्निर्माण का बहुत बड़ा काम है; लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए कि गुजरात की नई आकांक्षाएं, गुजरात की प्रतिमा, अनुभव-समृद्धि और अध्यवसाय के कारण शीघ्र ही यह राज्य दूसरे राज्यों के समकक्ष हो जाएगा। खम्भात में तेल निकलने की अद्भुत संभावनाओं के कारण गुजरात का भविष्य भी बहुत आशामय और उज्जवल हो गया है।

देश के अनेक प्रमुख उद्योपतियों को गुजरात ने जन्म दिया है और वे आज देश के विभिन्न भागों में रसायन, औषधि, रंग, स्टार्च, सीमेंट, अलौह धातु और इंजीनियरिंग के उद्योग चला रहे हैं। वस्त्र उद्योग पर तो उनका एकाधिकार सा ही है। अनेक नदियों से बिजली निकालने की योजनाओं पर अमल हो रहा है। किन्तु गुजरात की आवश्यकता देखते हुए शायद अनेक थर्मल स्टेशन चलाने पड़ें। गुजरात कोयले का क्षेत्र बिहार से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए भी भारी खर्च कर कोयले की अपेक्षा बिजली पर ध्यान देना आवश्यक है। भारत सरकार बम्बई और अहमदाबाद के बीच में समुद्र तट पर अणुशक्ति केन्द्र खोलने का विचार कर रही है। इसकी स्थापना हो जाने पर बिजली की कमी एक हद तक दूर हो जाएगी।

खम्भात के तेल के अलावा काँदला का नया बन्दरगाह भी गुजरात को भावी समृद्धि का सूचक है। इससे व्यापार और यातायात उद्योग को बहुत बल मिलेगा। यदि भारत सरकार ने तेल स्रोतों के निकट ही तेल संशोधन का कारखाना खोल दिया तो निश्चित रूप से गुजरात में समृद्धि का एक और स्रोत खुल जाएगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत की राष्ट्रीय आय

भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आय के वार्षिक पत्रक के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आय (१९४८-४९ के भावों के आधार पर) १९५८-५९ में ११,६९० करोड़ रु० और १९५७-५८ में १०,८९० करोड़ रु० थी जबकि १९५५-५६ में १०,४८० रु० थी। प्रति व्यक्ति आय (१९४८-४९ के भावों के आधार पर) १९५८-५९ में २८३.०६ रु०, १९५७-५८ में २७७.१ रु० और १९५५-५६ में २७३.६ रु० थी। ये आंकड़े केन्द्रीय अंक संकलन संस्था द्वारा प्रकाशित वार्षिक विवरण के सातवें अंक में दिये गये हैं।

१९५७-५८ में अच्छी उपज न होने के कारण राष्ट्रीय आय कम हो गयी थी। १९५८-५९ में उससे पिछले साल की अपेक्षा ८०० करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय अधिक हुई। इसमें से ५७० करोड़ रु० की अधिक आय अच्छी उपज के कारण हुई। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय में १९५८-५९ में १९५७-५८ की अपेक्षा ७.३ प्रतिशत वृद्धि हुई।

नीचे दी गयी तालिका में १९४८-४९ के भावों के आधार पर पिछले ग्यारह साल की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय दी गयी है :—

वर्ष	राष्ट्रीय आय (करोड़ रु० में)	प्रतिव्यक्ति आय (रु० में)
१९४८-४९	८,६५०	२४६.९
१९४९-५०	८,८२०	२४८.६
१९५०-५१	८,८५०	२४६.३
१९५१-५२	९,१००	२५०.१
१९५२-५३	९,४६०	२५६.६
१९५३-५४	१०,०३०	२६८.७
१९५४-५५	१०,२८०	२७१.९
१९५५-५६	१०,४८०	२७३.६
१९५६-५७	११,०००	२८३.५
१९५७-५८	१०,८९०	२७७.१
१९५८-५९	११,६९०	२८३.६

आंकड़े देखने से यह पता चलता है कि दूसरी योजना के पहले तीन सालों में यानी १९५६-५७ से १९५८-५९ तक राष्ट्रीय आय में ११.५ प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि पहली योजना की अवधि में यानी १९५१-५२ से १९५५-५६ तक राष्ट्रीय आय में १८.४ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार दूसरी योजना के पहले तीन सालों में प्रति व्यक्ति आय में ७.३ प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि पहली योजना में प्रति व्यक्ति आय में ११.१ प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

चालू भावों के आधार पर १९५८-५९ में राष्ट्रीय आय १२,४७० करोड़ रु०, १९५७-५८ में ११,४०० करोड़ रु० और १९५५-५६ में ९,९८० करोड़ रु० थी। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय क्रमशः ३१३.२ रु०; २९०.१ रु० और २६०.६ रु० थी। ● ●

'नर-नारी' का किशोर-अंक

सम्पादक—द्वारकाप्रसाद, एम० ए०, वीरेन्द्र वात्स्यायन

संसार के मनोवैज्ञानिक आज एकमत हैं कि बच्चों के यौन विषयक प्रश्नों का उत्तर न देना अथवा गलत उत्तर देना, दोनों ही, उनके स्वस्थ-विकास में बाधक हैं। बालक बालिकाओं को यौन-ज्ञान करा देना समाज का कर्त्तव्य है।

आप निःसंकोच होकर अपने किशोर-वय के बालक-बालिकाओं के हाथ में यह अंक दे सकते हैं। इस आयु के किशोर-किशोरियों को जो भी यौन-विषयक ज्ञान होना चाहिए, प्रायः वह सभी इसके अंदर आ गया है। अन्त में प्रश्नोत्तरी के द्वारा उनके तद्विषयक हर संभव प्रश्न के समुचित उत्तर प्रस्तुत किये गये हैं।

मूल्य एक प्रति ७५ नए पैसे : वार्षिक ८.००

नर-नारी प्रकाशन, अशोक राजपथ, पटना--६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजनाओं का मूल : प्राथमिकता का प्रश्न

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

किसी विकास योजना का अन्ततः उद्देश्य क्या है? देश की सर्वतोमुखी उन्नति करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाती है। हमारी महत्त्वाकांक्षाएं बहुत और साधन सीमित हैं। इसलिए योजना-निर्माता यह निश्चय करते हैं कि पहले किस कार्य को किया जाए। आवश्यकता के महत्त्व और अपने साधनों को देखते हुए किसी कार्य की प्राथमिकता या क्रम का निर्णय करना ही वस्तुतः योजना का उद्देश्य है। इस योजना के द्वारा ही हम महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को पहले पूर्ण करते हैं और कम महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को कुछ समय के लिए टाल देते हैं।

प्रत्येक समझदार मनुष्य भी अपने घर में इसी तरह की योजना बनाता है। वह अपनी आमदनी का पहला भाग अपने और अपने परिवार के भोजन के लिए व्यय करता है। इसके बाद वह वस्त्र लेता है। तन ढकने को कोई झोंपड़ी ढूंढ़ता है, और फिर यदि उसके पास पैसा बचता है तो वह बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। इसके बाद वह कुछ अच्छा मकान तलाश करता है, सिनेमा देखता है अथवा दूसरे कम आवश्यक कार्यों पर व्यय करता है।

ठीक यही अवस्था किसी राष्ट्र की भी होती है। राष्ट्र को यह दृष्टि सामने रखनी चाहिए कि जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुएं पहले मोहिया की जाएं और बाद में कम आवश्यक वस्तुएं और अन्त में मनोरंजन या विलास की वस्तुएं।

इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो अन्न सबसे पहली आवश्यकता है। यही समस्त आर्थिक चक्र का मेरुदण्ड है। जब तक अन्न की आवश्यकता पूर्ण न हो, तब तक इसमें बाधक किसी भी वस्तु को हम प्राथमिकता नहीं दे सकते। स्वर्गीय श्री जे० सी० कुमारप्पा ने आज से १०-१२ वर्ष पूर्व इस बात की ओर ध्यान खींचा था कि देश की भूमि का एक बहुत बड़ा भाग अनावश्यक या कम आवश्यक पदार्थों के उत्पादन में लगाया जाता है। उन्होंने बताया था कि दक्षिण में वर्जिनिया सिगरेट बनाने वाली बड़ी-बड़ी कम्पनियां किसानों को पेशगी रुपया देकर अनाज की जगह तम्बाकू पैदा करा रही है। इसी तरह उत्तरप्रदेश में चीनी उद्योग के विकास के साथ-साथ अनाज की जगह गन्ना ले रहा है। पिछले वर्षों में जूट की दृष्टि से स्वावलम्बी होने के लिए हमने बंगाल और उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में जूट की खेती पर बल दिया है। इन सबका परिणाम निश्चित रूप से अनाज की पैदावार पर पड़ रहा है। हमें यह सोचना है कि हमारी प्रमुखतम अनिवार्य आवश्यकता क्या है? एक तरफ हमने सिगरेट बेचकर कुछ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर ली या देशव्यापी लत पूरी की और दूसरी तरफ विदेशों से अन्न मंगाकर कई करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा समाप्त कर दी! नैतिक दृष्टि से विचार न करें, तो भी भौतिक दृष्टि से ही क्या अन्न तम्बाकू से अधिक अनिवार्य नहीं है? इस विषय में भी आज दो मत नहीं हैं कि तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। फिर भी योजना निर्माताओं का ध्यान इस ओर नहीं है और वे तम्बाकू उद्योग के विकास की ओर निरन्तर प्रयत्नशील हैं। चीनी के अधिक प्रयोग पर भी देशवासियों को स्वयं अंकुश लगाना होगा।

इसी तरह कला और संस्कृति के उत्थान के लिए, आज जिसका व्यावहारिक अर्थ केवल नृत्य और संगीत मात्र है, करोड़ों रुपये व्यय किया जा रहा है। हम कला और संस्कृति के विरोधी नहीं हैं, किन्तु जब तक हमारे पेट खाली हैं, नाच और गान कुछ पढ़े-लिखे बाबुओं, पैसे वालों और अफसरों को भले ही सन्तुष्ट कर लें, हमें सन्तुष्ट नहीं कर सकते। इसी तरह प्रतिवर्ष रेडियो ब्राडकास्टिंग के नये-नये स्टेशन भी संभवतः आज हमारी प्रमुख आवश्यकता नहीं हैं। इस पर व्यय होने वाला करोड़ों रुपया यदि पहले गांवों के अशिक्षित निरक्षर बालकों को शिक्षित करने और उन्हें पोषक भोजन देने पर व्यय किया जाए, तो वह रुपए का अधिक सदुपयोग होगा।

आज देश के अर्थशास्त्रियों में यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद हो गया है कि सरकार को दूसरी योजना में उद्योग की अपेक्षा कृषि पर अधिक बल देना चाहिए था और आज भी पुंजीगत उद्योगों की अपेक्षा उपभोग्य वस्तुओं के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए विशेष लेख

कृषि में सहकारिता की परम्पराएं

विनोदचन्द्र सिन्हा

बंगलौर अधिवेशन में कांग्रेस की महासमिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते ही लोगों का ध्यान सहकारी कृषि की ओर आकृष्ट हुआ। एक ओर जहाँ कृषि की इस प्रणाली का स्वागत किया गया, वहीं दूसरी ओर खुला विरोध और कटु आलोचनाएं भी हुईं। भारतीय कृषि में सहकारिता के अस्तित्व की प्राचीनता और परम्परागत उपयोगी विधि को अस्वीकार करना इतिहास का परिहास करना होगा।

उत्तम खेती और तत्सम्बन्धी विकास की रूपरेखा निश्चित करने के लिए कृषि तथा सम्बन्धित क्रिया प्रणालियों को सहकारिता पर आधारित करने का विचार सर्वप्रथम इम्पीरियल कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (अब इण्डियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) के सलाहकार बोर्ड ने सन् १९४४ में अपने प्रतिवेदन में प्रकट किया।

१९४४ में ही देश के आठ प्रमुख उद्योगपतियों ने कमेटी आर्थिक विकास योजना (अब बम्बई योजना) बनायी थी। इस कमेटी के स्मृतिपत्र में निर्देश किया गया था कि मुख्य समस्या कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की है। खेतों का स्वामित्व गांव के छोटे-छोटे खण्डों में बिखरा पड़ा है, जो ३ एकड़ से अधिक शायद ही कहीं है। स्वामित्व के एकीकरण तथा खेतों के माप में वृद्धि से लाभ की सीमा बढ़ेगी। साथ ही यह संशोधन प्रभावशाली कृषि प्रणाली अंगीकार करने में आवश्यक सिद्ध होगा। सहकारी कृषि प्रणाली से कृषकों के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों पर बिना कोई हस्तक्षेप किये या आघात पहुंचाये ही खेतों के क्षेत्रों का विस्तार सम्भव है। सहकारी खेती का प्रचार राष्ट्रीय और सार्वजनिक रूप में यथाशीघ्र हो, इसके लिए अनुरोध तथा दबाव डालने की सीमा की वांछनीयता निश्चित करनी होगी।" इससे स्पष्ट है कि बम्बई योजना में न केवल सहकारी खेती बल्कि इसके प्रसार के लिए आवश्यक अनुरोध तथा दबाव पर भी मनन किया था।

कोआपरेटिव प्लानिंग कमेटी ने इस क्षेत्र में १९४५ में पर्यवेक्षण किया। उसका मत था : "कृषि उत्पादन में वृद्धि के स्थायी समन्वय के लिए किसी भी प्रकार की उच्चस्तरीय प्रणाली की आवश्यकता है। सहकारी कृषि भी उच्च स्तर की चार कृषि प्रणालियों में से एक है। सहकारी ढंग की संयुक्त कृषि द्वारा भूमि से अधिकतम लाभ प्राप्त होने के साथ ही कुशल तकनीकों के विकास का अवसर मिलेगा।"

पैलेस्टाइन में सहकारी कृषि सम्बन्धी अध्ययन के लिए गये प्रतिनिधि मंडल ने १९४६ में अपनी रिपोर्ट में लिखा था : 'सहकारी कृषि का प्रयोग विस्तृत पैमाने पर किया जाना

उत्पादन पर अधिक बल देना चाहिए; ताकि एक ओर पदार्थों के मूल्य कम हों और दूसरी ओर लोगों को अधिक रोजगार मिले। आचार्य विनोबा बार-बार यह कहना चाहते हैं कि लोगों को रोजगार देने के लिए भारी मशीनरी को छोड़ना होगा। बड़ी बनाम छोटी बांध योजनाओं के प्रश्न पर भी इसी पहलू से विचार करना चाहिए।

मूल प्रश्न यह है कि हम यह निश्चय करें कि हमारी प्राथमिक और अनिवार्य आवश्यकता कौन-सी है और उसे सन्तुष्ट किए बिना हम कम आवश्यक वस्तुओं पर कम ध्यान दें। एक ओर हम अधिकाधिक बचत का आन्दोलन करते हैं, दूसरी ओर देश में जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठाने की बात करते हैं। जहां तक गांवों की गरीब जनता का प्रश्न है, उसके जीवन स्तर के ऊंचा करने की बात समझ में आती है; लेकिन यहां तो मध्यम और उच्च वर्ग का जीवन स्तर और ऊंचा करने की प्रवृत्ति ही बढ़ रही है और इसी कारण हमारे बचत आन्दोलन सफल नहीं हो रहे।

क्या हम आवश्यकताओं की पूर्वापरता का विचार करके ही योजनाएं नहीं बनाएंगे?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

चाहिए, जिससे इसके सदस्य न केवल सहकारी कृषि बल्कि आर्थिक और सामाजिक सक्रियता में रुचि लेते हुए संगठित हो जाएं।''

स्टेट रैवेन्यू मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में १६७७ में नियुक्त एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी ने अनुरोध किया था : ''ऐसी व्यक्तिगत स्वामित्व की कृषि की अनुमति ही न दी जाए, जिसका कोष आधारभूत स्वामित्व से कम हो। निश्चित अवधि में ही सहकारी संयुक्त कृषि के अन्तर्गत इनका विलीनीकरण कर दिया जाए।''

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया : ''लघु स्वामित्व—जिनका माप आधारभूत माप अथवा भूमि-सीमा-निर्धारण से कम है—के कारण कृषि संगठन में सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। यदि सहकारी सक्रियताओं द्वारा इन स्वामित्वों को विस्तृत रूप में संगठित कर दिया जाय तो कृषकों को मितव्ययिता तथा उच्चस्तरीय कृषि संगठन का लाभ प्राप्त होने लगे।''

द्वितीय आयोजना में कहा गया : ''द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि का मुख्य कार्य आवश्यक उपकरणों द्वारा सहकारी कृषि के विकास के लिए सुदृढ़ नींव डालना है, ताकि लगभग १० वर्षों में देश के अधिकांश क्षेत्रों में सहकारी सिद्धांतों पर कृषि होने लगे।

(१) उत्तम कृषि (बैटर फार्मिंग) सहकारी समिति : प्रत्येक सदस्य के पास अपनी निजी स्वतन्त्र भूमि एवं कृषि-सुविधाएं होती हैं। वह (अ) समिति द्वारा निर्मित कृषि योजना के नियमों का पालन करता है तथा (ब) समिति से कर्ज, बीज, खाद तथा उर्वरक, औजार और क्रय-विक्रय आदि की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उत्तम कृषि समितियाँ क्रियात्मक अथवा सेवा सहकारी समितियों के रूप में काम करती हैं।

(२) कास्तकारी कृषि (टेनैंट फार्मिंग) सहकारी समिति : इन समितियों को निःशुल्क अथवा पट्टे पर भूमि प्राप्त होती है जिसे सदस्यों में बराबर-बराबर बाँट दिया जाता है। सदस्य अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखकर स्वयं ही समिति की योजना बनाते हैं। सदस्यों को बीज, खाद तथा मूल्यवान उपकरण प्राप्त होने के साथ ही उत्पादन के क्रय-विक्रय की सुविधा भी समिति से प्राप्त होती हैं। ये सुविधाएं उन्हें भी मिलती जाती हैं जो इन समितियों के सक्रिय सदस्य नहीं हैं। प्रत्येक सदस्य को हस्तगत भूमि का किराया देना पड़ता है, उत्पादन की निकासी तथा उपभोग का अधिकार उसे अपने उस हिस्से पर मिलता है।

(३) संयुक्त कृषि (ज्वाइंट फार्मिंग) सहकारी समिति : भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत ही रहता है परन्तु व्यवस्था एवं खेती का संचालन चुने हुए सदस्यों की समिति के संरक्षण में होता है। भूमि का स्वामित्व मान्यता प्राप्त होता है और सदस्यों को उत्पादन का अंश पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि का आधार सहयोग होता है तथा लागत व्यय प्राप्त हो जाने के पश्चात् बिक्री में से श्रम और भूमि के आनुपातिक आधार पर वितरण किया जाता है।

(४) सामूहिक कृषि (कलेक्टिव फार्मिंग) सहकारी समिति : ये भूमि तथा अन्य उपकरण निःशुल्क अथवा पट्टे पर प्राप्त करती है। चूंकि इसमें भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व का अस्तित्व नहीं होता, अतः इस मद का पुरस्कार न देकर सदस्यों को उनके व्यक्तिगत श्रम का पुरस्कार प्राप्त होता है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संकेत किया गया है : ''सहकारी कृषि के अन्तर्गत भूमि के अधिक उत्पादन तथा प्रबन्ध की आवश्यक उत्तम व्यवस्था की गयी है। 'इंडियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स' के संयोजन में मई १६५८ में जो सेमिनार आयोजित किया गया था, उसमें कहा गया था : ''सहकारी कृषि समितियों में कृषि साधनों यथा भूमि, उत्पादन के आवश्यक उपकरण तथा श्रम का अधिकसम हितकारी उपयोग करने की क्षमता है।

सन् १६५६ के उत्तरार्ध के प्रारम्भ में देश में कुल १,४४० संयुक्त तथा सामूहिक सहकारी समितियों की सक्रियता में से १०६८ के सुचारू रूप से संचालन की सुचना एक सरकारी रिपोर्ट में दी गयी है। इन समितियों की कुल सदस्य संख्या ३६,०७५ थी जिसमें से २४,६८७ व्यक्ति खेतों में काम करते थे। शेष १४,४६८ सहानुभूति प्रदर्शक, श्रम न करने वाले सदस्य रहे। देश की कृषि योग्य कुल भूमि का ०.१ प्रतिशत इन समितियों के अधिकार में था। इस ३ लाख एकड़ अधिकृत भूमि में से २१.१२ लाख एकड़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में सहकारी प्रणाली से खेती हो रही थी।

पंजाब में इन समितियों की संख्या ५४१ अर्थात् देश की कुल समितियों की ३७ प्रतिशत, बम्बई में २२३ अर्थात १५ प्रतिशत और उत्तरप्रदेश में १६१ अर्थात् १२ प्रतिशत है। इस प्रकार की सबसे कम समितियों की संख्या ४, मद्रास तथा जम्मू और काश्मीर राज्यों में है। केन्द्रीय शासन के अधीन राज्यों में इनकी कुल संख्या २२ है जिसमें से १३ दिल्ली में, ८ मणिपुर तथा १ हिमाचल प्रदेश में हैं। त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार, लैक्के-टिक और मिनीकोय तथा पांडिचेरी में खेती समितियों की सक्रियता का अभी विकास नहीं हुआ है।

कोआपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो जाने के पश्चात् इस प्रकार के संगठनों की सक्रियता, जिसमें कृषि की परम्परागत प्रणालियों के साथ ही संयुक्त कृषि भी सम्मिलित है, विकसित हुई। बम्बई के दान जिले तथा अन्य अधिवासी क्षेत्रों में, जिनमें नेफा की सीमा भी सम्मिलित है, संयुक्त ढंग से खेती तथा उपज के अनुपातिक बंटवारे की प्रणाली का उपयोग प्रारम्भ हुआ है। वहां के कृषक उत्तम बैलों, कृषि-उपकरणों तथा बीजों की परख के अतिरिक्त सिंचाई की सुविधाओं, खेतों से घासपात तथा कूड़ा करकट के विनाश और निम्नस्तरीय जीवनयापन की कलुषित परम्पराओं के उन्मूलन में एक दूसरे को परस्पर सहयोग दे रहे हैं। वे मंदिरों की तथा अन्य सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने में प्रयत्नशील हैं।

लेबर इन्क्वायरी कमेटी की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के कुछ हिस्सों से कृषि श्रमिकों के जत्थे सागर, भिलसा तथा अन्य क्षेत्रों में जाकर फसल की निराई, कटाई तथा तत्सम्बन्धी कार्यों में भूस्वामी कृषकों का हाथ बटाते हैं। फसल की कटाई के पूरे मौसम में वे एक के बाद दूसरे गांवों में होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें फसल की कटाई तथा अन्य कार्यों के अनुपातिक दरों से पुरस्कार मिलता है। ऐसे प्रत्येक जत्थे में एक मुखिया होता है, जो भू-स्वामी कृषकों से मिलकर काम की शर्तें तथा पुरस्कार की दरें निश्चित करता है। नागपुर तथा विदर्भ क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी कार्य जुताई, बोआई, निराई तथा अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाना आदि—भूमि-विहीन कृषकों के ऐसे ही जत्थों द्वारा 'आंशिक-सेवा-पुरस्कार' के बदले में किये जाते हैं, जिसे वहां की बोलचाल में 'हुण्डा' कहते हैं। पंजाब में भी फसल की कटाई एवं निराई के समय संयुक्त श्रम की प्रथा का प्रचलन है, जिसे 'मांग' अथवा 'अहवात' प्रथा कहा जाता है।

कोल्हापुर के पश्चिमी क्षेत्रों में गन्ने की कृषि में पिछले लगभग १०० वर्षों से संयुक्त कृषि प्रणाली का परम्परागत प्रयोग होता चला आ रहा है। इस परम्परा को 'फाद' कहते हैं। 'फाद' प्रणाली के अन्तर्गत कृषक समुदाय भूमि सम्बन्धी अपनी समस्त कार्य एक साथ सम्पन्न करते हैं और उपज में से लागत श्रम तथा अन्य व्यय का अंश निकाल कर शेष में से सदस्यों में बराबर-बराबर वितरण होता है। इस क्षेत्र में १८ गांवों से एकत्रित किये गये आंकड़ों से पता चला है कि गन्ने की २,४८६ एकड़ कृषि भूमि में से ६० प्रतिशत में 'फाद' प्रथा के अनुसार संयुक्त खेती होती है। बम्बई स्टेट कोआपरेटिव बैंक की एक सूचना के अनुसार संयुक्त खेती होती है। बम्बई स्टेट कोआपरेटिव बैंक की सूचना के अनुसार कोल्हापुर जिले में १,००० 'फाद' संगठन कार्यरत हैं। यद्यपि 'फाद' के ये संगठन सहकारी समितियों की भांति पंजीकृत नहीं हैं, फिर भी यह प्रथा वहाँ के व्यावसायिक तथा स्थानीय रीतियों के अनुसार एक प्रकार से अधिकृत मानी जाती है।

आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में 'परंपरागत' आधार पर संयुक्त खेती का प्रचलन है, जिसे वहाँ 'गोंची' कहते हैं। गूटी तालुक के पमिदी फिरका क्षेत्र के सात गांवों के लगभग २०६ एकड़ क्षेत्र में संयुक्त खेती हो रही है। इन्हीं गांवों में से एक पेडवा डुगुर के ८५ भूस्वामी जिनके पास कुल ३५ एकड़ भूमि है और जिन्हें सरकार से सिंचाई की साधारण सी सुविधा प्राप्त है, इस परम्परा के अन्तर्गत काफी समय से खेती करते चले आ रहे हैं। उनके खेतों में व्यक्तिगत स्वामित्व के संकेत के लिए मेंड़ आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ स्थानों पर, एक खेतों के बीच में सर्वेक्षण आदि की सुविधा के लिए पत्थर के दो एक संकेत चिन्ह बना दिये गये हैं।

सहकारी कृषि का प्रश्न असाधारण महत्व का प्रश्न है। आवश्यक है कि राष्ट्र के नेता उस पर गम्भीरता से विचार करें। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५९-६० में विदेशों से सहायता

१९५९-६० के केवल एक वर्ष में ही भारत ने विदेशों से कितनी बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता ली यह निम्नलिखित विवरण से भली प्रकार स्पष्ट है। राष्ट्र के विकास के लिए विदेशों से सहायता लेना हमारे विस्तृत सम्पर्कों का प्रमाण तो है, किन्तु सहायता लेते समय उसे लौटाने की अपनी क्षमताओं पर भी ध्यान रखना चाहिए।

१. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने कोयना पन-बिजली प्रायोजना, भारतीय रेलों और भारत के औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के लिए कुल मिलाकर ८ करोड़ ५० लाख डालर के तीन ऋण दिये।

२. ब्रिटिश सरकार के साथ ३० लाख पौंड के लिए २३ जून, १९५९ और १ करोड़ ९० लाख पौंड के लिए २५ नवम्बर, १९५९ को ऋण सम्बन्धी करारों पर हस्ताक्षर किये गये।

३. गेहूं, कच्चे माल उर्वरकों और वैज्ञानिक साजसामान के आयात के लिए कनाडा ने कुल मिलाकर, २ करोड़ ५० लाख डालर के अनुदानों की स्वीकृति दी।

४. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघों के साथ ऋणों के लिए तीन करारों पर हस्ताक्षर किये गये। एक करार औषधों की कुछ प्रायोजनाएं के लिए ८ करोड़ रूबल (९.५ करोड़ रुपए) के ऋण के लिए है। दूसरे करार का सम्बन्ध तीसरी आयोजना के लिए सहायता देने से है और इसके अनुसार १५० करोड़ रूबल (१८० करोड़ रुपए) का ऋण मिलेगा। १२ फरवरी १९६० को एक और करार पर हस्ताक्षर किए गये जिसमें उपर्युक्त ऋण द्वारा वित्तपोषित होने वाले उद्योगों की सूची और टेक्निकल सहायता का ब्यौरा शामिल किया गया। तीसरा करार बरौनी में पैट्रोलियम साफ करने का कारखाना बनाने के लिए १० करोड़ रूबल (१२ करोड़ रुपए) के ऋण के लिए है।

५. औद्यौगिक संयंत्रों की स्थापना के लिए, २३.१ करोड़ रुपए के ऋण के लिए २४ नवम्बर, १९५९ को चेकोस्लोवाकिया के साथ ऋण सम्बन्धी एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। २१ जनवरी १९६० को ऐसे ही एक और करार पर हस्ताक्षर किये गये, जिसके अनुसार ४ करोड़ डालर (१९.०६ करोड़ रुपए) तक की अधिकतम रकम का पूंजीगत सामान मंगवाया जायगा।

६. गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा इस्पात के आयात के लिए जुलाई १९५९ में अमरीकी विकास ऋण निधि ने २ करोड़ डालर का एक और ऋण मंजूर किया। इस प्रकार अब तक निधि द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की कुल रकम १९ करोड़ ५० लाख डालर हो गई है।

पब्लिक ला ४८० कार्यक्रम के अनुसार अनाज, रुई और तम्बाकू का अतिरिक्त आयात करने के लिए अमरीका की सरकार के साथ नवम्बर १९५९ में एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। इस करार के आधीन लगभग ३० लाख मेट्रिक टन गेहूँ, १.५ लाख मेट्रिक टन चावल, १ लाख मेट्रिक टन मक्का, रुई की १.५ लाख गांठें (प्रत्येक ४८० पौंड) और ५ लाख पौंड तम्बाकू का आयात किया जायगा। इन वस्तुओं का मूल्य लगभग २५ करोड़ ७३ लाख डालर होगा। पब्लिक ला ४८० के अन्तर्गत किए गए चार करारों से जिन पर नवम्बर १९५९ के अन्त तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं—कुल ४४३ करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। जिसमें से लगभग २३५ करोड़ रुपया अमरीकी सरकार द्वारा भारत को ऋण के तौर पर और ९३ करोड़ रुपया उन आर्थिक विकास प्रायोजनाओं पर व्यय करने के लिए अनुदान के रूप में दिया जाने को है जिनके बारे में परस्पर समझौता हो जाय। रुपया ऋणों और अनुदानों को काम में लाने के लिए १२० करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रायोजना करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस वर्ष नवम्बर १९५९ तक लगभग १० करोड़ रुपया ऋण के तौर पर प्राप्त हो चुका था।

४० लाख डालर मूल्य के बराबर पिछले साल दी गई विदेशी मुद्रा के अलावा अमरीकी सरकार ने फ्रांस से उर्वरक खरीदने के लिए इस साल २० लाख डालर मूल्य के बराबर फ्रांसीसी फ्रैंक के लिए स्वीकृति दी। इस व्यवस्था के अधीन किये गये आयातों के मूल्य के बराबर की रकम भारत में अमरीकी खाते में रुपयों में जमा कर दी जायगी।

अमरीकी सरकार ने मलेरिया को खत्म करने के कार्यक्रम

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के लिए १६६० के वित्तीय वर्ष की टेक्निकल सहायता निधि से १ करोड़ ३६ लाख डालर के अनुदान की स्वीकृति भी दी है।

७. फोर्ड निधि और राकफेलर निधि से अलग-अलग प्रायोजनाओं के लिए इस वर्ष सयायता प्राप्त होती रही।

८. कनाडा से गेहूँ मंगाने के १६५६-६० के कार्यक्रम के लिए कनाडा ने अब तक ७० लाख डालर का अनुदान दिया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रायोजनाओं के लिए भारत को और अधिक पूंजीगत अनुदान देने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

६. संयुक्त राष्ट्र संघ विस्तृत शिल्पिक सहायता कार्यक्रम के अधीन भारत को ३८७ विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुई और आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में ७२६ भारतीयों को प्रशिक्षण की सुविधाएं मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी एजेंसियों ने भारत से ५८८ विशेषज्ञों को विदेशों में काम पर लगाने के लिए भर्ती किया और भारत में ६०८ विदेशी राष्ट्र जनों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध किया।

१०. संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष प्रायोजना निधि के १६५६ के कार्यक्रम में शामिल करने के लिए भारत ने लगभग १०.०५ करोड़ रुपए की पांच प्रायोजनाओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली।

११. भारत अमरीका शिल्पिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन अमरीकी राजस्व वर्ष १६५६ में ७४ लाख डालर के मूल्य की शिल्पिक सहायता प्रदान की गई। अमरीकी राजस्व से वर्ष १६६० में ८५ लाख डालर मिलने की सम्भावना है। इस कार्यक्रम के अधीन अब तक ४८६ अमरीकी विशेषज्ञों की सेवाओं तथा १,२०६ भारतीय राष्ट्रजनों के लिए अमरीका में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है।

१२. १६५६ की पहली छमाही में कोलम्बो आयोजन के अंतर्गत, भारत को २५ विशेषज्ञों की सेवाएं और २३१ भारतीयों के प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हुईं।

१३. भारत फ्रांस शिल्पिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत १२ विदेशी विशेषज्ञों को भारत लाया गया और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए २७ भारतीय प्रशिक्षार्थियों को फ्रांस भेजा गया। ● ●

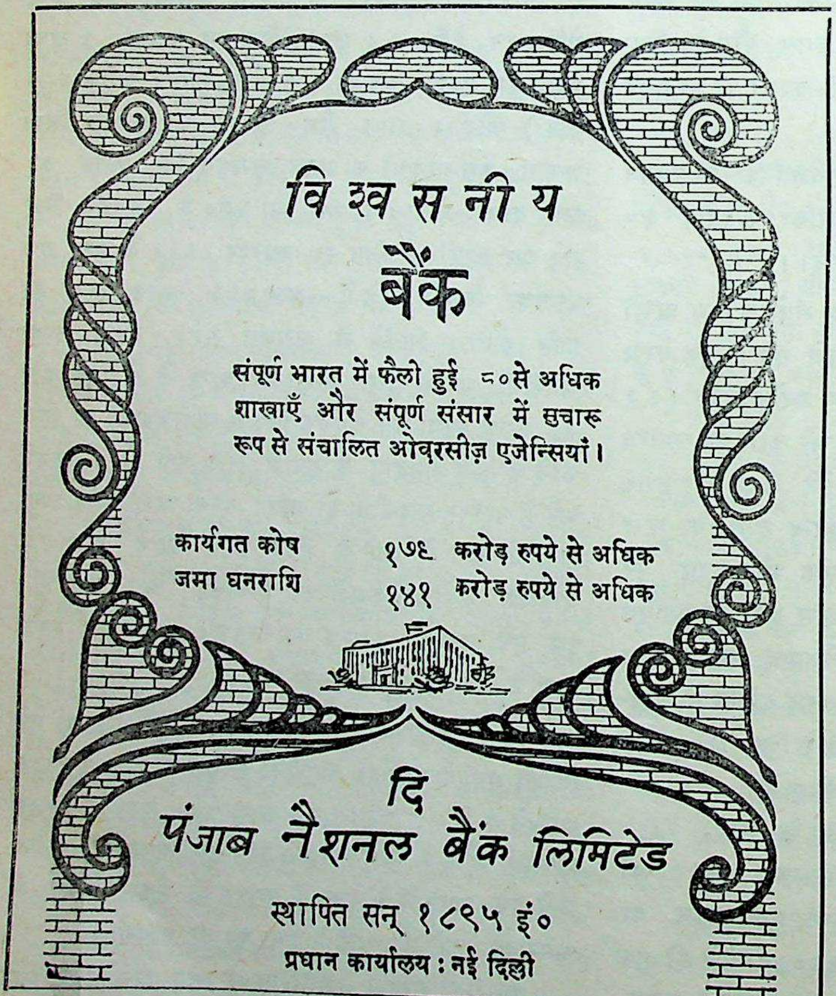

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह

जी० एस० पथिक

सड़क यातायात का विस्तार

भारत जैसे अविकसित देश की पंचवर्षीय योजना और विस्तार पाने वाली अर्थ-व्यवस्था में एक प्रकार के यातायात पर निर्भर रहना संभव नहीं है। भारतीय रेलों का विस्तार ३५,००० मील तक है, अतः वे १२ सौ लाख वर्ग मील में ६,००,००० ग्रामों तक अपना यातायात नहीं बढ़ा सकतीं। रेल के बाद सड़क यातायात का स्थान आता है, जो मध्य वर्ग द्वारा संचालित है और नए लोगों को काम देने का साधन है। सड़क यातायात ग्रामों तथा दूरस्थ क्षेत्रों की कड़ी को नगरों से जोड़ने वाला है। इस लिए पहली और दूसरी योजनाओं में इस यातायात के विस्तार पर जोर दिया गया है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं में (१९६०-८१) सड़क क्षेत्र के विस्तार को स्थान दिया है। इस दिशा में सड़कों का निर्माण पुराने पुलों की मरम्मत और नए पुलों की रचना द्वारा राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के मार्गों को जोड़ा जाएगा।

अनुमान यह है कि १९६०-८१ के २० वर्षों में माल का यातायात ८,००० करोड़ टन तक पहुँच जाएगा। इस काल में रेलवे की क्षमता जहां ५,२५० लाख टन होगी, वहां मार्ग यातायात की की २४ करोड़ ५० लाख टन होगी। १९५९-६० के लिए १६ करोड़ ५० लाख टन और १९६०-६१ के लिए १६ करोड़ ५० लाख टन यातायात का अनुमान किया गया है।

यदि रेलें माल ढोने का विस्तार करेंगी, उन्हें अधिक एंजिन और वेगन चाहेंगे तथा गाड़ियों की गति भी तेज करनी पड़ेगी। जहां तक गति का प्रश्न है, वहां माल गाड़ी की प्रति घण्टे १०.७ मील से गिर कर ९.२८ मील ब्राड-गेज में रह गयी और मीटर गेज तो में चाल बहुत ही कम रह गयी। १९४९-५८ तक यही गति रही। रेलवे मंत्री का कहना है कि रेलवे की मुसाफिर गाड़ियों के यातायात में प्रति वर्ष ३ प्रतिशत से अधिक वृद्धि संभव नहीं है। फिर हम गाड़ियों की भीड़ से परिचित हैं ही। १९४८ से १९२७ तक यात्रियों की संख्या ११,१४० लाख से १४,१०० लाख तक बढ़ी और यह बढ़ती ही जाती है। इस दिशा में सड़क यातायात के लिए भारी क्षेत्र खुला पड़ा है। थोड़ी थोड़ी दूर की यात्रा में सड़क यातायात यात्रियों की बड़ी सेवा कर सकता है। इस से रेलों के तीसरे दर्जे में कम भीड़ होगी।

संसार के सभी विकसित देशों में सड़क यातायात को प्रमुख स्थान दिया गया है। अमेरिका में सड़क यातायात रेलों से सेवाएँ, तेज चाल और प्रतियोगिता की दरें आदि में प्रतिद्वन्द्विता करता है। फिर भारत जैसे देश में, जहां ७० प्रतिशत जनता ग्रामों में बसती है, सड़क यातायात को सब से अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जनवरी १९६० में २१,५००० ट्रक और बसें चलती थीं। इन गाड़ियों में सब मिला कर ४०० करोड़ रुपए का विनि-योजन हुआ।

सड़क यातायात पेट्रोल उद्योग, मोटर उद्योग और अन्य उद्योगों के सिवा सड़कों, वर्कशाप, गैरेज और सर्विस स्टेशनों का उपयोग करता है। इन सब में जो पूंजी लगी है, वह अलग है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रति बस पीछे १७ आदमी और प्रत्येक ट्रक पीछे ११ आदमियों को काम मिलता है। रेलों की अपेक्षा सड़क यातायात वस्तुतः अधिक लोगों को काम देता है। देश के विकास काल में जब दूरस्थ प्रदेशों में नए उद्योग खड़े करने की योजनाएँ हैं, सड़क यातायात उद्योग रोजगार देने का प्रबल साधन है। सड़क यातायात उद्योग से केन्द्रीय और राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपए की आय होती है।

नई आयात नीति

नई आयात नीति में तीन नई बातें उल्लेखनीय हैं। देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल और पुर्जों की आमद की छूट दी गयी है, अनेक मदों के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिए बुनियादी-काल की अवधियां बढ़ा दी गयी हैं। जिन मदों के पदार्थों का आयात निश्चित किया गया है, उनके अनेक लाइसेंस दुहराए भी जा सकेंगे। १९५७-५८ और १९५८-५९ के ओ० जी० एल० और विवरल लाइसेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत आयातकर्त्ताओं पर जो रोकें थीं, वे बुनियाद काल के अपने कोटों का आयात कर सकेंगे। जो उद्योग माल का वास्तविक उपयोग करते हैं, उनके आयात के लिए वार्षिक लाइसेंस दिए जाएंगे। २०१ शेडयूल उद्योग और कई छोटे पैमानों के उद्योगों को वार्षिक लाइसेंस प्राप्त हो सकेंगे। इस आधार पर चाय, जूट और कोयले के उद्योग वार्षिक आधार पर मशीनें मंगा सकेंगे। इस नयी नीति से उद्योगों के लिए कच्चे माल की आमद बराबर होती रहेगी और उनका विस्तार भी संभव होगा।

भारत को सोवियत सहायता

सोवियत रूस ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए भारत को १,८०,००,००,००० रुपए की सहायता देना स्वीकार किया है। विदेशी राष्ट्रों में केवल सोवियत रूस आगे बढ़ा है, जिसने भारत में भारी उद्योगों के निर्माण करने में हाथ बढ़ाया। पश्चिम का कोई देश आगे नहीं आया। संभवतः पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत भारी मशीनों के निर्माण में आत्मनिर्भर बने। भारी उद्योगों का निर्माण होने पर भारत आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र हो सकता है।

समुद्री जहाज-उद्योग में भारत ने एक-एक करके पश्चिम के सभी राष्ट्रों से समुद्री जहाज निर्माण के लिए टेकनीशियन और इंजीनियरों की मांग की, पर किसी ने सहयोग नहीं देना चाहा। अतः सोवियत रूस की सहायता से बिहार के अंतर्गत रांची में भारी मशीनों का उद्योग स्थापित होना प्रशंसनीय कदम है। रूस की सहायता वालबियरिंग, और औद्योगिक कल पुर्जों के निर्माण में लगेगी। भूपाल के विद्यु त पदार्थों के कारखाने के बाद विद्यु त पदार्थों का दूसरा कारखाना भी रूसी सहायता से खड़ा करने का आयोजन है। इस दूसरे कारखाने में भारी टरबाइन और ऊंचे दर्जे के पावर जनरेटरों का उत्पादन डेजिल इंजनों के लिए होगा। सोवियत सहायता से खुलने वाले औषधि निर्माण के उद्योगों के लिए पांच स्थान चुने गए हैं।

औद्योगिक एस्टेट

तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनेक क्षेत्रों में २०० ग्रामीण औद्योगिक एस्टेटों की स्थापना की जाएगी। इससे ग्रामों के लोग शहरों में आने के लिए मजबूर न होंगे। और शहरों के पढ़े लिखे लोग या बगैर पढ़े लिखे भी कस्बों में जाकर इन उद्योगों में लगेंगे। भारत के ५ लाख ग्रामों में चालीस हजार एस्टेटों के खड़े करने पर देश की अर्थ-व्यवस्था का नक्शा बदल सकता है।

पश्चिमी बंगाल का विशाक्त कदम

कलकत्ता उत्तरप्रदेश, बिहार और आसाम का बंदरगाह है। जितना अधिकार कलकत्ते पर पश्चिम बंगाल का है, उतना ही बिहार और उत्तरप्रदेश का भी है। इन दोनों प्रदेशों में जो उद्योग और व्यापार संचालित होते हैं, उनके रजिस्टर्ड आफिस कलकत्ते में हैं। यहां के व्यापारी और एक्सचेंज बैंकों के कारबार में इन प्रदेशों का बड़ा हिस्सा है। यदि इन दोनों प्रदेशों की सरकारें रजिस्टर्ड आफिसों को अपनी सीमा में रखने पर जोर दें और इन प्रदेशों के बैंक सारा कारबार करें, तो कलकत्ते को भारी क्षति पहुँचे।

कलकत्ते में बिहार और उत्तरप्रदेश के लोग न रजिस्टर्ड आफिस में नौकरी पाते हैं, न बैंकों में तथा न आयात-निर्यात के कारबार में। वे जूट मिलों में मजदूर हैं, और सारा ऐसा काम करते हैं, जिसमें पसीना बहाना पड़ता है। बंगाली ऐसे कामों के लिए तैयार नहीं हो पाते। निजी क्षेत्र के सभी विदेशी और भारतीय प्रतिष्ठान बंगाली बाबुओं से भरे हुए हैं दूसरी बिहार में कुल बारह-तेरह सौ बंगाली हैं और इसी प्रकार उत्तरप्रदेश में भी न्यूनाधिक दूसरी हैं; पर वहां बंगाली मजदूर व कुली नहीं हैं। मगर उत्तरप्रदेश व बिहार में यह कभी आवाज नहीं उठी कि 'भूमि के पुत्रों' को काम दो, जो पश्चिम बंगाल में उठ रही है। निजी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है, कि वह अपने यहां के रिक्त स्थानों की सूचना एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को दें और जिन व्यक्तियों को एक्सचेंज भेजे, उन्हें नौकर रखें, पर प्रश्न यह है कि बिहार और यू० पी० वाले भूमि के पुत्र नहीं हैं? प्रादेशिकता का यह विशाक्त घातक रूप है, जिसमें प्रदेश के सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय कृषि का अंधकारमय भविष्य ?

सिद्धराज ढड्ढा

भारत के उप-कृषिमन्त्री श्री कृष्णप्पा ने भी इस बात को मंजूर किया कि "हम समूची भारतीय कृषि को यंत्रीकृत (मिकेनाइज्ड) करना नहीं चाहते।" कृष्णप्पा साहब या दूसरे कोई लोग चाहें, तब भी शायद ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी हालत में फिर सूरतगढ़ जैसे १० और बड़े फ़ार्म बनाने से देश को क्या लाभ होने वाला है, यह स्पष्ट नहीं है। अगर इस देश की खेती का ढाँचा—पैटर्न—बड़े-बड़े फार्मों का होने वाला होता तब तो नमूने और प्रयोग के तौर पर करोड़ों-अरबों रुपया खर्च करके इस प्रकार के यंत्रीकरण फार्म बनाना सरकार के लिए उचित था। पर जब वस्तु स्थिति को देखते हुए हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े फार्मों की खेती सम्भव ही नहीं है तब सरकार को उत्पादन बढ़ाने के या खेती-सुधार के जो कुछ प्रयोग करने हों, वे छोटे-छोटे फार्मों में और यथा-सम्भव उन्हीं परिस्थितियों में करने चाहिएं, जिन परिस्थितियों में सामान्य किसान आज खेती कर रहा है। खेती के तरीकों में या औजारों में सुधार करना तो आवश्यक है, लेकिन सुधार ऐसे हों, जिन्हें एक औसत किसान भी आसानी से ग्रहण कर सके, जहाँ वह आज है वहाँ से आसानी के साथ एक कदम आगे बढ़कर उसे अपना सके। कृष्णप्पा साहब ने बताया है कि सूरतगढ़ में पहले साल में ६ मन प्रति एकड़ अनाज उपजा, दूसरे वर्ष में १२ मन और तीसरे में २० मन। 'पानी की पर्याप्त मात्रा मिलने' से यह उपज ३० मन तक बढ़ सकती है। अगर पानी और खाद मिलें तो बड़े फार्मों से छोटे खेतों में उतनी ही, बल्कि उससे ज्यादा उपज प्रति एकड़ हो सकती है।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा ने कहा है कि भारत सरकार १० बड़े यंत्रीकृत (मिकेनाइज्ड) फार्म खोलने का विचार कर रही है। ये फार्म १० हजार एकड़ से ३० हजार एकड़ तक के होंगे। ऐसा एक फार्म राजस्थान के सूरतगढ़ इलाके में रूसी सरकार की मदद से अब भी चल रहा है।

मशीनों से खेती करना स्पष्ट प्रजाद्रोह है !

तीसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में, जहाँ अभी भी करोड़ों की संख्या में भूमिहीन खेतिहर मौजूद हैं, इस तरह हजारों एकड़ जमीन के बड़े-बड़े फार्म बना कर उन्हें मशीनों के जरिये चलाना एक तरह से 'प्रजाद्रोह' ही है। एक तरफ लाखों-करोड़ों लोग काम से वंचित हों और दूसरी तरफ हजारों एकड़ भूमि बड़े-बड़े फार्मों के नीचे कर दी जाय, इसका औचित्य समझ में आने लायक नहीं है।

बड़े फार्मों की तो बात अलग है। हिन्दुस्तान में तो मध्यम दर्जे के फार्म बना कर उनमें भी ट्रैक्टर आदि चलाना इस देश की दृष्टि से अवैज्ञानिक और अनुचित है। भारतीय खेती के लिए बैल-शक्ति ही सर्वोत्तम साधन है।

श्री ढेबर भाई ने स्पष्ट किया था, हिन्दुस्तान की तमाम जमीन अगर ट्रैक्टर से जोतनी हो तो उसके लिए ४० लाख ट्रेक्टर चाहिएं, जिन्हें जुटाना भारत के लिए असम्भव है। इतना ही नहीं उतने ट्रैक्टर बराबर उपयोग में रहें, इसके लिए हर साल ५ से ७ लाख नये ट्रैक्टर प्राप्त करने होंगे।

पर ट्रैक्टर पर्याप्त मात्रा में हो सकें, ऐसी स्थिति हो तब भी कम से कम हिन्दुस्तान की परिस्थिति में उनका उपयोग नहीं होना चाहिए, ताकि बैल को अपनी जगह से हटना नहीं पड़े। जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जायगी और हमें सघन खेती—इन्टेंसिव फार्मिंग—की ओर जाना होगा, त्यों-त्यों ट्रैक्टर के लिए गुंजाइश उत्तरोत्तर और भी कम होती जाएगी।

बैल हमारे अर्थशास्त्र का एक आवश्यक अंग है। फसल में से दाने का उपयोग आदमी के लिए होता है और बैल कड़बी (डंठल) खाकर जीता है। बैल कड़बी खा लेता है और जमीन को खाद देता है। ट्रैक्टर न कड़बी खाकर रह सकता है, न खाद दे सकता है। ट्रैक्टर का खाना यानि तेल, हमें अलग से प्राप्त करना होगा। लड़ाई के संयोगों में ट्रैक्टर और उसका खाना प्राप्त होने में अत्यधिक कठिनाई हो सकती है। बैल का उपयोग बन्द हो जाय तो गाय भी जिंदा नहीं रह सकेगी। वह भी आर्थिक दृष्टि से भार रूप हो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खेती : ट्रैक्टर से नहीं, बैलों से !

मशीनी खेती के समर्थकों के द्वारा प्रायः कहा जाता है कि ट्रैक्टर से खेती करने से प्रति एकड़ खेती पर व्यय कम होता है और भूमि से आय भी अधिक होती है। लेकिन पंजाब सांख्यिकी संगठन ने सर्वेक्षण के पश्चात जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह मशीनी खेती के समर्थकों को एक करारा उत्तर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मशीनों की सहायता से की जाने वाली वाली खेती, हल से की जाने वाली की अपेक्षा महंगी पड़ती है और उससे आय भी अपेक्षाकृत कम होती है।

मशीनी खेती में कृषि यंत्रों की मरम्मत और पुर्जों की सप्लाई एक गम्भीर समस्या है। जब खेतों में ट्रैक्टर बिगड़ जाता है तो उसे ठीक करने के लिए कुशल कारीगर मिलना कठिन हो जाता है। ट्रैक्टरों के व्यापारी कृषकों की सहायता करने के बदले उनसे अधिक से अधिक पैसा प्राप्त करने का यत्न करते हैं।

प्रशिक्षित ड्राइवरों और मैकेनेकों की कमी भी एक प्रमुख समस्या है। अकुशल मैकेनिकों द्वारा ट्रैक्टरों की मरम्मत करने से ट्रैक्टर-मालिकों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है।

यद्यपि मशीनी खेती अभी भारत में बहुत लोकप्रिय नहीं हुई है, फिर जितनी कुछ लोकप्रियता मिली है उसका कारण इसका सस्ती या अधिक उपज देने वाली होना नहीं; वे कारण और हैं। मुसलमानों के पाकिस्तान चले जाने से श्रमिकों का अभाव हो गया है। परिणामस्वरूप लोगों को ट्रैक्टरों द्वारा खेती करने के तरीके को अपनाना पड़ा। एक कारण और भी है—भूमि सुधार कानूनों द्वारा भूमि का स्वामित्व कृषक को दिए जाने के कारण भूमि के मालिकों ने ट्रैक्टरों की सहायता से अधिक से अधिक क्षेत्र में स्वयं खेती करना शुरू कर दिया।

शिक्षितों में फैली बेकारी के कारण भी यंत्रीकृत कृषि लोकप्रिय हुई और शिक्षित व्यक्ति हल की अपेक्षा ट्रैक्टर की सहायता से खेती करना अधिक पसन्द करता है।

यंत्रों की सहायता से खेती करने में भारी पूंजी लगानी पड़ती है। ट्रैक्टर द्वारा एक एकड़ भूमि में की गयी खेती पर १७३) व्यय होता है जबकि हल द्वारा इतनी ही भूमि पर १०६ रु०।

सिंचित क्षेत्रों में ट्रैक्टर द्वारा की गयी खेती से प्रति एकड़ कुल औसत आय २४६ रु० ५६ नये पैसे होती है और असिंचित क्षेत्रों में ६८ रु० १४ नए पैसे जबकि हल द्वारा की गई खेती से सिंचित क्षेत्रों में प्रति एकड़ औसत आय २६७ रुपए ६० नए पैसे और असिंचित क्षेत्रों में प्रति एकड़ १४७२ रु० ७० नये पैसे।

इन आंकड़ों से भली प्रकार स्पष्ट है कि ट्रैक्टरों द्वारा की जाने वाली खेती अधिक सस्ती और उपयोगी है, अथवा बैलों द्वारा की जाने वाली। ● ●

जायगी। इसके अलावा जब श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो तब श्रम बचाने के यंत्रों का उपयोग अवैज्ञानिक और अनर्थकारी है। ग्रामोद्योग का संरक्षण भी गाय ही सबसे ज्यादा करती है।

पर ट्रैक्टर के मुकाबले में बैल के उपयोग का सवाल हिन्दुस्तान का न केवल आर्थिक, बल्कि सांस्कृतिक सवाल भी है। अगर हमें ट्रेक्टर को रखना हो तो गाय और बैल को खाने का निश्चय करना पड़ेगा। बैल न केवल अर्थशास्त्र की दृष्टि से उपयोगी है बल्कि वह मानव और पशुओं के बीच होने वाले संघर्षों की लक्ष्मण रेखा भी है। और इस तरह उसका सांस्कृतिक महत्त्व भी कम नहीं!

सैकड़ों वर्षों के बाद जब ऐसा मौका देश में आया है कि हम अपने हाथों भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, उस समय भारतीय संस्कृति, भारतीय परम्परा, भारतीय वस्तुस्थिति और परिस्थिति इन सबका ख्याल रखते हुए नव-निर्माण की जो दिशा हमें लेनी चाहिए, वह लेने के बजाय हम पश्चिम के देशों की अंधी नकल करने में अपना गौरव समझते हैं! ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

काँदला का मुक्त बन्दरगाह ?

यात्री

'सम्पदा' के पाठक जानते हैं कि देश विभाजन के पश्चात् कराँची का बन्दरगाह भारत के हाथ मे नहीं रहा था। इससे जहाँ कराँची के जहाजी यातायात में लगे हुए हजारों व्यापारी व कर्मचारी अपनी आजीविका से वंचित हो गये, वहां कराँची के बन्दरगाह के हाथ से चले जाने के कारण उत्तरी भारत के व्यापार को गहरा धक्का लगा, उसके प्रतिकार के लिये स्वतंत्र भारत में कांदला के नये बन्दरगाह का विकास किया गया, यह बन्दरगाह अत्यन्त समर्थ और सब नये साधनों से युक्त है, सिन्ध के सम्पन्न और अनुभवी व्यापारियों की प्रतिभा और सरकार के सहयोग से यह बन्दरगाह बहुत ही विकसित हो गया है।

पिछले कुछ वर्षों से भारतीय व्यापारियों की मांग थी कि भारत में भी मुक्त व्यापार के केन्द्र के रूप में दो बन्दरगाह खोले जाएं। मुक्त व्यापार केन्द्र का आशय यह है कि उस बन्दरगाह में आने वाले किसी माल पर तस्कर नहीं लगे। हाँगकाँग इसी तरह का बन्दरगाह है। तटकरों से मुक्त होने के कारण यहां व्यापार और उद्योगों का असाधारण विकास हुआ है; क्योंकि यहां सब कच्चा माल तटकर न लगने के कारण बहुत सस्ता पड़ता है और इसलिये उत्पादन-व्यय बहुत कम रह जाता है।

भारत सरकार ने फिलहाल दक्षिण के किसी बन्दरगाह के सम्बन्ध में विचार नहीं किया किन्तु कांदला के बन्दरगाह को स्वतंत्र बन्दरगाह बनाने पर विचार किया है, यद्यपि अभी तक इसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय नहीं हुआ, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस बन्दरगाह को मुक्त व्यापार केन्द्र घोषित कर देगी।

संभावित जानकारी के अनुसार एक निश्चित क्षेत्र मुक्त व्यापार के लिये घोषित किया जाएगा। इस प्रदेश के चारों ओर एक मजबूत कांटेदार तार की बाड़ बना दी जायगी और रेलवे साइडिंग और आने-जाने के मार्ग के लिये फाटक बनाये जायेंगे। पानी गटर, रोशनी आदि व्यवस्था इसी क्षेत्र में की जायगी। जो कारखाने और कम्पनियाँ अपने गोदाम बनाना चाहेंगी, उन्हें विशेष अनुमति दी जायगी। इसी तरह माल उतारने लदान, करने तथा पैकिंगत था प्रोसेसिंग आदि के लिये व्यापारियों को किराये पर जमीन दी जायगी।

भारत के जिन उद्योगों के निर्यात को यहां बने कारखानों से हानि पहुँचेगी, वे उद्योग यहां स्थापित नहीं किये जायेंगे, जैसे सिलाई की मशीनों का आजकल बहुत निर्यात हो रहा है, इसलिए सिलाई की मशीनों का उद्योग यहां स्थापित नहीं किया जायेगा।

कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन्हें तटकर से मुक्ति मिलने पर ही प्रोत्साहन मिल सकता है और तभी वे दुनिया के बाजार में टिक सकते हैं। ऐसे उद्योगों को कांदला-बन्दरगाह में न केवल स्थापित किया जायेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा की वृद्धि के लिए मध्यपूर्व तथा अफ्रीका के देशों को निर्यात के लिये कांदला के बन्दरगाह का विशेष रूप से विकास किया जायेगा। यह ध्यान रखा जायेगा कि यहां व्यापार से निर्यात की अपेक्षा आयात न बढ़ने पाये।

हमने ऊपर चर्चा की है कि हाँगकाँग भी इसी तरह का बन्दरगाह है, हाँगकाँग के अतिरिक्त सिंगापुर, कोपनहेगन, स्टाकहोम, हैमबर्ग आदि बन्दरगाह भी इसी तरह के मुक्त व्यापार केन्द्र हैं। यही कारण है कि विभिन्न देशों के यात्री इन स्थानों से एक घड़ी, एक कैमरा या कोई अन्य वस्तु बहुत सस्ते दामों में खरीद लेते हैं। उन्हें व्यापार करने के लिये एक-सी अधिक वस्तुयें लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अमेरिका में भी न्यूयार्क, न्यूआर्लियन्स, सॉनफ्रांसिसको, लॉसएञ्जल्स और सियेटल ऐसे ही बन्दरगाह हैं। अमेरिका में वायु यातायात के एक आध केन्द्र को भी मुक्त व्यापार केन्द्र मान लिया गया है। अमेरिका में १९३४ के सेलर एक्ट के अन्तर्गत इस प्रकार के मुक्त व्यापार केन्द्र खोले गये थे।

हाँगकाँग, सिंगापुर आदि बन्दरगाह अत्यन्त सम्पन्न हो गये हैं। यह आशा की जाती है कि कांदला के परीक्षण में सफलता पाने के बाद भारत सरकार दक्षिण भारत में कोचीन या किसी अन्य बन्दरगाह पर मुक्त व्यापार केन्द्र स्थापित कर सकेगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कृषि-उत्पादन की समस्या

जे० महालनवीस

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा दूसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्य उत्पादन के लक्ष्य में कम सफलता मिली है इसका कारण औद्योगीकरण की तुलना में अपर्याप्त साधनों का जुटाव रहा है। उद्योगों के निर्माण तथा उनकी वृद्धि में सभी प्रकार के आवश्यक साधनों के जुटाने में कोई कसर नहीं रखी गई, जबकि कृषि की उन्नति में साधनों को जुटाने में बड़ी ढील बरती गई। वस्तुस्थिति यह है कि सरकार अपने भूमिसुधार के लक्ष्य से डगमगा गई है। मध्यममार्गीय अर्थव्यवस्था को अपनाने का जो ढोंग रचा गया, उसको भी समुचित रूप से पूरे जोश के साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सका। सत्तारूढ़ दल को कृषि-उत्पादन बढ़ाने की अपेक्षा अपने पक्ष में मत-वृद्धि की ही चिन्ता रही, जिससे वह समुचित ध्यान इस ओर नहीं दे सकी। प्रजातंत्र शासन-पद्धति में सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों की अपेक्षा सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता दल की नीति को अधिक सफल बना सकते हैं और अनेक नवीन सुधारों को यथाशीघ्र सर्वग्राह्य बना सकते हैं। परन्तु यह भावना हमारे देश में कुछ मुट्ठीभर लोगों को छोड़कर, कहीं भी दिखाई नहीं देती, ऐसी स्थिति में यदि देश की खाद्य समस्या बिगड़ती जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

देश के सम्मुख समस्याएं

देश के चहुंमुखी विकास में अन्न का इतना संग्रह करना आवश्यक है जिससे आम जनता को तंगी महसूस न हो और खाद्यान्न की मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सके।

आज खाद्यान्न के क्षेत्र में घाटे की अर्थव्यवस्था है; क्योंकि जिस तेजी से खपत व मांग बढ़ रही है उसके अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। योजना आयोग तथा सरकार दोनों की ओर से यही कहा जाता है कि खाद्यान्न के उत्पादन में इस योजना काल में बहुत कुछ वृद्धि हुई है जिससे विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में भविष्य में कठिनाई कम हो सकेगी और उपलब्ध विदेशी मुद्रा से नई योजनाओं में काफी मदद मिल सकेगी। योजना आयोग का कहना यह भी है कि उसने अन्न-संग्रह के मामले में बिलकुल भी उदासीनता नहीं दिखाई और हमेशा खाद्यान्न की पूर्ति के विषय में जोर देता रहा। १९५५ में उसको यह बात मालूम हुई कि नदी घाटी परियोजनाओं, रासायनिक खाद के जोरों से उत्पादन और कृषि सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान में वृद्धि से अनाज की पैदावार खूब बढ़ी, १९५१ से १९५५ तक इन तमाम बातों के आधार पर कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होती रही।

१९४७ से १९५१ तक की खाद्य स्थिति का विवेचन करना व्यर्थ ही है; क्योंकि वह समय देश में राजनीतिक उथल-पुथल का समय था जिससे भूमिसुधार करने तथा कृषि उत्पादन में सुधार लाने में सरकार कोई स्थिर तथा ठोस नीति नहीं अपना सकी। देश में अन्न वितरण की राशन पद्धति, खाद्यान्नों के मूल्य का नियंत्रण और अन्न के क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिबन्ध उत्पादन वृद्धि में बाधाएं ही साबित हुईं। इन बाधाओं में से कई बाधाएं प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में दूर हो गईं। खाद, उत्तम बीज, तकनीकी सहायता तथा कृषि सम्बन्धी उपकरणों को किसानों की सहायता के लिये मुहैया करने में अधिक दिक्कत नहीं उठानी पड़ी, यद्यपि बढ़ती हुई मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद तथा अन्य अनेक साधन नहीं जुटाये जा सके, जिससे खेती करने में उपयुक्त तरीके नहीं अपनाये जा सके; फिर भी जो काम इस क्षेत्र में उस अवधि में हुआ, वह बड़ा महत्व रखता है।

उत्पादन में वृद्धि

इस प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। इस वृद्धि के मूल कारण खाद्यान्नों पर से मूल्य नियंत्रण हटाया जाना और अन्न संग्रह पर से प्रतिबन्धों का अन्त किया जाना था। इस प्रकार सभी प्रतिबन्धों के अन्त किये जाने से उत्पादकों में नई आशा का संचार हुआ, उन्हें अब खुशी थी कि वे खाद्यान्नों में मूल्य वृद्धि करके खूब नफा कमा सकेंगे; किन्तु १९५३ और १९५४ में दो लाभकारी मानसूनों ने देश की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

खाद्यान्न की स्थिति को बिल्कुल बदल दिया। उत्पादन इतना बढ़ा कि खाद्यान्नों का मूल्य बहुत निम्न स्तर तक गिर गया। इस मूल्य की निरन्तर गिरावट से सरकार भी घबड़ा गई कि कहीं इससे किसानों की स्थिति में बिगाड़ न आ जाय। इसलिये मूल्य में स्थिरता कायम करने के लिये सरकार को बाजार में उतरकर अतिरिक्त अन्न संग्रहालयों की स्थापना के लिये अन्न की खरीद करनी पड़ी। १९५१ से १९५६ तक सरकार ने अन्न उत्पादन की ओर खूब ध्यान दिया, उत्पादन वृद्धि के लिए सभी साधन जुटाये गये तथा अनेक उपाय काम में लाये गये। कई नदी-घाटी परियोजनाएं चालू की गईं, जिनसे वर्षा के पानी पर निर्भर रहने वाली खेती की स्थिति में काफी सुधार हुआ। केवल १९५३ और ५४ के ही वर्ष थे जब यकायक मौसम में सुधार आने के कारण खाद्यान्न के क्षेत्र में घाटे की पूर्ति की जा सकी।

फिर कमी

लेकिन १९५६, ५७, ५८ और ५९ में उत्पादन स्थिति निरन्तर बिगड़ती गई, जिसकी वजह से आज देश इस दशा में है कि देशवासियों को पेट भर भोजन देने के लिये भारी मात्रा में विदेशों से अन्न का आयात लाजमी हो गया है। यही स्थिति एक बार १९५२-५३ में भी पैदा हुई थी, जब सरकार को स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिये विदेशों से अन्न के आयात पर १०० करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा था, कई क्षेत्रों में 'राशनिंग' भी लागू किया गया था। इस प्रकार स्वतंत्रता-प्राप्ति के १२ वर्ष बाद तक भी अनेक उपाय करने पर भी खाद्यान्न की कमी को दूर नहीं किया जा सका और आज भी देश की यह दशा है कि उसे परिस्थितियों से बाध्य होकर अनाज का भारी मात्रा में लाजमी तौर पर आयात करना पड़ रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये देश में कृषि-उत्पादन की समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस बात से कोई भी इन्कार न करेगा कि इस देश के अधिकांश हिस्सों में पुराने ढंग से ही खेती की जाती है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरीका और इटली की तुलना में भारत में प्रति एकड़ उपज बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण सिंचाई में अस्थिरिता है; क्योंकि हमारी समस्त छोटी-बड़ी कृषि योजनाएं बहुत कुछ वर्षा के पानी पर निर्भर करती हैं। अन्य कृषि उपयोगी साधन जुटाने और खेती करने के अनेक वैज्ञानिक तरीके अपनाने पर भी पानी की समस्या हल किये बिना सब कुछ व्यर्थ जाता है। सूखा पड़ना और बाढ़ की समस्या, हमारे देश की ऐसी समस्याएं हैं, जिनकी वजह से उत्पादन के विषय में निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, सिंचित भूमि के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि तभी संभव हो सकेगी जब समस्त खेती को एक योजना बद्ध सिंचाई योजना के अन्तर्गत लाया जाय, अब यह तो स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में उत्पादन में वृद्धि ज्यादातर उपयुक्त मौसम के कारण ही हुई, किन्हीं अन्य कारणों से नहीं।

कृषि उत्पादन में स्थाई तौर पर वृद्धि होती रहने के लिये एक निश्चित लम्बी अवधि तक सारे देश में कृषि के प्राविधिक रूपान्तरण के काम को सक्रियता से आगे बढ़ाया जाना उपयोगी होगा ताकि कृषि के क्षेत्र में श्रम उत्पादकता की वृद्धि की जा सके। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का लगातार खूब प्रचार किया जाय। आधुनिक और देसी तरीकों का साथ-साथ प्रयोग करने में सुधार करने और अर्धयंत्रीकृत कृषि औजारों के उपयोग पर मुख्य रूप से जोर दिया जाना चाहिये। उत्पादकों की सभी तरह की दिक्कतों को दूर करके उनकी मैत्री को आगे बढ़ाकर उसे एक नई मंजिल पर ले जाना होगा ताकि कृषि को सक्रिय सहायता व समर्थन प्राप्त हो सके और कृषि आधुनिक आधार पर खड़ी हो सके। इस बात का पूरा-पूरा प्रयत्न किया जाय कि दस वर्षों के अन्दर देश भर में कृषि के जल-संरक्षण के काम को बुनियादी रूप में पूरा कर लिया जाय, बड़े-बड़े जलाशयों के अलावा बाढ़ से बचाव, सिंचाई और जलविद्युत शक्ति पैदा करनेवाली मझोली तथा छोटी बहुधन्धी परियोजनाएं बड़ी संख्या में निर्मित की जाएं। एक दीर्घकालीन योजना के कार्यक्रमों के अन्तर्गत, मिट्टी का सुधार, खादों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, उचित रूप से पौधों की बुवाई, पौधों की हिफाजत, भूमि-सुधार की ओर दृढ़ निश्चय, सिंचाई के साधनों में वृद्धि, सुधरे बीजों का उपयोग और कृषि औजारों में सुधार आदि को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने से ही देश का कृषि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उत्पादन लगातार और तीव्र गति से उन्नति की दिशा में बढ़ सकता है।

अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक बाधाओं को तभी दूर किया जा सकेगा जब देश की बिखरी हुई जनशक्ति को संगठित करके एक जुट इस खाद्य समस्या के हल की ओर लगाया जाय। योजना काल की समाप्ति तक खाद्य-समस्या के गंभीर रूप धारण करने से बचने के लिये पर्याप्त अन्न-संग्रहालयों की स्थापना हो, जिससे मूल्य-वृद्धि रोकी जा सके। खाद्यान्न के वितरण में नियंत्रित उचित पद्धति अपनाना अब बहुत आवश्यक हो गया है।

जातिभेद को छोड़कर पड़ौसी देश चीन की भी प्रमुख समस्यायें कुछ वर्ष पूर्व वहीं थीं, जो आज हमारे सम्मुख हैं; परन्तु उसने अनेक गंभीर समस्याओं से घिरा रहने पर भी अपने खाद्य उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। चीन को १९३६ से १९४९ तक राजनैतिक अस्थिरता और गृहयुद्ध की स्थिति से गुजरना पड़ा, जिससे उसकी समूची अर्थ-व्यवस्था नष्ट हो गई थी। लाखों लोग हर साल बेकारी और भुखमरी से सड़कों पर अपने दम तोड़ते थे। ऐसी दशा में चीन की सरकार के समक्ष सर्वप्रथम खाद्य-उत्पादन में वृद्धि का प्रश्न था। इस समस्या को हल करने में वहां सरकार ने अनेक भूमि सुधार लागू करके उत्पादकों में नया जोश भरा। उनके सामने देश के खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य का नक्शा रखा गया। उनको अपनी नई तजवीज़ के अनुसार अनेक प्रकार की सहायता देकर नये सिरे से संगठित किया गया। निश्चय ही वहां की सरकार ने कुछ सख्ती से भी काम लिया, लेकिन यह सख्ती भूमि सुधारों के मामले में ही बरती गई।

चीन की अधिकांश जनता को नहरें खोदने के काम पर लगा दिया गया। कुछ ही वर्षों में सिंचित प्रदेश का क्षेत्रफल ३५ प्रतिशत बढ़ गया। इस असाधारण सफलता का अन्नोत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। केवल कृषि-सहकारिता व कम्यून इतना अच्छा परिणाम उत्पन्न करने में इतना सफल न होते। चीन का किसान खूब परिश्रम करता था और गहन खेती करता था। वहां की भी जनसंख्या के लिए यह आवश्यक भी था। जब सिंचाई की सुविधा अच्छी तरह मिल गई, तब उसका परिश्रम फल भी मिला।

भारत भी खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता था और हो सकता है; यदि केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें अफसरी मनोवृत्ति का त्याग कर दें और भूमि-सुधारों के कार्यान्वयन हेतु सामान्य हित की दृष्टि से दृढ़ निश्चय तथा विश्वास के साथ काम करें।

यदि हम कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाते हैं, तो निश्चितरूपेण हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं पनप सकेगी। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए अन्न-भण्डारों में पर्याप्त अनाज संग्रह करने, अन्न की बरबादी पर रोक, तथा सिंचाई की अधिकतम सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। ● ●

सुभाषित रत्नमाला

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

७ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था। कई वर्ष से पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी! अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा में प्रकाशित हो रहा है—

- वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी सुविधापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं।
- श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ।
- पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियाँ, जिनके उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सकें।
- आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य।
- उपहार और पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयुक्त।

मूल्य एक प्रति १.०० रु०। 'सम्पदा' के ग्राहकों से ००.७५ न० पै० प्राप्त होने पर 'बुक पोस्ट अन्डर-पोस्टल सर्टिफिकेट' द्वारा भेजी जाएगी। स्कूलों-कालेजों और पुस्तकालयों को १० प्रतियाँ ७.०० रु० में।

प्रकाशक :
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सर्वोदय पृष्ठ

यरवदा व अम्बर चरखा

अप्रैल १९५९ से अगस्त १९५९ तक यरवदा चक्र तथा अंबर चरखे पर कते हुए सूत और दोनों साधनों पर हुई कताई के आंकड़े इस प्रकार हैं :

यरवदा

औसत कत्तिन संख्या	औसत उत्पादन (रतल में)	मजदूरी प्रति कत्तिन
७८२२	१९०८६	४.२०

अंबर

औसत कत्तिन संख्या	औसत उत्पादन (रतल में)	मजदूरी प्रति कत्तिन
१०७३	५२२१	१२.४८

इन पाँच महीनों में यरवदा चक्र द्वारा कुल मजदूरी के रु० १,६४,०८२ चुकाये गये हैं, जबकि अम्बर द्वारा इसी समय में रु० ८०,३५६ चुकाये गये हैं। मजदूरी की दर समान गिनकर हिसाब किया जाय तो अम्बर में चुकाई गई रकम लगभग ड्योढ़ी याने रु० १,२०,५३४ होने जा रही है।

गत साल सौराष्ट्र के समस्त खादी उत्पादन में यरवदा तथा अम्बर का अनुपात ७५:२५ का था। इन पांच महीनों में यह अनुपात सुधर कर ५८:४२ का हुआ है। केन्द्रों का झुकाव निश्चित गति से अम्बर की ओर होता जा रहा है। उसकी यह स्पष्ट निशानी है। हर एक यरवदा चक्र पर कुल ४.२० नये पैसे की कमाई हुई है, जबकि अम्बर पर १२.४८ नये पैसे की होती है। इसमें भी अम्बर पर दी जाने वाली मजदूरी की दर यरवदा के अनुसार हो तो वह कमाई लगभग रुपए १८.७२ हो जाती है।

यह भी जानिए !

हमारे देश की आधी आबादी की यानी करीब २० करोड़ लोगों की, फी आदमी माहवारी आमदनी १४.६ रु० है, यानी रोजाना आठ आने से भी कम। हम में से लगभग १० या ११ फीसदी लोग ही दिन में एक रुपये से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। इससे हमारे देश के लोगों की गरीबी का अन्दाज लगाया जा सकता है। भारत की आबादी ३८ करोड़ है, जिसमें देहाता आबादी ३१.५ करोड़ है। औसत राष्ट्रीय सालाना आमदनी प्रति व्यक्ति १०४ रु० है।

२ करोड़ लोगों के पास प्रतिदिन १ घंटे या उससे भी कम का काम है। २ करोड़ ७० लाख लोगों के पास प्रतिदिन २ घंटे या उससे भी कम का काम है। ४ करोड़ ५० लाख लोगों के पास ४ घंटे या उससे भी कम का काम है।

गरीबी की हद

बीस करोड़ लोग रोजाना आठ आने से कम में गुजारा करते हैं। लेकिन कई करोड़ आदमी तो इससे भी कम खर्च में गुजारा करते हैं। जैसा कि नीचे दिखाया है :—

संख्या	वार्षिक खर्च	दैनिक खर्च
६ करोड़ व्यक्ति	१०१ रु०	५ आने या कम
४ करोड़ व्यक्ति	७८ रु०	४ आने या कम
२ करोड़ व्यक्ति	३८ रु०	२ आने या कम

सूतकारों की आय

सूतकार (परंपरागत)	२० से ४० रु०
सूतकार (अम्बर)	६० से ६०० रु०

देहाती आय-स्तर की तुलना में यह आय कम नहीं है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गाय न हो तो हिन्दुस्तान जिन्दा नहीं रह सकता। हिन्दुस्तान की जिन्दगी का आधार खेती पर है और खेती का आधार गाय पर। हिन्दुस्तान में ट्रैक्टरों की बात करना फिजूल की बकवास है, जो यह बात करते हैं, वे हिन्दुस्तान की हालत को नहीं जानते।

—ढेबर भाई

जब यरवदा चक्र की मजदूरी की दर तय हुई तब ऐसा अन्दाज किया गया था कि रोजाना ५० नये पैसे अथवा मासिक १५ रु० की कमाई उस पर हो सकेगी। जब इसी तरह की दर अम्बर के लिये निश्चित की गई तब रोज १ रु० अथवा तीस रुपया मासिक की कमाई हो सकेगी, ऐसा अनुमान किया गया था। क्या अम्बर और क्या यरवदा चक्र, दोनों में किसी से भी निर्धारित कताई हम नहीं करा सके हैं। यरवदा में यह अनुपात १००:२८ है। जबकि अम्बर का अनुपात १००:४१.६० है। यरवदा को जहां १०० रु० देना चाहिये वहां वह २८ रु० दे सकता है। और अम्बर को जहां १०० रु० देना चाहिए वहां वह ४१ रु० ६० नये पैसे दे सका है।

दूसरों के लिए जीना सीखो

आजकल सरकार की जो तीसरी योजना बनने जा रही है, उसमें पांच साल में ४,८०० करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था है। यानी हर साल ९६० करोड़; हर महीने में ८० करोड़ या हर रोज २॥ करोड़ रु०! यानि सरकार आज हर आदमी के लिए हर रोज एक आना अपने प्लानिंग के जरिए खर्च करती है। इसीलिए मैं इस योजना को 'एक आने की योजना' कहता हूँ। हमारे साथ यह जो ब्रह्मानन्द है, साथी पदयात्री, उसका तेल आदि पर रोज जो खर्च होता है, वह भी एक आने से ज्यादा है। तो आप यह समझ लीजिए कि पूरी पंचवर्षीय योजना ब्रह्मानन्द के तेल के खर्च के बराबर है। दूसरी ओर, अगर आप सब लोग रोज अपना आधा घण्टा या एक घण्टा समाज को समाज के लिए देंगे, तो पंचवर्षीय योजना का आठ गुना काम होगा। इससे सभी की बरकत होगी। इसके बदले अगर सब अपना कार्य संभालते हैं, सबकी अपनी छोटी-छोटी गिरोह-बन्दी होती है, तो गांव में बाहर वालों का दखल बढ़ता है। सरकार का, साहूकार का, सबका दखल चलता है। लेकिन गाँव वालों के पास ज्यादा वोट होते हुए भी उनकी कुछ नहीं चलती। गांव वाले सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे, तो ताकत नहीं बढ़ेगी। गांव वाले भूमिदान देंगे, तो भूमिहीनों को जमीन मिलेगी; सम्पत्ति दान देंगे, तो सम्पत्ति अच्छे काम में लगेगी; सर्वोदय-पात्र रखेंगे, तो सेवा-सेना खड़ी होगी, और तब गाँव की ताकत बढ़ेगी।

—विनोबा

नया अम्बर चर्खा!

अहमदाबाद में खादी ग्रामोद्योग प्रयोग समिति ने अम्बर चरखे के एक नये नमूने का डिजाइन तैयार किया है। ऐसा दावा किया गया है कि यह नया चरखा वर्तमान अम्बर चरखे से सस्ता और अधिक अच्छा है। इसकी कीमत रु० ७० है जबकि पहले वाले अम्बर चरखे की कीमत रु० ९५ है।

इस नये चरखे से एक व्यक्ति दो रुपया प्रतिदिन कमा सकता है जबकि वर्तमान चरखे से केवल ७५ नये पैसे ही कमाये जा सकते हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनीतिक अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिकअली

सम्पादक : श्री सुनील गुह

★ हिन्दी में अनूठा प्रयास

★ आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख

★ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,

७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नील नदी पर अस्वान बाँध

अशोक

नील नदी का पानी मौसम के अनुसार कम-ज्यादा होता रहता है। प्रतिवर्ष अगस्त व नवम्बर के बीच बाढ़ के मौसम में पानी खतरे के स्तर को पार कर जाता है। सिंचाई की आवश्यकताएं पूरी करने के बाद भी कुल मिला कर नील नदी का ८५ प्रतिशत जल व्यर्थ ही भूमध्य सागर में गिर जाता है और बाढ़ के कारण धन-जन की भी पर्याप्त हानि होती है। वर्ष के बाकी महीनों में 'मिस्र के वरदान' नील नदी का पानी इतना कम हो जाता है कि सिंचाई के लिए भी पूरा नहीं पड़ता। वर्ष के शेष महीनों में भी धरती प्यासी न रहे, इसीलिए नील नदी के पानी को जमा करने की आवश्यकता महसूस हुई।

इस समस्या के हल के लिए ही पुराने अस्वान बांध (वास्तव में जलाशय) का निर्माण १८९८ में शुरू हुआ जो १९०२ में जाकर पूरा हुआ। इसकी क्षमता थी ९८ करोड़ घन मीटर (१०० मीटर बराबर ११० गज)। उन दिनों इसके निर्माण पर एल० ई० ३,०४३,००० व्यय आया (एक एल० ई० बराबर २॥ डालर)। किन्तु जब गर्मियों में पानी की और अधिक आवश्यकता अनुभव हुई तब बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय किया गया ताकि पानी जमा करने की इसकी क्षमता २५० करोड़ घन मीटर हो सके। यह काम १९१२ में पूरा हुआ। फिर १९३३ में समुद्र स्तर की अपेक्षा बांध की ऊंचाई १२२ मीटर कर दी गई। तब इसकी क्षमता ५४० करोड़ घन मीटर हो गई और इस पर एल० ई० ४,६०,००० व्यय बैठा। इस तरह इस बांध पर कुल एल० ई० ९१,४३,००० व्यय हुआ। इस बांध की लम्बाई २,१४२ मीटर है। इसमें पानी निकालने के १८० फाटक हैं, जिन्हें दस-दस के १८ ग्रुपों में बांटा हुआ है।

सबसे बड़ी कृत्रिम झील

किन्तु इस जलाशय में दो कठिनाइयां थीं—(क) बाढ़ के दिनों में जो पानी आता है वह अपने साथ रेत भी लाता है, जिसके कारण इसकी क्षमता कम हो जाती है; इसलिए इस जलाशय में तब तक पानी नहीं लिया जा सकता जब तक रेत की मात्रा कम न हो जाए। और (ख) हल्की बाढ़ के समय इसमें पानी नहीं भरा जा सकता। इसलिए एक इतना विशाल बांध बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई, जिसमें कई वर्ष के लिए पानी जमा किया जा सके। दूसरे मिस्र की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगले ४० वर्षों में इसके दुगनी हो जाने की आशा है। इसलिए जनता के निम्न जीवन स्तर को और अधिक न गिरने देने के लिए भी विशाल बांध की आवश्यकता थी। तीसरे औद्योगीकरण के लिए भी इसकी आवश्यकता थी।

इसलिए अस्वान उच्च बांध के निर्माण का निर्णय किया गया। राकफिल (चट्टान और रेत) का बना यह उच्च बांध वर्तमान अस्वान बांध से लगभग २६ गुना बड़ा होगा और उससे ७ किलोमीटर ऊपर की ओर होगा। यह लगभग ३,५०० मीटर लम्बा और १११ मीटर ऊंचा होगा। सतह पर इसकी लम्बाई १,००० मीटर है। इस विशालकाय बांध के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी नील का पानी विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में एकत्र किया जाएगा जो ४,००० वर्ग किलोमीटर में (मिस्र व सूडान दोनों देशों में) फैली होगी और इसकी लम्बाई होगी ५०० किलोमीटर।

बांध के साथ जो अत्यन्त विशालकाय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है, वह भी विश्व का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र होगा। यहां प्रतिवर्ष १० खरब किलोवाट घंटे से भी अधिक बिजली तैयार हो सकेगी। अस्वान की बिजली गोबर से भी सस्ती पड़ेगी। तब अस्वान नगर मध्य पूर्व का पिट्सबर्ग बन जाएगा और संयुक्त अरब गणराज्य के दक्षिणी क्षेत्र का पूरी तरह औद्योगीकरण हो जाएगा।

कार्यक्रम के अनुसार १९६४ के अन्त तक इसका पहला चरण समाप्त होगा और १९७० में दूसरा चरण। पहला चरण समाप्त होने पर दस लाख एकड़ भूमि पुनः खेती योग्य बनाई जा सकेगी और ७ लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र में १२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रूस में सामूहिक फार्मों की सम्पत्ति

वाई० बोरीसोव

सोवियत संघ में किसानों की उत्पादक सहकारिताओं के रूपों में सामूहिक फार्म सबसे बड़ा रूप बन गए हैं। ऐसे फार्मों में समस्त भारवाही पशु तथा अन्य उत्पादक पशुओं का बड़ा भाग, बीज, चारा, फार्म के मकान, खेती की मशीनें तथा दूसरे औजार सामूहिक वस्तु हो गये हैं। ऐसे सामूहिक फार्मों में कृषि उत्पादन के प्रमुख साधनों का उपयोग किसान मिल कर करते हैं।

सामूहिक फार्म के संस्थापकों, किसानों के अगुवा मंडलों ने सार्वजनिक कोश बनाया जिसमें हर परिवार ने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ धन दिया। किसानों ने अपने खेतों के बीच की मेड़ें साफ कर दीं और कृषि सम्बन्धी बड़े मकानों, और पशुओं के एक बड़े भाग, तथा खेती के जरूरी औजारों आदि को उन्होंने सार्वजनिक सम्पत्ति घोषित कर दिया।

सामूहिक फार्मों के नियमों के अनुसार सामूहिक सम्पत्ति दो बड़े भागों में बांट दी गयी : अविभाज्य सामूहिक फार्म कोष जो सामूहिक फार्म की सम्पत्ति है और हिस्से वाला कोश जो किसान को सामूहिक फार्म छोड़ देने की हालत में वापस कर दिया जाता है।

सामूहिक सम्पत्ति में वृद्धि

व्यापक सामूहिकीकरण के आरम्भ होने के कोई ६० वर्षों के भीतर सामूहिक फार्मों की सार्वजनिक सम्पत्ति परिमाण और गुण के रूप में काफी बढ़ी है। उदाहरण के लिए १९६२ की तुलना में सामूहिक फार्मों के अविभाज्य कोश में ३६ गुनी वृद्धि हुई।

१९३० में किसानों के पूरे देश के हिसाब से सामूहिक फार्मों के मूलभूत उत्पादन साधनों के खर्च का प्रायः ६० प्रतिशत थे, अर्थात् उनका प्राधान्य था। आज उनका हिस्सा केवल ३ प्रतिशत है।

साथी जैसा सहयोग और शोषण से मुक्त मेहनतकश

महीने की सिंचाई की जा सकेगी। आजकल मिस्र की केवल ३.९ प्रतिशत भूमि में खेती की जाती है।

बांध के पूरा होने पर मिस्र की कृषि से होने वाली राष्ट्रीय आय ३५ प्रतिशत बढ़ जाएगी। सरकारी आय में ९६ करोड़ डालर की वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय २८ डालर बढ़ जाएगी।

सूडान को भी इससे अमित लाभ पहुंचेगा।

रोमांचक इतिहास

लगभग ५ वर्ष पूर्व १९५५ में राष्ट्रपति नासिर ने पश्चिमी राष्ट्रों से ऋण की मांग की और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। किन्तु ऐन वक्त पर जब अमरीकी विदेश मंत्री ने २७ करोड़ डालर की सहायता यह कहकर मन्सूख कर दी कि मिस्र अपनी कपास सोवियत गुट के देशों को बेच रहा है, तब राष्ट्रपति नासिर ने दृढ़ता से घोषणा की कि विदेशी सहायता मिले न मिले, मिस्र बांध बन कर रहेगा। बांध के लिए धन जुटाने के लिए उन्होंने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और १९५६ में स्वेज संकट विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या बन गया। रूस इस बांध के लिए ९.३ करोड़ डालर ऋण देने को तैयार हो गया, जिस पर ढाई प्रतिशत ब्याज लगेगा (पश्चिमी राष्ट्रों की ब्याज की दर ५ प्रतिशत थी!)। यह ऋण बांध के प्रथम चरण के लिए पर्याप्त होगा। अब न केवल २० लाख डालर के भारी रूसी उपकरण निर्माण स्थल पर पहुंच रहे हैं बल्कि रूसी इंजीनियर और टैक्नीशियन भी सहायता पहुँचा रहे हैं। इस समझौते पर २७ दिसम्बर, १९५८ को हस्ताक्षर हुए थे।

यद्यपि पहले पश्चिमी राष्ट्रों ने सहायता देने से इंकार किया, किन्तु अब फ्रांस और जर्मनी की मदद से यहां ६.७ करोड़ डालर की लागत का एक उर्वरक कारखाना लगभग तैयार हो चुका है। यहां प्रतिवर्ष ८ लाख टन अमोनियम नाइट्रेट बनेगा जो मिस्र के वर्तमान उर्वरक-उत्पादन का चौगुना है। मिस्र को यह भी आशा है कि बांध के दूसरे चरण पर होने वाले ४३ करोड़ २० लाख डालर के व्यय का बड़ा भाग पश्चिमी राष्ट्रों से मिल जाएगा। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की परस्पर सहायता सामूहिक फार्म की विशेषता हैं। सामूहिक फार्म प्रणाली ने सोवियत किसानों के भौतिक और सांस्कृतिक स्तर में पर्याप्त उन्नति की है। खेती से होने वाली उनकी शुद्ध आय कर आदि के बाद क्रान्ति से पहले की अपेक्षा साढ़े चार गुनी अधिक है। साझे की मिल्कियत वाले फार्म से होने वाली आमदनी सामूहिक किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

किसानों की निजी सम्पत्ति

सार्वजनिक सम्पत्ति के समान मालिक होने के अलावा सामूहिक किसानों के पास अपनी निजी सम्पत्ति होती है। सामूहिक फार्म में सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति का ऐसा सन्तुलन रखा जाता है, जिससे किसान के हित सामूहिक फार्म के सदस्य के रूप में और व्यक्ति के रूप में सुरक्षित रहें।

सामूहिक फार्मों के नियमों और सोवियत संविधान में ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार व्यक्तिगत जायदाद में वे सारी चीजें आती हैं, जो उसकी रोज की निजी जरूरतों और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति के अलावा होती है।

रहने का मकान, घर में काम आने वाली चीजें, सांस्कृतिक उपयोग की वस्तुएं और व्यक्तिगत खेत में काम करने के लिए जरूरी कुछ उत्पादन सम्बन्धी सम्पत्ति किसान की निजी जायदाद होती है। यह किस प्रकार की और कितनी होगी, यह स्थानीय अवस्थाओं पर निर्भर करेगा।

आम तौर से एक सामहिक परिवार के पास एक या कई गायें, एक दर्जन या इसके आसपास भेड़-बकरियां, कई सुअरिआं, २० तक मधुमक्खियों के छत्ते, मुर्गियां जिनकी कोई संख्या तय नहीं है, और खरगोश आदि हो सकते हैं। इन्हें रखने के लिए जरूरी मकान और सामूहिक फार्म से मिली जमीन के निजी मुरब्बे में खेती के लिए जरूरी छोटे औजार भी किसान की निजी सम्पत्ति होते हैं। निजी मुरब्बे का आकार देश के अलग-अलग भागों में भिन्न-भिन्न है। वह ०.२५ हेक्टर से १ हेक्टर तक होता है १ हेक्टर यानि ढाई एकड़।

कुछ आंकड़े

१९५९ के आरम्भ के आंकड़ों के अनुसार सामूहिक फार्मों के पास सार्वजनिक स्वामित्व वाले ३२० लाख से अधिक पशु थे, (यह संख्या देश के कुल आंकड़ों का ४५.३ प्रतिशत है।) दो करोड़ से अधिक पशु सामूहिक किसानों की निजी जायदाद हैं। यह संख्या कुल संख्या की २८.६ प्रतिशत है। इनमें कोई १३० लाख गायें हैं, जो सोवियत संघ की कुल संख्या की ३८ प्रतिशत से अधिक हैं। सामूहिक फार्मों में करीब ७४० लाख भेड़ें—देश की कुल संख्या की करीब ५७ प्रतिशत हैं। २२० लाख भेड़ें निजी संपत्ति हैं। यह संख्या कुल संख्या की १७ प्रतिशत है।

सारी जमीन और जोत वाली जमीन का वितरण भी मार्के की चीज है। सामूहिक फार्मों के पास ७,५६४ लाख हेक्टर सार्वजनिक भूमि है, जिसमें १,३१४ लाख हेक्टर जोत वाली जमीन शामिल है। यह कुल खेती वाली जमीन की ६७ प्रतिशत से अधिक जमीन है। सामूहिक फार्मों के निजी मुरब्बों का रकबा ६६ लाख हेक्टर है। ● ●

आप 'सस्ता साहित्य मंडल' की पुस्तकों के प्रेमी हैं। सस्ता साहित्य के व्यापक प्रसार में कृपया योग दीजिये। अपने इष्ट मित्रों, अपने क्षेत्र की संस्थाओं तथा पुस्तकालयों से अनुरोध कीजिये कि वे 'मंडल' की पुस्तकें अपने यहाँ अवश्य रक्खें।

पर ऐसा आप तभी कर सकेंगे
जबकि
'मंडल' के नये प्रकाशनों से
आपका परिचय रहे। इसके लिए आप
जीवन-साहित्य
के ग्राहक बन जाएं उसके प्रत्येक अंक में 'मंडल' के
नवीनतम प्रकाशनों की सूचनाएं रहती हैं
पत्र की सामग्री भी अत्यन्त उपादेय है
वार्षिक मूल्य केवल रु. ४.००

सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब की औद्योगिक समस्याएं और उनका समाधान

श्री मोहनलाल, उद्योग मंत्री, पंजाब

उद्योगों के विकास के लिए आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता, तकनीकी योग्यता और पर्याप्त बिजली शक्ति मुख्य आवश्यकताएं हैं। पंजाब में जिसका अब तक कृषि के क्षेत्र में देश भर में विशेष स्थान रहा है, गत कुछ वर्षों में देश के लिए योजना-बद्ध आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार तेज़ी से उद्योगों का विकास करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ हुए हैं। अपने वर्तमान साधनों को प्रयोग में लाकर पंजाब राज्य इस क्षेत्र में भी कई पहलुओं में अन्य राज्यों से आगे निकलता जा रहा है। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर पंजाब के औद्योगिक विकास में तेजी आना निश्चित है। इससे धन बढ़ेगा और हर एक को रोज़गार मिलेगा।

देश के बटवारे के तुरन्त बाद पंजाब में लगभग ७०० रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां थीं जिनमें कोई ३,६०० आदमी काम करते थे। गत १२ वर्षों में इन फैक्ट्रियों की संख्या ३२०० और इनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या एक लाख से भी अधिक बढ़ गई है। छोटे पैमाने की औद्योगिक यूनिटों की गिनती में भी वृद्धि हुई है। पूरे आंकड़े तो इस समय उपलब्ध नहीं परन्तु अनुमान है कि राज्य में ऐसी २५,००० से भी अधिक यूनिटें हैं। इनमें मशीन टूल, बाइसिकलें, सिलाई की मशीनें, पंखे, रेडियो, घरों में प्रयोग होने वाले बर्तन, फर्नीचर, हौजरी और बहुत सी अन्य रोजमर्रा काम में आने वाली चीजें बनती हैं। राज्य में बड़े उद्योगों की संख्या कम है और निम्नलिखित फैक्टरियां हैं: एक कागज की मिल, दो सीमेंट फैक्टरियां, ७ खांड की मिलें, ६ कपड़े की मिलें, ६ बाइसिकलों की फैक्टरियां, और थोड़े से अन्य उद्योग।

पंजाब की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इससे रोजगार की समस्या गम्भीर हो गई है। कृषिगत भूमि पर तो पहले ही काफी बोझ है और इस बढ़ रही जनसंख्या के लिए रोजगार का प्रबन्ध करने के लिए हमारे पास उद्योगों के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। कृषिगत भूमि पर काम करने वाले लोगों का बोझ हलका करने के लिए उनका कुछ हिस्सा उद्योगों की ओर मोड़ने की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि इस तरह कृषि और उद्योग के क्षेत्र में एकलयता लाकर अधिक धन और खुशहाली पैदा की जा सकती है।

आर्थिक साधन : एक मुख्य आवश्यकता

उद्योगों के विकास के लिए एक मुख्य आवश्यकता आर्थिक साधनों की है। इस सम्बन्ध में पंजाब को विशेष मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे यहां बड़े-बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों की कमी है। पंजाब के उद्योगपतियों के पास अन्य राज्यों के उद्योगपतियों के मुकाबले में बहुत कम साधन हैं। इसके साथ ही पंजाब में जो बैंक हैं, वे भी आमतौर पर अल्पविधि के कर्जे ही दे सकते हैं। किन्तु राज्य में गत कुछ वर्षों में उद्योगों का जोर बढ़ने से लम्बी और दरम्यानी मियाद के कर्जे की मांग बढ़ रही है। यह मांग कुछ हद तक तो सरकार की ओर से उद्योगों को सरकारी खजाने में से रुपया देकर पूरा करने का यत्न किया गया है। बंटवारे से लेकर पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक औद्योगिक कर्जों के रूप में लगभग ६४ लाख रुपए की राशि दी गई है और लगभग २ करोड़ रुपए इसी उद्देश्य के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च करने का फैसला किया गया है। द्वितीय योजना के पहले दो वर्षों में ७८.०८ लाख रुपए छोटे उद्योगों को कर्जों के रूप में दिए गए हैं। तीसरे वर्ष में ३८.०८ लाख रुपए बांटे गए हैं और चौथे साल अर्थात् १९५९-६० के लिए ४२ लाख रुपए रखे गए हैं। चालू साल में इस मन्तव्य के लिए ३४ लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

दरम्याने दर्जे की और छोटी सनअतों को आर्थिक सहायता देने के लिए पंजाब वित्त निगम भी दिन प्रतिदिन बढ़-चढ़कर अपना योग दे रही है। पिछले तीन वर्षों में निगम की ओर से ७५ लाख रुपए वितरित किए गए हैं। गत वर्ष इसने कर्जों के लिए ५४ लाख रुपए दिए।

इन सुविधाओं के अलावा भारत के स्टेट बैंक और कुछ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अन्य बैंकों की ओर से भी अल्प और मध्यमविधि के कर्जे दिए गए हैं और आशा है कि आगामी वर्षों में इनकी ओर से यह आर्थिक सहायता बढ़ती जाएगी, परन्तु यह बात अवश्य माननी पड़ेगी कि उद्योगों के लिए रुपए का प्रबन्ध करने के लिए अपनी आय में से बचत करके रुपया जमा करना भी बहुत जरूरी है। इस बात की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त निगम, सहकारी बैंकों और व्यापारिक बैंकों की ओर से सहायता दी जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र

आवश्यक धन का प्रबन्ध हो जाने से उद्योगों के योजनानुसार विकास के लिए यह जरूरी है कि राज्य के मुनासिब स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाए। बंटवारे के तुरन्त बाद पंजाब सरकार ने विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए लुधियाना, जालन्धर, जमनानगर, पानीपत, सोनीपत और बहादुरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया था। इन क्षेत्रों में लगभग २,००० औद्योगिक प्लाट बनाकर उद्योग कायम करने के लिए इच्छुक लोगों को दिए गए थे। इन क्षेत्रों में अब तक लगभग १,१०० फैक्टरियां लग चुकी हैं और ३०० अन्य बन रही हैं। इनमें अभी ६०० के लगभग और फैक्टरियां लगने की गुंजाइश है।

इन औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा सरकार औद्योगिक एस्टेटों को कायम करने के लिए भी पग उठा रही है। इन सरकारी औद्योगिक एस्टेटों में लगभग ४०० वर्कशापें होंगी। इन कार्रवाइयों से जहां औद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुओं को उत्साह मिला है, वहां इसे एक आरंभ ही कहा जा सकता है और आगामी वर्षों में इस कार्य में बहुत उन्नति होने की आशा है। और भी जहां कहीं उद्योगों के विकसित होने की संभावना है औद्योगिक क्षेत्र और एस्टेटें बनाई जाएंगी। तृतीय योजना के समय में कम से कम ५००० औद्योगिक यूनिट लगाने की गुंजाइश बनाई जाएगी। यह जरूरी नहीं कि सब औद्योगिक क्षेत्र और एस्टेटें सरकार ही विकसित करें। स्थानीय संस्थाएं, सहकारी और पब्लिक लिमिटिड कम्पनियां सब औद्योगिक क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास में अपना भाग डाल सकती हैं।

विशेष इलाकों और एस्टेटों में नियोजन औद्योगिक विकास की खास विशेषता है क्योंकि इससे इन क्षेत्रों और एस्टेटों में उद्योगों के लिए बुनियादी साझी सहूलतों का प्रबन्ध करने में आसानी रहती है। उदाहरण के तौर पर जहां कहीं भी हल्की इंजीनियरिंग की फैक्टरियां खासी गिनती में कायम हो जाएंगी, वहां साझी वर्कशापें स्थापित करना संभव हो जाता है और वहां ऐसी फैक्टरियों की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। द्वितीय योजना में इस प्रकार के प्रोजेक्ट लुधियाना, पटियाला और बस्सी पठाना में शुरू किए गए हैं और सरकार साझी सहूलतों की इस योजना को बहुत से नए औद्योगिक क्षेत्रों में भी चालू करना चाहती है। यहां भी वही बात फिर पैदा होती है कि यह जरूरी नहीं कि सरकार ही साझी सहूलतों के ये सब केन्द्र चलाए, परन्तु हमें यह आशा करनी चाहिए कि प्राइवेट लोग भी भारी संख्या में आगे आएंगे।

एक और समस्या टैक्नीकल महारत की है। इस उद्देश्य के लिए पंजाब सरकार पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण संस्थाएं चला रही है, कई पोलीटैक्नीक और इन्जीनियरिंग कालिज चला रही है। तृतीय योजना में ऐसी और भी संस्थाएं खोली जाएंगी।

कच्चे माल की आवश्यकता

उद्योगों के लिए कच्चे माल की सप्लाई की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में पंजाब अन्य राज्यों से कुछ पिछड़ा हुआ है। हमारे पास जो कच्चा माल है, वह प्रमुखतया कृषि सम्बन्धी है। हमारे यहां होने वाली बड़ी फसलें हैं कपास, गन्ना, तिलहन आदि। परन्तु फिर भी यहां छोटे और बड़े उद्योगों के विकास की काफी गुंजाइश है। इनके विकास के लिए बिजली की बड़ी जरूरत होती है और यह बिजली भाखड़ा बांध के पूरा हो जाने पर पर्याप्त मात्रा में, बंटवारे के समय से दस गुना अधिक उपलब्ध हो जाएगी। परन्तु इससे भी हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। आगामी पांच, छः वर्षों में हमें फिर भाखड़ा के दाएं किनारे पर बिजली घरों का निर्माण करना पड़ेगा। इससे कोयले की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी।

धन, बिजली, टैक्नीकल प्रशिक्षण, आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति की जा सकती है। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय जहाज़ उद्योग की कहानी

सुमति मुरारजी बहन

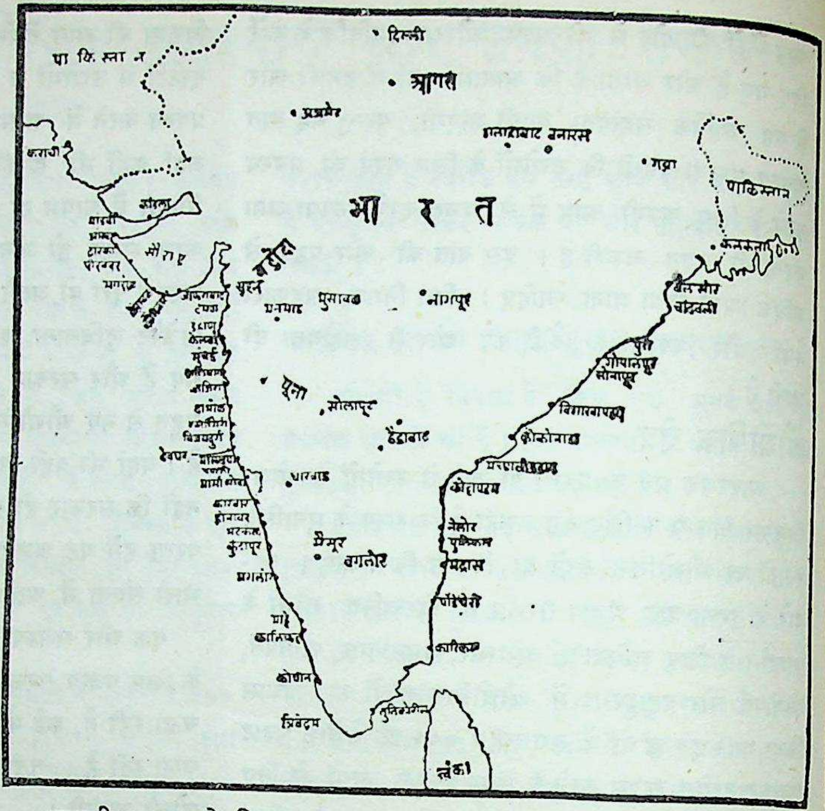

जहाजी व्यापार के लिए भारत का ३००० मील लम्बा विशाल समुद्री तट

भारत एक प्राचीन देश है—इसके तीन ओर सागर है, उत्तर में इसका प्रहरी हिमालय है और हजारों जलधाराएँ तथा महान नदियां, जिन्होंने यहां के सामाजिक विकास में विशेष योग दिया है, इस भूमि को सींचती है। इन जल मार्गों द्वारा ही देश के भिन्न नगरों के बीच सम्पर्क स्थापित होना सम्भव हो पाता था।

भारतीय जल-यातायाय के क्षेत्र में सदा ही बहुत आगे रहे हैं। भारत में जहाज-निर्माण की कला उतनी ही पुरानी है जितनी उसकी संस्कृति। प्राचीन काल से भारतवर्ष ने सामुद्रिक उद्योग के द्वारा संसार की अन्य संस्कृतियों से से सम्बन्ध कायम रखा और अन्य राष्ट्रों तथा जातियों को सम्पन्न बनाया। इस जल उद्योग के बगैर हमारी संस्कृति, वास्तव में, मूल रूप से ही निष्प्राण रहती।

भारतीय जहाज उद्योग की मनोरंजक कहानी दोहराने के लिए हमें पुरातत्व-विज्ञान, कला, साहित्य तथा मुद्रा-विज्ञान की ओर ध्यान देना होगा। जल तथा जहाज-उद्योग के प्रथम प्रमाण-चिन्ह मोहन जोदड़ो के ध्वंसावशेषों में मिलते हैं जो ५,००० वर्ष पुराने हैं। सर्वप्रथम साहसी व्यक्ति वृक्षों के खोखले तनों में ही अपार जल-राशियों पर अपनी साहसपूर्ण यात्रा को निकल पड़े थे। आज उनके उत्तराधिकारियों ने संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए तैरने वाले नगरों का—'जलउषा' जैसे लकड़ी और इस्पात के विशाल जहाजों का, निर्माण कर लिया है।

वैदिक साहित्य में हमारे जल यातायात-उद्योग के सम्बन्ध में अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। अथर्व वेद संहिता की एक ऋचा से यह ज्ञात होता है कि ये नौकाएं जल पर भली प्रकार से चलती थी, "इनकी कड़ियां चौड़ी होती थीं, यह आराम-देह, लम्बी-चौड़ी तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से सुसज्जित होती थीं; उनकी पतवारें मजबूत तथा बनावट त्रुटिहीन होती थी।"

'राजवल्लिया' नामक पाली पुस्तक के अनुसार जिस जहाज में विजय तथा उसके अनुगामी बंगाल से भेजे गए थे,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

उसमें ७०० यात्रियों के लिए स्थान था। 'शंख' जातक में एक ऐसे जहाज का उल्लेख है, जो ८०० क्यूबिट (१ क्यूबिट = १८ इन्च) लम्बा ६०० क्यूबिट चौड़ा और २० फैदम (१ फैदम = ६ फिट) गहरा था और उसके तीन पाल थे। इससे यह सिद्ध होता है कि बौद्ध काल में जहाज निर्माण की कला का काफी विकास हुआ था।

मौर्य काल

यूनानी साहित्य में पाये गए कई उल्लेखों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि ३२५ ई० पू० के आसपास भी जहाज-निर्माण भारत में एक मुख्य उद्योग था। एरियन ने जहाज-निर्माण केन्द्रों का, ३० पतवार वाले युद्ध-पोतों का तथा यातायात-नौकाओं का जिक्र किया है।

आंध्र में दूसरी तथा तीसरी शताब्दी ईसवी की जहाज-अङ्कित मुद्राएं पाई गई हैं। इन जहाजों का मस्तक उनके दाहिने हाथ को होता था, उनके सिरों पर एक गोलाकार होती थी। इसके नीचे उनके पतवार बाहर को निकले हुए होते थे जो सीधे शहतीरों के आकार के थे और जिनके सिरों की चम्मचनुमा आकृति होती थी; जहाज का डेक सीधा होता था और उस पर दो गोलाकार चीजें होती थीं जिनमें से दो मस्तूल निकले हुए होते थे—इनमें से प्रत्येक के ऊपरी भाग पर एक आड़ा शहतीर लगा होता था।

इसके पश्चात सांची के स्तूप तथा अजन्ता की गुफाओं के युग में हम पाते हैं कि भारतीय जहाज और अधिक मजबूत, बड़े तथा टिकाऊ हो गए थे।

'युक्तिकल्पतरु' प्राचीन भारत की जहाज-निर्माण कला पर एक प्रामाणिक तथा सम्पूर्ण ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ हमें विभिन्न प्रकार के जहाजों के आकार, रूप तथा उनके उपयोगों के बारे में दिलचस्प बातें बताता है। आकार दृष्टिकोण से दो मुख्य प्रकार के जहाज हुआ करते थे:—१. सामान्य जो देश के अंदरूनी यातायात के काम में लाये जाते थे, तथा २. विशेष, जो विदेशी यात्राओं के लिए थे।

'सामान्य' जहाज के दस उप-प्रकार थे। 'युक्तिकल्पतरु' इन भिन्न प्रकारों के जहाजों के माप का—उनकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, गहराई—पूरा विवरण देता है। 'विशेष' जहाज दो उप-प्रकारों में विभक्त थे। १. दीर्घ तथा २. उन्नत। इन दो उप-प्रकारों की फिर क्रमशः दस और पांच किस्में थीं।

श्रीमती सुमति मुरारजी बहन

सजावट के लिए चार प्रकार की धातुएं उपयुक्त बताई गई थीं: सोना, चांदी, तांबा तथा इन तीनों के मिश्रण से बनी हुई धातु। चार भिन्न प्रकार के रंग, उतने ही प्रकार के जहाजों के लिए अलग-अलग काम में लाये जाते थे। चार मस्तूलवाले जहाजों को सफेद, तीन मस्तूलवालों को लाल, दो मस्तूलवालों को पीला तथा एक मस्तूलवाले को नीला रंगा जाता था। नौका के मस्तक-भाग की बनावट के लिए कई विचित्र और कल्पनापूर्ण आकार प्रस्तावित किए गए थे। पशुओं, पक्षियों, यहां तक कि मानव सरों के प्रतीक उन्हें सजाने के काम में लाये जाते थे। इन सरों पर बहुमूल्य नगीने भी जड़े जाते थे और उनकी ग्रीवाएं स्वर्णहारों से सुसज्जित होती थीं।

इन प्राचीन भारतीय जहाजों पर तीन प्रकार के कमरे (केबिन) होते थे। 'सर्वमंदिर' प्रकार के जहाज में यह कमरा जहाज के एक भाग से दूसरे भाग तक फैला होता था। इस प्रकार के जहाज सेनाएं, पशुओं के दल तथा शाही खजाने के लाने-लेजाने के काम में लाये जाते थे। 'मध्य मन्दिर' नामक जहाज में यह कमरा जहाज के मध्य भाग में बना होता था। इस प्रकार के जहाज आनन्द-यात्राओं के

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लिए थे। 'अग्रमन्दिर' प्रकार के जहाज में यह कमरा मस्तक-भाग की ओर बना होता था ; ऐसे जहाज जल-युद्ध के लिए काम में लाए जाते थे। 'महाभारत' में एक ऐसे जहाज का उल्लेख है। जिसमें पांडव-बन्धु कौरवों के कोष से बचकर भागे थे।

सांची की मूर्त्तियां

सांची की मूर्तियों में भारतीय जहाज-उद्योग के सर्व-प्रथम प्रमाण पाये जाते हैं। स्तूप नं० १ के पूर्वी सिंह द्वार पर नौका का शिल्प-चित्र है, जो लकड़ी के कुछ खुरदुरे तख्तों को रस्सियों से भोंड़े रंग से जोड़ कर बनायी हुई दिखायी गयी है पश्चिमी सिंहद्वार पर चित्रित नौका इसकी अपेक्षा अधिक कुशलता से बनायी हुई दिखायी गयी है।

अजन्ता के भित्तिचित्रों में एक शाही बिहार नौका भी है जो 'मध्य मन्दिर' प्रकार की है। इस नौका का 'केबिन' खम्बों पर खड़े हुए शामियाने के आकार का है। कर्णधार को एक सीढ़ी पर खड़ा हुआ दिखाया गया है और पतवार चलाने वालों को 'बांध' में। अजन्ता के एक दूसरे चित्र में लंका में विजय के जहाज से उतरने का एक अत्यन्त सजीव तथा विस्तारपूर्ण दृश्य प्रस्तुत किया गया है। यह विश्वास किया जाता है कि १,५०० यात्रियों ने इस नौका दल के द्वारा यात्रा की थी। इस चित्र में इस नौका दल के कई अन्य प्रकार जहाज भी दिखाये गये हैं; कुछ पर घोड़े लदे हुए हैं और कुछ पर हाथी।

जावा में बोरोबुदूर की विख्यात भारतीय मूर्त्तियों में चित्रित कुछ जहाज 'कैटामरान' से बहुत अधिक मिलते-जुलते हैं। सातवी-आठवीं ईस्वी तक भारतीय जहाज-निर्माण कला और उद्योग निपुणता तथा कौशल के एक ऊंचे स्तर तक पहुंच चुके थे। बीरोपुर में जिन जहाजों का चित्रण है उनमें से एक का आकार लम्बा और संकरा है और उसका ऊपरी भाग बहुत भारी है। यह लकड़ी की कमानियां पस-लियों के आकार की ओर घूमी हुई हैं। बनावट में ऊपरी भाग के भारीपन के कारण, सुरक्षा के लिए 'आउट-रिगर' की आवश्यकता होती थी। यह 'आउट-रिगर' लकड़ी के अनेक तख्ते या लट्ठे होते थे जो लम्बे बांसों या शहतीरों के द्वारा जहाज से जुड़े होते थे। दूसरे लकड़ी की कमा-नियां घूमी हुई हैं।

जो जहाज बोरोबुदुर में चित्रित पाये गए हैं। वह ६० फिट लम्बे और १५ फिट चौड़े थे। जहाज के मध्य आधार के रूप में एक विशाल शहतीर होता था जिसके ऊपर लकड़ी का पिंजड़ेनुमा आकार बना दिया जाता था। जहाज में माल रखने की जगह अन्दर के ढांचे में तख्ते लगाकर बनायी जाती थी। सारा आकार ऊपरी भाग में इतना भारी होता था कि सुरक्षा के लिए 'आउट-रिगर' जहाज से बाहर को निकला हुआ लकड़ी या धातु का ढांचा—बनवाना अनिवार्य था।

प्रगति के चरण

पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर में 'मध्यमन्दिर' वर्ग के एक शाही बजरे की प्रतिमूर्त्ति है। इस बजरे के 'केबिन' की छत मेहराबनुमा है और वह चार व्यक्तियों की मूर्तियों पर टिकी हुई है। छत से झूलनेवाली 'सीट' लटकी हुई है, जो सम्भवतः इसलिए बनायी गई है कि यात्रियों को सागर यात्रा से पैदा होने वाली मिचलाइट न हो सके। छत से ही रस्सी या जंजीर की तरह की कोई चीज लटकी हुई है ताकि जहाज के हिलने-डुलने पर यात्री अपने को स्थिर रख सकें।

मार्कोपोलो ने जो १३ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में भारत आया था, तत्कालीन भारतीय जहाजों का मनोरंजक और विस्तृत वर्णन छोड़ा है। जहाज देवदारु की लकड़ी के बनाये जाते थे। उनकी बनावट में दोहरे तख्ते लगाये जाते थे, अर्थात् हर तरफ जड़े हुए तख्तों के ढांचे पर ऊपर से आवरण के रूप में तख्तों की एक और बाढ़ लगायी जाती थी। तख्तों के बीच की दरारों को अन्दर और बाहर दोनों तरफ, पुरानी रस्सियों की सन से भर दिया जाता था और अन्त में, उन्हें लोहे की मेखों से जड़ दिया जाता था। जहाज के पेंदे को वनस्पति तेल के साथ कुटे और मिले हुए कोरे चूने और सन के मिश्रण से ढक दिया जाता था।

यह जहाज इतने बड़े होते थे कि १५ से ३०० यात्री और पांच छः हजार टोकरी काली मिर्च ढो सकते थे। यह जहाज पतवारों से चलाये जाते थे और हर पतवार को खेने के लिए चार आदमियों की जरूरत होती थी। इनके साथ छोटी नौकाएं भी होती थीं। जिनकी संख्या कभी-कभी दस तक होती थी, बड़े जहाजों में केवल एक ही 'डेक' होता

(शेष पृष्ठ २८४ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ-वृत्त चयन

राज्य व्यापार निगम का प्रबन्ध व्यय

एक अप्रैल १९५९ को ५०० और अधिक वेतन पाने वाले अफसर, जो राज्जीय व्यापार निगम में नियुक्त थे, क्रमशः १२७ और ६९ थे, केन्द्रीय और क्षेत्रीय निगम कार्यालयों में काम करने वालों की संख्या १९३५ थी, जिनमें से १९६ ऊपर के अधिकारी थे।

इसी तरह कनाडा में भी व्यापार करने के लिए एक राज्य संस्था है, इसमें केवल ५१ अधिकारी हैं। इस संस्था ने १९५८-५९ में ६ करोड़ ५० लाख ५० हजार डालर का कारोबार किया था जो भारत के राज्य व्यापार निगम से कहीं अधिक है। दोनों के कार्यों में कुछ भेद होते हुए भी यह मानना होगा कि भारत में राज्य व्यापार निगम में कर्मचारी बहुत अधिक हैं।

(अनुमान समिति व्यापार निगम की रिपोर्ट)

सूती मिलों में वेतन और बोनस

भारत सरकार ने सूती मिल वेतन मंडल की सिफारिशों पर गहन विचार और सलाह मशविरा करके कुछ निर्णय किए थे। राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि सम्बन्धित संस्थाओं और व्यक्तियों की सलाह से वेतन मंडल की सिफारिशें लागू करवाएं। इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णय पक्के हैं और वेतन मंडल की सिफारिशें लागू करवाने में भी कोई विलम्ब नहीं किया जा रहा। मालिकों के प्रतिनिधियों ने वेतन मंडल स्थापित करने की स्वीकृति दे दी थी और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सलाह से ही दूसरी पंचवर्षीय-योजना के अन्तर्गत यह मंडल स्थापित हुआ था। स्थायी श्रम समिति में मालिकों के प्रतिनिधियों ने यह बात भी मान ली थी कि मंडल की सर्वसम्मत सिफारिशें सबको लागू करनी चाहिए।

सन् १९४७ में औद्योगिक शान्ति प्रस्ताव पास हुआ था। तब से बोनस निर्धारित करने और बांटने का तरीका निकालने के प्रश्न पर विचार होता रहा है। मालिक लोग स्वयं इस बात के इच्छुक रहे हैं कि आपसी समझौते के लिए शीघ्र ही कुछ नियम और सिद्धान्त बन जाने चाहिएं। ११ मार्च १९६० को स्थायी श्रम समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें यह निश्चय किया गया था कि बोनस सम्बन्धी समस्या पर विचार करने के लिए एक बोनस आयोग बैठाया जाय। इसमें यह भी निश्चय किया गया कि मजदूरों को हिस्सों के रूप में बोनस देने के प्रश्न पर भी यह प्रस्तावित आयोग विचार करे। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में स्वयं ही इस बात का संकेत किया था कि बोनस देने के नियमों में संशोधन करने के लिए एक उच्च आयोग बैठाया जाय। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, 'अगर संसद श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक न्याय के दावों को और स्पष्ट करना चाहता है तो उसे एक विधेयक पास करना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई उच्च आयोग भी विस्तारपूर्वक विचार कर सकता है।" अतः बोनस आयोग नियुक्त करके सरकार वह उत्तरदायित्व निभा रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उस पर आ पड़ा है।

इनामी बांड : बचत की नई योजना

भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९६० से बिना ब्याज के पंचवर्षीय पुरस्कार पत्र (इनामी बांड), १९६५ जारी किये हैं। ये वाहक बन्ध-पत्रों (बेयरर बांड्स) के रूप में, दो रकमों के—१०० रुपये और ५ रुपये के हैं। इन बांडों पर ब्याज नहीं मिलेगा और ये १ अप्रैल १९६५ को सममूल्य पर चुकता कर दिये जाएंगे। इनके खरीदारों को उन लाटरियों में शामिल किया जायगा, जिन्हें प्रतिवर्ष १ जून, १ सितम्बर, १ दिसम्बर और १ मार्च को डालकर इनाम निकाले जायंगे। इन इनामों पर आयकर नहीं लगेगा। खरीदारों को उन सभी लाटरियों में इनाम दिया जा सकता है जो बांड की बिक्री के महीने से दो महीने बाद डाली जायं। पहली लाटरी १ सितम्बर १९६० को और आखिरी १ मार्च, १९६५ को डाली जायगी।

सौ-सौ रुपये वाले एक लाख बांडों की प्रत्येक श्रेणी के लिए हर तिमाही कुल ९२,००० रुपये के ४० इनाम दिये जायंगे जो २५,००० रुपये से लेकर ५०० रुपये तक के होंगे। ५ रुपये वाले बांडों की दस-दस लाख की इकाइयों को प्रत्येक श्रेणी के लिए हर तिमाही कुल

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

४६,००० रुपये के २७८ इनाम दिये जायंगे जो ७५०० रुपये से लेकर ५० रुपये तक के होंगे।

इन इनामी बांडों के विषय में जनसामान्य तथा अर्थशास्त्रियों में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक ओर तो लोगों ने इन्हें खरीदने में पर्याप्त उत्साह दिखाया है और दूसरी ओर इस योजना को जुआ कहकर सरकार को बदनाम भी किया जा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस योजना से जो रुपया एकत्रित होगा, उससे देश को अधिक लाभ नहीं हो सकता; क्योंकि ये बांड सरकारी आय के अन्य कई स्रोतों को प्रभावित करेंगे।

पटसन का उत्पादन

● जनवरी से सितम्बर १९५९ की अवधि में इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन की सदस्य मिलों ने पटसन का ७,८२,००० टन माल तैयार किया।

● इसी अवधि में ६,७५,३६६ टन माल विदेशों को भेजा गया। इससे ८४ करोड़ ६७ लाख रु० की विदेशी-मुद्रा प्राप्त की गयी। १९५८ की इसी अवधि में ६,१४३३७ टन माल के निर्यात से लगभग ८० करोड़ रु० की विदेशी-मुद्रा प्राप्त हुई थी।

● भारत, पटसन की फसल के जुलाई १९५८ से जून १९५९ के साल में पहली बार कच्चे पटसन की पैदावार में आत्मनिर्भर हुआ। इस अवधि में पैदावार ६७ लाख ५६ हजार गांठ हुई, जबकि पटसन उद्योग की जरूरत ६५ लाख गांठ की थी। जुलाई सन् १९५८-५९ में पाकिस्तान से केवल ३,३०,२०० गांठें कच्चा पाट मंगाया गया, जबकि १९५७-५८ की इसी अवधि में ६,७५,००० टन पाट का आयात हुआ था। इस समय पाकिस्तान से केवल पटसन की कतरनें, जिनसे अमेरिका में कपास बांधने के थैले बनते हैं और बहुत बढ़िया किस्म का पटसन ही मंगाया जाता है।

● १० साल बाद १९५९-६० में राज्य-व्यापार निगम के जरिये विदेशों को भी पटसन का कुछ निर्यात किया गया।

विश्व में मुद्रा प्रसार रुक रहा है

आजकल देश में बढ़ती हुई महंगाई के कारणों की चर्चा करते हुए प्रायः मुद्रा प्रसार पर चिन्ता प्रकट की जाती है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी है। इसके कारण महंगाई बढ़ती रही है। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री परजेकबसन ने हाल ही में राष्ट्रसंघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद के सामने भाषण देते हुए जो विचार प्रकट किए हैं, उनका आशय निम्नलिखित है—

यद्यपि कुछ वस्तुओं के मूल्य अब भी बढ़ रहे हैं, किन्तु बहुत-सी वस्तुओं के मूल्य संसार के भिन्न-भिन्न भागों में घट गए हैं। जहां मूल्य नहीं बढ़े हैं, वहां वस्तुओं की किस्म ऊंची हो गई हैं। बहुत से पदार्थों के दाम अब बढ़ने से रुक गए हैं। और बाजार में स्थिरता और विश्वास की भावना पैदा होने लगी है। इसलिए विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि विश्व में मुद्रा प्रसार की प्रगति अब निश्चित रूप से रुक गई है। खाद्य पदार्थों के मूल्य कुछ कम हुए हैं जब कि कच्चे माल के मूल्यों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है। कोयला और तेल अब अधिक मिलने लगा है। जहाजों के भाड़े अपेक्षाकृत कम हुए हैं और निर्यात व्यापार बढ़ाने की होड़ लग गई है। इसलिए मूल्य कुछ कम होने लगे हैं। विभिन्न देशों में बजट के घाटों को निरन्तर कम किया जा रहा है। अनेक देश तो बचत के बजट बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने अपने भाषण के अन्त में उन देशों को चेतावनी दी है, जो आज भी मुद्रा प्रसार की नीति पर चल रहे हैं। ऐसे देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने बढ़े लागत खर्च के कारण टिक नहीं सकेंगे।

चन्द्रमा द्वारा जलवायु परिवर्तन

विश्व के आर्थिक चक्र में शीतोष्ण ऋतु का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती ठण्डे प्रदेश व सागर अगर कुछ गर्म हो जाएं तो आर्थिक भूगोल ही बदल जाएगा। अब वैज्ञानिक कल्पना कर रहे हैं कि यह भी संभव है।

सोवियत इंजीनियर निकोलाई रोमानोव ने दूरपूर्व की जलवायु सुधारने के लिए प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वे चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्रज्वारों का उपयोग करने का प्रस्ताव करते हैं। ज्वार के समय जापान

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय कृषि-व्यवस्था की रीढ़

सर्वसेवा संघ का प्रस्ताव

जनसंख्या की वृद्धि एवं जमीन की कमी के कारण भारत के लोग स्वयं ही जब तकलीफ में हैं, उनकी ओर से गोसेवा की अपेक्षा करना मुश्किल माना जाता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जैसे बिना खेती भारत की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना गाय भारत की खेती नहीं हो सकती, न भारत का स्वास्थ्य सुधर सकता है। भारतीय भूमि को जोतने के लिए जिस शक्ति की जरूरत है वह बैल से ही प्राप्त हो सकती है। ट्रैक्टर का उपायों समिति मात्रा में हो सकता है।

भारत में जितनी जमीन है और जितना चारा पैदा किया जा सकता है, उसको देखते हुए यह वांछनीय नहीं है कि खेती के लिए बैल और दूध के लिए भैंस दो-दो पशु रहें। भले ही भैंस व्यक्तिगत दृष्टि से लाभदायक लगती हो, दो प्रकार के पशुओं का बोझ उठाना सम्भव नहीं होगा। पशुओं की संख्या कम रहे और अच्छे ही पशु पैदा हों इसके लिए रद्दी सांड़ों को बधिया किया जाए और 'कन्ट्रोल ब्रीडिंग' हो।

गायों को बढ़ावा देने में गाय की रक्षा तो होगी ही, हमारी भी रक्षा होगी। इसलिए जरूरी है कि गाय की उन्नति के लिए प्रयत्न हों। भारत में आज गायों की जो स्थिति है, उसके तीन भाग किये जा सकते हैं—(अ) जिन प्रदेशों में गाय आज भी आर्थिक ढाँचे में खड़ी है—वहां केवल गाय को ही बढ़ाया जाय, भैंस का विस्तार न हो। जैसे राजस्थान, गुजरात-सौराष्ट्र, मालवा, हरियाना आदि भागों में (अ) जिन प्रदेशों में गाय या भैंस दोनों ही अच्छी स्थिति में नहीं हैं, वहाँ गाय को आगे लाने का यत्न किया जाय—जैसे आसाम, उड़ीसा, बंगाल में। (इ) जहाँ गाय और भैंस में प्रतियोगिता चल रही है—वहाँ गाय को संरक्षण दिया जाय।

गाय और मनुष्य दोनों का निर्वाह तभी हो सकता है, जब हम कृषि आयोजन में अनाज (क्राप प्लानिंग) के साथ-साथ चारे (फीडर-प्लानिंग) का भी आयोजन करें।

खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए पशुओं के खाद का सम्पूर्ण उपयोग करना ही होगा। इसलिए ईंधन का प्रश्न हल करने के लिए गैस प्लांट की ओर भी ध्यान देना होगा। मृत पशु के चमड़े, हड्डी, सींग आदि का पूरा उपयोग करने के लिए चर्मालियों की आवश्यकता है।

जो पशुधन निरुपयोगी बन गये हैं, उनका भार कम करने के लिए गो-सदनों की योजना हो। गाय के दूध-घी के मार्केट को हानि पहुँचाने वाले जमाये तेल, विदेशी मिल्क-पाउडर जैसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए।

ग्राम-स्वराज्य के सन्दर्भ में आज आवश्यक है कि कृषि, गोपालन, खादी-ग्रामोद्योग और नयी तालीम इन पाँचों को समग्र दृष्टि से चलाया जाय। जहाँ एक प्रवृत्ति मुख्य हो, वहाँ अन्य प्रवृत्तियाँ भी चलनी चाहिएं, तभी हमारे हर काम को प्रतिष्ठा मिलेगी। हमारा काम समाज में परिवर्तन लाने का है, अतः कोई काम लोक-सम्मति के बिना आज के समय में नहीं होना चाहिए। व्यापक लोक-शिक्षण की योजना होनी चाहिए। हर रचनात्मक केन्द्र में कम-से-कम एक गाय तथा एक साँड रखकर इस काम का आरम्भ किया जा सकता है। कार्यकर्तागण घर तथा केन्द्र में गाय के ही घी-दूध के इस्तेमाल का आग्रह रखकर गोसेवा में सहायक हो सकते हैं। ● ●

सागर का गर्म जल संकरी नेवेल्स्की प्रणाली से ओखोत्स्क सागर में चला आता है लेकिन भाटे के समय पीछे हट जाता है।

निकोलाई रोमानोव ने यह सुझाव दिया है कि प्रणाली के आर-पार सात किलोमीटर की लम्बाई में एक ऐसा पुल बनाया जाए जिसके फाटक झूलेदार हों। फाटक इस तरह बनाये जाएंगे कि जल प्रवाह एक ही तरफ से अन्दर आ सकेगा। इस प्रकार जापान सागर का गर्म जल ठंडे ओखोत्स्क सागर में आ जाएगा। चन्द्रमा एक शक्तिशाली पम्प की तरह १,००० घन किलोमीटर से अधिक गर्म जल प्रतिवर्ष उत्तर की तरफ प्रवाहित कर देगा। इससे दूरपूर्व का जलवायु पर्याप्त गर्म हो जाएगा। ग्रीष्मकाल की अवधि लम्बी होने के फलस्वरूप आज के टुन्ड्रा में अनेक प्रकार की फसलें पैदा होंगी और फलोद्यान पुष्पित होंगे। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया निर्माण

बीहड़ जंगल में पक्की सड़क

किसी भी राष्ट्र की उन्नति में वहाँ के यातायात साधनों का प्रमुख योग होता है। अब तक भारत के अनेक क्षेत्रों के पिछड़े होने का एक कारण, यहाँ यातायात का अभाव भी रहा है। स्वतंत्र भारत में इस दिशा में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। अनेक दुर्गम स्थानों में मार्ग बना कर वैज्ञानिक युग की सभ्यता की रोशनी पहुँचाने के द्वार खोले गए हैं। बीहड़ जंगलों में भी पक्की सड़कें बनाई गई हैं। राजस्थान में बनी एक सड़क ऐसे निर्माण कार्यों का एक श्रेष्ठ उदाहरण है।

बांसवाड़ा में जहां हाल तक बैलगाड़ी भी नहीं जाती थी, अब ३०-४० मील की रफ्तार से जीप दौड़ने लगी है। बांसवाड़ा जिले में दानपुर व पीपल खूंट को तीस मील लम्बी सड़क से जोड़ा जा रहा है। यह काम राज्य के वन विभाग के हाथ में है।

विभाग पहाड़ी ढालों पर अनावश्यक जंगलों को साफ कर सड़क का निर्माण कर रहा है। यह सड़क बांसवाड़ा के इस भाग को एक ओर चित्तौड़गढ़ जिले से और दूसरी ओर मध्यप्रदेश से भी जोड़ देगी। यहां के जंगलों में वन श्रमिकों के बालकों के लिए दो स्कूल चल रहे हैं। पानी की भी इधर बहुत

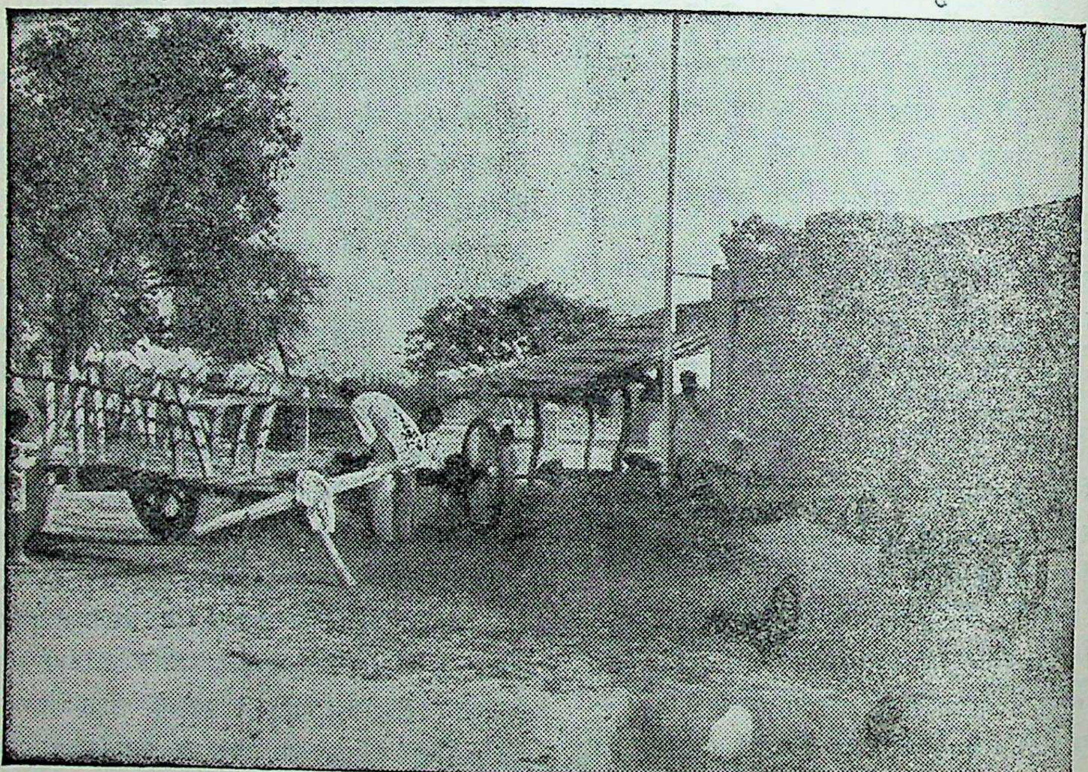

भारत के नये तीर्थ भाखड़ा नंगल का प्रसिद्ध ग्रामीण क्षेत्रों को भी विद्युत के रूप में मिलना आरंभ हो गया है। यह है गाँव का एक छोटा कारखाना जहाँ आटा पीसने, लकड़ी चीरने और कुट्टी काटने आदि के काम भाखड़ा की बिजली द्वारा होते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दिक्कत रही है। इस दिक्कत को हल करने के लिए अब कुछ कुएं खोदे जा रहे हैं।

दलदल को रोका जाएगा

निरंतर प्रयत्न करने के उपरांत भी अभी तक भारत खाद्य उत्पादन में आत्म निर्भर नहीं हो पाया है। यह खेतीहर कहे जाने वाले स्वतंत्र देश की आर्थिक दुर्दशा का एक श्रेष्ठ नमूना है। आवश्यकता इस बात की है कि हम हर संभव साधन से अपना खाद्य-उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करें। कृषि उत्पादन की अनेक बाधाओं में से एक बाधा यह भी है कि पानी जमा होने से दलदल हो जाने के कारण काफी जमीन खराब हो जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्यों की तीसरी योजना में नालियां तथा उथले नलकूप बनाने, वर्तमान नहरों की भीतरी दीवार को पक्का गरने तथा जमीन के नीचे नालियां बनाने का कार्यक्रम शामिल किया जायेगा। पंजाब, बम्बई, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली में ७२ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जहां पानी भरा हुआ है। इस भूमि में १० फुट तक गहरा पानी है।

पंजाब के लगभग ७० लाख एकड़ क्षेत्र में पानी भरा है। बम्बई में लगभग ८२ हजार एकड़ तथा जम्मू और कश्मीर में लगभग २९ हजार एकड़ भूमि में दलदल है।

पंजाब में दलदल को दूर करने के लिए कई उपाय किये गये हैं। प्रभावित क्षेत्रों में, नदियों, बड़े सोतों या झीलों के पानी को आने से रोकना, पानी की निकासी के लिए सिंचाई की नहरों के बराबर नालियां बनाना, नहरों आदि की भीतरी दीवार को पक्का करना, काफी संख्या में नलकूप खोदना, जमीन में नीचे के पानी की सतह ऊँची होने से रोकने के लिए कुएँ खोदना आदि प्रमुख आयोजन हैं।

आशा है कि इन उपायों से देश की बहुत सी बेकार पड़ी भूमि को कृषि के उपयोग की बना लिया जायगा, जिससे देश की समृद्धि बढ़ने के साथ-साथ खाद्य समस्या को हल करने में भी सहायता मिलेगी।

राजस्थान को भाखड़ा से बिजली

भाखड़ा बाँध भारत के नये तीर्थों में सर्वप्रमुख है। यह योजना पूर्ण हो जाएगी तो भारत की बिजली और सिंचाई की समस्या काफी अंशों तक हल हो जाएगी। इस योजना से राजस्थान को जो लाभ होगा, उससे इसका अन्य राज्यों के लिए भी महत्व भली भाँति प्रकट हो जाता है।

राजस्थान के रतनगढ़ और बीकानेर तथा रतनगढ़ और सीकर नगरों के बीच डाली गयी नई बिजली की लाइनें गत ११ अप्रैल को भाखड़ा बिजली व्यवस्था से सम्बद्ध कर दी गयीं। पिलानी कस्बे और गंगानगर जिले को बिजली पहले से ही दी जा चुकी थी। चुरू, बीकानेर, गंगानगर तथा सीकर जिलों में औद्योगिक एवं पारिवारिक उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध की जा चुकी है और नागौर एवं झुंझुनू जिलों को बिजली शीघ्र ही मुहय्या की जायेगी। राजगढ़ के ग्रिड सब स्टेशन तक राजस्थान को भाखरा की बिजली उपलब्ध होगी।

राजस्थान के इस ग्रिड सब स्टेशन को हिसार से बिजली प्राप्त हागी, जो रतनगढ़ तक इसके आगे बीदासर, नापासर तथा बीकानेर आदि स्थानों तक पहुँचायी जायेगी। भाखरा के बांये किनारे के पावर हाउस के निर्माण के पहले २,००० किलोवाट बिजली प्राप्त हो सकेगी। राजस्थान को इस योजना के प्रथम चरण में ४.५०० किलोवाट बिजली मिलने की संभावना है।

इस प्रकार भाखड़ा बिजली की उपलब्धि से इस क्षेत्र के उद्योगों एवं कृषि के विकास का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो गया है, जो अब तक बिजली के अभाव में सम्भव नहीं था। • •

—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कपड़े के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता की अवधि और बढ़ा दी है। यह सहायता १ अगस्त १९५९ से मिल रही है। इसके अनुसार प्रति पौंड के निर्यात पर ६ सेन्ट निर्यात व्यापारी को सरकार देगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएँ

तीन अर्थविदों के परामर्श

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री यूजिन ब्लैक के परामर्श से तीन अर्थ विशारदों का एक मण्डल भारत और पाकिस्तान आया। उसने भारत में घूम घूम कर सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन किया और हाल ही में उसने भारत की विकास योजनाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट दे दी है।

इस रिपोर्ट में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया गया है—

१—कृषि उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता।

२—निर्यात व्यापार की विविध क्षेत्रों में प्रगति।

३—योजना में लोच बनाए रखने की आवश्यकता।

४—कृषि उत्पादन के खाद के कारखाने को स्वावलम्बी बनाने, सरकार के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करने तथा कृषि यंत्रों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता।

देश की विकास योजनाओं को देखते हुए उक्त मण्डल ने कहा है कि यद्यपि भारत में कच्चा लोहा सबसे सस्ता है और अनेक कारखाने काम करने लगे हैं तथापि यह समझना भूल होगी कि अब हम आगामी १० या १५ वर्षों तक आयात कम कर सकेंगे। इसके विपरीत यह संभव है कि नई-नई आवश्यकताओं के साथ-साथ हमारे आयात भी बढ़ते जाएं। इसलिए भारत को निर्यात बढ़ाने पर विशेष बल देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो निर्यातित वस्तुओं की खपत पर देश में कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाएं तथा उन पर कर कुछ कम कर दिए जाएं।

उक्त मंडल ने योजना के आकार की चर्चा करते हुए सलाह दी है कि कुछ कम आवश्यक बड़ी योजनाओं को स्थगित भी किया जा सकता है। योजना में आवश्यकतानुसार कमीबेशी करने की सुविधा हमेशा रहनी चाहिए।

निजी उद्योगों का कठोर विरोध न करने की राय देने के बाद उक्त मंडल ने विदेशी पूंजीपतियों को राय दी है कि अपना रुपया भारत में लगाएं। विदेशों को मंडल ने यह सलाह भी दी है कि वे भारतीय माल के आयात पर अपने प्रतिबन्ध स्थित कर लें।

राज्य व्यापार निगम की प्रगति

राज्य व्यापार निगम की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उसने १९५८-५९ में सीमेंट के व्यापार में २ करोड़ २१ लाख रुपया उस पारिश्रमिक के अतिरिक्त कमाया है जो उसे ५ प्रतिशत के हिसाब से मिलता है। सीमेन्ट के व्यापार में निगम अधिकाधिक मुनाफा कमा रहा है। नीचे की तालिका से मालूम होगा कि सीमेन्ट के मूल्य का वितरण किस प्रकार हुआ है—

कारखाने पर	५८.१०
पैकिंग	१३.५०
औसत भाड़ा	१८.००
उत्पादन कर	२४.००
बिक्री कर	१.००
वितरण के खर्च	१.५०
रिबेट	००.५०
विविध	००.३०
निगम पारिश्रमिक	००.६०
कुल	१०७.५०

लेकिन वस्तुत: पहले तीन मदों में व्यय क्रमशः ५६.५०, ११.०० और १६.५० हुआ। इस तरह व्यापार निगम को २ करोड़ ३१ लाख का अतिरिक्त लाभ हुआ। अच्छा होता कि इस स्थिति में ग्राहकों को कुछ रियायत दी जाती।

अन्न के लिए अमेरिका से नया समझौता

भारत और अमरीका की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार अमरीका भारत को चार वर्ष की अवधि में ६० लाख टन गेहूँ और १० लाख टन चावल देगा। इस अन्न राशि के मूल्य और समुद्री यातायात के व्यय के रूप में भारत अमेरिका को ६०७ करोड़ रुपया देगा। पहले वर्ष में ४० लाख मीट्रीक टन गेहूँ और २॥

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लाख मीट्रिक टन चावल के लदान के लिए एक चौथाई दाम तत्काल उपलब्ध कर दिया जाएगा। इस समझौते के पश्चात् देश को अपना उत्पादन निश्चितता पूर्वक बढ़ाने की सुविधा सुलभ हो जायगी।

—रेल के इन्जन बनाने के चित्तरंजन कारखाने ने गत वर्षों में असाधारण प्रगति की है। इस वर्ष मार्च में १,००० वां इन्जन बनकर तैयार हो गया है। जिस दाम पर बाहर से इंजन मंगाये जाते थे उससे काफी कम कीमत पर इस कारखाने के इन्जन तैयार हो रहे हैं। भाप के इन्जन बनाने में सफलता प्राप्त करने के बाद यह कारखाना अब बिजली के इंजन बनाने की ओर भी प्रवृत्त हुआ है। पहले १० बिजली के इंजनों की किश्त आजकल निर्माणाधीन है।

—दुर्गापुर इस्पात कारखाने में अब इस्पात उत्पादन का प्रथम महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है। कारखाने की पहली खुली भट्टी से २०० टन पिघला हुआ इस्पात उत्पादन के पहले दिन प्राप्त हुआ। इस कारखाने में ऐसी ८ खुली भट्टियां लगाई जायेंगी।

—भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार ३४.८ करोड़ रुपये संयुक्त राज्य की सरकार भारत को चन्द्रपुरा विद्युत योजना के निमित्त देगी। यह योजना दामोदर घाटी योजना का ही एक अंग है।

—यूनियन कारपोरेशन के अनुसार १९५९ में कुल ३२४ लाख औंस सोना उत्पन्न हुआ है, जिसमें से ६२ प्रतिशत सोना केवल दक्षिण अमरीका में उत्पन्न हुआ।

—देश में १९५६ में ६ लाख ४० हजार बड़े टायर बने थे; १९५९ में इनकी संख्या बढ़कर ८ लाख १० हजार हो गयी। फिर भी यातायात बढ़ने के कारण अब भी देश में लगभग १,००,००० बड़े टायरों की और जरूरत पड़ती है।

वर्तमान कारखानों को टायर का निर्माण बढ़ाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और टायर बनाने की चार नयी योजनाएँ भी स्वीकार की गयी हैं। इससे देश में दो-तीन साल बाद हर साल २१ लाख टायर बनने लगेंगे। तब देश की मांग पूरी करने के अलावा टायर निर्यात भी किए जा सकेंगे।

● ●

भारत व्यापार पत्रिका

★ जनवरी '६० अंक के साथ काशी परिशिष्ट है जिसमें वाराणसी की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, दार्शनिक स्थानों के चित्र, कार्टून औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के परिचय तथा पूरे पते हैं।

★ फरवरी '६० अंक जिसमें उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी उपयोगी लेख, कम्पनियों के परिचय, आयात-निर्यात समाचार, चित्र एवं कार्टून हैं।

★ मार्च '६० के अंक के साथ बजट परिशिष्ट है, जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बजट सम्बन्धी पूर्ण जानकारी, बजट पर समीक्षा एवं कार्टून हैं।

अप्रैल '७० अंक से हर अंक के साथ एक एक उद्योग-परिशिष्ट दिया जा रहा है।

आज ही आठ रुपए भेजकर वार्षिक ग्राहक बनें।

विज्ञापक सम्बन्धी पूर्ण जानकारी के लिए लिखें :

व्यवस्थापक, भारत व्यापार पत्रिका

पताः—

राष्ट्रभारती

सम्पादक

मोहनलाल भट्ट : हृषिकेश शर्मा

वार्षिक चन्दा मनीआर्डर से ६ रुपये

नमूने की प्रति ६२ नए पैसे

इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् साहित्यकारों के ज्ञानपोषक और मनोरंजन अच्छे-अच्छे लेख, कविताएँ, कहानियाँ, एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र, आदि रचनाएँ पढ़ने को मिलेंगी।

इसमें संस्कृत, बँगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि विभिन्न भारतीय भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रूसी आदि विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के सुन्दर हिन्दी अनुवाद भी रहते हैं।

आज ही ६) भेजकर वार्षिक ग्राहक बन जाइये !

रियायत—स्कूल-कालेजों, पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को केवल ५) वार्षिक चन्दे में मिलेगी।

—व्यवस्थापक : राष्ट्रभारती

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिन्दीनगर, वर्धा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक्सल की कहानी

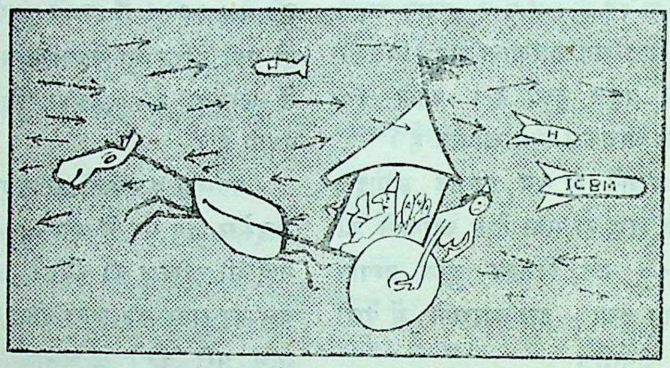

सारे रामायण महाकाव्य का उद्‌भव वास्तव में एक पुर्जे के टूटने से हुआ था. घमासान युद्ध के बीच शाही रथ का एक्सल टूट गया, परन्तु रानी कैकेयी ने अपनी उंगली डाल कर पहिए को यथास्थान रखा. राजा दशरथ ने उस से कोई वर मांगने को कहा जिस का फायदा कुटिल रानी ने श्री राम को बनवास भेजने में उठाया.

इसलिए आप मानेंगे कि हमें अपने एक्सल मजबूत रखने होंगे. वियरवेल साइकिलें हर प्रकार के काम के लिए बनाई गई हैं. उन का हर पुर्जा मजबूत होता है.

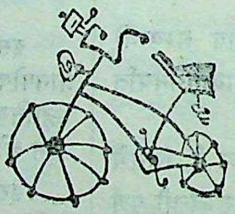

वियरवेल साइकिल्स

विमपैक्स (एजेंट्स) नई दिल्ली • बम्बई • कलकत्ता • मद्रास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ग्राम निर्माण की दिशा में

आज चारों ओर निर्माण और विकास के नारों की गूंज सुनाई देती है। सरकार अपनी अनेक कमजोरियों—टैक्स आदि की वृद्धियों को भी निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय की आड़ में छुपाने की कोशिश करती रहती है; किन्तु निर्माण कार्य—जिसे सही अर्थों में निर्माण कार्य कहा जा सके, कितना हो पाता है? भौतिक निर्माण से अधिक महत्व नैतिक निर्माण का है। इसे महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसकी ओर रंचमात्र भी सचेष्ट नहीं है।

सर्व सेवा संघ ने ग्राम निर्माण का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इस कार्यक्रम में गांव की आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ आन्तरिक समृद्धि के नियोजन का नक्शा भी है—

१. हमारे काम में और सरकारी विकास के काम में फरक यह है कि हमारे काम में खर्च कम, काम ज्यादा, गाँव का अभिक्रम और एक कुटुम्ब की भावना, ये चार बातें होंगी।

२. हमारी क्रान्ति की भावना कायम रहेगी, यदि कार्यकर्ताओं में आन्दोलन की भावना कायम रहे और वे खुद पदयात्रा पर निकलें, गाँव-गाँव जमीन माँगें। हमारा काम गाँव के नेतृत्व की मार्फत हो। कार्यकर्ताओं की मार्फत न हो।

३. गाँव के बाहर से कर्ज और मदद दोनों गाँवों को दी जाय। मदद उत्पादन के साधनों के रूप में हो। मदद का स्वरूप ऐसा रहे कि गाँव के लोगों का अभिक्रम उससे जागृत हो सके, जो काम श्रमशक्ति के बल पर हो सकते हैं, वे मदद मिलने में देरी लगने के कारण रुके न रहें।

४. पैसों के बिना हो सकने वाले श्रम के और नैतिक काम अवश्य हाथ में लिये जायँ, ऐसे कामों में मद्यनिषेध का काम एक है।

५. ग्रामदानी गाँवों में अन्नोत्पादन में एवं वस्त्रोत्पादन में वृद्धि हो। अगले पाँच वर्षों में ग्रामदानी गाँवों में अन्नोत्पादन छःगुना हो, अन्त्योदय की दृष्टि से नया ग्राम एक कुटुम्ब ही है।

६. अन्त्योदय की दृष्टि से जिन कुटुम्बों की आमदनी प्रतिवर्ष ३०० रुपये से कम हो, उनकी आमदनी ६०० रुपये की जाय।

७. सब गाँवों में नैतिक वातावरण कायम रहे और बाँट-बाँट कर खाने की इच्छा कायम रहे। जमीन की तरक्की होने के कारण व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना न बढ़े, बल्कि सामुदायिकता बढ़े।

८. ग्रामदानी गाँवों को राजनैतिक पक्षबाजी से बचाया जाय।

९. ग्रामदान कानून छोटा और सरल हो और वह जल्द पास कराया जाय।

१०. ग्रामदानी गाँवों को एक विशेष निधि से कर्ज दिया जाय। वैसे ही पुराने कर्ज को ३ साल तक मोराटोरियम किया जाय।

११. रोजगार का काम ग्रामदानी गाँवों में किया जाय।

१२. निर्माण समिति को अनुसंधान का काम करना चाहिए।

आशा है सरकार और जन नेता इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेंगे।

उद्योग-व्यापार पत्रिका

देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण में कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई कर सकते हैं? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या दशा है? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही है? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य जानने चाहिएं, और इन सबकी जानकारी पाने का श्रेष्ठ साधन है—उद्योग व्यापार पत्रिका इसलिये आप ६ रु० भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक बन जाइये। नमूना पत्र लिखकर मंगाइये।

एजेन्टों को भरपूर कमीशन।

पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी अर्थ-चर्चा

चेकोस्लोवाकिया का आर्थिक सहयोग

चेकोस्लोवाकिया इस सदी के प्रथम चरण में ही यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। भारत से उसके व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे, दूसरे विश्व युद्ध के काल में यह सम्बन्ध छिन्न-भिन्न हो गया, किन्तु उसने युद्ध समाप्त होने के कुछ ही वर्षों बाद ही फिर से—ध्वस्त औद्योगिक भवन को ठीक कर लिया और आज भारत की विकास योजनाओं में जो देश उसे उदार सहयोग दे रहे हैं, उनमें से चेकोस्लोवाकिया भी एक है।

पिछले वर्षों में भारत और चेकोस्लोवाकिया में व्यापारिक सम्बन्ध बहुत बढ़ गये हैं। दोनों देशों में परस्पर आयात-निर्यात बढ़ते जा रहे हैं, भारत से कच्चा लोहा मंगाने वाले देशों में चेकोस्लोवाकिया का भी स्थान है, इस वर्ष संभवतः १० लाख टन कच्चा लोहा मंगा रहा है। मैंगनीज, जूट और जूट का सामान, अभरक, खालें, तेल, चाय, काफी, काली मिर्च आदि का निर्यात भी चेकोस्लोवाकिया को किया जाता है। गत वर्षों में चेकोस्लोवाकिया ने जो माल भारत को दिया है, उसमें ८०% मशीनरी और इंजीनियरिंग का सामान है। उस देश के विदेशी व्यापार निगमों ने अब तक भारत को तीन चीनी मिलें, दो सीमेंट फैक्ट्रियां, दो बिजलीघर और साइकल की जंजीरें बनाने वाला एक संयत्र दिया है। आगामी वर्ष से वह और भी महत्वपूर्ण सामग्री भेजने वाला है।

रांची में फाउंड्री फोर्ज बनाने का विशाल कारखाना उसी के सहयोग से बनेगा। कलकत्ता में रबर टायर बनाने का प्लाण्ट, आसाम में एक सीमेंट फैक्ट्री तथा अन्य अनेक संयत्र चेकोस्लोवाकिया ने देने का समझौता भारत से कर लिया है।

चेकोस्लोवाकिया ने यह सब सामग्री देते समय भारत की विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों का ध्यान रखा है। एक समझौते के अनुसार वह भारत को २३.१ करोड़ रुपये की सामग्री उधार दे रहा है। इस राशि से फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट का तीसरा चरण—भारी मशीनरी और बिजली की मशीनरी के संयत्र भारत को उपलब्ध होंगे।

ये संयत्र १९६५ तक भारत को मिल जायेंगे। चेकोस्लोवेकिया ने इस विशाल ऋण का ब्याज केवल २.५ प्रतिशत लेना स्वीकार किया है।

उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त चेकोस्लोवाकिया भारत को प्राशिल्पक प्रशिक्षण में भी सहयोग दे रहा है। भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर बालचन्द नगर में स्कोडा के सहयोग से चीनी मिलों की मशीनरी बनाने का कारखाना शीघ्र खुलने जा रहा है। हमें आशा करनी चाहिए कि दोनों देशों का परस्पर सहयोग एक दूसरे के लिए और भी लाभकारी सिद्ध होगा।

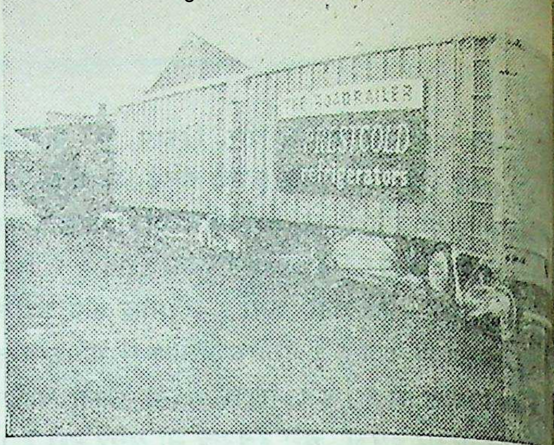

ब्रिटेन की नई कार, जो सड़क पर चलती है और रेल की पटरियों पर भी।

आकाश में मोटर गाड़ियां

पश्चिमी जर्मनी में मोटरगाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। १९५५ में इनकी संख्या १५ लाख थी, तो अब ४० लाख हो गई है। इनमें माल ढोने वाली व्यापारिक गाड़ियों की संख्या शामिल नहीं है। मोटरगाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ने से जर्मनी में और विशेषकर बर्लिन में यातायात की समस्या कठिनतम हो गई है। इसके लिए जर्मनी के इंजिनियरों ने आकाश में सड़कें बनाने का निश्चय किया है। ये सड़कें लोहे के बड़े-बड़े शहतीरों पर आधारित होंगी और इसके कारण सड़कों के लिए स्थान की समस्या हल हो जाएगी। भारी गाड़ियां नीचे की सड़क पर चलेंगी। और अधिकांश मोटर गाड़ियां ऊपर की सड़क पर। पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक और आर्थिक उन्नति का यह एक अच्छा उदाहरण है। • •

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

INDIA & U. S. AID

by

Danial Latifi

Published by:

The Public Affairs Forum, 5th Fl.

Bombay Mutual Chambers,
19-21, Hamam Street
Fort, Bombay-1.

A REPORT SOBERLY ALARMING THAT EVERY WELL WISHER OF INDO-U.S. FRIENDSHIP SHOULD READ

Sole selling Agents:

T. N. Varma,

5th floor, Bombay Mutual Chambers,
19-21, Hamam Street, Bombay-1.

Price: Rs. 5/- (rupees five) Standard Edition.

Rs. 3/- (rupees three) Cheap Edition.

Postage & Packing etc.

Attractive commission to book - sellers.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रम समस्या

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन क्या चाहता है

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन (आई० एल० ओ०) की ४०वीं वर्षगांठ के अवसर पर डायरैक्टर-जनरल डेविड ए० मौर्स के भाषण का सारांश प्रस्तुत है!

आशा की जाती है कि जून, १९६० में आई० एल० ओ०' अणुविकिरण के दुष्प्रभावों से श्रमिकों की रक्षा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय विधान बनाएगा।

आज हमको सिर्फ औद्योगिक कर्मचारियों से ही वास्ता नहीं है, हमें विश्व में उदीयमान सफेदपोश कर्मचारियों की विशाल शक्ति से भी वास्ता पड़ता है, जो कि श्रमिक शक्ति का परिवर्तित स्वरूप है। नये अणु-शक्ति संस्थानों के कर्मचारियों की समस्याओं की देख-भाल भी करनी है। इन सबसे भी बड़ी एक श्रमिक शक्ति है कृषि-श्रमिकों की शक्ति, जिनकी संख्या संसार में श्रमजीवी लोगों में सर्वाधिक है और जिनकी समस्याओं पर अब हमें प्राथमिकता के आधार पर विचार करना है।

संसार में ट्रेड यूनियन आन्दोलन तथा मालिकों के संगठन सरकारी नियन्त्रण और निर्देशन से कहां तक मुक्त हैं? स्वाधीनता केवल इतने थोड़े देशों में है कि आप उन्हें अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं।

जनसंख्या की समस्या भी हमारे सामने है। विश्व में हर सप्ताह वाशिंगटन जितने बड़े नगर की सृष्टि हो रही है, जिसका मतलब हुआ कि आबादी ४० लाख प्रति महीने या ४८० लाख प्रति वर्ष की गति से बढ़ रही है।

यही हाल उस फर्क के बारे में है जो आर्थिक दृष्टि से विश्व के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद है। अमरीका और यूरोप में जीवन-स्तर तेजी से उन्नत हो रहा है जिससे अल्प-विकसित क्षेत्रों में जीवन-स्तरों की निरन्तर प्रगति के बावजूद औद्योगिक देशों तथा अल्प-विकसित क्षेत्रों के बीच विषमता की खाई बढ़ती जा रही है।

हम अब भी ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसमें अधिकांश लोग या तो बीमारी से ग्रस्त हैं या अशिक्षित हैं।

अमरीका के श्रमिकों और मालिकों को 'आई० एल० ओ० में विश्व श्रम-नीति निर्धारित करने के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं और सिफारिशों की प्रक्रिया को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए।

हमारा ही एकमात्र ऐसा संगठन है, जिसने मानव-अधिकार सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में सक्रिय कदम उठाए हैं, और एक ऐसे विधान को कार्यान्वित करने का साहस किया है जिसमें बलात् श्रम के उन्मूलन, रोजगार में भेद-भाव के निवारण, समान कार्य के लिए समान वेतन और संगठन बनाने की स्वतन्त्रता की व्यवस्था है।

सर्वत्र संगठन बनाने की स्वतंत्रता के विधान पर अमल किए बिना स्वतंत्रता नहीं रह सकती। संसार में स्वतंत्रता का निश्चित मापदण्ड यही है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता के सिद्धान्तों को किस हद तक स्वीकार किया गया है।

जिन समस्याओं का मैंने उल्लेख किया है उन्हें प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के जरिए हल करने में हम महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं।

'आई० एल० ओ०' के शिक्षा सम्बन्धी अनेक कार्यक्रम हैं और उन पर जितना भी बल दिया जाए, थोड़ा है। हमारे पास श्रमिकों की शिक्षा का तथा श्रमिक-प्रबन्धक सम्बन्धों की अभिवृद्धि का एक सुन्दर कार्यक्रम है और प्रबन्ध-विकास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम तैयार करने वाले हैं। लेकिन हम जेनेवा में श्रम-सम्बन्धी विषयों के अध्ययन के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी कायम करना चाहते हैं जिसकी हमारे शिक्षा-सम्बन्धी सब कार्यों पर छत्र-छाया रहेगी। ●

नदियों एवं झरनों पर पुलों का निर्माण तो महत्वपूर्ण है ही परन्तु इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उस पुल का निर्माण है जिससे ४० करोड़ भारतीय निर्धनता से समृद्धि की ओर जा सकते हैं। आपने कहा कि यह पुल स्वयं जनता द्वारा सहकारिता तथा कठिन श्रम से बनाया जा सकता है। —जवाहरलाल नेहरू

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे उद्योग

नए उद्योगों का विस्तार

भारत में निजी क्षेत्र के उद्योगों का क्षेत्र उत्तरोतर बढ़ रहा है। पहली और दूसरी योजना के काल में मौजूदा उद्योगों का विस्तार हुआ—इण्डियन आयरन और टाटा-स्टील में कई गुनी अधिक पूंजी लगी, नई मशीनें लगी और उनका उत्पादन बढ़ा, वहां दूसरे उद्योगों का नवीनीकरण हुआ। इस प्रकार निजी क्षेत्र के उद्योग नए रूप में परिणत हुए।

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों में कुल विनियोजन ८२२ करोड़ रुपए और २,७५५ करोड़ रुपए का था, इसमें निजी क्षेत्र में ४० प्रतिशत से अधिक पूंजी लगी। निजी क्षेत्र में विदेशी प्रतिष्ठानों के हिस्सेदार आदि बनने पर भी अतिरिक्त विनियोजन बढ़ा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी और निजी क्षेत्रों के उद्योगों में ४,४०० करोड़ रुपए की पूंजी लगेगी। इसमें भी निजी क्षेत्र में ४० प्रतिशत पूंजी लगेगी। पहले की अपेक्षा निजी क्षेत्र अधिक बलशाली बना है।

सूती मिलों का झुकाव की दिशा

एक उद्योग गणना से मालूम होता है कि २९ परिगणित उद्योगों की कुल आय १६२१ करोड़ रुपया थी, जिसमें से ४८८ करोड़ रुपया अर्थात ३०% केवल वस्तु उद्योग की थी, इन २९ उद्योगों में लगी हुई उत्पादक पूंजी १००४ करोड़ हुई और इसमें से २८५ करोड़ रुपया अर्थात २८% केवल वस्त्र उद्योग में लगी हुई थी।

पिछले कुछ वर्षों से अनेक प्रमुख सूती मिलें वस्त्र उत्पादन के साथ-साथ कुछ नया कार्य भी प्रारम्भ करने लगी हैं। ये कार्य अलग-अलग किस्म के हैं, सेंचुरी मिल रेयन, बम्बई डाइनिंग मिल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मदुरा मिल टायर के कपड़े (फ्रेब्रिक फार टायर्स), कलिको मिल आलकली और कास्टिक सोडा तथा क्लोराइड, स्टैंडर्ड मिल सीमेण्ट या रंग, श्री अम्बिका मिल ट्यूब और पाइप आदि तैयार कर रही हैं या करने का विचार कर रही हैं। इसी तरह अन्य भी अनेक बड़ी सूती मिलें कपड़े के साथ-साथ कोई और उद्योग प्रारंभ करने में एक दूसरे से आगे बढ़ रही हैं। इस नई प्रवृत्ति का संभवतः एक कारण यह भी है कि ये मिलें वस्त्र उद्योग में अब कम लाभ की संभावना अनुभव कर रही हैं।

गन्ने का उपयोग

सरकारी समिति के एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल गन्ने का प्रयोग विभिन्न कार्यों में इस तरह होता है।

मौसम	कुल पैदावार हजार टन में	गन्ने का औसत उपयोग चीनी	गुड़	खांडसारी	चूसने
१९५२-५३	४९.७८९	२५.३६	५३.५२	३.३९	१७.७३
१९५३-५४	४३.८७३	२२.१९	५५.८८	३.२४	१८.७५
१९५४-५५	५६.९२३	२८.००	८०.६३	३.००	१८.३७
१९५५-५६	५९.३१७	३१.९३	४७.६२	२.८५	१७.६०
१९५६-५७	६६.९९८	३१.१९	४७.७७	२.५४	१८.५०
१९५७-५८	६३.९५४	३०.८०	४५.५५	५.३०	१८.३५

इससे यह स्पष्ट है कुल गन्ने की लगभग ३५% पैदावार चीनी बनाने के काम आती है और ५०% गन्ना गुड़ बनाने के काम आता है। ३% गन्ना खांडसारी और १६% चूसने के काम आता है, जब गुड़ की कीमत १४ रु० प्रतिमन से अधिक हो जाती है तब गन्ने का झुकाव गुड़ बनाने की ओर जाता है। इसी तरह खांडसारी उद्योग भी बढ़ने लगता है। यही सब देखकर टैरिफ कमीशन ने खांडसारी पर भी उत्पादन कर लगाने की सलाह दी है।

चीनी उद्योग की मशीनरी बनेगी

भारतीय उद्योग में वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग का स्थान है। इस उद्योग के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि चीनी मिलों की मशीनरी भारत में ही तैयार हो। भारत के प्रमुख उद्योग संस्थान बालचन्द्र नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चीनी मिलों के लिए संयंत्रों को स्वयं तैयार करके एक बड़ा भारी कदम उठाया है। कम्पनी ने बहुत भारी मशीनरी पंजाब आसाम और मद्रास के तीन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कारखानों के लिए बना कर दी है। पानीपत में तो यह कारखाना काम भी कर रहा है। कम्पनी की योजना यह है कि चीनी मिलों की तमाम मशीनरी वह तैयार करे। उन्होंने इसके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को पार कर लिया है। इसके लिए उन्होंने चेकोस्लोवाकिया की स्कोडा कम्पनी से भी सहयोग प्राप्त कर लिया है। वस्तुतः इस दिशा में देश में जो प्रगति हो रही है उसकी चर्चा करते हुए भारत के उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह ने कहा था कि देश इस दिशा में शीघ्र ही स्वावलम्बी हो जाएगा। और १९६० में चार, १९६१ में आठ, १९६२ में २१ और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १०५ संयत्र बनाने लगेगा और तब भारत चीनी उद्योग की दृष्टि से पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाएगा।

औद्योगिक बस्तियां

इस साल पहली जनवरी को देश में कुल ३४ औद्योगिक बस्तियां थीं, जिनमें कुल ४३२ कारखाने चालू थे। बस्तियों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है: मद्रास में ६, केरल और बम्बई में ५-५, बिहार में ४; पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश में २-२; आसाम, ैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब औरदिल्ली में १-१। दो बस्तियां सामुदायिक विकास खण्ड के क्षेत्रों में और ५ प्रारम्भिक योजना क्षेत्र में हैं।

टाइप राइटरों का निर्माण

उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह के कथनानुसार टाइपराइटरों का निर्माण १९५६ में १३,४२० से बढ़कर पिछले साल २१,४३७ हो गया। टाइपराइटरों के तीन कारखानों को स्टैण्डर्ड टाइपराइटर बनाने का लाइसेंस दिया गया है और इनमें काम हो रहा है। छोटे टाइपराइटरों (पोर्टेबल) के लिए एक कारखाने को लाइसेंस दिया गया है। अनुमान है कि यह जल्दी ही चालू हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइपराइटर कारखानों की उत्पादन क्षमता ३३,००० टाइपराइटर की है, जबकि छोटे टाइपराइटर के कारखानों की क्षमता १२ हजार है।

सबसे सस्ता और सुन्दर सचित्र मासिक

जागृति

संस्थापित १९४८

जिसे राष्ट्र भाषा के प्रायः सभी प्रमुख लेखकों, कवियों और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है। चार कहानियां, एक एकांकी, ६ लेख

तिरंगा आवरण अनेकों इक रंगे चित्र

५२ से ६४ पृष्ठ की सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर

इस पर भी मूल्य केवल २५ नए पैसे

एजेन्टों को ५ से १०० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें:

व्यवस्थापक, 'जागृति' कार्यालय, लोक सम्पर्क विभाग, पंजाब, चंडीगढ़

जहाजी उद्योग की कम्पनी ● पृष्ठ २७० का शेष

था। इन 'डेकों' के नीचे छोटे-छोटे 'केबिन' होते थे जिनकी संख्या जहाजों के आकार के अनुसार कम या ज्यादा होती थी। उनके परिचालक यंत्र (हेम्स) अच्छे होते थे; उनके चार मस्तूल और उतने ही पाल होते थे। कुछ बड़े जहाजों में, 'केबिनों' के अतिरिक्त, १३ तक 'बल्कहेड' अर्थात् माल भरने की जगह में मोटे तख्ते लगाकर बनाये गये भाग, होते थे ताकि जहाज में छेद हो जाने की स्थिति में माल को पानी से सुरक्षित रखा जा सके।

पन्द्रहवीं शताब्दी में निकोलो कॉन्टी नामक इतालियन यात्री भारत में आया था। उसने कहा है कि भारतीय यूरोप में बनने वाले तत्कालीन जहाजों से बड़े जहाज बनाते थे। मुगलों के काल में भी, देश के विभिन्न भागों में, जहाज-उद्योग ने बहुत उन्नति की। तत्कालीन साहित्य में उस काल में बंगाल में बनाये गये जहाजों का अत्यन्त मनोरंजक वर्णन है। सागौन, गम्भारी, पियाल, काथल आदि की लकड़ियों के मजबूत तख्तों को लोहे की मेखों से जोड़कर जहाज में माल रखने की जगह बनायी जाती थी। इसके बाद धातु की चादरें तथा चटाई की किवाड़ें लगायी जाती थीं। इसके बाद लकड़ी के तख्तों का 'डेक' बनाया जाता था और फिर मुख्य 'केबिन' एक अलंकृत प्रकोष्ठ होता था जिसमें कौड़ियों की मालाओं तथा बन्दनवार की सजावट होती थी। मुग़ल चित्र कला में भी कई प्रकार के जहाजों के अनेक उदाहरण चित्रित हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंक और बीमा

पंजाब नेशनल बैंक की प्रगति

पंजाब नेशनल बैंक की गत वर्ष की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि बैंक ने ३१ दिसम्बर १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में संतोषजनक कार्य किया है। वर्ष के अन्त में बैंक के पास १४१ करोड़ रुपये के डिपाजिट थे, जबकि गत वर्ष डिपाजिट केवल १२६ करोड़ रुपए थे। इसी तरह बैंक की क्रियाशील पूंजी १७६ करोड़ रुपये रही जबकि गत वर्ष इससे १९ करोड़ रुपए कम थी। इसी तरह सुरक्षित कोष भी गत वर्ष से २०.५ लाख बढ़ गया। ग्रेच्युटी फण्ड और डवलपमेंट रिबेट रिजर्व करीब १२॥ लाख रुपया निकालने के बाद ८८.६८ लाख रुपए का लाभ हुआ है। शेयर होल्डरों को २० प्रतिशत डिविडेन्ड दिया गया है। इस समय भारत, बरमा और पाकिस्तान में बैंक के ३८३ कार्यालय काम कर रहे हैं, जो कि गत वर्ष से २० अधिक हैं।

बैंकों की दर में वृद्धि ?

कुछ समय से बैंक की ब्याज दर बढ़ाने का सुझाव अनेक क्षेत्रों में दिया जा रहा है, इसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि मंहगाई और मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिये यह आवश्यक है, लेकिन निजी बैंकों ने इसका विरोध किया है, और आधार-भूत युक्तियां दी हैं एक ओर बैंकों को अपने विनियोजन मूल्य में ह्रास के कारण काफी घाटा हुआ, दूसरी ओर केन्द्र व राज्य सरकारों को ऋण लेने में भारी असुविधा होगी और उन्हें भी अपने भारी ऋणों पर अधिक ब्याज देना पड़ेगा।

रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री रामाराव ने भी ब्याज दर बढ़ाने का विरोध किया है। उनकी सम्मति में आगामी पांच छ वर्ष बड़े आर्थिक संकट के हैं, इनमें करोड़ों अरबों रुपया, बांध-योजनाओं; लोहे के कारखानों तथा दूसरी योजनाओं में लगेगा। निकट भविष्य में इनसे उत्पादन तो होगा नहीं और व्यय लगातार होता रहेगा। एक ओर सहकारी ऋणों पर ब्याज अधिक देना पड़ेगा दूसरी तरफ मुद्रा-प्रसार बढ़ेगा। बैंक की दर बढ़ाने से उद्योगों पर भी नया बोझ पड़ जायेगा। लोगों में रुपया उद्योगों में लगाने की प्रवृत्ति कम हो गई है।

बैंकों के एडवासों पर रोक

रिजर्व बैंक के ११ मार्च १९६० के आदेश ने शेयरों एडवांसों पर रोक लगायी है, यह कहा गया है कि ५० प्रतिशत मार्जिन होने पर बैंक एडवांस करें और बदले के सौदों पर कोई रकम न दें, इसके सिवा अन्य रुकावटें भी लगाई हैं, जिससे बैंकों का रुपया शेयरों के कारबार में न लगने पाए। रिजर्व बैंक का यह प्रतिबंध नया नहीं है। मई १९२६ में चावल पर प्रतिबंध लगा था और उसी वर्ष सितम्बर मास में गेहूँ पर भी लग गया था। जून १९५७ में चीनी पर तथा फरवरी १९५८ में मूंगफली पर और दिसम्बर १९५८ में अन्य तेलहनों पर लगा था। बैंकों पर भी जुलाई १९५८ में उनके एडवांसों पर एक बार रोक लग चुकी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-बीमा

भारत के मुख्यतया देहाती समझे जाने वाले प्रदेशों में से प्राप्त व्यवसाय में इस साल ६० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १९५९ में कारपोरेशन ने भारत में ४१७ करोड़ का नया व्यवसाय किया है। यह व्यवसाय १९५७ के व्यवसाय की तुलना में ५१ प्रतिशत से अधिक है। १९५७ का साल ही कारपोरेशन के व्यवसाय का प्रथम संपूर्ण वर्ष था। इस वर्ष में २७७ करोड़ रुपयों का व्यवसाय करके जीवन-बीमे के क्षेत्र में कारपोरेशन ने उच्चांक प्रस्थापित किया था। १९५८ में ३३६ करोड़ रुपयों और १९५९ में ४१७ करोड़ रुपयों का व्यवसाय करके नया रिकार्ड स्थापित किया।

शहरों में कारपोरेशन के व्यवसाय करने वाले १७ केन्द्र हैं, जो केवल शहरों में से ही व्यवसाय प्राप्त करते हैं। १ लाख की आबादी वाले शहरों तथा उसके अड़ोस-पड़ौस के देहाती विभागों में व्यवसाय करने वाले ५६ केन्द्र हैं। अन्य केन्द्र विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों तथा १ लाख से कम आबादी वाले शहरों में ही कार्य करते हैं। इन केन्द्रों की संख्या १६८ है। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया साहित्य

भारत आज और कल—जवाहरलाल नेहरू, प्रकाशक-प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, दिल्ली-८, पृष्ठ ४४ डिमाई आकार—मूल्य—७५ नये पैसे।

गत वर्ष श्री जवाहरलाल नेहरू ने 'आजाद स्मारक भाषण माला' के अन्तर्गत 'भारत आज और कल' शीर्षक से कई महत्वपूर्ण भाषण दिए थे। उस समय बौद्धिक वर्ग में इन भाषणों की चर्चा भी खूब हुई थी। इन भाषणों की प्रारम्भिक किश्तों में देश के क्रमिक विकास की कहानी कही गई है और उत्तरांशों में वर्तमान समस्याओं और भावी प्रगति की संभावनाओं का दिग्दर्शन कराया गया है। प्रकाशन विभाग ने इन भाषणों को पुस्तकाकार प्रकाशित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। छपाई सफाई सामान्य है।

हमारी बिजली—रामचन्द्र तिवारी, प्रकाशन—डपरोक्त, पृष्ठ ६६, आकार डिमाई, मूल्य ७५ नए पैसे।

प्रस्तुत पुस्तक में बिजली क्या है? कैसे बनती है? बिजली के तरह तरह के उपयोग और भारत में विशेष कर पंचवर्षीय योजनाओं में बिजली के उत्पादन में विकास किस तीव्र गति से हो रहा है—यह सब रोचक शैली में बतलाया गया है। पुस्तक विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों विषयों के अध्योताओं के लिए संग्रहणीय है।

इण्डिया एण्ड यू० एस० ऐड (अँग्रेजी) लेखक—दनियाल लतीफी, प्रकाशक—पब्लिक अफेयर्स फारम, बाम्बे म्युचुअल चेम्बर्स, १६-२१ हमाम स्ट्रीट, बम्बई, आकार डिमाई, पृष्ठ संख्या १३६, मूल्य—५.००, साधारण संस्करण—३.००।

प्रस्तुत पुस्तक के नाम से ऐसा संदेह होता है कि इसमें भारत को दी गई अमेरिकन सहायता का विस्तृत विवरण होगा; किन्तु परिशिष्ट संख्या—४ में एक गणना के सिवाय उक्त विषय की विशेष चर्चा नहीं है। लेखक वस्तुतः भारत में फैली हुई कुछ धारणाओं का, जिन्हें वह भ्रान्त मानता है, निराकरण करना चाहता है। लेखक की राय है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश वस्तुतः भारत की आर्थिक उन्नति नहीं चाहते। वे समय-समय पर उसमें बाधा डालने का प्रयत्न करते हैं, और वे जो सहायता देना चाहते हैं, उसमें स्वार्थ की भावना रहती है। पुस्तक में यह रहस्योद्घाटन करने का दावा किया गया है कि मिश्र को अास्वान बांध के लिए सहायता न देने की प्रेरणा अमेरिकन कृषि व्यापारियों ने की थी। इसी तरह रूस के साथ औषधि निर्माण सम्बन्धी भारत का समझौता भी कुछ स्वार्थ के कारण ही अमल में नहीं आ सका। यदि रूस भिलाई कारखाने में पहल न करता तो रूरकेला और दुर्गापुर के कारखाने भी न बन पाते।

अमेरिकन नीति की आलोचना के साथ-साथ लेखक भारत के निजी उद्योग पर भी बरस पड़ा है। इसकी अनेक चालों की चर्चा पुस्तक में अनेक स्थलों पर की गई है और सरकारी मशीनरी की अकर्मण्यता सुस्ती तथा अदूरदर्शिता आदि की भी खबर ली गई है।

लेकिन शैली की विशेषता यह है कि अपनी प्रत्येक बात की पुष्टि के लिए विभिन्न देशों के अर्थशास्त्रियों, अधिकारियों और संसद सदस्यों तथा जांच समितियों की रिपोर्टों से प्रायः अंश उद्धृत किए गए हैं। आज जब भारत सरकार, भारत के निजी उद्योग तथा अमेरिका का प्रकाशन विभाग अपने पक्ष को बलपूर्वक उपस्थित कर रहे हैं, तब चित्र का दूसरा पहलू इस पुस्तक से भली भांति प्रकट हो जाएगा। इसलिए इस पुस्तक की उपयोगिता को हम स्वीकार करते हैं। ● ●

'सम्पदा' की पूरे वर्ष की फाइल

केवल ४ रुपये में

१९५२ से १९५६ तक 'सम्पदा' की किसी भी वर्ष की फाइल (विशेषांकों सहित) केवल ४) में सुलभ हैं। कुछ ही फाइलें बची हैं। आज ही लिखें।

प्रसार विभाग सम्पदा, २८/११ शक्तिनगर दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा के अनूठे उपहार : ११ विशेषांक

'सम्पदा' का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विश्व-कोष ही होते हैं। प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम० कॉम० कहते हैं—'सम्पदा' के विशेषांक तो हमारे लिए गीता व बाइबिल के समान हैं।'

१-योजना अंक

(प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्व सामग्री)

एक प्रशंसनीय प्रयत्न। यह अंक पंचवर्षीय योजना को समझने की कुंजी है।

मूल्य : १.०० —जीवन साहित्य

२-भूमि-सुधार अंक

(भूमि समस्याओं का अद्भुत विवेचन)

इस विषय में अपने ढंग का अद्वितीय प्रकाशन है।

मूल्य : १.०० (अप्राप्य) —प्रताप

३-वस्त्र-उद्योग अंक

(भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं)

इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। सम्पादक को बधाई।

मूल्य : १.२५ —श्री घनश्यामदास बिड़ला

४-चम्बल अंक

(चम्बल योजना का विस्तृत परिचय)

अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है।

मूल्य : ००.७५ (अप्राप्य) —श्री मिश्रीलाल गंगवाल

५-मजदूर अंक

(मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन)

लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं। ...मानव की नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की संस्कृति व परम्पराओं के अनुकूल है।

मूल्य : १.२५ —श्री खंडूभाई देसाई

६-उद्योग अंक

(प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय)

भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याओं पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का अच्छा संग्रह है।

मूल्य : १.२५ —अजन्ता

७-राष्ट्रीय-विकास अंक

(द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन)

ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा।

मूल्य : १.२५ —श्री मोहनलाल सुखाडिया

८-बैंक अंक

(भारतीयों बैंक की समस्याओं का निरूपण)

Here is one more 'Sampada' Special worth treasuring. (अप्राप्य)

मूल्य : १.२५ —Organiser

९-समाजवाद अंक

(समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार)

सम्पदा का समाजवाद अंक मिला। यह काफी अच्छा और पठनीय है।

मूल्य : १.५० —श्री श्रीमन्नारायण

१०-राष्ट्र-प्रगति अंक

(द्वितीय योजना काल की समस्याओं का विवेचन)

यह अति लाभदायक तथा उपयोगी है। लिखने का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है।

मूल्य : १.५० —श्री अमरनाथ विद्यालंकार

११-सहकारी कृषि अंक

देश के अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न पर विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण। —मू० १.५०

रजिस्ट्री से सब प्राप्य अंक मंगाने के लिए रु० १०.५० भेजिये।

सम्पदा • २८-११ शक्तिनगर • दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'सम्पदा' का

आगामी विशेषांक

'सम्पदा' के विशेषांकों ने हिन्दी पत्रकारिता में एक विशेष परम्परा कायम की है। सदा की भाँति स्वतंत्रता दिवस—१५ अगस्त १९६० को इस वर्ष जो विशेषांक प्रकाशित होगा, वह न केवल इस परम्परा में एक कड़ी होगा, बल्कि 'सम्पदा' की नई प्रगति की सूचना भी देगा!

•

विषय सामग्री, आकार प्रकार, रूप सज्जा

सभी दृष्टियों से अपूर्व !

•

और क्या होगा विशेषांक का विषय ?

यह जानने के लिए एक मास की प्रतीक्षा कीजिए !

•

विशेषांक का मूल्य रुपए २.०० है; किन्तु स्थायी ग्राहकों को वार्षिक मूल्य रुपए ८.०० में ही विशेषांक सुलभ होगा। आज ही ८.०० भेजकर वार्षिक ग्राहक बनें !

सम्पदा • २८/११ शक्तिनगर • दिल्ली-६

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली से मुद्रित व अशोक प्रकाशन मन्दिर २८/११, शक्तिनगर दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

अर्थशास्त्र की नवीनतम गतिविधियों को मासिक पत्रिका

•

जून १९६०

मूल्य ७५ न.पै.

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक्सल की कहानी

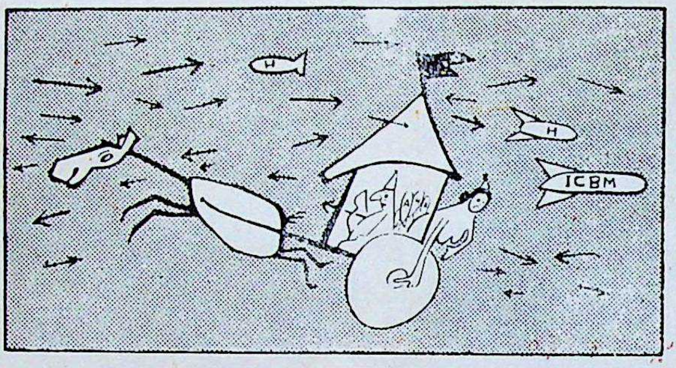

सारे रामायण महाकाव्य का उद्भव वास्तव में एक पुर्जे के टूटने से हुआ था घमासान युद्ध के बीच शाही रथ का एक्सल टूट गया, परन्तु रानी कैकेयी ने अपनी उंगली डाल कर पहिए को यथास्थान रखा. राजा दशरथ ने उस से कोई वर मांगने को कहा जिस का फायदा कुटिल रानी ने श्री राम को बनवास भेजने में उठाया.

इसलिए आप मानेंगे कि हमें अपने एक्सल मजबूत रखने होंगे. वियरवेल साइकिलें हर प्रकार के काम के लिए बनाई गई हैं. उन का हर पुर्जा मजबूत होता है.

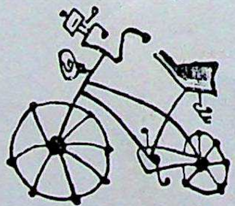

वियरवेल साइकिल्स

विमपेक्स (एजेंट्स) नई दिल्ली · बम्बई · कलकत्ता · मद्रास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

डालमिया

काश्म Stoneware एवं मृच्छिल्प Porcelain निर्मितियाँ (Products)

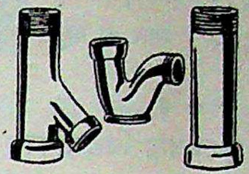

काश्म-नाल Stoneware Pipes
अधोभूमि जलोत्सारण के लिए

वज्रचूर्ण-अयस्संधा-नाल
(R. C. C. Spun Pipes)
पुलियाओं, जल-प्रदाय
और जलोत्सारण के लिए

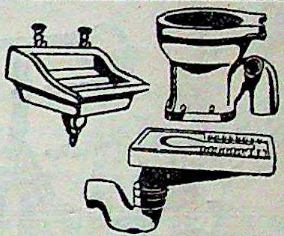

मृत्सा (Porcelain)
आरोग्य पात्र (Sanitary Wares)
भारतीय और यूरोपीय शौच-कुण्ड
(Water Closets)
धावन पात्री (Wash Basins)
मूत्र-कुण्ड (Urinals) इत्यादि

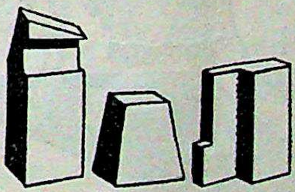

उष्मसह (Refractories)
समस्त औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए

पोर्टलैण्ड सिमेंट
सामान्य निर्माण के लिये

डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड
डालमियापुरम् (तिरुचिरापल्ली)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस अंक में

अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियाँ	अग्रलेख	२९३	नया निर्माण		३१७
टिप्पणियाँ		२९५	सर्वोदय पृष्ठ		३२०
लोकतंत्र में राजकीय उद्योग	मुरारजी जे० वैद्य	२९९	भारतीय जहाज उद्योग	सुमति मुरारजी बहन	३२३
योजनाएँ व औद्योगिक विकास	वेदप्रकाश गुप्त	३०२	संगठित और असंगठित मजदूरों के वेतन		३२५
वस्त्र-व्यापार संघों की सेवाएं	माधवप्रसाद कक्कड़	३०७	विदेशी अर्थचर्चा		३२६
क्या सहकारी खेती सम्भव है	चन्द्रदत्त शर्मा 'इन्दु'	३१०	पशु कैसे उन्नत हों ?	सुदर्शन चोपड़ा	३२८
ग्रामों का प्रवाह नगरों की ओर	त्रिलोकसिंह	३१२	अर्थवृत्त		३३१
हमारे उद्योग		३१५	मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएँ		३३४

• • •

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

संयुक्त सम्पादक : भीमसेन त्यागी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

अर्थशास्त्र की नवीनतम गतिविधियों की मासिक पत्रिका

वर्ष ६
अंक ५
जून १९६०

अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियां

अभी तक की सूचना के अनुसार 'सम्पदा' का यह अंक पाठकों के पास पहुँचने के कुछ दिन बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप प्रकाशित हो जायगा । इसका निश्चित रूप क्या होगा, यह पाठक जल्दी ही पढ़ लेंगे। इन पंक्तियों में हम इस नई योजना की कुछ परिस्थितियों पर विचार करना चाहते हैं।

अनेक दृष्टियों से आज तृतीय विकास योजना के लिये द्वितीय योजना की अपेक्षा कुछ स्थितियाँ अधिक अनुकूल हैं। पिछले दस वर्षों में हमने जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, वह भविष्य के लिये एक दृढ़ आधारशिला का काम करेगी। औद्योगिक उत्पादन विविध क्षेत्रों में काफी बढ़ गया है। न केवल पुराने उद्योगों का विस्तार हुआ है, बल्कि नये-नये कारखाने भी खुले हैं। लोहे के तीन कारखाने अब काम करने लगे हैं और आगामी योजना के दूसरे तीसरे वर्ष में पूरी गति से उत्पादन करने लगेंगे। खाद का कारखाना हो या इंजन बनाने का, दोनों अपनी प्रारंभिक बाधाओं को पार कर जोरों से उत्पादन करने लगे हैं। इस्पात, अलम्युनियम और रासायनिक द्रव्य पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने लगे हैं। रांची का भारी मशीनरी बनाने का कारखाना व भोपाल का बिजली की मशीनरी बनाने का कारखाना भी आगामी दो वर्ष तक उत्पादन करने लगेगा। इसी तरह नांगल और नेवेली के खाद के कारखाने बनने में अब अधिक समय नहीं लगेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनेक बाँध बन चुके हैं और अनेक शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं। इनके कारण सिंचाई की व्यवस्था के साथ-साथ बिजली का उत्पादन भी देश में पर्याप्त मात्रा में बढ़ने वाला है और इन सबका लाभ तीसरी पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने में हमें प्राप्त होगा। वस्तुतः तीसरी पंचवर्षीय योजना की आधारशिला काफी मजबूत बन चुकी है, जिस पर नया भवन खड़ा करने में वह कठिनता नहीं होनी चाहिये, जो पहली या दूसरी योजनाओं के प्रारंभ के समय थी।

भारत सरकार के उप वित्तमंत्री श्री बलीराम भगत, ने अपने एक भाषण में इन परिस्थितियों की चर्चा करते हुए कहा है कि विकास योजना की नई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनेक संस्थाएँ दृढ़ आधार पर स्थापित हो चुकी हैं और उन्हें पिछले वर्षों में पर्याप्त अनुभव भी हो गया है। किस तरह की कमियाँ आ सकती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इसका ज्ञान पहले न हो, पर आज तो यह नहीं कहा जा सकता। विभिन्न संस्थाएँ आज अनुभवी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सेना रखती हैं, इस सेना के अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले दक्ष मजदूरों और कुशल इंजनियरों की पर्याप्त संख्या आज देश के अन्दर मौजूद है, जो किसी भी नये कार्य को करने में समर्थ हैं।

भिन्न-भिन्न सरकारी और निजी उद्योगों को चलाने के लिये वित्तीय संगठनों की जरूरत होती है । दूसरी पंच-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वर्षीय योजना की अवधि में ऐसे अनेक संगठनों का विकास हो चुका है, जो न केवल निजी उद्योगों को पर्याप्त ऋण दे सकती हैं, बल्कि सरकारी उद्योगों के लिये भी धन की व्यवस्था कर सकती हैं। जीवन बीमा निगम के रूप में करोड़ों रुपये लगाने की क्षमता सरकार के पास आ चुकी है। राज्य व्यापार निगम भी आज सरकार को करोड़ों रुपया कमा कर दे रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण भी आज सरकार कुछ अधिक साहस के साथ व्यय करने की स्थिति में है।

इन सब दृष्टियों से देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल जान पड़ती हैं। इन्हीं अनुकूलताओं को देखकर ही सरकार ऊंची आकांक्षाओं से युक्त नई योजना तैयार कर रही है, इसका लक्ष्य ६५ अरब रुपया निश्चित प्रायः है, जिसमें निजी उद्योगों के लिए ४० अरब रुपया भी सम्मिलित है, इन्हीं अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय को ५ प्रतिशत वार्षिक बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है।

किंतु जहाँ ऊपर लिखी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं, जो दूसरी योजना की अपेक्षा अधिक प्रतिकूल हैं। किसी भी योजना की पूर्णता के लिये यह आवश्यक है कि मूल्यों में स्थिरता रहे। कमी न हो तो वृद्धि किसी भी अवस्था में नहीं होनी चाहिये। जब दूसरी योजना प्रारंभ की गई थी, तब मूल्यों का झुकाव नीचे की ओर था। राशन और कन्ट्रोल समाप्त करने की अवस्थाएँ उत्पन्न हो चुकी थीं। किन्तु दूसरी योजना की अवधि में मूल्य निरन्तर बढ़ते रहे हैं और आज करीब २०-२५ प्रतिशत मूल्य बढ़े हुए हैं। मूल्यों की अस्थिरता और वृद्धि की ओर झुकाव के कारण कोई भी कार्यक्रम निश्चित नहीं किया जा सकता। आज जो योजना ५ करोड़ रुपये की बनाई जाती है, कल उस पर ६·७ करोड़ रुपया व्यय हो सकता है। यही कारण है कि आज योजना के अधिकारी मूल्यों के स्थिरीकरण और मंहगाई रोकने पर अत्यधिक बल दे रहे हैं।

यद्यपि निकट भविष्य में किसी भीषण महा युद्ध की संभावना नहीं करनी चाहिये तथापि उत्तर में चीन के आक्रमणकारी रुख के कारण हमारी रक्षा व्यवस्था पर भारी बोझ आ पड़ा है, जो इस वर्ष के बजट से स्पष्ट है। किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के कारण देश को अपनी समस्त शक्ति विकास योजनाओं से हटानी पड़ सकेगी, इस संभावना को दूर नहीं किया सा सकता।

'सम्पदा' के पाठक जानते हैं कि द्वितीय योजना की अवधि में योजना आयोग को अपने लक्ष्य कम करने पर विवश होना पड़ा था। इसका मुख्य कारण साधनों का अभाव था। योजना के प्रारंभिक काल में ७४६ करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में रिज़र्व बैंक के पास था। इस मुद्रा का हमने खुलकर उपयोग किया और परिणामस्वरूप आज केवल १८० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हमारे भारत में बच गई है। हमारा निर्यात व्यापार हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं बढ़ा है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से आज हम अरबों रुपये का ऋण भले ही ले सकेंगे, किन्तु इन्हें व्याज सहित चुकाने की गंभीर समस्या को आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता।

यदि देश के आंतरिक साधनों से हम कुछ बड़ी राशि बचा सकते तो भी सन्तोष की बात थी। नये-नये करों से प्राप्त राशि शासन व्यय में लग जाने के कारण विकास योजनाओं में सहायक नहीं हो रही है। भारत सरकार के उप वित्त मंत्री श्री भगत ने अपने उक्त भाषण में यह स्वीकार किया है कि लोगों से बचत की प्रवृत्ति के कारण जिस राशि की आशा की जा रही थी, वह पूरी नहीं हो रही है। बचत की मद में बहुत कम रुपया आ रहा है। बढ़ती हुई मंहगाई तथा नये नये करों के अतिरिक्त मध्यम और उच्च वर्ग में जीवन स्तर को ऊंचा करने की झूठी प्रवृत्ति भी बचत में कमी का कारण है। श्री भगत कहते हैं कि बचत की दर को ऊंचा करने के लिए उपभोग पर नियंत्रण आवश्यक है। होना यह चाहिए कि हमारी जितनी आय बढ़े, उसका एक बड़ा अंश बचत के रूप में देश को मिलना चाहिये, लेकिन यह हो नहीं रहा।

अनेक सरकारी नीतियों के कारण भी आज जनता में वह उत्साह नहीं है जो ५ वर्ष पूर्व था। सामुदायिक विकास योजना, श्रमदान आदि की प्रवृतियाँ आज चेतनाहीन हो गई हैं। निजी क्षेत्र निरंतर अपने अधिकारों को कुंठित होता देखकर असन्तुष्ट है, यद्यपि सरकार ने उनके अनेक परामर्शों को दबी जबान से स्वीकार करना शुरू किया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ऊपर हमने तृतीय योजना के प्रारंभ के अवसर पर उपस्थित अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों की चर्चा की है। हमें आशा करनी चाहिये कि योजना निर्माता सब परिस्थितियों पर विचार करके अपनी योजना प्रस्तुत करेंगे। हमें यह भी आशा करनी चाहिये कि वे योजना की आलोचनाओं को विध्वंसात्मक न समझ कर सहानुभूति पूर्वक दिये गये परामर्श समझेंगे और तदनुसार आवश्यक परिवर्तन करने में संकोच नहीं करेंगे।

योजनेतर व्यय में वृद्धि

विकास योजनाओं के बढ़ते हुये खर्चे को पूरा करने के लिये दो ही उपाय आवश्यक हैं। एक तो आय के साधनों को बढ़ाकर उनका विकास कार्यों में उपयोग और दूसरा यह कि अपने विभिन्न खर्चों में यथा-संभव कमी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के वार्षिक कार्यों पर जब कभी दृष्टि डाली गई है तभी योजना आयोग ने यह शिकायत की है कि राज्य सरकारें नये नये कर लगाकर आमदनी जरूर बढ़ाती है लेकिन यह बढ़ी हुई आय विकास-योजनाओं में पूर्णतः नहीं लगती। इसका अधिकांश भाग प्रशासकीय व्यय में लग जाता है। शासन का व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हाल ही में सरकार की एक और रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है प्रशासकीय योजनेतर व्यय में वृद्धि। इसके अनुसार १९५५-५६ के आधार पर आगामी ५ वर्षों में २,५०० करोड़ रुपये की आय होनी थी, लेकिन दूसरी योजना की अवधि के ५ वर्षों में केन्द्र को नये करों की वजह से ३,२९२ करोड़ रुपये की आय होगी; अर्थात पहले के आधार से ७९२ करोड़ रुपया अधिक। हालांकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में करों से बढ़ने वाली आय का अनुमान केवल ४२० करोड़ रुपया किया गया था। यदि ७९२ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय केवल विकास योजनाओं पर लगती तो इसका बहुत लाभ होता, किन्तु योजनेतर प्रशासकीय व्यय बहुत बढ़ गया। पहले के अनुमान के अनुसार इस मद में २,३२६ करोड़ रुपये व्यय होने थे, किन्तु यह व्यय बढ़कर २,९३२ करोड़ रुपये हो गया। इस तरह योजना कार्यों के लिये केवल ४४० करोड़ बचा। विकास योजनाओं के नाम पर सरकार एक के बाद एक कर लगाती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा भाग प्रशासकीय कार्यों पर खर्च कर दिया गया। परिणाम स्वरूप वित्त-मंत्रियों को घाटे की अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है। यह ठीक है कि नई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण १८० करोड़ रुपया प्रतिरक्षा की मद में बढ़ाना पड़ा है। फिर भी प्रशासकीय व्यय में ४२६ करोड़ रुपये की वृद्धि के लिए सरकार को उत्तर देना चाहिए। शासन प्रबन्ध आय-व्यय का निरीक्षण, जेल, न्याय-पुलिस, बन्दरगाह, आदिमजाति तथा परराष्ट्र विभाग पर १९५०-५१ में केवल २२.०५ करोड़ रुपया व्यय हुआ था। १९५५-५६ में यह व्यय बढ़कर ३४.८१ करोड़ रुपया हो गया और १९५८-५९ में यह व्यय और भी बढ़कर ६२.४० करोड़ रुपया हो गया। इसका अर्थ यह कि १९५०-५१ की अपेक्षा करीब ८०% प्रशासन व्यय में वृद्धि हुई।

हमने ऊपर केवल केन्द्रीय प्रशासन व्यय की चर्चा की है। राज्यों की भी यही कथा है, प्रशासन व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है, यह ठीक है कि सरकार की अपनी जिम्मेवारियां बढ़ रही हैं, किन्तु सरकार का प्रशासन व्यय उससे भी तेजी से बढ़ रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या किस तरह बढ़ रही है, यह निम्न तालिका से स्पष्ट है :

	३१ मार्च १९५० ५१	३१ मार्च १९५९
कुल कर्मचारी	५८०४०५	७१९५६९
प्रबन्ध अधिकारी	४८६८५	७४१६९
क्लर्क	१३५२०१	२४१३१९
दक्ष या अर्ध-दक्ष कर्मचारी	१४६९७५	१५८३६८
अदक्ष	२४९५४४	२४५७१४

राज्य सरकारों की कहानी भी इससे मिलती हुई है, इन अंको के बाद किसी और टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

शक्ति की माँग

'नेशनल कौंसिल' ने १९६० से ७५ तक देश को बिजली की आवश्यकता पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है। इस पुस्तक में यह अनुमान किया गया है कि यदि १९५५-५६ में प्रति व्यक्ति आय २८१ रु० थी तो पांचवीं योजना के अन्त में वह ५६४ रु० तक पहुँच जायगी। इस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

दृष्टि से देश का औद्योगिक उत्पादन भी बहुत बढ़ता जायगा, उक्त कौंसिल के अनुमान के अनुसार यह उत्पादन निम्नलिखित रूप से बढ़ेगा।

औद्योगिक उत्पादन १९५१=१००

१९५५	१२१.१
१९६०	१८५.०
१९६५	२८५.०
१९७०	४२०.०
१९७५	६१०.०

उद्योग की इस प्रगति के साथ साथ देश को कोयले, बिजली, पेट्रोलियम, अणुशक्ति आदि साधनों से अधिकाधिक शक्ति की आवश्यकता प्रतीत होगी। उपर्युक्त साधनों से एक अनुमान के अनुसार निम्नलिखित मात्रा में शक्ति की आवश्यकता उत्पन्न होगी :

शक्ति की मांग (कोयले के १० लाख टन के बराबर)

	कोयला	पानी	पेट्रोलियम	अणुशक्ति	कुल
१९५५	३५.६३	३.०५	६.१६	—	४४.८४
१९६०	६२.४०	८.६५	१०.६३	—	८१.६८
१९६५	९७.१३	१५.५०	१६.९९	००.९५	१०३.५९
१९७०	१४९.७७	२६.००	१७.२९	३.२२	२०६.२७
१९७५	२२९.३६	४०.२०	४४.२१	७.५२	३१९.२९

इसके अलावा द्वितीय अवस्था में भी शक्ति की आवश्यकता होगी, जो १९७५ में ८८.०० (दस लाख टन में) टन तक बढ़ सकती है।

उक्त कौंसिल ने यह भी अनुमान लगाया है कि भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये शक्ति की कितनी खपत होगी।

१९७५ में शक्ति की माँग (हजार टनों में)

	कोयला	बिजली	पैट्रोलियम
१. कृषि तथा सन्बद्ध कार्य	४०००	१८००	२२८०
२. उद्योग	३५९६०	५०३७६	१३२४५
३. यातायात	२३२००	४१९०	१६६४८
४. घरेलू आवश्यकतायें	३७३००	४४६५	५१४२
५. सार्वजनिक और व्यापारिक सेवायें	३०००	४११०	—
६. विविध	४०००	—	९००

इन अनुमानों से प्रकट होता है कि बिजली कोयला, अणु तेल आदि विविध साधनों से शक्ति उत्पादन के लिये हमें कितना प्रयत्न करना पड़ेगा।

स्टेट बैंक की सफलता

कैराना (उत्तरप्रदेश) में एक शाखा कार्यालय खोलने के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने उस कार्यक्रम को पूर्णतः सम्पन्न कर लिया है, जिसकी घोषणा बैंक की स्थापना के समय की गयी थी और इसके साथ ही उसने अपने जीवन के प्रथम पांच वर्ष भी प्रायः पूर्ण कर लिये हैं। 'सम्पदा' के नियमित पाठकों को संभवतः यह स्मरण होगा कि १ जुलाई १९५५ को स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। एक सरकारी कानून द्वारा इम्पीरियल बैंक को, जो उन दिनों एक निजी बैंक था, स्टेट बैंक के रूप में परिणित कर दिया गया। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण वस्तुतः समाजवाद की दिशा में एक बड़ा प्रयत्न बताया गया था। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य गाँव-गाँव में बिखरे हुये किसानों को सहकारी बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता देना बताया गया था। यह बैंक अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सके तथा दूसरे व्यापारिक बैंकों के मार्ग में प्रतिस्पर्धी बनकर बाधा न पहुँचाये, इस ख्याल से उस समय यह घोषणा की गई थी कि यह बैंक प्रायः उन देहातों व छोटे नगरों में अपनी शाखायें खोलेगा, जहाँ निजी बैंक मैदान में नहीं आते हों। उस समय ५ वर्षों में ४०० शाखायें खोलने का विचार प्रकट किया गया था। अपनी अवधि के समाप्त होने से पहले ही कैराना में चारसौवीं शाखा खोलकर बैंक ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है।

बैंक के अध्यक्ष श्री पी० सी० भट्टाचार्य ने बताया है कि पहले साल में नया काम था, इसलिये ज्यादातर कार्य चार वर्षों में ही किया गया है। चार वर्ष में चार सौ शाखायें खोलने का अर्थ है प्रति वर्ष १०० और सप्ताह में करीब दो शाखाएं खोलना। श्री भट्टाचार्य के कथनानुसार स्टेट बैंक की यह सफलता भारतीय बैंकों के इतिहास में और संभवतः संसार के बैंकिंग के इतिहास में अद्वितीय है १९४८ से १९५८ तक के वर्षों में भारत के सब परिगणित बैंकों ने कुल मिलाकर ३,०११ शाखाएँ खोली हैं। यह ठीक है कि इस सफलता का मुख्य श्रेय सरकार और रिज़र्व बैंक की

GURUKULA KANGRI LIBRARY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अनुलनीय सहायता की है; फिर भी बैंक अधिकारी संगठन सम्बन्धी जटिल कार्य के सम्पादन के लिये बधाई के पात्र हैं।

राष्ट्रीयकरण के साथ स्टेट बैंक की स्थापना के समय अनेक नये क्षेत्रों से बैंक की सफलता के बारे में सन्देह प्रकट किया गया था, किन्तु बैंक अधिकारियों ने उन सब सन्देहों को दूर कर दिया है। एक ओर जहाँ उसने ग्रामों सहकारी समितियों को अधिकाधिक सहायता दी वहाँ उसने दूसरी ओर सफल व्यापारिक बैंक के कार्यों को भी निभाया है। श्री भट्टाचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि अब बैंक पहले की अपेक्षा निजी क्षेत्र की भी अधिक सेवा कर रहा है, आज सब व्यापारिक बैंक भी कोई नया कदम उठाने से पहले स्टेट बैंक के नेतृत्व की प्रतीक्षा करते हैं, हमें आशा है कि आगामी वर्षों में स्टेट बैंक देहाती या व्यापारिक, दोनों क्षेत्रों की आवश्यकतायें पूर्ण करने में और भी अधिक सफल हो सकेगा।

तेल के नये विपुल स्रोत्र

खम्भात के लुनेज क्षेत्र में तेल के स्रोतों का पता चलने के पश्चात् भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। इस क्षेत्र की नवीनतम खोजों के परिणाम और भी उत्साहवर्धक हैं, अब ६ नम्बर के परीक्षण कुएं में ६,७०० फुट की गहराई पर तेल मिला है। इतना ही नहीं ८ नम्बर के कुएं में तो केवल ३,८४० फुट की गहराई पर तेल निकल आया है। सामान्यतः इतनी कम गहराई पर तेल नहीं निकलता है। वैसे भी अनेक कुओं की खुदाई करने पर किसी एक में तेल निकला करता है; किन्तु खम्भात में जितनी आसानी के साथ और जितनी विपुल मात्रा में तेल निकल रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि खम्भात शीघ्र ही भारत का बाकू सिद्ध होगा।

लुनेज क्षेत्र के अतिरिक्त खोजों के परिणाम स्वरूप खम्भात नगर के दक्षिण में करीब १०० मील पर अंकलेश्वर में जो नया तेल का क्षेत्र मिला है, वह अब तक के तेल क्षेत्रों में सर्वोत्तम है। इस नये तेल क्षेत्र की खोज तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ने रूसी विशेषज्ञों की सहायता से की है। अंकलेश्वर में मिला तेल श्रेष्ठता और मात्रा में अब तक मिले तेल क्षेत्रों में सबसे अधिक है।

खम्भात के क्षेत्रों के अतिरिक्त उम्भानी आदि और भी कई स्थानों पर तेल की खोज का कार्य हो रहा है। इन स्थानों की मिट्टी के जो परीक्षण किए गए हैं, उनसे आशा की जाती है कि उन स्थानों में मात्रा में तेल मिलना चाहिए।

ये सब खोज परीक्षण सफल रहे तो आशा है कि भारत तेल के क्षेत्र में न केवल आत्म-निर्भर हो जाएगा, बल्कि तेल का निर्यात भी कर सकेगा। वह दिन भारत के औद्योगिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा।

धूम्रपान और राष्ट्र-विकास का प्रश्न

एक विज्ञप्ति के अनुसार १९५९ में भारत में सिगरेट उद्योग में लगी कुल पूंजी २० करोड़ रुपये थी और कुल ३,१६३ करोड़ सिगरेटों का उत्पादन हुआ। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कितनी बड़ी मात्रा में प्रति वर्ष सिगरटें बनाई और पी जाती हैं। यह आंकड़े मात्र सिगरेट के सम्बन्ध में हैं। इनके अतिरिक्त सिगार, बीड़ी, हुक्का आदि रूपों में भी धूम्रपान होता है। यह धूम्रपान देश के नागरिकों के लिए कितना हानिप्रद है, इस सम्बन्ध में जो वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं, उनसे स्पष्ट हो गया है कि बहुत अधिक धूम्रपान करने से मुँह और जबान का कैंसर होने की सम्भावनाएँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अभी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के ३४ हजार व्यक्तियों पर किये गये प्रयोग से पता चला है कि धूम्रपान करने वाले और तम्बाकू खाने वाले लोगों में कैंसर के कीटाणु अपेक्षाकृत अधिक थे। उसके पूर्व १९५२-५८ में टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई में १४६० मरीजों पर प्रयोग किया गया था और उसके परिणाम भी उपरोक्त ही रहे थे।

इस सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी मैडिकल रिसर्च कौंसिल आफ ब्रिटेन की एक खोज रिपोर्ट से मिलती हैं। उसमें कहा गया है, "अनेक देशों के अनेक व्यक्तियों पर प्रयोग करने से पता चला है कि दुनियाँ में कैंसर के मरीजों में अधिक संख्या सिगरेट पीने वालों की ही होती है।"

इसी प्रकार अमेरिकन कैंसर रिसर्च सोसाइटी द्वारा किये गये एक प्रयोग से भी पता चला है कि कैंसर के मरीजों में धूम्रपान करने वाले, विशेषरूप से सिगरेट पीने वाले ही अधिक होते हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन सब खोजों से स्पष्ट हो जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। लेकिन हमारी अर्थ-लोलुप अर्थव्यवस्था उन सब हानियों की तरफ ध्यान नहीं देती और सरकार भी तम्बाकू और सिगरेट उद्योग से करों के रूप में और निर्यात व्यापार के रूप में होने वाली आय के कारण इस विषैले दुर्व्यसन को रोकने की बजाय निरन्तर प्रोत्साहित कर रही है।

भारत में प्रतिवर्ष ४० करोड़ रुपये के तम्बाकू का उत्पादन होता है, जिसमें से विदेशों को बेचकर १६-१७ करोड़ रु. विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन कर रूप में सरकार को तम्बाकू उद्योग से भारी आय होती है। १९५९-६० के एक वर्ष में ही सरकार ने इस साधन से ५१ करोड़ रुपये प्राप्त किये। तम्बाकू उगाने और सिगरेट-बीड़ी बनाने तथा बेचने के काम में अनेक लोग लगे हुए हैं।

यह ठीक है कि सरकार को इस उद्योग से पर्याप्त आर्थिक लाभ होता है और इस बेरोजगारी के जमाने में कुछ लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है; लेकिन महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह लाभ उस हानि से अधिक बड़ा है, जो कि धूम्रपान करने से देश के करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य चौपट कर रही है। अर्थशास्त्र की दृष्टि में सब कार्यों का मापदण्ड केवल रुपया रह गया है, किन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि मानव जीवन का हित रुपये से अधिक मूल्यवान् है। इस मूल तथ्य की उपेक्षा के कारण ही महात्मा गांधी वर्तमान अर्थशास्त्र को अनर्थशास्त्र कहते थे। समाज कल्याण की योजनाओं में जहाँ हम बिना आय की अपेक्षा किए करोड़ों रु० व्यय करते है, वहाँ तमाखू के प्रयोग से होने वाली हानि को कम नहीं कर सकते, तो बढ़ने तो न देना चाहिए, भले ही कुछ आर्थिक हानि भी सहन करनी पड़े।

अणुशक्ति से बिजली

श्री एच. जे. भाभा कुछ साथियों के साथ रूस और अमरीका जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य अणुशक्ति की मशीनरी के लिए विदेशी मुद्रा उपलब्ध करना है। वे अणुशक्ति के उत्पादन के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं। कुछ वैज्ञानिकों के कथनानुसार अणुशक्ति से बिजली निकालना थर्मल स्टेशनों की अपेक्षा महँगा पड़ेगा। किन्तु श्री भाभा का विचार यह है कि यदि जल-विद्युत स्टेशनों पर होनेवाले बड़े-बड़े बाँध तथा शासन प्रबन्ध के व्यय को देखा जाय तो अणुशक्ति से बिजली महंगी नहीं पड़ेगी। थर्मल स्टेशनों से अणुशक्ति संयत्रों का खर्च जरूर डेढ़ गुना है, परन्तु जब हम यह देखते हैं कि देश में बिजली की कितनी कमी है तब हमें अणुशक्ति का सहारा लेना ही होगा और एक बार अणु-संयत्रों के साथ सहायक यंत्रों का (Breeder Plants) का निर्माण हो गया तो अणु-विद्युत महंगी नहीं पड़ेगी।

पुस्तकों के निर्यात से विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए भारत में प्रकाशित पुस्तकों का निर्यात भी एक अच्छा साधन बन सकता है। एक समाचार से ज्ञात हुआ है कि इस दिशा में श्रीगणेश किया जा चुका है। पिछले साल भारत ने लगभग १ करोड़ रु० की पुस्तकें बाहर भेजीं। पुस्तकें मंगानेवाले देशों में—पाकिस्तान, बर्मा, लंका, इन्दोनेशिया, मलाया, ब्रिटेन, अमरीका, थाईदेश, सिंगापुर, केनिया और अदन हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय निर्यात बढ़ाने के लिए इस वर्ष जून में देश के प्रमुख प्रकाशकों और पुस्तक निर्यातकों की बैठक कलकत्ता में बुला रही है। पाकिस्तान, अमरीका, जापान, हांगकांग, फिलिपाइन्स, थाईदेश, बर्मा, मलाया और आस्ट्रेलिया को अधिक पुस्तकें भेजी जा सकती हैं। इंजीनियरी और शिल्पिक विषयों की पुस्तकों के सस्ते संस्करणों की इन देशों में काफी खपत हो सकती है। भारतीय कला, पुरातत्व, सभ्यता और जन-जीवन संबंधी सचित्र पुस्तकें भी इन देशों में आसानी से बेची जा सकती हैं। पश्चिम एशिया के देशों को कुरान की प्रतियाँ काफी संख्या में निर्यात की जा सकती हैं। पूर्वी पाकिस्तान में अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों के अलावा उर्दू और बंगाली साहित्य की पुस्तकों की काफी खपत है। तामिल की पुस्तकें मलाया और लंका को निर्यात की जा सकती हैं। यह एक अच्छा मनोरंजक उद्योग है। इससे प्रकाशक और लेखक दोनों को लाभ हो सकता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लोकतन्त्र में राजकीय उद्योग

मुरारजी जे. वैद्य

आधुनिक जीवन का यह दुर्भाग्य है कि जो शब्द कुछ संज्ञाओं के लिए उपयोग में लाये जाते थे, आज अपने वास्तविक अर्थ को व्यक्त नहीं करते हैं उदाहरण के तौर पर साम्यवादी देशों में तथाकथित "जनता के लोकतंत्र" वास्तव में न तो जनता के ही होते हैं और न लोकतंत्र ही, इन देशों में कोई कानून लागू नहीं होता है, अपने ही मामलों के संचालन में स्वयं जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है, वहां न जान-माल की कोई सुरक्षा रहती है और न व्यक्तिगत स्वाधीनताओं का अस्तित्व और राज्य की सत्ता का उपयोग। केवल एक या कुछ इने-गिने व्यक्तियों द्वारा एक ऐसे दल के नाम पर किया जाता है, जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है लेकिन जो वास्तव में मजदूरों का दमन करता है और उनको न केवल उनके उचित वेतन से बल्कि स्वतंत्र लोकतांत्रिक कामगार संघों के अधिकारों से भी वंचित रखता है ।

इसी प्रकार भारत के सार्वजनिक विचार-विमर्श की भाषा में "सार्वजनिक क्षेत्र" शब्द से अधिक और कोई शब्द इतना अधिक गलत अर्थ बतानेवाला नहीं है, राजकीय उद्योग, जिनके लिए "सार्वजनिक क्षेत्र" शब्द का उपयोग किया जाता है, किसी भी अर्थ में सामाजिक नहीं है, सिवा इसके कि सैद्धांतिक तौर पर उनका स्वामित्व जनता में निहित है, वास्तव में इन उद्योगों का सार्वजनिक होना उसी प्रकार है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की नदी में दिखाई देनेवाली परछांई स्वयं नदी का एक अभिन्न अंग है ।

राजकीय उद्योगों पर कांग्रेस संसदीय दल की उप-समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार राजकीय संस्थानों को ८ प्रकार के बताया गया है, जैसे स्टेट बैंक, कानूनी निगम, विभागीय उद्योग, नियंत्रण मंडल, वस्तु मंडल आयोग, पतन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) और स्थानीय शासन और लिमिटेड कम्पनियां, दुर्भाग्य से अन्तिम श्रेणी को अर्थात् लिमिटेड कम्पनियों को "प्राइवेट" कहा जाता है ।

उक्त विविध प्रकार के राजकीय संस्थानों की समस्याएं विभिन्न है, लेकिन राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में उनके विद्यमान होने के कारण कुछ ऐसे मूलभूत प्रश्न पैदा होते हैं जिन पर लोकतांत्रिक जीवन में विश्वास करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को सावधानीपूर्वक विचार करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है ।

हमारे लिए राजकीय उद्योग कोई नये नहीं है, राजकीय उद्योग न ही तो सोवियत रूस के साम्यवाद की और न भारत की समाजवादी समाज रचना की ही देन हैं, प्राचीन यूनान के नगर राज्य खानों के मालिक थे और उनका संचालन करते थे, टकसालें और डाक-सेवाएं परम्परा से ही राज्य की थीं और उसकी ओर से ही संचालित होती आ रही हैं, लेकिन आज राजकीय उद्योग केवल खानों या टकसालों और डाक-सेवाओं तक ही सीमित नहीं है, आज ये समस्त औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त है ।

सार्वजनिक क्षेत्र

भारत में तथाकथित "सार्वजनिक क्षेत्र" की स्थापना, जिसका वास्तव में अर्थ राजकीय क्षेत्र या राजनैतिक नौकरशाही क्षेत्र है, सैद्धांतिक अनिवार्यता के अंतर्गत हुई है, आर्थिक विकास के सम्वर्द्धन या आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य के प्रवेश पर किसी भी व्यक्ति का निरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक रंग से सार्वजनिक जीवन में अनावश्यक तनाव और विवाद उत्पन्न होता है । उदाहरण के लिए जब सुरक्षा विभाग के आधीन गोला बारूद की फैक्टरियों (आर्डनेन्स फैक्टरियों) को सैद्धांतिक कारणों पर ट्रकों के उत्पादन में लगा दिया गया हो; जबकि ऑटोमोबाईल की निजी फैक्टरियों की वर्तमान क्षमता बेकार पड़ी हुई हो तब जनता का प्रश्न करना एवं सन्देहास्पद दृष्टि से देखना स्वाभाविक है । यह तो औद्योगिक क्षमता की बरबादी है, विशेषतया उस समय जबकि देश की मुख्य आवश्यकता देश की समृद्धि की वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी साधनों का भरसक उपयोग करना चाहिए था । यह एक और दुःखद पहलू है कि हमारे देश में ऐसे समय में जब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अस्त्र-शस्त्रों की कमी है, जबकि चीन का साम्यवादी साम्राज्यवाद हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर कर रहा है और हमारे नये लोकतंत्र के इस खतरे को दूर करने के लिए हमारी सुरक्षा सेनाओं को सम्पूर्ण रूप से सज्जित होना चाहिए, शस्त्राशस्त्र के कारखाने अधिक ट्रक तैयार करने में लगे हैं। यह स्पष्ट है कि न केवल अधिक उत्पादन और समृद्धि की दृष्टि से ही हमारे राष्ट्रीय हित को हानि पहुँच रही है। बल्कि राष्ट्र का जीवन भी संकट में आ पड़ा है; क्योंकि सैद्धान्तिक अनिवार्यता के आधीन आर्डनेंस फैक्टरियों को उनके उचित मार्ग से हटाया जा रहा है। यह तो एक उदाहरण है कि किस प्रकार राष्ट्रीय हित पर विचार किये बिना भारत में राजकीय क्षेत्र के व्यापक विस्तार के फलस्वरूप वे नागरिक संदिग्ध हो उठे हैं, जो देश का औद्योगीकरण, समान अवसर सुलभ कराने, जीवन के ऊंचे जीवनमान और सामाजिक न्याय को स्थापना शीघ्रता से करना चाहते हैं। एक प्रश्न यह उठ सकता है कि राजकीय उद्योगों के लिए कौन-सा आधार उचित है, राष्ट्रीय हित की दिशा में योग देने और औद्योगिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक जीवन में स्वतः सन्तुलन कायम करने के उद्देश्य से निम्न-आधारों पर विचार किया जा सकता है :

(१) क्या किसी राजकीय उद्योग की स्थापना या राजकीय उद्योगों के क्षेत्र में वृद्धि करना केवल एक सैद्धांतिक कदम है या वह देश के अधिकतम उत्पादन की दिशा में सहायक है? पहला कारण इस प्रकार के कदम को उचित नहीं ठहराता है ? (२) क्या राजकीय उद्योग विशेष का स्वरूप एकाधिकार या अर्ध-एकाधिकार है और इस प्रकार से उपभोक्ता पर अपना दबाव डाल सकता है और उसको उपभोक्ता पसन्दगी के सर्वोच्च अधिकार से वंचित कर सकता है, यदि वस्तुस्थिति ऐसी है तो वह उचित नहीं है, (३) क्या राजकीय उद्योग विशेष रूप से पदार्थों एवं सेवाओं का उत्पादन, कार्यक्षमता और मितव्ययता से किया जाता है? यदि नहीं तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं है, (४) क्या राजकीय उद्योग में कर्मचारियों के साथ वेतन, कार्य करने की श्रेष्ठ अवस्थाएं और अन्य सुविधाओं के रूप में उचित व्यवहार किया जाता है ? क्या उसमें कर्मचारियों के एक वर्ग के सन्तोष के लिए समुदाय पर किसी प्रकार का असन्तुलित भार पड़ता है ? दूसरे शब्दों में कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के साथ-साथ समुदाय के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए, यदि इस शर्त को पूरा नहीं किया जा सकता है तो राजकीय उद्योग का कायम रहना उचित नहीं है, (५) क्या राजकीय उद्योग राजनैतिक हस्तक्षेप में स्वतंत्र रह सकता है और उसकी स्थापना राजनीतिज्ञों और नौकरशाहियों के अधिकारों, संरक्षण और उनके विशेषाधिकारों से दूर रह सकता है ?

राजकीय उद्योगों का संचालन

इन सभी शर्तों पर विचार करने से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी राजकीय उद्योगों के संचालन की स्थिति उत्साहजनक नहीं है, इन स्थितियों पर हम क्रमशः विचार करेंगे।

(१) आज भारत जैसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देश की आवश्यकता है—उत्पादन में भरसक वृद्धि करना। इसलिए जनता के सभी वर्गों में नियोजन को समर्थन प्राप्त है, क्योंकि लोगों का यह सामान्य विश्वास है कि नियोजन के जरिए समुदाय के सभी साधनों का उपयोग भरसक कार्यक्षमता के साथ किया जा सकता है, इसलिए तीव्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से किसी खास उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र के अधिक घटकों की स्थापना करना है तो उस समय सैद्धान्तिक विचारों से वस्तुस्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। राज्य या निजी व्यक्ति जो भी उद्योग विशेष या औद्योगिक घटको सस्ते एवं शीघ्रता से क्रियान्वित करने की उचित योजना प्रस्तुत करता हो, उसका उपयोग करना चाहिए। ट्रकों के निर्माण की तरह हमारे अनुभवों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

(२) अमेरिका और रूस की आर्थिक पद्धतियों का उद्देश्य एक ही है; अर्थात् जनता के "जीवनमान" को बढ़ाना, लेकिन "जीवनमान" शब्द की परिभाषा तभी सार्थक होती है, जब व्यक्ति विशेष एक नागरिक के रूप में अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीद में अपनी पसन्दगी का उपयोग कर सके, इसके लिए न केवल वस्तुओं की विभिन्न किस्में होनी चाहिएं, बल्कि मूल्यों में भी अन्तर होना चाहिए ताकि वह अपनी पसन्दगी निर्धारित कर सके। लेकिन उपभोक्ता का यह मूल्यवान अधिकार उस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

समय संकुचित हो जाता है जब उद्योग विशेष का एकाधिकार (मोनोपली) होता है। उपभोक्ता को न केवल वस्तुओं की विभिन्न किस्मों से वंचित रखा जायगा बल्कि कीमतें भी ऐसी होंगी, जिन्हें एकाधिकारी अपनी इच्छानुसार वसूल कर सकता है। इस बात पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस देश के राजकीय उद्योगों में उपभोक्ता और उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान न देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

इस संदर्भ में सोवियत रूस की हाल ही की घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, उपभोक्ता वस्तुओं पर कम्युनिस्ट पार्टी के एक विवरण में १५ अक्टूबर १९५९ को कहा गया है कि :

"अनेक सांस्कृतिक और दैनिक घरेलू उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन जनता की उत्तरोत्तर भागों की तुलना में लगातार घट रहा है। टेलीविजन सेटों; पियानों; बच्चों तथा युवकों की सायकिलों; धुलाई और सिलाई की मशीनों; रेफ्रीजिरेटरों; बिजली के पंखों; खाद्य पीसने की मशीनों; चायना ग्लास और एनेमिल के बर्तनों; घरेलू रासायनिकों; लोहे आदि के सामानों का अभाव है।

"अनेक कस्बों और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यन्त साधारण घरेलू आवश्यकताओं को खरीदना संभव नहीं है हालांकि उनका उत्पादन उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है। प्लास्टिक तथा अन्य मिश्रित पदार्थों के बने सामान बहुत कम मात्रा में तैयार किये जाते हैं।

एकाधिकारी उत्पादक

ये शिकायतें इसलिए पैदा होती हैं कि राज्य एकाधिकारी उत्पादक है।

(३) सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और फासिस्ट जैसे सभी समूहवादियों का नारा है कि राजकीय उद्योगों का संचालन कार्यक्षम और सस्ते तरीकों से किया जाता है। कर्मचारी में सैद्धांतिक रूप से मानी हुई यह भावना कि राजकीय उद्योग स्वयं उसी का है, भौतिक प्रोत्साहन या नकद रकम का स्थान नहीं ले सकती है। इसलिए कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन देना आवश्यक समझा गया। लेकिन राजकीय उद्योगों का ढांचा इस प्रकार का है कि उससे तो सभी सम्बन्धित लोगों में गैर जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है, क्योंकि सभी का कार्य बाद में किसी का कार्य नहीं रह जाता है। दूसरे, यह बात है कि राजकीय उद्योग के पीछे करदाताओं के योग से विपुल साधन सम्पन्न राज्य का खजाना विद्यमान है और जिन्हें अधिक कर देने के लिए कानूनी तौर से बाध्य किया जा सकता है। राजकीय उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों में सुरक्षा और आराम की भावना पैदा हो जाती है। इस आत्मतुष्टि से कार्यक्षमता की नैतिकता में भारी पतन हो जाता है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जैसे राजकीय संस्थानों में भी जिसे भारत में राजकीय उद्योगों में कार्यक्षम संचालन का नमूना माना जाता है, अनेक ऐसे तथ्य हैं, जो निजी क्षेत्र के संस्थानों से भिन्न है। उदाहरण के तौर पर राजकीय उद्योगों पर कांग्रेस संसदीय दल की उपसमिति के प्रतिवेदन में इस बात को माना गया है कि हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० और भारत इलेक्ट्रोनिक्स दो प्रतिष्ठान हैं जिनको राजकीय उद्योग की सामान्य गति में श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता है।

"दो प्रतिष्ठान हैं जिनके बारे में विशेष उल्लेख करना आवश्यक है, और उनके नाम हैं हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर। रूपरेखा में ये कम्पनियां कम्पनी कानून के अन्तर्गत स्थापित हुई हैं लेकिन इनका मुख्य ग्राहक सरकार है और वह भी विशेष रूप से सुरक्षा विभाग और छोटे पैमाने पर रेलवे विभाग। ये प्रतिष्ठान सुरक्षात्मक अवस्थाओं में, जैसा कि इनको चाहिए भी, कार्य करते हैं और कुछ हद तक इनकी संचालन क्रिया को जनता के सामने सम्पूर्ण रूप से बताया भी नहीं जा सकता है, हालांकि ये गुप्त फैक्टरियां नहीं हैं। इनके विकास पहलुओं में गुप्त प्रक्रियाएं और राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण खर्च सम्बद्ध हैं, जिन्हें उनकी समीक्षा में शामिल करना जरूरी है। वास्तव में वे सुरक्षा फैक्टरियाँ है। इसलिए इन स्थानों में उत्पादन का आधार प्रायः केवल लागत नहीं हो सकती है।

(४) इस बात का हमेशा दावा किया जाता है कि राजकीय संस्थानों को एक आदर्श मालिक के रूप में होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कथन और व्यवहार के बीच इतना बड़ा अन्तर अन्यत्र दिखाई नहीं देता, जितना कि इस दिशा में। कामगारों को उनके राजनैतिक स्वाधीनता सम्बंधी वैध अधिकारों से वंचित किया जाता है। हाल ही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंचवर्षीय योजनाएं व औद्योगिक विकास

वेदप्रकाश गुप्त, एम. ए.

प्रथम योजना का उद्देश्य मुद्रास्फीति को रोकना तथा खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना था। परन्तु इसके साथ-साथ अन्य क्षेत्रों की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। उद्योगधन्धों की प्रगति के लिये प्रथम योजना के अन्तर्गत बड़े स्तर के उद्योगों, खानों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये १३६ करोड़ रुपया तथा लघु उद्योगों के लिये ४६ करोड़ रुपया रखा गया।

जहाँ तक व्यय का प्रश्न है, योजना काल में इन मदों पर केवल १०० करोड़ रुपया ही खर्च किया जा सका। इसका मुख्य कारण था नए उद्योगों को स्थापित करने में आने वाली कठिनातयाँ, नई मशीनों की उपलब्धि में देर तथा कुशल कर्मचारियों का अभाव।

प्रथम योजना की प्रगति

इन सब कठिनाइयों के बावजूद देश ने औद्योगिक क्षेत्र में असाधारण प्रगति की। उत्पादन सूचक अंक १९४६=१०० जो १९५० में केवल १०५ था, बढ़कर १९५६ में १६१ हो गया। भिन्न-भिन्न उद्योगों में प्रगति की गति भिन्न रही। मिल द्वारा उत्पादित वस्त्र का उत्पादन योजना के निर्धारित लक्ष्य से ४० करोड़ गज से भी अधिक रहा। सिलाई की मशीन, कागज, गत्ते तथा साइकिल के क्षेत्रों में भी उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों को छूने में सफल रहा। सीमेंट का उत्पादन २०.७ लाख टन (१९५०-५१) बढ़कर ४०.६ लाख टन (१९५५-५६) हो गया। कला तथा तकनीकी उत्पादनके क्षेत्रों में भी संतोषजनक प्रगति हुई। प्रथम

शित वेतन आयोग के प्रतिवेदन में भी राजकीय उद्योगों के कर्मचारियों को सभी नागरिकों को दी जाने वाली राजनैतिक स्वाधीनता के वैध अधिकारों को न देने का समर्थन किया है। वेतन आयोग का अनुभव है कि भारत में अभी वह स्थिति नहीं पहुँची है जबकि राज्य के कर्मचारी भी राजनैतिक दल से सम्बद्ध होकर अपनी औपचारिक हैसियत से निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकें। इसलिए यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार के एक प्रवर संस्था के मत के बावजूद भी राजकीय उद्योगों का क्षेत्र इतना बढ़ाया जा रहा है, जिसके आधीन काफी लोग आ रहे हैं और इस प्रक्रिया में उनको उनके वैध राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर स्वयं लोकतंत्र में गत्यवरोध किया जा रहा है। इसके अलावा राजकीय उद्योगों के संचालन में और भी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो प्रावैधिक न होने के बावजूद भी कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करती हैं, उदाहरण के तौर पर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में कामगारों द्वारा व्यवस्था में भाग ले सकने सम्बन्धी असफलता कामगारों और व्यवस्थापक वर्ग के बीच विद्यमान मतभेद की प्रतीक हैं; हालांकि दोनों ही राष्ट्र का होने तथा फैक्टरी की मालिकी का दावा करते हैं।

(५) राजकीय उद्योगों में राजनैतिक हस्तक्षेप से कार्यक्षमता में अवरोध पैदा होता है और सार्वजनिक आचरण के स्तर में कमी होती है। फिर भी इस प्रकार के हस्तक्षेप को कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के राजकीय उद्योगों के विकास में राजनैतिक पदों को जैसे विधान मण्डलों की सदस्यता और मंत्री पद को महत्व दिया जायगा। अधिकारों एवं संरक्षण के लिए राजनैतिक जीवन को अधिक महत्वपूर्ण बनने से हमेशा सामाजिक अशांति में वृद्धि होती है, जिससे अधिक औद्योगिक उत्पादन एवं देश के हितों को हानि पहुंचती है।

राजकीय उद्योगों पर संसदीय नियंत्रण का प्रश्न सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने जटिल रूप से विद्यमान रहता है, इस विषय के एक निष्णात व्यक्ति ने इस स्थिति की व्याख्या निम्न शब्दों में की है:

"राजकीय मण्डल जितने अधिक स्वतन्त्र होंगे, उतनी ही बिना "जवाबदारी" के साथ वे अपने अधिकारों का अधिक प्रयोग करेंगे; लेकिन उक्त मण्डल जितने कम स्वतंत्र होंगे उनमें केन्द्रीयकरण तथा उद्योगशीलता के अभाव की संभावनाएं अधिक होंगी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

योजना काल में कई नए उद्योगों का भी जन्म हुआ। नए-नए प्रकार की वस्तुएं जो पहले आयात की जाती थीं, देश में ही बनने लगीं। तेल-शोध उद्योग, जहाज निर्माण का कार्य, हवाई जहाजों का कारखाना, पैंसलिन फैक्टरी, तथा डी० डी० टी० का उत्पादन देश में ही होने लगा।

सार्वजनिक क्षेत्र में सिन्द्री खाद फैक्टरी, चितरंजन रेल कारखाना तथा टेलीफोन फैक्टरी ने विशेष सफलता प्राप्त की।

विभिन्न उद्योगों की ब्यौरेवार प्रगति

उद्योग	उत्पादन का लक्ष्य	उत्पादन (१९५५-५६)
मिल का कपड़ा (करोड़ गज)	९८.२	१३८.४
हैंडलूम वस्त्र (करोड़ गज)	८६.०	६३.६
चीनी (करोड़ टन)	४०.०	७६.०
साइकिल (१०००)	४३३.०	४१६.०
इंजन	१७०.०	१७६.०
सीमेंट (लाख टन)	२१.९	१६.०

द्वितीय योजना में

प्रथम अप्रैल १९५६ को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का श्रीगणेश हुआ। इस योजना के लक्ष्यों में शीघ्र औद्योगीकरण को प्रमुख स्थान मिला। तेज आर्थिक विकास के लिये भूमि पर बढ़ रहे भार को कम नहीं किया जा सकता। इसलिये भारत ने द्वितीय योजना-काल में ऐसा औद्योगिक कार्यक्रम बनाया जो कि देश का पूंजीगत आधार सुदृढ़ बनाए, उत्पादन की क्षमता तथा तकनीकी विकास को अधिक से अधिक बढ़ावा दे तथा जिससे विनियोग बढ़े। इस उद्देश्य को पूर्ण करने में मूल-उद्योग तथा वैज्ञानिक अनुसंधान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

द्वितीय योजना काल में छोटे तथा घरेलु उद्योगों को भी महत्व दिया गया है। हमारे ग्रामों में छिपी हुई मानव-पूंजी पड़ी है, उसे छोटे तथा कुटीर उद्योगों के द्वारा रोजगार तथा बल मिलेगा।

दूसरी योजना की अवधि में देश के औद्योगिक विकास की रूपरेखा इस प्रकार निश्चित की गई :

(१) लोहे तथा इस्पात के उत्पादन को प्रथम स्थान दिया जाए, इसका मूल कारण है कि लोहे तथा इस्पात का उत्पादन देश के आर्थिक विकास का मापदंड है। रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर के इस्पाती कारखाने इसी योजना के संदेशवाहक हैं।

(२) दूसरी योमना में मूल उद्योगों, भारी उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

(३) जो उद्योग आवश्यक माल का उत्पादन करते हैं, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उदाहारणतया—सीमेंट और खाद।

(४) उद्योगों के आधुनीकरण पर भी विशेष बल दिया जाए जूट, रुई तथा चीनी की मिलों ने उत्पादन को बढ़ाने के लिये आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाए।

(५) उद्योग की पूर्ण क्षमता उपयोग में आ सके इसके लिये भी प्रयत्न किया जाए।

कठिनाइयों पर विजय

देश का आर्थिक ढाँचा सुदृढ़ करने के लिये दूसरी योजना एक महान् प्रयत्न थी। मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आईं पर देश के उत्साह तथा सतत प्रयत्नों ने उन पर विजय प्राप्त की। खाद उत्पादन की असफलताएँ, विदेशी मुद्रा का अभाव, और बढ़ती हुई कीमतों ने देश के औद्योगिक विकास की गति को काफी कम कर दिया। परन्तु फिर भी योजना के पिछले चार वर्षों में उत्पादन असाधारण गति से बढ़ा है। लोहे तथा इस्पात का उत्पादन भी काफी बढ़ा। इन क्षेत्रों में देश न केवल अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण कर सकेगा, अपितु निकट भविष्य में दूसरे देशों को निर्यात भी करने लगेगा। लोहे तथा इस्पात के क्षेत्र में देश ने असाधारण प्रगति की है। १९५७ में उत्पादन १३.४६ लाख टन रहा। १९५८ में टाटा फैक्टरी में श्रम संघर्ष के कारण उत्पादन थोड़ा कम १२.९५ लाख टन रहा। इस वर्ष देश ने इस्पात का निर्यात भी किया है। सीमेन्ट की उत्पादन क्षमता भी काफी बढ़ गई है। अखबारी कागज भी देश की बढ़ती हुई आवश्यकताएँ पूर्ण कर रहा है।

कोयले का उत्पादन १९५८-५९ में ४.४ करोड़ टन था, जबकि १९५५ में यह केवल ३.८ करोड़ टन था। द्वितीय योजना का लक्ष्य ६ करोड़ टन उत्पादन रखा गया। लोहे तथा इस्पात के कारखानों के लिये कोयले की माँग

[शेष पृष्ठ ३०६ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

महाराष्ट्र की सिंचाई योजनाएं

विवेचक

●

'सम्पदा' के गत अंक में हमने नये गुजरात राज्य की कुछ आर्थिक संभावनाओं पर विचार किया है। इन पंक्तियों में हम महाराष्ट्र को सिंचाई आदि की समस्याओं के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहते हैं।

दोनों राज्यों में महाराष्ट्र अधिक बड़ा है। उसका क्षेत्रफल १, १८, ६०३ वर्ग मील तथा जनसंख्या ३२६.८ (१९५१ के आंकड़े) लाख है। कुल राज्य ५७.९२ प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। १७.४६ प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है। केवल ४.२ प्रतिशत भूमि में सिंचाई की व्यवस्था है। महाराष्ट्र को नदियों में प्रतिवर्ष १३.५० लाख एकड़ फुट पानी बहता है। लेकिन इसका केवल ३.५ प्रतिशत सिंचाई में प्रयुक्त होता है। यह अनुमान किया जाता है कि यदि सिंचाई की सब वर्तमान योजनाएं पूर्ण हो जाएं तो १० प्रतिशत पानी का प्रयोग हो सकता है। और २३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकती है।

सिंचाई को दृष्टि से महाराष्ट्र में निम्नलिखित नदियां सिद्ध हो सकती हैं—कृष्णा (अपनी सहायक नदियों—कोयना, नीरा, मूलामुथा, भीमा, घोड़, तुकड़ी के साथ), गोदावरी, तापी, और कोंकण में पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ।

कृष्णा नदी घाटी में मुथा नहर सबसे पुरानी है और यह १६,६०० एकड़ भूमि की सिंचाई करती है। लॉयड बाँध द्वारा १७०,००० एकड़ सिंचाई होती है और २,७४,००० किलोवाट बिजली भी प्राप्त की जाती है। कोन्या पॉवर प्रोजेक्ट, जो निर्माणाधीन है २४०,००० किलोवाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा। इस प्रोजेक्ट द्वारा सतारा जिले की १६१,००० एकड़ भूमि की सिंचाई भी हो सकेगी। रत्नागिरी प्रोजेक्ट द्वारा ४,५०० किलोवाट बिजली तथा लगभग १८,००० एकड़ सिंचाई की सुविधा प्राप्त की जा सकेगी। घोड़ प्रोजेक्ट से ६०,८०० तथा वीर बांध प्रोजेक्ट से ६७,००० एकड़ की सिंचाई हो सकेगी।

गोदावरी प्रोजेक्ट, जो १९१५-१६ में तैयार हुआ था, के द्वारा ६०,००० एकड़ की सिंचाई होती है और विलसन बाँध द्वारा ८०,००० एकड़ की। गंगापुर प्रोजेक्ट को ५,५०० घनफुट जल एकत्रीकरण क्षमता को बढ़ाकर ७२.०० घनफुट करने के प्रयास से किए जा रहे हैं। मुला घाटी प्रोजेक्ट पूरा होने पर १६५,००० एकड़, पूर्णा नदी पर येलारी प्रोजेक्ट १५२,००० एकड़ और मनर प्रोजेक्ट २५,००० एकड़ सिंचाई करेंगे। विदर्भ क्षेत्र में बोन, दीना, बान तथा इरियाडोह प्रोजेक्ट १,२६,२५० एकड़ सिंचाई करेंगे। तापी घाटी में गिरिना प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता १४२,०० एकड़ की है। नालगंगा प्रोजेक्ट भी निर्माणाधीन है। इसके पूर्ण होने पर २४,५०० एकड़ भमि की सिंचाई हो सकेगी।

पहली और दूसरी योजनाओं में १६-१६ मध्यम श्रेणी के प्रोजेक्ट आरम्भ किए गए। इन ३२ प्रोजेक्टों से २,१६,००० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई सम्भव हो सकेगी। निम्न श्रेणी ३३६ प्रोजेक्ट प्रथम योजना में तथा ४५५ प्रोजेक्ट दूसरी योजना में आरम्भ किए गए। इन से क्रमशः ६४,७०० तथा ३५०,००० एकड़ अतिरिक्त सिंचाई की जा सकेगी।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सब योजनाओं के पूरी हो जाने पर महाराष्ट्र की सिंचाई समस्या एक हद तक हल हो जाएगी; किन्तु मुख्य प्रश्न तो उचित समय में पूरी होने का है। दूसरे सरकारी कामों की तरह इन योजनाओं की प्रगति भी इतनी धीमी है कि इनका पूरा होना मरीज के दम तोड़ने के बाद डॉक्टर के आने जैसा न हो जाए—यह खतरा अर्थशास्त्रियों के सामने है। ● ●

—भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने निश्चय किया है कि आगामी नवम्बर, दिसम्बर में १९५५ की भांति अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनी की जाए, यह प्रदर्शनी नई दिल्ली में उसी स्थान पर होगी जहां प्रायः प्रदर्शनियां लगा करती हैं।

—अमेरिकन सरकार ने बरौनी और अहमदाबाद के बिजलीघरों के लिए ३.६५ करोड़ का ऋण देने का निश्चय किया है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इनामी बाँड : कुछ सुझाव

ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम० काम०

इनामी बाँड के विषय में दो प्रमुख आक्षेप लगाये गये हैं। एक, कुछ आलोचकों ने इस योजना को जुआ कह कर अनुचित माना है। दूसरे, इस योजना से ऋण प्राप्त करने के अन्य स्रोतों पर प्रभाव पड़ सकता है।

पहले आक्षेप का उत्तर है – इनामी बांड योजना जुआ नहीं मानी जा सकती। जुए में यद्यपि व्यक्ति अपने धन को अतुल धन की प्राप्ति करने की आशा में अवश्य लगता है, तथापि आशा के विपरीत स्थिति में वह लगाए गए धन को भी खो बैठता है। जुआ एक अनिश्चित सौदा है। जहाँ व्यक्ति अपनी किस्मत को इस आधार पर अजमाता है कि 'लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का' इनामी बांड में ऐसी कोई चीज नहीं है। इसमें लगाया गया धन सर्वथा सुरक्षित है, जिसका भुगतान पहली अप्रैल सन् १९६५ के बाद कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः इनामी बांड को जुआ समझना एक भूल है।

लोगों की मनोवैज्ञानिक भावना को आधार बना कर इनामी बांड योजना में बड़ी-बड़ी राशि के इनामों की लाटरी द्वारा जनता से धन प्राप्त करने की एक व्यावहारिक पद्धति अपनायी गई है। इनामों की ये बड़ी-बड़ी राशियाँ, हो सकता है कि सरकार अथवा उद्योगों के लिए अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव डालें। बड़ी धन राशियों की लाटरी के लालच में बड़े-बड़े विनियोक्ता भी अपने धन का एक अच्छा विनियोग इन बांडों में कर सकते हैं और परिणामस्वरूप इसका प्रभाव सरकार और उद्योगों के लिए धन प्राप्त करने के अन्य साधनों पर पड़ना स्वाभाविक है। अतः इस संदेह को हम निराधार नहीं मान सकते। यदि ऐसा होता है तो फिर इनामी बांड योजना का वह महत्त्व नहीं रह जाता, जिसको दृष्टि में रखकर यह योजना कार्यान्वित की गई है।

हमारा उद्देश्य जनता से धन प्राप्त करने के साथ-साथ उसमें बचत की भावना को निरन्तर बनाये रखना और बढ़ाना भी है। दो योजनाओं के पूरे होने के परिणामस्वरूप समाज के, सामान्य रूप से सभी वर्गों और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग की आय में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ी हुई आय के साथ-साथ उनके खर्चों का बढ़ना भी स्वाभाविक है, लेकिन सम्पूर्ण अतिरिक्त आय का खर्च कर देना आज की विकासोन्मुख अर्थ व्यवस्था के लिए न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः मध्यम और श्रमिक वर्गों में बचत की भावना को बनाये रखने की दृष्टि को हमें इनामी बांड योजना में प्राथमिकता देनी चाहिए थी। ऐसा करने से हम इस योजना के दूसरे ऋण स्रोतों पर पड़ने वाले कुप्रभाव से भी सरलता से बच सकेंगे। आज इस योजना के अन्तर्गत लोगों में रुपया विनियोग करने का जितना उत्साह है वह उत्साह न केवल बना रहे, बल्कि उसमें बढ़ोतरी हो, साथ ही इस योजना के कारण किसी भी संस्था के लिए ऋण प्राप्त करने में किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए हम आगामी नई बांड सीरीज़ में दो चीजें आवश्यक समझते हैं। प्रथम, इनामों की संख्या बढ़ाई जाए और दूसरे इनामों पर दी जाने वाली धनराशि कम की जाए, जबकि इनामों पर कुल दिया जाने वाला धन चालू योजना में रखे गए धन के बराबर ही हो। अब हर सीरीज में इनामों की जो संख्या रखी गई हैं वह इस प्रकार हैं :

१०० रु० के बांडों की प्रत्येक सीरीज में—

१ इनाम	२५००० रु० के	२५००० रु०
२ इनाम	१०००० रु० के	२०००० रु०
५ इनाम	५००० रु० के	२५००० रु०
१२ इनाम	१००० रु० के	१२००० रु०
२० इनाम	५०१ रु० के	१०००० रु०

१ लाख बोंडों की हर सीरीज में हर तिमाही इनाम की कुल धनराशि ९२,००० रुपए।

५ रु० के बांडों की प्रत्येक सीरीज में —

१ इनाम	७,५०० रु० का	७,५०० रु०
२ इनाम	२,५०० रु० के	५,००० रु०
१० इनाम	१,००० रु० के	१०,००० रु०
२० इनाम	५०० रु० के	१०,००० रु०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

२५ इनाम	१०० रु० के	२,५०० रु०
२२० इनाम	५० रु० के	११,००० रु०

१० लाख बांडों की हर सीरीज़ में हर तिमाही इनाम की कुल धनराशि ४६,००० रुपए।

इस प्रकार १०० रु० के बांडों की प्रत्येक सीरीज में ४० इनाम और ५० रु० के बांडों की प्रत्येक सीरीज में २७८ इनाम रखे गये हैं।

हमारी सम्मत्ति में इनामों की संख्या और धनराशियाँ निम्न प्रकार रखने से हम उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति करने में अधिक सफल हो सकते हैं—

१०० रु० के बांडों की प्रत्येक सीरीज़ में—

१ इनाम	१०,००० रु० का	१०,००० रु०
२ इनाम	५,००० रु० के	१०,००० रु०
४ इनाम	२,५०० रु० के	१०,००० रु०
१० इनाम	२,००० रु० के	२०,००० रु०
२० इनाम	१,००० रु० के	२०,००० रु०
३० इनाम	५०० रु० के	१५,००० रु०
३५ इनाम	२०० रु० के	७,००० रु०

५ रु० के बांडों की प्रत्येक सीरीज में—

१ इनाम	२,५०० रु० का	२,५०० रु०
२ इनाम	१,००० रु० के	२,००० रु०
४ इनाम	५०० रु० के	२,००० रु०
८ इनाम	२५० रु० के	२,००० रु०
१०० इनाम	१०० रु० के	१०,००० रु०
१०० इनाम	५० रु० के	५,००० रु०
५०० इनाम	२५ रु० के	१२,५०० रु०
५०० इनाम	२० रु० के	१०,००० रु०

इस प्रकार १०० रु० के बांडों की प्रत्येक सीरीज में १०२ इनाम और ५ रु० के बांडों की प्रत्येक सीरीज में १,२१५ इनाम होंगे। कुल मिलाकर प्रत्येक सीरीज पर ५ वर्ष की अवधि में १०० रु० के बांडों पर १,६३८ इनाम और ५ रु० के बांडों पर कुल इनामों की संख्या २३,०८५ होगी। चालू सीरीज में पाँच वर्ष की अवधि में १०० रु० के बांडों पर ७६० इनाम और ५ रु० के बांडों पर ५,२८२ इनाम होते हैं। चालू सीरीज में १०० रु० के लगभग प्रत्येक १३२ बांडों पर एक इनाम और ५ रु० के लगभग १६० बांडों पर १ इनाम की आशा रखी जा सकती है, जबकि प्रस्तावित इनामों की योजना के अन्तर्गत १०० रु० के लगभग प्रत्येक ५१ बांडों पर १ इनाम और ५ रु० के लगभग ४३ बांडों पर १ इनाम की आशा रहेगी।

इनाम प्राप्त करने की ये अधिक संभावनायें मध्यम और श्रमिक वर्ग की जनता में अधिक बचत और अधिक विनियोग की भावनाओं को उत्साहित करेंगी। सरकारी बचत योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले धन की राशि में प्रत्येक वर्ष कुछ बढोत्तरी अवश्य हुई है, तथापि कुल मिलाकर प्राप्त धनराशि प्रस्तावित लक्ष्य से कम ही रही है।

डेढ़ महीने में ३२ करोड़ रुपये के बांडों का बिक जाना इस बात का द्योतक है कि जनता ने बांड योजना का स्वागत किया है। लेकिन इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि इन बांडों के खरीदने में अधिकांश रुपया शिक्षित वर्ग का, कुछ मध्यम श्रेणी के लोगों का और अधिकतर सम्पन्न लोगों का लग रहा है। देश में 'श्रमिक वर्ग' के अन्तर्गत आने वाले लोगों से धन प्राप्त हो सके, उनमें बचत करने की चाह हो, इसके लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है। निःसंदेह इन लोगों से प्राप्त धन राशि थोड़ी होगी, लेकिन उससे देश के अन्दर जो वातावरण पैदा होगा, वह आगामी योजनाओं के लिए धन प्राप्त करने के मार्ग को सरस बनायेगा। इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि सरकार इनामों की संख्या बढ़ाए, इनामों की धनराशियों को कम करे और निम्न तथा मध्य वर्ग को बांड प्राप्त हो सकें, कोई ऐसी सरल पद्धति अपनाये। ● ●

[पृष्ठ ३०३ का शेष]

काफी रहेगी, इसलिए प्रयत्न किया जा रहा है कि निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाए।

चीनी उद्योग ने भी योजना काल में असाधारण प्रगति की है। १९५६-५७ में चीनी का उत्पादन २०.२६ लाख टन रहा। चाय, जूट, रबर, तम्बाकू तथा अन्य उद्योगों ने भी प्रगति दर्शायी है।

देश ने द्वितीय योजना में उद्योगों के आधुनीकरण, पूर्ण क्षमता के उपयोग तथा तकनीकी कुशलता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। आशा है तीसरी योजना काल में प्रगति की यह गति और भी बढ़ेगी। ● ●

GURUKULA KANGRI LIBRARY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वस्त्र-व्यापार और व्यापारिक संघों की सेवाएँ

माधवप्रसाद कक्कड़, एम० काम०

वाणिज्य के इस युग में व्यापार का कदाचित् कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां व्यापारिक संघ काम न कर रहे हों। ये संघ प्रधानतः किसी एक वर्ग के व्यापारियों को संगठित करने और उनके सामान्य हितों की रक्षा करने के लिए स्थापित किये जाते हैं। सूती वस्त्र व्यापार के क्षेत्र में काम करनेवाले कुछ संघ तो ६०-७० वर्ष से भी अधिक पुराने हो गये हैं और वे अपनी बहुमुखी सेवाओं द्वारा इस व्यापार के अपरिहार्य अंग बन गये हैं। उदाहरणार्थ, मस्कती क्लाथ मार्केट एसोसियेशन, अहमदाबाद (स्था० १९०६), बॉम्बे पीसगुड्स मर्चेन्ट्स महाजन, बम्बई (स्था० १८८१), देहली हिन्दुस्तानी मर्केन्टाइल एसोसियेशन, देहली (स्था० १८९३), आदि, दीर्घकाल से वस्त्र व्यापार की सेवा करते चले आ रहे हैं। प्रस्तुत लेख में इनकी सेवाओं का स्पष्ट विवेचन करने का प्रयास किया गया है।

विक्रय-प्रसंविदाओं का समानीकरण

व्यापारिक लेन-देन की सफलता बहुत हद तक विक्रय-प्रसंविदाओं के सुचारू-रूप से संपादित होने पर निर्भर है। अतः यह अपेक्षित है कि प्रसंविदा में अंकित शर्तें क्रेता और विक्रेता में भेद-भाव न करें और दोनों पक्ष अपने अधिकार और दायित्वों को ठीक-ठीक समझें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक समझा गया कि सभी थोक व्यापारी मिल-मालिकों के साथ समान रूप की विक्रय-प्रसंविदाएं करें अर्थात् उन पर अंकित शर्तें और आश्वासन एक से हों। बम्बई और अहमदाबाद में क्रमशः १९२५ और १९३४ में स्थानीय मिल-मालिक संघ और थोक व्यापारी संघों ने पारस्परिक विचार विमर्श करके विक्रय प्रसंविदाओं का समानीकरण किया है और वहां के अधिकांश सौदे इन समानीकृत प्रसंविदाओं के आधार पर होते हैं। सितम्बर १९२९ में मिल-मालिकों और निर्यात-कर्ताओं के लिये एक समानीकृत प्रसंविदा बनायी गयी, जिसका श्रेय मिल-मालिक संघ बम्बई और सूती-वस्त्र निर्यात परिवर्द्धन समिति, बम्बई को है। इस प्रकार समान रूप की विक्रय-प्रसंविदाओं द्वारा वस्त्र-विक्रय का काम सरल और शांत हो गया है। सभी व्यापारी मिल-मालिकों के साथ एक ही प्रकार की शर्तों द्वारा बद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप आपसी झगड़ों का निपटारा आसानी से हो जाता है और बाजार के लेन-देन में अधिक नियमितता आ जाती है।

बाजार पद्धतियों का निर्माण

सूती वस्त्र-बाजार में प्रचलित बहुत-सी पद्धतियों और रीतियों का निर्माण वास्तव में इन व्यापारिक संघों ने ही किया है। कपड़े की प्रमुख थोक मंडियों जैसे बम्बई, अहमदाबाद, देहली आदि में साख अवधि, कटौती, छूट, दलाली, मजदूरी, व्याज-दर आदि की रीतियों के सुव्यवस्थित होने का एकमात्र श्रेय वहां के व्यापारिक संघों को है। इस सम्बन्ध में संघों में आवश्यक उपनियम बना लिये हैं, जिनका अनुसरण करना प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक है।

व्यापारिक मतभेदों के सान्त्वन और पंचायत

व्यापारियों में आपसी झगड़ों और मनमुटाव को दूर करके उनमें सौहार्द भावना जागृत करना व्यापारिक संघों का एक प्रधान कार्य है। प्रायः सभी प्रमुख संघ अपने सदस्यों के आपसी तथा सदस्यों व गैर-सदस्यों के बीच उठने वाले मतभेदों के सान्त्वन और पंचायत का समुचित प्रबंध करते हैं। उदाहरण के लिये, मस्कती और पांचकुआं एसोसिएशन, अहमदाबाद, हिन्दुस्तानी मर्केन्टाइल एसोसिएशन, दिल्ली आदि कई वर्षों से पंचायती काम बड़ी तत्परता और जिम्मेदारी के साथ करते चले आ रहे हैं। इस काम के लिए एक स्थायी उपसमिति की व्यवस्था की जाती है, जिसमें प्रबंध-कारिणी सभा के कुछ सदस्य रहते हैं। उपसमिति के अतिरिक्त कुछ संघों में पंचायत बोर्ड, ट्रिब्यूनल आदि की भी व्यवस्था होती है।

मस्कती क्लाथ मार्केट एसोसियेशन, अहमदाबाद में एक पंचायत बोर्ड की व्यवस्था है जो मिल-मालिक संघ अहमदाबाद की सदस्य मिलों और अपने सदस्य व्यापारियों

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के बीच होने वाले मतभेदों की पंचायत करता है। इस बोर्ड में ३० सदस्य मनोनीत किये जाते हैं जिनमें से १५ सदस्य मिल-मालिक संघ और १५ इस एसोसियेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रति तीन वर्ष बाद बोर्ड का पुनर्निर्माण किया जाता है। यह वस्तुतः सराहनीय है कि पंचायत बोर्ड और सहायक उपसमितियां वर्ष में लगभग १,००० मामलों का निपटारा करती हैं। ये मामले ज्यादातर सुपुर्दिगी की अस्वीकृति, भुगतान में आनाकानी, दोषयुक्त माल का भेजना, माल का नमूने या दिये गये विवरण के विपरीत होना तथा अन्य इसी प्रकार की घटनाओं से सम्बन्ध रखते हैं।

हिन्दुस्तानी मर्चेन्ट्स एण्ड कमीशन एजेन्ट्स एसोसियेशन, बम्बई के संविधान में बेंचों और अपील समितियों की नियुक्ति और कार्यों का उल्लेख मिलता है। एसोसियेशन की ६०वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में कुल १५२ मुकदमे इनके सामने रखे गये जिनमें से ५४ पर निर्णय दिया गया, ४३ दोनों पक्षों के बीच आपस में पटा दिये गये और बाकी विचाराधीन रहे। कुछ ही वर्ष हुए इस एसोसियेशन ने बॉम्बे पीसगुड्स मर्चेन्ट्स महाजन के सहयोग से संयुक्त बांधा कमेटी और संयुक्त पंचायत बोर्ड की स्थापना की है जिसका प्रधान, कार्य स्थानीय थोक व्यापारी और आढ़तियों के बीच आपसी झगड़ों का निपटारा करना है। उपर्युक्त वर्ष में इस कमेटी और बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ ४२ मुकदमें आये, जिनमें से ४ पर निर्णय दिया गया, ३५ आपस में पटा दिये गये और ३ विचाराधीन रहे।

देहली हिन्दुस्तानी मर्केन्टाइल एसोसियेशन भी इस दिशा में पीछे नहीं रहा है। सन् १९५८-५९ में इस एसोसियेशन के न्यायाधीश और ट्रिब्यूनल के समक्ष ४४६ मुकदमें और ३७ अपीलें आईं जिनमें से ३७६ मुकदमों और ३६ अपीलों पर निर्णय दिये गये। यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि दिल्ली की मंडी में यह एसोसियेशन थोक वस्त्र व्यवसाय की सबसे अधिक संगठित प्रतिनिधि-संस्था है।

इसी प्रकार अन्य केन्द्रों में भी व्यापारिक संघ अपने सदस्यों के आपसी झगड़ों को निपटाने और मुकदमों पर निष्पक्ष निर्णय देने का कार्य सफलतापूर्वक कर रहे हैं और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हाईकोर्ट भी इन संघों के निर्णयों के विरुद्ध दायर की गई अपीलों को इस आधार पर अस्वीकृत कर देते हैं कि उनके निर्णय को मानना संघ की सदस्यता की एक प्रधान शर्त है। कुछ एसोसियेशनों ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनके सद्भावी सदस्य निर्णय न मानने वाले सदस्यों अथवा गैर-सदस्यों से कोई भी व्यापारिक संबंध न रखें।

बाजार की अवांछनीय पद्धतियों को रोकना

ऊपर इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि बाजार पद्धतियों के निर्माण में व्यापारिक संघों का प्रमुख हाथ रहा है। स्वभावतः उनका यह दायित्वपूर्ण कर्त्तव्य हो जाता है कि वे सदस्य-व्यापारियों को ऐसे अवांछनीय काम करने से रोकें, जो व्यापार-समुदाय को कलंकित करते हैं और अंत में व्यापारियों की ख्याति को समाप्त करते हैं। वस्त्र व्यापार ही नहीं, प्रायः सभी प्रकार के व्यापार में सामान्यतः यह देखा गया है कि कुछ व्यापारी संकीर्णतावश अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बाजार की परम्परा को तोड़ने में नहीं हिचकिचाते और ऐसे काम कर बैठते हैं, जिनसे उनका भविष्य बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए, प्रचलित सीमा से अधिक साख देना, सट्टे द्वारा माल की कृत्रिम कमी पैदा करना, उधार पर अत्यधिक व्याज वसूल करना, राज्य करों के भुगतान को टालना, ऋणों का भुगतान न करना और इस उद्देश्य से फर्म का नाम बदल देना, ट्रेडमार्क या डिजाइन की नकल करना, आदि कुछ ऐसे काम हैं, जो व्यापार-नीति के विरुद्ध हैं। इनको रोकने के लिए व्यापारिक संघ उपनियम बनाते हैं और आदर्श व्यापार नीति का निर्देशन करते हैं। विक्रय-प्रसंविदाओं के समानीकरण और उपयुक्त पंचायत व्यवस्था ने भी इस प्रकार की अवांछनीय क्रियाओं को रोकने में काफी सहायता की है।

यद्यपि कुछ दिशाओं में विधान द्वारा भी यह प्रयत्न किया गया है कि पद्धतियाँ सुव्यवस्थित और नियंत्रित रहें, लेकिन इस काम में भी व्यापारिक संघों का सदैव सहयोग रहा है। राज्य सरकारों के शॉप एण्ड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके द्वारा दुकानों के बन्द होने और खुलने तथा कर्मचारियों के काम करने की दशाओं पर नियंत्रण लगाया गया है, व्यापारिक संघों के सहयोग से ही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कार्यान्वित हो सका है। हाल के महत्त्वपूर्ण परिवर्तन जैसे मुद्रा का दशमलवीकरण और मैट्रिक तौल प्रणाली आदि की उपादेयता को व्यापारियों तक पहुँचाने में इन्होंने काफी मदद की है।

राज कार्यों का आलोचनात्मक अध्ययन

अपने विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापारिक संघों को राजकार्यों का आलोचनात्मक अध्ययन करना पड़ता है, विशेषतः ऐसे कार्यों को जो आर्थिक क्षेत्र में किए जाते हैं और जिनका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। अपने सदस्यों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वे इन कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करते हैं। उनके हितों की रक्षा के लिए वे उपयुक्त सरकारी विभाग से लिखा-पढ़ी करते हैं और अपने स्मरण पत्र (Memorandums) भेजते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त समितियों को पूर्ण सहयोग देते हैं, उनकी प्रश्नावली के लिखित उत्तर भेजते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रतिनिधि सदस्यों के द्वारा मौखिक गवाही भी देते हैं। वास्तव में देखा जाय तो यह व्यापारिक संघों के अनवरत परिणाम हैं कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने वस्त्र व्यापार के हित में महत्त्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे सूती कपड़े की सभी श्रेणियों पर से निर्यात कर हटा देना, विदेशी चुंगी की कार्य-विधि सरल बनाना, बिक्री-कर को उत्पादन कर में मिलाना, मीडियम कपड़े पर उत्पादन-कर कम कर देना आदि।

अनुकूल जन-मत का निर्माण करना

यह सब करने के साथ साथ व्यापारिक संघों को जन-मत भी अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, उन्हें ऐसे कार्य करने होते हैं जिनसे जनता व्यापार-समुदाय की आवश्यकताओं, कठिनाइयों और उत्तरदायित्वों को समझे तथा देश के आर्थिक ढांचे में उनके सही स्थान का अनुमान कर सके। इसके लिए वे प्रेस-विज्ञापन देते हैं, व्यापारिक सम्मेलनों का आयोजन करते हैं और बड़े संघ व्यापारिक व औद्योगिक प्रदर्शिनियों की भी व्यवस्था करते हैं।

व्यापारिक सम्मेलनों में देश की आर्थिक समस्याओं पर विचार किया जाता है और सम्भाव्य सुझाव सरकार के सामने रखे जाते हैं। जहां तक वस्त्र व्यापार का सम्बन्ध है, यहां पर कुछ सम्मेलनों का उल्लेख कर देना अनुचित न होगा। सन् १९५४ में अन्तर-राज्य बिक्री कर की समस्या पर विचार करने के लिए फैडरेशन ऑफ दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार कानपुर कपड़ा कमेटी ने सितम्बर १९५५ में लायसेंस प्रथा और बिक्री-कर के कारण कपड़ा व्यापार की शोचनीय स्थिति पर विचार करने के लिए उत्तर प्रदेश वस्त्र व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें राज्य के सभी भागों से प्रतिनिधि आए थे। जुलाई १९५७ में फैडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने एक वस्त्र उद्योग और व्यापार सम्मेलन बुलाया था जो काफी सफल सिद्ध हुआ। इस सम्मेलन में विशेषतः बढ़ते हुए उत्पादन कर, कपड़े पर लागू बिक्रीकर की जटिलता, मिलों में बढ़ते हुए स्टाक आदि समस्याओं पर विचार किया गया था।

व्यापारिक व औद्योगिक प्रदर्शिनियों के आयोजन में बड़े व्यापारिक संघ और चैम्बर्स ऑफ कामर्स का विशेष हाथ रहा है। अक्टूबर १९५५ में भारत में पहली बार एक वृहत् पैमाने पर औद्योगिक मेला नई दिल्ली में हुआ था, जिसका पूर्ण आयोजन फैडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने किया था। इसी प्रकार बम्बई में दिसम्बर १९५७—जनवरी १९५८ में सम्पादित टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज़ फेयर की सफलता में मिल मालिक संघ और इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर, बम्बई, का विशेष सहयोग रहा। व्यापारिक संघों द्वारा आयोजित छोटी प्रदर्शिनियों के भी कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। मई सन् १९५० में दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्केन्टाइल एसोसिएशन ने उस समय प्रवर्तित वस्त्र नियंत्रण की त्रुटियों को जनता के समक्ष रखने के लिए एक रोचक प्रदर्शिनी का आयोजन किया था। इसमें उन्होंने कपड़ों के कुछ थानों का प्रदर्शन किया था, जो थे तो एक ही स्तर (क्वालिटी) के परन्तु उन पर टेक्सटाइल कमिश्नर के विभिन्न मूल्य अंकित थे। प्रदर्शनी का आयोजन एक दिन के लिए केन्द्रीय सचिवालय में भी किया गया था। इधर कुछ वर्षों से मद्रास

(शेष पृष्ठ ३३६ पर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्या सहकारी खेती सम्भव है ?

चन्द्रदत्त शर्मा 'इन्दु'

एक बार राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने प्रधान मंत्री को संकेत रूप में कहा था, 'भूमि के बंटवारे तथा सहकारी खेती के लिए सामाजिक कानून बनाने में सतर्कता बरतने की जरूरत है—अधिकाधिक खाद्य-उत्पादन के कार्य को कानून बनाने के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।'

राष्ट्रपति ने अपने इन थोड़े से सन्तुलित शब्दों में ही भारत की आर्थिक विकास की धारा को, जिसमें उसकी सामाजिक परम्परा की गति है, स्पष्ट कर दिया है। वास्तव में इस संकेत में संदेह भी निहित है। भारत जैसे लोकतंत्रानुगामी होने के दावेदार देश में कानून को लोकमत के ऊपर बल-पूर्वक थोपना न केवल अन्याय है, प्रत्युत यह कानून की परम्पराओं और राजनीतिक आदर्शों के लिए अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है।

यह ठीक है कि हम आज स्वतंत्र हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश इस स्वतंत्रता का विकास कलेवर मात्र में हुआ है, मस्तिष्क में नहीं। अभी हम में अपने विचारों को सन्तुलित ढंग से व्यक्त करने की आदत नहीं आ पाई है। पार्टीबाजी या चुनावबाजी के चक्कर में पड़कर कभी-कभी हम कुछ बातों को बिना समझे गलत और अपरिष्कृत ढंग से कह जाते हैं, जो न केवल हमारे लिए बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी घातक होती हैं। इसलिए ऐसा कहने में भी कोई बुराई नहीं कि हम स्वतंत्र होते हुए भी अधिनायकवाद के पास खड़े हैं। आज जीवन के हर क्षेत्र में हमारे दैनिक, सामाजिक धार्मिक कार्यों पर सरकार अपना नियन्त्रण कर लेना चाहती है। यह अव्यावहारिक होने के अतिरिक्त, लोकतंत्र की मर्यादाओं और हमारी मान्यताओं के भी विरुद्ध है। यह सब अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है लोगों में सामाजिक चेतना आने भर की देर है कि यह कल्पना का महल ढह जा सकता है। चीन का उदाहरण हमारे सामने है; जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लोह के पिंजड़े में जानबूझ कर बन्द कर देने पर भी, मानव की, स्वतंत्रता की हुंकार रुक न सकी। चीन ने इसीलिए कम्यून-स्थापना की नीति का परित्याग कर दिया, क्योंकि परिवार को, जो मानव जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों का केन्द्र है, नष्ट नहीं किया जा सकता।

सहकारी खेती के विभिन्न पहलुओं पर कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में काफी विचार-विमर्श हुआ; किन्तु फिर भी विशेषज्ञों और समाज-शास्त्रियों का उसमें मतैक्य नहीं है। कुछ दूसरे ढंग से विचारने वाले विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों का विचार है कि सहकारी खेती आज की परिस्थिति में सफल नहीं हो सकती; क्योंकि भारत का आर्थिक विकास का ढांचा निम्न स्तर का है। अधिकांश सहकारी समितियाँ ऋणग्रस्त हैं। उनकी आवश्यकता का अधिकांश राज्य बैंक द्वारा पूरा हो पाता है। इनके सदस्यों द्वारा आवश्यक पूँजी का दशांश भी कठिनता से पूरा हो पाता है, और फिर केवल प्रस्ताव पास करके मजदूरों को चंद घंटों में कुशल किसान भी हम नहीं बना सकते। हमारी योजनाओं का सबसे बड़ा दोष यही रहा है कि वे वास्तविकता को छोड़ कर कागजी घोड़ों पर अधिक दौड़ी हैं, व्यवहारिक और ठोस बातों से उनका सम्बन्ध कम ही रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि "भारत गाँवों का देश होते हुए भी नगरों के ऊँचे-ऊँचे सरकारी कार्यालयों की अलमारियों में निवास करता है।"

योजनाओं के इस लम्बे सिलसिले में हम बड़े बड़े भवनों की दीवारों को अवश्य ऊँची करते जा रहे हैं; किन्तु जिसके लिए यह कार्य हो रहे हैं, उस मानव के निर्माण की बात अभी हमारी आंखों से दूर है।

हमारा ध्यान कृषि-उत्पादन की ओर अवश्य है किन्तु खेती के मूल कारण किसान की उन्नति की ओर हम ध्यान नहीं दे पाये हैं। यही हमारी एक बुनियादी गलती है, जिसके कारण करोड़ों रुपया व्यय करने पर भी कृषि की संतोषजनक उन्नति नहीं हो पा रही। जिस प्रकार रेत के महल खड़े नहीं हो सकते उसी प्रकार बिना किसान को उचित शिक्षा दिये हम उससे आधुनिक ढंग से ठीक प्रकार खेती करने की आशा नहीं कर सकते। इसका दूसरा एक बड़ा कारण किसानों की गरीबी भी है। कृषि-उत्पादन बढ़ने पर भी ९-१० वर्षों में उसमें ३० प्रतिशत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

से अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। इसके विपरीत, जापान और इजराइल के किसानों का उदाहरण है, जहां किसानों को प्रशिक्षण देने पर उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है।

केवल सरकारी सहायता मिलने से या सहकारी मंत्र पढ़ देने से खेतों की उपज नहीं बढ़ सकती। उपज बढ़ाने के लिए अच्छे खाद, अच्छे बीज, अच्छे यंत्र और सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध होने के साथ-साथ चतुर और साहसी किसान की भी आवश्यकता है। आज गांव वाले भी यही सोचते हैं कि जब हम में आपसी मेल नहीं, ईमानदारी नहीं और भाई चारे की पुरानी भावना नहीं तो एक साथ मिलकर रोजी कमाने की बात कैसे सोची जा सकती है? इंच-इंच भर जमीन के लिए लड़ने वाले किसान और ऊँच-नीच की भावना से ओत प्रोत ग्रामीण लोग एक साथ मिलकर काम कैसे करेंगे? आज की दशा में तो सहकारी खेती के सदस्य आलसी, कामचोर ही अधिक पाये जायेंगे। जब काम ही ठीक समय पर नहीं होगा तो अच्छे उत्पादन की आशा हम कैसे कर सकेंगे? ऐसी दशा में लाभ के बदले हानि ही हमें उपहार में मिलेगी। इसी लिए सहकारी खेती को अपनाने से पहले हमें लोगों में सहकारिता की भावना को जागृत करना होगा, गांव के आर्थिक ढांचे को उठाना होगा। सहकारिता की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वह समर्थों की सहकारिता हो; अर्थात् उसमें मजदूरी पाने वाला मजदूर कोई न हो। जितने लोग भी सहकारी समिति में सम्मिलित हों, वे सब उत्पादन में में समान साझीदार हों, उन सब के लिए उसमें प्रत्यक्ष रूप से शरिरिक श्रम करना अनिवार्य हो।

सहकारी खेती तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक खेती के विकास के लिए भूमि की जोत का अधिकतम परिमाण निर्धारण न कर दिया जाय। उससे अतिरिक्त भूमि मिलेगी और उस पर सहकारी खेती आसानी से हो सकेगी। छोटे खेतों को मिलाकर छोटे किसानों को दूसरे धंधों में भी लगाया जा सकता है। चकबन्दी करते समय छोटे खेतों को संयुक्त कृषि-भूमियों में शामिल कर देना होगा। जिससे इच्छा होने पर वे भी इनमें मिल सकें तथा अन्य घरेलू धंधों में भी सहकारिता का सिद्धांत लागू हो सके।

इन सभी बातों के लिए हमें ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है, जिसमें हम बिना किसी राजनैतिक भेद-भाव के शासन के भय को भूल कर स्वच्छन्द और स्वस्थ्य विचारों को कह और सुन सकें। आज तो राजनैतिक दल-दल और राजनैतिक भेदभाव के चक्कर में पड़कर कई अच्छे विचार भी व्यर्थ की आलोचना का विषय बनकर रद्दी की टोकरी में जा पड़ते हैं। ● ●

२० जून १९६०
को
प्रकाशित हो रही है

सुभाषित रत्नमाला

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

७ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था। कई वर्ष से पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी! अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा में प्रकाशित हो रहा है—

- वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी सुविधापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं।
- श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ।
- पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियाँ, जिनके उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सकें।
- आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य।
- उपहार और पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयुक्त।

मूल्य एक प्रति १.०० रु०। 'सम्पदा' के ग्राहकों से ००.८० न० पै० प्राप्त होने पर 'बुक पोस्ट अन्डर-पोस्टल सर्टिफिकेट' द्वारा भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ग्रामों का प्रवाह नगरों की ओर

त्रिलोक सिंह

चार साल पहले आयोजन आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा देश के २१ शहरों में इस बात की पड़ताल शुरू की थी कि गांव के लोग शहरों की तरफ क्यों दौड़ते हैं ? काम धंधों में परिवर्तन, गरीबी-अमीरी, मकानों की व्यवस्था, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जा बसने और सामुदायिक सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की गई है। शहरों की आबादी मुख्य रूप से (१) मंडी या व्यापार केन्द्र होने, (२) शासन तथा संस्कृति का केन्द्र होने, (३) विदेशी व्यापार का केन्द्र होने और (४) कल-कारखानों की बहुतायत होने के कारण बढ़ती है। यानी ऐसे शहरों में लोग गांवों से काम की तलाश में आकर बसते जाते हैं। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के शहर प्रायः पहले दो कारणों से बढ़े । उद्योग धंधों के कारण बढ़ने वाले शहर अधिक पुराने नहीं हैं।

आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, बड़ौदा, भोपाल, लखनऊ या पूना के फैलने का कारण इनका शासन और संस्कृति का केन्द्र होना रहा। शुरू में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास व्यापार-वाणिज्य के कारण बढ़े पर बाद में लोगों ने यह अनुभव किया कि यहां उद्योग धंधे भी पनप सकते हैं और फिर यहां उद्योग स्थापित किये गये । जमशेदपुर और विशाखपट्टनम् में थोड़े से समय में बहुत सी पूंजी लगाई जाने से ये शहर तेजी से बढ़े। यही स्थिति मध्यप्रदेश में भिलाई, उड़ीसा में राउरकेला और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के इस्पात-कारखानों की नगरियों में और भी जल्दी होने वाली है ।

किसान की अपेक्षा महाजन या व्यापारी की दुनिया अधिक बड़ी होती है और व्यापार बढ़ाने में उसकी रुचि अधिक होती है। इसलिए व्यापार-वाणिज्य के केन्द्र बनने पर सबसे पहले देहातों के महाजन आदि ही व्यापार में हाथ डालने के लिए छोटे शहरों में आकर बसे। १९वीं शताब्दी में भारतीय पूंजीवाद का इसी तरह विस्तार हुआ।

इसके बाद ज्यों-ज्यों शिक्षा की सुविधाएं बढ़ीं त्यों-त्यों नौकरी और दूसरे पेशे तथा मध्यम वर्ग के लोगों ने गांव छोड़ने शुरू किये। गांव में अपढ़ देहाती केवल मेहनत ही कर सकता है, जबकि शहर में कारीगर या स्कूल से निकले विद्यार्थी को काम मिलने की अधिक गुंजाइश है।

१९४७ में देश-विभाजन की मुसीबत के कारण कहीं-कहीं जो आबादी बढ़ी, वह दूसरी बात है। इससे तो अर्थ-व्यवस्था पर और भी बोझ पड़ा ।

छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर

प्रायः गांवों के लोगों के शहरों में जा बसने की ही बात की जाती है; लेकिन काफी आबादी गांवों से छोटे शहरों या कस्बों में और कस्बों से बड़े शहरों में जाती रहती है।

शहरों के बारे में पड़ताल करने से पता चला कि वहां मकानों और दूसरी चीजों की सुविधाएं भी सस्ती हैं, जितने लोग शहरों में आते हैं, उनके लिए वहां पूरा रोजगार भी नहीं मिल सकता, फिर भी गांवों और छोटे शहरों के लोग शहरों और बड़े शहरों की ओर भागते हैं। शहरों की यह अर्थ-व्यवस्था एक ओर देहातों की गरीबी की परिचायक है और दूसरी ओर समूचे देश की अविकसित अर्थ-व्यवस्था की। शिकायत की जाती है कि यदि यही रफ्तार रही तो गांवों में पढ़े-लिखे लोग देखने को नहीं मिलेंगे। फिर कौन वहां का नेतृत्व करेगा ?

पुरानी व्यवस्था छिन-भिन्न

गांवों की अर्थ-व्यवस्था सदियों से एक प्रकार से पूर्ण रही है। इसमें हरेक ने अपने कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां स्वीकार कर रखी थी। लेकिन अब इस व्यवस्था पर नये-नये प्रभाव पड़कर इसे छिन्न-भिन्न कर रहे हैं। पुराने जोड़ने वाले सूत्र कमजोर पड़ गये हैं और बाहरी प्रभाव प्रबल होते जा रहे हैं। यूँ तो सारे किसानों पर किन्तु उनसे भी अधिक भूमिहीन वर्ग पर, आबादी के बढ़ने का बहुत बुरा असर पड़ा है। देहातों में शिक्षित, कारीगर और महत्वकांक्षी लोगों के लिए आगे बढ़ने के उचित

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अवसर का बिलकुल अभाव है। आर्थिक विकास और उद्योग धंधों के बढ़ने से गांव और शहर वालों की आमदनी, रहन-सहन और रोजगार का अन्तर बढ़ना भी स्वाभाविक है। भारत की विकास योजनाओं में ग्राम-विकास की ओर खास ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ग्राम जीवन के पुनरुद्धार के लिए खेती के अलावा और बहुत सी चीजों को भी गांवों में बढ़ाना होगा। सहकारी ढंग की और विविधतापूर्ण अर्थ-व्यवस्था ही गांवों की बेरोजगारी और अन्य समस्याओं को हल कर सकती है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि आजकल जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, उन से गांवों की अर्थ-व्यवस्था शहरों की अर्थ व्यवस्था के समान तेजी से नहीं सुधर सकती।

कल्याणकारी शासन

जनसाधारण के लिए लोक कल्याणकारी शासन तभी होगा जब शहर और गांव की भी भलाई होती दिखाई दे। शहरों में कई बेमेल वर्गों के लोग रहते हैं। ये मिलकर कोई काम नहीं कर सकते। इनमें से बहुत बड़ी संख्या, ७५ प्रतिशत तक, नौकरी-पेशा होते हैं। इसलिए ये स्वास्थ्य शिक्षा, मकानों, पानी आदि के लिए शहरों के शासन पर निर्भर रहते हैं; लेकिन आज कोई भी शहर अपने सब निवासियों की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता।

पूना में १९५७ में जो पड़ताल कराई गयी थी, उससे पता चला कि वहां जिन परिवारों से पूछताछ की गई, उनमें से ६५ प्रतिशत गरीबों की श्रेणी में आते हैं। १९५४ में यह संख्या ७० प्रतिशत थी। निराश्रित लोगों की संख्या १९३७ में १५ प्रतिशत थी जो १९५४ में बढ़कर २५ प्रतिशत हो गई।

समाज में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय और एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना स्वाभाविक है। यदि हम इस परिवर्तन को समाज के लिए उपयोगी नहीं बना सके तो निस्संदेह इससे समाज में संघर्ष और असंतुलन और बढ़ेगा। विशेष प्रयत्नों के अभाव में गांवों और शहरों के हितों में अंतर बढ़ता जाएगा और इसी खींचतान से सारे देश की उन्नति में बाधा पड़ेगी। इस बिगाड़ से दोनों की आय, रोजगार, शिक्षा तथा दूसरी चीजों में तो अंतर बढ़ेगा ही, तैयार माल और खेती की उपज मूल्य नीति पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा।

विश्वसनीय
बैंक

संपूर्ण भारत में फैली हुई ३८० से अधिक शाखाएँ और संपूर्ण संसार में सुचारू रूप से संचालित ओवरसीज़ एजेन्सियां।

कार्यगत कोष १७६ करोड़ रुपये से अधिक
जमा धनराशि १४१ करोड़ रुपये से अधिक

दि
पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड
स्थापित सन् १८९५ ई०
प्रधान कार्यालय : नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन सब समस्याओं को देखते हुए हमें निम्नलिखित बातों का ख्याल रखना होगा :

● हर शहर में आवश्यक सेवाओं की ही नहीं, भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखकर विकास की योजना बनाई जाए। इसमें वर्षों आगे की जनसंख्या के लिए भी उद्योगों, शिक्षा, मकानों तथा अन्य सेवाओं की व्यवस्था की जाए।

● छोटे शहरों का भी विकास किया जाए ताकि वहां के लोग बड़े शहरों में न जाएं। आजकल की तरह योजनाएं कठोर न होकर स्थानीय समस्याओं को अधिकाधिक ख्याल में रखकर बनाई जाएं। स्थानीय सामग्री और वहीं के लोगों के प्रयत्न से योजना पर अमल कराया जाए।

● बड़े उद्योगों की योजना करने में छोटे उद्योगों को, और अधिक से अधिक सहकारी ढंग से स्थापित करने का यत्न किया जाए। कम उन्नत देशों में बड़े उद्योगों के पूरक रूप में छोटे उद्योग स्थापित करने से अधिक लोगों को काम मिल सकता है और छोटे शहरों और गांव को भी इसका लाभ मिल सकता है।

● शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की मिली-जुली योजना से जहां गांवों के लोग शहर में जाएंगे, वहां पढ़े-लिखे लोग, अध्यापक और शिल्पी आदि उद्योगों को चलाने तथा पढ़ाने आदि के लिए शहरों से गांवों में भी जाएंगे।

इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इन्हें अमल में लाया जाए तो नगरों में निरंतर बढ़ती आबादी की समस्या तो हल हो जाए; हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति भी तीव्र हो सके। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सुदृढ़ होने का यह प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपने ग्रामों को खुशहाल नहीं बना लेते, तब तक विश्व में हमारी प्रतिष्ठा होना न होना कोई अर्थ नहीं रखता।

● ●

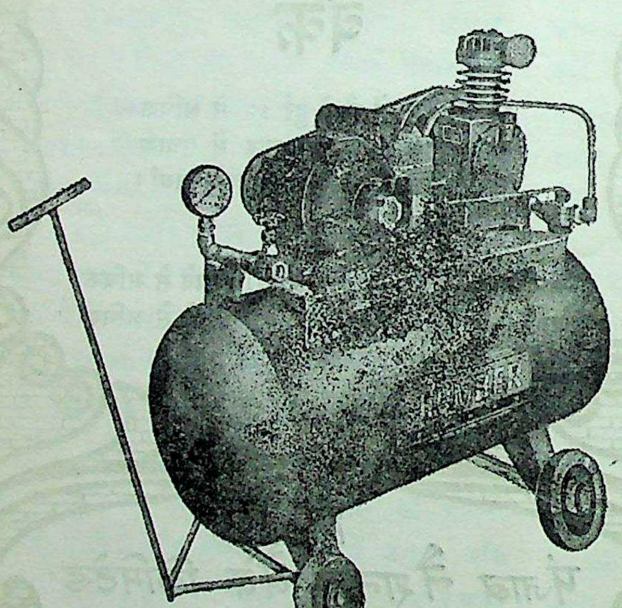

★ एयर कम्प्रेसर्स
★ स्प्रे पेंटिंग के साधन
★ कार वाशर
★ वैक्युम पम्प

डीडवानिया ब्रादर्स (प्रा.) लि.

कश्मीरी गेट, दिल्ली-६।

टेलीफोन : २३८१८

टेलीग्राम : डीडवानिया

GURUKULA KANGRI LIBRARY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ह मा रे उ द्यो ग

भारी मात्रा में लौह उत्पादन

भारत सरकार ने प्रतिवर्ष २,४३,७०० टन लौह-मेंगनीज बनाने के लाइसेंस दिये हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष १,६०,००० टन लौह-मेंगनीज बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से १९६०-६१ तक ६० हजार टन की देश में ही खपत होने का और १ लाख का निर्यात होने का अनुमान था। अभी तक ६ कारखाने स्थापित हो चुके हैं, जहां कुल ९३ हजार टन लौह-मेंगनीज बन सकता है। इनमें से ५ ने अपना उत्पादन शुरू भी कर दिया है। आशा है दूसरी योजना के अन्त तक २ और कारखाने खुल जाएंगे तथा २ का उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रतिवर्ष १,४०,-००० टन लौह-मेंगनीज और बनने लगेगा। अनुमान है कि आजकल देश में लगभग ३५,००० टन लौह-मेंगनीज की खपत है। जब ६० लाख टन इस्पात के पिंड बनाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब देश में ६०,००० टन लौह-मेंगनीज खपने लगेगा।

वैज्ञानिक यंत्रों का निर्माण

दूसरी योजना के शुरू से अब देश में तिगुने वैज्ञानिक यंत्र बनने लगे हैं।

१९५६ में देश में बने यंत्रों की कीमत ६३ लाख रु० थी, जबकि पिछले साल २ करोड़ रु० के यंत्र बने। देश में एक्स-रे की मशीनें भी शीघ्र ही बनने लगेंगी। सरकार ने प्रतिवर्ष ९० लाख रु० के एक्स-रे की मशीनें बनाने वाली तीन योजनाएं स्वीकार की हैं। दो फर्मों ने बाक्स-कैमरे बनाने शुरू कर दिये हैं। प्रतिवर्ष १२,००० कैमरे बनाने की क्षमता वाली एक भारतीय फर्म में भी पिछले साल के अंत में कैमरे बनने लगे थे। दूसरी फर्म पश्चिम जर्मन के सहयोग से बाक्स-कैमरे बना रही है।

महाराष्ट्र में अखबारी कागज की मिलें

नये महाराष्ट्र की स्थापना के साथ ही उसे उद्योग समृद्ध बनाने का विचार जोर पकड़ने लगा है। महाराष्ट्र प्रदेश में अखबारी कागज की मिलें बनाने की दो योजनाएं बन रही हैं। एक योजना के पुरस्कर्ता श्री शांतिप्रसाद जैन हैं। वे कोयना के बिजली क्षेत्र में अपना कारखाना खोलने का विचार कर रहे हैं। दूसरी योजना बिरला ब्रदर्स की है, जो कोल्हापुर क्षेत्र में मिल खड़ी करने का विचार कर रही है। बहुत संभवतः केन्द्रीय सरकार से इन दोनों को लाइसेंस मिल चुके हैं। संभवतः प्रारम्भ में दोनों मिलों को प्रिंटिंग पेपर, जिसमें लाभ की कुछ अधिक संभावना है, एक अनुपात में बनाने की अनुमति दी गई है। इन दोनों कारखानों की उत्पादन क्षमता १०० टन दैनिक होगी। इन योजनाओं के अलावा भारत सरकार आंध्र में भी एक मिल खोलने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रही है।

चीनी के उत्पादन में वृद्धि

इस साल ७ मई, १९६० तक देश में कुल २३ लाख ५० हजार टन चीनी बनायी गयी। इस प्रकार पिछले साल के इस अवधि के उत्पादन (१८.८८ लाख टन) से ४ लाख ६२ हजार टन चीनी अधिक बनी। पिछले पूरे साल में कुल १९ लाख १९ हजार टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

(१) उत्तरप्रदेश और बिहार में कारखाने पहले चालू करने पर ३१ नये पैसे प्रतिमन के हिसाब से रियायत दी गयी। (२) पिछले दो मौसमों के औसत उत्पादन से अधिक चीनी बनाने पर उत्पादन शुल्क में ५० प्रतिशत छूट दी गयी। (३) गन्ने की न्यूनतम कीमत बढ़ायी गयी।

सूती कपड़े का उत्पादन और निर्यात

• अनुमान है कि फरवरी, १९६० में देश की सूती कपड़ा मिलों में १३ करोड़ ८० लाख पौंड सूत और ४० करोड़ २० लाख गज कपड़ा बना।

• सन् १९५९ में भारत से ६१ करोड़ रु० के सूती कपड़े का निर्यात हुआ, जबकि १९५८ में इससे २५ करोड़ रु० कम का निर्यात हुआ था।

• जनवरी-नवम्बर, १९५९ में लगभग १७२ करोड़ ६० लाख हथकरघे का कपड़ा बना जबकि १९५८ की इसी अवधि में १६४ करोड़ २० लाख का कपड़ा बना था।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● जनवरी-नवम्बर, १९६९ में मिलों में बने और हथकरघे के कुल ७३ करोड़ ३० लाख गज कपड़े का निर्यात हुआ। १९५८ की इसी अवधि में ५६ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा निर्यात हुआ था।

● सूती कपड़े का निर्यात मुख्यतः इंग्लैंड, अदन, सऊदी अरब, लंका, बर्मा, सिंगापुर, इन्दोनेशिया, नाइजीरिया, केन्या, सूडान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका को हुआ।

सूती मिलों के श्रमिकों की वेतन वृद्धि

बम्बई और अहमदाबाद के मिल मालिकों ने सूती मिलों के वेतनों के संबंध में वेतन वृद्धि सिफारिशों को स्वीकार करके प्रशंसनीय कदम उठाया है। इसके अनुसार मजदूरों के वेतन रुपए ८.०० प्रति मास बढ़ेंगे। इन दोनों निर्णयों का असर दोनों शहरों के ३ लाख २१ हजार मजदूरों पर पड़ेगा। बम्बई की मिलों में १.२५ करोड़ और अहमदाबाद की मिलों को १ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अधिक वेतन देना पड़ेगा। लेकिन इस निर्णय से उन्होंने सद्भावना के जिस वातावरण की सृष्टि की है उसका मूल्य कहीं अधिक है। पूंजी और श्रम किसी उद्योग के दो पहिये होते हैं। इन दोनों में सद्भाव की स्थापना अनिवार्य है। हमें आशा करनी चाहिए कि वेतन मंडल की इच्छा के अनुरूप दोनों पक्ष उद्योग के विकास में रुचि लेंगे और आगामी ५ वर्षों तक श्रम नई माँगें पेश नहीं करेगा। संचालक भी श्रम के साथ सद्व्यवहार करेंगे।

—१९६०-६१ में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पैट्रोलियम की खोज के लिए २,८५६ वर्गमील इलाके की पड़ताल करेगा। ये इलाके पंजाब, आसाम, खम्भात और कच्छ में हैं। उन्हीं इलाकों की पड़ताल की जाती है, जिन्हें भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से पैट्रोलियम मिलने योग्य समझा जाता है।

भारत व्यापार पत्रिका

❀ काशी विशेषांक और प्लास्टिक्स उद्योग विशेषांक दिये जा चुके हैं तथा एक और विशेषांक देने की योजना है।

❀ चित्रों तथा उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी लेख-कहानियों के अलावा आपका भविष्य, विदेश-व्यापार समाचार, आयात-निर्यात समाचार, बैंकिंग तथा बीमा व्यवसाय, मंजिल के पत्थर, क्या आप जानते हैं, चलचित्र उद्योग, कृषि उत्पादन, वित्त मुद्रा और कर, सर्राफा बाजार की हलचल, सम्पादक की डाक, गंगा की लहरें, सुझाव और शिकायतें, आदि अनेक स्थायी स्तम्भ हैं।

❀ सामयिक कार्टून तथा सम्पादकीय पत्रिका की विशेषता हैं।

आज ही आठ रुपये भेजकर वार्षिक ग्राहक बनें : विज्ञापन दर तथा अन्य जानकारी के लिये लिखें।

एक प्रति का मूल्य : ७५ नये पैसे

भारत व्यापार पत्रिका

उद्योग व्यापार का सचित्र मासिक

पोस्ट बाक्स नं० ४९, वाराणसी

'नर-नारी' का किशोर अंक

(काम और मनोविज्ञान संबंधी मासिक)

सम्पादक—श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए०
श्री वीरेन्द्र वात्सायन

सेक्स अथवा प्रजनन संबंधी बच्चों के प्रश्नों का सही उत्तर देना उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बड़ा जरूरी समझा जाता है; लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में अधिकांश माता-पिता नहीं जानते कि वे बिना शर्म किस तरह अपने बच्चों को यह सब समझाएं। कई बार तो उन्हें बहुत-सी बातें स्वयं मालूम नहीं होतीं।

आप निःसंकोच होकर अपने किशोर वय के बालक-बालिकाओं के हाथ में यह अंक दे सकते हैं। उन्हें जितना और जो-जो काम विषयक ज्ञान होना चाहिए, प्रायः वह सभी इसके अन्दर आ गया है। झूठी लज्जा के कारण सेक्स पर डाले गये अवांछित और अकल्याणकारी पर्दे को हटाकर, सत्य को समझकर, अपने जीवन को सुचारु रूप से व्यवस्थित करने में यह उनका एक सच्चा पथ-प्रदर्शक साबित होगा। मूल्य एक प्रति—७५ नये पैसे। वार्षिक ८.०० रुपये मात्र।

नर-नारी प्रकाशन, पटना-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न या नि र्मा ण

चतुर्भुज का गाँव

संसार की खारे पानी की बड़ी झीलों में सबसे अधिक प्रसिद्ध सांभर झील से कोई दो मील दूर तेयद गांव के किनारे एक ऊबड़-खाबड़ खेत है। १५ बीघे के इस खेत की जमीन के तल में कोई २० फीट का अन्तर था। खेत का एक किनारा टीलों से ढका था, जो बीच में एक प्राकृतिक झील सी बन रही थी। इधर रेतीले प्रदेश में प्रायः ऐसी जमीनें मिलती हैं, जिनमें बरसात में कभी कुछ बाजरा और मोठ मूंग हो गया तो ठीक, नहीं तो जिन्हें सामान्यतः बरसाती या बंजड कहा जाता है। लेकिन इस खेत पर चार पांच किसान खलिहान में गेहूँ और जौ की अच्छी खासी फसल काट कर बरसा रहे थे, जिनमें से एक अंग्रेजी में उत्तर देने वाला युवक भी था।

युवक चतुर्भुज १९५३ में मैट्रिक पास कर अन्य पढ़े-लिखे युवकों की भांति आजीविका के लिए स्वभावतः शहरों की ओर आकर्षित हुआ था। भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से चलकर लगभग दो हजार मील की यात्रा तय कर वह ठेठ पूर्व में आसाम के किसी नगर में पहुँचा। इधर के लोग प्रायः नौकरी की तलाश में बंगाल और आसाम राज्यों का ही आश्रय लिया करते हैं। वहाँ एक साबुन के कारखाने में उसे काम भी मिल गया। युवक परिश्रमी था और परिश्रमी एवं ईमानदारी से कौन मालिक खुश नहीं हो सकता। चतुर्भुज का मालिक भी उससे खुश था। लेकिन ६ महीने तक अथक काम करने के बाद एक रात उसके सामने जीवन का रहस्य खुला कि यदि वह अपने खेत पर इतनी मेहनत और लगन से काम करे, तो क्या उसे इतना पैसा नहीं मिल सकता ?

चतुर्भुज जीवन का रहस्य जानकर उल्टे अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने दो भाइयों की मदद से उसने अपनी जमीन को संभाला और आज परिश्रम का पूरा फल प्राप्त कर वह संतुष्ट है।

"हाँ, जमीन यह अवश्य खराब थी। बरसात में तो प्रायः प्रतिवर्ष इसमें नाले पड़ जाते थे। जमीन जगह जगह से कट जाती थी और जब हमने इस पर काम शुरू किया तो गांव वालों ने हमारा उपहास भी किया था—पर यह सब मेढ़बंदी का परिणाम है—उसने ३ बीघा के एक प्लाट पर सब्जियों क्यारियों की ओर इशारा करते हुए गरिमा भरी नजरों से मेरी ओर देखा—मेरे मुंह पर जिज्ञासा के भाव पढ़कर एक क्षण बाद वह फिर बोला, बीच में जो आड़ी दीवारें नजर आ रही हैं न, तीन-तीन बीघा जमीन पर यह दीवारें खड़ी हैं हम इस जमीन का तल बहुत कुछ बदल चुके हैं। बरसात में टीलों पर से जो मिट्टी बहती थी—वह इन दीवारों के सहारे आकर रुक जाती है और इस प्रकार से टुकड़े अब काफी समतल से हो गये हैं। भूमि का कटाव रुक गया है और उसकी उपजाऊ शक्ति में भी वृद्धि हुई है।"

अब उन्होंने कुएं पर रहट भी लगा लिया है। जिससे श्रम के अतिरिक्त १०० रुपये महीने की बचत उनको हो गयी है और उस बचे हुए श्रम से वे और दूसरी फसलें पैदा करते हैं। पढ़ा लिखा होने के कारण चतुर्भुज खेती के नए और उन्नत तरीकों को शीघ्र अपना लेता है और उसके खेत की पैदावार देखकर गाँव वाले भी उसका अनुसरण करते हैं।

तेयद गाँव में आज इसी कारण कहीं खाद की रूड़ी दिखाई नहीं देती। सारा खाद गड्ढों में बनता है। मेढ़बंदी केवल नारा नहीं, गाँव के किसानों का नियमित कर्तव्य बन गया है और किसी समय कठिनाई से एक फसल पैदा करने वाले तेयद गाँव के किसान अपने श्रम से तीन-तीन फसलें पैदा कर रहे हैं।

भाखड़ा की प्रगति

भाखड़ा बाँध अब १ मई, १९६० को अपनी सबसे गहरी नींव से ५३४ फुट की ऊंचाई तक बन गया है और इसके बायीं तरफ के बिजलीघर में

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन बीजों से कैसी अच्छी फसल पैदा होगी !

और लो, फसल तैयार हो गई।

६० हजार किलोवाट के यंत्र के अक्टूबर, -१९६० चालू हो जाने की सम्भावना है। इसके टर्बाइन जेनरेटर, ट्रांसफार्मर तथा बिजली का वर्कशाप करीब करीब पूरे हो चुके हैं और १९६१ में ये काम करने लगेंगे। कोटला और गंगुवाल बिजलीघरों के तीसरे बिजली बनाने वाले यंत्र भी जनवरी-अप्रैल, १९६१ में तैयार हो जाएंगे। भाकड़ा और नंगल के बिजलीघरों की क्षमता अप्रैल, १९६१ में ९० हजार किलोवाट से बढ़कर ६ लाख ४ हजार किलोवाट की हो जाएगी।

पंजाब और राजस्थान में बिजली की लाइनें अधिकांश तैयार हो चुकी हैं। ६६ के० वी० की ६ मील लम्बी बिजली की लाइनें पंजाब में लग चुकी हैं और करीब १५० मील लम्बी राजस्थान में। इसके अलावा चार छोटे बिजलीघर भी बनकर करीब करीब तैयार हो चुके हैं। इनमें से दो पंजाब के सोलन और शिमला में हैं और दो राजस्थान के रतनगढ़ और बीकानेर में बन रहे हैं।

भारत में सहकारिता के बढ़ते पग

भारत में लगभग ५५ वर्ष पहले सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश आरंभ हुआ। देश में १९५७-५८ के अंत में सहकारी समितियों की संख्या २ लाख ३७ हजार थी। इनके दो करोड़ १० लाख सदस्य थे। इनकी हिस्सा-पूंजी और रक्षित राशि १८७ करोड़ रु० तथा चालू पूंजी ६९६ करोड़ रु० थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण खेती के लिए ऋण देने वाली सहकारी समितियाँ थीं, जिनकी संख्या १ लाख ६८ हजार या ६४.९ प्रतिशत थी। ये २ लाख ६९ हजार गांवों में फैली थी। अन्य समितियों में अधिक संख्या बुनकर तथा औद्योगिक सहकारी समितियों की क्रमशः ९,६०८ और १०,११७ थी। इसके बाद गन्ना सप्लाई समितियों का नम्बर आता है, जो खास तौर से उत्तरप्रदेश और बिहार में काम कर रही हैं।

कृषि-ऋण समितियाँ दो प्रकार की होती हैं।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

थोड़े या मध्यम समय के लिए और लम्बी मियाद के लिए कर्ज देती हैं। थोड़े या मध्यम मीयाद का ऋण गांव की प्राथमिक सहकारी समितियाँ देती हैं। वे जल, उर्वरक, और खेती के अन्य सामान भी उधार देती हैं। १६ प्रतिशत ग्रामीण परिवार या १ करोड़ २ लाख लोग इन समितियों के सदस्य हैं।

प्राथमिक समितियों की अपनी पूंजी और जमा पूंजी से सदस्यों की माँग पूरी नहीं होती। अतः उन्हें केन्द्रीय सहकारी बैंकों से ऋण लेना पड़ता है! केन्द्रीय सहकारी समितियों के संघ होते हैं और इनका नियंत्रण और प्रबन्ध ये समितियाँ करती हैं। १९५७-५८ के अंत में ४१८ केन्द्रीय सहकारी बैंक काम कर रहे थे। इनकी चुकता हिस्सा पूंजी और रक्षित राशि २४ करोड़ ९१ लाख रु० थी। इनके पास ६६ करोड़ रु० जमा कराया था। इन बैंकों ने राज्य-सहकारी-बैंकों और दूसरे बैंकों से ४९ करोड़ ८० लाख रु० कर्ज लिया। राज्य-सहकारी-बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायता देता है। इस बैंक का नियंत्रण और स्वामित्व अधिकांश में केन्द्रीय

> **लोक नर्तकों से हमें लोक-नृत्यों का उल्लास मिलता है और यह शिक्षा मिलती है कि जीवन का आनन्द भौतिक पदार्थों की उपलब्धि में ही नहीं है; वह उससे कहीं अधिक गहरी और प्रकृति के साथ एक रस होने पर कहीं अधिक व्यापक चीज है।**
>
> —जवाहरलाल नेहरू

बैंकों के हाथ में होता होता है।

राज्य सहकारी बैंकों की चुकता पूंजी ११ करोड़ ९२ हजार रु० थी। इनमें ४४ करोड़ ४४ लाख रु० जमा था और इन्होंने ५१ करोड़ ६६ लाख रु० ऋण प्राप्त किया था। राज्य-सहकारी-बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण देता है। रिजर्व बैंक राज्य-सहकारी-संस्थाओं को रियायती दर पर बैंक दर से २ प्रतिशत कम का ऋण देता है। १९५८-५९ में रिजर्व बैंक ने इस प्रकार ७० करोड़ रु० ऋण दिया।

सहकारी-भूमि-बंधक बैंक लम्बी मियाद के लिए कर्ज देते हैं। १९५७-५८ में १७ भूमि बंधक बैंक थे, जिन्होंने ४ करोड़ ९२ लाख रु० कर्ज दिये। ● ●

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनीतिक अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिकअली

सम्पादक : श्री सुनील गुह

★ हिन्दी में अनूठा प्रयास

★ आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख

★ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

सबसे सस्ता और सुन्दर सचित्र मासिक

जागृति

संस्थापित १९४८

जिसे राष्ट्र भाषा के प्रायः सभी प्रमुख लेखकों, कवियों और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है। चार कहानियां, एक एकांकी, ६ लेख

तिरंगा आवरण अनेकों इक रंगे चित्र

५२ से ६४ पृष्ठ की सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर

इस पर भी मूल्य केवल २५ नए पैसे

एजेन्टों को ५ से १०० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें :

व्यवस्थापक, 'जागृति' कार्यालय, लोक सम्पर्क विभाग, पंजाब, चंडीगढ़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सर्वोदय पृष्ठ

ताड़-गुड़ उद्योग को बढ़ाया जाए

गुड़ और चीनी की माँग देशमें बराबर बढ़ती जा रही है और इसे पूरा करने के लिए गुड़ के सभी साधनों का उपयोग जरूरी है। दूसरे, जिस उपजाऊ भूमि में आजकल गन्ना बोया जाता है, उसकी हमें अनाज उपजाने के लिए जरूरत है, जबकि विभिन्न किस्म के खजूर और ताड़ के पेड़ अधिकतर ऊसर भूमि पर उग सकते हैं। इसलिए हमें मौजूदा पेड़ों का अधिक से अधिक उपयोग ही नहीं करना है, बल्कि योजना के अनुसार बंजर भूमि पर, खासकर नहरों, रेलों, सड़कों और खेतों के किनारों पर फालतू भूमि में ताड़ के पेड़ लगाने के कार्यक्रम को भी हाथ में लेना है। रेलों, सड़कों आदि के किनारे इतनी अधिक भूमि को बेकार देख मुझे दुःख होता है, किन्तु मैंने सुना है कि इस भूमि को काम में लाने की योजनाओं पर अब विचार हो रहा है।

मैंने जापान में रेलों और सड़कों के साथ-साथ लहलहाती फसलों को देखा है। रेल की लाइन के दोनों तरफ करीब दो फुट के फासले पर ही वहाँ खेती शुरू हो जाती है। जब हमारे देश में भूमि पर इतना दबाव है, तो हमें भी इस फालतू भूमि का पूरा उपयोग करना चाहिए, अच्छी भूमि में अनाज पैदा करना चाहिए और बंजर भूमि में ताड़ के पेड़ लगाने चाहिएं। इस समय करीब चालीस लाख एकड़ उपजाऊ भूमि में, हमारे देश में गन्ना बोया जाता है। अगर इसमें से कुछ भूमि भी गन्ने की खेती से छुड़ाकर अनाज पैदा करने के काम में लाई जा सके, तो खाद्य की समस्या को हल करने की दिशा में यह एक ठोस कदम होगा।

इस समय हमारे देश में बीस लाख से कम ताड़-छेदक हैं, जबकि हमें इससे दुगने से भी अधिक की आवश्यकता है। देश के विभिन्न भागों में खासकर पश्चिमी बंगाल और बम्बई राज्यों में इन छेदकों और नीरा से गुड़ तथा चीनी बनाने वालों के लिए ट्रेनिंग का प्रबन्ध किया गया है और इसके लिए केन्द्र खोले गये हैं। इस उद्योग के कारण रोजगार का एक बड़ा साधन हमारे हाथ लगा है। ग्रामीण भाई दिन भर काम करके या अपना फालतू समय लगाकर नीरा निकालने और उससे गुड़ और चीनी बनाने से अच्छा रोजगार पा सकते हैं।

मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि यदि बिहार में पाए जानेवाले ताड़ और खजूर के सब पेड़ों को छेदा जाय तो उनसे प्राप्त नीरा से हम इतना गुड़ और चीनी बना सकते हैं कि जितनी, बिहार के सब चीनी के कारखाने मिलकर बनाते हैं।

यद्यपि यह देखकर कि मौजूदा ताड़-वृक्षों में अभी भी करोड़ों वृक्ष ऐसे हैं जो कभी छेदे नहीं गए, उत्साह कुछ भंग होता है; फिर भी मैं बंजर और पथरीली भूमि में अधिक से अधिक ताड़ और खजूर के पेड़ लगाने के कार्यक्रम को हाथ में लेने पर जोर देना चाहता हूँ। ये पेड़ आसानी से लगाए जा सकते हैं और इनकी देखरेख और भी सरल है। —डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

मेरे सपनों की आर्थिक व्यवस्था

मैं एक स्वपूरित आर्थिक व्यवस्था की कल्पना करता हूँ, जिसमें समाज की आर्थिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित होगी। असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका ध्येय नहीं होगा। इस आर्थिक व्यवस्था में ऐसे प्राकृतिक साधनों का उपयोग, जो उपयोग करने से समाप्त होते हैं, भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान रखकर किया जाएगा। अन्न, वस्त्र, मकान और दूसरी आवश्यकताओं के बारे में प्रारंभिक स्थानीय समाज स्वावलम्बी होगा। प्रत्येक को काम देना भी इस समाज का जिम्मा होगा। हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, स्वावलम्बन का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। योजना बनाने का काम गाँवों से शुरू होकर ऊपर की ओर जाएगा।

आर्थिक असमानता कम से कम होगी और शरीर श्रम करने वाले का केन्द्रीय महत्व होगा। काम ऐसा होगा जो व्यक्ति की शक्तियों को विकसित करे और अतिविशेषीकरण नहीं होगा। व्यक्ति कृषि और उद्योग दोनों में ही थोड़े थोड़े समय काम कर सकेगा।

प्रावैधिकता ऐसी होगी जो मानवीय सीमाओं के बाहर न जाए। अर्थात् बहुत बड़े-बड़े उद्योगों को आज से कहीं कम स्थान मिलेगा। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में ऐसी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संस्थाओं की प्रधानता होगी, जहाँ काम करने वाले ही स्वयं मालिक हैं। कुछ संस्थाएं व्यक्तिगत स्वामित्व में भी हो सकती हैं, जहाँ मजदूरों से भी काम लिया जायगा। बड़े-बड़े उद्योग सहकारिता के आधार पर या सामूहिकता के आधार पर या व्यक्तिगत साहस के आधार पर भी चलेंगे। सामूहिक उद्योग का संचालन सम्बन्धित समाज द्वारा नियुक्त संस्थाओं के हाथ में होगा। मजदूरों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। संचालन मजदूरों द्वारा स्थापित समितियों के हाथ में भी हो सकता है। ऐसी अर्थ-व्यवस्था में वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग समन्वय का सिद्धांत काम करेगा और हड़तालों आदि के लिए स्थान नहीं रहेगा। यद्यपि नैतिक प्रश्न उपस्थित होने पर अत्यन्त विशेष परिस्थिति में असहयोग का मार्ग अपनाया जा सकता है। आर्थिक संस्थाओं का शासनिक संस्थाओं में भी प्रतिनिधित्व होगा, जैसे जिले के भिन्न २ उद्योगों के अपने अपने संगठन होंगे, जिसका जिला परिषद् में प्रतिनिधित्व होगा। इस आर्थिक व्यवस्था में पुरुषार्थ के अर्थ में व्यक्ति साहस को पूरा अवसर मिलेगा और स्वशासन तथा समाज के प्रति दायित्व का उसे पूर्णतया पालन करना होगा।

—जयप्रकाश नारायण

खादी-ग्रामोद्योग और बेरोजगारी

अक्सर कहा जाता है कि सरकारी ऋण, सहायता, छूट आदि से खादी की भावना और कार्यकर्ताओं का ह्रास ही हुआ है। जब तक यह जारी रहेगी, तब तक यह ह्रास होता ही जायगा। खादी का काम जन-आधारित लोकसेवकों द्वारा ही होना चाहिए। व्यक्ति, परिवार या ग्राम-स्वावलम्बन के आधार पर ही खादी का काम चलना चाहिए। बाकी सारा काम बेकार है, उसे बंद कर देना चाहिए।

सरकारी योजनाओं के पीछे जो तस्वीर है, वह दोषपूर्ण है आज एक तरफ खादी-ग्रामोद्योग के क्रांतिकारी सामाजिक प्रयोग समग्रदृष्टि से आदर्शरूप में किए जाने की आवश्यकता है; दूसरी तरफ देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में खादीग्रामोद्योग को अपना उचित तथा सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करना जरूरी है, इसके लिए एक तरफ करोड़ों लोगों में खादी के काम को जल्दी से और नीचे तक ले जाना होगा, दूसरी तरफ आज की जन-रुचि के अनुसार तथा गरीबों और बेरोजगारों की आय बढ़ाने की दृष्टि से खादी का विस्तार करना होगा। इसके लिए सामान्य मूल्य-निर्धारण की आवश्यकता होगी, जो सरकारों तथा संस्थाओं के निकट सहयोग से ही संभव है।

देश में खादी का सारा काम खादी कमीशन द्वारा चलाया जा रहा है। खादी कमीशन को भारत सरकार द्वारा लगभग पैंतीस करोड़ रुपये का ऋण और सहायता मिली है, जिसके परिणामस्वरूप इस समय लगभग २४ करोड़ के मूल्य की खादी बनती है और लगभग १४ लाख लोगों को रोजगार मिलता है। पारिश्रमिक के रूप में लगभग ३० करोड़ रुपया इन पाँच वर्षों में ग्राम जनता के पास पहुँचा है। निःसंदेह खादी-कमीशन एक बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र बन गया है, जो दृष्टिकोण, वेतन ग्रेड, अलाउन्स काम-काज आदि के तौर-तरीकों में लगभग सरकारी तरीके पर ही है।

खादी का वास्तविक काम देश भर में रजिस्टर्ड और सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, जिनकी संख्या एक हजार से ऊपर पहुँची होगी। इन संस्थाओं में खादी के अनुभवी कार्यकर्ता मौजूद हैं और नये कार्यकर्ता भी हैं, जो समाजसेवा की भावना से आये हैं, या नौकरी पाने की भावना से ही आये हैं, और कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, इस मजबूरी से रह रहे हैं। कुछ भी हो, यह सत्य है कि ये कार्यकर्त्ता अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में बहुत कम निर्वाह-व्यय पर, शहरी-सुविधाओं से बहुत दूर, अनेक प्रकार के कष्ट सह कर भी, गांवों में ग्राम जनता में रहते हैं, काम करते हैं।

आज देश में करीब ६ करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनकी दैनिक आमदनी पाँच आने से भी कम है, इनमें २ करोड़ तो ऐसे हैं जिनकी आमदनी दो आने भी नहीं है। करोड़ों की तादाद में बेरोजगार लोग हैं। तीस लाख व्यक्ति प्रति वर्ष इस देश में बढ़ जाते हैं। खादी ग्रामोद्योग के अतिरिक्त ऐसे कौन से रोजगार हैं, जो गाँव-गाँव और झोंपड़ी-झोंपड़ी में फैले हुए इन करोड़ों लोगों को कुछ रोजगार दे सकें, इनको जिन्दा रहने के कुछ साधन दे सकें ? क्या खादी-ग्रामोद्योग देश की इस भयंकर गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में अपना योगदान छोड़ दें ?

—जवाहिरलाल जैन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

'सम्पदा' की पूरे वर्ष की फाइल

केवल ४ रुपए में

१९५२ में 'सम्पदा' का प्रकाशन आरम्भ हुआ था। तब से अर्थशास्त्र जैसे गम्भीर विषय की पत्रिका होते हुए भी, इसने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की है। 'सम्पदा' के पुराने अंकों की माँग बराबर हमारे पास आती रही है; और अब कार्यालय में कुछ ही फाइलें शेष हैं। पाठकों की सुविधा के लिए गत आठ वर्षों की फाइलें प्रतिवर्ष केवल ४) की दर से देने का निश्चय किया गया है। 'सम्पदा' का मूल्य प्रति अंक ७५ नये पैसे और वार्षिक ८) है। इस प्रकार आधे मूल्य में फाइलें पाठकों के लिए सुलभ होंगी।

और इन फाइलों के विशेष आकर्षण होंगे—विशेषांक। प्रति वर्ष दो या एक विशेषांक प्रकाशित होते रहे हैं। साधारण अंकों सहित ये विशेषांक भी ४) में ही सुलभ होंगे।

विशेषांकों का वर्ष-क्रम

१९५३ योजना अंक	१.००	१९५६ राष्ट्रीय विकास अंक	१.२५
१९५४ वस्त्र उद्योग अंक	१.२५	,, बैंक अंक	१.२५
१९५५ मजदूर अंक	१.२५	१९५७ समाजवाद अंक	१.५०
,, अ. भा. उद्योग अंक	१.२५	१९५८ राष्ट्र प्रगति अंक	१.५०

१९५९ सहकारी कृषि अंक १.५०

तुरन्त ४.५० (रजिस्ट्री डाक खर्च सहित) मनिआर्डर द्वारा भेजकर किसी भी वर्ष की फाइल मंगाएं। फाइलें वी० पी० पी० द्वारा नहीं भेजी जाएंगी।

विशेषः—रियायती मूल्य की यह सुविधा केवल ३१ जुलाई १९६० तक आने वाले आर्डरों के लिए ही है। संभव यह भी है कि तब तक जितनी फाइलें शेष हैं, सबके लिए आर्डर आ जाएं। इसलिए आप कल पर न टालकर, आज ही अपना आर्डर भेजें।

वितरण विभाग • सम्पदा • २८/११ शक्तिनगर • दिल्ली—६

GURUKULA KANGRI LIBRARY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय जहाज उद्योग की कहानी

सुमति मुरारजी बहन

'सम्पदा' के गतांक में विदुषी लेखिका ने मुगल काल तक के इतिहास में जहाज-उद्योग के विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया था, इस उत्तरार्द्ध में, उसके पश्चात् अधुनातन प्रगति का विवरण है।

१७ वीं शताब्दी के अन्तिम काल में, कानोजी आंग्रिया के नेतृत्व में, मरहट्ठा नौसेना विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक भयानक आतंकमय कोप बन गयी थी। 'बॉम्बे गजेटियर' ने आंग्रिया के जहाजी बेड़े का एक अत्यन्त मनोरंजक आंखों देखा वर्णन दिया है: "उसके बेड़े में 'ग्रैब' और 'गैलीवैट' प्रकार के जहाज ही हैं, 'ग्रैब' प्रकार के जहाजों में बहुत ही—कम दो से अधिक मस्तूल होते हैं। लम्बाई के अनुपात में वह चौड़े बहुत अधिक होते हैं। 'गैलीवैट' खेनेवाली नौकाएं होती हैं, जो कभी-कभी ही ७० टन से अधिक की होती हैं। इनमें ४० या ५० मजबूत पतवारें होती हैं और इन्हें चार मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है।

सन् १७३५ में जहाज-निर्माण के कारखाने को सूरत से बम्बई ले आया गया और उसकी देख-रेख एक भारतीय फोरमैन के सुपुर्द की गयी। भारतीय फोरमैनों की निगरानी में, भारतीय कारीगरों ने ही १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दियों में, इस 'लाइन' के नौ जहाज, और रॉयल नेवी के लिए सात रण-पोत तथा छः छोटे जहाज बनाये। कलकत्ता में, १७८१ और १८०० के बीच, ३५ जहाज बनाये गये, जिनका सम्मिलित भार १७,०२० टन था।

ईस्ट इंडिया कम्पनी एकाधिकारी व्यापारी थी। इसके बावजूद, इस एकाधिकार में हस्तक्षेप करके निजीरूप से तिजारत करनेवाले अनेक दल थे। सन् १७९८ में इनके और कम्पनी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार उन्हें हर साल ३,००० टन माल ढोने की इजाजत देनी पड़ती थी। लेकिन चूंकि किराये की दर के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ था, इसलिए कम्पनी उनसे मनमाना और निषेधात्मक रूप से ऊँचे दर पर किराया वसूल करती हैं। लॉर्ड वेलेजली नामक एक अंग्रेज गवर्नर-जनरल ने, सक्रिय रूप से, इन स्वतंत्र व्यापारियों को इस बात में सहायता दी कि वह उस काल के भारतीय जहाज-स्वामियों से जहाज प्राप्त कर सकें ताकि वह कम दर पर, ज्यादा अच्छे जहाजों के द्वारा और आर्थिक लाभ के साथ इंगलैंड के साथ व्यापार करते रह सकें। ऐसा करने में वह ईस्ट इंडिया कम्पनी की डायरेक्टर-समिति की विशेष आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे और इसके लिए उनको वहां से बराबर डांट मिलती रहती थी। लेकिन, अपने देशवासियों के आर्थिक लाभ के हित में वह भारतीय जहाज-निर्माण के विकास के हक में इतने उत्साहशील थे कि उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि अंग्रेजी नौसेना तथा अंग्रेजी व्यापार के लिए भी भारत में ही जहाज बनें।

डा० टेलर के शब्दों में: "भारत में बने जहाजों में भारतीय माल के लन्दन के बन्दरगाय में आने से अंग्रेजी एकाधिकारी व्यापारियों के बीच ऐसी सनसनी पैदा हुई, जिससे अधिक तब भी न होती, यदि शत्रु के जहाज टेम्स में आ जाते। लन्दन के बन्दरगाह के जहाज निर्माताओं ने खतरे का नारा लगाने में नेतृत्व किया। उन्होंने यह कहा कि उनका व्यापार और उद्योग पूर्णतया नष्ट और बर्बाद होने के निकट है; और सारे इंगलैंड के जहाज निर्माताओं के परिवार अब निश्चित रूप से भूखे मरेंगे।"

ईस्ट इण्डिया हाउस से डायरेक्टर-समिति ने २१ जून, १८०१, को हाउस ऑफ लॉर्ड्स् को एक अजीब प्रस्ताव भेजा। सस्ते और अधिक अच्छे बने हुए जहाजों से लाभ उठाने के कारण उन्हें इस बात में कोई आपत्ति नहीं थी कि भारत में बने हुए जहाज इंगलैंड और भारत के बीच की तिजारत में इस्तेमाल हों, उनका विरोध इस बात से था कि भारतीय नाविक उन जहाजों को चलायें।

अतः समिति ने यह सुझाव दिया कि भारतीय नाविकों को भारत में बने या अन्य किसी भी जहाज पर न लिया जाय, इसके स्थान पर यूरोपीय नाविक ही होने चाहिएं, जो समिति के कथनानुसार अधिक से अधिक संख्या में भारत

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में इकट्ठे होंगे और इस प्रकार, यह आशा की जा सकती है, उस देश में उपनिवेश-स्थापना का कार्य अधिक तेजी से होगा।"

भारतीय जहाज निर्माण के खिलाफ बढ़ती हुई विरोधी आवाजों के प्रत्युत्तर में, सर रॉबर्ट पील की अध्यक्षता में पार्लियामेंट की एक विशेष समिति ने भारतीय जहाज निर्माण से सम्बन्धित मामलों के बारे में प्रमाण इकट्ठे किए। यह प्रमाण सन् १८१४ में, पार्लियामेंट के सामने पेश किए गये। यह वर्ष ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भाग्य तथा गतिविधियों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण और निर्णायक था। विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर पार्लियामेंट ने कदम उठाया और एक कानून के द्वारा यह फैसला किया कि इंगलैण्ड के सम्राट की प्रजा होते हुए भी भारतीय नाविकों को अंग्रेजी नाविक नहीं माना जा सकता। कोई भी जहाज चाहे वह अंग्रेजी जहाज क्यों न हो, जिसके नाविकों की तीन-चौथाई संख्या अंग्रेजी नाविकों की नहीं होगी या जिस पर प्रति सौ रजिस्टर्ड टन पर सात अंग्रेजी नाविक नहीं होंगे, उसे जब्त किया जाएगा। साथ ही, लन्दन के बन्दरगाह में ऐसा कोई जहाज घुसने नहीं दिया जायगा, जिसका कप्तान कोई अंग्रेजी नाविक न हो।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी को इस बात की आज्ञा दे दी गई थी कि वह १ अगस्त, १८१४, तक भारत में बने हुए जहाज इस्तेमाल कर सकती है—यह अवधि, बाद को, एक साल के लिए बढ़ा दी गई थी। यही बात व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए भी लागू थी। दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण कानून, जो भारतीय जहाजों को उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र से निकाल फेंकने के लिए प्रयत्नशील थे, स्वयं भारत में ही बनाये जा रहे थे। सन् १८११ में बंगाल के विलियम ने अंग्रेजी तथा दूसरे जहाजों द्वारा लाये गये माल पर अलग-अलग आयात कर लागू किए; अंग्रेजी जहाजों वाले माल पर ७½ प्रतिशत और दूसरे जहाजों वाले माल पर १५ प्रतिशत। मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज तथा बम्बई के फोर्ट सेंट डेविड ने भी क्रमशः, सन् १८१२ और १८१३ में ऐसे ही कदम उठाये। सन् १८७५ तक पृथकता की भावना से प्रेरित आयात-कर की यह दरें एक न एक प्रदेश में चलती रहीं और उसके बाद व्यापार अधिकार पर शासकों का पूरा काबू हो गया। मूलतः यह दरें डच, फ्रांसीसी तथा गैरअंग्रेजी भारतीय जहाजों पर लागू होती थीं। लेकिन चूंकि निरन्तर युद्धों के परिणामस्वरूप फ्रांस और हालैंड ने इंगलैंड को उन्हें अनुकूल शर्तें देने के लिए विवश कर लिया था और अपने जहाजों के लिए समान व्यवहार हासिल कर लिए थे; अतः गैर अंग्रेजी भारतीय जहाज ही ऐसे थे, जिन्हें इस पक्षपात नीति का दंड सहना पड़ रहा था।

सिंधिया कम्पनी की स्थापना

पहले महायुद्ध के बाद ही भारतीय जहाज-उद्योग को पुनर्जीवित करने की दिशा में कुछ प्रयत्न किये गये। भारत में पहली बार, बड़े पैमाने पर, आधुनिक जहाज-उद्योग की स्थापना उचित रूप से और वास्तव में तब हुई जब २७ मार्च, १९१९, को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी स्थापित हुई।

सिंधिया कम्पनी के प्रथम जहाज 'एस. एस. लायल्टी' ने ५ अप्रैल, १९१९, को बम्बई से रवाना होकर इंगलैंड की यात्रा की और आधुनिक इतिहास में पहली बार विशाल सागरों पर भारतीय पताका को लहराया। इस ध्वज पर, जो सिन्धिया का निजी व्यापार-ध्वज है, नीली पृष्ठभूमि पर सफेद वृत्त में एक लाल स्वस्तिक चिन्ह है।

फिर भी इस बात में कई वर्ष लग गये कि पहले आधुनिक भारतीय जहाज को बनाया जा सके और विशाखापत्तनम के जहाज-बाड़े से उसे रवाना किया जा सके। 'जलउषा'—८,००० टन भार का पहला आधुनिक वाष्प-पोत है—जो सिन्धिया जहाज-बाड़े विशाखपत्तनम में बना और जिसकी जलावतरण-विधि भारत के प्रधानमंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने १४ मार्च, १९४८ को की। भारत की प्रगति और उसके औद्योगिक विकास में इस विशेष घटना का बहुत जबरदस्त महत्व है।

कई पीढ़ियों के कौशल, अनुभव और परम्परा के साथ आधुनिक संगठन तथा यांत्रिक विधियों के कौशल को मिलाकर भारतीय कारीगर फिर ऐसे जहाज बनाने लगे हैं जो आकृति, बनावट तथा कार्य-कौशल में पश्चिम में बने जहाजों का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संगठित और असंगठित मजदूरों के वेतन

'यूनियनों में संगठित होने से मजदूरी भी अच्छी मिलने लगती है'—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का खोज करने वाला (अनुसंधान) विभाग इसी नतीजे पर पहुँचा है। उसने मुकाबले के धन्धे में यूनियन वाले और बिना यूनियनों के मजदूरों की उजरतों का अध्ययन किया था और यह अध्ययन अमरीका के श्रम-विभाग की तरफ से उद्योगों में लगे मजदूरों की अभी हाल में की गई जांचों की बुनियाद पर किया गया था।

इस जांच-रिपोर्ट में नीचे लिखी बातें बताई गई हैं:

एक ही उद्योग में जहां यूनियन है, वहां के मजदूरों की उजरतें उन मजदूरों की उजरतों से ज्यादा हैं, जहां यूनियनें नहीं हैं। १,००० से ज्यादा यूनियन वाले और बिना यूनियन के कारखानों की तुलना की गई, जिनमें पेशे, उद्योग और भौगोलिक इलाके एक जैसे ही थे। तुलना करने पर पता चला कि यूनियन सदस्य के काम की औसत उजरत कोई ८० फीसदी मामलों में ज्यादा थी।

औसतन, यूनियन के जरिये काम पर लगाये गये मजदूर को उस मजदूर से ८ फीसदी ज्यादा वेतन मिलता है जो यूनियन की तरफ से नहीं लगाया जाता है। यह सच है कि वेतन-संबंधी जो लाभ मिलते हैं, वे हमेशा यूनियन की कार्रवाई का ही फल होते हैं। और भी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, जिनसे अलग-अलग उद्योगों में वेतनों का फर्क पैदा हो सकता है। जैसे, कारखानों की अपनी-अपनी किस्में, उनका आकार, उनका स्थान, मुकाबले के उद्योगों से होड़ ले सकने की हैसियत, उजरतों की अदायगी का तरीका और वेतन के अलावा मिलने वाले लाभों में फर्क।

इस अध्ययन से यह बात जाहिर है कि यूनियन के जरिये काम पर लगाये गये लोगों को जो वेतन सम्बन्धी लाभ मिल रहे हैं, वे उन लोगों के वेतनों से जो यूनियनों के जरिये काम पर नहीं लगाये जा रहे हैं, इतने ज्यादा और स्थायी होते हैं कि इस नतीजे पर पहुँचा जा सकता है कि यूनियन में संगठित होने से मजदूरी भी अच्छी मिलती है।

सवेतन छुट्टियां, आम छुट्टियां, पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याण के काम आदि कुछ ऐसे लाभ भी हैं जो बिना यूनियन के कारखानों के मुकाबले यूनियन वाले कारखानों में आमतौर से मिलते हैं।

यह अध्ययन सन् १९५१ से १९५७ तक उद्योगों में चालू उजरतों की जांच पर आधारित है। यह जांच उन्हीं उद्योगों में की गई थी, जहां यूनियन और बिना यूनियन के कारखानों की संख्या काफी थी।

इस जांच में नीचे लिखे उद्योग शामिल थे: सिगार, खाद, जूता, हौजरी, औद्योगिक रसायन, चमड़े की रंगाई और तैयारी, मर्दों व लड़कों की कमीज तथा रात की कमीज तथा रात की पोशाक, लोहे के अलावा दूसरी धातुओं की फाउण्ड्रियां, रेडियो, टेलिविजन और उनके पुर्जे, दक्षिण की आरा मिलें, इस्पात की फाउण्ड्रियाँ, ढांचों में काम आने वाली चीनी मिट्टी की वस्तुएं, सूती कपड़े की रंगाई और तैयारी, तम्बाकू, लकड़ी के बक्सों, घरेलू फर्नीचर ऊनी कपड़ों और काम के वक्त पहनी जाने वाली वर्दियों के उद्योग।

इस विश्लेषण से भली भांति प्रकट है कि यूनियन संगठनों द्वारा मजदूरों को बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। ● ●

आप 'सस्ता साहित्य मंडल' की पुस्तकों के प्रेमी हैं। सस्ता साहित्य के व्यापक प्रसार में कृपया योग दीजिये। अपने इष्ट मित्रों, अपने क्षेत्र की संस्थाओं तथा पुस्तकालयों से अनुरोध कीजिये कि वे 'मंडल' की पुस्तकें अपने यहाँ अवश्य रक्खें।

पर ऐसा आप तभी कर सकेंगे
जबकि
'मंडल' के नये प्रकाशनों से
आपका परिचय रहे। इसके लिए आप
जीवन-साहित्य
के ग्राहक बन जाएं उसके प्रत्येक अंक में 'मंडल' के नवीनतम प्रकाशनों की सूचनाएं रहती हैं
पत्र की सामग्री भी अत्यन्त उपादेय है
वार्षिक मूल्य केवल रु. ४.००
सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशी अर्थ-चर्चा

पोज़नान की अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शिनी

लगभग ४० वर्ष पूर्व १९२१ में पोलैंड के नगर पोज़नान में अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी की स्थापना हुई थी। तब से यह प्रदर्शनी निरन्तर प्रगति करती रही है। १९५८ में इस मेले में ४७ देशों ने भिन्न-भिन्न कक्षों में अपने उत्पादनों का प्रदर्शनों किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों ने प्रदर्शनी के कुल क्षेत्रफल का ६३.६ प्रतिशत लिया था, जबकि १९५५ में प्रदर्शनी के कुल क्षेत्रफल का ३७ प्रतिशत स्थान लिया था। गत वर्ष प्रदर्शनी में कुल ११९५ संस्थानों ने अपने उत्पादनों का प्रदर्शन किया था और १४१० हजार दर्शक इसे देखने के लिए आए थे। इनमें से ५००० दर्शक तो विभिन्न ५२ देशों थे।

पोज़नान प्रदर्शनी केवल दो सप्ताह तक चलती है। इस प्रदर्शनी में पोलैंड के विदेशी व्यापार मंत्रालय के प्रतिनिधि, तकनीकी सूचना केन्द्र, राष्ट्रीय बैंक की एक शाखा, विदेशी मेहमानों के लिए अतिथि गृह तथा क्लब, एक 'बालटोना'—ऐसी दुकान जहाँ से विभिन्न आवश्यकता की वस्तुएं खरीदी जा सकें तथा पोलैंड के टेक्निकल सूचना विभाग का केन्द्र होता है।

गत वर्ष भारत ने भी अपनी कलापूर्ण परम्परा का निर्वाह करते हुए एक सुन्दर कक्ष प्रदर्शित किया, जिसमें भारत के विभिन्न उत्पादनों का प्रदर्शन किया गया था। भारत के कलात्मक शिल्पों की दर्शकों ने असाधारण रूप से प्रशंसा की। इस सामग्री का अधिकांश आज भी पोलैंड की विभिन्न दुकानों में बिक्री के लिए सुलभ है।

३ अप्रेल १९५६ को भारत और पोलैंड के बीच एक व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार पोलैंड भारत को रौलिंग स्टाक्स भेजता रहा है। पोलैंड से भारत में आने वाली अन्य सामग्रियों में मशीनी औजार, भवन निर्माण सामग्री, खदान और वस्त्र उद्योग की मशीनें, अखबारी कागज तथा रासायनिक पदार्थ हैं।

भारत से भी पोलैंड को अनेक वस्तुओं का निर्यात होता है। इनमें खली, प्रमुख है। भारत की खली के कुल निर्यात का ३० प्रतिशत केवल पोलैंड ही मँगाता है।

पोज़नान की औद्योगिक प्रदर्शनी विभिन्न देशों के व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

योजना की २९वीं प्रदर्शनी इसी १२ जून १९६० को आरंभ हो रही है। इसमें राज्य द्वारा संचालित १,००० से भी अधिक फैक्टरियों के तरह-तरह के उत्पादनों का प्रदर्शन किया जाएगा। आशा है पिछले साल की तरह भारत भी प्रदर्शनी में उत्साहपूर्वक भाग लेगा।

रूस में उपभोग्य सामग्री उत्पादन

रूस ने अब तक अधिकांश ध्यान पूंजीगत उद्योगों की ओर दिया है, किन्तु अब वह उपभोग्य सामग्री बनाने की ओर भी लगा है, वह ब्रिटेन से ऐसी मशीनरी मंगाने की बातचीत कर रहा है, जिससे मांस को सुरक्षित रखा जा सके, और मक्खन, पनीर चाकलेट मिठाइयां तथा अन्य भोज्य सामग्री बनाई जा सकें।

चीन के आंकड़ों की पोल

'सम्पदा' के पाठक समय-समय पर चीन की आर्थिक प्रगति के अंक पढ़ते रहते हैं और इनके द्वारा यह कल्पना करते रहे हैं कि चीन भारत की अपेक्षा कितना आगे बढ़ रहा है। कुछ समय पहले यह प्रकट हुआ था कि चीन के अंक विश्वसनीय नहीं हैं। वे जान बूझ कर बहुत बढ़ा-चढ़ा कर लिखे जाते हैं। इस सम्बन्ध में एक नये प्रकाशन से ज्ञात होता है कि चीन के अधिकारी अंकशास्त्र को राजनीति का अनुचर और दलीय नीति का समर्थक मात्र बनाना चाहते हैं, इस प्रकाशन में राज्य के अंक विभाग के संचालक चिया-ची-मुन ने लिखा है कि विभिन्न अंक हमारे लिये ऐसे विशेष हथियार हैं जिनसे हम दल की नीति को पूर्ण सत्य सिद्ध करते हैं। अंकों का इस तरह वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिससे देश की आर्थिक नीति में जनता का विश्वास निरन्तर बढ़ता रहे। यह लेख 'योजना और सांख्यिकी' नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है।

इस सिलसिले में पिछले साल की तीसरी तिमाही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

में लुशान कान्फ्रेंस में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने गंभीर अंक गणना त्रुटियों को स्वीकार किया और फिर दुबारा आंकड़ों के पुनरावलोकन का निश्चय कर दिया गया।

फलस्वरूप १९५८ में खाद्यान्नों का उत्पादन २५ सौ लाख टन दिखाया गया, जो पहले ३५ सौ लाख टन दिखाया गया था। १९५९ में अनाज के उत्पादन के अनुमानित आंकड़ों में १०% की कमी की गई। अन्य औद्योगिक फसलों के आंकड़ों में भी कमी की गई।

राज्यीय सांख्यकी ब्यूरो ने अपनी संक्षिप्त विज्ञप्ति में इस अनियमितता का स्पष्टीकरण किया। इस विज्ञप्ति में कहा गया कि आंकड़ों में त्रुटियाँ हो जाने का कारण फसल उत्पादन काटने, बटोरने और जमा अनाज के आंकड़ों का अनुमान लगाने में अनुभवहीनता थी।

लेकिन अब वही ब्यूरो नये सिद्धान्त का प्रतिपादन

जापान में वैज्ञानिक सूत का उत्पादन

जापान में कृत्रिम और वैज्ञानिक सूत का प्रचार निरंतर बढ़ रहा है, सबसे प्रथम उत्पादक अमरीका है और दूसरे नम्बर पर जापान। १९५९ में इस कृत्रिम सूत का उत्पादन कुछ कम हुआ था; लेकिन १९५९ में रेयन का उत्पादन फिर बढ़ गया। रेयन के अतिरिक्त विनीलोन, नाइलोन, पोलिस्टर और अन्य कृत्रिम सूत का उत्पादन भी निरन्तर बढ़ रहा।

करता है कि आंकड़ों को सरकारी औचित्य सिद्ध करना चाहिये।

श्री चिया को निम्न पंक्तियों में अपने विशेषज्ञों के दल के सम्मुख कहना पड़ाः—

"हमें अपने सब अंकों को इस तरह पेश करना चाहिये ताकि हमारी विविध क्षेत्रों की प्रगति लोगों पर प्रकट हो और हमारी आर्थिक पद्धति पर लोगों का विश्वास जमे। देश के दक्षिणपन्थी या बाहर के विरोधी जब हमारी व्यवस्था पर आपत्ति करें तब हम वे अंक लेकर उन्हें निरुत्तर कर सकें।"

अंक शास्त्र एक विज्ञान है। उससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, परन्तु पहले ही कुछ निष्कर्षों की कल्पना करके उन्हें सिद्ध करने के लिये अंकों में ही परिवर्तन कर देना तो सरासर आत्म प्रवन्चना है।

स्काटलैंड में ग्लासगो के निकट ब्रिटिश मोटर कारपोरेशन के मो
तथा ट्रैक्टर बनाने के नये कारखाने का एक दृश्य

अमरीकी गेहूं को लाने का प्रश्न

एक बड़े समझौते के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका ने भारत को अन्न देने का निश्चय किया है। यह अन्न इतनी अधिक मात्रामें है कि अमरीका से भारत लाने के लिये चार वर्ष तक प्रति दिन १ जहाज को माल लेकर आना होगा। अमरीकी कानून के अनुसार ५०% तक लदान केवल अमरीकी जहाजों से होगा। शेष परिवहन अन्य जहाजों से भी किया जा सकता है।

इंग्लैण्ड का जहाज उद्योग इस परिवहन में साझीदार बनने को अत्यन्त उत्सुक हो उठा है। उसके द्वारा ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वह अमरीकी सरकार को विवश करे ताकि इस भारी लदान का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश जहाजों को मिले। अमरीकन जहाजी स्वार्थ इसे कहाँ तक स्वीकार करेंगे, यह हम नहीं कह सकते।

इधर भारत सरकार भी यह सोच रही है कि वर्तमान जहाजों से अथवा नये जहाज खरीदकर इस व्यापार का एक बड़ा भाग भारतीय जहाजों द्वारा किया जाय ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके।

डीजल रेल इंजन में आविष्कार

डीजल रेल इंजन के निर्माण में भारतीय रेल अनुसंधान विभाग के श्री एम. ए. सूरी ने डीजल इंजनों में शक्ति संचालन की एक नई प्रणाली निकाली है जिसके परिणाम स्वरूप शक्ति का लगभग १० प्रतिशत अधिक उपयोग हो सकेगा। अभी दुनिया में लगभग ८५ प्रतिशत शक्ति का उपयोग होता है। इस नए आविष्कार के कारण लगभग ९५ या ९६ प्रतिशत शक्ति का उपयोग हो सकेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हमारे पशु कैसे उन्नत हों ?

सुदर्शन चोपड़ा, एम० ए०

किसी भी ऐसे देश में जिसकी कृषि अपनी क्षमताओं अथवा सीमाओं के कारण मशीनीकरण को स्वीकार नहीं पाती, पशु अमूल्य सम्पत्ति होते हैं। भारत एक ऐसा ही देश है। यहाँ के वर्तमान आर्थिक साधनों और यहां की ग्राम्य अर्थव्यवस्था को देखते हुए खेती का पूरी तरह मशीनीकरण करना न उचित है और न ही संभव। ऐसी स्थिति में कृषि के संचालन के लिए पशुओं का बल ही हमारी प्रमुख शक्ति रह जाती है।

पशुओं का उपयोग खेती करने के लिए तो है ही, इसके अतिरिक्त दूध, घी, मक्खन, पनीर आदि वे पौष्टिक खाद्य भी पशुओं से ही प्राप्त होते हैं जिनके बिना देश के नागरिकों का स्वस्थ रहना असंभव है। इन पशुओं से प्राप्त पदार्थों में गोबर एक ऐसा पदार्थ है, जिसके खाद के रूप में उचित उपयोग के बिना खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। और अन्न की कमी तो हमारी प्रमुखतम समस्याओं में से एक है। पशुओं से हम मांस, अंडे, चमड़ा, ऊन, सींग और हड्डी भी प्राप्त करते हैं। इन सभी पदार्थों का राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

हमारे पशु विकसित न हों, तो न केवल कृषि उत्पादनों का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि अस्वास्थ्य और बेरोजगारी की समस्याओं को भी दूर नहीं किया जा सकता। देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग पशुपालन और पशुओं से प्राप्त उपादानों से संबन्धित उद्योगों में लगा हुआ है। पशुओं का विकास हुए बिना इन धन्धों में लगे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति दृढ़ नहीं हो सकती।

पशुओं की दुर्दशा

हमारी अर्थ-व्यवस्था का यह बहुत कमजोर पक्ष है कि हमारा पशुधन नितान्त अविकसित अवस्था में है। दूसरे देशों के अनुपात में हमारे दुधारु पशुओं का औसत उत्पादन कितना कम है, यह निम्न तालिका से भली भांति प्रकट है—

विश्व की वार्षिक दूध पैदावार (१९३५)

देश	गाय (लाखों में)	वार्षिक दूध (लाख मनों में)	विश्व-उत्पादन का प्रतिशत
नीदर लैंड	१४.७५	१,३५५.३४	२.४३
डेन्मार्क	१६.१०	१३७०.६८	२.४६
स्विटरज़र लैंड	८.७९	६९४.२३	१.२५
इंग्लैंड	२६.३२	१७.८४.२१	३.२०
अमेरिका	२४९.९१	१५,५३२.३३	२२.५०
आस्ट्रेलिया	३२.९२	१,३८५.३७	२.५
संयुक्त रूस	२०१.४७	५,७१४.८७	१०.३
भारत	६५८.००	६,०१८.००	१०.८

विश्व की कुल पैदावार का लगभग १० प्रतिशत दूध पैदा करने के लिए भारत को ६-७ करोड़ गायें रखनी पड़ती हैं जबकि रूस इतने दूध के लिए केवल दो करोड़ गायें पालता है। अमरीका इससे दुगुने दूध के लिए २॥ करोड़ गायें पालता है। भारत की गायों की अयोग्यता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है ?

भारत के पशुओं की उत्पादन क्षमता कम है इसलिए हमें आवश्यकता से अधिक पशु पालने पड़ते हैं। यहां प्रति वर्गमील क्षेत्रफल में पशुओं की संख्या २०४ है। आबाद भूमि के प्रति १०० एकड़ पर ६५ पशु हैं। व्यक्तियों की संख्या के अनुपात से देखें तो प्रति दो व्यक्ति एक पशु है। पशुओं की यह विशाल संख्या भारत के सीमित कृषि साधनों पर भार बन रही है।

१९५१ की पशु गणना के अनुसार भारत में मवेशियों की संख्या इस प्रकार थी—

(अंक लाखों में)

गायें	
प्रजनन करने वाली गायें	४६३.४
प्रजनन करने वाले सांड	६.२
जुताई और ढुलाई करने वाले नर	५८४.१
जुताई और ढुलाई करने वाली मादा	२३.१
बाल पशु	४३४.६
अन्य	३८.६
योग	१५५०.६०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भैंसे

प्रजनन करने वाली भैंसे	२०६.६
प्रजनन करने वाले भैंसे	३.१
जुताई और ढुलाई करने वाले नर	६०.१
जुताई और ढुलाई करने वाली मादा	४.३
बाल पशु	१४७.३
अन्य	७.८
योग	४३३.४

पशुओं की इस भारी संख्या के बावजूद १६५०.५१ में पशुधन उत्पादनों का कुल मूल्य केवल ६६४ करोड़ रु० अर्थात कृषि से होने वाली आय का केवल १६ प्रतिशत है।

कारण क्या हैं ?

यहां एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिर वे कारण क्या हैं, जिनसे हमारा पशुधन इतनी अनुन्नत अवस्था में है ? इस अवस्था का सर्वप्रमुख कारण चारे का अभाव है। अनुमान किया जाता है कि सूखे चारे की दृष्टि से पशुओं की संख्या उपलब्ध चारे के अनुपात में कम से कम एक तिहाई अधिक है। हरे चारे तथा खली आदि की दृष्टि से तो यह स्थिति और भी खराब है। मनुष्यों की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, इसलिए जिन क्षेत्रों में चराई की व्यवस्था हो सकती थी, वे क्षेत्र बराबर कम होते जा रहे हैं।

दूसरा प्रमुख कारण पशुओं की विकृत नस्लें हैं। भारत में गायों की लगभग २५ और भैंसों की छः नस्लें हैं, जो देशके विभिन्न भागों में बिखरी हुई हैं। हर नस्ल के अच्छे नमूनों की संख्या बहुत सीमित है, अधिकांश पशु घटिया किस्म के हैं। इनमें से कुछ पशु डेरी वर्ग के हैं, जिनकी मादाएं तो दूसरी नस्लों की अपेक्षा दूध अच्छा देती हैं, किन्तु नर पशु काम के लिए बेकार होते हैं। देश के अपेक्षाकृत सूखे भागों में पशुओं की कुछ ऐसी नस्लें भी पाई जाती हैं, जिनकी मादाएं औसत से कुछ अधिक दूध देती हैं और नर भी अच्छे खासे बैल होते हैं; लेकिन ऐसी नस्लें बहुत कम संख्या में हैं। पूर्वी और दक्षिणी भागों में जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, पशु किसी निश्चित नस्ल के नहीं हैं।

पशुओं के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा पशु रोग भी हैं। आवश्यकता से कम और पौष्टिक तत्वों से रहित चारा खाने के कारण हमारे अधिकांश पशु रोगी हो जाते हैं; और इन रोगों की समुचित चिकित्सा के अभाव में पशुओं की पूरी-पूरी नस्ल ही रोगी बन जाती हैं। हमारे पशुओं में कठिनाई से १० प्रतिशत ऐसे पशु निकल सकेंगे जो पूर्णतः रोगमुक्त हैं।

पशुओं के अनुन्नत होने का चौथा कारण, जिसकी ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता, अनुपयोगी और बेकार पशु हैं। अनुपयोगी पशुओं की समाप्ति के प्रश्न पर जनसामान्य की धार्मिक-सहिष्णुता आगे आ जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जंगली पशु पाया जाता है—नील गाय। नील गाय न केवल पशुओं के चारे को, बल्कि खाद्यान्न की भी बहुत बड़ी मात्रा को चर जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नील गाय के वध के आदेश जारी किए तो विरोध में आंदोलन खड़ा कर दिया गया। आंदोलन का मुख्य कारण था यह कि नील गाय के नाम में 'गाय' शब्द आता है; जब कि वस्तुस्थिति यह है कि नील गाय स्वभाव और शक्ति में गाय से कोई भी समता नहीं रखती। समता रखती ही है तो किसी हद तक खच्चर से अवश्य रखती है।

पशुधन के विकास के लिए क्या करें ?

हमारा पशु धन राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था पर भार न बन कर, उसकी समस्याओं को सुलझाने में सहायक बन सके, इसके लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। निम्न-लिखित उपाय समस्या को काफी हद तक हल कर सकते हैं—

१—चारे और खाने की उचित व्यवस्था—उपयोगी पशुओं को अच्छा चारा-खाना जुटाने तथा अच्छे स्तर पर उनका पालन करने के लिए सरकार अब तक जो कुछ करती रही है, उसे सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। पहली पंचवर्षीय योजना में १६० गोसदन स्थापित करके ३,२०,००० पशुओं की देख-भाल अच्छी तरह करने का लक्ष्य रखा गया था। देश में पशुओं की कुल संख्या २० करोड़ को देखते हुए पाँच वर्ष की योजना में केवल ३ लाख २० हजार पशुओं के सुधार का लक्ष्य नितान्त अपर्याप्त लक्ष्य था; किन्तु इससे भी विचित्र यह जानकारी है कि पहली योजना में इस छोटे लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया जा सका। इस अवधि में केवल २२ गोसदन स्थापित किए जा सके जिनमें

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

२,००० पशुओं की देखभाल की व्यवस्था है

दूसरी योजना में ३०,००० पशुओं के लिए ६० गोसदन खोलने का लक्ष्य रखा गया था, किन्तु अभी आँकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं कि इस लक्ष्य को कहाँ तक पुरा किया जा सका है।

पशुओं के अच्छे पालन-पोषण के लिए गोसदन खोलना ही एकमात्र हल नहीं है। अच्छे चारे और खली आदि की व्यवस्था पर भी अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्कता है।

२—नस्ल सुधार—पशुओं के नस्ल सुधार के लिए सरकार की ओर से जो प्रयत्न हो रहे हैं, उनमें ग्राम केन्द्रों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संयोजन प्रमुख है। इन योजनाओं के अनुसार घटिया सांडों को बधिया कर दिया जाता है और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में अच्छी नस्ल के सांड रख कर उनके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६०० ग्राम केन्द्र तथा १५० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए गए। दूसरी योजना में १,२५८ ग्राम केन्द्रों, २४५ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों और २५४ विस्तार केन्द्रों को स्थापित करने के लक्ष्य रखे गये थे।

३—पशु चिकित्सा की व्यवस्था—पशुओं की चिकित्सा उनकी कार्य क्षमता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए तो आवश्यक है ही, उनसे प्राप्त उत्पादन पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक हों, इसलिए भी आवश्यक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मनुष्यों के लिए ही मर्यादा चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हो सकी है, पशुओं की बात तो पीछे आती है। फिर भी आवश्यक है कि सरकार अधिक से अधिक मात्रा में पशु चिकित्सा की व्यवस्था का प्रयत्न करे।

४—अनुपयोगी और हानिकर पशुओं की संख्या कम करना—इस विषय में जहाँ तक संभव हो लोकमत को स्वस्थ और सही दिशा की ओर उन्मुख करने की आवश्यकता है। जो पशु कम उपयोगी हैं, उनके ऊपर दया प्रदर्शित करने से कहीं अच्छा है कि हम उनकी उपयोगिता बढ़ाने का प्रयास करें।

भारत की कृषि-प्रणाली, आर्थिक ढाँचे और यहाँ की सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्पराओं को देखते हमारा पशुधन सचमुच राष्ट्र की जीवती शक्ति है। इस शक्ति बिना देश का सर्वांगीय विकास संभव नहीं। ● ●

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र०
की
विज्ञप्ति संख्या ४।५५८० : २७।३३।५३, दिनांक १५
द्वारा
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

		रु०	आ०
वेद सार	प्रो० विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग			
सच्चा सन्त			३
सिद्ध साधक कृष्ण			३
जीते जी ही मोक्ष			३
आदर्श कर्मयोग			३
विश्व-शांन्ति के पथ पर			१
भारतीय संस्कृति	प्रो० चारुदेव		३
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२१
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१३
हमारा समाज		६	
व्यावहारिक ज्ञान		२	१२
फलाहार		१	४
रस-धारा		०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां		१	
नये युग की कहानियां		१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	
विशाल भारत का इतिहास	प्रो० वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार
साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ-वृत्त चयन

पाकिस्तान में भारतीय पूंजी

पाकिस्तान भारत के आर्थिक स्रोतों के साधारण प्रवाह में रुकावटें पैदा कर रहा है। अनेक प्रतिबंध और संकट पैदा करने के सिवा पाकिस्तान भारतीयों के व्यापार और उद्योगों को हस्तगत करने में लगा है। पाकिस्तानियों को भारत में कारबार चलाने और विनियोजन में जो सुविधाएं हैं, उसके सर्वथा विपरीत पाकिस्तान में भारतीयों के व्यापार और उद्योग तथा विनियोजन में रुकावटें हैं, जो वहाँ अन्य विदेशियों के प्रति नहीं हैं; फिर भी भारतीयों की ३६ करोड़ रुपए की पूंजी वहाँ लगी हुई है। जब इस देश में अधिक कर लगे, तब भारतीयों ने पाकिस्तान में छोटे-बड़े उद्योग खड़े करने की ओर कदम बढ़ाया। पर पूर्व बंगाल में पाट के कारबार से भारतीयों को हटाने का जो उपद्रव किया, गया, उससे उन्हें भारी क्षति हुई। किन्तु इतने पर भी एक स्तर तक विनियोजन बना हुआ है और यह कदाचित और बढ़े, यदि भारतीयों के साथ भेदभाव का बर्ताव न किया जाए। भारतीय कम्पनियों के एजेण्टों को पाकिस्तान में घूमने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में भारतीय फैक्ट्रियाँ भारत से इंजीनियरिंग और टेक्निशियन नहीं ला पातीं। पाकिस्तानी सरकार इस तरह से मजबूर कर रही है कि भारतीय अपना व्यापार और अपने उद्योग छोड़कर चले जाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक्सचेंज कन्ट्रोल का जो समझौता है, उसके अन्तर्गत फालतू मदों के रुपया भेजने पर कोई नियंत्रण नहीं है। इन मदों में मुनाफा किराया, डिवीडेण्ड, ब्याज और आय कर की फालतू रकम हैं। पर पाकिस्तान स्टेट बैंक इन मदों की रकमों को भारत में नहीं लाने देता है। पूंजी वापस लाना भी संभव नहीं है। पाकिस्तान की जो कम्पनियाँ भारत में काम करती थीं, पाकिस्तान ने उनके कारबार को वापस हटा लिया है। भारतीय व्यापारी सिक्यूरिटियों के द्वारा भी मुनाफा नहीं भेज पाते। पाकिस्तान में भारतीयों की एक बड़ी सीमेण्ट फैक्ट्री है। एक ओर तो उसका उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाता है और दूसरी ओर साधारण सहूलियतें भी नहीं दी जातीं। अनेक भारतीयों को कहा गया है कि वे पाकिस्तानियों को अपनी कम्पनियाँ बेच दें। जिन्होंने बेची, उनकी पूंजी रुकी पड़ी हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि बिना मुआवज़े चुकाए, भारतीय कम्पनियों पर अधिकार कर लिया जाए।

अणुशक्ति से बिजली

● हिमालय और दूसरे इलाकों की नदियों आदि को मिलाकर भारत में करीब ४ करोड़ ३० लाख किलोवाट बिजली तैयार की जा सकती है। अगले २५ वर्षों में इसमें से लगभग आधी का उपयोग हो सकेगा। दूसरे, भारत में कोयले का भंडार भी सीमित है और वह भी देश के पूर्वी-भागों में ही पाया जाता है। इसलिए कोयले से अधिक बिजली नहीं बनाई जा सकती। कल कारखानों के लिए भी काफी कोयले की जरूरत है और यह जरूरत बढ़ेगी। इसी प्रकार तेल से भी हमारे देश में बिजलीघर नहीं चलाये जा सकते। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि बिजली तैयार करने के लिए हमें अणुशक्ति का अधिकाधिक उपयोग करना होगा।

● केन्द्रीय सरकार ने १९५८ में अणुशक्ति आयोग स्थापित किया था और इसे देश में अणुशक्ति के विकास के लिए प्रबन्ध और वित्त सम्बन्धी पूरे अधिकार और स्वतंत्रता दी गई हैं।

● १९५९-६० की सबसे महत्वपूर्ण घटना खनिज यूरेनियम से ईंधन तत्व तैयार करना है।

● ट्राम्बे के यूरेनियम धातु यंत्र और फ्यूअल एलमेंट फैब्रीकेशन फैसिलिटी में इतना ईंधन तत्व बन सकता है, जो भारत-कनाडा अणु भट्टी और प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल करनेवाली अन्य भट्टियों की जरूरत पूरी कर सके। ये भट्टियाँ इस वर्ष चालू हो जाएंगी और इन्हें इतना बढ़ाया जा सकता है कि आगे चलकर ये २५० मेगा वाट बिजली वाले बिजलीघर को अणु शक्ति से चला सकें।

● देश में अणुशक्ति से चलनेवाला पहला बिजलीघर बनाने के लिए आरम्भिक काम शुरू हो चुका है। बिहार में यूरेनियम खोदने की व्यवस्था की गई है और यहाँ से जो खनिज यूरेनियन मिलेगा, वह इस बिजलीघर को चलाने के लिए काफी होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५९ में बैंक व्यापार की प्रगति

रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक विवरण के अनुसार सन् १९५९ में देश की अर्थ-व्यवस्था में विशेष सुदृढ़ता आई, यद्यपि मुद्रा बाहुल्य में कोई कमी नहीं हुई। सरकारी उद्योग धंधों में पूंजी अधिक लगी और निजी उद्योग धंधों में भी पिछले साल से अधिक धन लगाया गया। इस साल में व्यापारी बैंकों की जमा पूंजी में २ अरब ५३ करोड़ रु० की वृद्धि हुई; और यह राशि १८ अरब १६ करोड़ रु० तक पहुँच गयी। १९५८ में यह वृद्धि २ अरब १६ करोड़ रु० की थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक ओर लोग बैंकों में अपना रुपया जमा कराना पसन्द करने लगे हैं और दूसरी ओर बैंक भी अपने काम को बढ़ाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

पिछले साल अनुसूचित बैंकों ने पहले से बहुत अधिक ६१ करोड़ रु० कर्ज दिया। १९५८ में ११ करोड़ रुपया ही इस प्रकार दिया गया था। क्योंकि बैंकों के पास धन कहीं अधिक जमा कराया गया, इसलिए जमा और ऋण का अनुपात १९५८ के ५४.८ प्रतिशत से घटकर ५२.२ प्रतिशत रह गया। उद्योगों को बैंकों ने अक्टूबर में समाप्त वर्ष में २० करोड़ रु० अग्रिम दिया, जबकि पिछले साल १४ करोड़ रु० ही दिया था। कुल अगाऊ रकम में से उद्योगों के लिए इस वर्ष ४५ प्रतिशत दी गयी। पिछले पाँच सालों में पहली बार यह अनुपात इतना गिरा है, अक्टूबर १९५८ में यह ४८ प्रतिशत था।

इस वर्ष दामों के बढ़ने के डर से ऋण देने में काफी सावधानी बरती गयी और कई मदों के लिए ऋण देने पर नियंत्रण रखा गया। अनाज और चीनी के अलावा मूंगफली और तिलहनों पर भी ऋण देने में नियंत्रण रखा गया। इसी प्रकार बैंकों को आदेश दिया गया कि वे अधिक कारबार वाले दिनों में कच्चे माल और तैयार माल को रोके रखने के लिए अधिक ऋण न दें। रिजर्व बैंक ने यह प्रयत्न भी किया कि अनुसूचित बैंक रिजर्व बैंक से अधिक धन पाने की आशा न रखें। इसके लिए ऋण की सीमा पिछले साल के मुकाबले आधी कर दी गयी।

रिपोर्ट में बैंकों के नफे-नुकसान की समीक्षा की गयी है और कहा गया है कि भारत के उन २५ बड़े बैंकों को, जिनमें से प्रत्येक के पास ५ करोड़ रु० या अधिक जमा थी, इस वर्ष कुछ नफा ही रहा, यानी इनका शुद्ध लाभ पिछले साल से ३० लाख रु० बढ़कर ७.९ करोड़ रु० हो गया। १९५८ में ७.६ करोड़ रु० और १९५७ में ८.४ करोड़ रु० का लाभ हुआ था।

रिपोर्ट में परामर्श दिया गया है कि बैंकों को उद्योगों को मध्यम अवधि के लिए कर्ज देना चाहिए, क्योंकि पुनर्वित्त निगम भी ऐसी सुविधाएं दे रहा है। एक परामर्श के अनुसार भारतीय बैंकों को इस बारे में जाँच करनी चाहिए कि ग्राहकों को मिलने वाली किस सुविधा पर बैंकों को क्या खर्च करना पड़ता है और उसी हिसाब से उनसे वसूली करनी चाहिए। इसी तरह तीसरी पंचवर्षीय योजना की दृष्टि से भी कई प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए। इस काम में रिज़र्व बैंक भी हर तरह की सहायता करने को तैयार है।

सैनिक जहाजों का निर्माण

मजगांव गोदी का प्रबन्ध केन्द्रीय प्रतिरक्षा मंत्री, श्री कृष्णा मेनन को औपचारिक ढंग से सौंपा गया। ब्रिटिश जहाज-निर्माण मिशन के सुझावों के अनुसार मजगांव गोदी में लड़ाई के बड़े-बड़े समुद्री जहाज बनने लगेंगे। इसके पहले नौसेना के जहाजों की मरम्मत पर सरकार को काफी धन-व्यय करना पड़ता था। इससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होगी। भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन की इस महान समुद्री और औद्योगिक संस्था को अधिकार में लेने से देश के औद्योगिक विकास में नये अध्याय का सूत्रपात हुआ है।

मजगांव का गोदी पिछली शताब्दी में बना था। यह ३५ एकड़ में फैला है। इसमें दो सुखे गोदी हैं। एक में बड़े जहाज आ सकते हैं और दूसरे में बन्दरगाहों के छोटे जहाज। ६ स्लिपवेज हैं, जिनमें १५० टन के जहाज बनाए या मरम्मत किये जा सकते हैं। आशा है अब फारस की खाड़ी की अमेरिकी तेल कम्पनियों के ३०० टन के और रायल नौसेना के ५०० टन के और भारतीय बन्दरगाहों के कई प्रकार के जहाज बनने लगेंगे। यहाँ १०-२० अश्वशक्ति के कैम्पबेल इंजन भी बनते हैं। इस समय पश्चिमी बेड़े पर ३ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सेंचुरी मिल्स, बम्बई की

प्रसिद्ध फैशन फैब्रिक्स

● असली आरगंडी, ● लेक्स ब्यूटी मलमल

मोती वायल और फुल वायल

● परम सुख धोती ○ एम्बास्ड प्रिंट्स

सादी और धारीदार पापलीन

नित्य नवीन डिजाइनों में छपी हुई चमकदार छींट

लट्ठा, ड्रिल्स, चादरें, तौलिये,

काटन-वेस्ट, कम्बल आदि-आदि

नवीन आकर्षण

मिश्रङ्क—सेंचुराइज्ड शर्टिंग

पापलिन और ड्रेस मैटीरियल

निर्माता :

दी सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०

इंडस्ट्री हाउस, १५९ चर्चगेट रिक्लेमेशन

बम्बई—१

मैनेजिंग एजेंट्स : बिरला ग्वालियर प्रा० लि०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं

भारत में नया विशाल बिजली-घर

दामोदर घाटी में २,५०,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न करने वाले एक थर्मल (ताप) बिजलीघर की स्थापना की जायेगी।

इस विशाल कारखाने पर ७ करोड़ ३० लाख डालर (३४ करोड़ ८० लाख रु०) खर्च आयेगा और यह कलकत्ता से २०० मील पश्चिम की ओर चन्द्रपुरा में कायम होगा।

इस योजना के लिए ऋण की व्यवस्था अमेरिका के 'विकास ऋण कोष' से या सरकारी कानून-४८० के अधीन की जायेगी। इससे क्रमशः ३ करोड़ डालर (१४ करोड़ ३० लाख रुपये) और २० करोड़ ५० लाख रुपये की ऋण सहायता मिलेगी।

चन्द्रपुरा के बिजलीघर से लोहे व इस्पात और तांबे सीमेण्ट, रासायनिक द्रव्य, सूती वस्त्र तथा इंजिनियर के कारखानों को बिजली मुहैया की जाएगी।

यह बिजलीघर १८०० एकड़ भूमि में बनेगा और इसे दामोदर घाटी कार्पोरेशन के इंजिनियर बनायेंगे। उसके निर्माण-कार्य की देखरेख में न्यूयार्क की 'गिब्स एण्ड हिल' फर्म मदद करेगी। टर्बो जेनरेटर मंगाने के लिए न्यूयार्क की 'इन्टर नेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी' को आर्डर दे दिया गया है।

अनुमान है कि दूसरी ५-वर्षीय योजना की समाप्ति पर भारत के बिजलीघरों की कुल उत्पादन-क्षमता २३ लाख किलोवाट से बढ़कर ६४ लाख किलोवाट हो जाएगी। इस प्रकार विद्युत-उत्पादन में १७८ प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

इस्पात का आयात घटेगा

भारत में इस्पात का उत्पादन बढ़ जाने के फलस्वरूप चालू वर्ष में कुल ६ लाख टन इस्पात विदेशों से आयात किया जाएगा। सन् १९५९ में ७॥ लाख टन इस्पात का आयात किया गया था।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में पिण्ड लोह और इस्पात का उत्पादन होने लगा है। पिछले वित्तीय वर्ष में ७,७०,००० टन पिण्ड लोह तथा १,५०,००० टन इस्पात बनाया गया। निजी क्षेत्र के कारखानों में भी विस्तार का कार्यक्रम लगभग पूर्ण हो गया है और जमशेदपुर तथा बर्नपुर के कारखानों में सन् १९५९ में ५ लाख टन अधिक पिण्ड लोह तथा ४॥ लाख टन अधिक इस्पात बनाया गया। पिण्ड लोह का तो निर्यात भी किया जाने लगा है। इसके निर्यात से तथा इस्पात के आयात में कमी किए जाने से काफी विदेशी मुद्रा की बचत की आशा की जाती है।

कागज के नये कारखाने

भारत सरकार १३५ लघुस्तर के कागज का निर्माण करने वाले संयंत्रों की स्थापना करना चाहती है। इनकी स्थापना से देश में कागज का कुल कार्य करने के लिए उत्पादन काफी बढ़ जायगा। ६० संयंत्रों की देश में उत्पादन लाइसेंस दिये जा चुके हैं।

तीसरी योजना के लिए छोटे व बड़े समूचे कागज उद्योग के लिए ६,००,००० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसी आशा की जाती है कि प्रत्येक छोटे संयंत्र के लिए कागज की विशेष किस्म का निर्माण करने का काम अलग-अलग सौंपा जायगा। चालू योजना के लिए उत्पादन लक्ष्य अगले वर्ष पूरा हो जाने की आशा है। यह लक्ष्य ३,५०,००० टन का है। कागज की उत्पादन संख्या अब से १० वर्ष पूर्व की उत्पादन संख्या से १० गुनी अधिक है। यह संख्या २,१२,००० टन तक पहुँच गयी है। लेकिन कागज की माँग अभी भी बहुत अधिक है।

बिहार के ५९० गाँवों को बिजली

राज्य के ५९० गाँवों को बिजली देने का लक्ष्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जाएगा। मार्च, १९५९ तक कुल २३० गाँवों को बिजली मिल चुकी है; १९५९-६० की योजना के अंतर्गत ३० लाख रुपये की लागत से ११५ गाँवों को बिजली दी जानी थी। इस कार्य पर योजना के अन्तर्गत कुल १.५८ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा।

—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने 'कोबाल्ट—६०' गामा कृषिक विकिरणता संघटन 'गामा उद्यान' के नाम से

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कायम किया है। इससे फसल की किस्म में विविधता लायी जा सकेगी। कृषि नियंत्रण, खाद्य-संरक्षण आदि में भी इसका उपयोग हो सकेगा। गर्मी की फसलों, फलों के पौधों आदि पर 'कोबाल्ट—६०' का प्रयोग चल रहा है। यहाँ संस्थान के स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षण व्यवहारतः चला रहे हैं। यह अनुसंधान की सुविधा विश्वविद्यालयों, कृषि कालेजों और राजकीय कृषि विभागों को मिल सकेगी।

—एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बरौनी (बिहार) के पास सोगराहा गाँव में ७ लाख ६० हजार रुपये की लागत से एक मलाई, मक्खन और घी बनाने का कारखाना खोला जायगा। इस कारखाने में ४ हजार पौंड मक्खन रोज निकाला जायगा। मक्खन और घी की वार्षिक उत्पादन क्षमता ८ लाख पौण्ड की होगी। आशा है यह कारखाना १९६१-६२ में चालू हो जायगा।

—सहकारी ऋण समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी किसान को सहकारिता समिति से इसलिए ऋण देने से इंकार नहीं करना चाहिए कि उसके पास न भूमि है और न वह जमानतदार के रूप में किसी भू-स्वामी को ही पेश कर सकता है। आवश्यक यह है कि सहकारी समितियाँ किसानों को भी, उनके अदा करने की क्षमता और पर्याप्त जमानतदारों के आधार पर, जो अनिवार्य रूप से भू-स्वामी नहीं हो सकते, ऋण देती रहें।

—भिलाई इस्पात कारखाने में मई, १९६० में २१,५३८ टन इस्पात तैयार हुआ। इस प्रकार अब तक कुल १,३६,८७५ टन इस्पात तैयार हो चुका है।

—भारत सरकार की एक आज्ञा के अनुसार १ अगस्त १९६० से रूई के व्यापार पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिए जाएंगे। केवल सरकार द्वारा प्रमाणित मिलों को ही रूई बेची जा सकेगी और रूई के मूल्य तथा प्रकार भी एक विशेष कमेटी द्वारा नियुक्त किये जाएंगे।

—कॉफी बोर्ड की एक सूचना के द्वारा १९६०-६१ के उत्पादन में से ११,०७,००० किलोग्राम कॉफी के निर्यात की घोषणा की गई है।

—पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य के देहाती क्षेत्रों में संशोधित राशनिंग लागू करने का निश्चय किया है। इससे ९० लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे। कलकत्ता और राज्य के शहरी क्षेत्रों में यह राशनिंग व्यवस्था गत वर्ष से ही लागू है।

—एक जापानी फर्म दो भारतीय कम्पनियों के सहयोग से कागज बनाने वाले छोटे संयंत्रों की स्थापना करेगी। ये संयंत्र प्रतिदिन १ से ५ टन तक कागज का उत्पादन करने की क्षमता वाले होंगे।

आपका स्वास्थ्य

(हिन्दी की स्वास्थ्य सम्बन्धी श्रेष्ठ मासिक पत्रिका)

'आपका स्वास्थ्य' आपके परिवार का साथी है।

'आपका स्वास्थ्य' अपने क्षेत्र के कुशल डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है।

'आपका स्वास्थ्य' में अध्यापकों, अभिभावकों, माताओं और ग्रामीणों के लिए विशेष लेख प्रकाशित होते हैं।

आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक बनिए।

व्यवस्थापक

आपका स्वास्थ्य—बनारस-१

राजस्थान खादी संघ का मासिक मुखपत्र

राजस्थान खादी पत्रिका

खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय-भूदान पर अधिकारी विद्वानों के विचारपूर्ण लेख, खादी-आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी तथा अन्य सांख्यिकी परिशिष्ट आदि।

प्रधान सम्पादक : श्री जवाहिरलाल जैन

वार्षिक मूल्य ३) : एक प्रति २५ नये पैसे

राजस्थान खादी पत्रिका

पो० खादीबाग (जयपुर)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[पृष्ठ ३०९ का शेष]

पीसगुड्स मर्चेन्ट एसोसिएशन अपने कार्यालय में विदेशी कपड़ों का प्रदर्शन कर रहा है, ताकि भारतीय उत्पादक और निर्यातकर्ता यह जान सकें कि विदेशी उपभोक्ताओं की रुचि किस ओर बदल रही है और उसके अनुसार भारतीय वस्त्र उत्पादन और व्यापार में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। यह प्रदर्शन सूती-वस्त्र निर्यात परिवर्द्धन समिति, बम्बई की ओर से किया जाता है।

आंकड़ों का संग्रह और प्रसार

व्यापारिक संघों को अपने नित्य प्रति के काम में औद्योगिक और व्यापारिक आंकड़ों का काफी प्रयोग करना पड़ता है। महत्वपूर्ण आंकड़ों को वे दैनिक समाचार पत्रों, व्यापारिक पत्रिकाओं, सरकारी प्रकाशनों, वार्षिक डायरेक्ट्री (निर्देशिकाओं) आदि से एकत्रित करते हैं और आवश्यकतानुसार उनका विश्लेषण करके सदस्यों के बीच प्रसारित करते हैं। सरकारी विभागों के साथ लिखा-पढ़ी करते समय और सरकारी समितियों के प्रश्नों का जबाब देते समय भी इन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। बहुत से संघों ने इस कार्य को सुचारु रूप से करने के लिये छोटे पुस्तकालयों की व्यवस्था भी की है, जहाँ वे उपयोगी समाचार पत्र, व्यापारिक पत्रिकाओं तथा सरकारी प्रकाशनों को नियमितता से मंगवाते हैं।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सूती वस्त्र व्यापार में व्यापारिक संघों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मस्कती क्लाथ मार्केट एसोसियेशन, अहमदाबाद जैसे संघ अपनी दीर्घ कालीन सेवाओं और सुदृढ़ संगठन के कारण इतने प्रसिद्ध हो गये हैं कि उनके सदस्यों के विरुद्ध अन्य केन्द्रों के व्यापारी कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। इस एसोसियेशन की संगठित शक्ति का अनुभव करते हुए सरकार ने युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में नियंत्रित वस्त्र-वितरण का कार्य-भार उसी के ऊपर सौंप दिया था। इसी प्रकार दिल्ली मर्कैंटाइल एसोसियेशन वहाँ के थोक व्यापार का एक मजबूत स्तम्भ है। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे संघों ने वस्त्र व्यापार जगत् में सहयोग और सहकारिता की भावना को जागृत किया और यथासम्भव समाज की भी सेवा की है। बहुत सी सरकारी और शैक्षणिक संस्थाओं में इन संघों के भी प्रतिनिधि रखे जाते हैं। शिक्षा प्रसार और गरीबों की सहायता में भी ये पीछे नहीं रहे हैं।

ये पुराने संघ

साथ ही हमें यह मानना पड़ेगा कि वस्त्र व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ व्यापारिक संघ पुराने होते हुए भी अपने सदस्यों के लिये विशेष उपयोगी नहीं सिद्ध हुए हैं। बम्बई और मद्रास में काम करने वाले संघ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसका दोष इन संघों पर नहीं अपितु उनके सदस्यों पर ही डाला जा सकता है, क्योंकि उनमें से अनेक सदस्य पुराने विचारों और दूरदर्शिता के अभाव के कारण इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि बिना पारस्परिक सहयोग और सहायता के ये संघ कोई काम नहीं कर सकते।

यह गलत है कि ये संघ केवल विषम परिस्थितियों में ही लाभदायक हो सकते हैं। पर्याप्त सहयोग और साधनों के होने पर वे अपने सदस्यों की और भी कई प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी सुविधाएं व्यापारिक संघों के द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है, जिन्हें अकेला व्यापारी प्राप्त करने में असमर्थ होगा। ये संघ विदेशों से लब्धप्रतिष्ठ व्यापारियों को आमंत्रित कर सकते हैं, जो उनके सदस्यों को पाश्चात्य व्यापार पद्धति के नवीन सिद्धांतों से अवगत करायें। यह तो सभी मानेंगे कि भारतीय व्यापारी अब भी वैज्ञानिक व्यापार पद्धति से अनभिज्ञ हैं और अब वह समय आ गया है कि बिना उसके वे सफल नहीं हो सकते। हमारी राय में बड़े संघ वस्त्र-विक्रय के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करें ताकि थोक व फुटकर व्यापारी तथा उनके कर्मचारी विज्ञापन, विक्रय-कला, स्टाक नियंत्रण, विक्रय व्यय विश्लेषण, आदि के सिद्धांतों से परिचित हो सकें। सरकार को चाहिए कि वह सभी वस्त्र व्यापार केन्द्रों के व्यापारिक संघों को मान्यता प्रदान करे और वहाँ के व्यापारियों के लिये उनका सदस्य बनना अनिवार्य करे। ऐसी स्थिति में न केवल व्यापारिक संघ एक ठोस संगठन का रूप ग्रहण करेंगे, बल्कि उन व्यापारियों के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही करना सुगम होगा जो बाजार में अवांछनीय काम करते हैं या जो सरकारी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। ● ●

GURUKULA KANGRI LIBRARY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक समान सरल प्रणाली के लिए

देश भर में नाप-तौल की एक समान, सरल प्रणाली लागू करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

१ अक्तूबर, १९५८ को राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के कुछ चुने हुए इलाकों में मेट्रिक बाटों का प्रयोग चालू किया गया था। अब इस वर्ष, अक्तूबर मास से इन इलाकों में केवल मेट्रिक बाट ही कानूनी रूप से मान्य होंगे।

अप्रैल, १९६० से जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त बाकी सारे देश में भी मेट्रिक बाटों का प्रयोग चालू कर दिया गया है।

अप्रैल, १९६२ से देश भर में मेट्रिक बाटों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जायेगा।

मेट्रिक प्रणाली

सरलता व एकरूपता के लिए

भारत सरकार द्वारा प्रचारित

DA 60/86

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९५८ में भारत का समुद्री-व्यापार १४५५ करोड़ रुपये का हुआ था और इसका १० प्रतिशत करीब डेढ़ अरब रुपया जहाजी भाड़े में खर्च हुआ था। प्रतिवर्ष हमें करीब डेढ़ अरब रुपया जहाजी भाड़े के रूप में देना पड़ता है अर्थात्—

१० वर्ष में करीब १४ अरब रुपये

इस प्रकार भारत के लिए जहाजी उद्योग का महत्व स्पष्ट है! इसी महत्त्वपूर्ण उद्योग की प्रगति, स्थिति और विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए ही—

'सम्पदा' का वार्षिक विशेषांक

जहाज-उद्योग अंक

स्वतंत्रता दिवस—१५ अगस्त १९६० को प्रकाशित होगा!

सामग्री और रूप सज्जा दोनों ही दृष्टियों से यह विशेषांक 'सम्पदा' के अब तक प्रकाशित सब विशेषांकों से बढ़-चढ़ कर होगा।

विस्तृत विषय-सूची आगामी अंक में देखें। विशेषांक का मूल्य २.०० है; किन्तु स्थायी ग्राहकों को वार्षिक मूल्य—रुपये ८.०० में ही विशेषांक भी सुलभ होगा!

आज ही ८.०० रुपये भेजकर वार्षिक ग्राहक बन!

प्रसार विभाग • सम्पदा • २८/११ शक्तिनगर • दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा के अनूठे उपहार : ११ विशेषांक

'सम्पदा' का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विश्व-कोष ही होते हैं। प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम० कॉम० कहते हैं—'सम्पदा' के विशेषांक तो हमारे लिए गीता व बाइबिल के समान हैं।'

१-योजना अंक

(प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्व सामग्री)

एक प्रशंसनीय प्रयत्न। यह अंक पंचवर्षीय योजना को समझने की कुंजी है।

मूल्य : १.०० —जीवन साहित्य

२-भूमि-सुधार अंक

(भूमि समस्याओं का अद्भुत विवेचन)

इस विषय में अपने ढंग का अद्वितीय प्रकाशन है।

मूल्य : १.०० (अप्राप्य) —प्रताप

३-वस्त्र-उद्योग अंक

(भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं)

इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। सम्पादक को बधाई।

मूल्य : १.२५ —श्री घनश्यामदास बिड़ला

४-चम्बल अंक

(चम्बल योजना का विस्तृत परिचय)

अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है।

मूल्य : ००.७५ (अप्राप्य) —श्री मिश्रीलाल गंगवाल

५-मजदूर अंक

(मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन)

लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं। ···मानव की नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की संस्कृति व परम्पराओं के अनुकूल है।

मूल्य : १.२५ —श्री खंडूभाई देसाई

६-उद्योग अंक

(प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय)

भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याओं पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का अच्छा संग्रह है।

मूल्य : १.२५ —अजन्ता

७-राष्ट्रीय-विकास अंक

(द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन)

ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा।

मूल्य : १.२५ —श्री मोहनलाल सुखाड़िया

८-बैंक अंक

(भारतीयों बैंक की समस्याओं का निरूपण)

Here is one more 'Sampada' Special worth treasuring. (अप्राप्य)

मूल्य : १.२५ — Organiser

९-समाजवाद अंक

(समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार)

सम्पदा का समाजवाद अंक मिला। यह काफी अच्छा और पठनीय है।

मूल्य : १.५० —श्री श्रीमन्नारायण

१०-राष्ट्र-प्रगति अंक

(द्वितीय योजना काल की समस्याओं का विवेचन)

यह अति लाभदायक तथा उपयोगी है। लिखने का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है।

मूल्य : १.५० —श्री अमरनाथ विद्यालंकार

११-सहकारी कृषि अंक

देश के अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न पर विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण। —मू० १.५०

रजिस्ट्री से सब प्राप्य अंक मंगाने के लिए रु० १०.५० भेजिये।

सम्पदा • २८-११ शक्तिनगर • दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजस्थान हस्तकला का केन्द्र है

राजस्थानी कला के नमूने खरीदकर

घरों को सुशोभित कीजिए

तथा

गृह उद्योग को प्रोत्साहन दीजिए

GURUKULA KANGRI LIBRARY HARDWAR

हाथी दांत के खिलौने	कलापूर्ण सामान
लाख व नगीनों के कंगन	नीले व सफेद पाटरी के सामान
बँधाई व छपाई के स्कार्फ	आकर्षक नमूने की दरियां
जोधपुर की बनी शीतल जल की झारियां	सांगानेरी रंगाई व छपाई के वस्त्र इत्यादि
चन्दन की लकड़ी के खिलौने	उदयपुर के लकड़ी के खिलौने
रंगीन एवं बँधेज की साड़ियाँ	जयपुर की कसीदा की हुई जूतियाँ व जूते
पक्के रंग की चादरें	जयपुर की प्रसिद्धि प्राप्त चूड़ियाँ व चूड़े
लकड़ी एवं खस की बनी वस्तुएं	कोटा के सुन्दर डोरिये

प्रत्येक सरकारी विक्रय केन्द्र पर प्राप्त । राजस्थानी हस्तकला के नमूने अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं ।

राजस्थान हैन्डी क्राफ्ट्स एम्पोरियम
क्वीन्सवे लेन, नई दिल्ली

राजस्थान हैन्डी क्राफ्ट्स एम्पोरियम
जयपुर, जोधपुर व उदयपुर

राजस्थान राज्य द्वारा प्रसारित

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली से मुद्रित व अशोक प्रकाशन मन्दिर २८/११, शक्तिनगर दिल्ली-६ से प्रकाशित ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

अर्थशास्त्र की नवीनतम
गतिविधियों की
मासिक पत्रिका

जुलाई १९६०

मूल्य
७५ न.पै.

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

QUICK TRANSIT SERVICE

Delivers the Goods in Guaranteed Time

Some of the important services now operated by the Central Railway are shown below :

Wadi Bandar	to	Shalimar	8	days
,, ,,	to	Tata Nagar	7	,,
,, ,,	to	Nagpur	3	,,
,, ,,	to	Salt Cotaurs	6	,,
,, ,,	to	Adoni	5	,,
,, ,,	to	Yerraguntla	5	,,
,, ,,	to	Bangalore City	5	,,
,, ,,	to	Kolhapur	3	,,
,, ,,	to	Kanpur	5	,,
,, ,,	to	Bezwada	6	,,
,, ,,	to	Secunderabad	3	,,
,, ,,	to	Hyderbad	4	,,
,, ,,	to	Sholapur	2	,,
,, ,,	to	Akola	2	,,
,, ,,	to	Amraoti	3	,,
,, ,,	to	Jabalpur	4	,,
,, ,,	to	Satna	5	,,
,, ,,	to	Bhopal	4	,,
,, ,,	to	Gwalior	5	,,
,, ,,	to	Lucknow	7	,,
,, ,,	to	Allahabad	7	,,
,, ,,	to	Varanasi	8	,,
,, ,,	to	Patna	9	,,
,, ,,	to	Howrah	12	,,
Poona	to	New Delhi	6	,,
,,	to	Shalimar	7	,,
Sholapur	to	Bezwada	4	,,
,,	to	Salt Cotaurs	5	,,
,,	to	New Delhi	5	,,
,,	to	Shalimar	7	,,

Its Quicker and Safer by Rail

For further particulars please contact :

The Goods Superintendent,
Wadi Bandar

CENTRAL RAILWAY

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस अंक में :

क्या साधन जुटा सकेंगे ? अग्रलेख ३४५
टिप्पणियां ३४७
तीसरी योजना की प्रस्तावित रूपरेखा ३५१
विकास योजनाओं के प्रथम १० वर्ष ३५६
कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न चि० देशमुख ३६३
सरकारी उद्योगों में निजी पूंजी कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ३६४
श्रम समस्या ३६६
सन्तति निरोध विवेचक ३६७
भारत-अमेरिकी सहयोग सी० टायल वुड ३६६
अर्थ वृत्त चयन ३७१
हमारे उद्योग ३७४
राज्यों की आय के स्रोत ३७६
सर्वोदय पृष्ठ ३७७
नया निर्माण ३७८
विदेशी अर्थ चर्चा ३८०
नया साहित्य ३८१
मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं ३८२

• • •

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

संयुक्त सम्पादक : भीमसेन त्यागी

4th-11th SEPTEMBER 1960

LEIPZIG TRADE FAIR

International Display of Consumer Goods of Every Kind

Exhibits from 45 different countries for comparison

An ever growing volume of East-West Trade

Direct flights · Reduced fares by train over the continent
Literature from all leading travel agencies

For details contact :

LEIPZIG FAIR AGENCY
P.O. Box No. 1993, BOMBAY 1
D-17, Nizamuddin East, NEW DELHI 13
34-A, Brabourne Road, CALCUTTA 1.
"Lomond", 46, Harrington Road, MADRAS 31

Further information and free advice on sources of supply from :

Leipziger Messeamt
Hainstr. 18 a · Leipzig C 1
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा के अनूठे उपहार : ११ विशेषांक

'सम्पदा' का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विश्व-कोष ही होते हैं। प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम० कॉम० कहते हैं—'सम्पदा' के विशेषांक तो हमारे लिए गीता व बाइबिल के समान हैं।'

१-योजना अंक

(प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्व सामग्री)

एक प्रशंसनीय प्रयत्न। यह अंक पंचवर्षीय योजना को समझने की कुंजी है।

मूल्य : १.०० —जीवन साहित्य

२-भूमि-सुधार अंक

(भूमि समस्याओं का अद्भुत विवेचन)

इस विषय में अपने ढंग का अद्वितीय प्रकाशन है।

मूल्य : १.०० (अप्राप्य) —प्रताप

३-वस्त्र-उद्योग अंक

(भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं)

इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। सम्पादक को बधाई।

मूल्य : १.२५ —श्री घनश्यामदास बिड़ला

४-चम्बल अंक

(चम्बल योजना का विस्तृत परिचय)

अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है।

मूल्य : ००.७५ (अप्राप्य) —श्री मिश्रीलाल गंगवाल

५-मजदूर अंक

(मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन)

लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं। ···मानव की नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की संस्कृति व परम्पराओं के अनुकूल है।

मूल्य : १.२५ —श्री खंडूभाई देसाई

६-उद्योग अंक

(प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय)

भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याओं पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का अच्छा संग्रह है।

मूल्य : १.२५ —अजन्ता

७-राष्ट्रीय-विकास अंक

(द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन)

ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा।

मूल्य : १.२५ —श्री मोहनलाल सुखाड़िया

८-बैंक अंक

(भारतीय बैंकों की समस्याओं का निरूपण)

Here is one more 'Sampada' Special worth treasuring. (अप्राप्य)

मूल्य : १.२५ —Organiser

९-समाजवाद अंक

(समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार)

सम्पदा का समाजवाद अंक मिला। यह काफी अच्छा और पठनीय है।

मूल्य : १.५० —श्री श्रीमन्नारायण

१०-राष्ट्र-प्रगति अंक

(द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का विवेचन)

यह अति लाभदायक तथा उपयोगी है। लिखने का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है।

मूल्य : १.५० —श्री अमरनाथ विद्यालंकार

११-सहकारी कृषि अंक

देश के अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न पर विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण। —मू० १.५०

रजिस्ट्री से सब प्राप्य अंक मंगाने के लिए रु० १०.५० भेजिये।

सम्पदा • २८-११ शक्तिनगर • दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

वर्ष ६
अंक ७
जुलाई १९६०

अर्थशास्त्र की नवीनतम गतिविधियों की मासिक पत्रिका

क्या साधन जुटा पाएंगे ?

तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा गत सप्ताह प्रकाशित हो गई। इससे प्रकट है कि यह योजना कितनी बृहदाकार होगी। पहली तथा दूसरी योजनाओं के सम्मिलित लक्ष्यों से भी इसका ऊँचा लक्ष्य है। पहली दो योजनाएं क्रमशः २३ और ४८ अरब रु० की थी, तीसरी योजना १०२ अरब रुपए की है।

विकास योजना के लक्ष्य ऊँचे होते जायं यह स्वाभाविक है। बालक के बड़ा होने के साथ-साथ उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। उसे अधिक बड़े कपड़े, खेलकूद के सामान, बड़ी से बड़ी पुस्तकें तथा अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिक सामग्री चाहिए। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३॥ प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी, दूसरी योजना में ४॥ प्र० की वृद्धि हुई और अब स्वभावतः ५॥ प्र० वृद्धि की आकांक्षा की गई है। राष्ट्रीय आय में इस वृद्धि के लिए यह भी स्वाभाविक है कि विकास योजनाओं में अधिकाधिक व्यय किया जाय। इसी दृष्टि से प्रस्तावित योजना में ७२५० करोड़ रुपया जुटाने की योजना बनाई गई हैं। शेष राशि निजी उद्योग लगाएंगे, यह आशा की गई है। हम इन पंक्तियों में योजना के इन साधनों की संभावनाओं पर कुछ विचार करना चाहते हैं क्योंकि उत्पादन के ऊँचे लक्ष्यों की पूर्ति इन्हीं साधनों पर निर्भर है।

अन्यत्र प्रकाशित तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा कि योजना आयोग की दृष्टि में रुपये जुटाने के लिए कौन-कौन से साधन सुझाये गये हैं।

प्रशासन पर बढ़ता व्यय

जिन आशाओं के साथ आयोग ने उपर्युक्त साधनों का अनुमान किया है, हमें भय है कि उसकी वे आशाएं पूर्ण नहीं होंगी। सबसे पहले राजस्व से बचनेवाले धन की राशि ३५० करोड़ रुपया कूती गई है। दूसरी योजना के सम्बन्ध में सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, इसका नाम था 'प्रशासकीय योजनेत्तर व्यय में वृद्धि' इसके अनुसार विभिन्न नए करों से ४२० करोड़ रुपये की आय का अनुमान किया गया था, किन्तु वह आय ७६२ करोड़ रुपया हुई। यदि यह आय योजना के विकास कार्यों में लगती तो निस्सन्देह बहुत लाभ होता, किन्तु अत्यन्त खेद के साथ यह देखा गया कि योजनेत्तर प्रशासकीय व्यय बहुत अधिक बढ़ गया। २३२६ करोड़ रुपये के अनुमान के स्थान पर २६३२ करोड़ रुपये व्यय हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि विकास कार्यों के लिए साधारण राजस्व में से बहुत कम रुपया मिल सका। नये करों से होनेवाली आय शासन कार्य में ही व्यय हो गई। १६५०-५१ में शासन के अनेक मुख्य विभागों पर केवल २२·०५ करोड़ रुपया व्यय हुआ था। १६५८-५६ में यह व्यय बढ़कर ५२·४० करोड़ रुपया हो गया अर्थात् करीब ८० प्रतिशत प्रशासन व्यय बढ़ गया। केन्द्रीय सरकार की जो स्थिति है, वही राज्य सरकारों की भी है। आगामी योजना की अवधि में शासन व्यय नहीं बढ़ेगा और प्रशासन व्यय में कमी की जायगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वेतन-वृद्धि और हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। कुछ भी झुकने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पर सरकार का करोड़ों रुपया व्यय बढ़ सकता है। इन सब बातों को देखते हुए हम योजना आयोग के आशावाद में सहयोगी नहीं बन सकते।

कुछ अन्य स्रोत

वर्तमान आधार पर रेलों से मिलनेवाले धन के सम्बन्ध में शायद किसी का मत-भेद नहीं होगा। पिछले दिनों में सरकार ने सरकारी उद्योगों में उत्पन्न माल की कीमत निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों का परामर्श लिया था। उनकी राय थी कि मूल्य लाभ की दृष्टि से रखने चाहिएं। नए-नए सरकारी उद्योग अभी पनप रहे हैं, इसलिए इनसे ४४० करोड़ रुपए का अनुमान केवल कारखानों की उत्पादन क्षमता के आधार पर लगाया गया होगा। इस सम्बन्ध में व्यावहारिक अनुभव ही बताएगा कि यह अनुमान कहाँ तक सत्य है। सार्वजनिक ऋणों से ८५० करोड़ रुपए की आशा की गई है और इसके पूर्ण होने की काफी संभावना है। जब-जब सरकार ने कोई ऋण लिया है, वह नियत अवधि से कम में भी पूरा हो गया है।

अल्प बचत

लेकिन अल्प बचतों से की गई आशा पूर्ण होने में हमें सन्देह है। यह ठीक है कि राष्ट्रीय आय की अधिकाधिक वृद्धि के कारण बचत में भी वृद्धि की आशा की जा सकती है और यही आशा योजना आयोग ने भी की है। योजना आयोग के अनुसार तीसरी योजना के अन्तर्गत बचत को ११ प्रतिशत करना होगा लेकिन देश में बढ़ती हुई महंगाई और स्टैण्डर्ड आफ लिविंग को बढ़ाने के लुभावने मोह बचत को कहां तक बढ़ने देंगे, यह विचारणीय प्रश्न है। पिछली योजनाओं का अनुभव यह बताता है कि बचत के लक्ष्य कभी पूरे नहीं हुए। और जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं वे भी वास्तविकता को प्रकट नहीं करते। बहुत से लोग सरकारी अफसरों के दबाव में आकर रुपये जमा कर देते हैं और वर्ष समाप्त होते ही रुपया निकाल लेते हैं। आजकल प्रायः उद्योगों में प्रोवीडेन्ट फंड की व्यवस्था अधिकाधिक चालू होती जा रही है और सरकारी विभागों में भी इसे ज्यादा प्रचलित किया जाने लगा है, इसलिए भविष्य निधि आदि से मिलने वाले धन के सम्बन्ध में योजना आयोग के अनुमान करीब-करीब ठीक हो सकते हैं।

नये कर

योजना आयोग ने आय के बड़े साधन के रूप में सरकारी उद्योगों के साथ अतिरिक्त करों से १६५० करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान लगाया है। आजकल करों से राष्ट्रीय आय का लगभग ८.५ प्रतिशत मिलता है। आयोग ने अतिरिक्त कर बढ़ा कर इस संख्या को ११ प्रतिशत कर लगाने का अनुमान किया है। इस कर राशि में से एक तिहाई कर राज्य लगाएंगे। अंग्रेजी की एक कहावत के अनुसार ऊंट की पीठ पर घास का अन्तिम तिनका रखा जा चुका है। अब और कर लगाने की गुंजाइश कैसे निकलेगी? पिछले दिनों में इस प्रश्न पर देश के अर्थशास्त्रियों ने पर्याप्त विचार किया है। उनकी सम्मति यह है कि समय आ गया है जबकि देश के विकास में देहाती जनता का भी पूर्ण योगदान मिलना चाहिए। इसलिए मालगुजारी आदि के बीस-पच्चीस साल पुराने दरों में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य करनी चाहिए। और विशेषकर तब, जब कृषि पदार्थों के मूल्य चार गुना बढ़ चुके हैं। हम इस सिद्धांत से सहमत हैं, किन्तु इसकी व्यावहारिकता में हमें सन्देह है। आज की वोट लेनेवाली राजनीति में किसानों को छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। भूमि विकास कर के विरोध में हुए उनके संघर्ष इसके प्रमाण हैं। विभिन्न राजनीतिक तत्व अपने-अपने स्वार्थ के लिए किसानों और जनता में असन्तोष पैदा करने में संकोच नहीं करेंगे। व्यापार उद्योग पर भी करों का भार पहले ही अधिक है और ज्यादा कर लगाने से पूंजी निर्माण में कमी आने का खतरा है। यही देखकर पिछले वर्षों में कोई-कोई कर कम भी किये गये हैं। आय कर में छूट की मात्रा को और कम कर देना भी मध्यवित्तीय जनता में असंतोष उत्पन्न करेगा। बिक्री कर में विरोध के बावजूद वृद्धि की संभावना अवश्य है।

विदेशों से जिस रूप में सहायता मिल रही है, वह काफी उत्साहवर्द्धक है और इसलिए इससे २२ सौ करोड़ रुपए की आशा पूर्ण होना कठिन नहीं है।

मुद्रा प्रसार

मुद्रा प्रसार महंगाई को बढ़ाता है इस सत्य को योजना आयोग ने स्वीकार कर लिया है। इसीलिए दूसरी योजना

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की अपेक्षा करीब ५० प्रतिशत ही मुद्रा प्रसार करने का विचार किया गया है। इससे महंगाई अपेक्षाकृत कम बढ़ेगी और यदि अनुमान के अनुसार उत्पादन भी बढ़ता गया तो शायद महंगाई न बढ़े।

ऊपर की पंक्तियों में हमने संक्षेप से तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित आय साधनों पर संक्षिप्त दृष्टि डाली है। आगे के पांच वर्ष बताएँगे कि हम साधन जुटाने में कहां तक सफलता प्राप्त करते हैं और कहां तक असफलता? ● ●

हड़तालें कैसे रुकें !

इस अंक के पाठकों तक पहुँचते-पहुँचते यह सबको मालूम हो जाएगा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल कहां तक सफल या असफल हुई? इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री पण्डित नेहरू का सन्देश हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं। हम उनके विचार से सहमत हैं कि इस हड़ताल का प्रस्ताव उत्तरदायित्वहीन, हानिकारक और देश पर हमला है; किन्तु हम यहां इस प्रश्न के दूसरे पहलू पर विचार करना चाहते हैं।

हड़तालों की भावना के फैलने के दो कारण हैं : एक तो यह कि कुछ राजनीतिक तत्त्व देश में अराजकता देखना चाहते हैं; किन्तु इससे भी बड़ा कारण यह है कि सरकारी और गैरसरकारी, शिक्षित और अशिक्षित कर्मचारियों में राष्ट्रीयता का अभाव है और इस कारण थोड़ा-सा भी कारण उपस्थित होने पर इनका असन्तोष उग्र रूप धारण कर लेता है। इसमें सन्देह नहीं कि आज देश में अनेक अवांछनीय परिस्थितियाँ असन्तोष को जन्म दे रही हैं।

इसलिए जहाँ हमें प्रतिगामी और अराष्ट्रीय तत्त्वों का दमन करना चाहिए वहाँ असन्तोष के मूल कारणों को भी दूर करना चाहिए; ताकि साधारण जनता उन तत्त्वों के चक्कर में आने से बची रहे। असन्तोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। एक तो अपनी आर्थिक परिस्थिति से और दूसरे अपने से ऊँचे वर्ग को सुखी देखकर मानसिक असंतुलन उत्पन्न होने से। इन दोनों कारणों को दूर किए बिना निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में हड़तालों की सम्भावनाओं को दूर नहीं किया जा सकता। असन्तोष का प्रधान कारण महंगाई है। जिस तरह भी हो महंगाई को दूर करना होगा। महंगाई को दूर करने के लिए अन्न का अतिरिक्त उत्पादन जरूरी है। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अगर आवश्यकता हो तो तम्बाकू और गन्ने आदि की खेती पर कुछ प्रतिबन्ध भी लगा देने चाहिएं; और इस तरह उपलब्ध भूमि पर अनाज बोना चाहिए। देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम करने का खतरा उठाकर भी वस्त्र आदि के असीम प्रयोग को कम करने की भावना उत्पन्न की जाए। गाँवों में वस्त्र स्वावलम्बन के प्रयोग से कपड़ा कुछ सस्ता हो सकता है। मुद्रा-प्रसार को यथासंभव कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, भले ही कुछ आवश्यक खर्चीली योजनाएँ छोड़नी पड़ें। महंगाई दूर होने से असंतोष की मात्रा भी कुछ कम होगी।

असन्तोष को दूर करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक उपायों का भी प्रयोग करना होगा। भारत ने समाजवाद के लक्ष्य को अपनाया है, इसके लिए यह कदम अनिवार्यरूप से उठाना चाहिए कि ऊँचे अधिकारियों के वेतनों में यदि आज कटौती संभव न हो, तो भी आगामी पांच वर्षों तक वार्षिक वेतन वृद्धि बिल्कुल रोक देनी चाहिए। जब सरकारी अधिकारी यह आदर्श पेश करेंगे तो निजी संस्थानों को भी इसके लिए प्रेरित किया जा सकेगा। यह कदम निश्चित रूप से कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा। उन्हें यह विश्वास हो जाना चाहिए कि सरकार सचमुच विषमता कम करने के समाजवादी लक्ष्य में विश्वास करती है। देश हित की भावना को सर्वोपरिता देनी चाहिए। किसी उद्योग में संचालक या प्रबन्धकर्ता और कर्मचारी ही दो अंग नहीं है। इन दोनों से ऊपर जनता है, जिसका हित सर्वोपरि होना चाहिए। संचालकों और मजदूरों, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह जनहित को आंखों से ओझल करके केवल अपना स्वार्थ साधन करे।

म०प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य

भारत की आर्थिक प्रगति की समय-समय पर जाँच पड़ताल के लिए एक संस्था बनी हुई है, इसका नाम है—नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च। यह भिन्न-भिन्न स्थानों की आर्थिक गति-विधि की जाँच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट देती है। बिहार के सम्बन्ध में यह अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर चुकी है। और अब इसने

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मध्यप्रदेश के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट बहुत मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है।

उक्त कौंसिल के अनुमान के अनुसार आज मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय २८७ रुपये है यह आय अखिल क्षेत्रीय औसत से ९ रुपये कम है। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश गरीब कहा जा सकता है, किन्तु उक्त कौंसिल ने भी बताया है कि यदि आगामी १० वर्षों में २०९० करोड़ रुपये का प्रस्तावित व्यय मध्यप्रदेश में विकास योजनाओं पर किया जाए, तो १९७१ तक ४२७ रुपये प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। इस उज्ज्वल भविष्य की कल्पना इसी से की जा सकती है कि यह आय तत्कालीन अखिल देशीय आय से १७ रुपये ज्यादा होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कुल देश को विकास योजनाओं के कारण १० वर्ष में प्रति व्यक्ति आय १२४ रुपये बढ़ेगी, तब मध्यप्रदेश में यह आय १५० रुपये बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि २०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय अवश्य किया जाए।

नये उद्योगों की संभावना

मध्यप्रदेश में आय में इतनी अधिक वृद्धि की संभावना इसलिए की गई है कि वहाँ नये-नये उद्योगों की संभावना के कारण प्रति व्यक्ति विकास व्यय भी दुगुना हो जाने की संभावना है। बिहार में इस तेजी से नये उद्योग खुलने की संभावना नहीं है।

बिहार की एक कमज़ोर उसकी कृषि में है। वह कृषि की दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं है। अपने उद्योगों के लायक कच्चा माल भी वहाँ उपलब्ध नहीं होता। इसीलिए उक्त कौंसिल ने बिहार को यह सलाह दी है कि वह अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना का ४४ प्रतिशत कृषि विकास पर व्यय करे। इसके विपरीत मध्यप्रदेश में यद्यपि भूमि की उत्पादन शक्ति अन्य राज्यों से कम है, फिर भी वह न केवल अन्न की दृष्टि से स्वावलम्बी है, अन्य राज्यों को भी अनाज देता है। मध्यप्रदेश की औद्योगिक संभावनाएं कल्पनातीत हैं। भिलाई के कारखाने के साथ वहाँ अनेक सम्बद्ध उद्योग सफलतापूर्वक चल सकते हैं। बिजली की मशीनरी का कारखाना पहली जुलाई से बिजली की मशीनरी बनाना शुरू कर रहा है। यह कारखाना देश में पहला और एशिया में अपने किस्म का सबसे बड़ा कारखाना है। बिजली की छोटी बड़ी मशीनरी, मोटरें, बिजली गाड़ियों के यन्त्र आदि सब यहाँ बनेंगे। तीसरी योजना के अन्त तक १७ किलोवाट तक और चौथी योजना

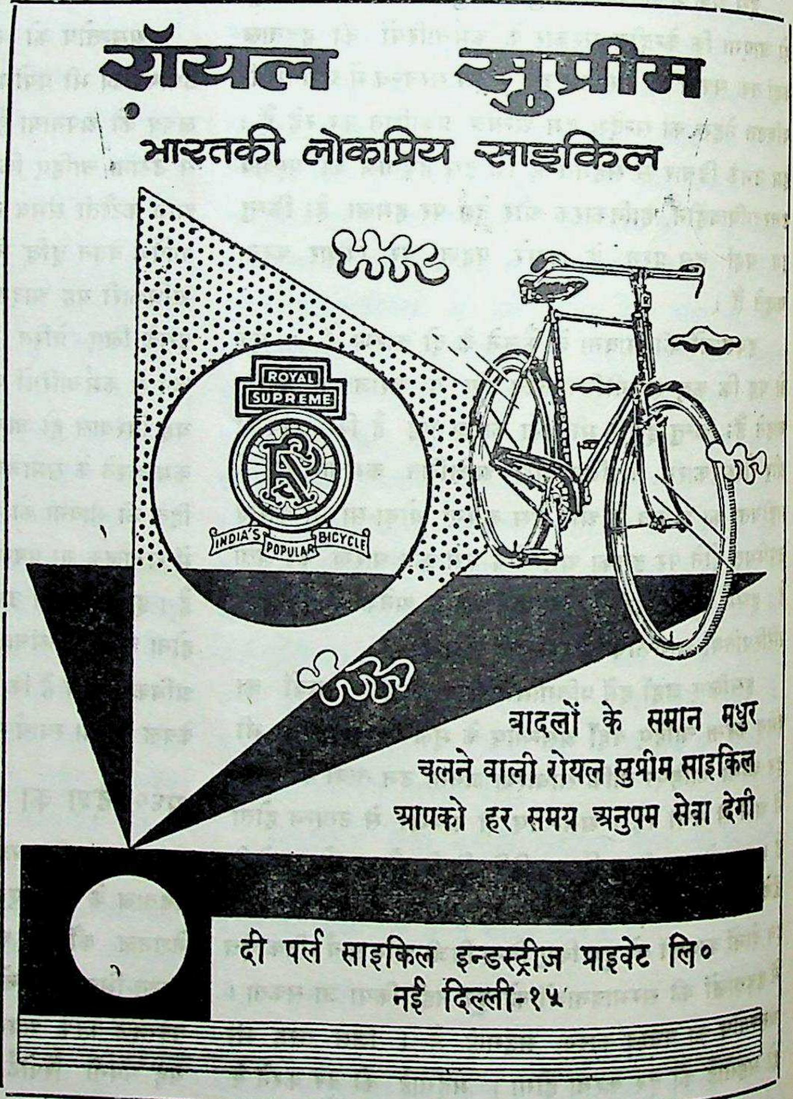

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

के अन्त में २० लाख किलोवाट तक बिजली तैयार करने की मशीनें तैयार होने लगेंगी ।

भिलाई के कारखाने और उससे सम्बद्ध कोयले की खानों में बड़ी तेजी से काम हो रहा है। नेपा का कागज का कारखाना बहुत शीघ्र अपना विस्तार कर लेगा। रासायनिक खाद, अन्य रासायनिक द्रव्य तथा अल्मूनियम आदि उद्योगों में भी बहुत विस्तार की संभावना है।

मध्यप्रदेश ऐसा भाग्यशाली राज्य है, जहाँ न जनसंख्या की समस्या विकट है और न बेकारी की। जब मध्यप्रदेश समृद्ध होने लगेगा, तब यह भी स्वाभाविक है कि अन्य राज्यों से भी बहुत लोग वहाँ आकर बसने लगेंगे।

राष्ट्रपति का त्याग

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने अपने निर्धारित दस हजार रु० मासिक वेतन को कम करके ढाई हजार रुपए कर दिया है। उनके इस त्याग का हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि उसमें राज्यपालों, मंत्रिमंडलों तथा ऊँचे अधिकारियों को इस त्याग का अनुसरण करने की आवश्यकता है। हम ऊपर लिख चुके हैं कि इस त्याग का हड़ताल की प्रवृत्ति पर भी असर पड़ेगा। समाजवाद को जिसकी घोषणा हम बार-बार करते हैं, निकट लाने के लिए यह कदम अत्यन्त आवश्यक है। आचार्य विनोबा ने भूदान-यज्ञ का प्रवर्तन किया है, अब बड़े-बड़े नगरों में वेतन-दान-यज्ञ करने की आवश्यकता है। जिन लोगों के वेतन एक नियत राशि से अधिक हों, उसका एक निश्चित भाग राष्ट्र को अर्पित कर दिया करें। इससे देश के वातावरण में सुधार होगा।

यूरोपीय व्यापारिक संघों का समझौता

'सम्पदा' के पाठक यूरोप के ६ या ७ राष्ट्रों के संघों से परिचित हैं। इन संघों के सदस्यों ने अपने-अपने गुट में परस्पर मिल कर आर्थिक प्रतिबन्धों को दूर करने और औद्योगिक विकास करने का निश्चय किया है। ७ राष्ट्रों के संघों ने आस्ट्रियां, डेनमार्क, नार्वे, पुर्तगाल, स्वीडन और ब्रिटेन, अपने इस राष्ट्रीय संघ का नाम, 'यूरोपियन फ्री ट्रेड ऐसोसियेशन' रखा है। गत प्रथम जुलाई से इनका समझौता अमल में आने लगा है और सदस्य देशों ने एक दूसरे के तटकरों में २० प्रतिशत की कमी कर दी है। इस संघ के उद्देश्य आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, साधनों का समझदारी से प्रयोग, आर्थिक स्थिरता तथा जीवन स्तर की उन्नति है। विचार यह है कि दस वर्षों तक क्रमशः कमी करते हुए तटकर समाप्त कर दिए जाएं। समझौते के अनुसार उपरोक्त देश गैरसदस्य देशों से व्यापार करने में नीति का स्वयं निर्धारण कर सकेंगे।

भारत की अणु-उत्पादन प्रगति

ट्राम्बे का दूसरा 'री एक्टर' जो कनाडा और भारत के सहयोग से बना है, चालू हो गया है। यह एशिया में सबसे बड़ा 'री एक्टर' है। भारत का यह प्रथम न्यष्ठि यंत्र-अप्सरा १९५६ में चालू हुआ था, दूसरे यंत्र पर दस करोड़ रुपया खर्च हुआ। इससे आइसोटोप तथा वैज्ञानिक और भौतिक शोध के लिए बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। एक तीसरा 'री एक्टर' ज़ैरलीना भी कुछ महीने में चालू हो जायगा। इन सब री एक्टरों से भारत अणु शक्ति के विकास में बहुत ऊँचा उत्पादन कर सकेगा। ● ●

स्वास्थ्य सम्बन्धी हिन्दी का प्रतिनिधि मासिक

स्वस्थ जीवन

प्रधान सम्पादक : राधाकृष्ण नेवटिया
प्रबन्ध सम्पादक : धर्मचन्द सरावगी

● स्वास्थ्य-सम्बन्धी कहानी, कविता, संस्मरण, डायरी, रिर्पोताज़, ललित लेख, नारी लोक, बाल जगत, समीक्षा, आपका पृष्ठ आदि रोचक स्तम्भ।

● लेखक बन्धु अपनी नयी कृतियाँ भेजकर हमें सहयोग दें—विज्ञापक बन्धु विज्ञापन दे कर लाभ उठावें—एजेण्ट इस बहुचर्चित पत्र की एजेन्सी लेना न भूलें।

एक प्रति : पचास नए पैसे मात्र
वार्षिक : पांच रुपए मात्र

कार्यालय : जैन हाउस
८/१ एस्प्लेनेड स्ट्रीट
कलकत्ता—१

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हड़ताल देश पर हमला

जवाहरलाल नेहरू

केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल से पूर्व राष्ट्रनायक श्री नेहरू ने देश को जो चेतावनी दी उससे स्पष्ट है कि यह हड़ताल कितना बड़ा खतरा सिद्ध हो सकती थी ? चेनावनी के विशेष अंश यहाँ प्रस्तुत हैं।

हिन्दुस्तान के सामने जो खतरा है, क्या हड़ताली उसे भूल गये हैं ? शायद उन्होंने सोचा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें मातृभूमि से कोई प्रेम हो और उनमें कोई राष्ट्रीयता न हो। कुछ लोग शायद ऐसे भी हैं, जो देश को कमजोर करना चाहते हों। मगर आम तौर से लोग ऐसे नहीं हो सकते। जहां देश के भविष्य का प्रश्न हो, वहां कोई दुकानदारी नहीं चल सकती।

असल में हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान के रहने वालों के सामने यह सवाल है कि हम कायम रहें या नहीं। मुझे यकीन नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी इन बुनियादी बातों को भूल जाएं।

मेरी राय में जहां हमारे बड़े सवाल हैं, भारत के भविष्य का सवाल सामने है, वहां कोई बहस नहीं हो सकती। ऐसी जनरल स्ट्राइक से खतरनाक धक्का मुल्क को लगेगा। आप सोचें कि हमारे सिपाही पहाड़ों में खतरे की जगह खड़े हैं। क्या हम उनको खाना और जरूरत का सामान भेजना बन्द कर दें ? यही नतीजा हो सकता है यदि स्ट्राइक कामयाब हो। मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह जहां जरूरत है, खाने का सामान नहीं भेज सकते। यह हमारे लोगों के लिए कोई खिदमत होगी ? क्या हम कोयला भेजना बन्द कर दें, जिससे हमारे बड़े-बड़े कारखाने चलते हैं; और खेती का सामान भी भेजना रोक दें ? क्या कोई भी बहस इन बातों को जायज़ कह सकती है ?

अभी हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का एक मसविदा निकला है। क्या हमारा जवाब इन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए यह है कि हम अपनी सारी मेहनत को खराब करने की कोशिश करें और हमारे जो ख्वाब हैं, उनको और भी दूर कर दें। यह कोई मामूली स्ट्राइक नहीं, जैसी कि उद्योग-धंधों में होती है। यह सारे मुल्क पर, सारी कौम पर, सब लोगों पर हमला है। कोई भी इस किस्म की हड़ताल को ठीक नहीं कह सकता। यह जनरल स्ट्राइक इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट या ट्रेड यूनियन डिसप्यूट (कारखानों के मजदूरों के झगड़े) जैसी नहीं है। उससे बिल्कुल अलग है।

मांग क्या है ?

पे कमिशन ने कम से कम तनखा १० रुपए बढ़ा कर ८० रु० करदी है, और कर्मचारियों के लिए जो फायदे सुझाये हैं, उन्हें भी स्वीकार किया है। हमारी गवर्नमेंट को इन पर सालाना ४०-५० करोड़ रु० खर्च करना पड़ गया है और यदि और मांगें, जो की जा रही हैं, उन्हें मंजूर कर लें तो ८० से १०० करोड़ रु० सालाना खर्च बढ़ जाएगा। इसके अलावा राज्यों के कर्मचारियों की तनखा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से कम है, उन पर भी इसका असर पड़ेगा। इस तरह से १५० करोड़ रु० सालाना खर्च बढ़ जाएगा। इस हिसाब से पांच साल में ७०० करोड़ रु० खर्च बढ़ जाएगा। यह हो सकता है ! सारी योजनाएं बननी खत्म हो जाएं। यह भी याद रखें कि दो मोटी बातों पर जो पे कमीशन ने सिफारिश की है, उससे आगे बढ़ कर कुछ दिया गया, तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा हो सकता है, जिससे वेतन-मजदूरी के बढ़ाने से जो लाभ मिलेगा, वह भी कम हो जाएगा। जो देश के साधन होंगे, उन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं, जिससे न केवल सरकारी कर्मचारियों की बल्कि अन्य लोगों की भी अधिक भलाई होगी। हम समझते हैं कि कर्मचारियों की भलाई गवर्नमेंट का फर्ज है साथ ही यह भी कि उनका लाभ तो हो, लेकिन इस लाभ से देश का नुकसान कतई न हो। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीसरी योजना की प्रस्तावित रूपरेखा

भारत की तीसरी योजना के लक्ष्य निम्नलिखित रखे गये हैं—

१—तीसरी योजना में देश के विकास में १०,२०० करोड़ रु० लगाये जायेंगे।

२—६,२०० करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र में और ४,००० करोड़ रुपए निजी क्षेत्र में।

३—सार्वजनिक क्षेत्र की योजना की लागत ७,२५० करोड़ रुपए होगी।

४—राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत की वृद्धि होगी।

५—अनाज की पैदावार १०—१०॥ करोड़ टन कर दी जाएगी।

६—१ करोड़ टन इस्पात के ढोके बनाने की क्षमता पैदा की जायगी। बिजली बनाने की क्षमता ४८ लाख कि० वा० से बढ़कर १ करोड़ १८ लाख कि० वा० कर दी जायगी।

७—१ करोड़ ३५ लाख आदमियों के लिये नये काम की व्यवस्था की जायगी।

८—देश के सब गांवों में सामुदायिक विकास योजना और सहकारिता का काम चालू कर दिया जायगा।

९—६ वर्ष से ११ वर्ष तक के उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जायगी।

१०—सब गांवों में पीने के पानी, रेल और मुख्य मार्ग तक सड़कें और पाठशाला भवन बनाये जायेंगे, जो पंचायत और पुस्तकालय का भी काम देंगे।

योजना की रूपरेखा

यह रूपरेखा प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि संसद, राज्यों की विधानसभाएँ और जनता तीसरी योजना के उद्देश्यों, विषयों और प्राथमिकताओं पर विचार कर सकें और लोगों को यह पता चले कि हमें देश के विकास के लिए कितना बड़ा प्रयत्न करना है। इससे केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों की सरकारों को तीसरी योजना के लिए अपने पक्के और तफसीलवार कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी। तीसरी योजना का अंतिम या पक्का रूप अगले साल के शुरू में संसद में पेश किया जाएगा।

पहली और दूसरी योजना

पिछले १० वर्षों में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये देश के प्राकृतिक साधनों और जनता की शक्ति को राष्ट्र के विकास में लगाने की कोशिश की गयी है। शुरू से इस बात का ख्याल रखा गया है कि योजना का उद्देश्य केवल पैदावार को बढ़ाना और देश की दशा सुधारना ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर आधारित ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की रचना करना भी है, जिसमें "सामाजिक, आर्थिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे।"

देश को दूसरे महायुद्ध और बटवारे से जो हानि पहुँची थी, पहली योजना में उसे पूरा करने की आर्थिक व्यवस्था की नींव मजबूत करने की कोशिश की गयी और संविधान में दिये हुए निदेशक तत्वों के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक नीतियां भी ग्रहण की गयीं। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ और भूमि-सुधार इस योजना की उल्लेखनीय बातें हैं। दूसरी योजना में पहली योजना की ही नीतियों को जारी रखते हुए पैदावार बढ़ाने, विकास में अधिक रुपया लगाने और लोगों को अधिक काम देने की कोशिश की गयी। इसमें आर्थिक उन्नति की गति को तेज करने पर, बुनियादी उद्योगों की स्थापना पर, रोजगार के जरियों को बढ़ाने पर, आय और धन की विषमता को कम करने पर और आर्थिक शक्ति को थोड़े से लोगों के हाथों में जाने से रोकने पर, जोर दिया गया। पहली योजना में राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष ३॥ प्रतिशत और दूसरी योजना में प्रति वर्ष ४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

तीसरी योजना के उद्देश्य

देश के आर्थिक विकास में तीसरी योजना का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके मुख्य उद्देश्य ये हैं:—

(१) अगले ५ साल में राष्ट्रीय आय में वार्षिक ५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

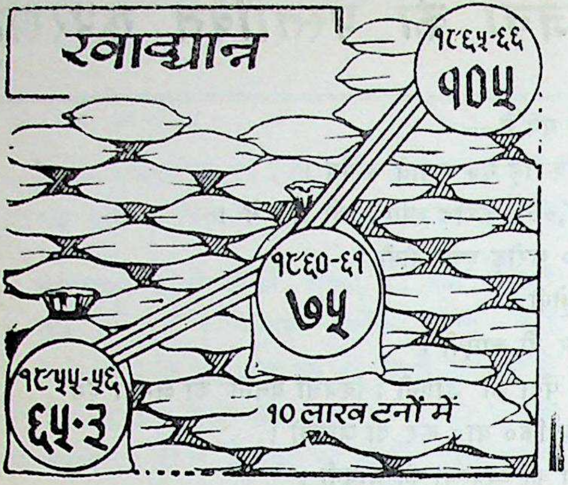

भारत में खाद्यान्न उत्पादन

प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करना और इस हिसाब से देश के विकास में रुपया लगाना, जिससे आगे भी वृद्धि का यही क्रम जारी रहे।

(२) अनाज की पैदावार में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और कच्चे माल की उपज को इतना बढ़ाना कि उससे हमारे उद्योगों की जरूरतें भी पूरी हों और निर्यात भी हो।

(३) इस्पात, बिजली, तेल, ईंधन आदि बुनियादी उद्योगों को बढ़ाना और मशीन बनाने के कारखाने कायम करना जिससे १० वर्ष के अन्दर देश के औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक मशीनें अपने देश में ही बनाई जा सकें।

(४) देश की जन या श्रम शक्ति का पूरा उपयोग करना और लोगों को रोजगार के अधिक जरिये देना; तथा

(५) धन और आय की विषमता को घटाना और सम्पत्ति का अधिक न्यायोचित वितरण करना।

स्वयं-स्फूर्त विकास

तीसरी योजना का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि देश में विकास का ऐसा क्रम चालू हो जाय जो अपने आप चलता रहे। स्वयं-स्फूर्त विकास का अर्थ यह है कि देश के लोग इतना धन बचाते और लगाते रहें जिससे राष्ट्र की सम्पत्ति और आय बराबर बढ़ती जाय। इस बात के लिये यह भी आवश्यक है कि देश में पूंजीगत माल और मशीनें आदि बनाने का प्रबन्ध हो, जिससे नये उद्योग-धंधों में पूंजी लगती रहे। तीसरी योजना में किसी उद्योग में कितनी पूंजी लगायी जाय, इसका निर्धारण इसी बात को ध्यान में रखकर किया गया है।

स्वयं-स्फूर्त विकास तभी हो सकता है जब खेती और उद्योग दोनों की समुचित उन्नति हो। औद्योगीकरण के बिना न तो आमदनी बढ़ सकती है, न काफी लोगों को काम मिल सकता है। साथ ही खेती की पैदावार बढ़े बिना औद्योगिकरण भी नहीं हो सकता। इसीलिये तीसरी योजना में अन्न और कच्चे माल की पैदावार बढ़ाने और उद्योग का आधार मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया गया है। अपने देश में लोगों को पूरा काम नहीं मिलता है, इसलिये रोजगार या काम के जरिये बढ़ाना बहुत आवश्यक है। लोगों को अधिक काम देने से पैदावार भी बढ़ती है। इसलिये तीसरी योजना में काम के जरिये बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है।

समाजवादी ढांचा

योजना का एक खास उद्देश्य धन और आय की विषमता को कम करने का उपाय निकालना भी है, ताकि समाज का ढांचा समाजवादी ढंग का हो सके, जिसमें सब लोगों को पूरी उन्नति करने का पूरा मौका मिले। समाजवादी ढांचे का अर्थ यह है कि हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए, जिससे सारे समाज का भला हो, केवल मुट्ठीभर आदमियों का नहीं। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार के आर्थिक उपाय करने पड़ेंगे और वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करने पड़ेंगे। इनमें राज्य के उद्योग और आर्थिक कार्य, देश में साधन जुटाने और विकास में रुपया लगवाने के लिये वित्तीय-उपाय, समाज-सेवाओं का विस्तार, भूमि सुधार, सहकारी संस्थाओं का विस्तार आदि शामिल हैं। ये उपाय ऐसे ढंग से होने चाहिएं कि नीचे की श्रेणियों की आर्थिक उन्नति हो और उन्हें अधिक अवसर मिले और ऊपर की श्रेणियों का धन और अधिकार कम हो।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जनसंख्या की समस्या

अनुमान है कि सन् १९६६ तक हमारी जनसंख्या ४८ करोड़ हो जायगी। कम विकसित देश में जनसंख्या के अधिक बढ़ने से आर्थिक उन्नति में बाधा पड़ती है। इसलिये जनसंख्या की वृद्धि को रोकना जरूरी है। साथ ही इस को देखते हुए और तेजी से उन्नति करना भी आवश्यक है।

खेती की प्राथमिकता

योजना में खेती को पहला स्थान दिया गया है। अनाज में आत्मनिर्भरता और उद्योगों तथा निर्यात के लिए कच्चे माल की पैदावार बढ़ाना तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य है। खेती की अधिक उन्नति होनी चाहिये, जिससे गांव के लोग देश के अन्य लोगों के मुकाबले पीछे न पड़ जांय।

योजना में खेती और सामुदायिक विकास के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में १,०२५ करोड़ रु० तथा सिंचाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं के लिये ६५० करोड़ रु० रखे गये हैं। इसके अलावा अनुमान है कि लोग निजी ओर से भी इन कामों में ८०० करोड़ रु० लगायेंगे। यदि आगे चलकर यह प्रतीत हुआ कि भावों में और तेजी से उन्नति करने और जन-शक्ति का पूरा उपयोग करने के लिये और रुपये लगाने की जरूरत है, तो इसका भी बन्दोबस्त किया जायगा। खेती की पैदावार में ३० से ३३ प्रतिशत की वृद्धि की जायगी। खास-खास फसलों के उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं:—

घरेलू व्यवहार की वस्तुएँ	वार्षिक—उत्पादन	
	१९६०-६१ (अनुमित)	१९६५-६६ (लक्ष्य)
अनाज (लाख टनों में)	७५०	१,०००-१०५०
तेलहन (,, ,,)	७२	९२-९५
गन्ना (गुड़ के रूप में) (,, ,,)	७२	९०-९२
कपास (,, ,,)	५४	७२
पटसन (लाख गांठों में)	५५	६५

इसके अलावा फल, शाक, दूध, मछली, मांस, अण्डा, नारियल, सुपारी, काजू, कालीमिर्च, तम्बाकू, चमड़ा, और

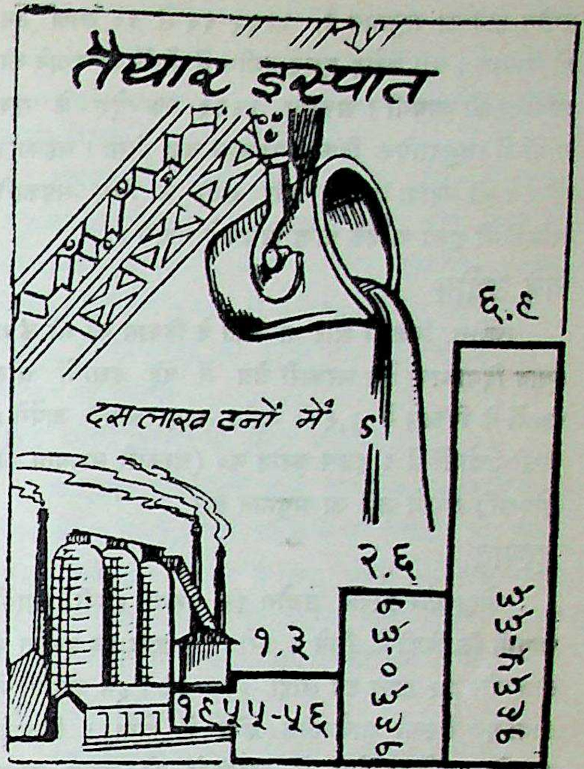

भारत में इस्पात उत्पादन

लकड़ी आदि की भी पैदावार बढ़ाने की पूरी कोशिश की जायगी।

आज की पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य इस हिसाब से रखा गया है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत १५ औंस अनाज और ३ औंस दाल, खाने को मिल सके तथा संकट के समय के लिये भी कुछ अनाज बच जाय। कपास की पैदावार का जो लक्ष्य है उससे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत १७॥ गज के हिसाब से कपड़ा मिल सकेगा और निर्यात के लिये भी कुछ बचेगा।

सिंचाई

तीसरी योजना के अन्त तक सिंचाई का रकबा ९ करोड़ एकड़ हो जायगा, जबकि दूसरी योजना के अन्त में यह ७ करोड़ एकड़ होगा। करीब ४ करोड़ एकड़ में बरानी खेती की जांयगी। १ करोड़ ३० लाख एकड़ अधिक जमीन को कटाव आदि से बचाने का काम किया जायगा। सन् १९६०-६१ तक करीब ३ लाख ६० हजार टन नत्रजनयुक्त खाद का

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

प्रयोग होने का अनुमान है, १९६५-६६ में १० लाख टन हो जायगा। ७।। करोड़ एकड़ जमीन में पौधों को बचाने की व्यवस्था की जायगी। अक्टूबर, १९६३ तक देश के सब गांवों में सामुदायिक विकास का काम चल पड़ेगा। सहकारी संगठन भी बढ़ाया जायगा और खेती के लिए सहकारी समितियों द्वारा अधिक ऋण दिलवाये जाएंगे।

बड़े उद्योग

उद्योग, बिजली और यातायात के विकास को भी ऊंचा स्थान दिया गया है। सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योगों और खानों के विकास में १,५०० करोड़ रुपए लगाये जायेंगे। निजी उद्योगों में १ हजार करोड़ रु० (सरकारी सहायता को छोड़कर) लगाये जाने का अनुमान है।

इस्पात

लोहा और इस्पात उद्योग की क्षमता इतनी बढ़ायी जायगी कि बिक्री के लिये १ करोड़ २ लाख टन इस्पात के ढोके और १५ लाख टन लोहा मिल सके। इन उद्योगों में प्रायः पूरा विस्तार सार्वजनिक क्षेत्र में होगा। भिलाई, राउरकेला, और दुर्गापुर के कारखानों को इतना बढ़ाया जायगा कि वे ५५ लाख टन इस्पात के ढोके बना सकें। बुकारा में चौथा इस्पात कारखाना भी खड़ा किया जायगा।

मशीन बनाने के कारखाने

तीसरी योजना में भारी मशीनें बनाने वाले, फाउंड्री फोज (गढ़ाई और ढलाई), कोयला खोदने की मशीन बनाने वाले और भारी मशीनी औजार बनाने वाले कारखानों को कायम करने की व्यवस्था की गयी है। बंगलौर के हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने का उत्पादन दुगुना करने, भोपाल के भारी बिजली के सामान के कारखाने को बढ़ाने, दो और भारी बिजली के सामान के कारखाने लगाने और ऊंचे दबाव के बायलर और सूक्ष्म यंत्रों के कारखानों को भी लगाने की योजना है। मशीन बनाने के निजी कारखानों में भी काफी काम होने की आशा है। आशा है कि कागज, सीमेंट, शक्कर और चमड़ा बनाने की प्रायः सब मशीनें देश में तैयार होने लगेंगी।

खाद

दूसरी योजना के अन्त में २ लाख १० हजार टन नाइट्रोजनयुक्त खाद बनेगी। तीसरी योजना में इसे बढ़ाकर १० लाख टन कर दिया जायगा। इसी तरह फासफटी खाद का उत्पादन भी ७० हजार टन से बढ़ाकर ४००-५०० हजार टन करने का विचार है।

कोयला

दूसरी योजना के अंत में ६ करोड़ टन कोयला निकाला जायगा। तीसरी योजना में इसे बढ़ाकर ९ करोड़ ७० लाख टन कर दिया जायगा।

तेल

अभी तक जो पता लगा है उसके हिसाब से नहरकटिया में प्रतिवर्ष २७ लाख ५० हजार टन अशोधित तेल जमीन से निकाला जायगा। इस तेल को साफ करने के लिये नूनमाटी और बरोनी में सफाई के कारखाने बनाये जायेंगे। खंभात में या और जगह जहां पर तेल मिलने की आशा होगी, वहां तेल की खोज की जाएगी।

खास-खास उद्योगों के उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

	वार्षिक–उत्पादन	
	१९६०-६१	१९६५-६६
अलमुनियम (हजार टनों में)	१७.०	७५.०
सीमेंट (लाख टनों में)	८८	१३०
कागज (हजार टनों में)	३२०.०	७००
गंधक तेजाब (हजार टनों में)	४००.०	१२५०
कास्टिक सोडा (हजार टनों में)	१२५.०	३४०
शक्कर (लाख टनों में)	२५	३०
कपड़ा (मिल का कपड़ा) (लाख गजों में)	५०,०००	५८,०००
साइकिल (कारखानों में) (हजार अदद)	१०५०	२०००
सिलाई की मशीन (हजार अदद)	३००	४५०
मोटरगाड़ी (अदद)	५३,५००	१००,०००

छोटे और ग्रामोद्योग

छोटे और ग्रामोद्योगों की उन्नति पर भी बहुत जोर दिया गया है। इनके लिये कारीगरों को सिखाने, कच्चा माल और ऋण की व्यवस्था करने का भी अधिक प्रबन्ध किया जायगा। हथकरघा और घरेलू उद्योग के जरिये सन्

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१९६५-६६ में ३५० करोड़ गज कपड़ा बनाया जायगा, जबकि सन् १९६०-६१ में इन से २६० करोड़ गज तैयार होने का अनुमान है। दूसरी योजना में ६० उद्योग-पुरियां बनायी गयी हैं। तीसरी में ३६० बनायी जायेंगी। गांवों और शहरों दोनों में छोटे उद्योग चलाने और उनको बड़े उद्योगों से जोड़ने का प्रयत्न किया जायगा, जिससे वे बड़े उद्योगों के लिये पुरजे आदि तैयार करें।

बिजली

दूसरी योजना में बिजली की उत्पादन क्षमता ५८ लाख कि० वा० है। तीसरी योजना के अंत तक यह बढ़ाकर १ करोड़ १८ लाख कि० वा० करदी जायगी। अणु-शक्ति से भी ३ लाख कि० वा० बिजली बनायी जाएगी। आशा है कि तीसरी योजना में १५ हजार गावों और छोटे कस्बों में बिजली लगायी जाएगी, जिससे इनकी कुल संख्या ३४ हजार हो जायगी।

रेल, जहाज और मोटर यातायात

आशा है कि सन् १९६५-६६ में रेलगाड़ियां २३ करोड़ ५० लाख टन माल ढोयेंगी, जबकि १९६०-६१ में वे १६ करोड़ २० लाख टन ढोयेंगी। १२०० मील नयी रेल-लाइन बिछाई जाएंगी। १९६०-६१ में पक्की सड़कों की लंबाई १ लाख ४४ हजार मील होगी। १९६५-६६ में यह बढ़कर १ लाख ६४ हजार मील हो जायगी। मोटर यातायात का विकास अधिकांश निजी क्षेत्र में होगा। अनुमान है कि किराये पर चलने वाली मोटरगाड़ियों और ठेलों आदि की संख्या २ लाख से बढ़कर ३ लाख हो जायगी। दूसरी योजना के अन्त तक हमारे पास ९ लाख टन के जहाज होंगे। तीसरी योजना में २ लाख टन के जहाज और लिये जायेंगे।

सामाजिक सेवा

६ वर्ष से ११ वर्ष तक की उम्र के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जायगा। इस उम्र के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या ६० से ८० प्रतिशत बढ़ जायगी। अनुमान है कि स्कूलों के छात्रों की संख्या सन् १९६०-६१ में ४ करोड़ १० लाख से बढ़कर १९६५-६६ में ६ करोड़ हो जायगी।

विज्ञान और शिल्प की शिक्षा का भी विस्तार किया जायगा। इंजीनियरी और शिल्प विद्यालयों में तीसरी योजना के अन्त तक ५३,५०० छात्र भर्ती हो सकेंगे, जबकि दूसरी योजना में ३७,८०० होते हैं।

रजिस्टर्ड डाक्टरों की संख्या भी ८४ हजार से बढ़कर १ लाख ३ हजार हो जायगी। अस्पतालों और कारखानों की संख्या १२,६०० १४,६०० और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या २८०० से बढ़कर ५,००० हो जायगी। संतति निरोध केन्द्रों की संख्या भी १,८०० से बढ़कर ८२०० हो जायगी।

कम आय वालों के लिए मकान

कम आय वाले लोगों और औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान बनाने, गन्दी बस्तियों की सफाई और उनमें सुधार करने और मकानों के लिए जमीन लेने तथा उसका सुधार करने के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। मकान बनाने के लिए धन आवास वित्त निगमों द्वारा दिया जाएगा।

स्थानीय विकास-कार्य

देहाती क्षेत्रों में कुछ न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए तीसरी योजना में स्थानीय विकास का एक कार्यक्रम शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत जिन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी वे ये हैं: (क) पीने के पानी की सप्लाई, (ख) प्रत्येक गांव को सबसे पास की मुख्य सड़क या रेलवे स्टेशन से मिलाने के लिए सड़कों का निर्माण और (ग) गांवों के स्कूल के भवनों का निर्माण, जो सामुदायिक केन्द्र और पुस्तकालय का काम भी देगा।

१०,२०० करोड़ रुपए

ऊपर जिन लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है, उनको पूरा करने के लिए तीसरी योजना की अवधि में १०,२०० करोड़ रु० की कुल पूंजी लगाने का विचार है। इसमें से ६,२०० करोड़ रु० सरकारी क्षेत्र में और ४,००० करोड़ रु० निजी क्षेत्र में लगाये जांगे। सरकारी क्षेत्र में कुल खर्च ७,२५० करोड़ रु० होगा। २०० करोड़ रु० की राशि सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में तबदील करने की सम्भावना है, जिससे निजी क्षेत्र में पूंजी का निर्माण हो सके। आगामी पृष्ठ पर दी गई लिखित सारिणी में तीसरी योजना के कुल व्यय और पूंजी की दूसरी योजना से तुलना की गयी है:

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(करोड़ रु० में)

	सरकारी क्षेत्र			निजी क्षेत्र	कुल पूंजी
	योजना का व्यय	चालू व्यय	पुंजी		
दूसरी योजना	४६००	९५०	३६५०	३१००	*६७५०
तीसरी योजना	७२५०	१०५०	६२००	४०००	*१०२००

(*सरकारी क्षेत्र से जो २०० करोड़ रु० निजी क्षेत्र में दिए जाएंगे, वे इसमें शामिल नहीं हैं।)

तीसरी योजना में पूंजी लगायी जायगी, जिन पर दूसरी योजना में लगायी गयी है, परन्तु सरकारी क्षेत्र में कृषि, उद्योग, बिजली और कुछ सामाजिक सेवाओं पर अधिक जोर दिया जाएगा। दूसरी और तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में व्यय जिस प्रकार बांटा गया, वह निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है।

(करोड़ रुपए में)

	व्यय		प्रतिशत	
	दूसरी योजना	तीसरी योजना	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१. कृषि और छोटी सिंचाई-योजनाएं	३२०	६२५	६.९	८.६
२. सामुदायिक विकास और सहकार	२१०	४००	४.६	५.५
३. बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाएं	४५०	६५०	९.८	९.०
४. जोड़ १-२-३	९८०	१६७५	२१.३	२३.१
५. बिजली	४१०	९२५	८.९	१२.८
६. ग्राम और लघु उद्योग	१८०	२५०	३.९	३.४
७. उद्योग और खनिज	८८०	१५००	१९.१	२०.७
८. परिवहन और संचार	१२९०	१४५०	२८.१	२०.०
९. जोड़ ५-८	२७६०	४१२५	६०.०	५६.९
१०. सामाजिक सेवाएं	८६०	१२५०	१८.७	१७.२
११. उत्पादन में रुकावट न आने देने के लिए जमा माल	——	२००	——	२.८
१२. कुल जोड़	४६००	७२५०	१००	१००

इस समय प्रत्येक विषय के लिए जो खर्च रखा गया है वह अस्थायी है। उद्देश्य यह है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अपने कार्यक्रमों को पूरी तरह से अध्ययन करने और प्रत्येक क्षेत्र में प्राथमिकता निश्चित करने में मदद मिले। यह कहा गया है कि कृषि, ग्राम और लघु उद्योग, प्राथमिक शिक्षा, शिल्पिक शिक्षा आदि के जो मंजूरशुदा कार्यक्रम और लक्ष्य हैं उनके लिए, यदि आवश्यकता हुई तो, राज्यों और मंत्रालयों द्वारा जांच के बाद अतिरिक्त धन दिया जाएगा। जहां तक ऐसे मंजूरशुदा कार्यक्रमों का प्रश्न है, जिनके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, जैसे ही विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी, वैसे ही उनके लिए देश में साधन जुटाने का भी पूरा प्रयत्न किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र में खर्च किए जाने वाले कुल ७२५० करोड़ रु० में से ३६०० करोड़ रु० केन्द्र और ३६५० करोड़ रु० राज्य खर्च करेंगे। केन्द्र द्वारा राज्यों को २५०० करोड़ रु० की सहायता देने का अनुमान है।

योजना के लिए साधन

दूसरी योजना में लगी कुल ६७५० करोड़ रु० की पूंजी की तुलना में तीसरी योजना में १०,२०० करोड़ रु० की पूंजी लगाने के लिए घरेलू साधन जुटाने का जी-जान से प्रयत्न करना पड़ेगा। तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने की आशा है। अधिक पूंजी लगाने के लिए इसी साधन से धन जुटाना होगा।

योजना का उद्देश्य यह है कि तीसरी योजना के अंत में राष्ट्रीय आय का १४ प्रतिशत हमारी अर्थ-व्यवस्था में लगे। दूसरी योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय का ११ प्रतिशत अर्थ-व्यवस्था में लगा होगा। इस समय राष्ट्रीय आय की बचत की दर लगभग ८ प्रतिशत है। इस बचत की दर को भी तीसरी योजना के अन्त तक बढ़ाकर ११ प्रतिशत करना होगा।

पहली दो योजनाओं की भांति तीसरी योजना के आरंभ के समय भी विदेशी मुद्रा कम रहेगी। विदेशी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मुद्रा कोष से धन लेने की आगे गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा दूसरी योजना के आरम्भ में वस्तुओं का जो मूल्य था, उससे अब उनका मूल्य २० प्रतिशत अधिक है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात की जरूरत है कि ऐसे खर्च न किए जाएं जिनसे मुद्रा-स्फीति हो।

इसके विपरीत, अब जैसी स्थिति है, वह पिछली योजनाओं के आरंभ की स्थिति से कई प्रकार से अच्छी है। पिछले दस वर्षों में उद्योग आदि में अधिक पूंजी लगायी गयी है। सिंचाई, बिजली और परिवहन में भी काफी प्रगति हुई है। दूसरी योजना में, सरकारी क्षेत्र में, अनेक कार्यक्रम अभी पूरे ही किए जाने थे, जबकि तीसरी योजना में वे पूरे हो चुकेंगे और उनसे लाभ होने लगेगा। इस लाभ को आगे पूंजी के रूप में लगाने के लिए लेना होगा। शिक्षा और प्रशिक्षण की जो सुविधाएं अब तक दी गयी हैं, वे तीसरी योजना में और भी बढ़ेंगी और इनसे भविष्य में अधिक लाभ होगा। नए-नए उद्योग धन्धे शुरू करने की क्षमता रखने वाले और प्रबन्ध का अनुभव रखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और वे अब अधिक संख्या में उपलब्ध हैं।

इस बात पर जोर दिया गया है कि योजना के लिए साधन जुटाने की समस्या को ऐसा नहीं मानना चाहिए, जैसे वह किसी स्थिर और निश्चित कोष से धन लेने की बात हो। एक हद तक अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ साधन भी बढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो कठिनाइयां रही हैं, उनके बावजूद इतनी प्रगति हुई है कि भविष्य में पहले से अधिक प्रयत्न करना सम्भव हो गया है। गरीबी और कम बचत के विषाक्त चक्र को तभी तोड़ा जा सकता है, जब पूरे साधन जुटाए जाएं और जो लाभ होता रहे वह निरंतर उत्पादन के लिए लगाया जाता रहे।

धन जुटाने की योजना

सरकारी क्षेत्र में तीसरी योजना में जो खर्च होगा, उसके लिए धन जुटाने की योजना निम्नलिखित सारिणी में दी गयी है :

(करोड़ रु० में)

	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१. वर्तमान करों के आधार पर बचत राजस्व से बचने वाला धन	१००	३५०
२. वर्तमान आधार पर रेलों से मिलने वाला धन	१५०*	१५०
३. वर्तमान आधार पर सरकारी उद्योगों से मिलने वाला धन	——	४४०
४. सार्वजनिक ऋण	८००	८५०
५. अल्प बचत	३८०	५५०
६. भविष्य निधि आदि से मिलने वाला धन	२१३	५१०
७. अतिरिक्त कर और सरकारी उद्योगों के लाभ में से मिलने वाला धन	१०००	१६५०
८. विदेशी सहायता जिसकी बजट में व्यवस्था की गयी हैं	९८२	२२००
९. घाटे की अर्थ-व्यवस्था	११७५	५५०
जोड़ :	४६००	७२५०

* यात्रियों के किराए और माल-भाड़े में हुई बढ़ती मिलाकर।

अतिरिक्त कर

पांच वर्ष की अवधि में १६५० करोड़ रु० के अतिरिक्त कर लगाने का जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति योजना की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। भारत में इस समय करों से राष्ट्रीय आय का लगभग ८.५ प्रतिशत भाग मिलता है। कर-उपलब्धि में सामान्य रूप से जो बढ़ती होगी और तीसरी योजना में जो अतिरिक्त कर लगाए जाएंगे, उनसे यह संख्या बढ़कर ११ प्रतिशत हो जाएगी।

विकास-कार्यों की तेज़ गति को देखते हुए अधिक भार नहीं माना जा सकता। फिर भी १६५० करोड़ रु० के अतिरिक्त कर लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इस कर-राशि में से एक-तिहाई के कर राज्य लगाएंगे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीसरी योजना के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के कर बढ़ाने और सरकारी उद्योगों का लाभ बढ़ाने की जरूरत होगी। जहां तक आय-कर और निगम कर का प्रश्न है, कर-प्रशासन को कड़ा करके उनकी वसूली बढ़ानी होगी, कम्पनियों के खर्च के ब्यौरे पर नज़र रखनी होगी और ऐसे कदम उठाने होंगे, जिनसे वे कर से बच न सकें। अप्रत्यक्ष करों और वस्तुओं के मूल्य में बढ़ती होने से निश्चय ही लागत और मूल्य दोनों बढ़ेंगे, पर यह ऐसा त्याग है जो करना ही पड़ेगा।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था

अप्रत्यक्ष करों और घाटे की अर्थ-व्यवस्था से मूल्य पर जो असर पड़ता है, उसमें भेद करने की आवश्यकता है। अप्रत्यक्ष करों द्वारा मूल्य बढ़ जाने से मुद्रा-स्फीति की संभावना कम रहती है जब कि घाटे की अर्थ-व्यवस्था से यह सम्भावना और बढ़ती है। अतः यह विचार है कि तीसरी योजना में केवल ५५० करोड़ रु० की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की जाए जब कि दूसरी योजना में १,१७५ करोड़ रु० की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गयी थी।

विदेशी-मुद्रा

तीसरी योजना में बड़ी तेज गति से उद्योगों की स्थापना के कारण विदेशी मुद्रा की काफी मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। यह अनुमान है कि योजना में १,६०० करोड़ रु० विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय होंगे। इसके अलावा लगभग २०० करोड़ रु० के पुर्जे आदि भी आयात करने की जरूरत पड़ेगी। जिससे देश में मशीनी सामान का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस प्रकार योजना के लिए २,१०० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी।

योजना में नए कामों के लिए जितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी, उसे छोड़ भी दिया जाए तो भी तीसरी योजना की अवधि में पिछले ऋणों और ब्याज की अदायगी के कारण ५०० करोड़ रु० की जरूरत रहेगी। इस प्रकार तीसरी योजना में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता बढ़कर २,६०० करोड़ रु० हो जाएगी। इस जोड़ में वह ६०० करोड़ रु० भी शामिल किए जा सकते हैं जो पी० एल० ४८० के अंतर्गत अमेरिका से मिलेंगे। इस प्रकार तीसरी योजना की कुल जरूरत ३,२०० करोड़ रु० हो जाती है।

विदेशों से सहायता के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। योजना का रूप ऐसा रखना होगा कि उसमें घटबढ़ की जा सके। सरकारी और गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों में कार्यक्रम इसी आधार पर शुरू किए जा सकते हैं कि बाहर से निश्चित रूप से क्या सहायता मिल सकती है। इसके लिए कार्यक्रम पहले से तैयार करके रखने होंगे, जिससे आवश्यक विदेशी मुद्रा मिलते ही उन्हें पूरा किया जा सके। विदेशी मुद्रा के उपयोग में देर करने से तीसरी योजना में उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम गड़बड़ में पड़ जाएगा।

भुगतान के विषय में देश को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है वे कोई स्थायी या आकस्मिक नहीं हैं, बल्कि हमारे विकास की क्रिया का ही एक अंग है। कुछ समय तक अत्यधिक आयात की जरूरत बाहरी सहायता से ही पूरी की जा सकती है, परन्तु यह याद रखना जरूरी है कि यह असन्तुलन धीरे-धीरे कम होता जाए और कुछ समय बाद समाप्त हो जाए। इसका यह अर्थ नहीं कि एक खास अवधि के बाद विदेशों से धन का आना रोक दिया जाएगा। व्यापार में लगी पूंजी आती ही रहेगी और आती ही रहनी चाहिए, परन्तु विशेष सहायता कार्यक्रमों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो जानी चाहिए, और कुछ समय बाद समाप्त हो जानी चाहिए।

निजी-पूंजी

निजी क्षेत्र में पूंजी केवल संगठित उद्योगों, खान, बिजली और परिवहन में ही नहीं लगी हुई है, बल्कि कृषि, ग्राम और लघु उद्योगों, तथा देहात और शहरों में मकान बनाने में भी लगी हुई। दूसरी और तीसरी योजनाओं में निजी क्षेत्र में लगी पूंजी निम्नलिखित सारिणी से स्पष्ट है :

(करोड़ रु० में)

	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१. कृषि (सिंचाई सहित)	६७५	८५०
२. बिजली	४०	५०
३. परिवहन	१३५	२००

[शेष पृष्ठ ३८६ पर]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकास योजनाओं के प्रथम दस वर्ष

पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं भारत के आयोजित आर्थिक और सामाजिक विकास के पहले चरण हैं। योजना के इन पहले १० वर्षों में राष्ट्रीय आय और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है और भारत के जन-साधन का भी विकास हुआ है। इन वर्षों में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का अपेक्षाकृत काफी रफ्तार से विकास हुआ है। रोजगार की सुविधाएं, राष्ट्रीय आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं को घटाने तथा आर्थिक साधनों को केवल कुछ लोगों के हाथ में जाने से रोकने पर जोर दिया गया।

योजना व्यय और पूंजी नियोजन

इन पहली दो योजनाओं में १० हजार करोड़ रु० से कुछ अधिक लगाये गए हैं, जिसमें से सरकारी क्षेत्र में लगभग ६,५६० करोड़ रु० लगे हैं।

(करोड़ रुपयों में)

	पहली योजना १९५१—५६	दूसरी योजना १९५६—६१	कुल १९५१—६१ (अनुमानित)
सरकारी क्षेत्रमें खर्च	१९६०	४६००	६,५६०
सरकारी क्षेत्र में पूंजी नियोजन	१५६०	३६५०	५,२१०
निजी क्षेत्र में पूंजी नियोजन	१८००+	३१००+	४,९००
कुल पूंजी लगी	३३६०	६७५०	१०,११०

(+ ये अनुमान पूरी सूचनाओं के आधार पर संशोधित हैं और पहली योजना के १,६०० करोड़ रु० और दूसरी योजना के २,४०० करोड़ रु० के पहले अनुमानों के स्थान पर हैं।)

राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत वृद्धि

पहले योजना काल में विशेषतः कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय १८ प्रतिशत बढ़ी। दूसरी योजना में पहली योजना की अपेक्षा आर्थिक विकास के लिए और अधिक तथा व्यापक प्रयत्न किये गये। आशा है कि दूसरे योजना काल की समाप्ति तक राष्ट्रीय आय में लगभग २० प्रतिशत वृद्धि होगी। इस प्रकार १९५१ से १९६१ तक के इन दस वर्षों में राष्ट्रीय आय लगभग ४२ प्रतिशत बढ़ जाएगी। प्रति व्यक्ति आय में लगभग २० प्रतिशत और प्रति व्यक्ति व्यय में लगभग १६ प्रतिशत वृद्धि होगी। कृषि उत्पादन ४० प्रतिशत और औद्योगिक उत्पादन १२० प्रतिशत बढ़ जायगा।

आगामी पृष्ठ पर दी गई तालिका में १०५१-५० से कृषि उपज की वृद्धि दिखाई गई है :

सफलताएं

★ राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत वृद्धि।

★ प्रति व्यक्ति आय में २० प्रतिशत वृद्धि।

★ सरकारी क्षेत्र में ५२१० करोड़ रु० की पूंजी।

★ निजी क्षेत्र में ४९०० करोड़ रु० की पूंजी।

★ कृषि उपज के प्रथम व दसवें वर्ष के सूचक अंक क्रमशः ९५.६ और १३५.०९।

★ दस वर्षों में १.९५ करोड़ एकड़ सिंचाई में वृद्धि।

★ लोहे के तीन बड़े कारखाने (रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई में)

★ विविध प्रधान उद्योगों में आशाजनक वृद्धि।

★ १२०० मील नई रेल लाइनें, ८०० मील पर यात्रि बिजली की गाड़ियां।

★ ४५५०० मील सड़कें।

असफलताएं

★ रोजगार के लक्ष्यों में पूर्ण नहीं हुए।

★ महंगाई वृद्धि नियंत्रण में असफलता।

★ जनता का सहयोग प्राप्त करने में सरकार सफल नहीं हुई।

★ सामुदायिक विकास योजनाओं में मूल भावना जाग्रत नहीं हुई।

★ प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन के कारण विदेशी मुद्रा की कठिनता प्रमुख हो गई।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कृषि उपज का सूचक अंक (१६४६--५० = १००)

	१६५०-५१	१६५५-५६	१६५८-५६	१६६०-६१
सभी जिंस	६५.६	११६.६	१३२.०	१३५.०
अनाज की फसलें	६०.५	११५.३	१३०.०	१३१.०
अन्य फसलें	१०५.६	१२०.१	१३६.०	१४३.०

ऊपर की तालिका से पता चलता है कि कृषि उपज में वृद्धि का रुख रहा, लेकिन विभिन्न वर्षों में अंतर काफी रहा। मुख्य कृषि जिंसों की उपज में वृद्धि के आंकड़े इस प्रकार हैं :

जिंस	१६५०-५१	६०-६२ अनुमित वृद्धि)
अनाज (गेहूँ, दाल आदि) (लाख टनों में)	५२४	७५०
तिलहन (लाख टनों में)	५१	७२
गन्ना (गुड़ के रूप में) (लाख टनों में)	५६	७२
कपास (लाख गांठों में)	२६	५४
जूट (लाख गांठों में)	३३	५५

पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देश भर में विस्तार सेवा शुरू करने का निश्चय किया गया। अक्टूबर, १६६३ तक यह कार्यक्रम देश के सभी देहातों में पहुंच जायगा। दूसरी योजना के अन्त तक विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तार खण्डों तथा गांवों में लगभग ३१ हजार ग्राम-सेवक और लगभग २८ हजार विकास अधिकारी कृषि, पशु-पालन तथा अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए काम कर रहे होंगे। लेकिन सामुदायिक विकास योजनाओं के नये मूल्यांकन (अन्यत्र प्रकाशित) से स्पष्ट है कि हम संतोषजनक प्रगति नहीं कर सके और जनता का बहुत कम सहयोग प्राप्त कर सके हैं।

१६५१ से १६५६ के दौरान प्रारम्भिक कृषि समितियों की संख्या १५ हजार से १ लाख ८३ हजार तथा इन के सदस्यों की संख्या ४४ लाख से १ करोड़ २० लाख तक बढ़ी है। गांव पंचायतों की संख्या लगभग दुगुनी से भी अधिक बढ़कर १ लाख ७८ हजार तक पहुँच गयी है।

सिंचाई, बीज और खाद

१६५०-५१ में ५ करोड़ १५ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी। १६६०-६१ तक ७ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। दूसरी योजना में सिंचाई की सुविधा प्राप्त सभी क्षेत्र को बढ़िया बीज सप्लाई करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज पैदा करने के लिए लगभग ४ हजार फार्म खोले जा रहे हैं। १६५०-५१ में ५५ हजार टन नत्रजनी खाद का प्रयोग किया गया। १६६०-६१ में नत्रजनी खाद के प्रयोग की मात्रा ३ लाख ६० हजार टन (नत्रजन के रूप में) तक बढ़ जायगी। कृषि विकास के अन्य कार्यक्रमों में भी काफी प्रगति हुई है। ४० लाख एकड़ भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाया गया है, २२ लाख एकड़ भूमि में हरी खाद का प्रयोग शुरू किया गया है और २७ लाख एकड़ भूमि को कटाव से रोकने की व्यवस्था की गयी है।

प्रधान उद्योग

पिछले १० वर्षों में बुनियादी उद्योगों, मशीनें तैयार करने वाले उद्योगों तथा उत्पादकों के लिए माल तैयार करने वाले उद्योगों में काफी प्रगति हुई है। मशीनें तथा इंजीनियरी का सामान तैयार करने वाले उद्योगों में यह प्रगति विशेषतः उल्लेखनीय है। सरकारी क्षेत्र में तीन नये इस्पात कारखाने खड़े किये गये हैं, जिनके कारण इस्पात की कुल उत्पादन क्षमता, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू में १० लाख टन और दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में १३ लाख टन थी, अब बढ़कर ४५ लाख टन हो जाएगी। सीमेंट, कोयला, अलमुनियम आदि आवश्यक औद्योगिक पदार्थों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। औद्योगिक मशीनों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। १६५१ में १६ करोड़ रु० मूल्य की मशीनें तैयार की गईं, जबकि १६५८ में ७६ करोड़ रु० मूल्य की मशीनें तैयार की गयीं। दूसरी योजना के अन्त तक रेलों के लिए आवश्यक अधिकांश उपकरण देश में ही तैयार होने लगेंगे।

बिजली का भारी सामान बनना भी देश में शुरू हो गया है। रासायनिक पदार्थ, जैसे दवा, खाद आदि के उद्योगों में भी वृद्धि हुई है। दूसरी योजना के दौरान जूट-मिलों तथा कपड़ा-मिलों की आधुनिक यंत्रों से युक्त करने के कार्यक्रम भी शुरू हुए हैं। अधिकांश उद्योगों को बाहर से सामान मंगाने में भारी कमी कर दी गई है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नीचे की तालिका में दूसरे उद्योगों में लगने वाली मुख्य वस्तुओं के ६०-६१ में अनुमित उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं।

वस्तुएं	१९५०-५१	१९६०-६१ अनुमित उत्पादन
तैयार इस्पात	१० लाख टन	२६ लाख टन
अलमुनियम	३.७ हजार टन	१७ हजार टन
डीजल इंजन	५.५ हजार	३३ हजार
बिजली के तार	१,६७४ टन	१८ हजार टन
रेल इंजन	३	२९५
नत्रजनीय खाद	९ हजार टन	२ लाख १० हजार टन
गंधक का तेजाब	९९ हजार टन	४ लाख टन
सीमेंट	२७ लाख टन	८८ लाख टन
कोयला	३ करोड़ २० लाख टन	५ करोड़ ३० लाख टन
खनिज-लोहा	३० लाख	१ करोड़ २० लाख टन

सूती कपड़ा, चीनी, साइकिल तथा मोटर गाड़ियों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

देश में पहली बार कुछ नई वस्तुओं का बनाना भी शुरू किया गया। जैसे—बायलर, पिसाई की मशीनें, मशीनी-औजार, विस्फोटक पदार्थ, सल्फा और एंटीबायोटिक औषधियां, डी० डी० टी० तथा अखबारी कागज आदि।

लघु उद्योग

इस अर्से में ग्रामोद्योगों और लघु-उद्योगों का भी विकास हुआ है। १९५०-५१ से १९६०-६१ के बीच हथकरघा कपड़े का उत्पादन ७४ करोड़ २० लाख गज से बढ़कर २ अरब १२ करोड़ ५० लाख गज, खादी का उत्पादन ७० लाख गज से ८ करोड़ गज और कच्चे रेशम का उत्पादन लगभग २० लाख पौण्ड से बढ़कर ३७ लाख पौण्ड हो गया है। कुछ लघु उद्योगों जैसे हाथ के औजार, सिलाई की मशीनें, बिजली के पंखे और साइकिलें आदि तैयार करने वाले उद्योगों में भी काफी विकास हुआ है। लगभग सभी राज्यों में लघु उद्योग सहायक संस्थाएं बना दी गयीं हैं। इनके अतिरिक्त ४२ विस्तार केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। दूसरी योजना के अंत तक ६० उद्योग नगर बन जाएंगे, जिनमें ७०० छोटे कारखाने होंगे।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की कठिनता का कठोर अनुभव हुआ, आयात बढ़ते गये और उनके मुकाबले में निर्यात नहीं बढ़े। इसलिए कुछ योजनाओं की पूर्ति में विलम्ब हो गया, कुछ योजनाएं स्थगित करनी पड़ी, और विदेशों से विपुल मात्रा में ऋण लिया गया।

बिजली

बिजली उत्पादन की क्षमता, जो १९५०-५१ में २३ लाख किलोवाट थी, १९६०-६१ के अंत तक बढ़कर ५८ लाख किलोवाट हो जाएगी। १९५०-५१ में ३,६८७ गांवों में बिजली लग चुकी थी। १९६०-६१ के अंत तक ऐसे गांवों की संख्या ५ गुनी बढ़कर १९,००० हो जाएगी।

यातायात

पिछली पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य यह था कि युद्ध और विभाजन के कारण रेलों के विकास को जो क्षति हुई है, उसे पूरा किया जाय। दूसरी योजना में इस्पात, कोयला और सीमेंट जैसे बुनियादी उद्योगों के विकास की व्यापक योजनाएं शुरू की गयी हैं। १९६०-६१ के अंत तक १,२०० मील लम्बी नई रेल लाइनें बिछ जाएंगी, १,३०० मील लम्बे रास्ते पर दुहरी रेल लाइनें बिछ जायेंगी तथा ८८० मील रास्ते पर बिजली की रेलें चलने लगेंगी। माल यातायात जो १९५०-५१ में ९ करोड़ १० लाख टन था दूसरी योजना के अंत तक ८० प्रतिशत बढ़कर १६ करोड़ २० लाख टन हो जाएगा। रेल इंजिनों की संख्या जो दूसरी योजना के शुरू में ८,२०० थी, योजना के अंत तक बढ़कर १०,६०० , रेल-डिब्बों की संख्या १९,-२०० से २८,६०० और माल-डिब्बों की संख्या १ लाख ९९ हजार १०० से बढ़कर ३ लाख ५४ हजार १०० हो जाएगी।

पहली योजना शुरू होने के समय ९७ हजार ५०० मील लम्बी सड़कें थीं, जो १९६०-६१ तक १ लाख ४४ हजार मील तक बढ़ जाएंगी। जहाजों का टन भार ३ लाख

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

६० हजार जी० आर टी० से बढ़कर ६ लाख जी० आर० टी० हो जाएगा ।

सामाजिक सेवाएं.

योजना के इन वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है । ६ से १२ वर्ष तक की आयु के स्कूल जानेवाले बच्चों की संख्या जो १९५०-५१ में ४३ प्रतिशत थी १९६०-६१ के अंत तक ६० प्रतिशत तक पहुंच जाएगी । स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में क्रमशः ७५ प्रतिशत और १४० प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी ।

अस्पतालों और कारखानों की संख्या जो १९५०-५१ में ८,६०० थी, १९६०-६१ में बढ़कर १२,६०० हो जायगी । मैडिकल कालेजों की संख्या ३० से बढ़कर ५५ और रजिस्टर्ड डाक्टरों की संख्या ५९,००० से बढ़कर ८४,००० हो जायगी । पहली योजना में परिवार आयोजन का जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसमें काफी प्रगति हुई है । १९५५-५६ में १४७ संतति नियोजन केन्द्र थे जिनकी संख्या १९६०-६१ में १,८०० हो जायगी ।

शिल्पिक शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान

शिल्पिक शिक्षा की सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है । इंजीनियरी और टैक्नालाजी के डिप्लोमा कोर्सों में १९५०-५१ में १०,००० छात्र भर्ती किये जाते थे । १९६०-६१ के अन्त तक यह संख्या चौगुनी बढ़कर ३७,५०० हो जायगी । कृषि और पशु-चिकित्सा कालेजों में १९५०-५१ में १,५०० छात्र भर्ती किये जाते थे, जिनकी संख्या १९६०-६१ में बढ़कर ५,८००० तक पहुंच जायगी ।

रोजगार के लक्ष्य पूर्ण नहीं हुए

योजना के पहले ४ वर्षों में अनाज तथा अन्य कृषि-जिन्सों और बहुत से औद्योगिक पदार्थों के भाव तेजी की ओर रहे । थोक भावों का सूचक अंक (१९५२-५३ = १००) जो पहली योजना के आखिरी वर्ष में ९९.२ था, अगले दो वर्षों में बढ़कर १०५.१ और १०६.१ हो गया । १९५८-५९ में यह अंक बढ़कर १११.७ हो गया । इस वर्ष उच्चतम अंक ११६.३ रहा । १९५९-६० के अंत में यह अंक ११८.६ था ।

दूसरी योजना में रोजगार उस अनुपात में नहीं बढ़े हैं, जितनी कि काम करने वालों की संख्या बढ़ी है । ऐसी आशा थी कि विकास कार्यक्रमों से खेती के अतिरिक्त ८० लाख और लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा । लेकिन इस समय अनुमान है कि लगभग ६५ लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा । ● ●

प्रकाशित हो गई है !

सुभाषित रत्नमाला

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

७ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था । कई वर्ष से पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी ! अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा में प्रकाशित हो रहा है—

- वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी सुविधापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं ।
- श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ ।
- पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियाँ, जिनके उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सकें ।
- आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य ।
- उपहार और पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयुक्त ।

मूल्य एक प्रति १.०० रु० । 'सम्पदा' के ग्राहकों से ००.८० न० पै० प्राप्त होने पर 'बुक पोस्ट अन्डर पोस्टल सर्टिफिकेट' द्वारा भेजी जाएगी ।

अशोक प्रकाशन मन्दिर,

२८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न

श्री चिन्तामणि देशमुख के विचार

भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री चिन्तामणि देशमुख भारत के माने हुए अर्थशास्त्रियों में हैं। बहुत समय के बाद उन्होंने देश के महत्वपूर्ण आर्थिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। हम संक्षेप से उन्हें यहां दे रहे हैं :

दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भी औद्योगिक विकास को कुछ भी शिथिल कर देना वांछनीय नहीं है, वह तो हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिये। अर्थ-व्यवस्था में स्वाश्रयी और स्वावलम्बी होने के लिए भारी उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है।

× × ×

दूसरी योजना में यदि हम कृषि उत्पादन में पूर्णतः सफल नहीं हुए, इसका मुख्य कारण, प्रबन्ध की शिथिलता है। हम रासायनिक खादों और हरी खादों की सन्तुलित व्यवस्था नहीं कर पाए। तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह मेरी सम्मति में ठीक है।

× × ×

किसी देश के विकास के लिए निम्नलिखित का विकास आवश्यक है :

१. कृषि, २. भारी उद्योग, ३. लघु उद्योग और ४. ग्रामोद्योग।

इन चारों में प्राथमिकता और महत्व की दृष्टि से योजना आयोग के निर्णय मुझे ठीक प्रतीत होते हैं। यदि विदेशों से अधिक सहायता मिले तो मेरी सम्मति में लघु-उद्योगों के लिए कच्चा माल मंगाने में उसका प्रयोग होना चाहिये। ग्रामोद्योगों का इस तरह संगठन और व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वे दृढ़ आर्थिक आधार पर खड़े हो सकें।

× × ×

जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि को देखते हुए २५ सालों में जाकर हम प्रति व्यक्ति—आय दुगुनी कर सकते हैं, किन्तु इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें ५५ करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

पहली पंचवर्षीय योजना में कुल राष्ट्रीय आय ३ प्रतिशत तक बढ़ी है (प्रति व्यक्ति नहीं)। दूसरी योजना के अनुसार यह आय ४ प्रतिशत तक बढ़नी चाहिए।

× × ×

यदि हमारा कृषि उत्पादन बहुत कम बढ़ा और मुद्रा-प्रसार ज्यादा हुआ तो मूल्यों के बढ़ने की पूरी संभावना है, हमारी विदेशी मुद्रा भी बहुत कम रह गई है, इसलिए मुद्राप्रसार में घाटे की व्यवस्था बहुत सोच-समझ कर करनी होगी।

× × ×

कम्पनियों पर से सम्पत्ति कर हटने के बाद मैं वर्तमान कर व्यवस्था में भारी दोष नहीं देखता। मेरी तो राय यह है कि कर लगाने की न्यूनतम सीमा और कम कर देनी चाहिए और जमीन की मालगुजारी की दर बढ़ा देनी चाहिए और वह रुपया स्थानीय विकास में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। देश की ४५ प्रतिशत जनता वस्तुतः नमक कर देने में भी असमर्थ है और फिर कपड़े पर उत्पादन कर के रूप में सभी देशवासियों को कुछ न कुछ कर देना ही पड़ता है।

× × ×

शराब-बन्दी का कोई आर्थिक महत्व हो, यह मैं नहीं मानता। गैर कानूनी भट्टियों ने हमारी शासन व्यवस्था को परास्त कर दिया है; और कानून का शासन कमजोर हो गया।

× × ×

मैं भारत में विदेशी पूंजी आने से कोई खतरा नहीं देखता। प्रत्येक उद्योग में अनुपात पर अलग-अलग विचार करना होगा।

—वस्त्रोद्योग संघ ने यह अनुमान लगाया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य १६.३ गज प्रति-व्यक्ति कपड़े की खपत है। तीसरी योजना में यह लक्ष्य १८.५ गज नियत किया जा रहा है। इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उद्योग को कम से कम ७० करोड़ रुपये का विनियोजन करना पड़ेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सरकारी उद्योगों में निजी पूंजी

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

●

'सम्पदा' के पाठक यह जानते होंगे कि पश्चिमी जर्मनी में सरकारी उद्योगों में निजी पूंजी लगाने की प्रकृति शनैः शनैः बढ़ रही है। एक ओर कुछ देश निजी उद्योगों को भी सरकारी सम्पत्ति बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पश्चिमी जर्मनी की सरकार सरकारी उद्योगों के द्वार निजी पूंजी के लिए खोल रही है। प्रीसाग के कारखानों के शेयर अब कुछ शर्तों के साथ साधारण जनता को बेचे जाने लगे हैं।

इस प्रवृत्ति के दो उद्देश्य हैं—एक तो यह कि उद्योगों के लिए सरकार पर बहुत अधिक बोझ न पड़े और दूसरा यह कि जनता की सरकारी उद्योगों में स्वयं रुचि उत्पन्न हो और वह उन्हें अपना उद्योग समझने लगे। ऐसा करते हुए जर्मन सरकार ने कुछ प्रतिबन्ध इस भय को दूर करने के लिए अवश्य लगाए हैं कि उद्योग का संचालन कुछ एक गिने-चुने लोगों के हाथ में न चला जाए। वही लोग ये शेयर खरीद सकेंगे, जिनकी आमदनी एक सीमित मात्रा से अधिक न हो और वे भी एक नियत संख्या में ही शेयर ले सकेंगे। ये शेयर होल्डर उद्योग के संचालन में और डायरेक्टरों के चुनाव में वोट दे सकेंगे।

दोनों पद्धतियों के गुण

इस नई व्यवस्था में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के दोषों से बचने की चेष्टा की गई है। समाजवाद में उद्योगों पर सरकार के गिने-चुने अधिकारियों का नियंत्रण रहने से सत्ता केन्द्रित हो जाती है पूंजीवाद में भी कुछ सम्पन्न लोग देश की आर्थिक सत्ता पर अधिकार जमा लेते हैं। इस नई व्यवस्था में न इने गिने सरकारी कर्मचारियों और न इने गिने पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता केन्द्रीभूत होगी। मध्य-वित्त वाले हजारों शेयर होल्डर किसी उद्योग के स्वामी होंगे और तब जनता का शोषण नहीं हो सकेगा। उसी उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को शेयर बेचने में प्राथमिकता दी जायगी।

जो समस्या जर्मनी के सामने है, वही भारत के भी है। पिछले कुछ वर्षों से समाजवादी आदर्श और उद्योग के नाम पर उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इन वर्षों में बहुत से सरकारी उद्योग खुले भी हैं, इनमें देश की करोड़ों अरबों रुपए कि पूंजी लगी है। आगामी वर्षों में और भी बहुत से ऐसे उद्योग खुलने वाले हैं, जो घोषित नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के होंगे।

पूंजी दुर्लभ

इन बहुसंख्यक और विशाल उद्योगों के लिए पूंजी को प्राप्त करना आसान नहीं है। कृषि, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई और बिजली तथा सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए सरकार को अनन्त राशि व्यय करनी पड़ेगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी कुछ साधनों की व्यवस्था नहीं की जा सकी थी। इसलिए यदि किसी स्रोत से नए साधन प्राप्त हो सकें, तो सरकार उनका स्वागत ही करेगी।

जनता का योगदान

१९५६ में सरकारी वित्त मंत्रालय ने अपने व्यापारिक संस्थानों में जनता को भाग लेने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया था, किन्तु यह विचार अधिक बल नहीं पकड़ सका। उस समय सरकारी उद्योग बहुत कम थे, इसलिए इसकी गंभीर आवश्यकता भी अनुभव नहीं की गई। देश के राजनीतिक नेता भी समाजवादी आदर्शों के मोह में पड़े रहे। उसकी विचार दिशा अधिकाधिक सार्वजनिक उद्योग खोलने की रही। किन्तु इस सैद्धांतिक आदर्श से वास्तविक समस्या का तो समाधान नहीं हो सकता, इसलिए सरकारी मंत्रालय और एस्टीमेट कमेटी इस प्रश्न पर विचार करती रही। उक्त कमेटी ने सिद्धांत रूप से इस विचार से सहमति प्रकट की, किन्तु जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो योजना आयोग के भी अध्यक्ष हैं, इस विचार से सहमत न हों, तब तक गाड़ी आगे नहीं चल सकती थी।

नेहरू सहमत

अब मालूम हुआ है कि श्री जवाहरलाल नेहरू भी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस प्रस्ताव से सहमत हो गए हैं, इसलिए कम्पनी ला विभाग के सेक्रेटरी श्री डी० एल० मजुमदार की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। वह कमेटी सरकार द्वारा संचालित उद्योगों की पूंजी में जनता को भाग लेने की अनुमति पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार करेगी। यदि यह प्रस्ताव तेजी से अमल में आ जाय, तो इसमें संदेह नहीं कि जनता पूंजी के काफी हिस्से खरीद कर सरकार का बोझ कम कर सकेगी।

मूल उद्देश्य

प्रश्न यह है कि इस नीति के मूल में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है ? यदि केवल तीसरी योजना के लिए साधन संग्रह ही इसका उद्देश्य हो तो कोई कठिन समस्या उत्पन्न नहीं होगी। केवल सरकार को तय करना होगा कि किसी नियत उद्योग में सरकार स्वयं कितनी पूंजी लगाए और शेष कितनी जनता के खरीदने के लिए उन्मुक्त कर दे। यह भी संभव है कि सरकार जनता के लिए केवल 'प्रिफरेन्स शेयर' खोले। इस अवस्था में शेयर होल्डरों के प्रतिनिधित्व की कठिन समस्या भी नहीं रहेगी और वह जनता को अपने नफे में हिस्सेदार बना सकेगी। लेकिन यह न भूलना चाहिए कि जनता तभी ये 'प्रिफरेन्स शेयर' खरीदेगी, जब उसे सरकारी ऋणों के ब्याज की अपेक्षा अधिक लाभ होगा।

क्या किया जाए ?

कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि 'प्रिफरेन्स शेयर' बहुत अधिक आकर्षक सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए सरकार को साधारण शेयर ही बेचने होंगे। इस अवस्था में सरकार को यह देखना होगा कि कुछ लोग अधिकाधिक शेयर खरीदकर सत्ता या लाभ को केन्द्रीभूत न कर लें। इस भय को दूर करने के लिए सरकार दो उपाय काम में ला सकती है: एक तो यह कि वह वोटों पर प्रतिबन्ध लगादे कि कोई व्यक्ति अधिक शेयर रखकर भी अधिक वोट नहीं दे सकता। इस तरह नियंत्रण की शक्ति सीमित हो जायगी। दूसरा उपाय यह कि कोई व्यक्ति नियत संख्या से अधिक शेयर न ले सके, ऐसी व्यवस्था कर दी जाय। यद्यपि कुछ अर्थशास्त्री इसमें यह भय देखते हैं कि पूंजी बहुत आकृष्ट नहीं होगी तथापि हमारी नम्र सम्मति में नियंत्रण शक्ति को केन्द्रित न होने देने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है।

सरकारी उद्योग इतने वृहताकार हैं और उनमें उसकी इतनी विशाल पूंजी लगी है कि कुछ लोग अधिकाधिक शेयर खरीदकर भी नियन्त्रण की शक्ति अपने हाथ में नहीं ले सके। पश्चिमी जर्मनी की तरह भारत सरकार भी यह बन्धन लगा सकती है कि मध्यवित्त वाले और उन उद्योगों के मजदूर ही शेयर खरीद सकें। इस व्यवस्था में धन के अधिकाधिक वितरण का समाजवादी आदर्श भी सुरक्षित रहेगा।

अमरीका और इंगलैंड के अनेक बड़े उद्योग भी अपने पूंजीगत साधनों को बढ़ाने और उद्योगों में शान्ति कायम रखने के लिए बड़ी सरल शर्तों पर मजदूरों को शेयर बेचने लगे हैं। इस व्यवस्था से मजदूर भी उद्योगों के सह-स्वामी हो जाएंगे।

हमें आशा रखनी चाहिए कि सोच समझ कर सरकार पर्याप्त साधन एकत्र कर लेगी और अपने शेष साधनों को समाज कल्याण में व्यय कर सकेगी। ● ●

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनीतिक अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिकअली

सम्पादक : श्री सुनील गुह

★ हिन्दी में अनूठा प्रयास

★ आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख

★ आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्रम समस्या

उद्योगों में वेतन

भिन्न-भिन्न उद्योगों में हजारों मजदूर काम करते हैं। उद्योग की किस्म, उनके लाभ, मजदूरों की दक्षता और उनकी उपलब्ध संख्या के अनुसार अलग-अलग वेतन मिलता है, सबसे अधिक मजदूर कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। उन्हें लोहा उद्योग को छोड़कर अन्य सब उद्योगों से अधिक वेतन मिलता है। इसके बाद पटसन उद्योग में मजदूरों की संख्या ज्यादा है और उन्हें प्रति-व्यक्ति १००) से अधिक वेतन मिलता है। इसके बाद जनरल इंजीनियरिंग उद्योग का नम्बर आता है। निम्न-लिखित तालिका से विभिन्न बड़े उद्योगों में लगे हुए मजदूरों की संख्या। उन्हें मिलने वाला कुल वेतन और व्यक्ति वेतन आदि की जानकारी मिलेगी।

लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि मजदूरों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को अधिक वेतन मिलता है, इसका अन्तर भी निम्नलिखित तालिका से प्रकट है।

मजदूर-संघों की लोकप्रियता

देश में संगठित मजदूर संघों में कभी-कभी यह विवाद खड़ा हो जाता है कि कौन मजदूरों का सच्चा प्रतिनिधि है और किसे अधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित निम्न-लिखित अंकों से यह स्पष्ट हो जाता है और विवाद की गुंजाइश नहीं रहती।

भारत सरकार ने ३१ मार्च १९५९ तक देश के चार ट्रेड यूनियन संगठनों की सदस्य संख्या की जांच पड़ताल करके उसका परिणाम घोषित कर दिया है। इन्टक एक बार फिर प्रतिनिधि ट्रेड यूनियन संगठनों में से सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली ट्रेड यूनियन निकली। उसकी पुनरीक्षित सदस्य संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार १०,१८,४४५ है, जो कि सब ट्रेड यूनियनों की सम्मिलित सदस्य संख्या से ज्यादा है। अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की सम्मिलित सदस्य संख्या ८,३९,८०३ है अर्थात् कम्युनिस्ट संचालित एटक को ५,०६,३०४ सोशलिस्ट संचालित हिन्द मजदूर सभा की २,४०६२२ तथा यूटक की ८९,८७७ है।

विभिन्न उद्योगों में श्रम

	रोजगार में लगे हुए मजदूरों की संख्या (हजारों में)	पारिश्रमिकों में दी गई धनराशि (हजार रु० में)	प्रति मजदूर पारिश्रमिक रुपयों में	रोजगार में लगे मजदूरों के अतिरिक्त काम में लगे अन्य व्यक्तियों की संख्या	कुल वेतन की धनराशि (हजार रुपयों में)	प्रति व्यक्ति वेतन
सूती कपड़ा उद्योग	७०४	९५७,११०	१३६०.००	५८.००	१६२,८४८	२८२७.००
ऊनी कपड़ा उद्योग	१४	२४,७७५	१०५५.३५	२.००	४,६१७	१७००.००
पटसन उद्योग	२३०	२३६,३५२	१०२८.००	१५.००	३७,३८४	२५०१.००
चीनी उद्योग	९८	७२,५८४	७४१.००	२०.००	२८,८१९	१४७६.३८
तेलघानी उद्योग	३८	१९,८८४	५२३.२६	७.३८	८,७१४	११८१.००
लोहा और इस्पात उद्योग	७५	१३९,७१७	१८६३.००	१७.००	५३,३०६	३२१७.०१
इंजीनियरिंग उद्योग	१५९	१८८,१५५	११८३.३६	३९.१९	७८,८७४	२०१३.००
कुल	१३१८	१६२८,५७७	१२३६.००	१५७.००	३७४,५५४	२३८७.००

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सन्तति निरोध : एक दूसरा पहलू

विवेचक

जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण की ओर भारत सरकार का ध्यान पिछले कई वर्षों से बरबस खिंचा जा रहा है। प्रतिव्यक्ति स्तर को ऊँचा करने की समस्या में, जनसंख्या वृद्धि-नियंत्रण घातक रोग के लिए रामबाण जैसा माना गया है। व्यक्ति मात्र के जीवन स्तर को ऊंचा करने का वास्तविक तरीका आर्थिक-विकास है, जिससे प्रति व्यक्ति को उत्पादन का उचित हिस्सा मिल सकता है, किन्तु इसमें भारी पूंजी की आवश्यकता होगी, और भारी पूंजी जमा करने के लिए, गृहबचत योजना, भारी विदेशी सहायता तथा ऋण व्यवस्था आदि कई कठिन समस्याएँ हैं। इन तमाम कठिनाइयों को पार किया जा सकता है, यदि जनसंख्या स्वयं घट जाय। जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की बजाय स्वयं जनसंख्या में ही कमी करने से समस्या कुछ सरल अवश्य हो जायगी, लेकिन यह अवास्तविक उपाय है। इस तरीके को अपनाने में संयुक्त राज्य अमरीका और जापान के सिवाय और कोई भी देश सफल नहीं हो सका। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर भारत से कम रही हो। वस्तुस्थिति यह है कि १,८०० ई० सन् के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों के मुकाबले में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक नहीं रही है।

संसार के अर्थशास्त्री इस समस्या पर पर्याप्त समय से विचार कर रहे हैं। दो महान अर्थशास्त्रियों ने बताया है—

"अठारहवीं शताब्दि के अन्तिम और उन्नीसवीं शताब्दि के पूर्वार्ध के समय की जनसंख्या की समस्या बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों के अध्ययन का केन्द्रबिन्दु रही है। परन्तु धीरे-धीरे इस ओर से ध्यान हटता गया, क्योंकि समस्या के समाधान का कोई हल नहीं मिल सका, और संभवतः इसका यह भी कारण रहा हो कि जनसंख्या के प्रश्न का समाधान आर्थिक विश्लेषण के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता।

यद्यपि यूरोप में जनसंख्या में कमी और अविकसित देशों में अत्यधिक वृद्धि के दबाव ने लोगों में सर्वेक्षण के लिए रुचि पैदा की, परन्तु बहुत कुछ प्रयत्न किये जाने पर अभी तक इस दिशा में सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकल सके।

मूल प्रश्न

जहाँ तक भारत का सवाल है, अवश्य ही जनता ने अन्धविश्वासों और तंगखयाली के कारण सन्तति-निरोध के लिए वैज्ञानिक उपचारों की ओर ध्यान नहीं दिया, पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये ही अकेले जनसंख्या-नियंत्रण की असफलता के कारण रहे हों। जब यह कोशिश की जाती है कि जनसंख्यावृद्धि में कमी लाई जाय तो सबसे पहले सवाल यह खड़ा होता है कि देश में आखिर कितनी न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, जो देश के आर्थिक विकास में समर्थ हो। जहां तक हमारा ज्ञान है भारत में इस प्रश्न का उत्तर कभी देने का प्रयत्न नहीं किया गया और न ही इसके समाधानकारक तथ्यों की जांच-पड़ताल व खोज की गई। जब आज तक इस मूल प्रश्न का हल निकाला ही नहीं जा सका, तब हम किस चीज के पीछे पड़े हैं? क्या हम छाया से ही लोहा ले रहे हैं? ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी योजनाबद्ध कोशिशों में अन्य अवास्तविक तथ्यों के साथ यह भी व्यर्थ का बखेड़ा तथा सिर-पिटाई है, जिस पर हम व्यर्थ में अपनी शक्ति का ह्रास कर रहे हैं। जब इस मुख्य उद्देश्य के समाधान के लिए हल का कहीं कोई छोर ही नहीं मिल पाता, तब इसके पीछे दीवाना बनने की क्या आवश्यकता? वास्तविक रूप में होना तो यह चाहिए कि सन्तति-निरोध आन्दोलन चलाने से पहले उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए कि देश को कितनी जनसंख्या की आवश्यकता है?

यह मान भी लिया जाय कि आज भारत में लोग केवल अपनी ही जगह लेने के लिए सन्तति पैदा करें अथवा एक दम्पत्ति दो से अधिक बच्चे न पैदा करे, तब उस हालत में हमारी जनसंख्या १९८६ तक ६१ करोड़ ५० लाख तक ही रह सकेगी और यदि जन्म का अनुपात आज का ही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

रहा तो उस वर्ष तक जनसंख्या ७४ करोड़ ३० लाख हो जाएगी।

१९८६ तक ६१ करोड़ ५० लाख से अधिक जनसंख्या न होने देने के उद्देश्य में कई सन्तति-निरोधक उपाय अवश्य ढूंढ़ने होंगे। हम यह मान भी लें कि वैज्ञानिक उपचारों से सन्ततिनिरोध की भावना देश में बलवती होकर सफलता लाएगी, तो भी क्या इससे देश की आर्थिक समस्या सुलझ जायगी। हमारे सामने दो विकल्प हैं। प्रश्न यह है कि आर्थिक समस्या को सुलझाने में हम कौनसा विकल्प चुनें ? ६१ करोड़ और ५० लाख की सीमित जनसंख्या का या ७४ करोड़ ३० लाख की जनसंख्या का ? कुछ लोग १९८६ तक ७४ करोड़ ३० लाख के स्थान पर ६१ करोड़ ५० लाख तक ही जनसंख्या सीमित करना वांछनीय समझते हैं और यह सोचते हैं कि इससे व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। परन्तु मेरे विचार से वे इसके केवल शास्त्रीय ढांचे के भूल-भुलैये में फँस गए हैं। २,००० ई० सन् तक देश की जनसंख्या, जन्म व मृत्यु की स्थिति में परिवर्तन आजाएगा और देश नई समाज व्यवस्था की ओर मोड़ ले चुकेगा। उस स्थिति में सन्तति-निरोध से वृद्ध नर-नारियों की आनुपातिक संख्या में भारी वृद्धि हो जायगी, जिससे युवक-युवतियों के ऊपर उनके पालन का भार बहुत बढ़ जायगा। आज तो देश में अर्जनशील युवकों की संख्या वृद्धों के मुकाबले में बहुत अधिक होती है। लेकिन सन्ततिनिरोध के प्रचार से युवक तो कम होने लगेंगे और वृद्ध, जो देश के आर्थिक विकास में बहुत कम सहायक होंगे, बढ़ते जायेंगे। फलतः गरीबी कम नहीं होगी। इस नई समस्या की कल्पना से उन लोगों की आँख खुल जानी चाहिए, जो देश में गरीबी मिटाने के लिए सन्तति-निरोध को ही मुख्य हल समझते हैं। सन्ततिनिरोध द्वारा गरीबी कम करने के बजाय गरीबी के मूल तथ्यात्मक कारणों को ढूंढना चाहिए। सच तो यह है कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण पिछड़ी कृषि पद्धति है और उस पर जनसंख्या का अधिकांश भार है। कृषियोग्य अधिकांश भूमि पर लोग छोटे-छोटे घरौंदे, और कारखाने बनाए फैले हुए हैं। ऐसी बात यूरोपीय देशों में नहीं है। इसलिए देश की गरीबी का मुख्य हल सन्तति-निरोध नहीं बल्कि खेती के विकास के लिए खेती करनेके ढंग में परिवर्तन है जिससे प्रति एकड़ उत्पादन बढ़े। ● ●

आप 'सस्ता साहित्य मंडल' की पुस्तकों के प्रेमी हैं। सस्ता साहित्य के व्यापक प्रसार में कृपया योग दीजिये। अपने इष्ट मित्रों, अपने क्षेत्र की संस्थाओं तथा पुस्तकालयों से अनुरोध कीजिये कि वे 'मंडल' की पुस्तकें अपने यहाँ अवश्य रखें।

पर ऐसा आप तभी कर सकेंगे
जबकि
'मंडल' के नये प्रकाशनों से
आपका परिचय रहे। इसके लिए आप

जीवन-साहित्य

के ग्राहक बन जाएं उसके प्रत्येक अंक में 'मंडल' के
नवीनतम प्रकाशनों की सूचनाएं रहती हैं
पत्र की सामग्री भी अत्यन्त उपादेय है
वार्षिक मूल्य केवल रु. ४.००

सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली।

उद्योग-व्यापार पत्रिका

देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण में कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई कर सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या दशा है ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही है ? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य जानने चाहिएँ, और इन सबकी जानकारी पाने का श्रेष्ठ साधन है—उद्योग व्यापार पत्रिका इसलिये आप ६ रु० भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक बनइये। नमूना पत्र लिखकर मंगाइये।

एजेन्टों को भरपूर कमीशन।

पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है।

वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत अमेरिकी सहयोग के दस वर्ष

सी० टायलर वुड

१६५१ में अमेरिका ने भारत को १६ करोड़ डालर (६० करोड़ रु०) का लगभग २० लाख टन गेहूँ भेजा था। अब हम संसार के दो बड़े लोकतंत्री देशों के बीच आर्थिक सहयोग के १० वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। अमेरिका ने भारत को अब तक कुल ३॥ अरब डालर (१,६६६ करोड़ रु०) की सहायता दी है। इसमें ५ अरब रु० के अनुदान और ६ अरब ३० करोड़ रु० के वे ऋण भी शामिल हैं, जिनका भुगतान रुपयों में किया जायेगा। कुल अमेरिकी सहायता के लगभग १० वें हिस्से का भुगतान डालरों में किया जायेगा। ऋणों का भारतीय मुद्रा में भुगतान करने से भारत को न तो अपनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी और न माल का निर्यात करके ही ऋण की अदायगी करनी होगी।

यह सहयोग पुस्तकों के रूप में है, जो बुद्धिजीवी को प्रेरणा देती हैं और कालेज के छात्र की जिज्ञासा शान्त करती हैं। यह सहयोग इलैक्ट्रो-एनसैफालोग्राफ मशीन की शक्ल में है, जो रोगी के मस्तिष्क के वैद्युतिक प्रभावों को बतलाती है और शल्य-चिकित्सक को गांठ का पता लगाने में मदद देती है। यह सहयोग रासायनिक खाद के उपयोग की नई विधि के रूप में है, ताकि किसान अपनी मेहनत और पूंजी का अधिक लाभ उठा सकें। यह सहयोग भारतीय इंजिनियर को अमेरिका में उच्च प्रशिक्षण देने की शक्ल में है, जिससे यह विशाल बांध के निर्माण में पेश आने वाली जटिल समस्याओं को हल करने में अधिक समर्थ हो सके।

भारत और अमेरिका का यह आर्थिक सहयोग इकतरफा नहीं है। इस सहयोग से अमेरिका को भी लाभ पहुंचता है, क्योंकि हमारा अनुभव है कि हमारी खुशहाली का शेष संसार की सुख-समृद्धि से गहरा सम्बन्ध है। प्रधान मंत्री नेहरू ने एक बार कहा था, 'खुशहाली ऐसी चीज नहीं है जिसके टुकड़े किए जा सकें। दुनिया सिमट कर इतनी छोटी हो गई है कि यह मुमकिन नहीं कि उसका एक हिस्सा तो गरीबी और मुसीबतों का शिकार बना रहे और दूसरा हिस्सा फलता-फूलता रहे।'

भारत की पुरानी संस्कृति उन सैद्धान्तिक विचारों का स्रोत रही है, जिनसे अमेरिका के ज्ञानकोष में वृद्धि हुई है। पिछली सदी में अमेरिकी किसानों की एक टोली सिंचाई का तरीका सीखने के लिए भारत आई थी। इस देश में प्रागैतिहासिक काल से ही सिंचाई के तरीके अपनाए जाते रहे हैं।

मलेरिया उन्मूलन सहायता

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हमारे दोनों देशों के बीच सफल सहयोग का एक उदाहरण है। मलेरिया हमेशा भारत का सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता रहा है। सात साल पहले अनुमानतः ७॥ करोड़ भारतीय प्रति वर्ष मलेरिया से पीड़ित होते थे और ८ लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी। १६५३ में भारत सरकार ने मलेरियाग्रस्त क्षेत्रों में डी-डी-टी नामक कीटमार दवा छिड़कने का कार्यक्रम चालू किया। अमेरिका ने भी इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में हाथ बटाया। अब तक अमेरिका मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ३७ करोड़ रु० से अधिक दे चुका है। अनुमान लगाया गया है कि पिछले साल सिर्फ ४० लाख लोग ही मलेरिया से पीड़ित हुए।

अमेरिका ने अनेक प्रमुख नदी घाटी विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है। इनमें रेहण्ड, हीराकुंड, चम्बल, दामोदर, नागार्जुन सागर, कोसी, भद्रा, तुंग भद्रा, कुण्डा और पराबती की योजनाएं भी शामिल हैं। अमेरिका ने इन योजनाओं के लिए सब मिलाकर १ अरब २० करोड़ रु० के अनुदान और ऋण दिए हैं। भारत दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और विद्युत विकास योजनाओं पर ६ अरब रु० से अधिक खर्च कर रहा है और अमेरिका ने जो मदद दी है, वह इस देश द्वारा दिए जाने वाले महान् प्रयत्न का सिर्फ ८ वां हिस्सा है। तथापि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जहां तक रेहण्ड योजना का सम्बन्ध है, अमेरिका कुल खर्च का लगभग ४० प्रतिशत देगा। इस योजना द्वारा २॥ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाएगी और एक जलाशय तैयार किया जायेगा, जिसमें ४६ लाख एकड़ फुट पानी जमा किया जा सकेगा।

बिजलीघरों का निर्माण

दामोदर घाटी के चन्द्रपुरा ताप बिजलीघर में २॥ लाख किलोवाट बिजली तैयार की जायेगी। इस बिजलीघर के निर्माण पर ३५ करोड़ रु० खर्च आयेगा। बरौनी (बिहार) के बिजलीघर का निर्माण भी पूरी तरह अमेरिकी सहायता से किया जा रहा है। यहां ३०,००० किलोवाट बिजली तैयार की जायेगी।

भारत ने अमेरिका के साथ अब तक ५ समझौते किये हैं। इन समझौतों द्वारा भारत को १.०६८ करोड़ रु० का २८० लाख टन से अधिक गेहूँ और चावल हासिल होगा।

वित्तीय संस्थाओं को सहायता

भारत की दो उच्च शिक्षण संस्थाओं—उत्तरप्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय तथा कानपुर के इण्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी' को भी बड़े-बड़े अनुदान मिले हैं। औद्योगिक कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली तीन मुख्य संस्थाओं—'रिफाइनेंस कार्पोरेशन' 'दि इण्डस्ट्रियल क्रैडिट एण्ड इन्वैस्टमैण्ट कार्पोरेशन ऑव इण्डिया' और 'इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन को भी सब मिलाकर ४६ करोड़ रु० के कर्ज मिले हैं।

अमेरिकी टैक्निशियन इस समय बीसियों क्षेत्रों में अपने भारतीय सहयोगियों को अपनी जानकारी का लाभ पहुँचा रहे हैं। एक योजना के अधीन करण्ट चालू रखते हुए बिजली के तारों की मरम्मत की जाती है। ग्राहक को बराबर बिजली देते रहने के लिए यह जरूरी है कि भारत में बिजली की दोहरी लाइनें हों। यदि एक ही लाइन हो तो मरम्मत करते समय बिजली बंद करनी पड़ेगी। इससे बिजली इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को बड़ी असुविधा होती है, उत्पादन घट जाता है और आमदनी कम हो जाती है। यदि दोहरी लाइनें लगानी पड़ें तो उससे बिजली उत्पादन के कार्यक्रम में भारी कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन एक विशेष विधि और सुरक्षा वाले औजारों का प्रयोग करके बिजली कर्मचारियों के जीवन को खतरे में डाले बिना ही उस समय भी बिजली के तारों की मरम्मत की जा सकती है, जब उसमें करण्ट चालू हो। गंगूवाल और बंगलौर के प्रशिक्षण केन्द्रों में विभिन्न राज्यों के बिजली मिस्तरियों को नई विधि की शिक्षा दी जा रही है। टैक्निकल सहयोग मिशन ने इस योजना में जो सहायता दी है वह २० लाख रु० से भी कम है। लेकिन इस नई विधि के इस्तेमाल से भारत को करोड़ों रुपयों की बचत हो जायेगी।

भारत ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए विदेशी सहायता से सिर्फ थोड़ी सी ही मदद मिलती है और भारत की अब तक की प्रगति मुख्यतः उनके अपने प्रयत्नों का ही फल है। ● ●

सबसे सस्ता और सुन्दर सचित्र मासिक

जागृति

संस्थापित १६४८

जिसे राष्ट्र भाषा के प्रायः सभी प्रमुख लेखकों, कवियों और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है। चार कहानियां, एक एकांकी, ६ लेख

तिरंगा आवरण अनेकों इक रंगे चित्र
५२ से ६४ पृष्ठ की सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर
इस पर भी मूल्य केवल २५ नए पैसे

एजेन्टों को ५ से १०० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें :

व्यवस्थापक, 'जागृति' कार्यालय, लोक सम्पर्क विभाग, पंजाब, चंडीगढ़

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बढ़ता हुआ उत्पादन कर

१९३०-३१ में उत्पादन कर से होने वाली आय केवल ६.१६ करोड़ रुपए की थी १९५०-५१ में यह बढ़कर ८६ करोड़ हो गई और चालू वर्ष में इस कर से ३४० करोड़ रुपए आमदनी का अनुमान है। इस वृद्धि के मुख्य चार कारण हैं—

१. नई-नई वस्तुओं पर उत्पादन कर लगता गया,

२. उत्पादन कर की दरों में लगातार वृद्धि होती गई।

३. पदार्थों के उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती गई।

४. वस्त्र और चीनी पर बिक्री कर उत्पादन कर में बदल गया।

प्रायः प्रत्येक वित्तमंत्री ने उत्पादन कर पर अपनी शनि दृष्टि रखी है। १९५४ से पहले पैट्रोल, किरासन तेल, चीनी, दियासलाई, तम्बाकू और वस्त्र पर उत्पादन कर लग चुका था। १९५४ में सीमेंट, साबुन और जूता, १९५५ में ऊनी कपड़े, बिजली के पंखे आदि तथा १९५६ में लोहे तथा टीन की चादरें, बिजली की मोटर तथा पुर्जे, सिनेमा की उतरी हुई फिल्मों आदि पर कर लगा दिया गया। साइकल की फ्री ह्वील तथा रिम भी इस कर से नहीं बची।

एकबार उत्पादन कर लग जाने पर वह बढ़ता रहता है। दियासलाई पर प्रति ग्रौस रु० १.५० न. पै. कर था। आज यह कर रु. ४.९० न. पै. है। चीनी पर उत्पादन कर से १९५०-५१ में ६॥ करोड़ रुपए की आय हुई थी। इस वर्ष ४६॥ करोड़ की आय होने की आशा है। इसी प्रकार वस्त्र पर उत्पादन कर ९ करोड़ से बढ़कर ४३ करोड़ रुपए, दियासलाई पर ८ करोड़ रुपए से बढ़कर १८ करोड़ रुपए आय का अनुमान है।

दस वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार की करों से होने वाली आय में उत्पादन कर का भाग १९ प्र० श० था। अब इसका भाग करीब ५० प्र० श० है। करीब तीसरी पंचवर्षीय योजना में १६५० करोड़ रुपए के अतिरिक्त करों से उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। इसका सबसे अधिक असर बहुत संभवतः उत्पादन करों पर ही पड़ेगा।

रूस के विद्यार्थी

रूस के बालकों में किस तरह देश-भक्ति राष्ट्रीयता और स्वावलम्बन के भाव उत्पन्न किये जाते हैं, यह उन पताका-घोषों से ज्ञात होता है, जो वे अपनी-अपनी टुकड़ियों के साथ किशोर शिविरों में गर्मियों की छुट्टी में ले जाते हैं। इन घोषों के नमूने कुछ निम्नलिखित हैं—

१. हम अपने स्कूल की सफेदी-रंगाई अपने आप करेंगे।

२. हमने रेल के तीन डीजल इंजन लायक धातु कबाड़ बटोरे हैं।

३. हमने एक सामूहिक फार्म का एक बिजली घर बना दिया है, दो और बनाएँगे।

देशभक्ति की ऊँची भावनाओं से ओत-प्रोत विद्यार्थी कल देश का निर्माण करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के विद्यार्थी कभी एक अध्यापक को निकालने का नारा लगाते हैं, कभी दूसरे को, कभी 'मेस' के प्रबन्ध के विरोध में हड़ताल करते हैं, तो कभी शिक्षणालय के दरवाजों, मेजों तथा दूसरे फरनीचर को आग लगाने का हुड़दंग मचाते हैं। इन अनुशासनहीन विद्यार्थियों से निर्माण की आशा कैसे की जाय?

गुजरात में तेल

गुजरात के खम्भात और समीपवर्ती प्रदेश में खनिज तेल के कुयें खोदे जा रहे हैं। इस कार्य में सोवियत रूस प्रशंसनीय सहायता दे रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ विवरण नीचे दिया जा रहा है।

खंभात चौरस और खुले मैदान में पड़ता है। धरती-तल पर चट्टानों का उभार आसपास कहीं नहीं है। खंभात के चारों ओर की धरती उपजाऊ है।

सोवियत इंजीनियर ले० वा० अलीयांचेकोव दिसम्बर १९५७ में खंभात पहुंचे। वे साथ में एक बरमा यंत्र लाये थे। उसकी क्षमता ५,००० मीटर की गहराई तक बरमाने की थी। उसके बाद वहां और कितने ही सोवियत विशेषज्ञ आये हैं। अनेक भारतीय विशेषज्ञ भी पहुंचे हैं। भारतीय कर्मियों की सलाह से यह तय पाया कि खंभात से आठ मील पश्चिम लुनेज गांव में बरमाई शुरू की जाय। बरमाई फरवरी १९५८ में शुरू हुई। ४ सितम्बर को

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

५,००० फुट की गहराई में ऊँचे तापमान की गैस और तेल का सुराग मिला। इस पहले तेल कूप को बरमाने का काम पूरा करने में कुल ९२ दिन लगे।

खंभात के कर्मियों ने ७ तेलकूप बरमाये हैं। सातों में तेल का पता पाने में सफलता मिली है। लगातार सात-सात कूपों में सफलता पाना दुनिया में यह पहली बार ही हुआ है। इस तरह सातवें कूप ने विश्व-रिकार्ड कायम कर दिया है। कूप के बरमाने में लगने वाला समय लगातार घटता गया है। पांचवें कूप के पूरा होने में कुल ३७ दिन ही लगे। अब आशा यह की जा रही है कि परीक्षण-कूप का बरमाना पूरा करने में केवल २५ दिन ही लगा करेंगे।

खंभात तेल क्षेत्र की तेल-विधि का कुछ अनुमान करने के लिए कम से कम २०० परीक्षण-कूप बरमाने होंगे। आशा है कि १९६१ के अंत तक ६० कूप पूरे हो लेंगे। जिस भू-गर्भ-तल की बरमाई चल रही है, वह लगभग १० वर्गमील में है। आजकल खंभात में चार बर्मा-यंत्र चल रहे हैं। दो सोवियत बरमे और दो रूमानियवी। खंभात क्षेत्र में छिछली गहराई के अंदर ही तेल मिल रहे होने के कारण सोवियत संघ ने २३०० मीटर बरमाई की क्षमतावाले १० हलके बरमें भेजना स्वीकार कर लिया है। ये बे-ऊ-७५ बनावट के हैं। आगामी सितम्बर या अक्तूबर तक ऐसे चार बरमे खंभात में चालू हो जायेंगे। अगले साल के मध्य तक तक बाकी छै बरमे भी भी खंभात पहुंच लेंगे। अंकलेश्वर खंभात से सौ मील है, वहां भी तेल मिला है। (यहां निकली तेलधारा को देखकर पं० नेहरू ने इसे वसुधारा का नाम दिया है।
—सं०)

पर भावी तेल-क्षेत्र की बाहरी सीमा-रेखा का पता अभी तक चल नहीं पाया है। यह पता पाने के लिए अभी और कितने ही कूप बरमाने होंगे। हो सकता है कि यह सीमा समुद्र-तल तल तक चली गयी हो। इस प्रक्रिया में अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है कि खंभात की खाड़ी में तेल निकल आये।

तेल पूर्वेक्षण में भारत-सोवियत सहकार्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारतीय प्रविधिज्ञों और इंजीनियरों को तेल निकालने की नवीनतम पद्धतियों का प्रशिक्षण मिल रहा है।

भारत सरकार ने खंभात और अंकलेश्वर से मिले कच्चे तेल के शोधन के लिए एक अग्रगामी कारखाना खोलने का फैसला किया है। यह शोधन कारखाना इन दोनों जगहों की जरूरतें पूरी कर देगा। कारखाना सरकारी होगा और तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में चालू हो चुका रहेगा। इस समय भारत में तेल-शोधन के चार कारखाने हैं। चारों निजी उद्यम के यानी पूंजीपतियों के हैं। परियोजित तेल-शोधन कारखाना सरकारी उद्यम का तीसरा होगा। दो उसके पहले ही बन चुके होंगे। एक बिहार के बरौनी में दूसरा असम में। आशा है कि इन दो से विदेशी विनिमय मुद्रा की जो बचत होगी, वह सालाना ४० करोड़ रुपये की होगी। परियोजित तीसरे तेल-शोधन कारखाने की स्थापना से यह बचत और भी काफी अधिक बढ़ जायगी।

अधिक बिजली की आवश्यकता

भारत इस समय बिजली पैदा करने के साज-सामान में आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न कर रहा है। भोपाल में एक कारखाना स्थापित किया जा चुका है। असल में प्रत्येक देश के औद्योगिक विस्तार का इतिहास बिजली के उत्पादन के विकास से जुड़ा होता है। भारत ने इस सम्बन्ध में स्वतन्त्रता के बाद ही मुख्य रूप से प्रयत्न करना प्रारम्भ किया जब हमारी राष्ट्रीय सरकार ने देश को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में आत्मनिर्भर बनाने का निश्चय किया। बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के लिए हमें बिजली की बहुत बड़े परिमाण में आवश्यकता होगी।

पहली पंचवर्षीय योजना से पहले भारत में केवल २३ लाख किलोवाट बिजली पैदा की जाती थी। पहली योजना में १९५६ तक भारत ३४ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने लगा। इसमें से ६० प्रतिशत भारी उद्योगों में खर्च होती थी। दूसरी योजना में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए ४२७ करोड़ रु० रखे गये, जिससे कि बिजली का उत्पादन ६९ लाख किलोवाट तक किया जा सके, परन्तु विदेशी-मुद्रा की कमी के कारण बिजली पैदा करने का साज-सामान पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सका, इसलिए सम्भवतः हम दूसरी योजना के अंत तक केवल ५८ लाख किलोवाट बिजली पैदा करने का प्रबन्ध कर सकेंगे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

लोहे और इस्पात के भारी कारखानों, और लुमुनियम के कारखानों आदि में बिजली की बहुत अधिक खपत होने के अतिरिक्त रासायनिक खादों और पटसन तथा सूती कपड़े के कारखानों में भी बिजली की खपत बहुत होती है। दूसरी योजना के अन्त तक रासायनिक खाद के उद्योग में १,३०,००० किलोवाट बिजली खर्च होगी। तीसरी योजना में राउरकेला, ट्राम्बे, दुर्गापुर, नवेली और नहर कटिया में रासायनिक खाद के कारखाने चालू हो जाएंगे। इसलिए तीसरी योजना के अन्त तक खादों के कारखानों में ७ लाख किलोवाट बिजली खर्च होने लगेगी। सूती कपड़े के उद्योग में १९६१ के अन्त तक इस उद्योग में ६३५ हजार किलोवाट बिजली खर्च होने लगेगी।

इसके अलावा कागज, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, चीनी, कोयला और बहुत से उद्योग-धंधों में बिजली का खर्च बढ़ रहा है। रेलों को बिजली से चलाने के लिए भी बहुत सी बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। बिजली की बढ़ती हुई खपत को देखते हुए उसका उत्पादन दुगना करना होगा और इसके लिए प्रायः ९५० करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी।

भारत में अभ्रक-उत्पादन

● अभ्रक उत्पादन में भारत सबसे आगे है। विश्व की कुल जरूरत का ८० प्रतिशत उत्तम अभ्रक भारत ही सप्लाई करता है।

● अभ्रक में कई अद्‌भुत गुण हैं। यह अधिकांश कम हानि (लो-लास) कन्डेन्सर बनाने में काम आता है, जो रेडियो, राडार तथा दूसरे बिजली के ऐसे यन्त्रों में लगते हैं, जो भिन्न-भिन्न तापक्रम, दबाव और नमी में काम करते हैं। अभ्रक में बिजली की धारा प्रवाहित नहीं होती।

● आमतौर से अभ्रक की किस्मों की छंटाई रंग, लहर और धारी तथा धब्बे के आधार पर की जाती है। केवल अच्छी किस्म का लाल (रुबी) अभ्रक उत्तम प्रकार के कन्डेन्सर बनाने के लिए ठीक होता है।

● अभ्रक को पीसने का तरीका भी मालूम किया गया है, जो व्यापारिक तौर पर अपनाया जा रहा है। इसके अलावा जमीन के अभ्रक का रंग बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है।

● १९५९ की पहली छमाही में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बन्दरगाहों से ११,४३७ टन अभ्रक बाहर भेजा गया; जबकि १९५७ की इसी अवधि में ४ करोड़ २५ लाख रु० का १०,८१३ टन अभ्रक भेजा गया था।

छोटी बचतें

● १९५६-५७ में छोटी बचतों में ६ अरब ५० करोड़ रु० जमा हुआ। १९५२-५२ में यह राशि ४ अरब ५६ करोड़ रु० थी। १९५७-५८ में छोटी बचतों में कुछ कमी हुई।

● छोटी बचत में लगभग ८३ प्रतिशत घरेलु बचत है। इसके अलावा कर्मचारियों की ११ प्रतिशत और निजी कर्मचारियों का ६ प्रतिशत हिस्सा है। घरेलू बचत में जो तिहाई हिस्सा शहरों और शेष गांवों का है।

● दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय का ७ प्रतिशत से लेकर ११ प्रतिशत तक छोटी बचतों में जमा हुआ। पर घरेलू बचतों में विशेष वृद्धि नहीं हुई। बचत होने के कारण विदेशों से ऋण लेना पड़ा।

● यदि तीसरी योजना १०० अरब रुपया की हुई तो इसमें राष्ट्रीय आय का लगभग १४ प्रतिशत लगाना होगा। दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय का ११ प्रतिशत लगा। ● ●

जीवन साहित्य

हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो—

१. लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं,
२. मानव को मानव से लड़ाते नहीं, मिलाते हैं,
३. आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ पर चलते हैं,

जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री को छोटे-बड़े, स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ़ सकते हैं। उसके विशेषांक एक से एक बढ़कर होते हैं।

वार्षिक शुल्क रु० ४.०० भेज कर ग्राहक बन जाइये।

ग्राहक बनने पर मण्डल की पुस्तकों पर आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी।

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ह मा रे उ द्यो ग

भारत में विदेशी पूंजी के लिए सुविधाएं

भारत और अमरीका की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार भारतीय पूंजी-नियोजन केन्द्र की स्थापना हुई। अमरीकी प्राविधिक सहयोग मिशन इस केन्द्र को ५९,१०,००० रु० की सहायता देगा। इसमें से ३४ लाख रु० (७ लाख १३ हजार डालर) विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त होंगे। २५ लाख रु० भारत में अमरीकी कृषि जिन्सों की बिक्री से प्राप्त हुई राशि में से दिए जाएँगे।

इस केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य निजी विदेशी पूंजी को भारत में लगाने के लिए प्रोत्साहन देना है। केन्द्र के मुख्य-मुख्य निम्नलिखित काम करेगा।

१. भारत में विदेशी पूंजी सम्बन्धी कानूनों और नियमों तथा औद्योगिक और बैंक व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी देना; २. विदेशी पूंजी कहां लगायी जा सकती है, इसके बारे में सर्वे करेगा। ३. विदेशी पूंजी लगाने वालों का सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में भारतीय व्यवसायियों को सलाह देगा; और ४; भारत में पूंजी लगाने के इच्छुक विदेशियों को सहायता देना।

भोपाल में बिजली का भारी सामान बनेगा

भोपाल में बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना खड़ा करने के लिए इस समय वहां २० हजार से भी अधिक कर्मचारी रात-दिन काम में लगे हैं और वे १ जुलाई, १९६० को कारखाना चालू करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। यह कारखाना देश में अपने किस्म का पहला और एशिया में सबसे बड़ा कारखाना बनेगा। वहां शुरू में छोटे आकार के कैपैसिटर बनेंगे। जब वहां कर्मचारियों को अनुभव होने लगेगा और वे अपने काम में अधिक दक्ष हो जाएंगे, तब बड़े आकार के यंत्र भी बनने लगेंगे। लगभग १९६७ में जब कारखाने में पूरी रफ्तार से काम होने लगेगा, तब वहाँ लगभग १० लाख किलोवाट बिजली तैयार करने की मशीनें बनने लगेंगी। एक मशीन से अधिक से अधिक १॥ लाख किलोवाट बिजली तैयार होगी। देश में अब तक इतनी बड़ी मशीनें तैयार नहीं की गईं। कारखाने में १ मील से भी अधिक लम्बी सुरंग गयी हुई है, जिसमें बिजली के केबुल, पानी, गैस और दबाव वाली हवा के पाइप लगे हुए हैं।

सामान की जांच करने और अनुसंधान करने के लिए प्रयोगशाला तैयार हो रही है। आधुनिक ढंग की बस्ती बनाई जा रही है, जिसमें अब तक लगभग ३,००० क्वार्टर बन चुके हैं।

विदेशी-मुद्रा की कठिनाई के कारण भोपाल योजना को तीन चरणों में बांटा गया है। आरम्भ में, पहला चरण ही स्वीकार किया गया। इस पर २८ करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान था। बाद में योजना के दूसरे और तीसरे चरण को भी स्वीकार कर लिया गया, जिन पर कुल ४७ करोड़ ५० लाख खर्च होगा। चौथी योजना में लगभग २० लाख किलोवाट बिजली तैयार करने के लिए हर साल ८० करोड़ रु० की भारी मशीनों आदि की जरूरत पड़ेगी।

तीसरी योजना में देश में दो और कारखाने खड़े किए जाएंगे। इनमें से एक रूस और दूसरा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से तैयार किया जाएगा। ये कारखाने संभवतः तीन साल में चालू हो जाएंगे। अगले १५ वर्षों में देश में इस समय से ४-५ गुनी कधिक बिजली तैयार होगी। दूसरी योजना में २३ लाख किलोवाट, तीसरी योजना में ५० लाख किलोवाट और चौथी योजना में लगभग १ करोड़ किलोवाट बिजली तैयार होने लगेगी।

कोयले की शक्ति के निरन्तर बढ़ते हुए उपभोग और खाद्यान्नों की उत्पादन क्षमता की सीमाओं को देखते हुए राष्ट्र की सर्वांगीण आर्थिक उन्नति के लिए बिजली के उत्पादन को बढ़ाना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है। हमने बिजली उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया तो शक्ति की समस्या बहुत अंशों तक हल हो जाएगी।

छोटे उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता

● छोटे उद्योगों को सरकारी सहायता प्रायः राज्यों के उद्योग निदेशकों के जरिए दी जाती है। कुछ उद्योगों को वित्त निगमों या शहरी सहकारी बैंकों द्वारा भी सहायता दी जाती है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

● १ हजार रु० तक का कर्ज निजी बंधक मिल सकता है। ५ हजार रु० तक का कर्ज एक या अधिक लोगों की निजी जमानत पर दिया जा सकता है। उधार लेने वाले के बंधक पर १ हजार रु० कर्ज देना सुरक्षित नहीं समझा जाता तो दूसरी तरह से कर्ज लिया जा सकता है।

● दूसरी तरह के ऋण, जमीन, मशीनों, इमारतों, स्टाक और दूसरी लेनदारी पर मिल सकते हैं। इन चीजों के मूल्य के ७५ प्रतिशत के बराबर तक कर्ज मिल सकता है। जमानन की जगह माल या मशीनरी पर ५,००० रु० या इससे कम कर्ज भी मिल सकता है।

● उद्योग सहकार समितियों को छोड़कर दूसरों को २५ हजार रु० तक ३ प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलता है और उद्योग सहकार समितियों को २ लाख रु० तक २॥ प्रतिशत ब्याज पर। ऋण १० सालों में और आसान किश्तों पर चुकाया जा सकता है।

● स्टेट बैंक ने ३१ दिसम्बर, १९५९ तक १,४९९ प्रार्थियों को ४ करोड़ ६२ लाख १९ हजार रु० के कर्ज देने की मंजूरी दी थी। इसी समय बकाया १ करोड़ ७७ लाख ६६ हजार रु० थी।

● कर्ज बहुत से उद्योगों को दिया गया। इनमें से इंजीनियरी, छुरी-काँटा, मोटर, चमड़ा, इमारत, रोगन तथा रसायन, बिजली का सामान, चीनी मिट्टी का सामान, लकड़ी का काम, प्लास्टिक, धातु के बर्तन, साइकिल के पुर्जे आदि उद्योग प्रमुख हैं। ● ●

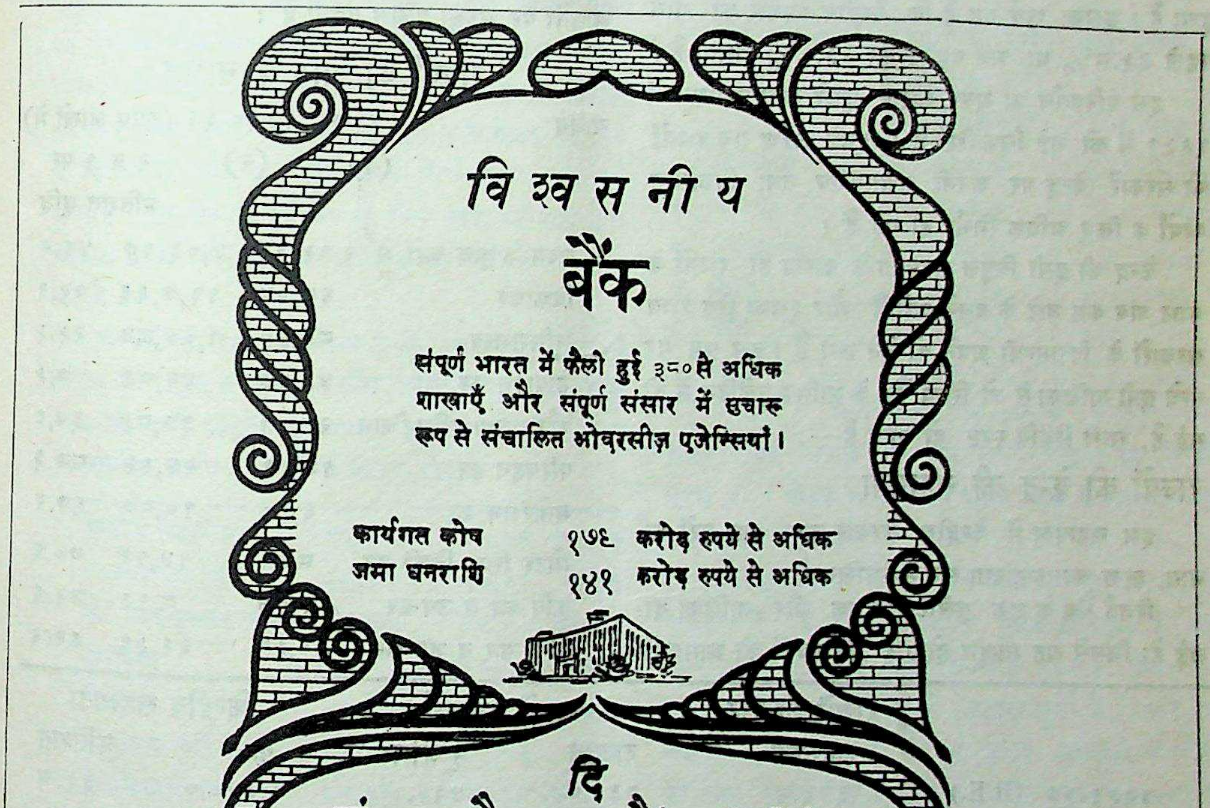

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राज्यों की आय के स्रोत : केन्द्र का बढ़ता हुआ सहयोग

पिछले पांच वर्षों में विभिन्न राज्यों के आय-साधनों में विशेष परिवर्तन हुआ है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को अधिकाधिक सहायता दी जाने लगी है। यह सहायता राजस्व और पूंजीगत दोनों क्षेत्रों में दी जाती है। राजस्व खाते में तो यह करीब-करीब दुगुनी होगई है, जबकि राज्यों के व्यय केवल ४०% बढ़े हैं। १९५६-५७ में केन्द्र की ओर से राज्यों को केवल ३७३ करोड़ रुपया मिला था और १९६०-६१ के बजट से यह मालूम होता है कि यह राशि ७८० करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुँच गई है, जबकि व्यय १०४१ करोड़ रुपए से बढ़कर केवल १४१६ करोड़ रुपए हुआ है। इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार का भाग पहले ३५.८% था, अब वह बढ़कर ५१.५% होगया है।

इस परिवर्तन का मुख्य कारण दूसरे वित्त कमीशन में १९५७ में की गई सिफारिशें हैं। इनके कारण सब राज्यों की सरकारें केन्द्र पर अपनी प्रशासकीय तथा विकासीय कार्यों के लिए अधिक निर्भर हो गई हैं।

केन्द्र की इसी विपुल सहायता के कारण ही राज्यों के बजट अब कम घाटे के बनने लगे हैं और इसका श्रेय राज्य सरकारों के वित्तमन्त्री अपने को देने लगे हैं। इस पृष्ठ पर नीचे छपी तालिका से जो रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में दी गई है, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है—

राज्यों को केन्द्र की सहायता

इस सहायता में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त करों का भाग, ऋण तथा सहायता सब सम्मिलित हैं।

रिजर्व बैंक के उक्त बुलेटिन में एक और तालिका दी गई है; जिससे यह मालूम होता है कि राज्यों की आमदनी के साधनों में अब किस तरह परिवर्तन हो रहा है। सबसे अधिक आमदनी बिक्री कर से होती है। यह कर सुरसा के बदन की तरह बढ़ता जाता है। कृषि से भी आय बढ़ी है, किन्तु कुल आय को देखते हुए इसका बहुत महत्व नहीं रहा। अभी तो सब राज्यों में कृषि की आय पर कर लगाया भी नहीं है। यदि जमींदारी पद्धति का उन्मूलन न होता और भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित न की जाती तो शायद कृषि आयकर से अधिक आमदनी होती। मनोरंजन कर से भी आय बढ़ाने का वित्तमंत्री ने आश्रय लिया है। निम्नलिखित तालिका से कुल राज्यों के विभिन्न आय-साधनों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है :

राज्यों की आय के साधन

साधन	१९५५-५६ (१)	१९६०-६१ (२)	(रुपए लाखों में) २ व १ पर प्रतिशत वृद्धि
१. राज्य के कुल करों से	२,७५,७२	४,०३,१७	४६.२
बिक्रीकर	६८,२८	११,७,९६	७२.६
भूमिराजस्व	८०,३३	१,००,८४	२५.५
उत्पादन कर	४३,४९	४६,७९	७.५
स्टैम्प तथा रजिस्ट्रेशन	२८,११	३७,८५	३४,६
परिवहन कर	१४,३९	२६,९५	८७.३
मनोरंजन कर	६,५०	१०,८७	६७.२
मोटर स्प्रिट बिक्री कर	८,३०	१४,१६	७०.६
कृषि कर व उप कर	५,७४	८,१९	४२.६
अन्य कर व उप कर	२०,५८	३९,५६	९२.२

	राज्यों को कुल सहायता	राज्यों का खर्च राजस्व	पूंजीगत	कुल	केन्द्रीय सहायता प्रतिशत
१९५६-५७ (B.E.)	३७३.२	६३०.७	४१०.०	१,०४०.७	३५.८
१९५७-५८	५१८.९	६८४.४	३४७.२	१,०३१.६	५०.३
१९५८-५९	५८६.७	७६८.३	३५७.३	१,१२५.६	५२.१
१९५९-६०	६७०.९	६८४.७	४४४.४	१,३०९.१	५१.२
१९६०-६१	७२९.५	९३८.९	४७७.१	१,४१६.०	५१.५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सर्वोदय पृष्ठ

जापान से सबक लें !

ग्राम नटाया, जिला होशंगाबाद के श्री बनवारीलाल चौधरी कोई एक साल के लिए जापान गये थे। वहां से लौटने पर उन्होंने जापान की खेती के बारे में एक पुस्तक लिखी है। नाम है—जापान की खेती। उन्होंने तरकारी की खेती के बारे में लिखा है—"जापान में तरकारी की क्यारियों में एक-दो सप्ताह के अन्तर से दवा बराबर छिड़की जाती है। कई प्रकार के कीड़े और रोग हर प्रकार की तरकारी पर आक्रमण करते हैं। हर किसान के पास दवा छिड़कने के साधन हैं। वहाँ लोग एक-एक पत्ती को देखकर रोग को जड़ से मिटाने की चिन्ता रखते हैं। उत्पादन का ४॥ प्रतिशत खर्च दवा पर होता है।" जापान में १४७ लाख एकड़ में खेती होती है। प्रति एकड़ २० रु० के हिसाब से कोई ३० करोड़ रुपया सिर्फ दवा पर खर्च होता है। हर तरकारी को कितनी, किस तरह की खाद देनी चाहिए, इसके बारे में पुस्तक में जरूरी आँकड़े भी दिए गए हैं।

आंकड़ों से यह पता चलता है कि जापान ने भारत की अपेक्षा २२३ गुना उर्वरक दिए और ३गुनी पैदावार ली, इसलिए जापान के अनुभव के आधार पर भी यहाँ कृत्रिम खाद का उपयोग करना उचित नहीं मालूम होता।

२. केन्द्रीय सहायता	१४१,४२	२८३,६८	१००.५
आयकर का भाग	५५,२७	६०,३०	६.१
के० उत्पादनकर का भाग	१६,६०	७५,०५	३५२.१
सहायता	६७,६१	१३२,७६	९६.४
मिश्रित	१,९४	१५,५४	७०१.०
३. अराजस्व करों से	१४२,९९	२५७,७५	४०.२
प्रशासकीय आय से	५०.४४	१४८,१७	१४५.१
सरकारी उद्योगों का भाग	३०,०७	४६,४८	५४.५
अन्य राजस्व	५२,४८	६३,१०	२०.२
कुल राजस्व	५,६०,१३	९,४४,६०	६८.६

भारत का फसल-चक्र ऐसा है कि वैसा दूसरे देशों में मिलना मुश्किल है। आजकल लालच के फेर में पड़कर लोगों ने उस चक्र की चिन्ता रखना छोड़ दिया है। इसलिए धीरे-धीरे बीमारियां बढ़ने लगीं हैं। हमें यह समझना चाहिए कि शरीर, पौधे और जमीन सब एक-जैसे ही हैं। जैसे, शरीर को जितना कुदरत के साथ रखेंगे, उतना ही वह स्वथ्य रहेगा, वही बात इनके बारे में भी है। जमीन मूक है, अगर हम उसे बुद्धिपूर्वक खाद देंगे और समय पर पानी सींचेंगे, तो हमें उसके अन्दर छिपी प्रचण्ड शक्ति का पता चल सकेगा।

देशी खाद को प्रोत्साहन दें !

विभिन्न देशों के निम्नलिखित तुलनात्मक आकड़ों से भली प्रकार स्पष्ट है—

देश	प्रति एकड़ उर्वरकों का प्रयोग (पौण्ड में)	प्रति एकड़ औसत उपज (पौण्ड में)
१. नीदरलैंड	३९५.८	३,१३२
२. जापान	२२३.५	२,९४३
३. स्विट्ज़लैंड	१४९.३	२,९२५
४. ब्रिटेन	११३	२,५०२
५. फ्रांस	६७.७	२,०५२
६. अमेरिका	३०.७	१,६८३

भारत ने प्रति एकड़ पौंड उर्वरक उपयोग करके ९४५ पौण्ड अनाज प्राप्त किया, जबकि नीदरलैण्ड ने प्रति एकड़ ४०० पौण्ड का उपयोग करके भारत के मुकाबले साढ़े तीन गुनी फसल ली।

आजकल हमारे देश के कृषि-विशेषज्ञ का एक ही राग अलापते हैं कि भारत की जमीन बेकस हो चुकी है, इसलिए कृत्रिम खाद का ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। आज देश में जितने सरकारी फार्म हैं, उनके पास सैंकड़ों एकड़ जमीन है, लेकिन उसके मुकाबले में गोबर की खाद नगण्य-सी है। ये सब फार्म रासायनिक खाद का ही अधिक उपयोग करते हैं।

जमीन से मिलने वाले नाइट्रोजन में और जमीन के उपजाऊपन को कायम रखने की कुदरती प्रक्रिया में पूरा सन्तुलन है, परन्तु अत्यधिक बरसात, बाढ़ और धूप आदि

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

न या नि र्मा ण

आज परिश्रम कल लाभ !

प्रधान मन्त्री श्री नेहरू का नया नारा है : 'आज परिश्रम कल लाभ'। उभरते हुए देश के प्रत्येक नागरिक के मन में सुख-सुविधाओं की चाह है। यह चाह बुरी भी नहीं है, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए हमें व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना और विचार को व्यावहारिक रूप देना होगा। मात्र सुखों की कल्पना से सुख प्राप्त नहीं होंगे। विश्व के अन्यान्य राष्ट्र आज आर्थिक प्रगति में एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। ऐसे समय श्री नेहरू ने देश को बहुत उपयुक्त आह्वान दिया है। इस सम्बन्ध में आपने कहा है :

"हमें चल निकलने वाली समर्थता की स्थिति १० वर्षों के भीतर प्राप्त कर लेनी है, जबकि हमारी प्रगति कहीं अधिक ठोस, पुष्ट और त्वरित गतिशील हो चुकी होगी।

"मुझे विश्वास है कि राष्ट्र का भविष्य उज्वल है। हमें श्रम करना चाहिए और वह भी कठोर श्रम। हम ग्राम पंचायतों को वृहत्तर प्राशासनिक सुविधाओं के साथ और भी अधिकार देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी सामुदायिक विकास योजनाएं भी इसी दशा में चल रही हैं, जिससे हम अधिक ठोस आधार पर काम कर सकें।

"कुछ वर्षों तक लोगों को चाहिए कि वेतन वृद्धि के लिए जोर न दें। मैं यह मानता हूँ कि वेतन बढ़ाए जाने की जरूरत है; पर यह याद करना जरूरी है कि राष्ट्र गरीब है और बहुत बड़ी संख्या में लोग भूखे

से जमीन में इनकी कमी हो जाती है। ऐसी हालत में गोबर की खाद के साथ थोड़ी रासायनिक खाद देना जरूरी हो जाता है। जैसे, दवा बीमारी की हालत में ही दी जाती है और तभी वह रोगी को फायदा भी पहुंचाती है, वैसे ही अगर जमीन को रासायनिक खाद देनी हो, तो उसके लिए हमें जमीन का 'डॉक्टर' खोजना होगा। ऐसे डाक्टर आज के शहरी स्कूलों से मिलना मुश्किल ही है। आज के शिक्षित नागरिक खेती के 'विशेषज्ञ' बनकर जब गाँवों में जाते हैं, तो किसानों को सुझाव देते हैं कि 'कम्पोस्ट' तैयार करने से बड़ा फायदा होता है। लेकिन आज तक का अनुभव यही है कि कोई किसान उसे अपनाता नहीं, क्योंकि उसका जो तरीका है, वह मेहनत माँगता है और थकाने वाला है। जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए लम्बे समय की जरूरत तो है ही, साथ ही मेहनत भी जरूरी है। इस देश में विदेशों की हवा लगने से लोगों में आलस्य का असर ज्यादा होता जा रहा है। आज हम लोग तुरन्त फायदा चाहने लगे हैं। रासायनिक खाद से फसल ज्यादा मिल सकती है, लेकिन हमारे देश के लिए वह उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। भारत की खेती अधिकतर बरसात पर अवलम्बित है। ऐसी हालत में गहरी जुताई करना और रासायनिक खाद देना जुआ खेलना है। खाद इतनी महँगी है कि मामूली किसान उसे ज्यादा खरीद नहीं सकता।

जमीन को उम्दा बनाना हो और उसकी उर्वराशक्ति को स्थिर रखना हो, तो इसके लिए जानवरों का मल-मूत्र, कूड़ा-कचरा और जुताई आदि की खास जरूरत है। इन सबके साथ थोड़ी मात्रा में रासायनिक खाद का भी उपयोग हो सकता है। आजकल दम्भ और अभिमान के कारण जानवरों का मल-मूत्र इकट्ठा करना तुच्छ माना जाता है। इन दिनों में जिस गाँव में बैठा हूँ, उसमें कोई मर्द गोबर नहीं उठाता। यही हाल कम-बेशी सारे प्रदेश का है। जुलाई से आगे चार महीनों तक गाँवों की बहनें अपने बैलों और दुधारू पशुओं का गोबर उठाकर उसे जहाँ-तहाँ फेंक देती हैं। नवम्बर से आगे ४ महीनों तक वे गोबर के उपले पाथती हैं। अप्रैल से आगे तीन महीनों तक कोई अपने घरों में मवेशी बाँधते ही नहीं, न कोई गोबर इकट्ठा करते हैं। बरसात में पालतू जानवरों को लोग जंगलों में चरने भेज देते हैं। वहाँ सारा गोबर बरबाद ही होता है। गाँव के कुछ भाइयों ने खेतों में कभी खाद दी ही नहीं। फिर भी वे फी एकड़ ४-७ मन फसल तो ले ही लेते हैं।

—गो० प्रा० वर्मा

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारतीय तम्बाकू

रह जाते हैं। यदि धन अधिक वेतन देने में ही खपता रहेगा तो धनाभाव में बहुत से लोगों का पीड़ित रहना चलता ही रहेगा।''

आशा है जनता राष्ट्रनायक के इस आह्वान को अपने मार्ग-दर्शन के सूत्र-वाक्य के रूप में ग्रहण करेगी।

नए भारत के बदलते गाँवों का प्रतीक

राजस्थान में डूंगर एक हजार बीघा जमीन में फैला छोटा सा गांव है। यहां गांव वालों ने मिलकर आठ कुओं के लिए मिली सहायता से नौ कुएं खोद डाले हैं। कुल अठारह कुंए खोदे गए हैं, जिनमें कई बिना किसी प्रकार की राजकीय सहायता के खोदे गए हैं। सब किसानों ने अपने खेतों में छोटी नर्सरी के लिए फलों के वृक्ष लगाये हैं।

गांव में नौजवान किसानों का एक संगठन बना हुआ है। इन लोगों ने कृषि विस्तार अधिकारी के सक्रिय सहयोग से अपने गांव को आदर्श बनाने का बीड़ा उठाया है। इस गांव में सब खेतों में मेढ़-बन्दी की गयी है। हर मेढ़ पर अरंड के पेड़ लगाए गये हैं। गांव वाले उत्साह के साथ बताते हैं कि उन्होंने गत वर्ष दो सालों का लगान इन अरंड के पेड़ों से हुई आय से चुका दिया।

सब खेतों में सुधरे बीज सी० ५९१ गेहूं तथा सी० ४१९ गन्ना डाले जाते हैं। गन्ना पेरने की तीन चर्खियां हैं। सब गांव वालों ने अपने जानवरों के टीका लगवा लिया है। बछड़ों को बधिया भी करा दिया गया है। बैलों को मुंह की बीमारी से बचाने के लिए सीमेंट का एक फुटपाथ बनाया गया है।

सब गांव वाले ५ रुपये के राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र खरीद रहे हैं। ५-५ रुपए के इनामी बांड भी हर घर में खरीद लिये गये हैं।

गांव में एक सहकारी समिति संगठित की गई है। ३५ में से ३० परिवार इसके सदस्य हो चुके हैं।

गांव में कोई विवाद नहीं होता। कोई आज तक अदालत नहीं गया। पंचायत में भी झगड़े नहीं जाते! महिलाओं ने स्वेच्छा से कई कुरीतियां छोड़ दी हैं—ये गांव वालों की मदद करती हैं।

यह कहानी केवल डूंगर गांव की ही नहीं, स्वतन्त्र भारत के अनेक उभरते गांवों की कहानी भी है। नागरिकों के श्रम से देश के अनेक गांवों का कायापलट हो रहा है। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

वि दे शी अ र्थ - च र्चा

अमेरिका और क्यूबा में आर्थिक युद्ध

अमेरिकन महाद्वीप के दो देशों में एक नया आर्थिक युद्ध शुरू हो गया है। एक ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरी ओर छोटा सा देश क्यूबा है। क्यूबा में अमेरिका द्वारा स्थापित तेल शोधन संस्थान—रिफायनरी—है। वहां साम्यवादी शासन है और इसलिए रूस से अधिक सहानुभूति है, इसलिए उसने रूस से तेल मंगवाना शुरू किया है। इस से असन्तुष्ट होकर अमेरिकन रिफाइनरियों ने उस तेल की सफाई करने इन्कार कर दिया है। इस पर क्यूबा की सरकार ने उन रिफाइनरियों को अपने कब्जे में ले लिया है। बदला लेने के लिए उन विदेशी कम्पनियों ने क्यूबा के हवाई जहाजों को उधार तेल देना बन्द करके नकद रकम मांगना शुरू कर दिया है। क्यूबा के हवाई जहाजों को अब विदेशों में जाने के लिए बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ रहा है। इन कम्पनियों ने न केवल क्यूबा में बल्कि दुनिया के किसी भी भाग में उधार तेल देना बन्द कर दिया है और क्यूबा से हवाई जहाज पूरा तेल लेकर नहीं जा सकते। इस कारण कई हवाई उड़ानें स्थगित करनी पड़ी हैं और कुछ में बहुत कम यात्रियों को बैठाया जाता है।

अमेरिकन सरकार बहुत संभवतः क्यूबा की चीनी लेना बन्द कर दे और उधर से क्यूबा अमेरिका की ५० करोड़ डालर की सम्पत्ति को जब्त कर ले। यह भी ख्याल किया जा रहा है कि क्यूबा तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर ले। इस सम्बन्ध में सोवियत रूस क्यूबा को बहुत सहायता दे रहा है। उसके तेल के टेंकर क्यूबा पहुंच रहे हैं।

जर्मनी का पुरुषार्थ

दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के समय जर्मनी लगभग पूरी तरह बरबाद हो गया था। विजेताओं ने उसे पूरी तरह कुचल कर दो भागों में बाँट लिया था। लेकिन इन पन्द्रह सालों के अन्दर उसने इतनी तरक्की कर ली है कि देखने-सुनने वाले दंग रह जाते हैं। लगभग साढ़े पाँच करोड़ की आबादी वाले पश्चिमी जर्मनी में, जहाँ एक करोड़ चालीस लाख शरणार्थी आ बसे हैं, आज ३,५०२ करोड़पति हैं। सन् १९४५ में, जब दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ था, वहाँ करोड़पतियों की कुल संख्या ३०० से भी कम थी।

सन् १९५१ में पश्चिमी जर्मनी की राष्ट्रीय आय ९१.२ बिलियन अर्थात् ९ नील १२ खरब डूशे मार्क थी, जो अब १६ नील हो गई। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण शुरू होने के दो साल बाद यानि सन् १९५० में उसका औद्योगिक उत्पादन ८० अरब डूशे मार्क था, जो अब तिगुना हो गया है। पिछले दस सालों में वहाँ मजदूरों की आय ९१% बढ़ गई है, जबकि इसी अवधि में मँहगाई केवल २१ प्रतिशत बढ़ी है। सारे उद्योगों के विकास और विस्तार की बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनी हैं, पर मजदूरों की कमी के कारण वे उन्हें कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं।

युद्ध में बरबाद हुए देश के पुनर्निर्माण का काम पश्चिमी जर्मनी के ग्यारह राज्यों ने शुरू कर दिया है। इसमें मकान बनाने के काम को सबसे पहला स्थान दिया गया है। इसके लिए वे इटली से मजदूर ला रहे हैं। सन् १९५० में जहाँ इस योजना पर कुल ३,८०० मिलियन मार्क खर्च किए गए थे, सन् ५९ में यही खर्च बढ़कर १३,००० मिलियन मार्क हो चुका है और पश्चिम जर्मनी अब तक कुल मिलाकर केवल भवन-निर्माण पर ३,२०,००० मिलियन मार्क खर्च कर चुका है। अगले चार वर्षों में वह अपनी मकान-सम्बन्धी समस्या हल कर लेगा। उसके बर्लिन, हैम्बर्ग-जैसे शहर ८० प्रतिशत बरबाद हो गए थे, पर आज उन्हीं शहरों में आपको कोई सड़क पर सोता दिखाई नहीं पड़ेगा।

जर्मनी की आबादी कम है, इसलिए वहाँ परिवार-नियोजन की नहीं, परिवार-वृद्धि की योजनाएँ चल रही हैं। वहाँ की सरकार तीसरे बच्चे से लेकर बाद के हर बच्चे के लिए ४० मार्क प्रतिमास के हिसाब से अलावा भत्ता देती है और घर के बड़े-बूढ़े बहन-बेटियों और बहुओं को 'अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव' का कंजूस आशीर्वाद न देकर 'बहुपुत्रा बहुकन्यावती भव' का उदार आशीर्वाद न देते हैं।

आज पश्चिम जर्मनी में हर मजदूर की औसत मासिक आय ४५० मार्क यानी ५०५ रुपए है, वह किसी कारखाने में काम करता हो या कहीं और! इसलिए वह

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया साहित्य

समाजवाद और पूंजीवाद का अध्ययन—लेखक—प्रो० विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, एम० ए०, एल० एल० बी०, प्रकाशक—नावल्टी एण्ड कम्पनी, अशोक राज पथ, पटना-४, मूल्य ३. ५० नये पैसे, सजिल्द।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक से 'सम्पदा' के पाठक भलीभांति परिचित हैं। वे अर्थ-शास्त्र के माने हुए विद्वान हैं, फिर भी उनकी लेखनशैली सरल और गंभीर होती है।

प्रस्तुत पुस्तक के विषय की चर्चा आजकल बहुत होती है; किन्तु बहुत कम शिक्षित और विशेषकर जनता में भाषण देने वाले सार्वजनिक कार्यकर्ता विषय को समझते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में समाजवाद के सम्बन्ध में समाजवाद और पूंजीवाद की एतिहासिक तथा सैद्धान्तिक विवेचना करते हुए दोनों के गुण दोष का परिचय दिया गया है। आज हमारा देश जब पंचवर्षीय योजनाओं के काल में से गुजर रहा है, तब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के रूप में समाजवाद और पूंजीवाद का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस गम्भीर विषय पर हम हलकी लेक्चरबाजी के आधार पर कोई मत स्थिर नहीं कर सकते। इसके लिए प्रस्तुत पुस्तक जैसी गंभीर पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है।

लेखक की विवेचना प्रणाली शिक्षित पाठक को चिन्तन के लिए पर्याप्त विचार सामग्री देती है।

प्राप्ति स्वीकार

भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें प्राप्त हुई हैं।

१. पुजारी जी का ब्याह, मूल्य १ रुपया
२. भारतीय श्रमिक, मूल्य ७५ नए पैसे।
३. मुसकान भरी घाटी, मूल्य ७५ नए पैसे। ● ●

काफी बचत कर सकता है। आज वहाँ का हर मजदूर अपना निजी घर बनाने की योजनामें लगा है।

सन् १९५० में जनता की अपनी बचत १ बिलियन मार्क के रूप में बैंकों में जमा थी। आज यह रकम लगभग ६ बिलियन है।

जर्मनी में नौकरों और मजदूरों के पास भी अपनी मोटरें हैं। पहले वहाँ कारखानों के आस-पास काफी जमीन खुली पड़ी रहती थी। अब मोटरों को लगाने के लिए भी वहाँ जगह की बड़ी तंगी पड़ने लगी है। आज अकेले पश्चिमी जर्मनी में ४० लाख मोटरें हैं। अनुमान यह है कि अगले तीन सालों में यह संख्या दुगुनी हो जाएगी। वैसे तो दुगुनी वह कभी की हो जाती, लेकिन कारखाने उतनी तेजी से मोटरें बना नहीं पा रहे हैं।

पर इस सारी तरक्की के बाद भी वहाँ लोग बहुत प्रसन्न नहीं हैं। बड़े-से-बड़े आनन्द की गहराई के भीतर भी उनके दिलों में इस बात का दुःख छिपा रहता है कि उनके देश के दो टुकड़े हो गए हैं और पता नहीं कि ये टुकड़े फिर कब जुड़ पाएँगे! आज भी पूर्वी जर्मनी से प्रतिदिन सैकड़ों शरणार्थी पश्चिमी जर्मनी में आते रहते हैं। और वहाँ वाले उन्हें प्रेम से बांहें पसार कर अपने समाज में मिला लेते हैं। ● ●

(पृष्ठ ३२८ का शेष)

४. ग्राम और लघु उद्योग	२२५	३२५
५. बड़े और मध्यम उद्योग और खनिज	७००	१०५०
६. आवास और अन्य निर्माण-कार्य	१०००	११२५
७. उत्पादन में रुकावट न आने देने के लिए कच्चा या अर्ध-तैयार माल	५२५	६००
जोड़	३३००*	४२००*

(* इसमें सरकारी क्षेत्र से दिए गए २०० करोड़ रु० भी शामिल हैं।)

दूसरी योजना में बड़े और मध्यम उद्योगों ७०० करोड़ रु० की पूंजी लगायी गयी, जबकि तीसरी योजना में १०५० करोड़ रु० की पूंजी लगाने का विचार है।

योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को उद्योगों में फैलने का काफी अवसर है। इसका मुख्य कारण यह है कि अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप उद्योगों के बढ़ने के अवसर ज्यादा हो गये हैं। इस विषय में नीति यह है कि इन अवसरों से छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगपति लाभ उठाएं और आर्थिक शक्ति थोड़े से लोगों के हाथ में केन्द्रित होने की प्रवृत्ति पर शुरू में ही अंकुश लग जाए। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं

विपुल मात्रा में तेल-प्राप्ति की संभावना

अंकलेश्वर में तेल शोध का कार्य करने वाले रूसी विशेषज्ञों के अनुसार अंकलेश्वर का तेल क्षेत्र भारत को सम्पूर्ण आसाम के मुकाबले कहीं अधिक परिमाण में तेल सुलभ करेगा। यद्यपि सही गणना अभी नहीं दी जा सकती, फिर भी ऐसी सम्भावना है कि २-३ साल में खम्भात और अंकलेश्वर के तेल क्षेत्रों से प्रतिवर्ष प्रायः २० लाख टन तेल मिलने लगेगा। भूछेदन कार्य का सम्पूर्ण ७ करोड़ रुपये का यन्त्र रूस प्रदान करेगा।

रूस ने यह भी प्रस्ताव किया है कि तेल के लिए भूछेदन के निमित्त जितने भी जिम्मेदार भारतीय प्रविधिज्ञों की जरूरत होगी, उनका प्रशिक्षण हम कर देंगे। रूस यह नहीं चाहता कि उसके प्रविधिज्ञ अधिक समय तक भारत के लिए अटके रहें, यह चाहता है कि भारत स्वयं अपना काम चलाये। रूस संभवतः प्रति वर्ष १ सौ भारतीय तेल प्रविधिज्ञों को रूस प्रशिक्षित करेगा।

सस्ते रेडियो का उत्पादन

भारत सरकार ने १२५ रुपये की कीमत तक के सस्ते रेडियो सेटों के उत्पादन का एक कार्यक्रम बनाया है। इस योजना के मातहत तक मीडियम और शार्टवेव को पकड़ने वाले ५०,०० से ६०,०००० तक रेडियो सेट आगामी वर्ष के अन्त तक तैयार करने की योजना है। सभी प्रमुख उत्पादक अपनी उत्पादन क्षमता का २५ से, ३० प्रतिशत तक इन सस्ते रेडियों के उत्पादन पर लगाने को तैयार हो गए हैं। उत्पादकों को निर्यात की सुविधाएं देकर इस योजना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पेट्रोल के लिए पाइप लाइन

भारत सरकार देश में साफ पेट्रोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए पाइप बिछाने पर विचार कर रही है। इससे रेलों का भार कम होगा। अब पाइप बनाने पर बहुत कम विदेशी मुद्रा खर्च होगी, क्योंकि अब राउरकेला के हिन्दुस्तान इस्पात लि० में पाइप बनने लगे हैं।

भारत और हंगरी में व्यापार समझौता

भारत और हंगरी में एक नये व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए हैं जो १ जुलाई, १९६० से लागू होगा और ३॥ साल तक चलेगा। वर्तमान करार ३० जून, १९६० को समाप्त हो रहा है।

भारत से हंगरी को मुख्य रूप से चाय, कहवे, वनस्पति तेलों, अदरक, चमड़े, तेलहन, पटसन और नारियल के रेशे की चीजें, खनिज लोहा और इस्पात की सिलें, कपास, ऊनी और रेशमी कपड़े, हाथकरघे और दस्तकारी की चीजें, खेल का सामान, जूते, इंजीनियरी का हल्का सामान, कपड़े की मशीनें आदि का निर्यात होगा।

हंगरी से ये चीजें खास तौर से मंगाई जाएंगी: छोटे उद्योगों के काम की मशीनें, फोटो सामग्री, औजार, बिजली के मोटरों के हिस्से, भट्टियों में लगाने वाली ईंट और रेडियो के हिस्से आदि।

पेट्रोल को तेल कारखानों और बन्दरगाहों से स्टीमर या नाव और मोटर गाड़ियों पर भी भेजा जाता है। परन्तु नदियों में बारहों महीने नाव या स्टीमर चलने लायक पानी नहीं रहता, इसलिए हर समय पेट्रोल नहीं भेजा जा सकता। मोटर गाड़ियों से दूर तक पेट्रोल भेजने में अधिक खर्च पड़ता है।

—१९५९ में २,९०,१२५ टन लोहे की कतरनें और टुकड़े आदि जमा हुए थे। कलकत्ता बन्दरगाह से १,६६,४७८ टन, बम्बई से ७८,९९३ टन, मद्रास से १६,८४८ टन और कांदला से २,०८७ टन लोहे की कतरनों और टुकड़ों आदि का निर्यात हुआ। पिछले साल भारत में बिजली की भट्टियों में ८४,३८६ टन बेकार लोहा पिघलाया गया। भारत में इस्पात की कतरनों का दाम १०० रु० प्रति टन और हलकी चादरों आदि की कतरनों का ९० रु० प्रति टन है। पहली किस्म की कतरनों का अंतर्राष्ट्रीय भाव १६ पौंड प्रति टन (लगभग २१३.३ रु० प्रति टन) और दूसरी का १३ पौंड प्रति टन (लगभग १७३.३ रु० प्रति टन) है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एक्सल की कहानी

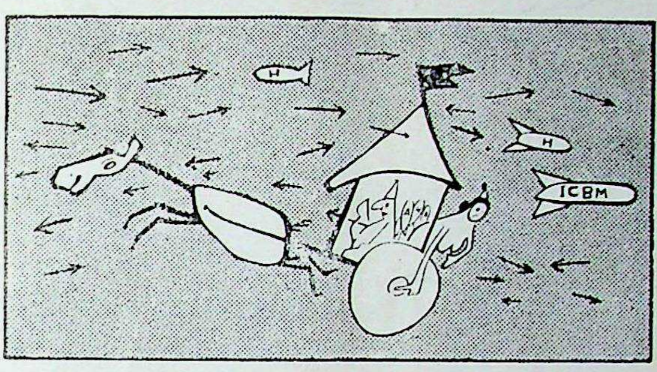

सारे रामायण महाकाव्य का उद्‌भव वास्तव में एक पुर्जे के टूटने से हुआ था. घमासान युद्ध के बीच शाही रथ का एक्सल टूट गया, परन्तु रानी कैकेयी ने अपनी उंगली डाल कर पहिए को यथास्थान रखा. राजा दशरथ ने उस से कोई वर मांगने को कहा जिस का फायदा कुटिल रानी ने श्री राम को बनवास भेजने में उठाया.

इसलिए आप मानेंगे कि हमें अपने एक्सल मजबूत रखने होंगे. वियरवेल साइकिलें हर प्रकार के काम के लिए बनाई गई हैं. उन का हर पुर्जा मजबूत होता है.

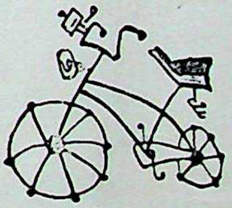

वियरवेल साइकिल्स

विम्पैक्स (एजेंट्स) नई दिल्ली · बम्बई · कलकत्ता · मद्रास

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कृषि का विकास

देश के अन्य भागों की तरह उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश लोगों की जीविका खेती से चलती है। अतः यह स्वाभाविक है कि प्रदेश के विकास की कोई योजना बनाते समय खेती-बाड़ी के विकास पर समुचित ध्यान दिया जाय। सन् १९५१ में जब पहली पंचवर्षीय योजना बनकर तैयार हुई तो सरकार द्वारा कृषि की उन्नति तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर सम्पूर्ण धन-राशि का लगभग चौथाई भाग खर्च करने के निश्चय का सर्वत्र स्वागत हुआ। जनता ने भी सरकारी सहायता के सहारे खाद्योत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनने के लिए कठिन श्रम किया और योजना की अवधि पूरी होने से पहले ही प्रति वर्ष लगभग १० लाख टन अतिरिक्त खाद्योत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी कृषि की उन्नति के लिए समुचित प्रयास चल रहे हैं। इस बार कृषि तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर पहले की अपेक्षा लगभग दूना धन खर्च करने का निश्चय हुआ है और इसी अनुपात में खाद्योत्पादन का लक्ष्य भी ऊँचा रखा गया है। सन् १९६०–६१ तक वार्षिक खाद्योत्पादन २४ लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनेक उपायों का सहारा लिया गया है। उदाहरण के लिए किसानों को सरल शर्तों पर ऋण तथा अच्छी किस्म के बीज, खाद्य, उर्वरक और कृषि-यंत्र दिये गये हैं। अब तक ६६७ बीज क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा १०० और क्षेत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक तैयार हो जायेंगे। नेत्रजन-खाद के वितरण का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है।

इसके साथ-साथ तालाबों को गहरा करने, उनके तल में पायी जाने वाली घास आदि से खाद तैयार करने और उनका खेतों में उपयोग करने तथा खेती की प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन करने के विशेष कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं। आशा है इन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रदेश का वार्षिक खाद्योत्पादन निर्धारित लक्ष्य तक बढ़ाया जा सकेगा और सामान्य जनता आर्थिक उन्नति का अनुमान कर सकेगी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रसारित

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित व
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सम्पदा

अर्थशास्त्र की नवीनतम गतिविधियों की मासिक पत्रिका

•

अगस्त १९६०

मूल्य ७५ न.पै.

अशोक प्रकाशन मन्दिर शक्ति नगर दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

DA—Ju

डालमिया

काश्म Stoneware एवं मृच्छिल्प Porcelain निर्मितियाँ (Products)

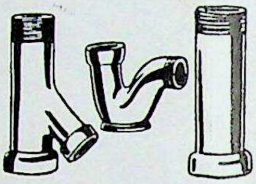

काश्म-नाल Stoneware Pipes
अधोभूमि जलोत्सारण के लिए

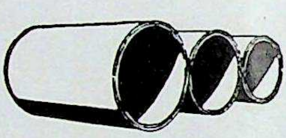

वज्रचूर्ण-अयस्संघा-नाल
(R. C. C. Spun Pipes)
पुलियाओं, जल-प्रदाय
और जलोत्सारण के लिए

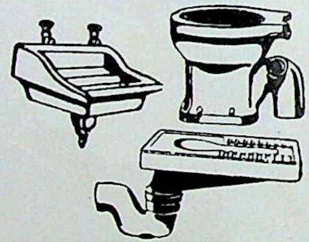

मृत्सा (Porcelain)
आरोग्य पात्र (Sanitary Wares)
भारतीय और यूरोपीय शौच-कुण्ड
(Water Closets)
धावन पात्री (Wash Basins)
मूत्र-कुण्ड (Urinals) इत्यादि

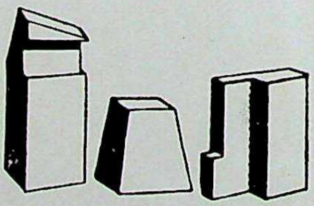

ऊष्मसह (Refractories)
समस्त औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए

पोर्टलैण्ड सिमेंट
सामान्य निर्माण के लिये

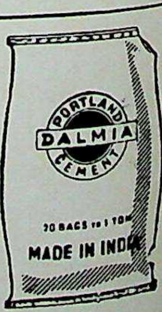

डालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड
डालमियापुरम् (तिरुचिरापल्ली)

DC-H-0

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इस अंक में

तीसरी विकास योजना	अग्रलेख	३८६
मँहगाई की विकट समस्या		३६१
टिप्पणियाँ		३६२
भारत में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था	बी० एल० कोठारी	३६५
जापान व भारत का आर्थिक विकास	कृष्णचन्द्र विद्यालंकार	३६८
भारत के लिए रूस का सस्ता तेल		४०१
गाँव-गाँव में सहकारिता	निरंजन सिंह	४०३
अपनी जानकारी बढ़ाइए		४०५
पंजाब ने क्या पाया ?	एन० के० मुकर्जी	४०७
विदेशों से सहायता	एक अमरीकी पत्रकार	४१०
अर्थवृत्त चयन		४११
राजधानियों पर अपव्यय	सिद्धराज ढड्ढा	४१४
बैंक-बीमा		४१६
तीसरी योजना कैसे सफल हो ?	अर्थशास्त्री	४१७
भारत के प्रमुख सार्वजनिक उद्योग	श्रीकृष्ण इनाणी	४१६
नया निर्माण		४२३
हमारे उद्योग		४२४
भूमि सुधार के कार्यक्रम		४२७
मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं		४३२

• • •

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

संयुक्त सम्पादक : भीमसेन त्यागी

•

वार्षिक मूल्य : आठ रुपया

एक प्रति : ७५ नये पैसे

कार्यालय : २८।११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

फोन : २५८७३

सुभाषित रत्नमाला

सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

७ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था। कई वर्ष से पुस्तक अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी ! अब परिवर्धित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा में प्रकाशित हुआ है—

- वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी सुविधापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं।
- श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ।
- पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्तियाँ, जिनके उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सकें।
- आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें नैतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य।
- उपहार और पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयुक्त।

मूल्य एक प्रति १.०० रु०। 'सम्पदा' के ग्राहकों से ००.८० न० पै० प्राप्त होने पर 'बुक पोस्ट अन्डर-पोस्टल सर्टिफिकेट' द्वारा भेजी जाएगी।

अशोक प्रकाशन मन्दिर

२८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

DA—J

सम्पदा के अनूठे उपहार : ११ विशेषांक

'सम्पदा' का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विश्व-कोष ही होते हैं। प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल, एम० कॉम० कहते हैं—'सम्पदा' के विशेषांक तो हमारे लिए गीता व बाइबिल के समान हैं।'

१-योजना अंक

(प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्व सामग्री)

एक प्रशंसनीय प्रयत्न। यह अंक पंचवर्षीय योजना को समझने की कुंजी है।

मूल्य : १.०० —जीवन साहित्य

२-भूमि-सुधार अंक

(भूमि समस्याओं का अद्भुत विवेचन)

इस विषय में अपने ढंग का अद्वितीय प्रकाशन है।

मूल्य : १.०० (अप्राप्य) —प्रताप

३-वस्त्र-उद्योग अंक

(भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं)

इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। सम्पादक को बधाई।

मूल्य : १.२५ —श्री घनश्यामदास बिड़ला

४-चम्बल अंक

(चम्बल योजना का विस्तृत परिचय)

अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है।

मूल्य : ००.७५ (अप्राप्य) —श्री मिश्रीलाल गंगवाल

५-मजदूर अंक

(मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन)

लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं। ...मानव की नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की संस्कृति व परम्पराओं के अनुकूल है।

मूल्य : १.२५ —श्री खंडूभाई देसाई

६-उद्योग अंक

(प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय)

भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याओं पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का अच्छा संग्रह है।

मूल्य : १.२५ —अजन्ता

७-राष्ट्रीय-विकास अंक

(द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन)

ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा।

मूल्य : १.२५ —श्री मोहनलाल सुखाड़िया

८-बैंक अंक

(भारतीय बैंकों की समस्याओं का निरूपण)

Here is one more 'Sampada' Special worth treasuring. (अप्राप्य)

मूल्य : १.२५ —Organiser

९-समाजवाद अंक

(समाजवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार)

सम्पदा का समाजवाद अंक मिला। यह काफी अच्छा और पठनीय है।

मूल्य : १.५० —श्री श्रीमन्नारायण

१०-राष्ट्र-प्रगति अंक

(द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का विवेचन)

यह अति लाभदायक तथा उपयोगी है। लिखने का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है।

मूल्य : १.५० —श्री अमरनाथ विद्यालंकार

११-सहकारी कृषि अंक

देश के अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न पर विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण। —मू० १.५०

रजिस्ट्री से सब प्राप्य अंक मंगाने के लिए रु० १०.५० भेजिये।

सम्पदा • २८-११ शक्तिनगर • दिल्ली-६

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सम्पदा

अर्थशास्त्र की नवीनतम गतिविधियों की मासिक पत्रिका

वर्ष : ९

अंक : ८

अगस्त १९६०

तीसरी विकास योजना के उद्देश्य

पिछले अंक में हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के साधनों पर विचार किया था। इस अंक में हम यह देखना चाहते हैं कि तीसरी योजना के उद्देश्य क्या हैं और उनकी पूर्ति के लिए क्या-क्या प्रयत्न सुझाये गये हैं। दूसरी योजना में चार उद्देश्य बताए गये थे। इस योजना में ५ उद्देश्य बताए गये हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

(१) अगले ५ सालों में राष्ट्रीय आय में वार्षिक ५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करना और इस हिसाब से देश के विकास में रुपया लगाना, जिससे आगे भी वृद्धि का यही क्रम जारी रहे।

(२) अनाज की पैदावार में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना और कच्चे माल की उपज को इतना बढ़ाना कि उससे हमारे उद्योगों की जरूरतें पूरी हों और निर्यात भी हो सके।

(३) इस्पात, बिजली, तेल, ईंधन आदि बुनियादी उद्योगों को बढ़ाना और मशीन बनाने के कारखाने कायम करना, जिससे १० वर्ष के अन्दर-अन्दर देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीनें अपने देश में ही बनाई जा सकें।

(४) देश की जन या श्रम शक्ति का पूरा उपयोग करना और लोगों को रोजगार के अधिक जरिए देना।

(५) धन और आय की विषमता को घटाना तथा सम्पत्ति का अधिक न्यायोचित वितरण।

दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो उद्देश्य रखे गये थे, उन्हीं को पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट किया गया है। इन ५ उद्देश्यों में से प्रथम उद्देश्य राष्ट्रीय आय की वृद्धि है। सरकारी अनुमान के अनुसार आजकल भारत की कुल राष्ट्रीय आय ११६९० करोड़ रुपया है। इसे बढ़ाने के लिए हमें विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। एक हिसाब के अनुसार पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में अर्थात् १९५१ से १९६१ तक राष्ट्रीय आय लगभग ४२ प्रतिशत बढ़ी है। इसे अधिक बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम १४ प्रतिशत नई विकास योजनाओं में लगाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम अपनी राष्ट्रीय आय का केवल ७ प्रतिशत विकास योजनाओं में लगा सके और सम्भवतः दूसरी योजना के अन्त तक विनियोजन का अनुपात ११ प्रतिशत तक हो जायगा। जितना रुपया हम ज्यादा लगाएंगे, उतनी ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। देश के अर्थशास्त्रियों का यह अनुमान है कि हम आजकल अपनी राष्ट्रीय आय का ८ प्रतिशत बचाते हैं। योजना आयोग के सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की है कि तीसरी योजना के अन्त तक हम ११ प्रतिशत तक बचाने लगेंगे। तभी हम योजनाओं में अधिक रुपया लगा सकेंगे और अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ा सकेंगे। उत्पादन—उद्योग या कृषि—के जो लक्ष्य तीसरी योजना में रखे गए हैं, उनसे यह आशा की जानी चाहिए कि हम अपनी राष्ट्रीय आय में योजना के उद्देश्य को प्रायः पूर्ण कर लेंगे। इस्पात व लोहे और नई-नई मशीनरी बनाने के कारखानों तथा कृषि-उत्पादन के नये लक्ष्यों से हमारी राष्ट्रीय आय अवश्य बढ़ जानी चाहिए। श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि विकास योजना तो एक ऐसा सिलसिला है, जो एक के बाद एक दूसरी

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विकास योजनाओं को जन्म देगा। तीसरी योजना में भी स्वयं-स्फूर्त विकास की बात कह कर यही इच्छा प्रकट की गई है।

योजना के दूसरे और तीसरे उद्देश्य इसी स्वयं स्फूर्ति के लिए रखे गये हैं। कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। खेती और सामुदायिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में १०२५ करोड़ रुपये तथा सिंचाई की छोटी बड़ी योजनाओं के लिए ६५० करोड़ रुपये रखे गये हैं। लोगों द्वारा निजी रूप से भी ८०० करोड़ रुपया लगाने की सम्भावना की गई है। तीसरी योजना के कुल व्यय का २३.१ प्रतिशत रुपया कृषि आदि पर खर्च होगा। योजना बनाते समय यह ध्यान में रख लिया गया है कि जहाँ लोगों का जीवन-स्तर बढ़ने से अन्न की खपत ज्यादा होगी, वहाँ २ प्रतिशत वार्षिक जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी। योजना आयोग की सम्मति में कृषि उत्पादन इतने अवश्य होने चाहिएं कि प्रति व्यक्ति १५ औंस अनाज और ३ औंस दाल तथा १७.५ गज कपड़े के लिए रुई सुलभ हो सके।

योजना का तीसरा उद्देश्य औद्योगिक विकास का है। दूसरी पंचवर्षीय योजना लोहे के तीन नये कारखानों पर गर्व कर सकती है। नई योजना में मशीनें बनाने के अनेक कारखाने, बोकारो में नया लोहे का कारखाना तथा दूसरे अनेक उद्योग खोलने के लिए लक्ष्य नियत किये गये हैं। तीसरी योजना में उद्योग और तत्सम्बन्धी कुल ४१.२५ करोड़ रुपया व्यय हुआ था और हमने काफी बड़ी सफलता प्राप्त की थी। इसलिए यह आशा स्वाभाविक ही है कि तीसरी योजना में हम १॥ गुना खर्च करके ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। द्वितीय योजना का परिणाम संतोषजनक रहा है। उत्पादन के निर्देशक अंक १०० से २६७ तक बढ़ गये हैं। इस सहायता में निजी उद्योग का योगदान प्रशंसनीय रहा है। इसी कारण तीसरी योजना में उनसे भी कम अपेक्षा नहीं की गई। सरकार पूर्वाग्रह को छोड़कर वस्तुस्थिति समझने लगी है।

योजना का चौथा उद्देश्य लोगों को रोजगार देना है। वस्तुतः किसी राष्ट्रीय योजना का यह सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। २ प्रतिशत वार्षिक की गति से हमारी जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस कारण योजना आयोग के सदस्यों को स्वयं यह भय है कि इन ५ वर्षों में काम करने लायक जितने युवा बढ़ जायेंगे, उन सबको काम नहीं दिया जा सकेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६७५० करोड़ रुपया लगाकर ८० लाख आदमियों को रोजगार देने का विचार किया गया था। किन्तु ६५ लाख से अधिक आदमियों को रोजगार नहीं मिल सका। यदि आयोग के अपने अनुमान को भी मान लिया जाये तो भी एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए ८४४० रुपया व्यय होता है। इस दृष्टि से तीसरी योजना में भी हम १२० लाख से अधिक आदमियों को रोजगार देने में समर्थ नहीं हो सकते। इन ५ वर्षों में करीब १॥ करोड़ आदमी रोजगार मांगने लायक बढ़ जायेंगे। कम से कम ३० लाख आदमी, अगर योजना के सब लक्ष्य पूर्ण भी हो गये, तो रोजगार नहीं पा सकेंगे। इसलिए यह अच्छा होता कि उद्योगों के विकेन्द्रीकरण तथा ग्रामोद्योगों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाता।

योजना आयोग ने विकेन्द्रीकरण के महत्व को अवश्य स्वीकार किया है और कुछ उद्योग ग्रामों के लिए ही सुरक्षित रखने की राय दी है, जैसे तेल पेरना, धान कूटना, कपास ओटना आदि किन्तु इस दिशा में और भी ठोस प्रयत्न की आवश्यकता है। गावों में अनेक सुधार योजनाओं से कुछ बेकारी अवश्य दूर हो सकती है, बशर्ते कि यह योजनाएं व्यापक और संगठित रूप में प्रारम्भ की जाएं।

भारत की समस्या श्रम की अधिकता की समस्या है, जबकि यूरोप की समस्या श्रम की कमी की समस्या है। इसलिए यहां हमें बहुत केन्द्रीभूत उद्योगों के मोह को छोड़ना होगा और छोटे उद्योगों को प्रश्रय देना होगा।

योजना का ५ वां उद्देश्य समाजवाद की दिशा में प्रयत्न करना है, जिसके लिए संसद् प्रतिज्ञाबद्ध हो चुकी है। जमीदारी उन्मूलन, श्रम सम्बन्धी नियम, सम्पत्तिशाली वर्ग पर नये-नये टैक्स तथा सार्वजनिक क्षेत्र में नये-नये उद्योग खोलने की प्रवृत्ति आदि उपायों से सरकार समाजवाद की दिशा में प्रयत्न करना चाहती है। दूसरी योजना में इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र में ७२५० करोड़ रुपये के विनिमय की व्यवस्था की गई है, जबकि निजी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्षेत्र में केवल ४ हजार करोड़ रुपये की। आजकल समाजवाद का अर्थ केवल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण रह गया है और इस अर्थ के पालन के लिए हम कभी-कभी यह भी भूल जाते हैं कि इससे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता उत्पादन-वृद्धि को हानि पहुंचेगी या नहीं। हमारी नम्र सम्मति में जहां बड़े-बड़े उद्योगों का सरकार द्वारा खोला जाना आवश्यक है, वहां जनता में समाजवाद की मूल भावना—सामान्यजन के प्रति आत्मीयता की भावना—का प्रचार अधिक आवश्यक है। इस दृष्टि से यदि उच्च वर्ग को अपना जीवन-स्तर कुछ नीचा भी करना पड़े, बड़े अधिकारियों (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में) के वेतन कम भी करने पड़ें, तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जितने आडम्बर सामान्य जनता से उच्च वर्ग को पृथक करते हैं, उन आडम्बरों पर ही चोट करनी चाहिए, तभी हम अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखते हुए, समाजवाद की दिशा में वास्तविक प्रगति कर सकते हैं। ● ●

मंहगाई की विकट समस्या

किसी भी योजना, विशेषकर पंचवर्षीय योजना को चलाने के लिए अनिवार्य है कि पदार्थों के और विशेषकर जीवनोपयोगी पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि न हो। आज सबसे बड़ी समस्या देश के नेताओं के सामने यही है कि वे पदार्थों के मूल्य स्थिर रखने में सफल हो रहे हैं। बढ़ती हुई मंहगाई ने सामान्य और मध्यम वर्ग को विचलित कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों की पिछली हड़ताल के मूल में मंहगाई के प्रति क्षोभ भी मुख्य कारण था, जब दूसरी योजनां प्रारम्भ हुई थी, मूल्य कुछ कम हो रहे थे; किन्तु आज मूल्यों का स्तर करीब २० प्रतिशत ऊँचा हो गया है। और यह भय है कि यदि मूल्यों के स्तर को बढ़ने से न रोका गया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, न केवल करोड़ों भारतीयों को अपने जीवन निर्वाह में कठिनता होगी, बल्कि योजना का व्यय भी बढ़कर नई सपस्याएँ पैदा कर देगा। नीचे लिखे आंकड़ों से मालूम होगा कि मूल्य किस तरह बढ़ रहे हैं :

	मई १९५९	दि० ५९,	मई ६०
मिल का कपड़ा	११३.८	१२३.२	१२८.८
हथकर्घे पर बुना कपड़ा	१०६.६	१०७.८	११३.७

नीचे की तालिका से मूल्य वृद्धि किस प्रकार हो रही है, उस पर भी प्रकाश पड़ेगा :

	अप्रैल १९५९	अप्रैल १९६०	२५ जून १९६०	२० जुलाई १९६०
भोज्य पदार्थ	११३.१	११८.८	१२०.४	१२१.८
अन्न	९९.९	१०८.८	१०८.१	१०८.३
दालें	९६.२	८९.४	९०.२	९२.८
तमाखू	९५.८	१०१.२	११०.५	११०.५
कपड़े	११२.३	१२४.६	१२६.७	१२६.७
तिलहन	१२७.४	१४१.२	१४७.५	१४८.३

इस तालिका से पाठक यह जान जाएँगे कि मूल्यों में वृद्धि किस तरह हो रही है और यही कारण है कि देश के नेता मंहगाई की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने को विवश हैं।

अनेक अर्थशास्त्रियों का विचार तो यह है आज, जब हम अपनी विकास योजनाओं में अरबों रुपए व्यय कर रहे हैं और विवश होकर मुद्रा-प्रसार का आश्रय लेना पड़ रहा है, तब मूल्य में वृद्धि अनिवार्य ही है। मुद्रा-प्रसार के कठिन परिणामों को रोकने के लिए दो ही उपाय संभव है—एक तो यह कि हमारा उत्पादन माँग के अनुरूप बढ़ता जाय और दूसरा यह कि हम अपनी बचत का अनुपात ७-८ प्रतिशत से बढ़ाकर १३-१४ प्रतिशत तक करें। दूसरे शब्दों में हम अपनी आवश्यकताएँ काफी कम कर लें और कम से कम चीजों की मांग करें। इसी के परिणामस्वरूप मांग और उत्पादन में जनता स्वयं सन्तुलन करने की चेष्टा करे, लेकिन जहां जीवन का स्तर पहले ही निम्न हो, वहां इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता। तरह-तरह के नियंत्रण और राशन पद्धतियां मूल्य नियंत्रण करते में असफल रहीं; इसलिए कभी-कभी हम यह सोचने लगाते हैं कि मुद्रा-प्रसार को अधिक सीमित करना तथा योजना की अवधि पांच वर्षों की अपेक्षा ७ वर्ष तक करना तो उपयुक्त न होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशों से अरबों रुपया उधार लेकर भी हम मुद्रा प्रसार की भीषण समस्या को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं।

योजना आयोग ने जनता की क्रय शक्ति को कम करने के लिए नए कर लगाने का परामर्श दिया है, इससे राष्ट्र की सामूहिक बचत बलात् होने लगेगी, परन्तु यह कर भार कहां तक लादा जाना सहन किया जायेगा ? यह हम सहन नहीं कर सकते। सरकार यदि किसी तरह जनता का विश्वास संपादन करके उसमें राष्ट्रीयता और राष्ट्रहित में मितव्यय की सच्ची भावना भारत के और स्वयं अपने व्यवहार में क्रियान्वित कर सके, तभी मंहगाई के निवारण में कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है। ● ●

खाद्य का उत्पादन व्यय

तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न का उत्पादन ७५० लाख टन से बढ़ाकर १०५० लाख टन करने का प्रस्ताव है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का उत्पादन बढ़ाने के बहुत ऊँचे लक्ष्य नियत किए गए हैं। दूसरी योजना के अन्त में २ लाख १० हजार टन नत्रजनयुक्त खाद बनेगी। तीसरी योजना में इसे बढ़ा कर १० लाख टन कर दिया जाएगा, इसी तरह फासफटी खाद का उत्पादन भी ७० हजार टन से बढ़ाकर ४-५ लाख टन करने का विचार है, ये लक्ष्य पूर्ण हों, यह सबकी कामना है। किन्तु, दूसरी तरफ यह समाचार है कि सिन्दरी के कारखाने में १९५८ की अपेक्षा १९५९ में ५५ हजार टन खाद कम तैयार हुई। यह स्थिति अत्यन्त शोचनीय है और सरकार की व्यवस्था पर एक बड़ी टीका है।

आखिर उत्पादन में इस कमी का कारण क्या है ? पत्रों में प्रकाशित समाचारों से प्रतीत होता है कि इस कमी का मुख्य कारण पर्याप्त कोयला प्राप्त न होना है। इन समाचारों के अनुसार सिन्दरी के लिए प्राप्त होने वाला कोयला अचानक ही लोहे के नए कारखानों को दे दिया गया। 'कोकिंग कोल' की समस्या नई समस्या नहीं है। इसकी ओर पहले भी कोयला उद्योग सरकार का ध्यान खींच चुका है, पिछले साल ऐसी स्थिति आ गई थी कि कोयले की कमी के कारण कई माल-गाड़ियों का चलना स्थगित करना पड़ा था। रेलों के लिए दस दिन का भी कोयला शेष नहीं रहा था। और इस संकट को पूरा करने के लिए निजी कारखानों के लिए प्राप्त कोयला रेलों के लिए भेज दिया गया था। इसी तरह सिन्दरी के कारखाने का कोयला दूसरी जगह भेज दिया गया है।

सरकार ने कोयला धोने के लिए जो कारखाने स्थापित करने थे, वह अब तक स्थापित नहीं कर पाई। निजी उद्योग ने यह माँग की थी कि इसमें अधिक कोयला पैदा करने की सुविधाएँ दी जाँय, क्योंकि हमने १९५५ में ३३८ लाख टन। कोयला पैदा किया जबकि सरकार ने केवल ४२ हजार टन। योजना आयोग ने इस माँग को अस्वीकार करके निजी उद्योग के लिए १० लाख टन (पहले उत्पादन का छठा भाग) और सरकारी उद्योग के लिए १२ लाख टन का (पहले उत्पादन का तीन गुना) अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य नियत किया था। सरकार स्वयं इस काम को करने में असमर्थ रही। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ७० लाख टन की कमी रही। हमें आशा करनी चाहिए कि इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी। विचारणीय प्रश्न यह है— क्या कोयले की कमी के कारण सिन्दरी में खाद का उत्पादन कम हुआ है, अथवा दूसरे कारण से ? कोयले का उत्पादन लक्ष्य पूर्ण न होने में कौन अपराधी है सरकारी उद्योग या निजी उद्योग? किन परिस्थितियों में यह हुआ और इस सम्बन्ध में भावी नीति क्या रहनी चाहिए ? ● ●

इंजन और रेल डिब्बों का उत्पादन

अब भारतीय रेलें इतने इन्जन और रेल डिब्बे तो तैयार करने ही लगी हैं कि उनकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, साथ ही पड़ौसी देशों को भी केवल ये दो चीजें ही नहीं, बल्कि रेलों के कुछ और उपकरण भी भेजने की स्थिति में है। भारतीय रेलों को टूटे और खराब इंजन बदलने तथा अतिरिक्त आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रति वर्ष लगभग २५० स्टीम इन्जनों की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता अब हम अपने देश में बने इन्जनों से ही पूरी करते हैं। केवल १० वर्ष पहले हम एक भी इंजन नहीं बना सकते थे। चितरंजन कारखाने में इस समय प्रति वर्ष औसतन २०० के हिसाब से इन्जन बन रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान बड़े आकार के डब्ल्यू०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जी० इंजन बनाने पर दिया जा रहा है, जिसका वजन १२५ टन होता है और जो दो हजार टन भारी गाड़ी को ३५ मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकता है।

आवश्यक सेवाओं में हड़ताल

भारत सरकार ने रेल तार और डाक आदि आवश्यक सेवाओं पर प्रतिबन्ध लगाकर बहुत उचित किया है। जब कोई वर्ग, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण हो, समाज और देश की उपेक्षा कर केवल अपने हित को ही सामने रखता है, तब उसके प्रति विरोध की भावना उत्पन्न हो जाना स्वभाविक है। इंगलैण्ड में १९२६ की व्यापक हड़ताल ने मजदूर दल को अप्रिय बना दिया था। मुसोलिनी और हिटलर के फासिस्ट और नाजी आन्दोलन कितने ही बदनाम क्यों न हो, वे तत्कालीन वामपक्षी अव्यवस्था की प्रतिक्रिया थे। भारत में भी जनता की सहानुभूति इस हड़ताल ने खो दी। आज देश के प्रत्येक वर्ग को चाहे वह मजदूर हो या मालिक अनुभव करना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघों के सम्बन्ध में यह भी उचित निश्चय किया कि बाहर के व्यक्ति उसके अधिकारी नहीं बन सकते। इससे राजनीतिक दलों के अनुचित स्वार्थपूर्ण प्रभावों से मजदूर संघों के श्रमिक आन्दोलन को बचाया जा सकेगा। श्रमिक आन्दोलन केवल आर्थिक दृष्टि से चलने चाहिएं। राजनीतिक कारणों से इन आन्दोलनों का चलाना खतरनाक होगा।

बिक्री-कर और राज्य

व्यापारियों और दुकानदारों की बहुत समय से यह माँग रही है कि बिक्री कर को उत्पादन कर के रूप में बदल दिया जाय। कपड़ा, चीनी और तमाखू के बिक्री कर उत्पादन कर के रूप में लिए जाने लगे, जिससे अनेक लाभ हुए हैं। बिक्री-कर की चोरी बन्द हो गई। दुकानदारों की परेशानी कम हो गई। कर वसूली के खर्चे बहुत कम हो गए। व्यापारियों की माँग थी कि अन्य वस्तुओं पर भी बिक्री कर हटाकर उत्पादन कर लिया जाय; किन्तु अनेक राज्यों की सरकारें इस पर सहमत नहीं हुईं। फलतः इस विषय पर कोई निर्णय नहीं हो सका। राज्य सरकारों के लिए जहाँ बिक्री कर कामधेनु बना हुआ है, वहाँ उनके अधिकार और सत्ता की आकांक्षा को भी पूर्ण करता है, किन्तु अपनी इस आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने छोटे-छोटे दुकानदारों की परेशानियों को समझने की चेष्टा नहीं की।

रोजगार देने के लिए

हमने अपने सम्पादकीय अग्रलेख में यह आशंका व्यक्त की है कि योजना आयोग की प्रस्तावित योजना के अनुसार भी सब लोगों को रोजगार नहीं मिल सकेगा। यह आवश्यक है कि छोटे उद्योग धन्धों तथा ग्रामोद्योगों को प्रश्रय दिया जाए। यह प्रश्रय देने के लिए जरूरी है कि अनेक उद्योगों को केवल ग्रामों तक सीमित कर दिया जाए। तेल पेरना, धान कूटना, चमड़े के जूते और बैग बनाना तथा कुछ खास किस्म के कपड़े बड़े बनाना, उद्योगों के लिए वर्जित कर दिया जाए। सिद्धान्त रूप से सरकार ने यह नीति कुछ उद्योगों के लिए स्वीकृति की हुई है, किन्तु उसके व्यवहार में कुछ 'यदि' आकर नीति को निष्क्रिय कर देते हैं। "मशीनों का प्रयोग वहीं हो, जहाँ रुपये और समय की बहुत बचत होती हो।" यह शर्त तो सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। बड़ी मशीनों से समय और श्रम की बचत तो होती ही है; और इसी कारण तो ये उद्योग चलते हैं। योजना की रूपरेखा में कहा गया है कि कारखानों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जाए; लेकिन साथ ही फालतू आदमी भरने का निषेध भी किया गया है। नई और आधुनिक मशीनें तो होती ही इसलिए हैं कि कम लोगों से अधिक काम लिया जा सके। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के दो ही तरीके हैं। ग्रामोद्योगों का विकास और बाँध, मकान, स्कूल, पंचायतघर, सड़कों, पुलों, तालाबों और नालियों के निर्माण की अधिकाधिक योजनाएँ। ● ●

विशेषांक

गत अंक में घोषणा थी कि 'सम्पदा' का अगस्त अंक वार्षिक विशेषांक 'जहाज उद्योग अंक' होगा, किन्तु आपके हाथ में यह साधारण अंक है। 'जहाज उद्योग अंक' की तैयारी में, विषय की विशिष्टता के कारण अनुमान से अधिक समय की अपेक्षा थी। इसी कारण से विशेषांक को अल्प समय के लिए स्थगित करना उचित समझा गया। अब शीघ्र ही विशेषांक प्रकाशित होगा। आशा है पाठक सदा की तरह विशेषांक की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे और इसे अपना स्नेह-मान देंगे।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

सन्तुलित विकास

डा० सम्पूर्णानन्द ने केन्द्र से यह मांग की कि विकास कार्यों के लिये निधि का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिये। गत २ योजनाओं में जिन में ३१२६ करोड़ रुपये राज्यों के विकास कार्यों में व्यय किये गये, उत्तर प्रदेश को केवल ३८३ करोड़ का कोटा मिल सका। यह राशि पूरी निधि की १२·३ प्रतिशत थी, जब कि प्रदेश की आबादी देश की कुल जनसंख्या की १७·४ प्रतिशत है।

सन्तुलित आर्थिक उन्नति का अर्थ है कि प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध साधनों का भरपूर उपयोग किया जाए और देश के सभी भागों में रहन-सहन, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क आदि की समान सुविधाएं हों। एक ही राज्य में भी कुछ भाग उन्नत हैं और कुछ बहुत पिछड़े हुए। ये क्षेत्र काफी समय से उपेक्षित रहे हैं।

इस भूल को सुधारने और पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति करने की ओर अब ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी योजना में, और १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भी, इस पर जोर दिया गया कि सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास किया जाए और पिछड़े क्षेत्रों को उन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। पिछले दस वर्षों में राज्यों ने अपनी विकास योजनाओं पर ३८ अरब रु० खर्च किया, जिसमें से २२ अरब रु० उन्हें केन्द्रीय सरकार ने सहायता के रूप में दिया। हीराकुड, कोसी, चम्बल, रेंड, नागार्जुन सागर और भाकड़ा-नंगल जैसी बड़ी योजनाओं के बनाने में पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति का खास ध्यान रखा गया।

१९५३-५४ में आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बम्बई, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अभावग्रस्त क्षेत्रों की कठिनाइयों को स्थायी रूप से दूर करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। इस पर लगभग ४० करोड़ रु० खर्च किया गया और इसके अन्तर्गत छोटी तथा मध्यम सिंचाई के काम दिए गए। बाढ़ से रक्षा के लिए पुश्ते बनाए गए, बेकार जमीन को खेती के योग्य बनाया गया और कंटूरबंदी की गयी। जब कुछ राज्यों में अन्न का अभाव हुआ, तब १९५७ में एक और विकास कार्यक्रम चलाया गया।

राउरकेला और भिलाई में इस्पात कारखाने तथा भोपाल का बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना भी ऐसे इलाकों में है, जहां पहले कोई उद्योग नहीं थे। अवश्य ही पिछड़े इलाकों को लाभ पहुँचाने के अलावा इन स्थानों का चुनाव प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से भी किया गया। जिन खनिज क्षेत्रों में खानें नहीं हैं या बहुत कम खनिज निकलता था, वहां अब भरपूर खनिज निकाला जाने लगा है। दक्षिण अरकाट में लिग्नाइट (भूरा कोयला) सलेम (मद्रास राज्य) में बाक्साइट और राजस्थान में सीसे-जस्ते तथा तांबे की खानें खोदी जा रही हैं। इससे इन पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों को काफी लाभ पहुंच रहा है। तीसरी योजना में काफी मात्रा में कच्चा लोहा विदेशों को भेजा जाएगा। इससे उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में खानें खोदी जाएंगी। इससे इन पिछड़े क्षेत्रों को लाभ होगा। पिछले कुछ वर्षों में देश के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में चीनी की अनेक मिलों को खोलने के लाइसेन्स दिए गए हैं। जिन क्षेत्रों में सूती कपड़े की मिलें नहीं हैं, वहां इनको खोलने के लिए बढ़ाव दिया जा रहा है।

लेकिन यह समस्त काम केवल केन्द्रीय सरकार का नहीं है। अन्य सरकार का भी कर्तव्य है कि वे अपने पिछड़े हुए जिलों में नई योजनाएं चालू करें। सरकार ने कुछ चीजों का उत्पादन खास तौर पर छोटे ग्रामोद्योगों के लिए नियत या रिज़र्व कर दिया है, ताकि राज्य सरकार लोगों को ये कारखाने खोलने के लिए प्रेरित कर सकें।

तीसरी योजना में राज्यों की उद्योग योजनाओं पर लगभग ३६ अरब ५० करोड़ रु० खर्च होगा। इसमें से २५ अरब रु० केन्द्रीय सरकार सहायता के रूप में देगी। राज्य सरकारें कम विकसित क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देंगी, और वहां उद्योग शुरू करने का विशेष प्रबन्ध करेंगी। ●●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था

बी० एल० कोठारी

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का उदय अभी हाल ही में हुआ है। इस नवीन युग की यह एक नई विचार-धारा है। यह अर्थ व्यवस्था दो अर्थ-व्यवस्थाओं से मिलकर बनी है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत पूंजीपति व राष्ट्रीय सरकार संयुक्त रूप से एवं सहयोग से कार्य करे। पूंजीवाद एवं समाजवाद के गुणों का सम्मिश्रण कर मिश्रित अर्थ-व्यवस्था एक ऐसी मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था है जिसका उद्देश्य प्रजातंत्रात्मक देश में केवल जीवन स्तर ऊँचा उठाना, एवं सुरक्षा ही नहीं है; अपितु यह वह सामाजिक तथा विकाशशील पद्धति है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए प्रत्येक कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त कर सकता है। यह अर्थ-व्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की मिली-जुली पृष्ठभूमि है। ग्रेट ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की विशाल प्रगति मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाने के ही कारण हुई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना होता है। स्वतंत्र होने के बाद भारत में दिसम्बर सन् १९४७ को उद्योग परिषद की सिफारिशों को मानकर नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया। इस नीति की घोषणा तात्कालिक उद्योग मंत्री स्वर्गीय डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने ६ अप्रैल १९४८ को संसद में की। इस नीति के अन्तर्गत श्रम, पूंजी तथा साधारण जनता द्वारा देश के शीघ्र औद्योगिककरण की आशा प्रकट की गई थी। इस नीति के अनुसार उद्योगों को चार वर्गों में बांटा गया। प्रथम वर्ग में युद्ध सामग्री का निर्माण, अणुशक्ति का उत्पादन एवं नियंत्रण तथा रेल यातायात का स्वामित्व एवं प्रबन्ध आदि उद्योग रखे गये, जिन्हें नितान्त सरकारी क्षेत्र कहा गया।

द्वितीय वर्ग के उद्योगों पर प्रान्तीय एवं केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण रखा गया। इस वर्ग में कोयला, लोहा एवं इस्पात, जहाज निर्माण, टेलीफोन व टेलीग्राफ तथा वायरलेस एपरेटस का निर्माण तथा खनिज तैल आदि उद्योगों को रखा गया।

तृतीय वर्ग में वे उद्योग रक्खे गये, जिनका प्रबन्ध तो निजी साहसी करता; किन्तु नियंत्रण सरकार का रहता था। इस वर्ग में नमक, शक्कर, ऊनी एवं सूती वस्त्र, कागज, सीमेंट, मशीन के औजार आदि उपभोग की वस्तुएं रक्खी गयी।

चतुर्थ वर्ग में शेष सभी वस्तुओं का निर्माण रक्खा गया जिसके लिए निजी व्यवसायी स्वतंत्र था। समय-समय पर लागू किये गये सरकारी नियमों का पालन इन्हें भी करना होता था। केन्द्रीय सरकार ने कुटीर एवं लघु उद्योगों को संगठित उद्योगों के साथ समन्वय करने हेतु 'केन्द्रीय

तृतीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना पर जोर देते हुए स्वीकार किया गया है: "राष्ट्र-विकास में निजी उद्योग का महत्त्वपूर्ण योगदान होगा।" यह मान लिया गया है कि निजी उद्योग भी राष्ट्रीय योजना के व्यापक मूल्यों को स्वीकार करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सहयोग पूर्वक काम करेगा। निजी उद्योग में केवल बड़े-बड़े संगठित उद्योग ही नहीं आते, करोड़ों किसान, मजदूर, कारीगर छोटे-छोटे उद्योग चलाने वाले भी निजी उद्योग के अंग हैं। सभी उद्योग चाहे वे सरकारी हों या निजी, राष्ट्र के आर्थिक विकास और जनहित के लक्ष्य के सामने रखेंगे।

तीसरी योजना में कुल १०२ अरब रुपए का व्यय निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार निजी उद्योग में इस तरह खर्च किया गया:

	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
दूसरी योजना	४६००	३१०००	६७००
तीसरी योजना	७२५०	४०००	१०२००

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कुटीर उद्योग सभा' की भी स्थापना की। औद्योगिक श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण का भी उचित प्रबन्ध किया गया। देश की वर्तमान नीति ऐसी है जिसमें सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में भावी औद्योगिक विकास की संभावना है। किन्तु इस नीति के अनुसार राष्ट्रीयकरण की अस्पष्ट सरकारी नीति के कारण निजी पूंजीपतियों को सदैव खतरा रहा है।

औद्योगिक नीति को अमल में लाने के लिए १९४९ में 'उद्योग विकास एवं नियंत्रण विधेयक' प्रस्तुत किया गया, जो काफी गरमागरम बहस के पश्चात् १९५१ में स्वीकृत हुआ। इस नीति को लागू करने में अनेकों कठिनायां आईं। इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये गये। इन संशोधनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को वर्तमान उद्योगों के पंजीयन, उनका उत्पादन एवं विकास का नियमन करने तथा इस संबंध में प्रान्तीय सरकार को सलाह देने का अधिकार मिला है, कोई भी वर्तमान उद्योग पंजीयन के बिना एवं नया उद्योग सरकार से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किये बिना अपना उद्योग संचालन नहीं कर सकता। साथ ही कोई भी उद्योग नई वस्तु का उत्पादन बिना अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये नहीं कर सकता है। इस संशोधन पर बोलते हुए योजना मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने कहा था कि "सरकार तथा व्यक्तिगत उद्योगपति का अस्तित्व परस्पर निर्भर है। जब दोनों की क्रियाओं में सहकारिता आवश्यक है, ऐसी परिस्थिति में सरकार का उद्योगों पर कड़ा नियन्त्रण अनुचित प्रतीत होता है।"

१९५६ में नई घोषणा

सन् १९५५ में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारतीय संसद द्वारा समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की पद्धति की स्वीकृति, तथा उसकी आवड़ी एवं अमृतसर कांग्रेस अधिवेशनों में पुष्टि एवं अभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुभ आरम्भ आदि ऐसी घटनाएँ हैं जिनकी पृष्ठभूमि में औद्योगिक नीति को पुनः संबोधित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलस्वरूप नई औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया जो कि मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पर आधारित है एवं जिसका लक्ष्य समाजवाद की ओर है। भारतीय पृष्ठभूमि में समाजवाद से तात्पर्य यह है कि "आम जनता के सहयोग से सरकार द्वारा देश के आर्थिक जीवन का संचालन एवं नियंत्रण!" ३० अप्रैल सन् १९५६ को प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार उन सभी उद्योगों को जो आधार भूत उद्योग है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रक्खा गया। सभी उद्योगों के भावी विकास का उत्तरदायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया जिससे आर्थिक विषमता दूर हो सके।

इस नवीन नीति के आधार पर उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया। प्रथम श्रेणी में १७ उद्योग हैं, जिनकी नई इकाइयों की स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार का रहेगा। इनमें हथियार, बारूद, अणुशक्ति, लोहा तथा इस्पात, बिजली की मशीनें, कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, जिपसम, सल्फर, सोना, चांदी, तांबा, हवाई जहाज, रेलवे, जल उषा निर्माण, टेलीफोन आदि शामिल है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र होगा। द्वितीय श्रेणी का क्षेत्र मिश्रित क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत पूंजीपति एवं सरकार दोनों ही नवीन उद्योग स्थापित कर सकेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत १२ उद्योग हैं जिनमें से प्रमुख सड़क, यातायात, समुद्री यातायात, खनिज, एलमूनियम, मशीन, औजार, दवाएं, खाद आदि शामिल है। तृतीय क्षेत्र में बचे हुए सभी उद्योग आते हैं। यह क्षेत्र निजी क्षेत्र कहलाता है। इसके विकास के लिए भी सरकार पंचवर्षीय योजना में आवश्यक स्थान देगी। जनवरी-सितम्बर १९५८ तक इस अधिनियम के अन्तर्गत ५५४ नये उद्योगों को लाइसेंस देने की स्वीकृति दे दी गई है।

आरोप-प्रत्यारोप

इस नवीन नीति की कड़ी आलोचना की गई एवं इस पर अनेक आरोप भी लगाये गये। निजी क्षेत्र को इस नीति से कम प्रेरणा अवश्य प्राप्त हुई है। यह सत्य भी है कि सरकारी मशीनरी अभी तक अकुशल एवं दोषपूर्ण है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को इस नीति के अनुसार दिया गया महत्व काफी अंश तक कम हो सकता है और देश की औद्योगिक विकास में भी बाधा खड़ी हो सकती है। इस नीति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को दिये अत्यधिक महत्व की भारतीय उद्योगपतियों द्वारा जोरदार शब्दों में आलोचना की

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

की गई है । जहांगीर ने कहा है कि मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली में परिवर्तन कर लगाने आदि के लागू होने से निजी क्षेत्र को काफी धक्का पहुंचा है । वास्तविकता तो यह है कि इस नीति में निजी क्षेत्र के विकास के लिए भी पर्याप्त अवसर दिये है । सरकार निजी उद्योगों को भी आवश्यकतानुसार सहायता दे रही है । उन महत्त्वपूर्ण उद्योगों के विकास के लिए जिनके लिए निजी क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं हो रही है, सरकार ने विशेष शर्तों पर ऋण देकर अथवा पूंजी लगाकर वित्तीय सहायता दी है । डा० राधाकृष्णन भी इस मत के समर्थक है'' कि पूर्ण राष्ट्रीयकरण देश के हित में नहीं हो सकता । इसी आधार पर मार्च १७, १९५५ को संसद में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाने की घोषणा की गयी जिसका देशवासियों द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया । भारत आज भी अपने भावी विकास के लिए इस नीति को अपना रहा है एवं अपनाता रहेगा, ऐसी आशा की जाती है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना सन् १९५१ से १९५६ तक पूर्ण हुई । भारत १९५९ के अनुसार प्रथम योजना काल में कुल २९३ करोड़ रुपए का उद्योगों में विनियोग किया गया । ६० करोड़ रुपया सार्वजनिक क्षेत्र में एवं २३३ करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में विनियोग किया गया । सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय टेलीफोन उद्योग, चितरंजन का इन्जन बनाने का कारखाना, पैराम्बूर का सवारी डिब्बों का कारखाना, सिंदरी का रसायनिक खाद का कारखना, मशीन टूल्स फैक्टरी आदि बड़े कारखाने प्रारम्भ किये गये । निजी क्षेत्र में भी इसी प्रकार के कारखाने खोले गए । उत्पादन में सन् १९५१ से ३८ प्रतिशत की वृद्धि हुई । कहा जाता है कि ''यह मूल रूप में एक तैयारी की तथा स्थिरता की योजना थी ।'' कई अर्थों में यह अपने आप में पूर्ण योजना थी । इसके निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति में जो सफलता प्राप्त हुई है, उससे देश में आशा और आत्म विश्वास का एक वातावरण उत्पन्न हुआ है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७२०० करोड़ रुपया खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से ४८०० करोड़ रुपए निजी क्षेत्र में खर्च होंगे । सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का अनुपात, क्रमशः ६१ व ३९ प्रतिशत है । द्वितीय योजना में विदेशी विनिमय संकट का सामने करने के कारण से सार्वजनिक क्षेत्र को ४८०० करोड़ से घटाकर ४५०० करोड़ रुपया कर दिया गया । द्वितीय योजना काल में इम्पीरियल बैंक तथा जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण तथा राजकीय व्यापार निगम की स्थापना देश के औद्योगिक एवं आर्थिक ढांचे में समाजवादी समाज की ओर महत्त्वपूर्ण कदम है । इस योजना में लोहा एवं इस्पात उद्योग को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है । सार्वजनिक क्षेत्र का कुल उत्पादन २३ लाख टन होने की आशा है । द्वितीय योजना काल में राष्ट्रीय आय में २० प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि लक्ष्य २५ प्रतिशत का था । इस प्रकार से लौह एवं इस्पात उद्योग में भी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को समान महत्त्व दिया गया । सरकार दोनों ही क्षेत्रों को विकसित देखना चाहती है । इन सबको देखते हुए यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जिन अन्तिम लक्ष्यों की पूर्ति होने जा रही है । वे कुछ अधिक उत्साहप्रद नहीं दिखाई देते हैं । हमारी सफलताएं बताती है कि हम इस मार्ग पर आंख बन्द किए ही नहीं चल रहे हैं । इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को बल मिला । देश के भावी विकास में यह व्यवस्था काफी अन्त तक सहायक सिद्ध हुई है किन्तु योजना की अर्थ-व्यवस्था में समय समय आने वाली कठिनाइयां बाधक अवश्य बनी है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में ६,७०० करोड़ रुपए एवं निजी क्षेत्र में ४,३०० करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान किया गया है । स्पष्ट है कि तृतीय योजना में भी भारत विभिन्न अर्थ-व्यवस्था को ही अपनायेगा । जिससे राष्ट्र का औद्योगिक विकास द्रुत गति से हो सके ।

भारतीय नवीन आर्थिक नीति रूस और चीन की नीति से इस बात से भिन्नता स्पष्ट करती है कि वहां आर्थिक जनतन्त्र का निर्माण ऊपर से हुआ है और भारत निम्न स्तर से आर्थिक जनतन्त्र की रचना के लिए प्रयत्नशील है । इस दिशा में भारत की सफलता निश्चय ही महान होगी । ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जापान व भारत का आर्थिक विकास

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार

आज जब कि भारत अपनी विविध योजनाओं के द्वारा आर्थिक विकास करने की दिशा में प्रयत्नशील है, स्वाभाविक है कि वह अन्य विकासशील देशों पर दृष्टिपात करे तथा देखे कि वे किन तरीकों से व किस गति से अपनी आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। इसीलिए देश के विभिन्न अर्थशास्त्री रूस व चीन की योजनाओं का ध्ययन करते हैं और उनकी आश्चर्यजनक प्रगति से विस्मित होकर उनका अनुकरण करने का भी परामर्श देते हैं, इसमें सन्देह नहीं कि रूस व चीन की उन्नति सचमुच अध्ययन योग्य और माननीय है, किन्तु एक देश और है जो इन दस-बारह वर्षों में फिर शून्य से उन्नति करते हुए विश्व के लिए प्रतिस्पर्द्धा और आशंका का कारण बन गया है और वह है जापान।

गत महायुद्ध में जापान जितना क्षत-विक्षत और ध्वस्त-विध्वस्त हुआ था, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। भारत उस समय ब्रिटेन की अनिवार्य आवश्यकताओं के कारण एक के बाद एक नए उद्योग का विकास कर रहा था, परिणामस्वरूप देश में अनेक नये उद्योगों का विकास हो रहा था। इंगलैण्ड, जापान, जर्मनी व अमेरिका सभी देशों के युद्ध में लिप्त होने के कारण भारत औद्योगिक विकास का भारी केन्द्र बन गया था और उधर जापान बमबारी व अग्नि वर्षा और अणु बमों के कारण तबाह हो रहा था। उसके उद्योग, बड़े-बड़े कारखाने, जहाज तथा परिवहन के अन्य साधन नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। जापान की मानव-शक्ति तथा विशेषकर उसके उत्साह का भी विनाश हो गया था। पिछले ५० वर्षों में बनाया गया उसका व्यापारी साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था। जनरल मैकार्थर के अपमानजनक शासन ने जापान की प्रतिभा व क्षमता को पद-दलित कर दिया था परन्तु इन ८-१० वर्षों में अर्थात भारतीय स्वाधीनता के बाद १० वर्षों में जापान ने चमत्कार कर दिखाए हैं, अलादीन का चिराग लेकर जो जादू कर दिया है, वह सब देशों के लिए और भारत के लिए आश्चर्यकारक और स्फूर्तिदायक है।

१९४७ में वहां कृषि की उपज ७६७० लाख टन हुई थी, किन्तु १९५७ में यह उपज बढ़कर १३६५० लाख टन अर्थात् करीब दुगुनी हो गई। औद्योगिक अनुमानों के अनुसार १९५० में जापान की कुल राष्ट्रीय आय ३३८४ अरब रुपये थी जो १९५७ में बढ़कर ८२५२ अरब रुपये अर्थात् करीब ढाई गुनी हो गई। इन अंकों का महत्त्व तब और भी स्पष्ट हो जाएगा जब हमें यह मालूम होगा कि इन वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय ९५·३ अरब रुपए से बढ़कर ११४·२ अरब रु० हुई है अर्थात् जापान ने जब २५० प्रतिशत उन्नति की है तब स्वतंत्र भारत ने केवल २० प्रतिशत आय बढ़ाई है। जापान की वास्तविक प्रगति का महत्त्व इन अंकों से अधिक स्पष्ट हो जायगा।

जापान की युद्धोत्तर आर्थिक उन्नति के निर्देशक अंक

१९३४=१००

	वास्तविक राष्ट्रीय आय	प्रति व्यक्ति आय	औद्योगिक उत्पादन	कृषि उत्पादन
१९३९ युद्ध से पूर्व	११६.७	११३·३		
१९४६ युद्ध समाप्ति का वर्ष	५७·१	५२·०	३३·२	७७·३
१९४७	६०·५	५२·०	४०·३	७४·७
१९४९	७०·६	६६·६	६०·५	८९·०
१९५४	१२७·८	९९·३	१६६·९	१०५·८
१९५५	२४२·८	१०९·७	१८९·७	१२७·९
१९५५	१५६·८	११९·२	२३१·७	१२१·५

(जापान सरकार की प्लैनिंग एजेंसी की रिपोर्ट से)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इन अंकों से स्पष्ट है कि जापान की राष्ट्रीय आय १९४६ की अपेक्षा करीब तिगुनी, प्रति व्यक्ति करीब सवा दो गुनी और औद्योगिक उत्पादन करीब साढ़े छः गुना बढ़ गया है।

यह बात हमें स्मरण रखनी चाहिए कि जापान के पास भारत व चीन के समान न तो विशाल जन-संख्या है और न विस्तृत प्रदेश-क्षेत्र है। वहां खनिज पदार्थ भी भारत व चीन जैसे उपलब्ध नहीं हैं उसका विस्तृत व्यापारिक साम्राज्य भी दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, भारत तथा अन्य बाजार उसके हाथ से निकल गए थे और समस्त उद्योग, रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, जहाजी बन्दरगाह आदि सब नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। इन विषम परिस्थितियों में जापान की प्रायः सभी क्षेत्रों में आश्चर्यकारी उन्नति आर्थिक जगत का चमत्कार ही है। आर्थिक विकास के विभिन्न अंगों पर संक्षेप से एक दृष्टि मनोरंजक और उपयोगी होगी।

भारतीय अर्थ व्यवस्था का मेरुदण्ड कृषि है। जापान यह दावा नहीं कर सकता। जनसंख्या के अनुपात से उसके पास भूमि कम है। इसलिए उसने गहन (Intenrune) कृषि की ओर अधिक ध्यान दिया है। उसने कृषि का वैज्ञानिकीकरण करते हुए भी बड़े-बड़े खेतों व ट्रैक्टरों पर कम बल दिया है और कृषि के उन्नत उपायों से—सिंचाई, गहरा हल, अच्छे बीज और खाद आदि से अपनी उपज बढ़ाई है। नीचे के अंकों से दोनों देशों की पैदावार की अच्छी तुलना हो सकेगी—

प्रति हैक्टर जापान में पैदावार भारत की अपेक्षा तीन गुने से भी अधिक है। यही कारण है कि कुछ वर्ष पूर्व भारत में जापानी धान की खेती के अनुकरण का आन्दोलन सरकार ने जोरों से चलाया था। आज भारत में कृषि क्षेत्र थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है, किन्तु जिस वेग से जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए कृषि-पद्धति में ही परिवर्तन करना होगा। कृषि पद्धति के साथ भूमि के क्षेत्रों का प्रश्न भी विचाराधीन हो जाता है। भारत में पिछले वर्षों से कृषि भूमि की कितनी जोत हो, छोटी जोत हो या बड़ी, इस पर अर्थ-शास्त्रियों में काफी विवाद रहा है, जो

	भारत			जापान		
	क्षेत्रफल (००० हैक्टर)	उपज १०० किलोग्राम प्रति हैक्टर	कुल उपज ००० लाख टन	क्षेत्रफल (००० हैक्टर)	उपज १०० किलोग्राम प्रति हैक्टर	कुल उपज ००० लाख टन
१९४७	९८५३	८.४	४८.२००	५७८	१३.३	७६७०
१९४८	८२३६	६.६	५४.७६०	६६०	१५.८	१०४१०
१९५४	१०६८१	७.५	८०.१७०	६७१	२२.६	१५१६०
१९५५	१११३६	८.०	८९.१९०	६८१	२२.२	१४६८०
१९५६	१२२८७	७.१	८७.०७०	६५७	२०.९	१३७५०

इन अंकों से स्पष्ट है कि प्रति हैक्टर जापान में गेहूँ की पैदावार १९५६ में करीब तीन गुनी हुई। चावल की पैदावार का उत्पादन तो और भी अधिक है।

चावल

	भारत		जापान	
	प्रति हैक्टर (१०० किलोग्राम)	कुल पैदावार (०००० लाख टन)	प्रति हैक्टर (१०० किलोग्राम)	कुल पैदावार (००० लाख टन)
१९४८	११.८	३४२.३२०	३८.४	११९.९३०
१९४९	११.७	३५३.१२०	४०.२	११९.२९०
१९५५	१३.२	४०९.१५०	४८.१	१४८.१८०
१९५६	१३.६	४२८.९००	४२.२	१३०.८००

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अब भी जारी है। जापान का अनुभव बताता है कि छोटे खेत भी यदि खेती की पद्धति का विकास ठीक तरह हो, तो ज्यादा पैदावार में बाधक नहीं होते। भारत में ज़मीदारी पद्धति का उन्मूलन हो चुका है, जापान में अमेरिकन शासन के दिनों में ही बड़े जमीदारों का उन्मूलन कर दिया गया था। वहां जमीदारों को भारत की अपेक्षा बहुत कम मुआवज़ा दिया गया था। यों दोनों देशों की परिस्थितियों में भी अन्तर है। भारत में आज भी प्रतिशत जन-संख्या कृषि पर अवलम्बित है, जबकि जापान में केवल ४६ प्रतिशत ही आजीविका पर निर्भर करती है। भारत में यद्यपि चकबंदी की जा रही है, तथापि छोटे-छोटे खेत आज भी देश की बड़ी भारी समस्या है। जापान में भी छोटे-छोटे खेतों के टुकड़ों को एक साथ नहीं किया जा सका। जमींदारी पद्धति की समाप्ति के बाद जापान की ९२ प्रतिशत कृषि भूमि छोटे किसानों के पास थी। भूमि सुधारों के बाद भूमि पर अनुपस्थित जमींदारों की तथा स्वयं बोने वाले काश्तकारों की १ हैक्टर (२.४७ एकड़) से अतिरिक्त जमीन छीन ली गई। अधिकतम खेती की जोत ३ हैक्टर नियत की गई। होकायडो द्वीप में १२ हैक्टर वहां भूमि की कमी नहीं। ये भूमि सुधार जापान में इसलिए सम्भव हो सके, क्योंकि उन दिनों स्वेच्छाचारी शासक जनरल मैकार्थर का शासन था। उसने जमींदारों को जो देश में बहुत प्रभाव व सत्ताशाली थे, कुचलना आवश्यक समझा। भारत जैसे लोकतंत्र देश में यह उस तरह सम्भव नहीं है। भारत के खेत कितने छोटे जोतों में बंटे हुए है, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा—

भारत से जापान की तुलना के लिए प्रतिशत के आंकड़े ही अधिक उपयोगी हैं। बहुत छोटे जोत तो दोनों देशों में एक से हैं, किन्तु १। से २॥ एकड़ तक के खेत जापान में ३२.० प्रतिशत हैं, जबकि भारत में १७.६ प्रतिशत। १२ एकड़ से ऊपर के खेतों का प्रतिशत भारत में बहुत अधिक है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जापान में छोटे खेतों की संख्या अधिक है, परन्तु ये छोटे खेत भी भारत की अपेक्षा पैदावार में बहुत आगे बढ़े हुए हैं जैसा कि ऊपर दिए गए अंकों से स्पष्ट है।

उत्पादन कैसे बढ़ता है ?

आचार्य विनोबा और श्रीमन्नारायण आदि अर्थशास्त्री छोटे खेतों के समर्थन में इसीलिए जापान का उदाहरण देते हैं। पैदावार वृद्धि का रहस्य उसकी कृषि पद्धति में है। इसकी दो विशेषताएँ हैं:—(१) अच्छे बीज, खाद व सिंचाई का अधिक प्रयोग तथा (२) सहकारी सेवाएँ। अन्तर्राष्ट्रीय खाद व कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) की रिपोर्ट से मालूम होता है कि जापान में कृषि उत्पादन का निर्देशक अंक (युद्ध पूर्व = १००) १९५३-५४ में १०७ था, पर १९५६-५७ में वह १३४ तक बढ़ गया, परन्तु भारत में यह अंक १२० से केवल ३ अधिक अर्थात् १२३ तक बढ़ा। नीचे के अंक इसे पुष्ट करते हैं:—

	जापान		भारत	
	प्रति हैक्टर किलोग्राम		प्रति हैक्टर किलोग्राम	
फसल	१९४८-५२ औसत	१९५६	१९४९-५२	१०५६
गेहूँ	१८५०	२०६०	६६०	७१०

(शेष पृष्ठ ४३० पर)

एकड़ों में खेतों का आकार	जोतों की संख्या (००० में)	कुल जोतों का प्रतिशत	भारत में कुल आकार खेत	भारत में कुल खेतों का प्रतिशत
०.७५ से नीचे	१४७२	२३.८	०.५ से नीचे	२३.९
०.७५ से १.२५ तक	१०५१	१७.००	०.५-१.०	८.०
१.२५ से २.५ से नीचे	१९७३	३२.७	१.०-२.५	१७.६
२.५ से ५.० से नीचे	१३४०	२१.७	२.५-५.०	१७.५
५.० से १२.५ से नीचे	२८५	४.७	५.०-१०.०	१६.५
१२.५ से २५.० से नीचे	३९	०.६	१०.०-२५.०	११.८
२५.० या ऊपर	१०	०.२	२५.० या ऊपर	४.५
कुल	६१८	१००		१००

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत के लिए रूस का सस्ता तेल

विवेचक

पिछले महीने समाचार पत्रों में दो समाचार प्रकाशित हुए। एक यह कि सोवियत रूस और भारत में एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार रूस भारत को १५ लाख टन तेल देगा। यह तेल न पश्चिमी कम्पनियों के तेल से केवल १० से १५ प्रतिशत सस्ता होगा; बल्कि रूस इसकी कीमत भी रुपये में वसूल करेगा। इसका अर्थ यह कि रूस भारत से तेल के बदले कुछ अन्य वस्तुएं ही खरीदेगा। इस समाचार से अधिकारियों और जनता को भी पर्याप्त प्रसन्नता हुई। यह प्रसन्नता महंगा तेल बेचने वाली कम्पनियों के प्रति आक्रोश के रूप में भी प्रकट हुई।

दूसरा समाचार यह है कि तेल का शोधन करने वाली बर्मा शेल, स्टेनवक आदि कम्पनियों ने रूस के क्रूड आयल को साफ करने से इंकार कर दिया है। कुछ दिन पूर्व ऐसा ही समाचार क्यूबा की तेल-शोधक कम्पनियों के बारे में भी प्रकाशित हुआ था। इसी प्रश्न को लेकर क्यूबा और अमेरिका में भयानक आर्थिक-संघर्ष भी छिड़ा। अनेक क्षेत्रों में विशेष कर कम्युनिस्ट क्षेत्रों में यह बात उठाई गई है कि भारत सरकार को भी क्यूबा की तरह इन विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना और राष्ट्रीयकरण करने से इंकार कर दिया।

ये समाचार कुछ प्रश्न पैदा करते हैं : रूस द्वारा सस्ता तेल देने का यह समझौता राजनैतिक कारणों से किया गया है या आर्थिक कारणों से? भारत सरकार को यह समझौता करना चाहिए था या नहीं? भारत स्थित तेल शोधक विदेशी कम्पनियों को रूस से इन्कार करने का अधिकार था या नहीं? भारत सरकार को अपनी बात न मानी जाने पर इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए या नहीं? हम इन पंक्तियों में प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करेंगे।

जो लोग रूस की प्रत्येक गति-विधि के पीछे राजनैतिक कारण तलाश करते हैं, उनकी दृष्टि में भले ही पश्चिमी देशों को नीचा दिखाने की इच्छा विद्यमान हो, हम यह मानते हैं कि रूस ने यह समझौता आर्थिक कारणों से किया है। उन्नत यंत्रिकरण, कम मजदूरी, अपनी आवश्यकता से अधिक तेल का उत्पादन और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आकर उपभोक्ता सामग्री प्राप्त करने की इच्छा आदि कारणों से वह तेल का यह व्यापार करने को प्रस्तुत है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के इस युग में रूस के इस व्यापार की आलोचना नहीं की जा सकती।

भारत सरकार को जब सस्ता तेल मिल रहा था तो उसे अस्वीकार कर देना बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती थी। रूस से जो तेल मिलेगा उसकी कीमत अन्दाज़न ४० करोड़ रुपए होगी। इस विपुल राशि को विदेशी मुद्रा में चुकाने की चिन्ता भी हमें नहीं करनी होगी। कुछ ही वर्षों में रूस इसके बदले में भारतीय सामग्री खरीद लेगा। इस समझौते के कारण स्वभावतः भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है—जिस ओर शायद लोगों का ध्यान बहुत कम गया है। यदि भारत ने रूस को उसका मुंह मांगा माल देने में इस बात का ख्याल नहीं रखा कि कहीं दूसरे विदेशी बाजार हमसे छिन न जाएं तो भारत को रूस की मांग पूरी करने से विशेष लाभ नहीं होगा। जो माल आज पश्चिमी देश मंगाते हैं, वह माल उन्हें न देकर इस समझौते के अन्तर्गत रूस को दें, तो वे बड़े बाजार हमारे हाथों से सदा-सदा के लिए निकल जाएंगे। उन देशों से होने वाला व्यापार अधिक प्रतिकूल होकर विदेशी मुद्रा के लिए नई समस्या खड़ी कर देगा। इसलिए तेल के बदले में रूस जिस माल की मांग करे, उसका उत्पादन बढ़ाकर ही हमें पूर्ति करनी चाहिए, न कि दूसरे स्थायी बाजारों को खो कर।

अब एक प्रश्न यह रह जाता है कि भारत स्थित विदेशी कम्पनियों को रूस के क्रूड आयल को साफ करने से इंकार करने का अधिकार था या नहीं? भारतीय जनता की इच्छा तो यह थी कि वह कम्पनियां रूस का सस्ता क्रूड आयल साफ करतीं, ताकि भारत को सस्ता तेल मिलता। उनके ऐसा न करने पर कुछ क्षोभ अवश्य हुआ, इसलिए भारत सरकार की राय को वे स्वीकार कर लेती तो

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अच्छा होता। लेकिन इसी प्रश्न का दूसरा पहलू भी है। इन विदेशी कम्पनियों ने संसार भर में खनिज तेल के अन्वेषण, निष्कासन और शोधन तथा समस्त संसार में वितरण-व्यवस्था पर अरबों रुपया खर्च किया है। यदि उन्हें दूसरी संस्थाओं द्वारा निकाले गए तेल को साफ करने के लिए कहा जाए, तो उन्हें कहां तक लाभ होगा? यदि उनका अपना क्रूड आयल कम हो तो दूसरों का क्रूड आयल साफ करना कैसे सहन हो सकता है? इसीलिए जब तक इन कम्पनियों को अपना क्रूड आयल मिल रहा है, तब तक रूस का क्रूड आयल साफ करने के लिए इन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता।

भारत सरकार ने इन कम्पनियों के इंकार करने पर, क्यूबा की तरह राष्ट्रीयकरण की धमकी नहीं दी; लेकिन ऐसा न करके भी उसने इस संघर्ष का लाभ अवश्य उठा लिया है। वह कुछ समय से निरन्तर यह प्रयत्न कर रही थी कि ये कम्पनियां तेल का मूल्य कम कर दें। अब उन्होंने स्वयं समझौते की शर्तों में कुछ छूट दे दी है। बर्मा शैल, स्टनवक और काल्टेक्स ने अपने मूल्यों में कुछ कमी कर दी है। इससे भारत को २० करोड़ रुपया वार्षिक अथवा ५ वर्षों में १ अरब रुपये की बचत होगी। इस तरह इन कम्पनियों ने रूस के सस्ते तेल को देखते हुए अपने तेल की कीमत भी कम कर दी है। और कुल मिलाकर रूस का समझौता भारत के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है।

अन्त में एक महत्वपूर्ण दायित्व सरकार पर आता है। उसे प्रयत्न करना होगा कि मूल्यों में हुई कमी का लाभ साधारण ग्राहक तक पहुंचे, न कि सम्पूर्ण लाभ सरकारी खजाने में चला जाए। एक तरफ यदि डिजेल आयल की कीमतों में कुछ कमी संभव थी, वह वित्तमंत्री द्वारा उत्पादन कर बढ़ा देने से जनता को नहीं मिलेगी। ● ●

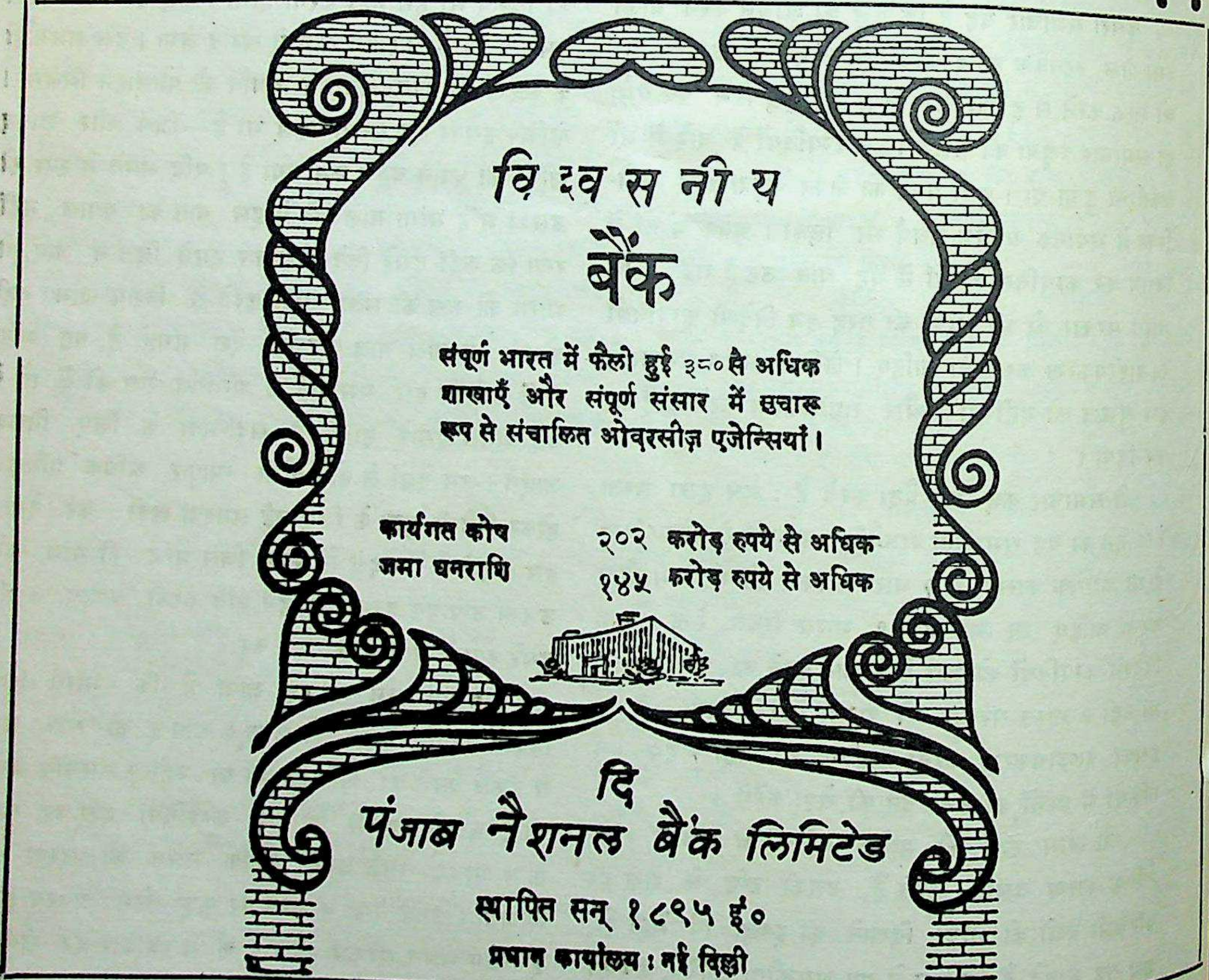

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गाँव-गाँव में सहकारिता

निरंजन सिंह

किसी भी देश के नव-निर्माण और विकास के लिए किसी न किसी योजना की आवश्यकता होती है। भारत में बनी योजनाओं के मूल में यह बात सदा याद रखी गई है कि देहाती क्षेत्र में जितना सुधार जितनी जल्दी किया जा सकेगा, उतना ही देश खुशहाल होगा। चाहे किसी व्यापार को लें या किसी उद्योग को, सबका आधार हमारे देहात हैं। वहीं हमारी ८० प्रतिशत जनता रहती है। उनके सुखी और समृद्ध बनने से ही सारा देश सुखी बनेगा। प्रश्न यह है कि क्या सरकारी विकास की योजना से गाँव गाँव और प्रत्येक किसान का भला हो सकता है या क्या सरकार प्रत्येक किसान के भले के लिए कोई योजना बनाकर उसे सफलतापूर्वक चला सकती है? हमें इसमें सन्देह है।

सरकारी सहायता, उसकी देख रेख और मार्ग-दर्शन जहां आवश्यक है, वहां जनता का सहयोग और योजना को पूरा करने की क्षमता भी बहुत आवश्यक है। इसलिए गांव के लोग पारस्परिक सहयोग के बल पर जो अपनी योजना बनायेंगे, उसे निस्संदेह पूरा कर सकेंगे। राज्य से उन्हें सहायता और प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

राजस्थान सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में ३० प्रतिशत गांवों को और १५ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के क्षेत्र में लाने की योजना बनाई थी, लेकिन करीब डेढ़ साल हुए, राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारिता सम्बन्धी नई नीति निर्धारित की। उससे देश में एक नई सहकारी विकास की चेतना का उदय हुआ है। इस नई योजना के अनुसार गांव को इकाई मानकर लगभग एक हजार की आबादी के गाँव में, या पास-पड़ौस के छोटे गांव की उस संख्या तक आबादी के लिए एक सेवा सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य रखा गया। अब तक किसान को उसकी हैसियत के आधार पर ऋण दिया जाता था, पर अब उसकी उत्पादन योजना के अनुसार ऋण दिया जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक २७ प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को और ४० प्रतिशत गांवों को सहकारिता के क्षेत्र में लाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी गांवों को और ८० प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सहकारिता के क्षेत्र में लाने की योजना बनाई गई है। इस योजना को पूरा करने के लिए सहकारिता के विपुल प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। ग्राम जनता को और सहकारी समितियों के सदस्यों, कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों को समुचित शिक्षा, और प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, जन-जन के सहयोग की आवश्यकता होगी, तभी यह काम पूरा हो सकेगा।

ऋण की आवश्यकता

इस बढ़ती हुई सहकारिता के लिए उसके लाखों सदस्यों के लिए कृषि उत्पादन के लिए समुचित ऋण की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसान की उत्पादन योजना तो दूर-किनारे, उसकी गरीबी और अज्ञान इतना बढ़ा-चढ़ा है कि उसे प्रत्येक फसल को उगाने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। बिना करजा लिए तो वह एक फसल भी नहीं बो सकता है। वैसे देखा जाए तो कर्ज़ लेना बड़ा बुरा है, एक बार इसमें फंसने के बाद फिर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन जब किसान का काम बिना कर्जे के चल ही नहीं सकता, तो उसका प्रबन्ध तो करना ही होगा और वह भी इस तरह कि वह उसे जरुरत के मुताबिक, समय पर, सस्ते ब्याज पर मिल जाय। कृषि भी एक प्रकार का व्यवसाय है, कोई व्यवसाय ऐसा नहीं जो बिना कर्जे के तरक्की कर सके। संसार में कोई ऐसा देश नहीं कि जहां के किसान व अन्य व्यवसायी का काम बिना करजे के चल जाता हो। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यही है कि जो कर्जा लिया जाय वह उत्पादन के काम में ही इस्तेमाल किया जाय, और उत्पादन कार्य के लिए किया गया कर्जा तभी सही तौर पर काम में लाया जायगा, जब यह सहकारी ऋण होगा, क्योंकि तब एक पड़ौसी किसान दूसरे पड़ौसी सदस्य की इतनी खबर जरूर रखेगा कि जो कर्जा उसने अपनी जमानत पर दिलाया है, वह बीज, खाद आदि की खरीद में खर्च किया गया है या नहीं, और उसको खेत में इस्तेमाल किया है या नहीं और फसल के पकने पर उस

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्जे को फसल को बेच कर चुकाने के लिए इन्तजाम हुआ है या नहीं। इस काम के लिए गांव की सेवा सहकारी समिति बनाई जाती है। उससे किसान को सस्ते ब्याज पर कर्जा मिलता है, जरूरत के वक्त बीज, खाद, औजार आदि का इन्तजाम होता है। किसान को उसके घरेलू इस्तेमाल की सभी चीजें गांव में घर बैठे सस्ती और अच्छी मिलने का प्रबन्ध होता है व किसान को पैदावार बढ़ाने के नये २ तरीके, अच्छे सुधरे बीज और नई नई खोजों की जानकारी कराई जाती है।

उत्पादन में वृद्धि

उक्त सब सेवाएं किसान को घर बैठे उसकी सेवा सहकारी समिति से मिलती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सब सुविधाएं और सेवाएं मिलने पर किसान अपनी उपज में तरक्की अवश्य कर सकेगा। समिति के सदस्य मिल-कर बैठेंगे, अपनी उत्पादन योजना बनाएंगे, उसको पूरा करने के लिए तरीके सोचेंगे, उन पर अमल करने के लिए रास्ते ढूंढेंगे, और सब मिलकर यह निश्चय करेंगे कि न सिर्फ अपनी प्रति एकड़ पैदावार बढ़ावेंगे, बल्कि गांव में जितना खाद्यान्न या अन्य वस्तुएं पैदा की थीं, उससे अधिक उत्पादन की योजना साल में करेंगे। उनका ऐसा निश्चय और उनकी योजना को सफल बनाने के लिए सह-कारी समिति से जरूरी साधन और सुविधाएं मिलने पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसान की पैदावार न बढ़े, और उसका मिलजुल कर खेती करने से पारस्परिक सहयोग और भाईचारा से काम करने से उत्पादन में जो खर्च होता वह कम न हो, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि छोटे २ किसान जिनके पास ३-४ बीघा ही जमीन है उनको भी एक बैल जोड़ी तो रखनी पड़ती है और उनको खाने-पिलाने का खर्चा साल भर भोगना पड़ता है, अगर ऐसे किसान मिलकर खेती करें, अपने साधन, हल बैल, भूमि आदि को मिलाकर खेती करें तो उनको पहले के मुका-बले कम बैलों आदि की आवश्यकता होगी और इस तरह उस खर्च में भी कमी होगी।

क्रय-विक्रय समिति से उत्पादन का पूरा मोल गांव की सेवा सहकारी समिति अपने सदस्यों की पैदावार की बिक्री का इंतजाम करेगी। इसके लिए सबसे सरल तरीका यह है कि जैसे ही समिति अपने सदस्यों को ऋण देती है उसकी सदस्यकार सूचना सम्बन्धित क्रय विक्रय संघ को दे दे और यह भी बता दे कि कौन सदस्य अपने कर्जे को चुकाने के लिए कितना माल संघ के जरिये बेचेगा, कितना माल संघ के पास गोदाम में रख कर हाथ खर्च के लिए कुछ रुपया लेना चाहेगा। इस प्रकार की सूचना अपनी सभी सदस्य समितियों से मिलने पर संघ गल्ले को गांव से इकट्ठा करके अपने गोदामों में रखने और बिकवाने का प्रबन्ध करेगा और चूंकि इस प्रकार किसानों का बहुत सा गल्ला संघ के जरिये बिकने को इकट्ठा होगा, संघ के हाथों में उसकी उचित कीमत पाने के लिए खरीदार व्यापा-रियों से सौदा करने की क्षमता होगी। ऐसा न होने पर ही तो यह होता है कि किसान फसल पर अपनी २ पैदा-वार को मंडी में ले जाते हैं और जब मंडी फसल से भरी होती है तो लाजमी तौर पर अनाज के भाव गिर जाते हैं, इसका नुकसान किसान को उठाना पड़ता है।

सभी दृष्टियों से लाभकारी

मिलजुलकर काम करने के द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में तथा परस्पर भाई चारे के साथ रहने में सहकारी तरीका महत्वपूर्ण योग देता है। गांव में खास तौर से सहकारी भावना के विकसित होने से वहां के रहने वालों की आर्थिक दशा में सुधार होता है। और वे एक दूसरे से प्रेम और स्नेह के साथ जीवन व्यतीत करने की कला को समझने लगते हैं। सहकारिता के प्रवेश से गांवों में अधिक उत्पादन, बिचौलियों से छुटकारा, उत्पादन का उचित मूल्य व अवकाश के समय में छोटे धन्धों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है, जिससे कि ग्रामीण जीवन में उदासी व दुखों के स्थान पर प्रसन्नता और आशा की नई किरण अपना प्रकाश फैलाती है। ● ●

स्थायी ग्राहकों से !

स्थायी ग्राहकों से निवेदन है कि वे पत्रव्यवहार में ग्राहक संख्या अवश्य लिखें। संख्या न लिखे होने पर पत्रों का उत्तर देना कठिन होता है। कभी-कभी तो उत्तर जा ही नहीं पाता।

—व्यवस्थापक

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

अपनी जानकारी बढ़ाइए

विदेशी सहायता

सोवियत रूस तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए बहुत सहायता दे रहा है, १८० करोड़ रुपए की प्रतिज्ञात राशि के अतिरिक्त अन्य सहायता भी देगा, जिसका निश्चय कुछ दिनों में हो जायगा।

आगामी सितम्बर में वाशिंगटन में अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, कनाडा और जापान की एक कान्फ्रेंस होने वाली है। यह कान्फ्रेंस विश्व बैंक की ओर से बुलाई गई है। इस कान्फ्रेंस के बाद ही यह कहा जा सकेगा कि विदेशों से तीसरी योजना के लिए कितनी सहायता मिलती है। इसी कान्फ्रेंस में विदेशी ऋणों में किस्त और ब्याज, जिसकी मात्रा एक अरब वार्षिक होती है चुकाने पर विचार किया जायगा। योजना आयोग ने अपनी योजना में इस काम के लिए ५०० करोड़ रुपए की राशि नियत की है।

सरकारी उद्योगों में पूंजी

पहली या दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक उद्योगों की काफी वृद्धि की गई है। यद्यपि राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक उद्योगों का योगदान काम कर रहा है, तीसरी योजना में इसके बढ़ने की बहुत सम्भावना की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्रों का आकार और विस्तार कुछ निम्न-लिखित अङ्कों से हो जायगा।

१९५०-५१ में रेलवे की कुल पूंजी ८५० करोड़ रुपए थी। १९६०-६१ में पूंजी बढ़कर १५६० करोड़ रुपए हो गई है और तीसरी योजना तक २३०० करोड़ रुपए हो जायगी।

सार्वजनिक क्षेत्रों के अन्तर्गत १९५१ में बिजली घरों की पूंजी १७ करोड़ रुपए थी १९५६ में यह बढ़कर ३३० करोड़ रुपए हो गई और तीसरी योजना के अन्त तक १७०० करोड़ रुपए होने की संभावना है।

सरकारी उद्योगों की हाल ही में की गई जांच पड़ताल से मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार के जो १९ उद्योग अब काम करने लगे हैं। १७१ करोड़ रुपए की पूंजी रखते हैं।

लोहे के नए कारखाने आदि भी सात प्रधान सरकारी उद्योगों की कुल पूंजी ५६२ करोड़ रुपए है।

रेल, डाक-तार को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के अन्य २० उद्योगों में १९५८-५९ में १७५ करोड़ रुपए की पूंजी लगी थी।

भिन्न भिन्न राज्यों में सरकार द्वारा चालित उद्योगों में जो पूंजी लगी है, वह भी विपुल राशि है।

तीन प्रकार के आंकड़े

आज देश में योजनाओं से क्या मिला, इसके बारे में सरकार की ओर से कभी आशावादी तो कभी निराशावादी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी राज्य के खाद्य मंत्री ने 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' के भूतपूर्व प्रबन्ध संचालक को कहा था कि वे तीन प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े रखते हैं—पहली प्रकार के आंकड़े वह होते हैं जो केन्द्र को देते हैं। दूसरे प्रकार के आंकड़े प्रेस के लिए तैयार किए जाते हैं और तीसरे प्रकार के आंकड़े अपने प्रयोग के लिए रखते हैं।

विदेशी सहायता का वितरण

योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा में विदेशों से ३२००० करोड़ रुपए सहायता लेने

तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि उद्योगों का विकास उसी औद्योगिक नीति के आधार पर होगा, जो अप्रैल १९५६ में प्रस्तुत की गई थी!

इस उद्योग नीति को समझने के लिए पढ़िए—

प्रो० रामनरेश लाल द्वारा लिखित

हमारी उद्योग-नीति

७० नये पैसे के डाक टिकट भेजकर आज ही प्राप्त करें!

अशोक प्रकाशन मंदिर

२८/११ शक्तिनगर, दिल्ली-६

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

का प्रस्ताव किया है। यह सहायता निम्नलिखित रूप से प्रयुक्त होगी।

.५ सौ करोड़ रुपये विदेशों को पिछले ऋणों की किश्त और ब्याज देने के लिए।

.१६०० करोड़ रुपये विदेशों से मशीनरी और साज के लिए।

.२०० करोड़ रुपये पुरजे तथा कच्चा माल आदि देने के लिए, जिससे बहुत से नये उद्योग चल सकें।

.६०० करोड़ रुपये उपभोग और सुरक्षित भण्डार के लिए।

यह स्मरण रखना चाहिए कि विदेशों से ली जाने वाली यह राशि कुल योजना व्यय का एक तिहाई भाग है।

सड़कें भारत व अन्य देश

यह अनुमान लगाया गया है कि बड़ी सड़कों के बनाने पर लगाए गये रुपये का लाभ ८ से १२ प्रतिशत तक इन सड़कों के निर्माण पर व्यय करना लाभकारी विनियोजन है।

भारत में प्रति एक लाख व्यक्तियों के पीछे ८५ मील सड़कें हैं, जबकि लंका में ११५ मील, ब्रिटेन में ३२४ मील, फ्रांस में १२०२ मील और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १८३४ मील। अन्य देशों में भी व्यापारी रेलों की बजाय सड़क परिवहन को ज्यादा पसन्द करने लगे हैं। १९३८ में ब्रिटेन में सड़क परिवहन से ८० लाख टन माल व्यापार होता था। अब १९५९ में २४६ लाख टन माल होने लगा है अर्थात् ९६ प्रतिशत व्यापार बढ़ गया है। अमेरिका में रेलों में १२२.८ करोड़ टन माल ढोया गया, तब सड़क से १६५ करोड़ माल ढोया गया।

चीनी उत्पादन का लक्ष्य

तीसरी पंचवर्षीय योजना में चीनी उत्पादन का लक्ष्य तीस लाख टन रखा गया है। यह लक्ष्य रखने का आधार यह है कि वर्तमान खपत के आधार पर ४८ करोड़ की जनसंख्या को २५ लाख ६ हजार टन चीनी चाहिए। बदलते हुए भोजन की प्रवृत्ति के कारण २ लाख १४ हजार टन चीनी और चाहिए। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाने के कारण २ लाख ५१ हजार टन चीनी की और भी आवश्यकता पड़ेगी। ● ●

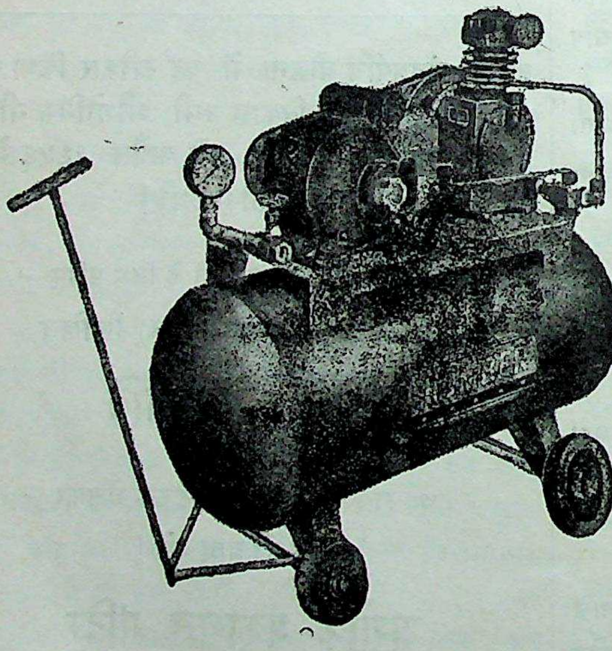
★ एयर कम्प्रेसर्स
★ स्प्रे पेंटिंग के साधन
★ कार वाशर
★ वैक्युम पम्प
डीडवानिया
ब्रादर्स (प्रा.) लि.
कश्मीरी गेट, दिल्ली-६।
टेलीफोन : २३८१८
टेलीग्राम : डीडवानिया

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पंजाब ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या पाया ?

श्री एन० के० मुकर्जी

पंजाब ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के अन्य राज्यों का जो नेतृत्व किया है, वह उसे भविष्य में भी उसी प्रकार बनाये रखेगा। राज्य की वित्तीय योजनाओं पर ३१ मार्च १९६० तक ११२.३६ करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। योजना के अन्तिम वर्ष में राज्य द्वारा अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करने की आशा की जाती है और योजना पर कुल व्यय ११२.३६ करोड़ रुपये से बढ़कर १४५.२१ या कुल राशि का ९५ प्रतिशत हो जायेगा, जब कि कुल १५२.५१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

योजना के प्रथम चार वर्षों में अब तक प्राप्त हुए आंकड़ों के अनुसार—

१८.५० करोड़ रुपये कृषि और सामुदायिक विकास पर।

सिंचाई और बिजली पर ६०.४३ करोड़ रुपये।

उद्योग पर ३.७१ करोड़ रुपये।

परिवहन और यातायात पर ७.४२ करोड़ रुपये।

१६.०६ रुपये समाज सेवाओं पर।

६.२४ करोड़ रुपये अन्य विभिन्न योजनाओं पर व्यय किये।

पंजाब ने द्वितीय योजना में कृषि उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक सफलता प्राप्त कर ली है। वर्ष १९५८-५९ में ६०.८ लाख टन अनाज पैदा किया गया जब कि वर्ष १९६०-६१ के लिए उत्पादन लक्ष्य ५९.० लाख टन रखा गया था।

राज्य ने वर्ष १९५८-५९ के अन्त तक ७.१ लाख गांठें रुई पैदा की जब कि १९६०-६१ के लिए इसका लक्ष्य १०.५ लाख गांठें रखा गया है। इसी प्रकार तिलहनों के सम्बन्ध में भी निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक की सफलता पहिले प्राप्त कर ली गई है। अर्थात् १.८ लाख टन के स्थान पर १.९ लाख टन की उपज १९५८-५९ में ही प्राप्त कर ली गई है। गन्ने की उपज का लक्ष्य ७.८ लाख टन था जबकि ७.३ लाख टन पैदा कर लिया गया है।

राज्य में २६.८३ एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव था। योजना के प्रथम चार वर्षों में १५.५९ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएँ जुटाई गई। द्वितीय योजना अवधि के अन्त तक सिंचित क्षेत्र ८४ लाख एकड़ तक बढ़ जाने की आशा की जाती है। जब कि वर्ष १९४७ में यह क्षेत्र ७ लाख एकड़ था। जहाँ तक भूमि की चकबन्दी का सम्बन्ध है, वहाँ द्वितीय योजना अवधि के अन्त तक १०.० लाख एकड़ क्षेत्र में चकबन्दी का प्रस्ताव था। मार्च १९६० तक कुल २१९.५० लाख एकड़ में चकबन्दी की जा चुकी है। यह आशा की जाती है कि कुल २१९.५० लाख एकड़ क्षेत्र में सितम्बर १९६४ तक चकबन्दी कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत १५३ खंड (इसमें १४ पूर्व विस्तार खंड भी सम्मिलित हैं) जिनके अन्तर्गत राज्य की १०३.६५ लाख ग्राम्य आबादी है, जारी किए जा चुके हैं। सितम्बर १९६३ तक कार्य पूरा हो जाने की आशा की जाती है, जबकि राज्य में २२८ खंड कार्यरत होंगे, जिनके अन्तर्गत राज्य के २१४०० ग्रामों की आबादी आ जाएगी।

राज्य में सहकारिता कार्यक्रम भी सन्तोषजनक रूप से जारी है। राज्य में सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं की संख्या मार्च १९६० में २८६९९ हो गई जबकि वर्ष १९५०-५१ में इनकी संख्या १५,५०४ थी और वर्ष १९५६-५७ में यह संख्या २०,२७३ थी। ग्राम्य ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं को सेवा सहकारिताओं में परिवर्तित करने के लिए उचित पग उठाये जा रहे हैं।

लघु स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र में पंजाब ने उदाहरणीय कार्य किया है। योजना के प्रथम चार वर्षों में राज्य में १३ औद्योगिक स्कूलों की स्थापना की गई और डेढ़ करोड़ रुपये २२०० लघु स्तरीय औद्योगों के यूनिटों को ऋण रूप में दिये गये। लघु स्तरीय औद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि दी जाती है इस प्रकार का एक औद्योगिक क्षेत्र लुधियाना में कायम किया जा चुका है।

राज्य में सड़कों का विकास कार्य भी द्रुत गति से जारी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के १४८३ मील के निर्धारित लक्ष्यों में से योजना के पहिले चार वर्षों में १०३० मील लम्बी सड़कों का निर्माण कर लिया गया है।

पंजाब राज्य ने लाभ के आधार पर अपनी बसें चला कर अन्य राज्यों का पथ प्रदर्शन करते हुए इस राज्य के वित्तीय कोष में आय का एक साधन बना दिया है। योजना के पहिले चार वर्षों में ७६६ मील रूट पर ५ बसें चला दी गई हैं, जब कि योजना में लक्ष्य १०३ बसें २२८ मील के रूट पर चलाना था।

राज्य के शिक्षा संस्थानों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इनकी संख्या वर्ष १९५६ में १४,३८५ थी, जो कि वर्ष १९५९ में बढ़कर १४,८३३ हो गई।

जहाँ तक प्राविधिक शिक्षा का सम्बन्ध है, राज्य के तीन इंजिनियरिंग कालेजों की २२० सीटों को बढाकर ४८० कर दिया गया है। ओवरसीयरों और ड्राफ्टसमैनों की शिक्षा के लिए सीटें बढ़ाकर क्रमशः ११२६ और ३४५ कर दी गई हैं।

स्वास्थ्य योजनाओं के अन्तर्गत पानी की सप्लाई और निकास नालियों की सुविधाएँ १२० ग्रामों और ५०० नगरों में जुटाने और २७ परिवार नियोजन केन्द्र, ३६ स्वास्थ्य यूनिट, १७ ग्राम्य स्वास्थ्य केन्द्र, ७ दन्त चिकित्सालय, २५० आयुर्वेदिक एवं यूनानी डिस्पैंसरियाँ जारी करने का प्रस्ताव था। इसमें से २२ परिवार नियोजन केन्द्र, ३० स्वास्थ्य केन्द्र, १५ ग्राम्य स्वास्थ्य केन्द्र और ७ दन्त चिकित्सालय योजना के प्रथम चार वर्षों में जारी किए गए हैं। राज्य की एक १.२ करोड़ आबादी की प्रतिवर्ष मलेरिया से रक्षा की जाती है।

योजना अवधि में राज्य में १३६५० मकान बनाने का प्रस्ताव था जब कि योजना के पहले चार वर्षों में १०९२९ मकान बनाए जा चुके हैं। राज्य की राजधानी परियोजना का निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से जारी है।

राज्य के आर्थिक ढाँचे का बिजली एक अत्यावश्यक अंग है। यह प्रस्ताव था कि द्वितीय योजना अवधि में २६१४ ग्रामों और कसबों में बिजली लगाई जाए जिसके अनुसार ३७२६ मील ११ किलोवाट लाइनों, ३३४५ वितरण लाइनें और ३५४१ वितरण सब स्टेशनों की आवश्यकता होती। इन लक्ष्यों के अनुसार योजना के प्रथम चार वर्षों में १६४५ कसबों और ग्रामों में बिजली लगाई जा चुकी है और ३०२६ मील ११ किलोवाट लाइनें, १५३६ मील वितरण लाइनें और २०४६ सब स्टेशन लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा २४ हजार किलोवाट बिजली पैदा करने वाले २ सेट कोटला और गंगूवाल में लगाये गये हैं। भाखड़ा के बाएँ किनारे पर ४,५०,००० किलोवाट बिजली पैदा करने वाला बिजली घर योजना के अन्त तक कार्य शुरू कर देगा। ● ●

जनगणना में आर्थिक जानकारी का संकलन

१९६१ की जनगणना में लोगों के काम, नौकरी आदि के आंकड़े इकट्ठे किये जाएंगे। सरकार जो विकास योजना चला रही है और चलायेगी, उन्हें ध्यान में रखकर देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। इस संबंध में ५ प्रश्न हैं :—(१) किसान, (२) खेतिहर मजदूर, (३) घरेलू धंधे करने वाले, (४) अन्य काम करने वाले तथा (५) जो कुछ धंधा नहीं करते वे क्या करते हैं? ● ●

सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित

जीवन साहित्य

उन मासिक पत्रों में से है, जिसके प्रत्येक अंक में चुनी हुई बढ़िया, विचार-प्रेरक सामग्री रहती है।

● आचार्य विनोबा ने कहा, "जीवन साहित्य विचार के लिए अच्छा खाद्य देता है।"

● श्री वियोगी हरि की राय में "इस पत्र के जैसे स्वस्थ विचार-पूर्ण लेख अन्यत्र कम ही देखने में आते हैं।"

पत्र के ग्राहकों को 'मंडल' के प्रकाशनों के मुल्य में भी रियायत मिलती है।

सम्पादक

हरिभाऊ उपाध्याय : यशपाल जैन

वार्षिक शुल्क : केवल चार रुपये

तत्काल ग्राहक बन जाइये!

सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

स र्वो द य पृ ष्ठ

पश्चिम की नकल

हमने अपनी पंच वर्षीय योजना बनाते हुए पश्चिम की नकल की है। हम यह भूल गए हैं कि पश्चिम की समस्याएं हमारे देश से भिन्न और परस्पर विरोधी हैं। पश्चिम में मानव श्रम की कमी है, इसलिए वहां की समस्या का समाधान प्रशिल्पीकरण और मशीनीकरण में है, जिससे मनुष्य की कमी मशीनें कर सकें। दूसरी तरफ भारत की मुख्य समस्या मानव श्रम की अधिक संख्या है, क्योंकि यहां जन संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पश्चिम का समाधान—शिल्पीकरण यहां नहीं चल सकता। यदि महज पश्चिम की नकल करते हुए हमने पूंजीगत प्रधान उद्योगों पर बहुत बल दिया तो बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में विकट रूप धारण कर लेगी।

राजधानी दिल्ली तरक्की पर

१९६० में राजधानी दिल्ली ने हर क्षेत्र में प्रगति (?) का रिकार्ड कायम करते हुए प्रवेश किया है। १९५९ के प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि गत वर्ष दिल्ली की जनता ने अन्य वर्षों के मुकाबले में कहीं अधिक शराब पी, रेडियो खरीदे और फिल्में देखीं!

जहां १९५५ में केवल २,३६,२८४ गैलन शराब पी गयी, वहां १९५९ में २,५९,३८६ गैलन पर हाथ साफ किया गया है।

सिनेमा सम्बन्धी आँकड़ों में यह ज्ञात हुआ है कि यदि १९५९ में दिल्ली निवासियों ने प्रति माह १०० फिल्में देखीं, तो १९५९ में २६०।

१९५५ में ५६,०२० रेडियो लाइसेंस बनाये गये। १९५९ में ९९,४३२।

यह तो हुई शराब, सिनेमा और रेडियो की बात। अब जरा चोरियों, डकैतियों के आँकड़ों पर भी नजर डालिये।

१९५९ में ७० खून हुए, ५२ खून की कोशिशें हुईं, ५६०६ चोरियां हुईं। इसके मुकाबले में १९५५ में केवल ४२ खून हुए, ४० खून की कोशिशें हुईं और ४,२२३ चोरियां हुईं।

प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ है कि प्रति माह जेल में दाखिल होने वाले मुजरिमों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है: १९५५ में ८५० से १९५९ में १,०६४ तक पहुँच गयी है।

गाँव का हर घर शादी का बैंक बने

आज गाँव में किसी के घर शादी होती है, तो उसे कर्ज लेना पड़ता है। फिर वह उस कर्ज से बरी नहीं हो पाता। असल में होना यह चाहिए कि गांवों में किसी के घर शादी निकले, तो वह पूरे गांव का उत्सव बन जाए। हर घर से रुपए-आठ आने का समान इकट्ठा हो और पूरा गांव मिलकर शादी का बोझ बंटा ले। इस तरह गांव का हर घर शादी का बैंक बन जाएगा।

हर घर से मन पीछे एक सेर अनाज मिले

गांव में फिर से यह परम्परा खड़ी करनी चाहिए कि हर किसान अपनी फसल पर मन पीछे एक सेर अनाज गांव के लिए दे। इस अनाज में से उन किसानों को बीज की मदद दी जा सकेगी, जिनकी फसल कम पकी है। इसी में से गांव के बच्चों, बूढ़ों, बीमारों और बेवाओं को खिलाने का एक बड़ा काम भी हो सकेगा। मान लीजिए, गांव का एक बढ़ई बहुत बूढ़ा हो गया है। अब उसके लिए गांव वाले क्या करेंगे? जिसने जिन्दगी भर गांव में काम किया, क्या वह बुढ़ापे में भूखों मरेगा? गांव को ही उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

अनाज कम क्यों पड़ता है?

आखिर यहां अनाज कम क्यों पड़ता है? अभी हम झालावाड़ से आ रहे हैं। वहां की जमीन बहुत अच्छी है, पर उसमें अफीम की खेती होती है। उधर गंगा के किनारे मुजफ्फरपुर में, आन्ध्र के गुन्तूर जिले में, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में और गुजरात के खेड़ा जिले में जमीन बहुत अच्छी है, पर वहां वाले उस जमीन में तम्बाकू की खेती करते हैं। इन जमीनों में अनाज खूब पैदा हो सकता है। अगर सरकार लगान अनाज के रूप में ले, तो उसके पास भी अनाज का भरपूर संग्रह रह सकता है। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

विदेशों से सहायता

एक अमरीकी पत्रकार

"हिन्दुस्तान को दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए विदेशी सहायता व कर्ज की काफी सुइयां (इंजेक्शन) लेनी पड़ी हैं। १९५८ के अन्त तक तो यह संख्या २५ अरब रुपये तक पहुँच गयी थी। ३१ मार्च, १९६१ तक प्राप्त सहायता पांच सालों में ३२ अरब रुपये तक पहुँच जाती है। इसके अलावा १९६१-६२ की शुरुआत की स्थिति को हिन्दुस्तान ने सोचा तक नहीं है, जिसमें इसको फिर से २ अरब रुपया प्रति वर्ष कर्ज लेना होगा।

अगस्त १९५९ के अन्त तक संयुक्त राष्ट्र का कर्ज, देन, निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में कुल विदेशी मदद १८ अरब रुपये आंकी गयी है। बिना अमरीकी मदद के अकाल व विदेशी विनिमय जैसी समस्या को सुलझाते हुए बरकरार नहीं रह सकता था। अमरीका ने हिन्दुस्तान को इस्पात, रेलवे, यातायात के साधन, जूट और सीमेंट-उद्योग के लिए मशीनें तक कर्ज के रूप में दी हैं।

रूस ने भी वस्तु और सेवाओं के रूप में भारत को करीबन आधे अरब तक में से कुछ तो कर्ज दे दिया है और कुछ देने की प्रतीज्ञा की है रूस द्वारा दी जाने वाली हर मदद एक कर्जे के रूप में है, जिसे १२ वर्ष में २॥ प्रतिशत ब्याज के साथ लौटा देना होगा, लौटाने का माध्यम रुपया व वस्तुएं दोनों मान्य हैं।

हिन्दुस्तानियों ने अभी-अभी तीसरी योजना का अन्तिम ड्राफ्ट बनाना शुरू किया है। इसके लिए करीबन दो अरब डालर के नये कर्जे की आशा की जाती है, जिसमें से ४ अरब डालर यहां के निजी निर्यात व कर्ज तथा सहायता के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा होगी। हिन्दुस्तान का निर्यात यूँ तो घट ही रहा है, लेकिन पिछले दो वर्षों में इस तेजी के साथ घटा है कि बिना बाहरी मदद के विदेशी विनियम की जरूरत को पूरा करने का और कोई चारा ही नहीं रह जाता।

रूस पहले से ही यहां की तीसरी पंचसाला योजना में घुस गया है। मास्को ने भारी मशीनों, कोयला काटने की मशीनों की एक मिल, दो बिजली के कारखानों, चश्मे के काँच की एक मिल तथा टेकनिकल सहयोग के साथ कोरबा कोयला क्षेत्र की तरक्की में भी सहायता देने का वादा किया है। जन-चिकित्सा के इन्तजाम के लिए दवाइयों के कारखाने बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है।

रांची में ढलाई-कारखाने के लिए चेकोस्लोवाकिया २ करोड़ १० लाख डालर की पूंजी दे रहा है। रूमानिया व रूस, कुजरार में तेल खोज निकालने का प्रयत्न करते हुए साथ-साथ आसाम व बिहार में तेल साफ करने के दो शोधनालय भी बैठा रहे हैं। पोलैंड मद्रास में चीनी साफ करने की मिल बैठाने का काम कर रहा है, तो चेकोस्लोवाकिया आसाम में डटा हुआ है। पूर्वी जर्मनी ने कपड़े की मिलों को मशीनरी दी है।

अमेरिकी सहायता-फंड भी खुलने को है। पश्चिम जर्मनी तथा ब्रिटेन ने इस्पात कारखानों को मशीनरी दी है तथा बराबर मदद करते रहने का वादा किया है। जापान ने भी अब तक ६ करोड़ डालर तक की मदद दे दी है।

संसार के इतने शक्तिशाली राष्ट्रों से मदद मिलने के बाद तो हिन्दुस्तान को उन्नतिशील मुल्क हो जाना चाहिए था। लेकिन देश की आर्थिक उन्नति ऐसी ढुलमुल रही है कि किसी भी क्षेत्र में कोई ठोस तरक्की नहीं हो पायी है। आयात और विदेशी विनियम का लाइसेंस नयी दिल्ली से ही मिलने के कारण विदेशी विनियम की कमी से उद्योगीकरण को निजी तथा सरकारी, दोनों ही क्षेत्रों में काफी धक्का पहुँचा है।

कुछ साल पहले तक हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञों की यह धारणा थी कि विदेशी पूंजी देश में साम्राज्यवाद के पैर जमा देगी। लेकिन भारत में अमरीकी पूंजी काफी मात्रा में लग चुकी है और अभी भी लोग तहेदिल से इसका स्वागत करने को तैयार हैं। दो सालों में भारत में लगी अमेरिका की व्यक्तिगत पूंजी ग्यारह करोड़ से बीस करोड़ डालर तक पहुंच गयी है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अर्थ वृत्त चयन

कृषि बनाम उद्योग से आय

केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय सचिवालय के सांख्यिकी संगठन द्वारा 'अनुमानित राष्ट्रीय आय' प्रसारित की गई है। निम्न-तालिका १९४८-४९ की कीमतों के आधार पर कुल उत्पादन के प्रतिशत पर प्रकाश डालती है—

क्षेत्र	१९५०-५१	१९५८-५९
प्रथम	४९.०	४७.७
द्वितीय	१६.७	१६.०
तृतीय	१८.८	१८.९
चतुर्थ	१५.७	१७.५

प्रथम क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन और मत्स्य उद्योग शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्र में खान, हाथ का काम तथा कुटीर उद्योग और अन्य कई छोटे-छोटे उद्योग शामिल हैं। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, यातायात आदि शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी में कई प्रकार के पेशे राजकीय सेवा, घरेलू सेवा और मकान आदि सम्पत्ति सम्मिलित हैं।

योजना अवधि में वस्तुतः जो कुछ हुआ, उसे उपर्युक्त आंकड़े शीशे की तरह स्पष्ट करते हैं। देश का वास्तविक उत्पादन पहले दो क्षेत्रों में होता है, उनकी दशा अपेक्षाकृत बिगड़ती जा रही है। तीसरे और चौथे क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रीय आय में इनका भार अपेक्षाकृत बहुत थोड़ा है।

उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट है कि पहले दो प्रधान क्षेत्रों, कृषि और गृह उद्योगों के उत्पादन के अनुपात में कमी आती गई कृषि की अपेक्षा अन्य उद्योगों में पर्याप्त वृद्धि हुई और कुल राष्ट्रीय आय बढ़ी। जिस तरह जन-संख्या बढ़ रही है उस अनुपात से प्रथम वर्ग के उत्पादन में जिसमें अधिकांश जनता लगी हुई है वृद्धि नहीं हुई। इसी असंतुलन से देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन का वितरण ठीक ढंग से नहीं हो सका।

कोलम्बो योजना पर एक दृष्टि

१९५० के जनवरी मास में कोलम्बो में हुए राष्ट्रकुलीन विदेश मन्त्री सम्मेलन में परिकल्पित इस योजना का हुआ अब यह सोलह एशियायी देशों के राष्ट्रस्तरीय आर्थिक आयोजनों के लिए सहायता प्रदान करने वाली महान व्य-वस्था बन गई है। कोलम्बो योजना के माध्यम से कुछ देश अपने उद्योग-सम्बन्धी एवं कृषि-सम्बन्धी विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए सहायता प्राप्त करते हैं, और कुछ सहायता प्रदान करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की बढ़ती हुई जन संख्या के अनुरूप उनके उत्पादन भी बढ़ाना है।

१९५० और १९५८ के मध्य कोलम्बो योजना से सम्बद्ध देशों की जन संख्या में तेरह प्रतिशत वृद्धि के कारण कुल ६८,००,००,००० बन गई और अब वह ७०,००,००,००० हो गई है। जन्म की दर में किसी प्रकार की कमी नहीं आई, पर इलाज की नई युक्तियों के कारण मृत्यु देर में कमी लायी जा सकी है। यद्यपि यह स्थिति निस्सन्देह वांछनीय है, तथापि इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के लगभग सारे देशों के सामने अधिक प्राणियों के उदर-पोषण की समस्या उपस्थित हो गई है।

इस बात के बावजूद कि सम्बन्धित क्षेत्र के ७० करोड़ प्राणियों में से अधिकतर का धन्धा खेती-बारी है। इस क्षेत्र में ठोस परिमाण में वृद्धि हासिल करना बड़ा मुश्किल कार्य सिद्ध होता है—फिर भी, कोलम्बो योजना के नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, १९५९ के दौरान खाद्य उत्पादन में पर्याप्त प्रगति की गई है।

अनुपयोगी भूमि को नई उपयोगिता प्रदान करने, नई सड़कों की स्थापना करने, बाढ़ों की रोक थाम के उपाय करने और अधिक बढ़िया किस्म के बीज सुलभ बनाने, अधिक मात्रा में खाद के सेवन की रीति चलाने, सामुदायिक विकास की योजनाओं को क्रियान्वित, भूमि प्रबन्ध की योज-नायें विकसित करने और सहकारिता के आधार पर भू-कर्म को व्यवस्थित करने में कोलम्बो योजना ने दाता देशों द्वारा दी गई मदद के रूप में या टेक्निकल सहायतायें पहुँचाकर सहायता पहुँचायी है।

कोलम्बो योजना ने सम्बद्ध देशों के औद्योगिक विकास में भी पूरा योग दिया। गत दस वर्षों के दौरान, बिजली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और सीमेन्ट के उत्पादन में दुगुनी वृद्धि की प्राप्ति हो सकना; और वस्त्र, खाद, इस्पात, इन्जीनियरी तथा अन्य उद्योगों को प्रगति पथ पर अग्रसर पाना और १९५९ में कोयले और तेल में उत्पादन-वृद्धि के प्रोत्साहनप्रद उदाहरणों का सामने आना—कोलम्बो योजना की गति विधियों की सार्थकता के स्पष्ट प्रमाण हैं।

यदि यह स्पष्ट है कि इस समस्या के समाधान के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है, तो इसमें भी क्या शक है कि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण को सफल बनाने के लिए काफी मात्रा में बाहरी सहायता अपेक्षित है। पूँजीगत सामान का आयात, और टेक्निकल अनुभव से लाभान्वित होने की व्यवस्था जिस बढ़े-चढ़े स्तर पर की जानी चाहिए, उसकी वित्त-व्यवस्था निजी साधनों-स्रोतों से करने में ये अल्प-विकसित देश असमर्थ हैं। यद्यपि इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल है कि कुल कितने मूल्य की मदद इन देशों को मिली है, पर १९५८-५९ में सहायता प्रदाताओं द्वारा दी गई मदद ५० करोड़ पौंडों से अधिक कूती गई थी और यह भी विदित है कि कोलम्बो योजना के समारम्भ से लेकर २,१४,००,००,००० पौंड मूल्य की सहायता पहुँचाई जा चुकी है।

१९५९ की मध्यावधि तक, कोलम्बो योजना सम्बद्ध देशों में निजी स्रोतों द्वारा किये गये विनियोगों के अतिरिक्त, विविध योजनाओं के लिए १५,००,००,००० पौंडों की सार्वजनिक राशि निर्धारित की जा चुकी थी। विशेष ज्ञाताओं की संख्या तीन सौ अट्ठावन थी और ब्रिटेन में विविध प्रकार के प्रशिक्षण ग्रहण करने के लिए आये लोगों की संख्या तीन हजार थी।

—राव मेन्सफील्ड

विचारणीय प्रश्न

इंगलैंड के एक प्रसिद्ध औद्योगिक संस्था मनी लेबर है, इसने गत १० वर्षों में ३३७० लाख पौंड अपनी स्थिर सम्पत्ति में तथा १७६० लाख पौंड अपनी कार्यशील पूंजी में लगाए हैं, इसका धन ब्रिटेन, युरोप के अनेक देश, अमरीका अफ्रीका और एशिया में लगा हुआ है। इसके भूतपूर्व अध्यक्ष लोर्ड हेवर्थ ने अपने एक भाषण में बताया है कि वे रुपया लगाने से पूर्व निम्न प्रश्नों पर विचार करते हैं।

—क्या जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है?

—क्या लोगों का जीवन-स्तर बढ़ रहा है?

—क्या हमारे मार्ग में नये प्रतिस्पर्धी तो नहीं खड़े हो गए हैं?

—क्या कारखाना बनाने के लिए हमें सामग्री, काम करने के लिए मजदूर, सामान ले जाने वाले के लिए यातायात के साधन मिल सकते हैं?

और—क्या हमें कच्चा माल उपलब्ध हो सकता है? क्या देश की सरकार अस्थायी है?

—सरकार की विदेशी पूंजी के बारे में क्या राय है?

—क्या हम कुछ लाभ भी कमा सकते हैं?

विदेशों को सहायता

संयुक्तराष्ट्र-संघ ने एक सूची निम्नलिखित प्रकाशित की है, जिसमें संयुक्तराष्ट्र संघ के नए टैक्निकल सहायता कार्यक्रम और विशेष कोष में १ जून, १९६० तक चन्दा देने वाले सदस्य राष्ट्रों के नाम प्रकाशित किए गए हैं। इसी सूची के अनुसार कनाडा, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, भारत, नीदरलैंड्स, स्वीडन, इंगलैण्ड और अमेरिका इन सभी गैर साम्यवादी देशों ने सोवियत रूस की तुलना में कहीं अधिक धन राशि देने का वचन दिया है।

—भाखड़ा बाँध, जिसकी नींव से औसत ऊंचाई इस समय ४५० फुट है, इस वर्ष सतलज नदी की बाढ़ से अप्रभावित रहेगा। पिछले वर्ष से बाँध अब किनारों पर १०० फुट से अधिक और बीच में १८ फुट और ऊंचा हो गया है। इस वर्ष बिजली तैयार करने के लिए सहाय निर्माण-कार्य में विशेष प्रगति हुई है। दायीं ओर की सुरंग को पूरी तरह बन्द कर दिया गया है।

—भारत से १९५९ में करीब ५ करोड़ रुपए के गलीचे दरी आदि विदेशों में गए। गत वर्ष से ३३ लाख रुपए के कालीन अधिक गए। यदि आस्ट्रेलिया, सिंगापुर कुवैत, न्यूजीलैंड आदि देशों में माल कुछ कम गया तो अमरीका, कनाडा, आदि ने पहले से ज्यादा माल मंगाकर यह कमी पूरी कर दी।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	टैक्निकल सहायता कार्यक्रम		विशेष कोष	
१. कनाडा	२०,००,५००	डालर	२०,००,०००	डालर
२. प० जर्मनी	१४,२८,५७१	,,	११,०४,७६२	,,
३. भारत	७,५०,०००	,,	१७,५०,०००	,,
४. फ्रांस	१५,४३,७८०	,,	१०,७२,०६७	,,
५. नीदरलैंड्स	१३,२३,०५२	,,	२४,४० १०५	,,
६. स्वीडन	९,०२,७६४	,,	२१,०३,२२८	,,
७. इंगलैण्ड	३०,००,०००	,,	५०,००,०००	,,
८. अमेरिका	१,४०,२२,६५९	,,	१,५०,३६,०७०	,,
९. रूस	१०,००,०००	,,	१०,००,०००	,,

अमेरिका ने यह इच्छा भी प्रकट की है कि अन्य देशों द्वारा संयुक्तराष्ट्र-संघीय टैक्निकल सहायता और विशेष कोष में वृद्धि करने पर वह ४ करोड़ डालर की अतिरिक्त धन राशि चन्दे के रूप में देने के लिए तैयार है।

हिन्दुस्तान लीवर का अनुभव

हिन्दुस्तान लीवर के अध्यक्ष श्री एम० एच० टर्नर ने अपने एक भाषण में बताया कि १९५० में कम्पनी का ज्यादातर माल रेलों से जाता था, लेकिन अब ५० प्रतिशत माल ट्रकों से जाता है। इसका एक बड़ा लाभ यह हुआ है कि पहले एक माल के दूसरी जगह तक पहुँचने में पहले २१ दिन लगते थे, जबकि अब केवल ५ दिन लगते हैं। इससे पहले हमारा यह अनुभव रहा है कि कई-कई दिन तक रेल को माल गाड़ी के डिब्बे ही नहीं मिलते थे और कई बार एक ही दिन में १६-१६ मील जाते थे। इसलिए हमें अपने ग्राहक व्यापारियों का बहुत-सा रुपया काफी समय पहले जमा करना पड़ता था और व्यापारी को भी ४-५ महीने की आवश्यकता पूरी करने योग्य माल अपने गोदाम में रखना पड़ता था और अब माल सड़क परिवहन से बहुत कम समय में गांव-गांव और घर-घर पहुँच जाता है। पहले स्टेशन से माल लाने का खर्च व्यापारी को देना पड़ता था। रेलवे के अधिकारी माल के नुकसान की जिम्मेदावारी नहीं लेती थी अब सड़क परिवहन कम्पनियां इस जिम्मेदारी को उठाती हैं। जब रेलवे अधिकारी किसी क्षतिपूर्ति की रकम चुकाने में महीनों लगा देते थे, अब सड़क परिवहन के अधिकारी एकदम चुकाते हैं, और वह भी बिना किसी हिलो-हुज्जत के। ● ●

सबसे सस्ता और सुन्दर सचित्र मासिक

जागृति

संस्थापित १९४८

जिसे राष्ट्र भाषा के प्रायः सभी प्रमुख लेखकों, कवियों और कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है। चार कहानियां, एक एकांकी, ६ लेख

तिरंगा आवरण अनेकों इक रंगे चित्र

५२ से ६४ पृष्ठ की सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर

इस पर भी मूल्य केवल २५ नए पैसे

एजेन्टों को ५ से १०० प्रतियों पर २५ प्रतिशत और इससे ज्यादा पर ३३⅓ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। डाक खर्च प्रकाशकों के जिम्मे। नमूने की प्रति के लिए आज ही लिखें :

व्यवस्थापक, 'जागृति' कार्यालय, लोक सम्पर्क विभाग, पंजाब, चंडीगढ़

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनैतिक अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र

आर्थिक समीक्षा

प्रधान सम्पादक : श्री सादिकअली

सम्पादक : श्री सुनील गुह

- हिन्दी में अनूठा प्रयास
- आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विषयों पर विचारपूर्ण लेख
- आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत

भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक।

वार्षिक मूल्य : ५) रु०   एक प्रति २२ नये पैसे

लिखें—व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी,

७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

राजधानियों पर अपव्यय

सिद्धराज ढड्ढा

•

योजना के अनुसार भोपाल पौने दो करोड़ रुपए की लागत से राज्य-सरकार के सचिवालय के लिए और उनके दफ्तरों के लिए मकान बनाए जाएंगे और ४ करोड़ रुपए राज्य के कर्मचारियों के रहने के मकानों पर खर्च होंगे। एक करोड़ रुपया बिजली और पानी की सुविधाओं पर खर्च होगा और करीब २७ लाख रुपए सिर्फ राजधानी की सड़कों पर लगेंगे। विधान-सभा के लिए नया भवन बनाने की योजना है, जिसमें सब 'नये से नए ढंग की सुविधाएं' होंगी। इसकी लागत करीब ३२ लाख रुपए होगी। यों कुल मिलाकर इस नयी राजाधनी पर सवा तेरह करोड़ रुपए खर्च होगा।

इसी तरह अभी गुजरात की नई राजधानी के लिए १० करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई है। पंजाब में भी नई राजधानी बनी है, जिसका नकशा फ्रांस के एक प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री ने बनाया था और जिसकी छटा आज देखते ही बनती है।

विदेशी लोग हिन्दुस्तान की शान-शौकत से प्रभावित हों और यह न समझें कि यह मुल्क पिछड़ा हुआ है, इसलिए दिल्ली में ढाई तीन करोड़ रुपयों की लागत से अद्यतन सुविधाओं वाला 'अशोक होटल' बनाया गया, जिसको चलाते रहने के लिए भी लाखों रुपया खर्च करना ही पड़ता है और अभी-अभी बम्बई, कलकत्ता व दिल्ली में ४० लाख रुपए खर्च करके विदेशी विद्यार्थियों के लिए तीन नए छात्रावास बनाए जा रहे हैं। नए कामों के लिए नए सिरे से कुछ न बनाया जाए या खर्च न किया जाए, यह हमारा मतलब हरगिज नहीं है। हम कहना यही चाहते हैं कि इस सारे काम और खर्च का देश की परिस्थिति और हालत के साथ कुछ मेल होना चाहिए। देश में अधिकांश लोग गरीब हैं। उन्हें और सुविधाओं की बात तो दूर, दोनों वक्त पेटभर और स्वास्थ्यकर संतुलित भोजन भी नहीं मिलता है। पर्याप्त कपड़ा सर्दी-गर्मी-बरसात से बचने लायक घर, बीमारी में इलाज का और बच्चों के लिए तालीम का इन्तजाम, बावजूद इन सारी 'योजनाओं' के आज भी उनके लिए एक सपना है। ऐसे करोड़ों लोगों को जब हम न खाकर कल के लिए बचाने का उपदेश देते हैं, और १०-२० बरस इन्तजार करने को कहते हैं, तो क्या इन करोड़ों लोगों के 'प्रतिनिधियों' और 'सेवकों' के लिए नए-नए महल खड़े करने का, नई-से-नई अद्यतन सुविधाएं देने का, बिजली, पानी, सड़क, सिनेमा, बाग-बगीचे इन सबका इन्तजाम करने का काम थोड़े साधारण पैमाने पर नहीं हो सकता ? या कि १०-२० बरस के लिए मुल्तवी नहीं किया जा सकता ?

हमारे ख्याल से बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए शायद वह समय आ गया है जब हड़ताल-जैसी चीज की इष्टानिष्टता पर व्यापक समाज-हित की दृष्टि से पुनः विचार किया जाना चाहिए। मशीन-युग की शुरुआत में, जब पूंजीपतियों द्वारा मजदूर का शोषण अपनी चरम सीमा पर था और मजदूर की रक्षा के लिए शासन द्वारा हस्तक्षेप का विचार इतना मान्य नहीं हुआ था, उस परिस्थिति में मजदूर के पास हड़ताल के सिवाय अपने बचाव का दूसरा कोई साधन नहीं था। आज जबकि कारखाने द्वारा मन-माना मुनाफा करने के तत्व (लैसे-फेयर) की मान्यता कायम नहीं रही है और प्रबुद्ध जनमत सामाजिक अन्याय और शोषण के खिलाफ काफी हद तक संगठित हुआ है, जिसके असर के कारण शासन की जिम्मेदारी की कल्पना में भी परिवर्तन हुआ है, ऐसी स्थिति में हड़ताल ही मजदूर के लिए एक-मात्र उपाय हो, सो बात नहीं है। इसके अलावा, १००-५० वर्ष पहले की और आज की परिस्थिति में एक और दूसरा बड़ा अन्तर यह हुआ है कि उस जमाने में जनता का दैनिक जीवन बहुत हद तक उसके अपने हाथ में था और कभी-कभी या कहीं-कहीं होने वाली कारखानों की हड़तालों से उसके रोजमर्रा के जीवन पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता था। लेकिन आज जनता का सारा जीवन केन्द्रित उद्योगों और यातायात आदि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में हड़ताल के हथियार का उपयोग केवल सम्बन्धित 'मालिक' पर ही

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

असर डालता है, सो नहीं, बल्कि वह समूचे जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर देता है। झगड़ा समाज के ऐसे दो तबकों में होता है, जो संख्या की दृष्टि से समाज का एक नगण्य-सा हिस्सा है, पर उसका खमियाजा, उसका फल, सारे समाज को भोगना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि चन्द संगठित मजदूर अपने संगठन बल पर कभी-कभी तो झगड़े करके भी अपनी मांगें मनवा लेते हैं। हमने ऊपर कहा है कि जब तक समाज में मालिक-मजदूर का रिश्ता कायम है, तब तक मजदूर के इस अधिकार में कुछ औचित्य जरूर है। इसलिए इस परिस्थिति का असली इलाज तो यही है कि समाज-व्यवस्था में ऐसा बुनियादी परिवर्तन हो कि मालिक और मजदूर का सम्बन्ध खतम होकर एक ऐसा स्वाश्रयी समाज का निर्माण हो, जिसमें लोग आम तौर पर अपने जीवन के खुद मालिक हों। पर जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक भी, ऊपर जिन बदली हुई परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए, हड़तालों के औचित्य पर पुनर्विचार करना जरूरी है। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उद्योगों में या सेवा कार्यों (सर्विसेज) में काम कर रहे लोगों के संबंध में तो यह प्रश्न और भी विचारणीय बन जाता है। सरकार में और व्यक्तिगत मालिक में फर्क है ही, खासकर जब सरकार लोगों के वोट पर आधारित हो और जनतंत्रीय व्यवस्था के अनुसार चलती हो। खुद जनतंत्रीय व्यवस्था में कोई दोष हो, तो वह प्रश्न स्वतंत्र रूप से विचारणीय है।

तो एक तरफ, जब कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों में मनुष्य उत्तरोत्तर परिष्कृत और विकसित साधनों का उपयोग करने की ओर बढ़ रहा है तब कोई वजह नहीं है कि मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए हम हड़ताल-जैसे 'क्रूड' यानी अविकसित भोंडे हथियार को काम में लाते रहें। आज की परिस्थिति में हड़ताल एक समाज-विरोधी चीज हो गई है। हम जानते हैं कि जब हड़तालें होती हैं, तो मामला सिर्फ दोनों संबंधित पक्षों के बीच तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सारे समाज पर उसकी प्रतिक्रिया होती है, और शांति-भंग होने का खतरा भी पैदा हो जाता है। ● ०

4th - 11th SEPTEMBER 1960

LEIPZIG TRADE FAIR

International Display of Consumer Goods of Every Kind

Exhibits from 45 different countries for comparison

An ever growing volume of East-West Trade

Direct flights · Reduced fares by train over the continent
Literature from all leading travel agencies

For details contact:

LEIPZIG FAIR AGENCY
P.O. Box No. 1993, BOMBAY 1
D-17, Nizamuddin East, NEW DELHI 13
34-A, Brabourne Road, CALCUTTA 1.
"Lomond", 46, Harrington Road, MADRAS 31

Further information and free advice on sources of supply from:

Leipziger Messeamt
Hainstr. 18 a · Leipzig C 1
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

बैंक-बीमा

राज्य सरकारों के ऋण

भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों ने हाल ही में कुल ७५ करोड़ नए ऋण लेने की घोषणा की है। इन पर ४ प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अभी तक इतनी बड़ी राशि राज्यों ने ऋण के रूप में नहीं ली थी। मद्रास ने गत वर्ष ८ करोड़ रुपए का ऋण लिया। अब वह १२ करोड़ रुपए ले रहा है। गत वर्ष बम्बई ने (महाराष्ट्र-गुजरात मिलाकर ६ करोड़ रुपए का ऋण लिया था) अब महाराष्ट्र ने १० करोड़ और गुजरात ने ५ करोड़ रुपये ऋण लेने का निश्चय किया है। निम्नलिखित तालिका से यह मालूम होगा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकारों ने कितना-कितना ऋण लिया है।

सरकार ने कितने सार्वजनिक ऋण पिछले दस वर्षों में लिए हैं और विभिन्न वर्षों में सार्वजनिक ऋण की स्थिति क्या रही, यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

(करोड़ रु० में)

	राज्यों की संख्या	विज्ञापित ऋण राशि	प्राप्त राशि
१९५६	१५	६४	७४.२३
१९५७	२	९	१२.५२
१९५८	११	५०	६५.८४
१९५९	१२	६१.५	१०२.२७
१९६०	१२	७५	—

वित्तीय क्षेत्रों का यह अनुमान है कि इस वर्ष बैंकों में रुपए की कुछ कमी होने के कारण पहले की अपेक्षा कुछ कम ऋण सरकार को मिल सकेगा।

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आन्तरिक ऋण	विदेशों से ऋण	कुल
१९४९	२१२५	७ (०.३३)	२१३२
१९५०	२१८३	२३ (१.०४)	२२०६
१९५१	२२३३	२९ (१.२८)	२२६२
१९५२	२२१४	११६ (४.९८)	२३३०
१९५३	२२४५	११८ (४.९९)	२३६३
१९५४	२३१०	११६ (४.७८)	२४२६
१९५५	२६६६	११५ (४.१४)	२७८१
१९५६	२९४२	११८ (३.८६)	३०६०
१९५७	३३३८	१४० (४.०३)	३४७८
१९५८	३७९०	१९० (४.७७)	३९८०
१९५९	४४१०	३७१ (७.७६)	४७८२

जीवन बीमा निगम की सफलता

जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्णन् के अध्यक्षीय भाषण से मालूम होता है कि बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण से जो आशंकाएं प्रकट की गई थी, वे क्रमशः कम होती जा रही हैं। १९५८ में ३४५ करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। १९५९ में ४२९ करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, अर्थात् २५% अधिक, १९५८ में भी १९५७ अपेक्षा २२% कारोबार अधिक हुआ था। जीवन बीमा निगम का लक्ष्य यह है कि १९६३ तक एक हजार करोड़ रुपए का कारोबार होने लगे। जो बीमा पालिसियाँ बीच में ही बन्द हो जाती थीं, उनकी संख्या भी निरन्तर कम हो रही है। १९५६ में ९.१% पॉलिसियाँ बीच में बन्द हो गई थीं। १९५७ में ६.४ और १९५८ में ५.१ प्रतिशत रह गई। पुनर्नवीकरण के व्यय भी क्रमशः कम हो रहे हैं। १९५६-५७ में यह व्यय १५.४६ प्रतिशत था १९५८ में गिरकर १२.९२ रह गया। राष्ट्रीयकरण से पूर्व अच्छी कम्पनियों का व्यय भी इससे अधिक था। जीवन-कोष में भी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीयकरण के समय यह कोष ३८० करोड़ रुपए का था जबकि १९५९ के अन्त में ४९३ करोड़ रुपए का हो गया। बीमेदारों के दावों का भुगतान भी अब तेजी से होने लगा है। अध्यक्ष के भाषण से यह मालूम होता है कि ऐजेन्टों और क्षेत्रीय अधिकारियों के कारोबार में वृद्धि हो रही है, एक फील्ड अफसर की देख-रेख में १९५७ में ४ लाख ९० हजार रुपए का कारोबार हुआ था तो १९५९ में ७॥ लाख का। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तीसरी योजना कैसे सफल हो

अर्थशास्त्री

तीसरी पंच वर्षीय योजना की सफलता दो बातों पर निर्भर है—

१. जीवनोपयोगी आवश्यक पदार्थों के मूल्य में स्थिरता रहे और उनमें किसी तरह की वृद्धि न हो।

२. जनसंख्या में कम से कम वृद्धि हो।

३. जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है इसकी जानकारी का होना किसी भी योजना के निर्माण के लिए आवश्यक है। जब तक हमें यह मालूम न हो, कि कितने मुखों को भोजन देना है, कितने शरीरों को कपड़े पहनाने है, कितने प्राणियों के लिए मकान बनाने है अथवा अन्य आवश्यकताएँ पूरी करनी है, तब तक हम किसी भी योजना में विभिन्न उत्पादनों के लक्ष्य नियत नहीं कर सकते।

योजना आयोग ने विशेषज्ञों के लिए एक समिति नियुक्त की थी, जो भिन्न-भिन्न राज्यों की जनसंख्या आदि के बारे में निश्चित अनुमान करें। इस कमेटी की रिपोर्ट पर योजना कमीशन ने भी विचार किया। यह कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जन्म संख्या में कोई विशेष अन्तर नही पड़ा है, किन्तु मृत्यु संख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा आदि में उन्नति के कारण मृत्यु संख्या अवश्य कम हो गई, इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात बढ़ता जा रहा है।

विशेषज्ञों की कमेटी ने अपनी जांच के लिए जो आधार लिए हैं, वे पूर्णतः शुद्ध भी हों, इसका निश्चय नहीं है; क्योंकि अभी तक जन्म-मृत्यु के ठीक-ठीक विवरण सब जगह नहीं रखे जाते। फिर भी इस समिति ने कुछ एक स्थानों की रिपोर्ट को नमूने के तौर पर स्वीकार किया है।

नेशनल सैम्पल सर्वे के प्रयत्न इस सम्बन्ध में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं। समिति ने तीन वर्षों के सम्बन्ध में कल्पनाएँ की हैं। १९५६-१९६१ और १९६६। १९६६ के बाद के लिए कोई कल्पना करना अभी उचित और सम्भव नहीं होगा। अपनी कल्पनाओं के लिए समिति ने निम्नलिखित विचारों को आधार बनाया है—

१. १९५१ की जनसंख्या, जिसमें एक और दो वर्ष के लिए बच्चों की संख्याओं को भावी अनुमानों के लिए स्वीकार किया है।

२. ४२ प्रति हजार के जन्म-अनुपात को जो १९५१ की जनसंख्या से पुष्ट होता है, भविष्य के लिए स्वीकार कर लिया है।

३. मृत्यु संख्या में निरन्तर कमी हो रही है और यह स्वीकार कर लिया गया है कि १९४६ में यदि औसत आयु ३२ थी तो १९६६ तक औसत आयु ५० हो जायगी अर्थात् प्रतिवर्ष ०.९ की वृद्धि होगी।

४. संयुक्त राष्ट्र संघ ने जीवन तालिका में जो मृत्यु का अनुपात दिया है, उसे भी उप-समिति ने मान लिया है

५. भिन्न-भिन्न राज्यों की स्त्री और पुरुष तथा विभिन्न आयु की तालिकाओं को भी समिति ने अपने सामने रखा है। १९६६ के बाद के अनुमान के सम्बन्ध में समिति ने इसलिए विचार नहीं किया कि आज चलाए जा रहे सन्तति निरोध आन्दोलन के प्रभाव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह ख्याल अवश्य किया गया है कि गर्भ धारण में शनैः शनैः कमी होती जायगी। अपने परिणामों पर पहुँचने के लिए भिन्न-भिन्न आयु के स्त्री और पुरुषों की गणना भी नमूने के तौर पर ली है। यह भी मान लिया गया है कि भारत में विदेशों से लोगों का अधिक आना जाना नहीं होगा।

मृत्यु संख्या निरन्तर कम हो रही है, इसके कुछ उदाहरण देना ठीक होगा। १९५१ की जनगणना के अधिकारी ने २७.४ प्रति हजार मृत्यु संख्या का अनुमान किया था। पंजाब और मदरास में, जहाँ जन्म-मृत्यु का विवरण अधिक ठीक रखा जाता है, मृत्यु संख्या में पर्याप्त कमी हुई है। दोनों राज्यों में क्रमशः यह अनुपात १६.५ से १३.८ तक और १५.८ से १४.२ तक गिर गया है। मलेरिया नियंत्रण के विविध उपाय, बी० सी० जी० के टीके, भोजन का अधिक अच्छा वितरण और चिकित्सा की अधिक सुविधाओं के कारण यह मृत्यु संख्या कम हुई है। बिहार, मध्यप्रदेश और पश्चिमी बंगाल में मलेरिया इन्स्टीट्यूट के अनुसार

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

तिल्ली और बुखार के बीमारों की संख्या क्रमशः ४६.१ ३४.७ और २०.४ से गिरकर ११.२, ८.७, और ४.० तक पहुंच गई है। ये दोनों संख्याएं क्रमशः १९५३-५४ और १९५६-५७ के हैं। भारत की सीमा पर स्थित लंका में तो मलेरिया निरोधक उपायों से यह संख्या २० से ११ तक गिर गई है। इसलिए उस समिति ने भी अपनी कल्पना करते हुए इस विशेष महत्व दिया है।

गणना करके यह भी अनुमान किया गया है कि १५ और १९ साल की उम्र में लड़कियां कम गर्भधारण करेंगी। किन्तु २० से २४ साल में यह स्तर बढ़ जाता है, जो ३५ से ३९ साल तक रहता है और उसके बाद बहुत कम हो जाता है। पश्चिमी देशों में यह क्रम विपरीत होता है। वहां १५-१९ वर्ष में अधिक गर्भ धारण होता है और पीछे कम हो जाता है। अभी तक सन्ततिनिरोध आन्दोलन कुछ शहरों और शिक्षित वर्ग में चल रहा है।

समिति ने प्रत्येक पांच वर्ष के लिए अलग-अलग तालिकाएं बनाई हैं। यह भी ध्यान रखा है कि औसत आयु क्रमशः बढ़ती जायगी और मृत्यु संख्या क्रमशः कम होती जायगी। भिन्न-भिन्न आयु में मृत्यु संख्या का अनुपात अलग-अलग होता है। पिछली जन-गणनाओं से यह भी मालूम होता है कि स्त्री-पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात १०० और १०५ है।

इन सब बातों का विचार करके समिति विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में एक परिणाम पर पहुँची है। ● ●

विभिन्न राज्यों की अनुमानित जन-संख्या

राज्य	१९५६	१९५९	१९६१	१९६६	१९७१
१. आन्ध्र प्रदेश	३३.८१	३५.८५	३७.२१	४१.४३	४५.६१
२. आसाम	९.८८	१०.५३	१०.९६	१२.३४	१३.६४
३. बिहार	४१.३८	४३.५५	४४.९९	४२.६२	५३.८८
४. बम्बई	५३.१२	५६.८५	५९.३४	६६.८३	७४.७६
५. केरल	१५.१७	१६.३६	१७.१६	१९.४९	२२.०७
६. मध्यप्रदेश	२७.६४	२८.९८	२९.८६	३२.८३	३५.४१
७. मद्रास	३२.५८	३४.६२	३५.९८	४०.१६	४४.३५
८. मैसूर	२१.५४	२३.०४	२४.०४	२७.२४	३०.५१
९. उड़ीसा	१५.३६	१६.०६	१६.५३	१८.०२	१९.३४
१०. पंजाब	१७.७६	१८.९८	१९.८०	२२.२३	२४.८४
११. राजस्थान	१७.५६	१८.८०	१९.६३	२२.०४	२४.६३
१२. उत्तर प्रदेश	६७.८२	७१.६९	७४.२६	८२.३०	८९.९६
१३. पश्चिमी बंगाल	२७.६४	२८.८७	२९.६९	३२.४०	३४.७३
१४. दिल्ली	२.१२	२.३५	२.५१	२.९८	३.४३
१५. हिमाचल प्रदेश	१.१२	१.१४	१.१६	१.२४	१.३२
१६. मनीपुर	०.६२	०.६६	०.६८	०.७६	० ८४
१७. त्रिपुरा	०.६६	०.७०	०.७२	०.८०	०.८९
१८. सिक्किम	०.१५४	०.१६	०.१६९	०.१९०	०.२०९
१९. अंडमान निकोबार द्वीप	०.०४३	०.०४७	०.०५१	०.०५६	०.०६१
२०. लकादिव मिनीकोई आमिन डिवी द्वीप	०.०३९	०.०४१	००.४२	०.०५०	०.०५२
२१. जम्मू-कश्मीर	४.७८	५.१०	५.३१	५.८५	६.४५
२२. आसाम के आदिम जाति क्षेत्र	०.६२	०.६४	०.६९	०.७५	०.८४
योग	३९१.४	४१५.०	४३०.८	४७९.६	५२७.८

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भारत के प्रमुख सार्वजनिक उद्योग

श्रीकृष्ण ईनाणी

गत वर्षों में भारत तीव्रगति से औद्योगिकरण की ओर बढ़ा है और हमने इस दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। निजी उद्योगों के साथ-साथ सरकार ने भी बड़े स्तर पर कई उद्योगों को आरम्भ करके राष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया है। यहां ऐसे ही कुछ सरकारी अर्थात् सार्वजनिक उद्योगों की प्रगति और समस्याओं के बारे में विचार किया जाता है।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रासायनिक खाद की आवश्यकता को पूरा करने के हेतु बिहार में धनाबाद से १५ मील दूर सिन्दरी नामक स्थान पर २३ करोड़ रुपये की लागत के सिन्दरी उर्वरक कारखाना की आधार शिला रखी। १६ जनवरी १९५२ को इसे "सिन्दरी फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल (प्रा०) लि०" कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया और २ मार्च १९५२ को इसका उद्घाटन किया गया।

सम्पूर्ण कारखाना ५ भागों में बंटा हुआ है :

(१) पावर प्लाण्ट (२) गैस प्लाण्ट
(३) अमोनिया प्लाण्ट (४) सलफेट प्लाण्ट
(५) नया कोक ओवन प्लाण्ट।

पहला पावर प्लाण्ट, जो ८० हजार किलोवाट शक्ति का है, फैक्टरी को बिजली देता है। गैस प्लाण्ट गैस मिक्सर बनाता है। इसमें ४४० लाख क्यूबिक फुट गैस प्रतिदिन बनती है। तीसरे प्लाण्ट में गैस कारबन डाई आक्साइड से मुक्त की जाती हैं। यह प्लाण्ट प्रतिदिन २७० टन अमोनिया बनाता है। सलफेट प्लाण्ट में जिप्सम और अमोनियम कारबोनेट के घोल में रासायनिक पदार्थ मिलाकर अमोनियम सलफेट बनाया जाता है। कोक ओवन प्लाण्ट प्रतिदिन ६०० टन कोक बनाता है।

सिन्दरी खाद कारखाने पर प्रथम व द्वितीय योजना में क्रमशः २८ व ७ करोड़ रुपये व्यय किये गये। योजना आयोग ने इसके निम्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये थे :

१९५५-५६ उत्पादन		१९६०-६१ उत्पादन	
क्षमता	वास्तविक	क्षमता	वास्तविक
७० हजार टन नाइट्रोजन	६६ हजार टन नाइट्रोजन	११७ लाख नाइट्रोजन	११७ लाख नाइट्रोजन

जबकि उत्पादन निम्न रहा :

	अमोनिया सलफेट (लाख टन)
१९५२	१.७२
१९५३	२.६५
१९५४	२.७८
१९५५	३.२१
१९५६	३.३३

इससे प्रतिवर्ष ४० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई तथा २३ हजार टन अतिरिक्त अन्न (मूल्य ६५ करोड़ रुपये) का उत्पादन हुआ।

इस समय इसके विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कोक ओवन प्लाण्ट से अधिक गैस बनाकर ६०% उत्पादन बढ़ाने की योजना है। आशा है वह इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जायगी, जिससे प्रतिदिन ७० टन युरिया तथा ४०० टन अमोनिया सलफेट नाइट्रेट बनेगा।

नांगल उर्वरक कारखाना

फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने नांगल नामक स्थान पर एक उर्वरक कारखाना बनाया है, जिसे २० अप्रैल १९५६ को मैसर्स नांगल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल लि० को नियमित रूप से अन्तरित कर दिया है। इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी ३० करोड़ रुपये है। यह कारखाना होशियारपुर के दक्षिण-पश्चिम में सतलज नदी के पश्चिमी तट पर बांध के नीचे की ओर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर २२ करोड़ रुपया व्यय होगा। १९६०-६१ तक इसकी उत्पादन

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

क्षमता ७० हजार टन तथा वास्तविक उत्पादन ४० हजार टन है।

रूरकेला फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट

यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुरकेला नामक स्थान पर बनाया जा रहा है, जिस पर ८ करोड़ रुपया व्यय होगा तथा जिसकी उत्पादन क्षमता व वास्तविक उत्पादन १९६०-६१ तक क्रमशः ८० व ७० हजार टन होंगे।

नवेली प्रोजेक्ट

यह दक्षिणी भारत में लिगनाइट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इसमें २१ करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत का एक संयंत्र लगाया जायेगा, जो १९६१ के मध्य तक उत्पादन कार्य करेगा। यह ७० हजार टन सलफेट नाइट्रेट और यूरीया खाद बनायेगा।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

द्वितीय महायुद्ध के बाद बढ़ते हुए आवागमन को देखते हुए भारत सरकार ने चांदमारी नामक स्थान पर इन्जिनों का कारखाना खोलने का निश्चय किया, किन्तु विभाजन के बाद यह आवश्यक समझा गया कि इस स्थान को न चुनकर मिही जान को चुना जाय, क्योंकि चांदमारी पाकिस्तान की सीमा के बहुत निकट था और सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। इसी स्थान पर १९४८ में एक एन्जिन कारखाने की स्थापना की गई, जिसका नाम "चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स" रखा गया। इस कारखाने की लागत १५ करोड़ रुपया है। यहां से १९५० में पहला एन्जिन बनकर निकला। यहां १६८ डब्ल्यू० जी० एन्जिन बनते हैं, जो बड़ी लाइनों पर माल ले जाने वाली मालगाड़ियों में प्रयुक्त किये जाते हैं। ये ७८. फुट लम्बे तथा १२४ मन भारी होते हैं। आरम्भ में प्रति एन्जिन लागत व्यय ७.५ लाख रुपये थी, लेकिन अब ५ लाख रुपये ही है।

प्रथम योजना में इसमें १४.६ करोड़ रुपया विनियोग किया गया। १९५५-५६ में इसकी उत्पादन क्षमता १२० इंजन आंकी गई, जबकि वास्तविक-उत्पादन निम्न रहा :

	प्रथम योजना	
	लक्ष्य	वास्तविक
१९५१-५२	२०	१७
१९५२-५३	३२	३३
१९५३-५४	५२	६४
१९५४-५५	७२	९८
१९५५-५६	९२	१२९

द्वितीय योजना के अन्त तक इस पर ५ करोड़ रुपया व्यय होगा तथा प्रतिवर्ष ३०० इंजन बनने लगेंगे।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड

मार्च १९५२ में विशाखापट्टम शिपयार्ड को सिन्धिया शिप नेवीगेशन कं० से भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका प्रबन्ध हिन्दुस्तान शिपयार्ड (प्रा०) लि० को सौंप दिया, जिसकी कुल पूंजी ४५.२७५ लाख रुपये है, जिसमें ३४८.५० लाख रुपये सरकार तथा शेष १०४.२५ लाख रुपये के सिंधिया के अंश हैं। इस कम्पनी द्वारा ४ नये डीजल एन्जिन प्रतिवर्ष बनाये जाते हैं। १९५२ में जबसे सरकार ने इस शिपयार्ड का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है, तब से इसके विकास में एक उल्लेखनीय बात यह हुई है कि इसमें मेअरफोर्म ढंग के जहाजों का निर्माण होने लगा है, जो डीजल इंजन से चलते हैं। ये जहाज पुराने 'जल टाइप' जहाजों से भिन्न हैं, जिन्हें पहले सिन्धिया कम्पनी बनाती थी। सरकार ने शिपयार्ड के विकास के पहले दौर के लिये १९६ लाख रुपये स्वीकृत किये थे। इसके १९५६ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा थी। २८ फरवरी १९५७ तक १२.९८७ लाख रुपये खर्च कर लिये थे। यार्ड के विकास के दूसरे चरण की योजना भी अब तैयार की जा चुकी है, जिसमें यार्ड के फ्रांसिसी प्राविधिक सलाहकार ए० सी० एल० की सहायता ली गई हैं। इसमें अब तक २३ जहाज बन चुके हैं तथा द्वितीय योजना के अन्त तक ९ जहाज और बनाये जायेंगे। प्रथम योजना में इस पर ६ करोड़ रुपया व्यय किया गया तथा वास्तविक उत्पादन ५० हजार जी. आर. टी. हुआ। दूसरी योजना में इस पर ९.८ करोड़ रुपया व्यय होने का प्रावधान रखा गया तथा उत्पादन ७५ हजार से ९० हजार जी. आर. टी. होगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

हिन्दुस्तान केबिल्स

डाक और तार विभाग की आवश्यकता को पूरा करने के लिये १९५२ में रूपनारायणपुर में हिन्दुस्तान केबिल्स (प्रा०) लि० की स्थापना की गई, जिसने १ सितम्बर १९५४ से उत्पादन चालू किया। प्रथम योजना में इस पर १.६ करोड़ रुपया व्यय हुआ तथा द्वितीय योजना के अन्त तक ५० लाख रुपया और व्यय किया जायगा। प्रथम योजना में इसका लक्ष्य एक पाली चलाकर ४७० मील लम्बे केबिल बनाने का रक्खा गया था, जबकि १९५५-५६ में ५२५ मील लम्बे केबल बनाये गये। द्वितीय योजना में इसका लक्ष्य बढ़ाकर एक हजार मील लम्बे केबल तैयार करने का रक्खा गया है।

हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स

पेनिसिलिन फैक्ट्री की स्थापना भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र बालकोष तथा संयुक्तराष्ट्र प्राविधिक सहायता प्रशासन की प्राविधिक और वित्तीय सहायता से की है। भारत सरकार ने १.३० करोड़ की फैक्ट्री तथा अन्य भवनों के लिये भूमि और संचालन के लिये आवश्यक सेवाएँ प्रदान की, जबकि संयुक्तराष्ट्र बाल कोष और सं० रा० प्रा० सहायता प्रशासन ने क्रमशः ८.५० लाख पौंड की मशीनें, संयत्र और ३.५० लाख पौंड की प्राविधिक सहायता दी हैं। १ जून १९५४ से पैनिसिलिन फैक्टरी का प्रबन्ध हिन्दुस्तान एन्टी-बायोटिक्स (प्रा०) लि० को सौंप दिया है। यह पूर्णतया सरकारी कम्पनी है, जिसकी अधिकृत पूंजी ४ करोड़ रुपये है। प्रथम योजना में इस पर २.१ करोड़ रुपया व्यय किया गया तथा द्वितीय योजना में १ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया, जो बाद में ४ करोड़ कर दिया गया प्रथम योजना में इसका उत्पादन लक्ष्य ४८ लाख मेगा यूनिट हुआ, जो १९५६-५७ में बढ़कर १४१.२ लाख मेगा यूनिट हो गया।

इसमें बाइसिलीन बनाने के लिये भी एक अमरीकन फर्म से बातचीत चल रही है, जिसे कि इसका पेटेन्ट अधिकार है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

भारत में मशीनी औजारों की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भारत सरकार ने जलहाली (बंगलौर) में मशीनी औजारों के एक कारखाने की स्थापना के लिये ज्यूरिच स्थित ओरलीकन मशीन टूल्स वर्क्स-ब्यूहर्ले एण्ड कम्पनी नामक एक स्विस फर्म से २० साल का एक करार किया है। इसका प्रबन्ध एवं नियंत्रण १ मार्च १९५३ से बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्रा०) लि० को सौंप दिया है। बाद में सरकार ने स्विस कम्पनी से सारे अंश खरीद लिये हैं।

यह कारखाना ६० एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इससे भारतीय खरादों की पहली किस्त ३१ मई १९५६ को बनकर तैयार की गई। १९५७ में १४८ खरादें तैयार की गई। १९६०-६१ तक कारखाने का निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ८६५ मशीने बनानें का रखा गया है जो कि लगभग ३ करोड़ रुपये के होंगे। प्रथम व द्वितीय योजना में इस पर क्रमशः ४.४ तथा २ करोड़ रुपया व्यय किया गया।

हिन्दुस्तान इनसैक्टी साइट्स

यह कारखाना विश्व स्वास्थ्य संघ डब्ल्यू एच. ओ. तथा सं० रा० अन्तर्राष्ट्रीय आपतकालीन बाल कोष की शैल्पिक तथा वित्तीय सहायता से बनाया गया है। इन दोनों संस्थाओं ने क्रमशः १ लाख तथा १॥ लाख डालर दिये हैं। इस कारखाने ने २१ मार्च १९५५ से उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसमें प्रथम योजना के अन्त तक ७०० टन डी० डी० टी० बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक उत्पादन २८४ टन ही हुआ। १९६०-६१ तक इसकी उत्पादन क्षमता २८०० तथा वास्तविक उत्पादन २५०० टन रखा गया है। प्रथम व द्वितीय योजनाओं में इस पर क्रमशः ५० लाख व १ करोड़ रुपया व्यय किया गया।

इसके साथ ही इसी कम्पनी के अन्तर्गत केरल राज्य के अलवाय नामक स्थान में १४०० टन वार्षिक क्षमता का एक कारखाना खोलने की योजना है। इस पर ७६ लाख रुपये व्यय होगा और यह कारखाना इसी वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायगा।

इन्टग्रेल कोच फैक्टरी

अक्टूबर १९५५ को मद्रास के निकट पैराम्बुर नामक स्थान पर रेल के डिब्बे बनाने का उद्योग शुरू हुआ। ५२

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

एकड़ में फैले हुए इस कारखाने पर ७.३ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। १९५५-५६ में सिर्फ २० डिब्बे ही बनाये गये; लेकिन आशा है कि १९६०-६१ में यह ३५० डिब्बे प्रतिवर्ष बनाने लगेगा। यह अपने तरह का एशिया में एक ही कारखाना है। द्वितीय योजना के अन्त तक इसमें १० करोड़ रुपया व्यय होगा।

नेशनल इन्सट्रूमेन्ट फैक्टरी

यद्यपि यह फैक्टरी १८३० से ही यंत्रों की मरम्मत और अनुरक्षण करती रही है। लेकिन जून १९५७ में इसे निजी कम्पनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अब यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में उपयोग आने वाले वैज्ञानिक एवं शुद्ध माल यंत्रों का निर्माण करती है। प्रथम व द्वितीय योजना में इस पर क्रमशः ६० व ६५ लाख रुपए व्यय किये गये। १९५५-५६ में इसने १४.२ लाख रुपये के यंत्र बनाये थे। अब इसे जादवपुर में पुर्नसंगठित किया जा रहा है।

हैवी इलेक्ट्रिक

बिजली के संयत्रो तथा उपकरणों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने भोपाल में भारी विद्युत उपकरण बनाने के एक कारखाने की स्थापना का। इसके लिए ब्रिटेन की एसोसियेटेड इलेक्ट्रिक इन्डस्ट्रीज कम्पनी से १५ वर्ष का एक समझौता किया है। इसके लिए २९ अगस्त १९५६ की हैवी इलेक्ट्रिक (प्रा०) लि० नाम की एक कम्पनी स्थापित की, जिसकी अधिकृत पूंजी ३० करोड़ रुपया है, इसमें १९६१ से काम होना शुरू होगा, व १९६८ तक पूर्ण क्षमता से काम करने लगेगा। प्रथम योजना के अन्तर्गत इस पर सिर्फ २० लाख रुपया व्यय किया गया, जबकि द्वितीय योजना के अन्तर्गत कुल २० करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। कारखाने से जो उत्पादन होगा, उसमें १० करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

नाहन फाउण्ड्री

इसका आरंभ अक्तूबर १९५२ में किया गया और जनवरी १९५३ को इसका नियन्त्रण नाहन फाउण्ड्री को सौंप दिया गया। यहां खेती के औजार बनते हैं।

लोहे व इस्पात के कारखाने

द्वितीय योजना के अन्तर्गत भिलाई, रूरकेला व दुर्गापुर नामक स्थानों पर लोहे व इस्पात के तीन कारखाने खोले गए। ३० मार्च १९५७ को एक प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार ने तीनों कारखानों का प्रबन्ध एक कम्पनी "हिन्दुस्तान स्टील (प्रा०) लि०" को सौंप दिया है।

उड़ीसा में रूरकेला नामक स्थान पर एक कारखाना बनाया जा रहा है इसको स्थापित करने के लिए पश्चमी जर्मनी की क्रुप्स तथा डेमाग नाम की फर्मों से भारत सरकार ने दिसम्बर १९५३ में समझौता किया था। इस पर दूसरी योजना के अन्त तक १२८ करोड़ रुपया व्यय होगा तथा यहां ७.२ लाख टन इस्पात प्रति वर्ष बनेगा।

भिलाई में १० लाख टन पिण्ड बनाने वाला लोहा और इस्पात का एक कारखाना खोलने के लिए २ फरवरी १९५५ को सोवियत संघ से एक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार सोवियत संघ ५५ करोड़ की कीमत के मुख्य यंत्र और उपकरण तथा ८ करोड़ की कीमत के इस्पाती ढांचे देगा। इसके अलावा सोवियत संघ से शैल्पिक सहायता भी प्राप्त हुई है। इस कारखाने का निर्माण कार्य १९५६ में प्रारम्भ हो गया है और ३१ दिसम्बर १९५९ तक पूर्ण हो जाने की आशा है। द्वितीय योजना के अन्त तक इस पर ११० करोड़ रुपये व्यय होंगे।

दूसरी योजना के लक्ष्य (६० लाख टन) तक पहुंचने के लिए पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर नामक स्थान पर कोलम्बो योजना के अंतर्गत एक कारखाना ब्रिटिश शैल्पिक मिशन की सिफारिशों के आधार पर खोलने का निश्चय किया। इस्पात तथा तत्सम्बन्धी अन्य चीजें बनाने के लिए एक ब्रिटिश कम्पनी समूह—दी इण्डियन स्टील वर्क्स कन्सट्रक्स कं० से अक्तूबर १९५६ में एक समझौता हुआ। इस कारखाने की स्थापना में ८५ करोड़ रुपया व्यय होगा। इसकी पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार १॥ करोड़ पौंड तथा ब्रिटिश बैंकों का सिन्डीकेट १.१५ करोड़ पौंड देगा। यह कारखाना ऐसा होगा कि इसकी क्षमता बढ़ाकर १३ लाख टन इस्पात बनाने तक जा सके। द्वितीय योजना के अंत तक इस पर ११० करोड़ रुपया व्यय होगा तथा ७.९ लाख टन इस्पात उत्पादन होने लगेगा। यह अक्तूबर १९६० में अपना उत्पादन कार्य चालू करेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नया निर्माण

तीसरी योजना में खेती

तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित रूपरेखा में १६६५-६६ तक अनाज की पैदावार १०-१०॥ करोड़ टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार अगले ५ वर्षों में अनाज की उपज में ३५ से ४० प्रतिशत वृद्धि की जायगी, जबकि पिछले १० वर्षों में केवल १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए खेती को प्राथमिकता देना और अटल निश्चय के साथ काम करना जरूरी है। चीनी, तेल, सूती कपड़े आदि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी गन्ना, तेलहन और कपास का उत्पादन बढ़ाना परमावश्यक है।

गांव के कार्यक्रम में ये बातें होंगी—

(१) सिंचाई के साधनों का पूरा उपयोग किया जाए।

(२) खेतों में साल में एक से अधिक फसल बोयी जाए।

(३) गांवों में उत्तम बीज बोये जाएं और इन्हें खेती के लिए किसानों में बांटा जाए।

(४) उर्वरक सप्लाई किया जाए।

(५) हरी खाद और गड्ढे की खाद (कम्पोस्ट) मनाई जाए।

(६) खेती के सुधरे हुए तरीके अपनाए जाएं। जैसे—भूमि संरक्षण, मेंढ़ बांधने, बारानी खेती, पानी की निकासी, जमीन को सुधारने, फसल को कीड़े मकोड़ों से रक्षा करने आदि के तरीके।

(७) सिंचाई को छोटी योजनाएं बनायी जाएं।

(८) खेती के आधुनिक औजार काम में लाए जाएं।

(९) फल और तरकारी की पैदावार बढ़ायी जाए।

(१०) गाय-भैंस, मुर्गी और मछली-पालन के कार्यक्रम बनाए जाएं।

(११) किसानों को अच्छे और मजबूत बैल और सांड दिए जाएं। कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र खोले जाएं और बैलों को बधिया किया जाए।

(१२) गांव में चरागाह की व्यवस्था हो और ईंधन के लिए पेड़ आदि की रक्षा हो।

खेती की पैदावार बढ़ाने में ग्राम पंचायतों और गांव सहकारी समितियों का बहुत महत्व है, परन्तु विकास और विस्तार खण्डों के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। किसानों को ठीक समय पर अच्छे बीज, उर्वरक, अच्छे औजार, कीड़े मारने की दवाएं आदि देना उनका कर्तव्य है। किसानों की साधारण शिकायत है कि सरकार से बीज, उर्वरक आदि सामान समय से नहीं मिलते हैं। ये शिकायतें बहुत हद तक सही भी हैं। अतः यह आवश्यक है कि सरकारी मशीन को ठीक किया जाए अन्यथा ये योजनाएं अधूरी ही रह जाएंगी।

गांवों में धन बहाने से ही खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी। अवश्य ही किसानों को खेती के लिए बैंकों और सहकारी समितियों से थोड़े, मध्यम और लम्बे समय के कर्ज मिलने चाहिएं, परन्तु सरकारी प्रबन्ध को सुधारने से ही तीसरी योजना में देश को अन्न में स्वावलम्बी बनाया जा सकता है। सामुदायिक विकास विभाग ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वे ८० प्रतिशत समय और शक्ति इस उद्देश्य की पूर्ति में लगाएं।

देश के कोने-कोने में प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए हरेक उपाय करना जरूरी है। भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य के एक जिले में भरपूर खेती की आजमायशी योजना (पैकेज प्रोग्राम) चलाने का निश्चय किया है। इन योजनाओं पर कुल १५ करोड़ रु० खर्च होंगे। जिसमें से ३ करोड़ ४० हजार रु० फोर्ड फाउण्डेशन देगा, शेष रकम भारत सरकार और राज्य सरकारें देंगी।

खेती की पैदावार भारत की आर्थिक योजना की रीढ़ है। दृढ़ संकल्प, सरकारी प्रबन्ध में सुधार और

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ह मा रे उ द्यो ग

तीसरी योजना के लक्ष्य

बिजली : तीसरी योजना में बिजली उत्पादन की क्षमता दूसरी योजना की क्षमता ५८ लाख किलोवाट से बढ़कर १ करोड़ १८ लाख किलोवाट, अर्थात् दुगुनी हो जाएगी। बिजली का वास्तविक उत्पादन भी दुगुना हो जाएगा। अब १६ हजार शहरों और गांवों में बिजली है, जब कि तीसरी योजना में ३४ हजार शहरों और गांवों में बिजली हो जाएगी।

कोयला : कोयले का उत्पादन ५ करोड़ ३० लाख टन से बढ़कर ९ करोड़ ७० लाख टन हो जाएगा। खनिज लोहे का उत्पादन १ करोड़ २० लाख टन से ३ करोड़ २० लाख टन, अर्थात् १६७ प्रतिशत बढ़ जाएगा।

इस्पात : दूसरी योजना में २६ लाख टन तैयार इस्पात होने का अनुमान है। तीसरी योजना में ६९ लाख टन इस्पात तैयार होगा। दूसरी योजना का ४५ लाख टन का लक्ष्य तीसरी योजना के शुरू में पूरा होने की आशा है।

मशीनी औजार : साढ़े पांच करोड़ रु० के मशीनी औजारों के स्थान पर ३० करोड़ रु० के मशीनी औजार बनने लगेंगे। अर्थात् इनके उत्पादन में ४०० प्रतिशत की वृद्धि होगी।

साइकिल : साढ़े दस लाख साइकिलों की जगह २० लाख, अर्थात् लगभग दुगुनी साइकिलें बनने लगेंगी।

सूती कपड़ा : कपड़ा मिलों में ५०० करोड़ गज की जगह ५८० करोड़ गज सूती कपड़ा बनने लगेगा। हथकरघे और बिजली के करघों पर २६० करोड़ के स्थान पर ३५० करोड़ गज कपड़ा बनने लगेगा।

जहाजरानी : देश के पास कुल ९ लाख से बढ़कर ११ लाख टन के जहाज हो जाएंगे।

डाक-तार : डाकघरों की संख्या ७५ हजार से बढ़कर ९५ हजार, डाकघरों की ६,३०० से ८,३०० और टेलीफोनों की ४ लाख ७५ हजार से ६ लाख ७५ हजार हो जाएगी।

संगठन तथा कुशलता के बिना इस उद्देश्य में हम सफल नहीं हो सकेंगे।

सभी राज्यों में भरपूर खेती योजना

देश में सात राज्यों में एक-एक जिले में भरपूर खेती का जो कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) चलाने का निश्चय हुआ था, वह अब अन्य राज्यों में भी चलाया जायगा। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने आसाम, बम्बई, जम्मू-काश्मीर, मैसूर, पश्चिमी बंगाल, केरल और उड़ीसा से कहा है कि अपने यहां यह कार्यक्रम चलाने की ठोस योजना बनाकर भेजें। यह कार्यक्रम फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से चलाया जायगा। पर यह सहायता केवल पूर्व निश्चित सात राज्यों के लिए ही मिलेगी।

यह कार्यक्रम उन जिलों में चलाया जाएगा। जहां सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध है और जहां ग्राम-पञ्चायतें और सहकारी संस्थाएं कायम हैं। यह कार्यक्रम पांच वर्षों में पूरा होगा। आशा है पहले इसमें २० प्रतिशत किसान शामिल होंगे और अन्त में ५ प्रतिशत हो जायंगे। ● ●

केलाशेयन केबल का निर्माण

रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) के हिन्दुस्तान केबल कारखाने ने २० जुलाई, १९६० को पहला कोएक्सियल ट्रंक केबल बनाकर, देश में तार-संचार के उपकरण बनाने के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस कारखाने ने ६ साल पहले अन्य प्रकार के केबल बनाने शुरू किए थे और इस प्रकार विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता की थी। अब यह कारखाना कोएक्सियल केबल बनाकर अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया है।

१९५९-६० में इस कारखाने में १ करोड़ ५० लाख रु० के केबल बनाए गए।

कोएक्सियल केबल के बनने से अब देशभर में ट्रंक टेलीफोन के तार बिछाए जा सकेंगे; टेलीफोन पर दूसरे शहर से आने वाली ध्वनि अधिक स्पष्ट सुनाई देगी और बीच में कोई गडबड़ी नहीं होगी; तथा देश में तार और टेलीप्रिंटर की अधिक लाइनें बिछाई जा सकेंगी। कोएक्सियल केबल जमीन के नीचे बिछाए जाते हैं, इसलिए इनमें गड़बड़ होने का कम अंदेशा रहता है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसके अलावा, तांबे के तार चोरी चले जाने से काफी दिक्कत होती है। इसलिए डाक और तार विभाग ने बड़े-बड़े शहरों के बीच जमीन के नीचे कोएक्सियल केबल बिछाने का निर्णय किया है।

कोएक्सियल केबल में एक खूबी यह भी है कि इससे टेलीफोन के अधिक कनक्शन दिए जा सकते हैं।

कोएक्सियल केबल बनाने में मुख्यतः तांबे के तार और फीते, पोलिथीन की रकाबियां और सीस-इस्पात के फीते इस्तेमाल होते हैं। इसलिए केबलों के निर्माण के साथ इन वस्तुओं के उद्योग भी बढ़ेंगे। अभी तो इन केबलों को बनाने में विदेशी वस्तुएं ही लगायी जा रही हैं, परन्तु कुछ समय बाद इनके लिए देश में ही ये वस्तुएं बनने लगेंगी। तीसरी योजना में हिन्दुस्तान केबल कारखाने में तांबे के तार बनाने का विभाग भी खोलने का विचार है।

खाद का उत्पादन

हिन्दुस्तान केमिकल्स नंगल का उर्वरक कारखाना पूरा होने वाला है और इस साल के अंत तक यहां रासायनिक खाद बनने लगेगी। राउरकेला और नवेली के कारखाने भी १९६२ और १९६३ में तैयार हो जाएंगे। इनके अलावा ट्राम्बे के उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में भी काफी काम हो चुका है और १९६३ के अन्त में यहां भी उर्वरक बनने लगेगा। इस प्रकार देश में रासायनिक खाद का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ाने की योजना है।

हाल में ही आसाम में नाहरकटिया के तेल के कुंओं से मिलने वाली प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने का विचार किया गया है। यह बहुत बड़ा कारखाना नहीं होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वर्तमान उत्पादन को मिलाकर १० लाख टन नत्रजन और ४ से ५ लाख टन फास्फेट युक्त रासायनिक खाद बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में छहों कारखानों के बन जाने पर भारी मात्रा में उर्वरक तो तैयार होगा ही, ७५ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा भी हम बचा सकेंगे और लगभग २० हजार लोगों को काम मिल सकेगा। ● ●

संचालक पंचायत राज विभाग उ० प्र०
की
विज्ञप्ति संख्या ४।५५८० : २७।३३।५३, दिनांक १५
द्वारा
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत

सुन्दर पुस्तकें

		रु०	आ०
वेद सार	प्रो० विश्वबन्धु	१	८
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग			
सच्चा रूत			३
सिद्ध साधक कृष्ण			३
जीते जी ही मोक्ष			३
आदर्श कर्मयोग			३
विश्व-शांन्ति के पथ पर			१
भारतीय संस्कृति	प्रो० चारुदेव		३
बच्चों की देखभाल	प्रिंसिपल बहादुरमल	१	१२
हमारे बच्चे	श्री सन्तराम बी. ए.	३	१३
हमारा समाज		६	
व्यावहारिक ज्ञान		२	१२
फलाहार		१	४
रस-धारा		०	१४
देश-देशान्तर की कहानियां		१	
नये युग की कहानियां		१	१२
गल्प मंजुल	डा० रघुबरदयाल	१	
विशाल भारत का इतिहास	प्रो० वेदव्यास	३	८

१० प्रतिशत कमीशन और ५० रु० से ऊपर के आदेशों पर १५ प्रतिशत कमीशन।

विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार
साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

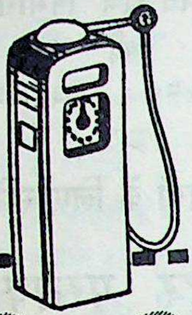

पेट्रोल व

केरोसीन तेल

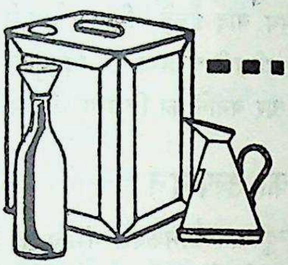

अब लिटरों में बिकते हैं

पेट्रोल उद्योग ने अब मेट्रिक प्रणाली अपना ली है । पेट्रोल और केरोसीन तेल अब लिटरों में बिकते हैं ।

इस प्रकार के परिवर्तन का इनकी कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

गैलन	लिटर	गैलन	लिटर	लिटर	गैलन	लिटर	गैलन
१	४.५५	२०	९०.९	१	०.२२	२०	४.४
२	९.१	३०	१३६.४	२	०.४४	३०	६.६
३	१३.६	४०	१८१.८	३	०.६६	४०	८.८
४	१८.२	५०	२२७.३	४	०.८८	५०	११.०
५	२२.७	६०	२७२.८	५	१.१०	६०	१३.२
६	२७.३	७०	३१८.२	६	१.३२	७०	१५.४
७	३१.८	८०	३६३.७	७	१.५४	८०	१७.६
८	३६.४	९०	४०९.१	८	१.७६	९०	१९.८
९	४०.९	१००	४५४.६	९	१.९८	१००	२२.०
१०	४५.५			१०	२.२०		

१ गैलन = लगभग ४½ लिटर

मेट्रिक प्रणाली

सरलता व एकरूपता के लिए

भारत सरकार द्वारा प्रचारित

DA 64/7

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

भूमि सुधार के कार्यक्रम

स्वाधीनता के बाद से भूमि सुधार कार्यक्रम पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उपज बढ़ाने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना और तत्सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करना। दूसरा किसानों के शोषण को समाप्त करना और उन्हें पूरी सुरक्षा देना। संक्षेप में कहें तो ये उद्देश्य उपज बढ़ाना और असमानता दूर करना हैं। पर यह स्पष्ट है कि यह काम धीरे-धीरे और एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार ही सफलता पूर्वक हो सकता है। मोटे तौर पर इस कार्यक्रम के विभिन्न चरण – जमींदारी उन्मूलन, पट्टेदारी में सुधार, पट्टे की सुरक्षा और लगान को कम तथा नियमित करना, किसानों को भूमि का अधिकार देना, जोत की सीमा निश्चित करना और सहकारी खेती हैं! खेतिहर मजदूरों की हालत में सुधार करना भूमि-सुधार कार्यक्रम का आवश्यक अंग है।

अधिक लोग, कम जमीन

सभी जानते हैं कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा भाग जीविका के लिए खेती पर निर्भर करता है, पर इसके अनुपात में हमारे पास खेती-योग्य जमीन नहीं है। अनुमान है कि देश में प्रति व्यक्ति १.६ एकड़ या प्रति परिवार ८ एकड़ जमीन पड़ती है। ये आंकड़े पिछली जनगणना के अनुसार हैं। लेकिन हमारे देश की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए निश्चित है कि इस अनुपात के घटने की ही सम्भावना है। अतः सामाजिक और आर्थिक न्याय के अलावा उपज बढ़ाने की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि जमीन का बँटवारा और प्रबन्ध ठीक से हो। यह भी जरूरी है कि किसान स्वयं को अपनी जमीन का मालिक समझें, जिससे वह इसके सुधार के लिए जी तोड़ मेहनत कर सकें,

दी बॉम्बे स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. बम्बई

९, बेक हाउस लेन, फोर्ट, बम्बई-१

टेलीफोन : २५५४७४-५ | स्थापित : १९११ | टेलीग्राम : 'फार्मर्स बैंक'

पोस्ट बाक्स नं० ४७२

चेयरमैन : प्रो० डी० आर० गाडगिल

इस बैंक में जमा किये हुए रुपये से भारतीय कृषकों और सहकारी संस्थाओं को सहायता मिलती है।

हिस्सेदारों की परिदत्त पूंजी	कुल डिपाजिट
हिस्सेदारों द्वारा खरीदी गई—रु० ४६ लाख	रु० १७.२० करोड़
बम्बई सरकार द्वारा खरीदी गई—१ करोड़ ३० लाख	सक्रिय पूंजी
रिज़र्व तथा अन्य कोष—५६ लाख	रु० २६.६७ करोड़

बम्बई राज्य में ३०४ स्थानों पर शाखाएं अथवा दूसरी संस्थाओं से संयुक्तीकरण।

भारत के सब प्रमुख नगरों में रुपया एकत्र करने की व्यवस्था है। सभी प्रकार के डिपाजिट स्वीकार किये जाते हैं। नियम प्रार्थना-पत्र पर।

जी० एम० लाड
मैनेजिंग डायरेक्टर
बॉम्बे स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, बम्बई

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

अधिकांश राज्यों में जमींदारी, जागीर और इनाम प्रथा समाप्त कर दी गई है। देश की आधी कृषि भूमि जमींदारी पट्टों के अधीन थी और आधी में रैय्यतवाड़ी थी। पहले जो किसान जमींदार को लगान देते थे, अब वे सीधे सरकार को लगान देते हैं। इससे किसानों को जमींदारी के शोषण से मुक्ति मिली। कुछ राज्यों में तो किसानों को भूमिधारी अधिकार भी दिए गए हैं।

जमींदारों, जागीरदारों आदि को मुआवजा भी दिया गया है। जमींदारी उन्मूलन की विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए जमींदारों को ४ अरब ३५ करोड़ रु० का मुआवजा दिया जाएगा! १९५८-५९ के अन्त तक १ अरब २९ करोड़ रु० मुआवजे में दिया जा चुका है।

लगान में कमी

बहुत से राज्यों में लगान को नियमित करने के लिए कानून बनाये गये हैं और शेष में बनाये जा रहे हैं। साधारणतया एक किसान को अपनी कुल उपज का चौथाई से अधिक लगान में नहीं देना होता। कुछ राज्यों में उपज का छठा भाग लगान में लिया जाता है।

अधिकांश राज्यों में पट्टे की सुरक्षा-सम्बन्धी कानून बनाए जा चुके हैं। शेष राज्यों के विधान सभाओं में इसके लिए विधेयक पेश किये गये हैं। पर इन कानूनों के लागू होने तक किसी किसान को बेदखल नहीं किया जा सकेगा। कुछ राज्यों में किसान के, तथाकथित स्वेच्छा से जमींदार को अपनी जमीन सौंपने की धांधली को समाप्त करने के लिए भी कारवाई की गई है।

दूसरी योजना में यह व्यवस्था की गई कि दूसरों की जमीन जोतने वाले किसान मुआवजा अदा करने पर जमीन के मालिक हो जायेंगे। इसके लिए राज्यों में अलग-अलग कारवाई की गई। पुराने बम्बई राज्य में १ अप्रैल, १९५७ को किसान दिवस मनाया गया। इस दिन लगभग १३ लाख किसानों ने २० लाख एकड़ जमीन का स्वामित्व प्राप्त किया। तीसरी योजना की प्रस्तावित रूप-रेखा में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस काम में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किसानों को भू-स्वामित्व प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की जानी चाहिए।

जोत की अधिकतम सीमा, आय की नहीं

भविष्य में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी जमीन खरीद सकता है, इसके लिए सब राज्यों में कानून बनाये गये हैं। कुछ राज्यों में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कानून बनाये जा चुके हैं और शेष राज्यों में बनाये जा रहे हैं।

जोत की सीमा निश्चित करने का अर्थ किसानों की आय की सीमा निश्चित करना नहीं है, हालाँकि जोत की सीमा निर्धारित करने में यह ध्यान रखा जा रहा है कि इस जमीन से कम से कम इतनी आय होगी। पर बाद में किसान के प्रयत्नों से आय बढ़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। आय बढ़ने पर भी पूरी जमीन किसान की ही रहेगी और उसे इसका जरा-सा भी हिस्सा नहीं छोड़ना होगा।

यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने पर उपज बहुत बढ़ाई जा सकती है, जिससे किसान की आय भी स्वतः ही बढ़ेगी। इस समय देश की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है, अतः इसे बढ़ाने की बहुत सम्भावना है।

भूमि सुधार के कार्यक्रम में भूमिहीन मजदूरों की हालत सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस काम के लिए इन लोगों में ३० लाख एकड़ कृषि योग्य परती जमीन बाँटी गई है। ग्रामदान और भूदान में मिली १० लाख एकड़ जमीन भी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दी गई है।

भूमि सुधार के इस कार्यक्रम के लागू हो जाने पर देश की अधिकांश जमीन इन भू-स्वामी किसानों के पास होगी। इस कार्यक्रम की पूर्ण सफलता और उपज बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि इन किसानों की सहकारी समितियाँ बनाई जाएँ, जो ऋण, हाट व्यवस्था, खाद और बीज आदि के वितरण की व्यवस्था करें। यह काम किसानों की सहमति और पूर्ण सहयोग से किया जाना चाहिए। ● ●

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जीवन-बीमा याने व्यक्ति की सुरक्षा। जीवन-बीमा याने राष्ट्र का आर्थिक विकास। अपनी निधि को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में लगाकर निगम ने उनमें नयी गति प्रदान की है—उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। १९५८ में निगम ने ७८ करोड़ रुपयों को खांड, कागज़, सीमेंट, पटसन, रुई, मिलें, लोहा और इस्पात, जहाज-निर्माण, परिवहन, खेतीबारी आदि उद्योगों में लगाया था।

जैसे-जैसे निगम के पास धन बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे उद्योगों में अधिक रुपयों को वह लगाता रहेगा। इससे कर्मचारियों में जीवन-बीमे के प्रति जागृति के भाव निर्माण करते हुए मालिक अपने उद्योगों की अभिवृद्धि में जी-जान लगाकर जुटे रहेंगे। मालिक और कर्मचारियों में इससे सौहार्द निर्माण होगा।

औद्योगिक संस्थाओं के लिए निगम के पास विविध योजनाएँ हैं। आज ही जीवन-बीमा एजेंट से सम्पर्क स्थापित करके वेतन-बचत-योजना, सामूहिक बीमा योजना और वृद्धावस्था की पेन्शन योजना आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।

औद्योगिक क्षेत्रों में निगम का महत्वपूर्ण कार्य

रसायन और औषधियाँ

खेतीबारी | जहाज-निर्माण और परिवहन | बीमा

खांड और आसव | कोयला | बैंक

कागज़ और गूदा | पटसन | सीमेंट

रुई | एन्जीनियरिंग | विद्युत्

लाइफ़ इन्श्योरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इन्डिया

P/LIC/E-16 Hindi

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

जापान व भारत का आर्थिक विकास

(पृष्ठ ४०० का शेष)

बाजरा	११३०	१२६०	३७०	३८०
चावल (धान)	५००७	४२२०	११००	१३६०
आलू	११००	१३२००	६६००	६०००
तमाखू	१७३०	२०१०	७५०	७१०
रुई	१२०	१३०	६०	१००

श्री सी० सी० एलन ने 'जापान इकानामिक रिक्वरी' में उपज में इस वृद्धि का श्रेय धान की विशेष कृषि-पद्धति तथा रासायनिक खादों और सिंचाई को दिया है। जब भारत में कुल कृषि प्रदेश का एक तिहाई भाग सिंचित प्रदेश है, तब जापान में ६५ प्रतिचत कृषि सिंचाई से होती है। सिंचाई करने से फसल की पैदावार निःसन्देह बहुत अधिक करीब दुगनी हो जाती है।

सिंचाई के अतिरिक्त खाद का प्रयोग भी फसल की पैदावार बढ़ाने में किस तरह सहायक होता है, यह नीचे के अंकों से स्पष्ट है:—

खाद मीट्रिकटन	भारत	जापान	वर्ष
नाइट्रोजीनिय खाद	७८६००	८३५०००	१९५४-५५
	८२०००	७७००००	१९५६-५७
फास्फरिक खाद	१४४००	३१४०००	१९५४-५५
	१४०००	३८१६००	१९५६-५७

इन संस्थाओं का विषम अन्तर तब और भी स्पष्ट हो जाएगा, जब हमें यह मालूम हो कि भारत में कृषि क्षेत्र जापान की अपेक्षा २६ गुना है। भारत जापान की तुलना में क्रमशः सिर्फ ११ व ४ प्रतिशत दोनों खादों का प्रयोग करता है। जापान की अतुल पैदावार का यह बड़ा भारी रहस्य है।

सहकारी कृषि

आज भारत में सहकारी समितियों पर बहुत बल दिया जा रहा है। जापान में संयुक्त कृषि पर भले ही बहुत बल न दिया जाता हो, किन्तु प्रायः सभी कृषि सेवायें सहकारी आधार पर संगठित की जाती है। खास, बीज, खाद व कृषि उपकरणों की उपलब्धि, पैदावार की बिक्री आदि सब कार्य सहकारी समितियों के द्वारा होते हैं। आज भारत जापान से इस दिशा में बहुत कुछ सीख सकता है। भारत से गए पाटिल प्रतिनिधि-मण्डल ने जापान की सहकारी समितियों के सम्बन्ध में कहा था कि वहाँ ९६ प्रतिशत किसान परिवार इन समितियों के सदस्य हैं। ९६ प्रतिशत अतिरिक्त धान, व ८५ प्रतिशत गेहूँ इन समितियों के द्वारा बेचा जाता है। भारत के अपेक्षाकृत बहुत छोटे देश जापान में ६०० औसत सदस्यों की ३५००० सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें १४ हजार बहु-उद्देशीय समितियाँ हैं। इनमें १२ हजार बहु-उद्देशीय समितियों की पूँजी १९५५ में ३६० करोड़ रुपये थी और उन्होंने किसानों को २७७ करोड़ रुपया कर्ज दे रखा था। उन्होंने ४८७ करोड़ रुपये का माल बाजार में बेचा था। इन समितियों के पास जो गोदाम थे उनमें ४२ लाख टन अनाज रखा जा सकता था। छोटे-छोटे किसानों को इन सहकारी समितियों से असीम लाभ पहुंचता है और कम समय तथा कम व्यय में उनका बहुत सा काम हो जाता है।

उद्योग की उन्नति

हमने ऊपर के अनुच्छेदों में जापान के कृषि विकास की चर्चा की है। पर जापान तो उद्योग प्रधान देश है। कुछ ही वर्षों में उसने जो अद्भुत औद्योगिक विकास किया है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसका उत्पादन किस तरह बढ़ा यह नीचे के निर्देशांक अंकों से देखिए—

जापान का औद्योगिक उत्पादन १९३४-३६ = १००

	उत्पादन (क)	वास्तविक वेतन कारखानों में
१९५१	११८·४	८४·२
१९५२	१३०·६	९६·२
१९५३	१६१·४	१०३·५
१९५४	१६६·९	१०५·५
१९५५	१८९·७	१०९·६
१९५६	२३१·७	१०७·६

(क) इसमें खनिज, निर्माण तथा सरकारी सेवाएं सम्मिलित हैं। १९५५-५६ में जापान युद्ध पूर्व के उत्पादन स्तर पर पहुँच चुका था। १९३० की अपेक्षा उसका अतिरिक्त राष्ट्रीय उत्पादन ४४ प्रतिशत बढ़ चुका था। प्रति व्यक्ति आय १० प्रतिशत अधिक हो चुकी थी। बड़े उद्योगों को उसने करीब-करीब पुनः स्थापित कर लिया था। लोहे

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

और इस्पात उद्योग की ओर उसने विशेष ध्यान दिया। युद्ध के पूर्व वहां कुल ४७ लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ था। पर १९५६ में १११ लाख टन का उत्पादन उसने किया अर्थात् करीब ढाई गुना।

यह ठीक है कि कोरिया में प्रारम्भ होने वाले युद्ध ने जापान को अकस्मात् औद्योगिक विकास की सुविधाएं तथा अवसर प्रदान किए। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ने जो जापान के उद्योगों के विध्वंस का मुख्यत: उत्तरदायी था, अपने स्वार्थ-वश उद्योग विकास में जापान को पर्याप्त सहायता व सुविधा दी। किन्तु जापान की उन्नति का कारण केवल यही न था। दीर्घकालीन अनुभव, योग्यता, विकास की प्रबल आकांक्षा, निष्ठा और ऊंचे दर्जे की व्यवस्था को जापान की औद्योगिक उन्नति को श्रेय दिया जा सकता है। युद्ध से पूर्व प्रायः समस्त अर्थ व्यवस्था पर जेबत्सू परिवार का आधिपत्य था। जनरल मैकार्थर के अमेरिकन शासन में इस परिवार के एकाधिपत्य व प्रभुत्व को खण्ड-खण्ड कर दिया गया। तथापि निजी उद्योग की प्रेरणा के तत्वों को नष्ट नहीं किया गया और राष्ट्रीयकरण की अपेक्षा नियंत्रण की नीति सरकार ने अपनाई। कुछ उद्योग तो जिन पर अमेरिकन शासन के समय में सरकार ने अधिकार कर लिया था, लोगों को वापस कर दिए गए। परिणाम स्वरूप राष्ट्र की आकांक्षा व प्रतिभा औद्योगिक विकास में जुट गई। इस कार्य में विदेशी पूंजी की भी सुविधाएं देकर सहयोग किया गया जैसा कि आजकल भारत उसका सहयोग प्राप्त कर रहा है। १९५६ में वहां ५५० लाख पौण्ड विदेशी पूंजी लगी थी पर इसी वर्ष जापानी उद्योग की सफलता की आशाएं उज्ज्वल देखकर ८५० लाख पौंड विदेशी रजिस्टर्ड हो गई। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक नई नीतियों का अवलम्बन किया गया।

इस पृष्ठ पर नीचे छपी तालिका में कुछ उद्योगों के तुलनात्मक अंक दिए जाते हैं जिनसे जापान व भारत के औद्योगिक विकास की जानकारी मिलेगी।

जापान में कृषि व उद्योग के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है उसका यह प्रभाव हुआ है कि भारत की अपेक्षा जापान में जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में कम वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित अंकों से प्रकट होगा—

१९५३ = १००

	जीवन व्यय निर्देशक अंक		थोक मूल्य निर्देशक अंक	
	भारत	जापान	भारत	जापान
१९५६	९९	१०६	९७	१०२
१९५७	१०४	१०९	१०३	१०५

मूल्यों में कम वृद्धि का श्रेय जापान के उन छोटे उद्योगों को भी देना चाहिए जो वहां की अर्थ व्यवस्था में विशेष स्थान रखते हैं। १९५५ में लघु और मध्य उद्योग संख्या में कुल उद्योगों का ९९·६ प्रतिशत थे जब कि ७३·१ प्रतिशत आदमी उद्योगों में लगे हुए थे और ५९·२ प्रतिशत उत्पादन इन लघु और मध्य उद्योगों द्वारा होता था। बहुत विविध वस्तुओं का उत्पादन इन लघु और मध्य उद्योगों से होता है जब कि लोहा आदि का उत्पादन बड़े उद्योगों के हाथ में है। ये छोटे और मध्य उद्योग बड़े उद्योगों

जापान में

	कोयला लाख टन	क्रूड स्टील ००० मी० टन	अलमीनियम ००० मी० टन	सीमेंट ००० मी० टन	सीने की मशीनें ००० में	सूती कपड़ा लाख गज
१९४७	२७२	९५२	२·७	१२३७	१४७·१	६२२०
१९४८	३३७	१७१५	७·०	१८५९	१८०·१	९८४०
१९५१	४३३	६५०२	४६·९	६५४८	१०७८·६	२१७९०
१९५५	४२४	९४०८	५७·५	१०५५७	१८०३·०	३०१८०
१९५६	४६६	१११०६	६६·०	१३०२४	१८९७·८	३४८००

भारत में

	कोयला लाख टन	क्रूड स्टील ००० मी० टन	अलमीनियम ००० मी० टन	सीमेंट ००० मी० टन	सीने की मशीनें ००० में	सूती कपड़ा लाख गज
१९५१	३४३·१	१५००	३·८	३१९६	४४·४	४०७६०
१९५६	३९४·०	१७१५ (१९५७)	६·५	४९२८	१३·०	५३०६०

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

112998

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं

सोवियत रूस से पेट्रोल-आयात

मिट्टी के तेल और पैट्रोल की दूसरी चीजों के आयात के बारे में १५ जुलाई को भारत सरकार और सोवियत रूस के महत्त्वपूर्ण करारनामे पर हस्ताक्षर हो गये।

इन्डियन कम्पनी पूरी तरह सरकारी कम्पनी है और भारत में पैट्रोल की चीजों का वितरण और बेचने के लिए स्थापित की गई है। रूस से पेट्रोल की चीजों का आयात इसी सरकारी कम्पनी के जरिये होगा। पेट्रोल की चीजों का मूल्य भारतीय रुपयों में चुकाया जायगा, शुरू में करार ४ साल के लिए है और हर साल आयात बढ़ता जाएगा। देश में मिट्टी के तेल और डीजल तेल की खपत काफी बढ़ती जा रही है। इस कारण जब देश के दोनों तेल-शोधक कारखाने भी चालू हो जायेंगे, तब भी आयात घटाने की नौबत नहीं आएगी। रूस से पेट्रोल की चीजों के आयात से देश को चीजों की बढ़ती हुई मांग पूरी की जाएगी।

१७५ करोड़ रु० के दो नये केन्द्रित ऋण

भारत सरकार ने १८ जुलाई, से २० जुलाई, १९६० तक १ अरब ७५ करोड़ रु० के दो नये ऋण लेने की घोषणा की है। ये ऋण (१) ३॥ प्रतिशत ब्याज के १९६६ के बांडों के रूप में जिनका मूल्य ९९·७५ प्रतिशत होगा और जो १८ जुलाई, १९६६ को भुगताया जा सकेगा और (२) ४ प्रतिशत ब्याज के १९८० तक के कर्ज के रूप में होंगे जिसका मूल्य ९९·९० प्रतिशत होगा और जो १८ जुलाई, १९८० को भुगताया जायगा। दोनों ऋणों पर ब्याज छमाही मिलेगा और हर साल १८ जनवरी और १८ जुलाई को लिया जा सकेगा। ब्याज पर १९५२ के भारतीय आयकर कानून के अनुसार आयकर लगेगा।

देश में सिलेंडरों का निर्माण

भारत सरकार ने देश में सिलैंडर बनाने के कारखाने खड़े करने के लिए अनुमति देने का निर्णय किया है।

के पूरक के रूप में बहुत सहायक हो रहे हैं। भारत की उद्योग नीति से जब जापान की भांति भारत में भी पूंजी की कठिनता और मन्द मानव शक्ति की अधिकता है। इस लिए यहां भी लघु और मध्य उद्योगों का विकास स्वाभाविक और वांछनीय है। आवश्यकता यह है कि दोनों उद्योग एक दूसरे के प्रतिस्पर्द्धी न हों, परस्पर पूरक हों और उनमें समन्वय स्थापित किया जाए।

परस्पर व्यापार

जापान व भारत में पारस्परिक व्यापार निम्नलिखित रूप में हो रहा है—

भारत से जापान को निर्यात और आयात (करोड़ रु० में)

	निर्यात	आयात
१९५४	१६	१७
१९५५	२६	३२
१९५६	३०	४४
१९५७	२७	५४

हाल ही में किए गए समझौतों के अनुसार जापान भारत से पर्याप्त मात्रा में कच्चा लोहा लेगा और इस उद्योग व व्यापार के विकास के लिए वह उड़ीसा में रेलवे लाइन और बन्दरगाह के निर्माण के निमित्त विपुल राशि भी देगा। वस्त्रोद्योग की मशीनरी विलम्बित भुगतान की शर्त पर भी एक समझौता हो गया है।

जापान यद्यपि उद्योग प्रधान देश है तथापि वहां की सभ्यता एशियाई है। वहां की प्रकृति यूरोप की अपेक्षा भारत से ही अधिक मिलती है। इसलिए अपने देश के आर्थिक विकास में हमें जापान से काफी सूचनाएं मिल सकती हैं। सघन वैज्ञानिक कृषि, सहकारी सेवाएं, छोटे व बड़े उद्योगों का समन्वय, उद्योगों की प्रबन्ध कुशलता, संगठन की पद्धति, उत्पादन-क्षमता और जापान की बैंकिंग प्रणाली जिससे उद्योग को बहुत सुविधाएं मिलती है आदि का पर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है। ● ●

*यह लेख करीब एक वर्ष पूर्व लिखा गया था, इसलिए इसमें नवीनतम अंक नहीं आ सके, तथापि तुलना के लिए कोई अन्तर नहीं पड़ता।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

नंगल कारखाने में इस साल उर्वरक बनने लगेगा

नंगल का उर्वरक कारखाना पूरा होने वाला है और इस साल के अन्त तक यहां खाद बनने लगेगी। राउरकेला और नेवेली के कारखाने भी १९६२ और १९६३ में तैयार हो जाएंगे। इनके अलावा ट्राम्बे के उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में भी काफी काम हो चुका है और १९६३ के अन्त में यहां भी उर्वरक बनने लगेगा।

आसाम में नहर कटिया के तेल के कुओं से मिलने वाली प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने पर भी विचार किया गया है। यह छोटा कारखाना होगा और यहां हर साल ३२,५०० टन नाइट्रोजन तैयार किया जाएगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वर्तमान उत्पादन को मिलाकर १० लाख टन नाइट्रोजन और ४-५ लाख टन फास्फेटयुक्त रासायनिक खाद बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में छहों कारखानों के बन जाने पर भारी मात्रा में उर्वरक तैयार होगा, जिससे हमारी ७५ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा बचेगी और लगभग २० हजार लोगों को काम मिलेगा।

पाकिस्तान से आयात के लाइसेंस

भारत सरकार ने पाकिस्तान से ६ चीजों के आयात के लाइसेंस देने का निश्चय किया है। ये चीजें २९ मार्च १९६० के भारत-पाक व्यापार करार में दी गयी है। ये चीजें हैं : सुपारी, पान, अंडे और मुर्गियां, मछली सूखी और नमक लगी, दवाएं (यूनीनी और आयुर्वेदिक दवाएं भी) और घोड़े तथा दूसरे पशु। इन ६ चीजों के लाइसेंस इस शर्त पर दिये जाएंगे कि इनका आयात भारतीय रुपये में होगा जो अपरिवर्तनीय (नान-कनवर्टिबिल) होगा।

असम में तेल का भंडार

असम के नहरकटिया और मोरन तेल क्षेत्र में जो अनुमान लगाया गया है, उससे पता चलता है कि आसाम के उत्तरी क्षेत्र से लगभग २ करोड़ ६० लाख टन पेट्रोल निकाला जा सकेगा। इसके अलावा वहां १ करोड़ ३० लाख टन और पेट्रोल होने का अनुमान है। यह भी अनुमान लगाया है कि इस क्षेत्र में और खुदाई करने से २ करोड़ टन और पेट्रोल मिल जाएगा।

इस प्रकार इस क्षेत्र में १५ साल तक हर साल ३० लाख टन पेट्रोल निकाला जा सकता है।

सोन नदी पर बांध और पुल बनेगा

भारत सरकार ने सोन बांध योजना मंजूर की है। इसके अन्तर्गत बिहार में डेहरी से ५ मील ऊपर की ओर सोन नदी पर ४,७२२ फुट लम्बा बांध और पुल बनेगा। इसके अलावा इस नदी के दोनों ओर एक-एक नहर बनेगी। इसके बाद में बिजली भी बनाई जा सकेगी। योजना पूरी हो जाने के कुछ दिन बाद नदी के दोनों ओर काफी गहरी नहरें भी बनाने का विचार है। बांध बन जाने पर १३ लाख १६ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी।

दोनों गहरी नहरों का खर्च, ६ करोड़ १६ लाख रु० मिलाकर इस योजना पर कुल २० करोड़ ५९ लाख रु० खर्च होने का अनुमान है। इस योजना का निर्माण-कार्य शुरू हो चुका है और आशा है १९६५-६६ तक यह बन कर पूरी हो जाएगी।

रेंड बांध

रेंड बांध में १ जुलाई, १९६० तक लगभग ९३ प्रतिशत कंकरीट डाली जा चुकी है। रेंड योजना के बिजलीघर, कंट्रोल रूमर, आउट और स्विचयार्ड के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है।

रेंड बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पिपरी गांव के निकट बनाया जा रहा है। इसका जलाशय १८० वर्ग मील तक फैला है और इसमें ८६ लाख एकड़ फुट पानी जमा हो सकेगा। यह बांध कंकरीट का होगा और इसकी लम्बाई ३'०६५ फुट और ऊँचाई ३०० फुट होगी। रेंड योजना के बिजलीघर में ५०-५० हजार किलोवाट बिजली पैदा करने के ५ यंत्र लगाये जायगे। यह बांध १९६१-६२ तक तैयार हो जाएगा।

—१९५९-६० में भारत ने ६४१ करोड़ रुपये का निर्यात करके अपने निर्यात व्यापार में रिकार्ड कायम किया है। यह निर्यात गत वर्ष के कुल निर्यात से १५ प्रतिशत अधिक है।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि

वित्तमंत्री ने लोकसभा में बताया है कि १५० रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वेतन का ७॥ प्रतिशत से अधिक मकान किराया नहीं देना पड़ेगा। वेतन और मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में आयोग की सभी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इनके अतिरिक्त प्रायः सभी अन्य बड़ी सिफारिशों को भी सरकार ने मान लिया।

रेल मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार रेलवे की नई वेतन दरें १ जुलाई १९५९ से लागू होंगी। नई वेतन दरों के अनुसार ३०० रुपये तक वेतन पाने वालों का अधिकांश मंहगाई भत्ता उनके मूल वेतन में मिला दिया जायगा। इसके लिए रेलवे को ३ करोड़ रुपए वार्षिक अधिक खर्च करना पड़ेगा। निम्न दर्जे के कर्मचारियों को अधिक मुआवजा, भत्ता दिए जाने के कारण रेलों का १ करोड़ रुपया खर्च बढ़ जाएगा। सामान्यतया कर्मचारियों के कुल वेतन में तात्कालिक वृद्धि ५॥ रु० प्रतिमास से लेकर २५ रु० मासिक से अधिक होगी। चौथे दर्जे के कर्मचारियों के वेतन में ११ रु० की वृद्धि होगी।

नहरकटिया में ५०,४०० किलोवाट बिजली तैयार होगी

भारत सरकार ने नहरकटिया ताप बिजली घर योजना स्वीकार कर ली है। इसके अन्तर्गत कामरूप (आसाम) में ताप-बिजली घर बनाया जाएगा और वहाँ से चारों ओर बिजली भेजने के लिए तार बिछाए जायेंगे। बिजली घर में नहरकटिया तेल-क्षेत्र में मिलने वाली प्राकृतिक गैस से बिजली बनाई जाएगी। वहाँ गैस से चलनेवाले तीन यंत्र लगाए जायेंगे, जिनसे कुल ५०,४०० किलोवाट बिजली तैयार होगी।

नवम्बर में चम्बल घाटी योजना का उद्घाटन

इस साल नवम्बर में चम्बल घाटी योजना का उद्घाटन होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें मिलकर इस योजना का निर्माण करेंगी। इस बहुमुखी योजना पर ६३ करोड़ रु० खर्च होंगे। इससे दोनों राज्यों में १४ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की जायेगी और २ लाख १० हजार किलोवाट बिजली बनाई जायेगी।

गन्ने की पैदावार की वृद्धि

१९५९-६० के अखिल भारतीय अन्तिम प्राक्कलन में ५१ लाख ७८ हजार एकड़ जमीन में गन्ने की खेती हुई और ७ करोड़ ५० लाख ३८ हजार टन गन्ना उपजा, जो अब तक के रकबे और पैदावार से सबसे अधिक है। १९५९-६० में ३ लाख ७५ हजार अधिक एकड़ जमीन में गन्ना बोया गया और गन्ने की पैदावार में ४५ लाख ८२ हजार टन अर्थात् ६.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

—केन्द्रीय सरकार के ३॥ प्रतिशत बांड, १९६६ और ४ प्रतिशत ऋण, १९८० की रकम पूरी हो गई हैं। अतः इन दोनों केन्द्रीय ऋणों के लिए २० जुलाई को दोपहर १ बजे के बाद से रुपया लेना बन्द कर दिया गया।

कुल १७५ करोड़ रु० के इन दोनों ऋणों की घोषणा ४ जुलाई, १९६० को की गई थी।

—१९६० के प्रारम्भिक तीन महीनों में भारत का कुल खनिज उत्पादन ३७३० लाख रुपये का हुआ। गत वर्ष की इसी अवधि के खनिज उत्पादन ३४३० लाख रुपये था।

—जुलाई २९, १९६० को अमेरिका के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए जिसके अन्तर्गत अमेरिका से रुई की ४ लाख और गांठों का आयात होगा। यह आयात पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत होगा। कपास का मूल्य और जहाज का आधा खर्च १८ करोड़ ८० लाख रु० बैठेगा जिसका भुगतान रुपए में होगा। कपास के मूल्य का ८५ प्रतिशत आर्थिक विकास में लगाने के लिए भारत सरकार को मिल जाएगा।

इसके अलावा २ लाख और गांठों के आयात के लाइसेंस देने का निश्चय किया गया है। यह माल व्यापारियों से लिया जाएगा।

—कोयले की कमी क्षतिपूर्ति के लिए और कोयले की खानों से दूर होने के कारण परिवहन की कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अणुसंयंत्र लगाने का निश्चय किया है। पहला अणुसंयंत्र ही बम्बई और अहमदाबाद के बीच लगाया जाएगा।

112998

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

मनुष्य का विश्वास

एक विश्वास जागता है मनुष्य में नई प्रेरणाओं का गीत बन कर
सुबह की रोशनी में उठकर मनुष्य छूता है जिन्दगी के सफ़र को फिर से
एक विश्वास ही है जो पत्थरों, चट्टानों को चीरता है, तराशता है
और पानी को ढाल कर नये रास्तों में वह शक्तियों को है जन्म देता।

एक विश्वास कि सुनहरा भविष्य होगा
आने वाली वह दुनिया लायेगी अपने आंचल में नई सौग़ातें
गीत ख़ुशियों के चहचहायेंगे......जिन्दगी वरदान होगी
एक विश्वास, जो कि जीवन को सात रंगों से भर रहा है।

आज, हमेशा की तरह हमारे उत्पादन घरों को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और सुखी बनाने में सहायक होते हैं। लेकिन आज हम प्रयत्नशील हैं....... आने वाले कल के लिये, जब और अधिक सुन्दर जीवन के लिये दिन प्रति दिन बढ़ती हुई आकांक्षा हम से और अधिक प्रयत्नों की मांग करेगी। और हम अपने नये विचारों, नये उत्पादनों और अधिक विस्तृत साधनों के साथ उस समय भी आप की सेवा के लिये तैयार पाये जायेंगे........

आज और हमेशा...घर घर की सेवा...हिन्दुस्तान लीवर का आदर्श

PR. 6-X52 HI

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

गांवों में नया जीवन

देश के अन्य भागों की तरह उत्तरप्रदेश में भी अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। अतः यह बात सब की समझ में आसानी से आ सकती है कि जब तक हमारे गांव समृद्ध नहीं बनते हैं तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इस तथ्य को सामने रख कर भारत सरकार ने गांव वालों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक योजना चलायी, जिसे सामुदायिक विकास योजना कहा जाता है। इस योजना का प्रारम्भ सर्वप्रथम उत्तरप्रदेश में इटावा नामक स्थान पर हुआ। बाद में इसका प्रसार देश के सभी भागों में हो गया और प्रत्येक जगह जनता ने इसे अपनी योजना समझकर अपनाया। आज प्रदेश में फैले ५५२ विकास खण्ड इस योजना की सफलता के प्रतीक हैं। जिन लोगों ने विकास खण्डों में रहने वालों को पास से देखा है उन्हें यह विश्वास हो गया है कि सामुदायिक विकास योजना थोड़े समय में गांवों में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर देगी। प्रत्येक सामुदायिक विकास-खण्ड में सामान्य जनता सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने, अच्छे बीज, अच्छी खाद और वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से खेती करने, लघु उद्योगों का विकास करने, यातायात की सुविधाओं में वृद्धि करने तथा नये-नये चिकित्सालय एवं विद्यालय खोलने में सरकार की ओर विकास कार्यकर्त्ताओं की सहायता कर रही है। यह गांवों में नये जीवन का उद्घोष है। ऐसा जीवन जिसे गांव का किसान और श्रमिक बड़ी प्रसन्नता से अंगीकार करेगा।

उत्तरप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित

सम्पादक—कृष्णचन्द्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (प्रा०) लि० (लीजिज ऑफ अर्जुन प्रेस) दिल्ली-६ से मुद्रित व अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११, शक्तिनगर, दिल्ली-६ से प्रकाशित।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Compiled
1999-2000

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar